

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj.)**

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र

INTERNATIONAL ECONOMICS

डॉ. डी. एन. गुट्टू

बी. एस्सी. आनर्स (तदर्थ),

एम. ए. (यू. एस् ए.), पी-एच डी (यू. एस् ए.)

प्रोफेसर एव यश्याग, अर्थशास्त्र विभाग

दिल्ली इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड साइंस, पिलानी

८

कॉलेज बुक डिपो, जयपुर

Topics for Study

- 1 The need for a separate theory of International Trade. The Theory of Free Trade. Trade under absolute cost differences and comparative cost differences. Trade with constant; diminishing and increasing unit costs. Heckscher-Ohlin theory. Factor price equalization.
- 2 Empirical verification of comparative cost and Heckscher Ohlin theories. Leontief paradox. Reciprocal demand. Marshall-Edgeworth offer curves. Determination of terms of trade and gains from trade.
- 3 Effects of tariffs on production, distribution and terms of trade effects of quotas. Custom unions. GATT. The cause for protection in less developed economies. Trade barriers to export of less developed economies. Stabilization of primary product prices. Role of UNCATAD. Regional Economic Co-operation between less developed economies.
- 4 Balance of payment, Exchange rates. The adjustment mechanism under gold standard, fixed exchange rates and flexible exchange rates. Effects of devaluation. Price effects and income multipliers. Exchange control. Role of the IMF. The problem of international liquidity. Destabilizing effects of short-term capital movement Long-term private investments, trends and problems. Foreign aid. Debt service burden of less developed economies. Role of IBRD and IDA.
- 5 Trends in the value, composition and direction of India's trade in recent years. Exchange control in India. Devaluation of the rupee in 1966 Role of the STC in India's foreign trade. India's balance of payments. Recent trends and present position.

नवीन संस्करण की भूमिका

‘अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र’ का यह परिवर्द्धित एवं सशोधित संस्करण पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए अतीव हर्ष हो रहा है। इसमें तुलनात्मक लागत सिद्धान्त पर रिकार्डो, हैबरलर, हेक्सलर एवं मोहलिन आदि अर्थशास्त्रियों के विचारों का धृष्ट से विवेचन किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष, विश्व-बैंक तथा भारत के विदेशी व्यापार के विभिन्न पहलुओं का अद्यतन (up-to-date) बनाने के लिए नवीनतम माँकडे प्रस्तुत किए गए हैं। प्रत्येक समस्या को उसके सम्पूर्ण परिवेश में रख कर देखने का प्रयास किया गया है। आशा है यह रचना विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा विषय में सामान्य रुचि रखने वाले पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

रचनात्मक प्रालोचना तथा शुभाव सहर्य स्वागतव्य है।

लेखक

दो शब्द

अन्तर्राष्ट्रीय जगत में व्यापार और व्यवसाय का महत्त्व अत्यन्त प्राचीन काल से है किन्तु राष्ट्र-राज्यों के उदय ने इसे एक अपूर्व मोड़ दिया है। वर्तमान विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच स्थित सम्बन्धों की प्रकृति न केवल राजनीतिक अथवा कूटनीतिक है बल्कि यह मुख्य रूप से आर्थिक है। काले मार्क्स की भाषा में समस्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार आर्थिक कारणों से अनुप्रेरित होते हैं। लेनिन ने समस्त अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों की जड़ में पूंजीवाद को माना है। विश्व का विभिन्न समूह में विभाजन मुख्यतः आर्थिक कारण से ही है।

इस पृष्ठभूमि में यदि हम समाजवादी, पूंजीवादी और तीसरे विश्व-युद्ध की गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अध्ययन परम आवश्यक होगा।

प्रस्तुत ग्रन्थ इसी आवश्यकता की पूर्ति की दिशा में एक प्रयास है। इसकी सार्थकता दिशा के विभिन्न सीमा-चिन्हों द्वारा निर्धारित की जा सकेगी।

लेखक

अनुक्रमणिका

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता

(The Need for a Separate Theory of International Trade)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ (1), अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का जन्म (3), अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता (4), अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्त्व या उसके लाभ (7), अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियाँ (9), अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता (11), अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता नहीं (16)

स्वतन्त्र व्यापार के सिद्धान्त, पूर्ण लागतों के अन्तर और तुलनात्मक लागतों के अन्तर का व्यापार, स्थिर, घटती हुई और बढ़ती हुई इकाई लागतों की दशा में व्यापार

(The Theory of Free Trade, Trade under Cost Differences and Comparative Differences, Trade with Constant, Diminishing and Increasing Unit Costs)

स्वतन्त्र व्यापार का सिद्धान्त (19), लागत विभिन्नताओं का सिद्धान्त (21), तुलनात्मक लागत अन्तरों के आधार (27), तुलनात्मक लागत सिद्धान्त का विश्लेषण (28), तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के विभिन्न रूपान्तर (29), अवसर लागत सिद्धान्त (35), स्थिर लागतों की अवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (36), घटती हुई लागतों के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (42), घटती हुई लागतों के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (45), प्रांशिक विशिष्टीकरण (47), आनुपातिक लागतें (48), तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की आधारभूत मान्यताओं की आलोचना (49), तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की आलोचना (52), तुलनात्मक लागत सिद्धान्त में किए गए परिवर्तन (58)

3 हेक्शर-ओह्लिन सिद्धान्त एवं साधन मूल्य समानोकरण
(Heckscher-Ohlin Theory and Factor Price Equalization)

प्रती हेक्शर का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विचार (63),
ओह्लिन का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (64), हेक्शर-ओह्लिन
सिद्धान्त की मान्यताएँ (65), हेक्शर-ओह्लिन सिद्धान्त की
प्रालोचना (69), साधन-मूल्य समानोकरण (71)

4 तुलनात्मक लागत एवं हेक्शर-ओह्लिन सिद्धान्त का प्रा-
भाषिक प्रमाणीकरण अथवा लियनतीफ का विरोधानास
(Empirical Verification of Comparative Cost and
Heckscher-Ohlin Theory or Leontief Paradox)

विदेशी व्यापार के प्रति वर्तमान दृष्टिकोण (82)

5 प्रतिपूरक मांग, मार्शल-एडवर्थ का प्रस्ताव वक्र
(Reciprocal Demand, Marshall-Edgeworth Offer Curves)

प्रतिपूरक मांग का सिद्धान्त (84), मार्शल-एडवर्थ का प्रस्ताव
वक्र (89)

6 व्यापार शर्तों के निर्धारक घटक एवं व्यापार से लाभ
(Determination of Terms of Trade and Gains from Trade)

व्यापार की शर्तों का अर्थ (94), व्यापार की शर्तों के रूप
(96), व्यापार की शर्तों के मापक (106), व्यापार शर्तों
के निर्धारक घटक (109), व्यापार शर्तों के मापने में दोष
(118), व्यापार शर्तों का व्यावहारिक महत्व (120),
व्यापार शर्तों और अर्द्ध-विकसित देश (120), अन्तर्राष्ट्रीय
व्यापार से होनेवाले लाभ (122), व्यापार से लाभ—एक
सरल रेखाचित्रीय विश्लेषण (127), लाभ की मात्रा को
प्रभावित करनेवाले तत्व (128), व्यापार से होनेवाले
लाभ का मापक (130), व्यापार से होनेवाली प्राप्तिशों का
वितरण (132)

7 उत्पादन, वितरण एवं व्यापार की शर्तों पर प्रशुल्क के प्रभाव
(Effects of Tariffs on Production, Distribution and Terms
of Trade)

प्रशुल्क सिद्धान्त का इतिहास (134), स्वतन्त्र व्यापार और
प्रशुल्क (139), प्रशुल्क सिद्धान्त की मान्यताएँ (139),
प्रशुल्क की लैन्डार्ड का माप (141), प्रशुल्कों की तीन

धेरियाँ (143), दो दृष्टिकोण (149), प्रशुल्क का मुग्तान कौन करता है (149), प्रशुल्क के प्रभाव (152), प्रशुल्क के समर्थन में दिए गए तर्क (157), प्रशुल्क के उपयोग एवं दुरुपयोग (160), श्रेष्ठतम कर (161)

8 नियन्त्रिता के प्रभाव 163

(Effects of Quotas)

नियन्त्रिता व्यवस्था के उद्देश्य (163), नियन्त्रिता का नियन्त्रिकरण (164), नियन्त्रिता का भावटन (166), आयात-नियन्त्रिता के रूप (171), नियन्त्रिता के प्रभाव (174), नियन्त्रिता एवं प्रशुल्क (177), नियन्त्रिता व्यवस्था (180)

9 बुँगी-संघ 182

(Customs Unions)

बुँगी संघों का सिद्धान्त (183), कल्याणकारी प्रभावों के मूल्यांकन की समस्याएँ (186)

10 तटकरों एवं व्यापार पर सामान्य समझौता 195

(General Agreement on Tariff and Trade-GATT)

तटकरों एवं व्यापार पर सामान्य समझौता (196), तटकरों एवं व्यापार के सामान्य समझौते के उद्देश्य (198), तटकर सम्बन्धी वार्ताओं के महत्वपूर्ण नियम (202), विकाशशील देशों पर प्रभाव (206), सामान्य समझौते के दोष (207), गैट का भविष्य (208), भारत सरकार की 1977-78 की रिपोर्ट के अनुसार गैट-कार्यकचाप (209)

11 अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था में संरक्षण के कारण और निर्यात में रुकावटें 213

(The Cause for Protection in Less Developed Economies, Trade Barriers to Export of Less Developed Economies)

मुक्त व्यापार : पक्ष में तर्क (213), संरक्षण का सिद्धान्त (216), संरक्षण के तरीके (217), संरक्षण की नीति की आवश्यकता एवं महत्व (221), कुछ सम्भावित हानियाँ (236), अर्द्ध-विकसित-अर्थ व्यवस्था में संरक्षण के कारण (237), अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में निर्यात की व्यापारिक रुकावटें (244)

12. प्राथमिक उत्पादक मूल्यों का स्थिरीकरण एवं विकासशील अर्थव्यवस्था के मध्य क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग की भूमिका
(Stabilisation of Primary Product Prices and Role of Regional Economic Cooperation Between Less Developed Economies)

....

247

स्थिरीकरण के पक्ष में तर्क (247), स्थिरीकरण के विपक्ष में तर्क (248), विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के मध्य क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग की भूमिका (249), विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के मध्य-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के लाभ (250)

13. भुगतान सन्तुलन
(Balance of Payment)

....

251

भुगतान सन्तुलन का अर्थ (252), भुगतान सन्तुलन (254), भुगतान सन्तुलन में प्रमुख मदें (257), भुगतान सन्तुलन और व्यापार सन्तुलन (259), भुगतान सन्तुलन सदैव सन्तुलित रहता है (261), भुगतान सन्तुलन में घाटे और पूर्तियाँ (263), भुगतान सन्तुलन में तुल्यभारिता व अतुल्यभारिता (266), असमतुल्यभारिता के स्रोत (269), भुगतान सन्तुलन के लेखे (273)

14. विनिमय दरें एवं भुगतान सन्तुलनों का समायोजन
(Exchange Rates and the Adjustment Mechanisms under Gold Standard, Fixed Exchange Rates and Flexible Exchange Rates)

....

278

विनिमय दर का अर्थ (279), विनिमय दर का निर्धारण (280), विनिमय दर तथा मॉन एवं पूँति (281), घटती-बढ़ती दर व्यवस्था में दर निर्धारण (283), दर का स्थायित्व (283), निश्चित विनिमय दरें (284), लोचशील विनिमय दरें (284), मॉन और पूँति का सन्तुलन (285), घटती-बढ़ती दरों के लाभ व हानियाँ (287), अग्रिम विनिमय बाजार (287), अग्रिम विनिमय दरों का निर्धारण (288), अग्रिम विनिमय सुविधाओं का लाभ (289), त्रय-शक्ति क्षमता सिद्धान्त (290), विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के कारण (292), अनुवृत्त एवं प्रतिकूल विनिमय दरें (294), भुगतान सन्तुलनों का समायोजन (294)

- 15 अवमूल्यन के प्रभाव, मूल्य प्रभाव एवं आय गुणांक
(Effects of Devaluation, Price Effects and Income Multipliers) 302
- अवमूल्यन के उद्देश्य (302), अवमूल्यन से लाभ (304), अवमूल्यन के प्रभाव (305), मूल्य प्रभाव (311), आय गुणांक (311)
- 16 विनिमय नियन्त्रण
(Exchange Control) 316
- विनिमय नियन्त्रण के उद्देश्य (317), विनिमय नियन्त्रण के तरीके (323), विनिमय नियन्त्रण की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता (329), विनिमय-नियन्त्रण का व्यावहारिक रूप (331), विनिमय नियन्त्रण का संचालन (332), विनिमय नियन्त्रण बनाम प्रणुलक और नियतांश (333), ट्रिफिन योजना (334)
- 17 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका
(Role of the International Monetary Fund—IMF) 337
- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पृष्ठभूमि (337), अनुवृत्त परिस्थितियाँ (338), अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लक्ष्य (343), अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मूल सिद्धान्त (344), कोष की सदस्यता एवं नियतांश प्रणाली (346), मुद्रा कोष का संगठन एवं प्रबन्ध (348), मुद्रा कोष की कार्य प्रणाली (348), सदस्यों के सामान्य दायित्व (350), मुद्रा कोष के कार्यों की प्रगति और उपलब्धियाँ (351), भारत तथा कोष (352)
- 18 अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या
(The Problem of International Liquidity) 353
- तरलता का अर्थ (353), अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या (356), समस्या का हल (359)
- 19 अस्थिरता उत्पन्न करने वाले अल्पकालीन पूँजीगत आवागमन के प्रभाव, दीर्घकालीन निजी पूँजीगत निवेश की प्रवृत्ति एवं समस्याएँ
(Destabilizing Effects of Short-term Capital Movement, Long term Private Investment : Trends and Problems) 366
- अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी के आवागमन का इतिहास (369), अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी की गतिशीलता के कारण (374),

सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रेरणाओं के बीच अन्तर (383), पूँजीगत आवागमन का वर्गीकरण (385), अस्थिरता उत्पन्न करने वाले अल्पकालीन पूँजीगत आवागमन के प्रभाव (390), पूँजी के आवागमन की समस्याएँ (390), पूँजीगत आवागमन के अनुमान के तरीके (391), अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी के आवागमन का मूल्यांकन (393), दीर्घकालीन पूँजीगत निवेश की प्रवृत्ति एवं समस्याएँ (394)

20 विदेशी सहायता एवं विकासशील अर्थ-व्यवस्था में विदेशी धन सेवा का भार

....

397

(Foreign Aid and Debt Service Burden of Less Developed Economies)

विदेशी सहायता की आवश्यकता (399), भारत को विदेशी सहायता से लाभ (400), विदेशी सहायता के खतरे और हानियाँ (401), विदेशी-सहायता के प्रति भारत सरकार की नीति (402), सम्पूर्ण योजना-काल में विदेशी सहायता का आकार व उपयोग (403), विदेशी सहायता की प्राप्ति सकल एवं शुद्ध (405), विदेशी सहायता के उपयोग के कुछ मुख्य क्षेत्र (406), व्याज और मूलधन के भुगतान का बढ़ता हुआ भार (407), बढ़ बनाम घटती सहायता (407), विदेशी सहायता से सम्बन्धित कुछ प्रश्न और समाधान के उपाय (408)

21 अन्तर्राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण एवं विकास-बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ

....

412

(Role of the International Bank for Reconstruction and Development and International Development Association)

विश्व बैंक के उद्देश्य (412), विश्व बैंक का संगठन (413), बैंक की पूँजी की सुरक्षाएँ (416), बैंक की कार्य-प्रणाली (417), बैंक के कार्यों का सैलाबोसा (419), विश्व बैंक और भारत (421), अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ (422), आर्थिक विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का विशेष कोष (423), व्यापार विकास सम्मेलन (423), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (423)

- 12 भारत के विदेश व्यापार के मूल्य, रचना और दिशाओं की
घासुनिक प्रवृत्तियाँ 425
(Trends in the Value, Composition and Direction of
India's Trade in Recent Years)
- विदेशी व्यापार की मात्रा (426), भारत के प्रमुख आयात
और आयात मूल्य (426), भारत के प्रमुख निर्यात एवं
निर्यात मूल्य (432), भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य
प्रवृत्तियाँ (438), भारत के विदेश व्यापार की प्रवृत्तियाँ
सम्पूर्ण स्थिति भारत सरकार की रिपोर्ट 1977-78
(442), भारत सरकार की रिपोर्ट 1977-78 के अनुसार
भारत के विदेश व्यापार की दिशा (445), निर्यात का
महत्व और निर्यात संवर्द्धन के उपाय (448), विदेश
व्यापार-नीति (450), कांग्रेस सरकार की व्यापार नीति
(450), जनता सरकार की नई निर्यात आयात नीति की
विशेषताएँ (454)
- 3 भारत में विनिमय नियन्त्रण तथा 1966 में रुपये का
अवमूल्यन 461
(Exchange Control in India and Devaluation of the Rupee
in 1966)
- विनिमय नियन्त्रण का संगठन (461), विनिमय नियन्त्रण
के लक्ष्य (462), अवमूल्यन (465), 1949 का अवमूल्यन
(468), 1966 में रुपये का अवमूल्यन (473), अवमूल्यन
के लक्ष्य (474), अवमूल्यन के अपेक्षित लाभ (477),
अवमूल्यन की हानियाँ (478), अवमूल्यन का मूल्योत्पन्न
(479), अवमूल्यन का आयात-निर्यात पर प्रभाव (482)
- 24 भारतीय विदेश व्यापार में व्यापार निगम की भूमिका 485
(Role of the STC in India's Foreign Trade)
- उद्देश्य (485), भारतीय विदेशी व्यापार में निगम की
भूमिका (485), भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 1977-
78 के अनुसार राज्य-व्यापार निगम के कार्यकलाप (488)
- 15 भारत का भुगतान सन्तुलन 492
(India's Balance of Payments : Recent Trends and Present
Position)
- युद्ध पूर्व के भुगतान (493), युद्धकालीन भुगतान सन्तुलन
(493), युद्धोत्तर भुगतान सन्तुलन (495), भारत-पाक

मुग़तान सन्तुलन (497), पीण्ड क्षेत्र में गारत का मुग़तान सन्तुलन (498), बठोर मुद्रा क्षेत्रों में मुग़तान सन्तुलन (498), अवमूल्यन और मुग़तान सन्तुलन (499), मुग़तान सन्तुलन पर विभाजन का प्रभाव (499), पंचवर्षीय योजनाएँ और मुग़तान सन्तुलन (506), वार्षिक समीक्षा 1976-77 के अनुसार विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में घटबढ़ और समग्र मुग़तान शेष की प्रवृत्तियाँ (509), वार्षिक समीक्षा 1977-78 के अनुसार विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में घट-बढ़ और समग्र मुग़तान शेष की प्रवृत्तियाँ (512), मुग़तान असन्तुलन की समस्या के निराकरण के उपाय (516)

प्रश्नावली

(University Questions)

5

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता

(THE NEED FOR A SEPARATE THEORY
OF INTERNATIONAL TRADE)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ (The Meaning of International Trade)

साम प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूहों के बीच वस्तुओं के विनिमय को व्यापार कहते हैं। परन्तु यह व्यापार का संकुचित अर्थ है। विस्तृत अर्थ में व्यापार उन सभी आर्थिक क्रियाओं को कहते हैं जिनसे समाज में उत्पादित वस्तुओं के उपभोग के लिए वितरण किया जाता है। संक्षेप में व्यापार के अन्तर्गमन उन सभी मानवीय क्रियाओं का समावेश होता है जो वस्तुओं के उत्पादन से वितरण तक की जाती हैं।

किसी देश के व्यापार को दो भागों में बाँटा जा सकता है—

(अ) आन्तरिक व्यापार—यह व्यापार जो एक ही देश के निम्नलिखित स्थानों या क्षेत्रों के बीच होता है उसे आन्तरिक व्यापार कहते हैं। जैसे भारत में जयपुर का कोई व्यक्ति अथवा फर्म नई दिल्ली के किसी व्यक्ति अथवा फर्म के साथ व्यापार कर तो यह आन्तरिक व्यापार कहना पड़ेगा। आन्तरिक व्यापार को गृह-व्यापार (Home-Trade), राष्ट्रीय व्यापार (National Trade) तथा अन्तर-क्षेत्रीय व्यापार (Inter-Regional-Trade) भी कहते हैं।

(ब) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की इकाईयाँ राष्ट्र होते हैं। जब दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच वस्तुओं या सेवाओं का प्रदान-प्रदान किया जाता है तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार जन्म लेता है। अर्थात् जब एक वस्तु एक देश से दूसरे देश को भेजी जाती है अथवा मँगवाई जाती है तो यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। जैसे कि भारत द्वारा अमेरिका, रूस तथा जर्मनी आदि देशों से मशीनें तथा तकनीकी ज्ञान आदि का मँगवाना एवं अपने यहाँ से इन राष्ट्रों को सूखे मेवे, चाय, कॉफी, कच्चा तेल, हस्तकला की परम्परागत वस्तुओं का भेजना अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में आते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बाह्य-व्यापार (External Trade) अथवा विदेशी-व्यापार (Foreign Trade) भी कहते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के तीन अंग होते हैं—यथा (1) आयात व्यापार, (2) निर्यात व्यापार, एवं (3) पुनर्निर्यात व्यापार। इन तीनों पक्षों अथवा अंगों का वर्णन आगे यथास्थान विभिन्न अध्यायों में किया गया है। यहाँ हमारा मन्तव्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अर्थ को स्पष्ट करना है।

जब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार दो अथवा अधिक राष्ट्रों के मध्य होने वाला व्यापार है तो यह जानना आवश्यक है कि 'राष्ट्र' क्या है? 'राष्ट्र' शब्द राजनीति शास्त्र के विचारियों की रूचि का प्रमुख विषय है, किन्तु आर्थिक दृष्टिकोण से भी इस शब्द का विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है जिसने अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय को सम्भव बनाया है। बेजहाट ने लिखा है कि "आर्थिक अर्थ में एक राष्ट्र उत्पादकों का वह समूह है जिसमें श्रम एवं पूँजी का संचार स्वतन्त्रतापूर्वक हो सकता है।"¹ भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा एवं भौगोलिक अन्तरो द्वारा राष्ट्री के बीच अनेक असमानताएँ पैदा कर दी जाती हैं और इनके परिणामस्वरूप उनके पारस्परिक व्यापारिक सम्बन्ध प्रभावित होते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में 'राष्ट्र' शब्द का प्रयोग प्रायः सभी विचारकों ने नहीं किया है। वेस्टेवेल की भाँति कुछ विचारक राष्ट्र की अपेक्षा समाज शब्द का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त समझते हैं। उनका कहना है कि "सामान्यतः सामाजिक विज्ञानों की दृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न समाजों के बीच का व्यापार है अर्थात् यह उन सामाजिक अंगों के बीच का व्यापार है जिनको समाजशास्त्र अपने अध्ययन-क्षेत्र के अन्तर्गत मानता है।"²

'राष्ट्र' शब्द के विशेष अर्थ के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दो विशेषताएँ सामने आती हैं—(1) प्रत्येक राष्ट्र में श्रम एवं पूँजी का संचार स्वतन्त्रतापूर्वक होता है अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के सभी साधनों में गतिशीलता आसानी से स्थापित हो जाती है।

(2) उत्पादन के साधन एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक गतिशील होने के लिए स्वतन्त्र नहीं होते। राष्ट्रीय कानूनों द्वारा अनेक ऐसे प्रतिबन्ध लगा दिए जाते हैं जो दूसरे राष्ट्री के उत्पादन के साधनों को आने में रोक देते हैं तथा स्वयं के साधनों को वहीं जाने से प्रतिबन्धित कर देते हैं। संस्थापक अर्थ-शास्त्रियों (Classical Economists) के मतानुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की यह विशेषता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मि. क्लीमेंट (M. O. Clement) तथा अन्य के कथनानुसार व्यापार उन

1 "A Nation in the economic sense—that is a group of producers, within which labour and capital freely circulate" —Bagehot

2 "From the point of view of social science in general, we may further say that international trade is trade between 'societies' i. e. between the different social organisms which sociology assumes as its field of investigation" —Bastable, C. F. The Theory of International Trade, p 5

दुनिया में होने हैं जहाँ माल की गति तथा उत्पादन के तत्त्व की गतिशीलता अपूर्ण होती हैं।¹

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का जन्म (The Origin of International Trade)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रचलन अनेक कारणों से लोचप्रिय बना है। अनेक स्थिति ने इसका जन्म एवं विकास पर प्रभाव डाला है। इसकी परम्पराओं के जन्म का मूल कारण अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन है। इस सम्बन्ध में मि. हैरॉड लिखते हैं— साधारणतः विनिमय को श्रम-विभाजन के द्वारा आवश्यक बनाया जाता है। जब यह श्रम विभाजन राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर लेता है तो विदेश व्यापार का जन्म होता है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का आवश्यक परिणाम है।² प्रत्येक देश स्वावलम्बी बनने के लिए एक विशाल अनुपात में श्रमिकों को प्रमुख वस्तुओं के उत्पादन में तथा शेष श्रमिकों को अन्य वस्तुओं के उत्पादन में लगाना है। जिस प्रकार दो व्यक्तियों की योग्यताएँ एवं क्षमताएँ एक-दूसरी नहीं होतीं उसी प्रकार दो देशों की योग्यताओं एवं क्षमताओं के बीच भी असमानता पाई जाती है। जो देश श्रम वस्तु के उत्पादन में अधिक क्षमता एवं कुशलता रखता है उसे वही वस्तु उत्पादित करनी चाहिए। इससे वह स्वयं भी सामान्वित होगा और दूसरे देश भी स्वयं उत्पादन करने की प्रेरणा उस वस्तु का आयात करने से लाभ में रहेगा। प्रत्येक देश की सुविधाएँ भिन्न होती हैं। अतः उनके बीच स्वभावतः ही श्रम-विभाजन हो जाता है।

श्रम विभाजन को आवश्यक एवं उपयोगी बनाने वाली अनेक परिस्थितियाँ हैं—(i) देशों के प्राकृतिक साधनों का अन्तर—कुछ देश खनिज पदार्थों की दृष्टि से सम्पन्न होते हैं जबकि दूसरे देशों में इनका अभाव होता है। कुछ देशों का जलवायु कुछ चीजों के उत्पादन के लिए बहुत अच्छा होता है और इसलिए वहाँ ऐसी चीजों को बहूलायत में उत्पन्न करके उनका निर्यात किया जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक साधन अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन को जरूरी बना देने हैं।

(ii) विभिन्न देशों की जनसंख्या असमान होती है—अधिक जनसंख्या वाले देश इतना अधिक उत्पादन नहीं कर पाते कि उनकी जनता के लिए वह पर्याप्त हो सके। दूसरी ओर कम जनसंख्या वाले देशों में सामग्रियों का उत्पादन वहाँ की जनता की माँग से अधिक किया जाता है। यह स्थिति आयात और निर्यात को जरूरी बना देती है।

1 "Trade occurs in a world where the movement of goods and the mobility of productive factors are more or less imperfect" —M. O. Clement, Richard L. Pfister and Kenneth J. Rothwell : Theoretical Issues in International Economics, Constable, London, 1967, p. 3

2 "An exchange in general is necessitated by the division of labour, so foreign trade appears when the division of labour is pushed beyond national frontiers. It is the necessary consequence of an international division of labour" —Harrod : International Economics, p. 9

(iii) प्राकृतिक साधनों की भाँति मानवीय गुणों के आधार पर भी राष्ट्रों के बीच अन्तर रहता है—कुछ देश शारीरिक श्रम की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं जबकि दूसरे दस्तकारी की दृष्टि से कुशल होते हैं। देश का राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण और दीर्घकालीन जाति व्यवस्थाएँ इस प्रकार, के अन्तरों का कारण होती हैं। शारीरिक श्रम की आवश्यकता वाले उद्यमों को उन देशों में प्रपनाया जाएगा जहाँ स्वस्थ और शक्तिशाली जनता निवास करती है। दूसरी ओर जिन कार्यों में बुद्धि, साहस एवं योग्यता की आवश्यकता है उन्हें प्रगतिशील, शिक्षित एवं वैज्ञानिक ज्ञान सम्पन्न समाज में प्रपनाया जाएगा।

(iv) विभिन्न देशों की पूँजी का प्रकार अलग-अलग होता है—कही चल पूँजी अधिक होती है तो कही अचल पूँजी अधिक होती है। इस प्रकार के अन्तर के आधार पर देशों के बीच विशिष्टीकरण किया जाता है।

(v) विभिन्न देशों के राजनीतिक तथा सामाजिक वातावरण के भिन्न होने के कारण भी उनके बीच विभिन्नताएँ स्थापित हो जाती हैं। ये श्रम-विभाजन को जरूरी बना देती हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता (Necessity of International Trade)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आज के युग की आवश्यकता बन चुका है। यद्यपि इसका महत्व सभी देशों के लिए एक जैसा नहीं है फिर भी कोई देश इसकी प्रवहेलना नहीं कर पाता। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कई कारणों से जरूरी बन जाता है, इसमें भाग लेने वाले प्रायः सभी पक्ष लाभान्वित होते हैं तथा इससे किसी का कोई अनिष्ट नहीं होता। इसमें आयात करने वाला देश भी उतना ही लाभान्वित होता है जितना निर्यात करने वाला देश होता है। जब विभिन्न देशों के बीच मूल्य-अनुपात भिन्न-भिन्न होता है तो सस्ती चीजों को एक देश खरीद लेता है और महंगी चीजों को बेच देता है। माँग की लोच के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ की मात्रा निर्धारित होती है। इसी के अनुसार व्यापार की शर्त तय की जाती है। माँग जितनी अधिक लोचदार होती है, उतना ही अधिक लाभ होता है और जितनी कम लोचदार होती है उतना ही कम लाभ होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता आधुनिक युग में जिन कारणों से है उन कारणों को दो भागों में बाँटा जा सकता है—

(क) आर्थिक कारण

(ख) गैर-आर्थिक कारण

(क) आर्थिक कारण

(i) श्रम-विभाजन—जो देश जिस चीज के उत्पादन का विशेषज्ञ होता है वह उसे स्वयं बनाता है और उसे दूसरे देशों को निर्यात करता है अन्य वस्तुओं का वह उन देशों से आयात करता है जो उन चीजों के उत्पादन के विशेषज्ञ हैं। मि. वेस्टेडेल के मतानुसार अनेक वस्तुएँ ऐसी हैं जिनको एक देश पर्याप्त कम कीमत पर

उत्पादित नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में य चीजें अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय द्वारा अत्यन्त मरलता से प्राप्त की जा सकती हैं।

(ii) प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपयोग सम्भव हो जाता है। प्रायः प्रत्येक देश में कुछ विशेष प्राकृतिक साधन उपलब्ध होते हैं जिसके उत्पादन में वह देश विशिष्टता प्राप्त कर लेता है और उसमें उसे तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रत्येक देश अपने प्राकृतिक साधनों पर आधारित उद्योगों को अपने यहाँ विकसित करता है जिससे उसके प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपयोग सम्भव हो जाता है। बेस्टेबेल के मतानुसार देश की उत्पादन शक्तियाँ देश के प्राकृतिक-साधनों का स्वतन्त्र उपयोग करती हैं। जिसमें अधिकतम लाभ की सम्भावना रहनी है और इस कारण उत्पादन इकाई की माय्यता बढ़ जाती है।

(iii) औद्योगीकरण को बढ़ावा—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार औद्योगीकरण को भी बढ़ावा देता है। औद्योगीकरण के लिए जब किसी देश के पास किमी वस्तु जैसे कच्चा माल, मशीनें आदि का अभाव होता है तो उसे विदेशों से आयात करके पूरा किया जा सकता है। भारत विदेशों और तकनीकी ज्ञान का आयात करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा देता है। ज्ञान और इंग्लैंड कच्चे माल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं।

(iv) आर्थिक संकट काल में सहायता—आर्थिक संकट के कष्टों को भी विदेशी-व्यापार की सहायता से कम किया जा सकता है। यदि किमी देश में अकाल या स्वाध्याय की कमी हो जाए तो उस कमी को बाहर से अन्न भेगाकर दूर किया जा सकता है। उदाहरणार्थ हमारे देश में गत कुछ वर्ष पूर्व अन्न की कमी को अमेरिका से PL-480 के अन्तर्गत गेहूँ का आयात करके पूरी की गई।

(v) रोजगार एवं आय में वृद्धि—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की अवस्था में देश का निर्यात-व्यापार बढ़ता है। फलतः निर्माण उद्योगों में लगे श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि होती है और इसके फलस्वरूप अन्य उद्योग एवं व्यवसायों में कार्यरत श्रमिकों की आय में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार सम्पूर्ण देश की आय का स्तर ऊँचा होता और विकास की प्रक्रिया मचयी हो जाती है।

(vi) बाजार का विस्तृत क्षेत्र—अन्तर्राष्ट्रीय-व्यापार के कारण वस्तुओं एवं सेवाओं की बाजार की सीमा बहुत ही विस्तृत हो जाती है। व्यापार का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण देश को अपने प्राकृतिक साधनों के पूर्ण उपयोग का अवसर मिल जाता है। बड़े बाजार से अधिक प्रत्याशों के प्राप्त होने से विनियोगों को बढ़ाने वाले बलों को शक्ति मिलती है।

(vii) एकाधिकारों पर रोक—विदेशी-व्यापार के कारण देश के व्यापारी आपस में मगठन करके एकाधिकार की स्थापना नहीं कर सकते हैं और न एकाधिकार मूल्य ही ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें सदैव विदेशी-प्रतियोगिता का खतरा बना रहना है।

(viii) बड़े पैमाने पर उत्पादन—विदेशी-व्यापार के कारण जब बाजार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है तो देश को अपने प्राकृतिक-साधनों का पूर्णतम उपयोग करने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। इस कारण उत्पादन की मात्रा अधिकतम बिन्दु तक पहुँच जाती है जिससे आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलता है। प्रो० हिक्स के मतानुसार “विदेशी व्यापार करने के लिए किसी देश को बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से लाभ होने लगता है।”

(ix) उत्पादन विधि में सुधार की बढ़ावा—अन्तर्राष्ट्रीय-व्यापार की अवस्था में विदेशी-प्रतियोगिता के भय के कारण देश के उत्पादक अपनी उत्पादन-विधियों में सुधार करने के लिए सदैव सचेष्ट एवं कार्यशील रहते हैं। क्योंकि तभी वे अपनी वस्तुओं का उत्पादन अधिक अच्छा और कम लागत पर करने एवं बाजारों को बनाए रखने में सफल हो जाते हैं। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय-व्यापार के कारण उत्पादन में निरन्तर सुधार होता रहता है। जिससे सम्बन्धित देश को उत्पादन के क्षेत्र में बड़ा लाभ होता है।

(x) कच्चे माल की उपलब्धता—विदेशी-व्यापार के माध्यम से आवश्यक कच्चे माल, मशीनरी तथा कृत्रिम योग्यता विदेशों से मँगवाकर देश के औद्योगीकरण को आगे बढ़ाया जा सकता है।

(xi) उपभोक्ताओं की वस्तुओं की सस्ती कीमत पर मिलना—विदेशी व्यापार के द्वारा उपभोक्ता को न केवल वे वस्तुएँ प्राप्त होती हैं, जो स्वयं उसके देश में नहीं होती, बल्कि वह वस्तुएँ उन देशों से खरीद सकता है जहाँ उनकी कीमतें न्यूनतम होती हैं। इससे मानव-समाज के रहन-सहन के स्तर में वृद्धि हो जाती है।

(xii) मूल्यों में समता—विदेशी-व्यापार द्वारा मूल्यों में समता स्थापित होती है। यदि एक स्थान पर वस्तु का मूल्य कम है और दूसरे स्थान पर अधिक है तो कम मूल्य वाले स्थान से वस्तु अधिक मूल्य वाले स्थान पर मँगवाई जाएगी। परिणामस्वरूप इस स्थान पर पूर्ण में वृद्धि हो जाने पर मूल्य में कमी घट जाएगी। इस प्रकार व्यापार में सुविधाओं के कारण मूल्य में समानता आने की प्रवृत्ति रहती है।

(ख) गैर-आर्थिक कारण—

(i) शिक्षाप्रद महत्त्व—जिन देशों के लोग निश्चय, अकर्मण्य, असह्य, पूर्ण सन्तुष्ट या अविकसित होते हैं और वे अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाते होते हैं ऐसे देशों में विदेशी व्यापार शुरू होने से नए लक्ष्यों से उनका परिचय बढ़ता है तथा उन वस्तुओं को घासानी से प्राप्त करने की लालसा पैदा हो जाती है जिन्हें वे पहले अप्राप्य समझते थे, और यह सब शिक्षा का आयात करने से होता है। परिणामस्वरूप उस राष्ट्र में नई शक्ति का संचार होता है तथा लोगों में प्रतियोगिता की भावना बढ़ जाती है जिससे कि वे भी समृद्ध राष्ट्र के लोगों के समान अपना जीवनयापन कर सकें।

(ii) सांस्कृतिक महत्त्व—विदेशी-व्यापार से विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित होते हैं जिससे व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल एक देश से दूसरे देश

का प्राप्ति जाने रहते हैं। इस प्रकार भिन्न-भिन्न सभ्यता के लोग एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं। इससे एक देश के निवासियों के रीति-रिवाज राजनैतिक आचार विचार के सम्बन्ध में ज्ञान बढ़ता है। वे एक दूसरे को समझने लगते हैं, आपस में सामंजस्य स्थापित होता है। विश्व एकता का बड़ावा मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि 'अन्तर्राष्ट्रीय-व्यापार-सम्बन्ध का सबसे बड़ा प्रचारक है।'

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और एकता की स्थापना—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा विभिन्न राष्ट्र पारस्परिक सम्पर्क में आते हैं एक दूसरे को समझने लगते हैं तथा परस्पर अच्छे सम्बन्ध बनाते हैं जिसके कारण आपसी सहायता की भावना सभी देशों के अन्दर जाग्रत हो जाती है और राजनैतिक-शान्ति में वृद्धि होती है। जब अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति होती है तो मानव-जाति के विचार सम्पूर्ण और सभ्यता का पूर्ण विकास हो पाता है। आज विश्व में ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहाँ राजनैतिक-सम्बन्ध न होने पर भी आर्थिक-सम्बन्ध स्थापित हुए हैं और बाद में आर्थिक-सम्बन्धों के कलस्वरूप राजनैतिक सम्बन्ध भी स्थापित हो गए हैं। जैसे कि भारत एवं चीन के मध्य राजनैतिक सम्बन्ध न होने पर भी भारत ने चीन को मालगाड़ी के डिब्बों का निर्यात कर आर्थिक सम्बन्ध स्थापित किए। इस आर्थिक सम्बन्ध के बाद दोनों देशों में राजनैतिक-सम्बन्ध व सहयोग में वृद्धि हुई।

इस प्रकार अनेक कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार लाभदायक एवं आवश्यक बन जाता है। यह देश के मानव स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग करने का प्रयत्न देता है। इसमें एक देश के लाभ बचाने में सक्षम हैं—उन्हें पूँजी की रचना में सहायता मिलती है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल ने बताया है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से दोहरा लाभ होता है—इससे देश में उपयुक्त साधनों का अधिकतम उपयोग लिया जा सकता है तथा विदेशों से वस्तुएँ मँगाकर देशवासियों की आवश्यकताएँ पूरी की जा सकती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अनेक कारणों से एक ऐसा आकर्षण पैदा हो जाता है जो प्रायः राष्ट्रीय व्यापार में नहीं हो पाता। व्यापार करने वालों की नए-नए स्थानों पर घूमना होता है, अनेक चीजें देखनी होती हैं, नए लोगों के साथ व्यवहार करना होता है। विचारकों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को सभ्यता का सबसे बड़ा प्रचारक माना है।

अन्तर्राष्ट्रीय-व्यापार का महत्त्व या उसके लाभ

(Importance or the Advantages of International Trade)

जिन कारणों एवं परिस्थितियों ने राष्ट्रों के व्यापार को प्रोत्साहन दिया है वे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार बने हैं। प्राकृतिक साधनों का असमान वितरण, धन की माया में अन्तर, जलवायु की अनुकूलता एवं प्रतिफलता की स्थिति आदि के प्रभाव से एक राष्ट्र किसी वस्तु विशेष का उत्पादन तो अधिक कुशलता एवं कम खर्च में कर सकता है, परन्तु दूसरा देश ऐसा करने की क्षमता नहीं रखता है। विभिन्न राष्ट्रों के तकनीकी विकास एवं वैज्ञानिक आविष्कारों के स्तर का अन्तर वहाँ किसी वस्तु का उत्पादन को अन्य की अपेक्षा अधिक कर देता है। निम्न

वस्तुओं के उत्पादन में एक राष्ट्र दक्ष होता है वे वस्तुएँ आवश्यकता से अधिक उत्पादित की जाती हैं जबकि अन्य चीजों का उत्पादन पर्याप्त नहीं हो पाता है।

अतः आवश्यक है कि वह देश अतिरिक्त उत्पादित वस्तुओं का दूसरे देशों को निर्यात करे और जो वस्तुएँ वह पर्याप्त मात्रा में पैदा नहीं कर पाता है उनका दूसरे देशों से आयात करे जहाँ पर इनका उत्पादन क्षमता एवं कम मूल्य के साथ होता है। इस दृष्टि से आज की दुनिया का प्रत्येक राष्ट्र परावर्तम्बी है। दूसरे के सैन्य सहयोग एवं समर्थन के बिना वह अपना जीवन व्यवस्थित रूप में संचालित नहीं कर सकता है। इस स्थिति ने सारे संसार को एक इकाई बना दिया है। परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आज जनजीवन के लिए परम महत्वपूर्ण है।

(क) यह देश के कृषि, उद्योग, धर्म एवं समाज की दृष्टि से पर्याप्त महत्व रखता है, यह न केवल एक देश के जीवन स्तर को ऊँचा बनाए रखने के लिए जरूरी है, वरन् इसके बिना कुछ देश तो अपनी जनसंख्या का पर्याप्त मात्रा में पोषण भी नहीं कर पाते। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अभाव में कुछ देश कच्चे माल को लेकर बैठे रहेंगे जबकि दूसरे देश खाली मशीनों का दर्शन करते रहेंगे। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार जैसा कि वाल्टर क्रोज का कहना है—“अधिक लोगों को जीवित रहने की सुविधा देता है। उन्हें विभिन्न रसों का आनन्द लेने और अपने जीवन स्तर को ऊँचा बनाए रखने की सुविधाएँ देता है।”¹

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एक देश की कृषि की स्थिति को बढ़ाने में सहयोग करता है, क्योंकि आवश्यक पदार्थों एवं लाख लाख वस्तुओं की माँगों से उपलब्ध किया जा सकता है। कृषि उत्पादन अत्यधिक होने पर उसे कमी वाले प्रदेशों में भेज दिया जाता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो कृषि उत्पादन कम करना होगा और देश की अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न उद्योगों पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव डालता है। एक देश के उद्योग-धन्धे सभी चल सकते हैं जब उनके लिए उपयुक्त कच्चा माल प्राप्त किया जा सके। कच्चे माल के अभाव में उद्योग धन्धों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार धर्मिकी के लिए पर्याप्त महत्व रखता है, इससे उनकी आय अधिक हो जाती है। अनेक देशों के मजदूरों की आय का प्रमुख स्रोत विदेशी व्यापार होता है। धर्मिकी को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूप में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। आयात और निर्यात का काम सम्भालने के लिए अनेक मजदूरों को रोजगार मिलता है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि आयात के कारण देश में रोजगार की संभावनाएँ कम हो जाएँगी, किन्तु यह सोचना सही नहीं है क्योंकि आयात के द्वारा निर्यात का सृजन भी किया जाता है। यदि

1 “International Trade permits more people to live, to gratify more varied tastes and to enjoy a higher standard of living than would be possible in its absence.”
—Walter Krause : The International Economics, p. 3.

कोई देश केवल आयात करे और निर्यात न करे तो कुछ समय में ही उसकी अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाएगी।

(च) आयात और निर्यात के द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ होना है इससे उपभोक्ता लाभान्वित होने हैं क्योंकि उनकी आवश्यकता को अनेक चीजें विदेशों से आयात की जाती हैं। इसके अनिश्चित यह उत्पादकों के लिए लाभदायक है क्योंकि अनेक धन्य, रसायन पदार्थ, विभिन्न प्रकार की धातुएँ एवं अन्य अनेक वस्तुएँ आयातित की जाती हैं जिनसे उत्पादकों को उत्पादन करने में सरलता होती है।

(छ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखकर ही समय-समय पर विभिन्न देशों की सरकारें अपनी आयात और निर्यात की नीति में परिवर्तन करती रहती हैं।

(ज) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तकनीकी विकास को सम्भव बनाता है, इसके कारण जो प्रतियोगिता जन्म लेती है उसमें देश में उत्पादित वस्तुओं के गुण एवं मात्रा में वृद्धि हो जाती है। देशी व्यापारी अपनी वस्तु को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। आयात और निर्यात देश को विभिन्न साधनों से सम्पन्न बनाते हैं और प्रकार उसकी सुरक्षा का सहारा देते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों के आर्थिक विकास को सम्भव बनाना है और जो देश अपने विकास के लिए आवश्यक उपकरणों का स्वयं नहीं बना सकने के उनका आयात करते हैं। पारम्परिक निर्भरता बढ़ जाने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन मिलता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन का महत्व आज के राष्ट्रवादी एवं अन्तर्राष्ट्रवादी युग में अत्यन्त बढ़ गया है। प्रो. किडलेबर्गर के शब्दों में "बढ़ते हुए राष्ट्रवाद की दुनिया में, अथवा बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीयतावाद या दोनों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र ज्ञान और समझौतों का एक महत्वपूर्ण साधन है।"¹

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियाँ (Demerits of International Trade)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक एवं उपयोगी होने हुए भी अनेक प्रकार से नुकसानदायक बन जाता है। इसके ये विभिन्न दोष, इतने स्वाभाविक एवं अपरिहार्य नहीं हैं। कुछ सावधानी बरतने के बाद इन पर रोक लगाई जा सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्भावित दोष अग्रनिमित्त हैं—

(1) इसमें प्राकृतिक सम्पदा का दुरुपयोग किया जाता है। जब एक देश केवल अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उत्पादन करता है तो उसके सीमित साधन धीरे-धीरे समाप्ति की दिशा में अग्रसर हो जाते हैं।

1 "In a world of rising Nationalism, rising Internationalism or both, International Economics is an important tool of understanding and negotiation"
—Charles P. Kindleberger : International Economics, 1963, p 12

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण, कोयला, पेट्रोल, मैंगनीज आदि विभिन्न पदार्थों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। इससे इनके भीख समाप्त होने का अन्देशा बढ़ जाता है। सनित्र पदार्थ एक बार काम में आने के बाद समाप्त हो जाते हैं। यदि इनका प्रयोग राष्ट्रीय आवश्यकताओं की दृष्टि से ही किया जाए तो ये इतनी जल्दी समाप्त न हों।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व्यापारियों को यह ज्ञान देता है कि वे लाभ कमाने के लिए वस्तुओं का निर्यात अधिक करें। इसके परिणामस्वरूप देश में वस्तुओं की कमी आ जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। इस प्रकार देशवासी उन वस्तुओं के उपयोग से वंचित रह जाते हैं। फलतः उनका जीवन स्तर गिरना प्रारम्भ हो जाता है।

(3) विदेशी प्रतिस्पर्धिता देश के उद्योग धंधों को नुकसान पहुँचाती है, इसके कारण नए उद्योग नहीं बन पाते और पुराने उद्योग भी पूर्ण रूप पाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। विदेशी व्यापार आर्थिक दृष्टि से उन्नत देशों के लिए लाभदायक हो सकता है किन्तु यह विकासशील देशों के लिए हानिकारक होगा है। इन देशों के उद्योग धंधे अपने सीमित साधनों के होने के कारण प्रतिस्पर्धिता में टिक नहीं पाते। भारत में कुटीर उद्योग धंधों का पतन विदेशी प्रतिस्पर्धिता का ही एक परिणाम माना जाता है।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विशिष्टीकरण की जन्म देता है। इसके अनुसार एक देश के द्वारा कुछ विशेष चीजें बनायी जाती हैं किन्तु दूसरी चीजों के लिए उसे अन्य देशों पर निर्भर रहना होता है। इस प्रकार का व्यापारिक केन्द्रीयकरण आर्थिक स्वायत्त की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता। यदि इन प्रमुख उद्योग धंधों में कोई सनट आ जाए तो सारे देश की अर्थ-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाती है, इसके परिणाम भी भयंकर हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक देश के आर्थिक संकट का अन्य देशों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है।

(5) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कई बार हानिकारक वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देता है, और इसके परिणामस्वरूप सम्बन्धित देश पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आयातकर्ता देश इन चीजों को प्रयोग करने की गलत आदत से दूषित हो जाता है। उदाहरण के लिए जब भारत से एक बड़ी मात्रा में चीन की अफीम भेजी जाती थी तो वहाँ के लोग उसका प्रयोग करके बहुत बालसो बन गए।

(6) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से दसिपातन (Dumping) की आशंकाएँ बढ़ जाती हैं। एक देश अपनी वस्तुओं को जितनी कम कीमत पर बेचता है वह उस देश के लागत मूल्य से भी कम होती है, उसके परिणामस्वरूप वहाँ के छोटे और बड़े उद्योग धंधे नष्ट हो जाते हैं। जब वह देश अपने प्रयास में सफल हो जाता है तो उन चीजों की कीमत पुनः बढ़ा देता है। इस प्रकार वह अनुचित रूप से अत्यधिक लाभ कमाना चाहता है। इस सम्पादना से बचने के लिए यह जरूरी है कि विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाए।

स्वतन्त्र व्यापार के सिद्धान्त, पूर्ण लागतों के अन्तर और सुलनान्मक लागतों के अन्तर का व्यापार, स्थिर, घटती हुई और बढ़ती हुई इकाई लागतों की दशा में व्यापार

(THE THEORY OF FREE TRADE, TRADE UNDER COST DIFFERENCES AND COMPARATIVE DIFFERENCES TRADE WITH CONSTANT DIMINISHING & INCREASING UNIT COSTS)

स्वतन्त्र व्यापार का सिद्धान्त (The Theory of Free Trade)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में विभिन्न सिद्धान्त प्रचलित हैं जिनके द्वारा इस बात का स्पष्टीकरण दिया जाता है कि आयात और निर्यात का हान है तथा व कौन सी दशाएँ हैं जिनके कारण एक देश कुछ वस्तुओं का निर्यात करता है और अन्य वस्तुओं का आयात करता है। ये सिद्धान्त मुख्य रूप में चार प्रकार के हैं। हैबरलर (Habersler) का कहना है कि चारों सिद्धान्त यद्यपि विभिन्न लेखकों द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं और इनका कभी भी एक सत्रादक रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है किन्तु फिर भी ये एक दूसरे के बहुत कुछ पूरक हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के ये चार सिद्धान्त हैं—

- (1) तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त (Comparative Cost Theory)
- (2) पारस्परिक पूर्ति एवं माँग का सिद्धान्त (Reciprocal Supply and Demand Theory)
- (3) आर्थिक साम्य का सिद्धान्त (Economic Equilibrium Theory)
- (4) आंशिक साम्य का सिद्धान्त (Partial Equilibrium Theory)

1. पहला सिद्धान्त तुलनात्मक लागत का है। लेखकों का कहना है कि इस सिद्धान्त का जन्मदाता सम्भवतः रॉबर्ट टोरन्स था। इसे आधुनिक रूप में परिभाषित करने का श्रेय डविड रिकार्डों को दिया जाता है। अपने आन्तरिक मूल्यों के अन्तर्गत सिद्धान्त में इन्होंने इस सिद्धान्त की व्याख्या की। बाद में ज. एस. मिचलसन

सिद्धान्त में कुछ अन्य बातों को जोड़ दिया। केयरनेस और मि. बेस्टवेल को इस सिद्धान्त का प्रमुख निरूपणकर्त्ता माना जाता है। प्रो. टॉसिंग (Taussing) का नाम इस सिद्धान्त के व्याख्याकारों में लिया जाता है।

अठारहवीं शताब्दी में स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में जो तर्क दिए जाते थे, उनका आधार मूल्यों की असमानता थी। यह विश्वास किया जाता था कि प्रत्येक देश को अपनी घरेलू चीजों के बदले उन वस्तुओं का आयात करना चाहिए जिनको या तो वह स्वयं पैदा नहीं कर सकता अथवा यदि करता है तो निश्चय ही उन मूल्यों पर जो विदेशों में उसके उत्पादन पर लगता है। स्वतन्त्र व्यापार के अधीन इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक वस्तु उन देश में पैदा की जाएगी जहाँ उसकी लागत का खर्चा सबसे कम आएगा। एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित स्वतन्त्र व्यापार का सिद्धान्त हमसे आगे नहीं बढ़ता। यद्यपि तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त एडम स्मिथ के पहले विचारकों द्वारा भी प्रतिपादित किया गया था किन्तु उसमें स्पष्टता का अभाव था।

सन् 1817 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में मि. रिकार्डों ने इस सिद्धान्त को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया। रिकार्डों का कहना था कि इस्लैण्ड को कपड़े या अन्य निमित्त वस्तुओं को तैयार करने और उनका निर्यात करने में अधिक लाभ होगा अपेक्षाकृत कृषि वस्तुओं को उगाने और निर्यात करने के। विदेशों को कपड़ा भेजकर इस्लैण्ड जितना अनाज मंगा सकता था उतना वह स्वयं पैदा नहीं कर सकता था। मि. ई. लैसर (Mr E. Lessar) और ई. आर. ए. सेलिगमैन (E. R. A. Seligman) ने इस सिद्धान्त को प्रतिपादित करने का श्रेय टोरेन्स (Torrens) को दिया है। किन्तु हॉलैंड (Holland) इस विचार से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि टोरेन्स ने सिद्धान्त के पूरे महत्त्व को कभी नहीं पहचाना और न ही उन्होंने कभी इसको व्यवहृत किया। उन्होंने मि. रिकार्डों को इसका श्रेय दिया है क्योंकि बाद के अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धान्त का परिचय रिकार्डों से ही प्राप्त किया। हमके अतिरिक्त रिकार्डों के विचार पर्याप्त स्पष्ट भी हैं।

2. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का दूसरा सिद्धान्त 'पारस्परिक पूर्ति एवं माँग का सिद्धान्त' (Reciprocal Supply and Demand Theory) कहा जाता है। इसका प्रतिपादन प्रो. मार्शल द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की कुछ समस्याओं को हल करने के लिए किया गया। इसका अध्ययन करने के लिए मार्शल ने प्रस्ताव-वक्रों का प्रयोग किया। यह सिद्धान्त असल में तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त है। इसका आधार रिकार्डों की रचनाएँ और मिल के अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त हैं।

3. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का तीसरा सिद्धान्त आर्थिक साम्य (Economic Equilibrium) का सिद्धान्त है जिसका प्रतिपादन मि. पैरेटो ने किया है। इस सिद्धान्त के अनुसार किसी भी वस्तु के मूल्य का निर्धारण उसकी माँग और पूर्ति के संतुलन द्वारा किया जाता है। किसी वस्तु की माँग उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं, इच्छाओं तथा उनकी आय आदि पर निर्भर करती है। दूसरी ओर वस्तुओं की पूर्ति उसके उत्पादन की सम्भावना और उत्पात्ति की भौतिक एवं तकनीकी

दशाओं पर निर्भर करती है। जहाँ माँग और पूर्ति का साम्य स्थापित हो जाए वही उस वस्तु की कीमत निर्धारित हो जाती है। यह कीमत वस्तु की उत्पादन लागत के बराबर होती है जिसमें लाभ भी सम्मिलित है। एक वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त किए गए साधनों की कीमत उसकी उत्पादन लागत में शामिल की जाती है।

4 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का चौथा सिद्धान्त आंशिक साम्य (Partial Equilibrium) कहलाता है। इसका उल्लेख हमको रिचार्ड श्लर (Richard Schiller) तथा एनरिको बैरोन (Enrico Barone) के लेखों में मिलता है। ये दोनों लेखक एक ही विषय सामग्री पर भिन्न-भिन्न तकनीकों को अपनाकर विचार करते हैं। बैरोन ने बक्र रेखाओं का प्रयोग किया जबकि श्लर ने अक-गणितीय माध्यम से समझाया है। इस सिद्धान्त के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का पूरा चित्र प्रस्तुत किया जा सकता है वरन् केवल एक भाग को ही हमारे सामने रखा जा सकता है।

लागत विभिन्नताओं का सिद्धान्त (Doctrine of Cost Differences)

विभिन्न देशों में एक ही वस्तु के उत्पादन की लागत अलग-अलग होती है। लागत की भिन्नता तीन प्रकार की हो सकती है—

- (1) लागतों का पूर्ण अन्तर (Absolute Cost Differences)
- (2) समान लागत (Similar Cost Differences)
- (3) तुलनात्मक लागत अन्तर (Comparative Cost Differences)

अब जब भी विभिन्न देशों में किसी वस्तु का व्यापार होगा उस समय उस वस्तु के उत्पादन में आई लागत का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। यह प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार लागतों के सिद्धान्त के अनुसार तीन प्रकार का होगा—

- 1 पूर्ण लागतों के अन्तर का व्यापार
- 2 समान लागत के अन्तर का व्यापार
- 3 तुलनात्मक लागत के अन्तर का व्यापार

1 पूर्ण लागतों के अन्तर का व्यापार (Trade under Absolute Cost Differences)

लागतों का पूर्ण अन्तर यह मानकर चलता है कि श्रम एवं देश के अन्तर्गत पूर्ण रूप से गतिशील किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्णतः गतिहीन है। देश में गतिशील होने के कारण श्रम विनिरूप उत्पादन की विभिन्न शाखाओं में इस प्रकार हो जाता है कि प्रत्येक जगह उसकी सीमान्त उत्पादकता एक जैसी हो जाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम एक उद्योग से दूसरे उद्योग में नहीं जा सकता और इसीलिए श्रम की लागत द्वारा पूर्ति को नियन्त्रित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दो देशों के बीच वस्तुओं का विनिमय केवल तभी हो सकता है जब दोनों ही देश किसी एक चीज को निरपेक्ष (Absolute) रूप से कम लागत पर उत्पन्न करें।

लागत के इस पूर्ण अन्तर को हम एक उदाहरण द्वारा समझा सकते हैं। माना कि रूस में जूते की एक इकाई की उत्पादन लागत 5 श्रम इकाइयाँ हैं और स्वेड की एक इकाई की उत्पादन लागत 10 श्रम इकाइयाँ हैं। भारत में जूते की एक इकाई की उत्पादन लागत 10 श्रम इकाइयाँ हैं और स्वेड की एक इकाई की उत्पादन लागत 5 श्रम इकाइयाँ हैं तो इस स्थिति में रूस स्वेड की एक इकाई के बदले में जूते की 2 इकाई का विनिमय करेगा और भारत स्वेड की एक इकाई के बदले में जूते की दो इकाइयों का विनिमय करेगा। इस प्रकार रूस में इन दोनों चीजों का लागत अनुपात 1:2 है जबकि भारत में 1:1 है। अतः रूस को जूतों के उत्पादन में लाभ रहेगा जबकि भारत को स्वेड के उत्पादन में पूर्ण लाभ होगा। ये दोनों देश अपनी-अपनी लाभ की वस्तुओं में विशिष्टीकरण प्राप्त करेंगे। यह स्थिति लागतों का पूर्ण अन्तर कहलाती है। रूस द्वारा भारत को जूतों का निर्यात दिया जाएगा और भारत द्वारा रूस को स्वेड भेजे जाएंगे।

यदि सम्पूर्ण उत्पादन को धीरे ध्यान दिया जाए तब भी दोनों देशों के लिए एक ही वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करना लाभदायक होगा माना रूस तथा भारत दोनों ही अलग-अलग उत्पादन करते हैं तो ऐसी स्थिति में—

रूस 1 इकाई जूता + 1 इकाई स्वेड = 15 श्रमिक

भारत 1 इकाई जूता + 1 इकाई स्वेड = 15 श्रमिक

अर्थात् 2 इकाई जूता + 2 इकाई स्वेड = 30 श्रमिक

अब माना कि रूस ने जूते के उत्पादन में और भारत ने स्वेड के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर ली है तो ऐसी स्थिति में—

रूस द्वारा दो इकाई जूते का उत्पादन व्यय = 10 श्रमिक

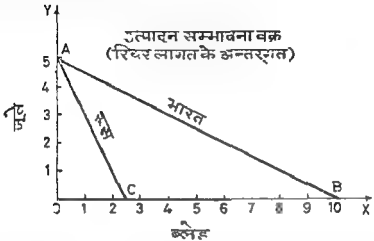
भारत द्वारा दो इकाई स्वेड का उत्पादन व्यय = 10 श्रमिक

अर्थात् दो इकाई जूते + दो इकाई स्वेड का उत्पादन व्यय = 20 श्रमिक

अतः स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होने की दशा में 2 इकाई जूते और 2 इकाई स्वेड केवल 20 श्रमिकों द्वारा उत्पादित किया जाएगा जबकि अन्तर्राष्ट्रीय-व्यापार के अभाव में इतनी ही वस्तु उत्पादित करने के लिए 30 श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। यही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ है और इसी लाभ के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पन्न होता है। इस प्रकार पूर्ण-लागत-अन्तर की स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अनिवार्य रूप से होने लगता है।

लागतों के पूर्ण अन्तर को रेखाचित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। इस रेखाचित्र में रूस का उत्पादन सम्भावना वक्र (Production Possibility Curve) एक इकाई जूता = 2 इकाई स्वेड के प्राप्ति पर खोला गया है और भारत का उत्पादन सम्भावना वक्र 1 इकाई जूता = 1 इकाई स्वेड के प्राप्ति पर बनाया गया है। चित्र में AB रेखा भारत की और AC रेखा रूस की उत्पादन सम्भावना रेखाएँ हैं। CB इस 'अतिरिक्त' को प्रदर्शित कर रहा है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय-व्यापार होने की दशा में भारत को प्राप्त होगा अर्थात् यही अन्तर्राष्ट्रीय-व्यापार का लाभ है।

और इसी लाभ के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पन्न होता है। B व C के बीच कोई भी विनिमय दर दोनों देशों के लिए लाभदायक होगी। चित्र में उत्पादन सम्भावना रेखा एक सीधी रेखा, इस मान्यता के आधार पर खींची गई है कि उत्पादन 'लागत-समता-नियम' के अधीन है।



व्यवहार में लागतों के पूर्ण अन्तर से प्राप्त लाभ अपवाद-स्वरूप ही दिखाई देते हैं। प्रत्येक देश में आवश्यकता की सभी वस्तुओं का किसी न किसी मात्रा में उत्पादन करना आवश्यक समझा जाता है। पूर्ण विशिष्टीकरण द्वारा उत्पादन-लागत में कमी करना तो सम्भव है परन्तु इससे देश की अन्य देशों पर निर्भरता में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। विशेष रूप से विकासशील देशों में तो सभी वस्तुओं की उत्पादन लागत अधिक होने के विशिष्टीकरण की कोई सम्भावना ही नहीं रह जाती। राजनीतिक एवं राष्ट्रीय भावना के कारण भी कोई देश अन्य देशों पर अपनी निर्भरता को बढ़ाना नहीं चाहता है। अतः पूर्ण लागत अन्तर का सिद्धान्त आधुनिक सन्दर्भ में अप्रयोज्य प्रतीत होता है।

2 समान लागत के अन्तर का व्यापार

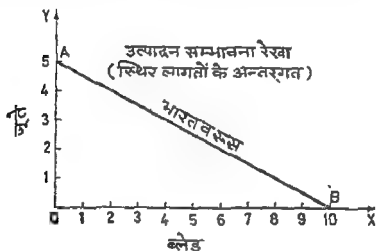
(Trade under Similar Cost Difference)

जब दो विभिन्न देशों में दो वस्तुओं के उत्पादन व्यय का अनुपात एक जैसा होता है तो यह लागतों में समान अन्तर कहलाता है। परन्तु ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्भव नहीं है। इसको हम निम्नानुसार समझ सकते हैं—

देश	उत्पादन की थम लागत		घरेलू व्यापार की शर्तें	
	जूते	वस्त्र		
भारत	10	20	10 20	अथवा 1 2
रूस	5	10	5 10	अथवा 1 2

माना कि यदि रूस में जूते की एक इकाई की लागत 5 थम इकाइयाँ हैं और वस्त्र की एक इकाई की लागत 10 थम इकाइयाँ हैं, दूसरी ओर भारत में भी जूते

को एक इकाई की लागत 10 थम इकाइयाँ हैं और ब्लेड की इकाई की लागत 20 थम इकाइयाँ हैं तो लागत का अनुपात दोनों देशों में 1 : 2 रहेगा। ऐसी स्थिति में थम-विभाजन या विशिष्टीकरण किसी भी देश के लिए लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। न तो रूस को इसमें फायदा होगा कि वह ब्लेड के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करने के लिए उत्पत्ति के साधनों को जूतों के उत्पादन से हटाकर ब्लेड के उत्पादन में लगाए और न भारत को इसमें लाभ होगा कि वह थम का परिवर्तन करे। जब दो देशों में किन्हीं दो वस्तुओं का उत्पादन-व्यय समान होता है तो प्रत्येक देश को प्रत्येक वस्तु उत्पादित करनी होती है तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है।



उपरोक्त में माना कि AB रेखा भारत व रूस दोनों देशों की उत्पादन सम्भावना रेखा है। यह रेखा एक इकाई जूता = 2 इकाई ब्लेड के आधार पर खींची गई है क्योंकि दोनों ही देशों में लागत-अनुपात समान है। इसलिए दोनों देशों के मध्य व्यापार नहीं हो सकता है क्योंकि इससे किसी को कोई लाभ नहीं होगा।

3. तुलनात्मक लागतों के अन्तर का व्यापार

(Trade under Comparative Cost Differences)

लागतों का तीसरा अन्तर तुलनात्मक होता है। यद्यपि मि हैवलर ने यह माना था कि विश्व का अधिकांश व्यापार लागतों में पूर्ण अन्तर पर आधारित है किन्तु वाल्टर क्राउस (Walter Krause) के मतानुसार अन्य अन्तर भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारों में महत्त्व रखते हैं। यान लीजिए इस सम्बन्ध में दो प्रश्न हैं—

(i) किसी देश को किसी क्षेत्र में कोई विशेष लाभ नहीं होता तो वह विशेषीकरण अथवा व्यापार क्यों करेगा।

(ii) जिस देश को विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में लाभ प्राप्त होता है वह किस वस्तु का विशेषीकरण और व्यापार करे ?

इन दोनों प्रश्नों का उत्तर तुलनात्मक सागत सिद्धान्त के आधार पर दिया जा सकता है। इसके अनुसार प्रत्येक देश को यह देयना चाहिए कि जिस वस्तु के उत्पादन में उसे सबसे अधिक लाभ होना है वह उसी में विशेषीकरण प्राप्त करे। इसके विपरीत जिस देश को किसी वस्तु के उत्पादन में लाभ नहीं होना है उस ऐसी वस्तु के उत्पादन में विशेषीकरण करना चाहिए जिसमें उसे कम से कम हानि हानी है। रिकार्डों ने इसी मान्यता के आधार पर अपना सिद्धान्त प्रतिपादित किया है।

सागता में तुलनात्मक अन्तर—दो देशों के बीच लागतों में तुलनात्मक अन्तर उस समय होता है जबकि एक देश का दूसरे देश की अपेक्षा दोनों वस्तुओं के उत्पादन में ही श्रेष्ठता प्राप्त होती है। यद्यपि यह श्रेष्ठता एक वस्तु के सम्बन्ध में कम और दूसरी वस्तु के सम्बन्ध में अधिक होती है। निम्न उदाहरण द्वारा तुलनात्मक लागत अन्तर का स्पष्ट किया जा सकता है।

देश	उत्पादन की अम-सागत				घरेलू व्यापार की शर्तें
	जूने	ब्लेड			
भारत	80	90	80	90	अर्थात् 1 0.88
रूस	120	100	120	100	अर्थात् 1 1.2

उपरोक्त उदाहरण में स्पष्ट है कि रूस की अपेक्षा भारत में दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन अधिक सम्पन्न है परन्तु भारत में जूने के उत्पादन में अधिक तुलनात्मक लाभ है क्योंकि जूने में उसका लागत अन्तर (120-80) ब्लेड में भारत अन्तर (100-90) की अपेक्षा अधिक है अथवा लागत-अनुपात की दृष्टि में दखन पर

$$\frac{80}{120} < \frac{90}{100}$$

$$\text{अथवा} \quad \frac{2}{3} < \frac{9}{10}$$

$$\therefore 0.66 < 0.90$$

यदि दोनों देशों के बीच किसी प्रकार का व्यापार नहीं होता है तो भारत और रूस में वस्तुओं का निम्न द्विनिमित्त अनुपात रहेगा—

भारत एक इकाई जूने = 0.88 इकाई ब्लेड

रूस एक इकाई जूने = 1.2 इकाई ब्लेड

परन्तु यदि दोनों देशों के मध्य व्यापार होने लगे और भारत जूनों के उत्पादन में तथा रूस ब्लेड के उत्पादन में विशेषीकरण प्राप्त कर ले और एक दूसरे के साथ व्यापार करने लगे तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा। इस प्रकार भारत के लिए यह लाभदायक रहेगा कि वह रूस की जूने भेजे क्योंकि वहाँ से जूनों की एक इकाई के बदले 1.2 इकाई ब्लेड मिल सकती है जबकि उसे अपने देश में एक इकाई जूनों के बदले में केवल 0.88 इकाई ब्लेड ही मिलती है। दूसरी तरफ रूस ब्लेड के उत्पादन में विशेषीकरण करके और ब्लेड का भारतीय जूनों से विनियम बग्न अपेक्षाकृत कम मूल्य पर जूने प्राप्त कर सकता है।

यदि सम्पूर्ण उत्पादन की ओर ध्यान दिया जाए तो भी दोनों देशों के लिए किसी एक वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करना अधिक लाभदायक होगा। माना कि भारत और रूस दोनों ही अलग-अलग जूते तथा ब्लेड का उत्पादन करते हैं तो ऐसी स्थिति में—

भारत एक इकाई जूते + एक इकाई ब्लेड = 170 श्रमिक

रूस एक इकाई जूते + एक इकाई ब्लेड = 220 श्रमिक

∴ 2 इकाई जूते + 2 इकाई ब्लेड = 390 श्रमिक

अब माना कि भारत जूतों में और रूस ब्लेड के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर लेता है तो ऐसी स्थिति में—

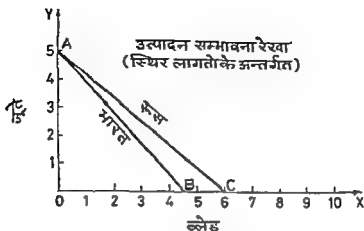
भारत द्वारा 2 इकाई जूते उत्पादन करने का व्यय = 160 श्रमिक

रूस द्वारा 2 इकाई ब्लेड उत्पादन करने का व्यय = 200 श्रमिक

∴ 2 इकाई जूते + 2 इकाई ब्लेड का उत्पादन व्यय = 360 श्रमिक

उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि पहले 2 इकाई जूते और 2 इकाई ब्लेड का उत्पादन व्यय 390 श्रमिक था जब दोनों देशों ने अलग-अलग वस्तुओं का उत्पादन करना आरम्भ कर दिया तो उत्पादन व्यय 360 श्रमिक हो गया, इससे एक ही मात्रा में प्राप्त होने वाली वस्तुओं के उत्पादन व्यय में 30 श्रमिकों की बचत हुई। अतः स्पष्ट है कि दोनों में से एक देश को दूसरे देश की अपेक्षा दोनों वस्तुओं के उत्पादन में अधिक दक्षता प्राप्त है परन्तु लागत का अनुपात भिन्न-भिन्न है तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा उस वस्तु को उत्पादित करके भेजने में अधिक लाभ होगा जिससे उत्पादन में अधिक तुलनात्मक लाभ होता है। रिकार्डों के मतानुसार, “इस तुलनात्मक लागत अन्तर की अवस्था में भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार लाभप्रद होगा यदि कुशल देश उसमें विशिष्टीकरण प्राप्त करे जिसमें उसकी कुशलता अधिकतम हो तथा अकुशल देश उसमें विशिष्टीकरण प्राप्त करें जिसमें अकुशलता न्यूनतम हो।”

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त को हम रेखा चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। माना कि AB भारत की उत्पादन सम्भावना रेखा एक इकाई जूते = 0.88 इकाई ब्लेड के आधार पर खींची गई है। AC रेखा रूस की उत्पादन सम्भावना रेखा है जो कि एक इकाई जूते = 1.2 इकाई ब्लेड के आधार पर खींची गई है। BC वह ‘प्रतिरेक’ है जिसे विदेशी-व्यापार के द्वारा दोनों देश आपस में बांट सकते हैं। B व C के बीच किसी भी विनिमय दर से दोनों देशों को लाभ होगा।



वासरमैन व हल्टमैन के अनुसार यह सिद्धान्त सिद्ध करता है कि "एक देश को अपने साधनों का व्यवहार सबसे अधिक लाभदायक विरूप में करना चाहिए, या तो उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जिनमें उसे सबसे अधिक तुलनात्मक लाभ प्राप्त था या उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जिनमें उसे सबसे कम तुलनात्मक हानि है।"³

सरल गणितीय रूप में इसे निम्न प्रकार में समझाया जा सकता है—

यदि A व B दो देश बनाते हैं तब

A_1 = प्रथम देश में A की थम लागत है,

A_2 = द्वितीय देश में A की थम लागत है,

B_1 = प्रथम देश में B की थम लागत है,

B_2 = द्वितीय देश में B की थम लागत है,

यदि $\frac{A_1}{A_2} < 1$ है तो प्रथम देश में 'A' द्वितीय देश में सस्ती होगी।

यदि $\frac{A_1}{A_2} < \frac{B_1}{B_2} < 1$, तो प्रथम देश को A एवं B दोनों ही वस्तुओं के

उत्पादन में निरपेक्ष या तुलनात्मक दृष्टि से प्रथम देश को A वस्तु के उत्पादन में व द्वितीय देश को B वस्तु के उत्पादन में लाभ होगा।

तुलनात्मक लागत अन्तरों के आधार (Bases of Comparative Cost Differences)

सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि एक उन्नत और विकसित देश में वस्तुओं के उत्पादन की लागत अर्द्ध-विकसित या अविकसित देशों की अपेक्षा कम प्राणी है। जो देश प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से सम्पन्न है उसका उत्पादन ऐसे

देशों की अपेक्षा कम लागत में होता है जहाँ खनिज पदार्थों का अभाव है, जलवायु उपयुक्त नहीं है, वर्षा समय पर और पर्याप्त नहीं होती, रेतीले या पहाड़ी प्रदेश हैं। जिन देशों के निवासियों का स्वास्थ्य अच्छा होता है वे कमजोर और बीमार जनसंख्या वाले देशों की अपेक्षा सस्ते में उत्पादन कर पाते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि लागतों के अन्तर स्पष्टतः कुछ कारणों के परिणाम हैं जिनका सरलता से उल्लेख किया जा सकता है। असल में ऐसा नहीं है। प्रायः यह देखा जाता है कि एक राज्य कुछ चीजों का उत्पादन अधिक व्यय से करता है किन्तु वह दूसरी चीजें बहुत कम लागत पर उत्पादित करता है। पिछड़ा हुआ, घुरे प्राकृतिक साधनों से युक्त और अस्वस्थ जनसंख्या वाला राज्य भी कुछ चीजें कम लागत पर पैदा करता है। उत्पादित के निर्धारणकर्ता विभिन्न उत्पादनों को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं।

तुलनात्मक लागत अन्तरो के आधार मुख्यतः निम्नलिखित हैं—

- (1) श्रमिकों की साक्षरता,
- (2) देश में पूंजी की मात्रा,
- (3) प्रति श्रमिक भूमि की मात्रा,
- (4) तकनीकी का स्तर, प्रवण्य की कुशलता, व्यावसायिक सगठनों के प्रकार,
- (5) उपभोक्ताओं की मात्रा, एवं
- (6) प्राय का स्तर।

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त का विश्लेषण (Analysis of Comparative Cost Theory)

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त का जन्म 18वीं शताब्दी की बणिज्जवादी नीति (Mercantilist Policy) की आलोचना के रूप में हुआ। बाद में अर्थशास्त्रियों ने इसे इसलिए अपनाया क्योंकि यह सरक्षणवादी प्रशुल्क के विरुद्ध तथा स्वतन्त्र व्यापार की नीति के पक्ष में एक वैज्ञानिक का तर्क था। इंग्लैण्ड में बणिज्जवादियों का कहना था कि जब इंग्लैण्ड स्वयं खाद्यान्न तथा अन्य कृषि वस्तुएँ पैदा कर सकता है तो उसे ये चीजें पोलैण्ड या रूस से क्यों मँगानी चाहिए? डेविड रिकार्डों ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि इंग्लैण्ड को कृषि-वस्तुओं को पैदा करने तथा निर्यात करने में इतना लाभ नहीं है जितना अन्य वस्तुओं को बनाने और उनका निर्यात करने में है।

तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त की मान्यता है कि यदि व्यापार को स्वतन्त्र छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक देश दीर्घकालीन में विशेषीकरण कर लेगा। वह उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात करेगा जिनमें उसे वास्तविक लागतों की दृष्टि से तुलनात्मक लाभ है। वह उन वस्तुओं का आयात करेगा जो देश में वास्तविक लागत की तुलनात्मक हानि उठाकर उत्पादित की जा सकती है। यह विशेषीकरण सभी सम्बन्धित देशों के पारस्परिक लाभ के लिए होता है। इससे ससार में उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है।

वास्तविक लागत (Real Costs) को श्रम के समय (Labour-Time) के रूप में अभिव्यक्त किया गया। सस्थापक ग्रंथशास्त्रियों ने तुलनात्मक लागत की अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार माना है। एडम स्मिथ की मान्यता के अनुसार एक देश अपने उत्पादनों के बदले दूसरे देशों से उन्हीं उत्पादकों को लेना है जिन्हें या तो वह पैदा नहीं कर सकता अथवा विदेशों की अपेक्षा अधिक लागत में पैदा कर सकता है।

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के विभिन्न रूपान्तर (Various Versions of Comparative Cost Theory)

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त का इतिहास सस्थापक ग्रंथ-शास्त्रियों से प्रारम्भ होता है। इसे बणिक्वादी सिद्धान्त की प्रतिक्रिया माना जा सकता है। बणिक्वादी सिद्धान्त की पृष्ठभूमि में यह विकसित हुआ। सस्थापक ग्रंथ-शास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से प्रतिबन्धों और सरक्षणों की नीति का विरोध करते थे। अन्तर्गते तुलनात्मक लागत सिद्धान्त को अपने पक्षपोषण के लिए प्रमुख तर्क बनाया। 18वीं शताब्दी में स्वतन्त्र व्यापार के सिद्धान्त का प्रारम्भ हुआ। इसके लिए यह आर्थिक तर्क दिया गया कि आयातकर्त्ता देश अपने घरेलू उत्पादन के बदले में ऐसी वस्तुओं का आयात करना है जिन्हें वह घर में उत्पादित नहीं कर सकता अथवा केवल अधिक लागत के साथ उत्पादित कर सकता है। स्वतन्त्र व्यापार के अन्तर्गत यह अन्तर्निहित है कि एक देश केवल उसी वस्तु को उत्पादित करेगा जिसमें आयात-लागत को निकाल कर उत्पादन लागत सबसे कम आती है।

सस्थापक ग्रंथ-शास्त्रियों में सुपरिचित चमकते हुए मितारे डेविड ह्यूम, एडम स्मिथ, हेनरी थोरंटन (Henry Thornton), डेविड रिकार्डों तथा ज. एस. मिल को माना जाता है। इनके अतिरिक्त इस सम्प्रदाय के कुछ कम प्रभावशाली ग्रंथ-शास्त्री भी हैं जिन्हें आंशिक रूप से मौलिक कहा जा सकता है। इनमें टोररेन्स (Torrens), माल्थस (Malthus), ब्लैक (Blake), व्हीटली (Wheatly), लॉग फील्ड (Long Field) और सीनियर (Senior) आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यहाँ इन सभी विचारकों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना उपयुक्त रहेगा ताकि सिद्धान्त को विभिन्न पक्षों से देखा जा सके। सस्थापक ग्रंथ-शास्त्रियों के अतिरिक्त कुछ आधुनिक विचारकों का उल्लेख भी किया जाएगा जिन्होंने सिद्धान्त के नए रूपान्तर प्रस्तुत किए।

डेविड ह्यूम—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त की दृष्टि से ह्यूम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ह्यूम की रचना में पर्याप्त मौलिकता दिखाई देती है। इसने अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक-यन्त्र के सम्बन्ध में विचार किया। अनेक व्यावसायिक घुटियों को दूर करने के साथ-साथ ह्यूम ने कुछ कार्यात्मक सम्बन्ध भी विकसित किए। उसने गतिशील तत्वों की अवहेलना नहीं की। उसका मत था कि दो समतुल्य स्थितियों के बीच यदि धन की मात्रा में परिवर्तन आता है तो उत्पादन

का आकार अस्थायी रूप से प्रभावित होगा। इस विचार ने माल्थस और केंनीशियन के सिद्धान्तों को पर्याप्त प्रभावित किया।

एडम स्मिथ—एडम स्मिथ ने गुगतान सन्तुलनों (Balances of Payment) के समायोजन यन्त्र की व्याख्या की, जो ह्यूम के सिद्धान्त से पर्याप्त मेल खाती है। एडम स्मिथ ने स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय गतिशीलता और श्रम-विभाजन के लाभों को अधिक ऐतिहासिक उदाहरणों द्वारा विस्तार के साथ अभिव्यक्त किया है। इसने वणिकवादियों की त्रुटियों का भी स्पष्ट उल्लेख किया है।

हेनरी थोर्नटन—इसने अन्तर्राष्ट्रीय मॉद्रिक यन्त्र पर विचार किया है। बाढ़ के अर्थ-शास्त्रियों में माल्थस, जे. एस. मिल, टीसिय और कीन्स प्रादि सभी ह्यूम और थोर्नटन की शाला के विचारक हैं।

डेविड रिकार्डो—तुलनात्मक सागतों के सिद्धान्त को सर्वप्रथम प्रकाशित करने का श्रेय रिकार्डो को दिया जाता है। मि. लेंसर (Mr. Leser) ने यह श्रेय टोरेन्स को दिया है। प्रो. सैलिगमैन ने भी इस मत का समर्थन किया किन्तु प्रो. हीलंडर ने रिकार्डो का पक्ष लेते हुए कहा है कि टोरेन्स ने तुलनात्मक सागत सिद्धान्त के पूर्ण महत्त्व को कभी स्वीकार नहीं किया और स्पष्टतः इसका उपयोग नहीं किया।

सिद्धान्त के प्रथम प्रतिपादक के बारे में सन्देह किया जा सकता है किन्तु यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि इस सिद्धान्त की स्पष्ट अभिव्यक्ति रिकार्डो की रचना (Principles) के प्रथम संस्करण (1817) के 7वें अध्याय में हुई। रिकार्डो के अनुसार—(1) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक सागत सिद्धान्त लागू होता है, (2) स्वतन्त्र व्यापार में प्रत्येक देश कम सागत वाले उत्पादनों में विशेषीकरण प्राप्त कर लेता है, (3) सागत की श्रम-समय (Labour-Time) की इकाई के रूप में जाना जा सकता है, (4) राष्ट्रीय-स्तर पर उत्पादन के सभी साधन गतिशील होते हैं किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय-स्तर पर वे गतिहीन होते हैं। उत्पादन का एक मात्र महत्वपूर्ण साधन श्रम है। रिकार्डो ने अपने सिद्धान्त को निम्नलिखित गणितीय उदाहरण द्वारा प्रतिपादित किया है—

देश	वस्तु की इकाई के उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम	
	कपड़ा	शराब
पुर्तगाल	90	80
इंग्लैण्ड	100	120

उपपुक्त उदाहरण में बताया गया है कि इंग्लैण्ड में एक गैलन शराब की सागत कार्य के 120 घण्टे (Working Hours) हैं तथा एक गज कपड़े की सागत कार्य के 100 घण्टे हैं। पुर्तगाल में शराब और कपड़े की सागत क्रमशः 80 और 90 कार्य के घण्टे हैं। स्पष्ट है कि इंग्लैण्ड की अपेक्षा पुर्तगाल को इन दोनों वस्तुओं

के उत्पादन में लाभ रहेगा फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से उसे शराब के उत्पादन में अधिक लाभ होगा। इसलैण्ड में तुलनात्मक रूप से कपड़ा सस्ता है। इन दोनों देशों के बीच जब व्यापार होगा तो इंग्लैण्ड कपड़े का निर्यात करेगा और शराब का आयात करेगा।

यदि इंग्लैण्ड को व्यापार का सम्पूर्ण लाभ प्रदान करना है तो अंग्रेजी कपड़े की एक इकाई के लिए शराब की $\frac{1}{2}$ इकाई के अनुपात में विनिमय करना चाहिए। यदि सारा लाभ पुर्तगाल को सौंपना है तो अंग्रेजी कपड़े और पुर्तगाली शराब के विनिमय का अनुपात क्रमशः 1 तथा $\frac{1}{2}$ होना चाहिए। रिकार्डों का कहना था कि अंग्रेजी कपड़ा और पुर्तगाली शराब का विनिमय कपड़ की एक इकाई के लिए शराब की एक इकाई के अनुपात में होगा। इस प्रकार इंग्लैण्ड 100 व्यक्तियों के उत्पादन को 110 व्यक्तियों के उत्पादन के लिए बढ़ावेगा। इस अनुपात में व्यापार से होने वाली प्राप्तियाँ दोनों देशों के बीच विभाजित हो जाएंगी। रिकार्डों के सिद्धान्त को समझने के लिए कुछ विशेष बातों का अध्ययन किया जाना उपयुक्त है। ये निम्नलिखित हैं—

(1) तुलनात्मक लागत और व्यापार शर्तें—रिकार्डों के उदाहरण में दो वस्तुओं के विनिमय की लिया गया है। विनिमय में वस्तु की एक इकाई के बदले दूसरी वस्तु की एक इकाई को लिया जाता है। प्रत्येक देश को उसी वस्तु में तुलनात्मक लाभ होता है जिसे वह कम लागत पर उत्पादित कर सके। बाद में ऐलिस (1825) और जेम्स मिल (1826) ने भी यह प्रतिपादित किया कि व्यापार के लाभ दो देशों के बीच बराबर विभाजित हो जाएँगे, बाद के सत्यापक विचारकों ने भी प्राप्ति के अनुपात को दोनों देशों के लिए समान बताया है।

(2) औसिक विशेषीकरण की सम्भवना—रिकार्डों ने अन्तर्राष्ट्रीय विशेषीकरण के लाभ के लिए अपने तर्क का समर्थन तुलनात्मक लागत के अनुरूप किया है। दो व्यक्तियों के बीच व्यापार से सादृश्यता दिखात हुए उसने उदाहरण दिया है—यदि दो व्यक्ति टोप और जूते दोनों चीजें बना सकते हैं तथा एक व्यक्ति दोनों कार्यों में अधिक कुशल है। वह टोप बनाने के कार्य में अपने प्रतियोगी से 20 प्रतिशत अधिक है और जूते बनाने के कार्य में 33 प्रतिशत अधिक है तो यह उन दोनों के हित में रहेगा कि कुशल व्यक्ति जूते बनाने के कार्य में सगे और अकुशल व्यक्ति टोप बनाने का कार्य करे।

उक्त उदाहरण में रिकार्डों ने पूर्ण विशेषीकरण को लाभप्रद माना है। पेरैटो (Pareto) ने बताया है कि विशेषीकरण न करने की अपेक्षा पूर्ण विशेषीकरण को आवश्यक रूप से लाभप्रद मानना भ्रमपूर्ण है। उसने अपने एण्टीथी चित्र द्वारा प्रदर्शित किया है कि कुछ परिस्थितियों में पूर्ण विशेषीकरण एक वस्तु की अपेक्षा दूसरी का अधिक हो सकता है। यह उन वस्तुओं की सापेक्षिक माँग पर निर्भर करता है। एक वस्तु में होने वाली वृद्धि आवश्यक नहीं कि दूसरी वस्तु की कमी से होने वाली हानि को पूरा कर देगी। कभी कभी इस तर्क को स्वतन्त्र व्यापार के पक्षपाती तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की औसिक अस्वीकृति भी मान लिया जाता है।

रिकाडों का कहना था कि यदि दो व्यक्तियों में से प्रत्येक को एक चीज के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ है तो दोनों को पूर्ण विशेषीकरण कर लेना चाहिए। यह मत सन्तोषजनक नहीं है। उत्पादन लागत में तुलनात्मक अन्तर होने पर पूर्ण विशेषीकरण आवश्यक रूप से दोनों देशों के लिए लाभदायक रहेगा यह मानना गलत है। केवल एक देश द्वारा आंशिक विशेषीकरण किए जाने की सम्भावना है।

(3) दो से अधिक वस्तुओं में व्यापार—तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त विभिन्न समस्याओं का अध्ययन इस सरल मान्यता के अन्तर्गत करता है कि व्यापार केवल दो वस्तुओं का और दो व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। सम्भवतः यह सोच लिया जाता है कि दो से अधिक राज्यों अथवा वस्तुओं के होने पर विश्लेषण जटिल बन जाएगा किन्तु पहले से निकाले गए निष्कर्षों में गम्भीर परिवर्तन नहीं करने पड़ेंगे। मि० ग्राहम (Mr. Graham) ने इस दावे को संस्थापक सिद्धान्त के प्रति गम्भीर आपत्तियों का आधार माना है। वस्तुओं और देशों की संख्या अधिक होने पर निष्कर्षों में परिवर्तन किया जाना आवश्यक बन जाता है जो दो वस्तुओं और दो देशों के आधार पर निकाले गए हैं। सम्भवतः सौमस्कीस्ट वह पहला व्यक्ति था जिसने दो से अधिक वस्तुओं तक अपने विश्लेषण को बढ़ाया।

(4) दो से अधिक देशों के बीच व्यापार—पुराने लेखकों ने विदेशी व्यापार में भाग लेने वाले केवल दो देशों का उल्लेख किया है। दो देशों से अधिक के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने के उदाहरण बहुत कम प्रस्तुत किए गए हैं। जे० एस० मिल ने तीसरे देश को भी व्यापार की शर्तों पर विचार करते समय उल्लेखित किया है किन्तु रिकाडों ने वही भी दो से अधिक देशों के व्यापार को अपने उदाहरणों का आधार नहीं बनाया।

(5) यातायात लागत—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त प्रायः इस मान्यता के आधार पर प्रतिपादित किया गया है कि यातायात लागत नहीं होती। यही कारण है कि आलोचकों ने इसे विरोध का आधार बनाया। यातायात लागत घरेलू व्यापार की अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिक महत्त्व रखती है क्योंकि बाजारों की दूरी अधिक होती है, इसके अपवाद भी हैं। किसी-किसी वस्तु की कीमत घरेलू स्तर पर भी यातायात लागत के कारण पर्याप्त बढ़ जाती है। यातायात लागत उत्पादन और उत्पादन के साधनों की कीमत को प्रभावित करती है। ऐतिहासिक दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त ने इसे अपना दायित्व स्वीकार नहीं किया है। यातायात की लागत यद्यपि निर्यातकर्ता द्वारा दी जाती है किन्तु वह उसे वस्तु की कीमत में जोड़ देता है और इस प्रकार आयातकर्ता से बसूल कर लेता है।

(6) धृद्धिशील और ह्रासमान लागतें—रिकाडों ने तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त में बताया है कि उत्पादन की लागतों में निरन्तरता पाई जाती है। बाद के साहित्य में भी इस मान्यता को जाने या अनजाने में स्वीकार किया गया है। लागतों को निरन्तर मानने पर औसतन और सीमान्त लागतों का प्रश्न नहीं

उठना क्योंकि ये दोनों सम्बन्ध बन जाती हैं। यदि व्यक्तिगत उत्पादक की लागत उसके उत्पादन के साथ बढ़ जाती है तो तुलनात्मक लागत सिद्धान्त तो लागू होगा किन्तु यह तुलनात्मक मीमान्त लागतों का रूप धारण कर लेगा।

रिकार्डों न माना कि उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर भी लागतें एक रैखी बनी रहती हैं। इस धारणा का आधार रिकार्डों की पूर्व मान्यताएँ हैं जैम-केवल दो वस्तुएँ केवल दो देश, उत्पादन का एकमात्र माध्यम धन, यातायात लागत का अन्तग्न रहना आदि। रिकार्डों का कहना था कि एक देश व्यापार तभी करना है जब उसे किसी विशेष वस्तु का उत्पादन की मीमान्त लागत में तुलना में लाभ होना है। वह देश अपने धनिकों को दूसरी वस्तुओं में हटाकर लाभप्रद वस्तु के उत्पादन में लगा देता है, और उस समय तक लगाता है जब तक उसकी तुलनात्मक मीमान्त लागत में लाभ होना रहे। निरन्तर लागत का अन्तग्न व्यापार से लाभ स्पष्ट होता है।

निरन्तर लागत का अन्तग्न एक देश जब तक किसी विशेष वस्तु का आयात में कोई लाभ प्राप्त नहीं करता तब तक वह उसका उत्पादन या आयात नहीं करता। वृद्धिशील लागत की परिस्थिति का अन्तग्न उत्पादित वस्तुओं के सम्बन्ध में यह धारणा लागू नहीं होती।

(7) कीमतें मौद्रिक लागत एवं वास्तविक लागतें—रिकार्डों तथा उनके अनुयायियों ने तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की मौद्रिक लागतों की अवधारणा वास्तविक लागतों के रूप में वर्णित किया। कुछ आधुनिक विचारकों का मत है कि उन शक्ति के मन्थारक सिद्धान्त में पूरी तरह से परिवर्तन किया जाना चाहिए।

प्रायः सभी मन्थारक अवधारणाएँ यह मानते हैं कि स्वतन्त्र व्यापार का अन्तग्न तथा यातायात लागत का अभाव में अन्तराष्ट्रीय व्यापार की एक जैसी वस्तुओं की कीमतें एक ही मुद्रा में सभी देशों में एक जैसी होंगी। देश में उत्पादित वस्तु की कीमतें उत्पादन की मौद्रिक लागतों (Money costs) के अनुपात में होंगी। पूँति की कीमतों का अन्तर व्यापार के तात्कालिक निधारणकर्ता होते हैं। कीमतें और मौद्रिक लागतों के अन्तर वास्तविक लागतों के अन्तरों में अभिव्यक्त होते हैं और इसलिए व्यापार की शक्ति से मन्थारक का निष्कर्ष महत्वपूर्ण है। मन्थारक विचारकों ने वास्तविक लागतों का मन्थारक महत्त्व न देकर प्रथम स्तर का महत्त्व प्रदान किया। धरतू तथा विदेशी उत्पादक जिस कीमत पर एक वस्तु का उत्पादन को बन के लिए तैयार होंगे उसका अन्तर ही यह तय करना है कि उस वस्तु का आयात किया जाएगा या निर्यात किया जाएगा या देश में ही उत्पादन को जाएगी। यातायात लागतों के अभाव में प्रत्येक वस्तु की कीमत हर जगह एक ही होनी है। यदि धरतू उत्पादन की मौद्रिक लागत अधिक है या कीमतें विदेशी पूँति की अवस्था अधिक है तो उस वस्तु का आयात किया जाएगा।

रिकार्डों का मतानुसार उत्पादन के माध्यम राष्ट्रीय-स्तर पर पूर्ण व्यावसायिक गतिशीलता और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण गतिहीनता रहने हैं। यही कारण है

कि देश में उत्पादित वस्तुओं का सापेक्षिक मूल्य उत्पादन की सापेक्षिक वास्तविक लागतों द्वारा प्रशासित होता है। यह नियम विभिन्न देशों में उत्पादित वस्तुओं पर लागू नहीं होता।

रिकाडों ने तुलनात्मक लागत सिद्धान्त को थम के समय की इकाई के रूप में वर्णित किया है। देश में उत्पादित वस्तुओं का मूल्य उनकी थम-समय (Labour-time) की लागतों के अनुपात में होता है। बाद के कुछ विचारकों ने भी इसका समर्थन किया है किन्तु आजकल मूल्य के थम-लागत सिद्धान्त के समर्थक बहुत कम रह गए हैं। कुछ विचारक तो इसकी खातिर तुलनात्मक लागत सिद्धान्त को भी अस्वीकार करने पर तैयार होते हैं। दूसरे इसकी प्राधुनिक मूल्य सिद्धान्त के सन्दर्भ में पुनर्स्थापना करते हैं।

आलोचना—रिकाडों द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक लागत सिद्धान्त अनेक जटिलताओं से पूर्ण है। उसने अनेक सरल मान्यताओं पर अपने सिद्धान्त को आधारित किया किन्तु केवल कुछ को ही वह सत्य प्रमाणित कर सका। अनेक मान्यताओं का केवल उल्लेख मात्र किया गया है तथा उनको स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है। रिकाडों के निष्कर्षों की आलोचना करते हुए विचारकों ने बताया कि—
(i) ये उसकी मान्यताओं से नहीं निकले हैं, तथा (ii) इन निष्कर्षों की आधारभूत मान्यताएँ गलत हैं। यदि इनको सुधारा या सही किया जाता है तो निष्कर्ष बदल जाते हैं। जेकब वाइनर (Jacob Viner) के मतानुसार रिकाडों की प्रमुख मान्यताएँ ये थी—दीर्घकालीन समायोजनों के लिए पर्याप्त समय, स्वतन्त्र प्रतियोगिता, केवल दो वस्तुएँ और दो देश, उत्पादन भिन्न होने पर निरन्तर थम-लागतें आदि-आदि।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के परवर्ती सिद्धान्तों ने एक-एक करके रिकाडों की मान्यताओं को छोड़ दिया। स्वयं रिकाडों ने भी बताया है कि थम-लागतों को किस प्रकार मौद्रिक लागतों तथा कीमतों में बदला जा सकता है?

महापुरुष अर्थ-शास्त्रियों ने तुलनात्मक लागत सिद्धान्त का प्रतिपादन वास्तविक लागत के सन्दर्भ में किया था। इस दृष्टिकोण की अनेक आलोचनाएँ की गई—

(i) यह दृष्टिकोण केवल तभी उचित रहेगा जब वस्तुओं की बाजार कीमतें उनके उत्पादन की वास्तविक लागतों के अनुरूप हों।

(ii) विभिन्न उद्योग उत्पादन के विभिन्न साधनों का प्रयोग भिन्न-भिन्न अनुपातों में करते हैं। इसके अतिरिक्त उत्पादन का प्रत्येक साधन विभिन्न रूपों में उपलब्ध होता है। अतः ऐसा कोई वस्तुगत मापक नहीं है जिसके आधार पर विभिन्न तत्वों की वास्तविक लागत का मूल्यांकन किया जा सके। यह कार्य केवल तभी सम्भव है जब उत्पादन का साधन केवल एक हो।

(iii) विभिन्न उद्योगों में समान थम के लिए अलग-अलग-मजदूरी दी जाती है तथा भिन्न वेतन पाने वाले थम के विभिन्न प्रकारों को अलग-अलग अनुपातों में प्रयुक्त किया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि हम थम को उत्पादन का एक मात्र तत्व

मानें तो वस्तुओं का मूल्य श्रम के समय की लागत से निर्धारित नहीं होगा बल्कि वेतन की लागत से होगा।

(iv) वास्तविक लागत का दृष्टिकोण उत्पादन तथा उत्पादन के साधनों के बाजार में पूर्ण स्पर्धा का अस्तित्व मानकर चलता है, जिससे वास्तविक संसार में प्रायः नहीं होती। अमल में व्यापार का निर्धारण मौद्रिक लागतों एवं कीमतों द्वारा होता है। अपूर्ण-स्पर्धा घन सम्बन्धी लागतों एवं कीमतों का वास्तविक लागतों के बराबर होना आवश्यक नहीं है।

वास्तविक लागत सिद्धान्त के विरुद्ध की गई उक्त प्रालोचनाओं से बचने के लिए तुलनात्मक लागत सिद्धान्त को अवसरगत लागत (Opportunity Cost) के रूप में वर्णित किया गया। जेकब वाइनर (Jacob Viner) के कथनानुसार अवसरगत लागत सिद्धान्त को सर्वप्रथम हेवरलर द्वारा प्रतिपादित किया गया।

अवसर लागत सिद्धान्त (Opportunity Cost Theorem)

प्रो हेवरलर के मतानुसार श्रम-लागत सिद्धान्त महत्त्वहीन है। आपने उत्पादन सम्भावना वक्र का प्रयोग करके इस सिद्धान्त को दो से अधिक साधनों पर लागू किया। आपका मत था कि अवसर लागत सिद्धान्त को तुलनात्मक वास्तविक लागतों के सिद्धान्त के स्थानापन्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।

प्रोफ़ेसर हेवरलर द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धान्त "अवसर लागत सिद्धान्त" (Opportunity Cost Theorem) कहलाता है। यह सिद्धान्त हमें बताना है कि निश्चित मात्रा में एक वस्तु का प्राप्ति करने हेतु कोई देश अपनी वस्तु की कितनी मात्रा का निर्यात करेगा। हम जानते हैं कि दो देशों के बीच दो वस्तुओं का विनिमय-अनुपात इनकी उत्पादन-लागत द्वारा निर्धारित होता है। पहले हम यह स्पष्ट करें कि विनिश्चयता न होने की स्थिति में प्रत्येक देश दोनों वस्तुओं की कितनी इकाइयों का उत्पादन करेगा। मूल्य-सिद्धान्त के अनुसार दो वस्तुओं का इष्टतम संयोग उम स्तर पर होता है जहाँ कि उत्पादनकर्ता की उत्पादन सम्भावना वक्र का ढाल सम लागत वक्र (Iso-cost-curve) के ढाल के बराबर हो।

अवसर लागत

अवसर लागत की धारणा इस तथ्य पर आधारित है कि उत्पत्ति के साधन सीमित और बहुप्रयोगात्मक होते हैं, क्योंकि प्रत्येक साधन सीमित है। इसलिए उसको सभी प्रयोगों में पूर्ण रूप से प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। समाज की दृष्टि से उसको किसी एक उद्देश्य के लिए प्रयोग करने का अर्थ है उसको अन्य उद्देश्यों में प्रयोग करने के अवसर का त्याग करना। किसी एक वस्तु के उत्पादन की लागत अन्य वस्तु की के मानाएँ है जिनका हमें त्याग करना पड़ता है। इस प्रकार उत्पादित वस्तु की लागत को उसमें लगे साधनों में व्यक्त करने के बजाय उस वस्तु में व्यक्त किया जा सकता है जो उत्पन्न नहीं की

जाती है। उत्पन्न न की जाने वाली वस्तु एक प्रकार से खोया अवसर है और इसलिए यह उस वस्तु की अवसर लागत है जो वास्तव में उत्पन्न की गई है। उदाहरण के लिए माना कि यदि एक किसान कुछ साधनों से 100 क्विंटल गेहूँ का उत्पादन कर रहा है और यदि उन्हीं साधनों से वह 120 क्विंटल जौ उत्पन्न कर सकता है तो 100 क्विंटल गेहूँ की अवसर लागत 120 क्विंटल जौ है। इसी प्रकार यदि एक बढ़ई एक दिन में काँच करके एक टेबल या 2 कुर्तियाँ बना सकता है तो यह कहा जा सकता है कि एक टेबल की अवसर लागत 2 कुर्तियाँ हैं जो एक टेबल के बदले तैयार की जा सकती है। इसी प्रकार यदि कुछ साधनों से 20 इकाई खद्दर का कपड़ा या 10 इकाई रेशमी कपड़ा बनाया जा सकता है तो 20 इकाई खद्दर-कपड़े की अवसर लागत = 10 इकाई रेशमी कपड़ा होगा, क्योंकि 20 इकाई खद्दर का कपड़ा = 10 इकाई रेशमी कपड़ा है। अतः इनकी प्रतिस्थापना दर 2:1 होगी। अर्थात् 2 इकाई खद्दर के कपड़े का त्याग करके एक इकाई रेशमी कपड़ा बनाया जा सकता है अथवा एक इकाई रेशमी कपड़े का त्याग करके दो इकाई खद्दर का कपड़ा बनाया जा सकता है। यह 2:1 का अनुपात इन दो वस्तुओं खद्दर का कपड़ा व रेशमी कपड़े के उत्पादन की लागत का अनुपात है। इस अनुपात को हम अवसर लागत अनुपात अथवा तुलनात्मक लागत अनुपात अथवा प्रतिस्थापना लागत अनुपात कह सकते हैं। क्योंकि यह अनुपात एक वस्तु की दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापन दर को प्रदर्शित करता है। अतः स्पष्ट है कि किसी निश्चित वस्तु की अवसर लागत वह उत्तम विकल्प है जिसका परिस्थान कर दिया जाता है। अब हम अवसर लागत सिद्धान्त की धारणा का अध्ययन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्तर्गत करेंगे।

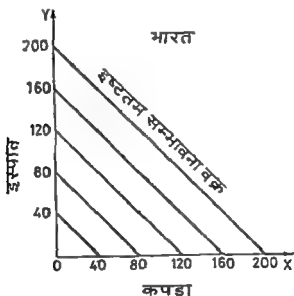
हम जानते हैं कि “मूल्य के क्रम सिद्धान्त” के प्रयोग का एक मात्र उद्देश्य दो देशों में सापेक्षिक मूल्यों का निर्धारण है। रिकाडों के मतानुसार श्रम-लागत वस्तु की पूर्ति पर प्रभाव डालकर मूल्य का निर्धारण करती है। प्रो. हैबलर ने प्रतिष्ठित सिद्धान्त की इस कमजोरी को दूर करके बताया कि वस्तुओं के सापेक्षिक मूल्य उनके उत्पादन में प्रयुक्त श्रम की निरपेक्ष मात्राओं द्वारा नहीं बरन् त्याग किए गए विकल्पों, अर्थात् प्रतिस्थापना अनुपातों द्वारा निर्धारित होंगे। इस सिद्धान्त का हम अब तीनों लागतों अर्थात् स्थिर, घटती तथा बढ़ती हुई लागतों की अवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन करेंगे।

स्थिर लागतों की अवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

(International Trade under Conditions of Constant Costs)

यदि यह मान लिया जाए कि उत्पादन लागतें स्थिर हैं, अर्थात् उत्पादन की प्राप्ति समता प्रतिफल के अन्तर्गत हो रही है, तो उत्पादन सम्भावना वक्र एक सरल रेखा के रूप में होगा। यदि हम दो देशों—भारत व जापान तथा दो वस्तुओं—इस्पात एवं वस्त्र का उदाहरण लें तथा यह मानें कि प्रत्येक देश में दोनों वस्तुओं का उत्पादन स्थिर लागतों के अन्तर्गत निम्नानुसार हो रहा है—

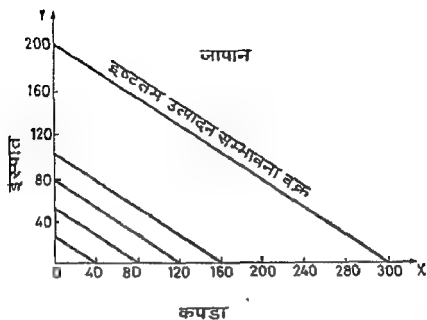
साधन की इकाइयाँ	उत्पादन की इकाइयाँ			
	भारत		जापान	
	इस्पात	कपड़ा	इस्पात	कपड़ा
200	—	—	200	300
100	200	200	100	150
80	160	160	80	120
60	120	120	60	90
40	80	80	40	60
20	40	40	20	30



उपरोक्त रेखाचित्रों (पृष्ठ 38 सहित) में प्रस्तुत विभिन्न उत्पादन सम्भावना क्षेत्र साधन के भिन्न-भिन्न स्तरों पर प्राप्त उत्पादन के विभिन्न स्तरों को दर्शाते हैं। इन रेखाचित्रों में श्रम की इकाइयों को प्रदर्शित नहीं किया गया है। परन्तु श्रम एक उत्पादन की मात्राओं के बीच एक निश्चित अनुपात लिया गया है।

भारत एवं जापान दोनों देशों के इष्टतम उत्पादन सम्भावना वक्र इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि श्रम की उपलब्ध मात्रा से कपड़े व इस्पात की कितनी इकाइयाँ प्राप्त होती हैं।

प्रबन्ध यह मान लें कि भारत में श्रम की 100 इकाइयाँ उपलब्ध हैं जबकि जापान में 200 इकाइयाँ उपलब्ध हैं। यदि भारत की श्रमशक्ति का पूर्ण उपयोग होना है तो यहाँ 200 इकाइयाँ इस्पात, या 200 इकाइयाँ कपड़ा, अथवा दोनों का



कोई संयोग प्राप्त करना सम्भव है। यदि इसके विपरीत जापान में ध्रुम का पूर्ण उपयोग किया जाए तो वहाँ 200 इकाइयाँ इस्पात या 300 इकाइयाँ कपड़ा अथवा दोनों का कोई संयोग प्राप्त किया जा सकता है। बहुधा हमारी भावना यह रहती है कि प्रत्येक देश उपलब्ध साधन का पूर्ण उपयोग करता है और इसी कारण यह मान लिया जाता है कि वह इष्टतम सम्भावना वक्र पर कहीं भी स्थित हो सकता है।

भारत के लिए उत्पादन रूपान्तरण की सीमान्तर दर (Marginal Rate of Product Transformation or MRPT) = $\frac{\Delta \text{इस्पात}}{\Delta \text{कपड़ा}}$ होगी।

अर्थात् इस स्थिति में $MRPT = -\frac{1}{3}$ होगी, जबकि जापान के लिए यह $\left(-\frac{2}{3}\right)$ के बराबर होगी क्योंकि इस स्थिति में MRPT स्थिर है, अतः दोनों उत्पादन सम्भावना वक्र एक सरल रेखा के रूप में होंगे जो कि केवल स्थिर लागतों को ही प्रदर्शित नहीं कर करते बल्कि इन वक्रों के ढाल (Slope) बीमत अनुपात (Price ratio) को भी बताते हैं।

ग्रान्तरिक दृष्टि से दोनों देश इस्पात व कपड़े के उन संयोगों को चुनेंगे जिनका निर्धारण उत्पादन सम्भावना वक्रों एवं समाज की तटस्थता वक्रों के स्पर्श-बिन्दुओं (Touching Points) द्वारा होता है। यह स्मरणीय है कि समाज के तटस्थता वक्र देश की जनता द्वारा व्यक्त दोनों वस्तुओं की माँग अथवा जनता की रचि को प्रदर्शित करते हैं जबकि उत्पादन सम्भावना वक्र देश की उत्पादन या पूर्ति क्षमता को दर्शाते हैं।

सन्तुलन की अवस्था में

$$\frac{\frac{\partial C}{\partial \text{कपड़ा}}}{\frac{\partial C}{\partial \text{इस्पात}}} = \frac{\frac{\partial U}{\partial \text{कपड़ा}}}{\frac{\partial U}{\partial \text{इस्पात}}}$$

जहाँ

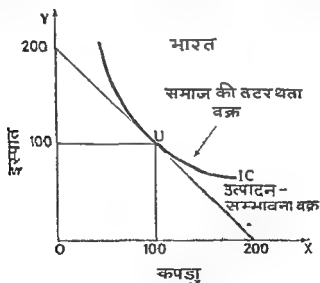
$$\frac{\partial C}{\partial \text{कपड़ा}} = \text{कपड़े की सीमान्त लागत}$$

$$\frac{\partial C}{\partial \text{इस्पात}} = \text{इस्पात की सीमान्त लागत}$$

$$\frac{\partial U}{\partial \text{कपड़ा}} = \text{कपड़े की सीमान्त उपयोगिता}$$

$$\frac{\partial U}{\partial \text{इस्पात}} = \text{इस्पात की सीमान्त उपयोगिता}$$

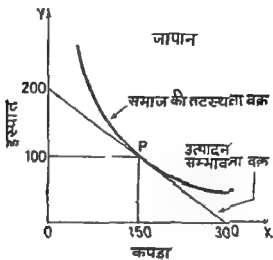
माना कि भारत व जापान के लिए उत्पादन सम्भावना वक्रों एवं समाज की लक्ष्यता वक्रों का स्पर्श क्रमशः U एवं P बिन्दुओं पर होता है। धन शक्ति के पूर्ण रोजगार की स्थिति में भारत कपड़े व इस्पात में प्रत्येक की 100 इकाइयों का उत्पादन करेगा जबकि जापान कपड़े की 150 इकाइयों व इस्पात की 100 इकाइयों का उत्पादन करेगा। यह स्थिति अमान्य विधो (पृष्ठ 40 सहित) से प्रकट की गई है—



भारत में कपड़े व इस्पात का इष्टतम संयोग

अब यदि भारत में कपड़े की माँग बढ़ जाए तो वहाँ स्थिर प्रतिस्थापन की दर से कपड़े का उत्पादन अधिक एवं इस्पात का उत्पादन कम कर दिया जाएगा। इसी प्रकार की स्थिति जापान के लिए भी उत्पन्न हो सकती है। कुल मिलाकर यह

कहा जा सकता है कि प्रतिस्थापन की निदिष्ट दर (2:3) पर भाँग में परिवर्तन के अनुरूप एक वस्तु का अधिक उत्पादन तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी की जाए।



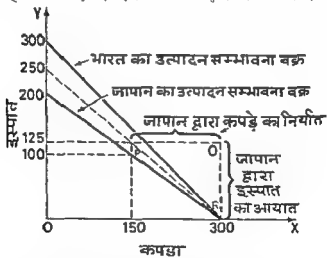
जापान में कपड़े व इस्पात का इष्टतम संयोग

अब तक हमने यह मान्यता ली थी कि धम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है। अब हम इस मान्यता को छोड़कर पैमाने के समता प्रतिफल (Constant returns to scale) का उदाहरण लेंगे। यह सर्वविदित है कि पैमाने में परिवर्तन का अर्थ भूमि, धम, पूँजी आदि साधनों में एक ही अनुपात से वृद्धि या कमी होने से है। पैमाने के समता प्रतिफल एवं स्थिर लागतों की स्थिति वस्तुतः पर्यायवाची हैं। ऐसी स्थिति में दोनों वस्तुओं के रूपान्तर की सीमान्त दर यानी MRPT भी स्थिर रहेगी। यदि भारत में कपड़े का उत्पादन बढ़ाया जाए तो इस्पात के उत्पादन में हुई कमी कपड़े के प्रतिरिक्त उत्पादन की अवसर लागत होगी। भारत में प्रति इकाई कपड़े की अवसर लागत या MRPT एक इकाई इस्पात है। इसी प्रकार जापान में यह इकाई कपड़े के विरुद्ध 1.5 इकाई इस्पात है, या प्रति इकाई इस्पात के बदले 1.5 इकाई कपड़ा है। पैमाने के समता प्रतिफल अथवा स्थिर लागत की स्थिति में अवसर लागत या MRPT स्थिर रहती है। इन रूपान्तर दरों (MRPT) को दो वस्तुओं के बीच आन्तरिक विनिमय अनुपात की सजा भी दी जा सकती है।

उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट होता है कि दो वस्तुओं के आन्तरिक विनिमय अनुपात की अभिव्यक्ति उत्पादन सम्भावना वक्र के ढलाव द्वारा की जाती है। भारत के लिए यह अनुपात (1:1), अर्थात् एक इकाई इस्पात = एक इकाई कपड़ा है जब कि जापान में यह (1:1.5), अर्थात् एक इकाई इस्पात = 1.5 इकाई कपड़ा है। अतः भारत को इस्पात के उत्पादन में एवं जापान को कपड़े के उत्पादन में तुलनात्मक

लाभ है। इस प्रकार जब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रारम्भ होता है तो भारत सभी साधनों को इस्पात हेतु प्रयुक्त करेगा जबकि जापान केवल कपड़े का उत्पादन करेगा।

परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए यह आवश्यक है कि इससे दोनों देशों को लाभ मिलता हो। यह तभी सम्भव है जबकि भारत के लिए व्यापार की शर्तें एक इकाई इस्पात = एक इकाई कपड़े से बेहतर हो, अर्थात् आन्तरिक विनिमय दर से अधिक हो। इसी प्रकार जापान के लिए जब तक व्यापार की शर्तें या विनिमय अनुपात एक इकाई इस्पात = 1.5 इकाई कपड़े से बेहतर नहीं होगा तब तक उसके लिए यही श्रेयस्कर है कि वह विदेशी व्यापार न करे। विदेशी व्यापार केवल उसी स्थिति में होगा जब प्रत्येक देश को वस्तु की प्रबलता लागत से अधिक इकाइयों व्यापार के माध्यम से प्राप्त हो जाएँ। यदि भारत को इस्पात में विशिष्टता प्राप्त करने के बाद भी इस्पात को एक इकाई के बदले एक इकाई से ज्यादा कपड़ा जापान से न मिले तो बेहतर यही है कि वह इस्पात व कपड़ा दोनों ही का उत्पादन करे। इसी प्रकार कपड़े में विशिष्टता प्राप्त करके अतिरिक्त कपड़े के बदले भारत से इस्पात इसी शर्त पर मंगाएगा कि उस देश में कपड़े के बदले प्राप्य मात्रा से अधिक इस्पात मिल जाए। अर्थात् जापान को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में तभी लाभ प्राप्त होगा जबकि एक इकाई कपड़े के बदले 1.5 इकाई से अधिक इस्पात मिले।



स्थिर लागतों के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

उपरोक्त चित्र से स्पष्ट होता है कि भारत के लिए सबसे अधिक लाभप्रद स्थिति वह होगी जबकि व्यापार की शर्तें जापान के आन्तरिक विनिमय अनुपात के समान हो। इसी प्रकार जापान को सबसे अधिक लाभ तब होगा जब व्यापार की शर्तें भारत के आन्तरिक विनिमय अनुपात की शर्तों की सीमाओं के रूप में स्वीकार किया जाए। वास्तविक अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य, विनिमय-अनुपात या व्यापार

की शर्तें इन दोनों रेखाओं के बीच कहीं भी वस्तुओं की परस्पर माँग के अनुसार निर्धारित होंगी।

अब माना कि व्यापार की शर्तें 5:6 अथवा 1:1.2 यानी एक इकाई इस्पात = 1 2 इकाई कपड़े पर तय हुई। यह भी माना कि विदेशी व्यापार प्रारम्भ होने से पूर्व जापान 100 इकाइयाँ इस्पात और 150 इकाइयाँ कपड़े का उत्पादन कर रहा था। व्यापार प्रारम्भ होने के बाद तुलनात्मक लाभ के कारण जापान केवल कपड़े का उत्पादन करता है और अतिरिक्त कपड़े का निर्यात करके आवश्यकता-नुसार भारत से इस्पात का आयात करता है। जापान 300 इकाइयाँ कपड़े का उत्पादन करता है। इसमें से वहाँ 150 इकाइयाँ का आन्तरिक उपयोग होने के बाद शेष 150 इकाइयाँ निर्यात हेतु रहती हैं। उपरोक्त व्यापार की शर्तों के अनुसार कपड़े की 150 इकाइयों के बदले जापान को भारत से 125 इकाइयाँ इस्पात की प्राप्ति होगी। इस प्रकार जापान चित्रानुसार PQ मात्रा में (150 इकाइयाँ) कपड़े का निर्यात करके QR (125 इकाइयाँ) इस्पात का आयात करेगा। उपरोक्त चित्र से यह स्पष्ट है कि विशिष्टीकरण एवं विदेशी व्यापार से जापान को पूर्वविक्षा लाभ ही होता है क्योंकि जहाँ विशिष्टीकरण से पूर्व जापान को 150 इकाइयाँ कपड़ा तथा 100 इकाइयाँ इस्पात ही उपलब्ध होता था, वहाँ विशिष्टीकरण एवं विदेशी व्यापार के कारण उसे 150 इकाइयाँ कपड़ा एवं 125 इकाइयाँ इस्पात की प्राप्ति होती है।

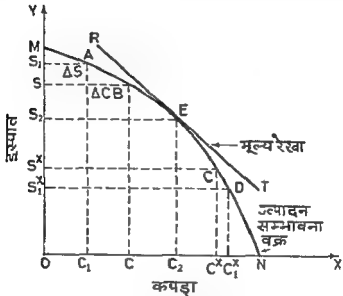
इसी प्रकार का विश्लेषण भारत के लिए भी लिया जा सकता है तथा यह प्रमाणित किया जा सकता है कि केवल इस्पात के उत्पादन में विशिष्टीकरण करके तथा अतिरिक्त इस्पात के बदले जापान से कपड़े का आयात करने पर भारत को उतनी ही मात्रा में इस्पात प्राप्त करने पर भी पूर्वविक्षा अधिक मात्रा में कपड़ा उपलब्ध होता है। अतः भारत को भी विदेशी व्यापार का लाभ प्राप्त होता है।

बढ़ती हुई लागतों के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (International Trade under Conditions of Increasing Costs)

बढ़ती हुई लागतों के अन्तर्गत भी अक्सर लागत पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त लागू होता है। प्रो. हैवरलर ने बढ़ती हुई लागतों की समस्या पर सविस्तार विचार किया और बताया कि "जिस सुगमता से एक वस्तु का प्रतिस्थापन दूसरी वस्तु के साथ किया जा सकता है, वह दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ाए जाने के साथ ही साथ कम होती जाती है।" बढ़ती हुई लागत की दशाओं के अन्तर्गत जो उत्पादन होता है वह इस बात को समझाने में महत्वपूर्ण है कि क्यों कोई देश अपनी पूर्ति के एक अंश के लिए अपने घरेलू स्रोतों पर और शेष अंश के लिए विदेशी स्रोतों पर निर्भर रहता है। बढ़ती हुई लागतों की दशाओं में पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं होगा, केवल आंशिक विशिष्टीकरण होगा अर्थात् एक ही समय में दोनों देशों में दोनों ही वस्तुएँ उत्पन्न भी जाएँगी। परन्तु हर देश उस वस्तु का उत्पादन प्रोत्साहित

अधिक करेगा जिसमे उसकी अवसर लागत कम होगी। यही उसकी निर्यात वस्तु होगी।

जब वस्तुओं का उत्पादन बढ़ती हुई लागतों के अन्तर्गत होता है तब उत्पादन सम्भावना वक्र निम्न रेखाचित्र के अनुसार मूल बिन्दु से नतोदर (Concave to the Origin O) हो जाता है, X-अक्ष पर कपड़े तथा Y-अक्ष पर इस्पात की इकाइयों को लेते हैं यदि देश सभी साधनों का उपयोग इस्पात के उत्पादन हेतु किया



बढ़ती हुई लागतों के अन्तर्गत उत्पादन सम्भावना वक्र

जाए तो इस्पात की OM मात्रा प्राप्त होगी। इसी प्रकार सभी साधनों का उपयोग कपड़े के हेतु करने पर ON इकाइयाँ प्राप्त होगी। इसलिए MN उत्पादन सम्भावना वक्र वाला देश या तो केवल इस्पात, या केवल कपड़ा अथवा इन दोनों का कोई संयोग प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

उपरोक्त उत्पादन सम्भावना वक्र MN रेखीय न होकर नतोदर है। इसका मुख्य कारण यह है कि कपड़े की अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन हेतु देश को उत्तरोत्तर अधिक लागत वहन करनी पड़ी है अर्थात् कपड़े की (इस्पात के रूप में) अवसर लागत बढ़ती जाती है। यही कारण है कि उत्पादन सम्भावना वक्र का ढलाव $\left(-\frac{\Delta \text{इस्पात}}{\Delta \text{कपड़ा}} = \frac{MC_c}{MC_i} \right)$ बढ़ता जाता है। हम इससे पूर्व यह देख चुके हैं कि स्थिर लागतों के सन्दर्भ में यह ढलाव (दोनों वस्तुओं की सीमान्त लागतों का अनुपात अथवा कपड़े की इस्पात के रूप में अवसर लागत) स्थिर रहता है।

माना कि उपरोक्त रेखाचित्र में देश की मूल स्थिति A बिन्दु पर है जहाँ

OS_1 इकाइयाँ इस्पात तथा OC_1 इकाइयाँ कपड़े की निर्मित होती हैं। यदि कपड़े का उत्पादन OC तक बढ़ता है तो इस्पात का उत्पादन OS तक घटाना होगा। इस प्रकार कपड़े की प्रतिरिक्त इकाइयों की अवसर लागत इस्पात की मात्रा में होने वाली कटौती है अर्थात् A व B बिन्दुओं के बीच उत्पादन सम्भावना वक्र का ढलाव या कपड़े की अवसर लागत $-\frac{\Delta S}{\Delta C}$ होगी। इसी प्रकार कपड़े की अवसर लागत C व D बिन्दुओं के बीच ज्ञात की जा सकती है। विपरीत दिशा में चलने पर भी हमारे इस निष्कर्ष में कोई परिवर्तन नहीं होगा कि एक वस्तु की प्रतिरिक्त इकाइयाँ प्राप्त करने की (अवसर) लागत दूसरी वस्तु की त्यागी गई मात्रा के रूप में व्यक्त की जाती है।

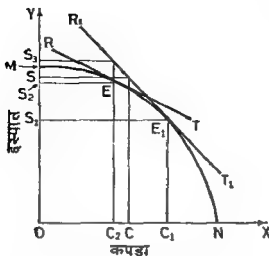
रेखाचित्र में E बिन्दु उस स्तर को व्यक्त करता है जहाँ दोनों ही वस्तुओं का इष्टतम संयोग (घरेलू उपयोग हेतु) निर्मित होगा। इस बिन्दु पर कपड़े व इस्पात के मूल्यों के अनुपात एवं कपड़े की अवसर लागत अथवा दोनों वस्तुओं की सीमान्त लागत के अनुपात में समानता है। सरल रेखा RT का ढलाव वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात $\left(\frac{P_c}{P_s}\right)$ है। जहाँ

P_c = कपड़े की प्रति इकाई कीमत है।

P_s = इस्पात की प्रति इकाई कीमत है।

उपरोक्त चित्र के माध्यम से हमने अभी तक बढ़ती हुई लागतों के अन्तर्गत उपलब्ध साधनों से प्राप्त इस्पात एवं कपड़े के इष्टतम संयोग के निर्धारण का वर्णन किया है। अब हम यह देखेंगे कि बढ़ती हुई लागतों के संदर्भ में आयात व निर्यात व्यापार की संरचना किस प्रकार की होगी।

अब हम मानते हैं कि देश को कपड़े के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ है अर्थात् यह देश कपड़े के उत्पादन में अधिकाधिक साधनों का उपयोग करके प्रतिरिक्त कपड़े का निर्यात करेगा एवं आवश्यकतानुसार इस्पात बाहर से मँपाएगा। कपड़े की माँग विदेशों से आने एवं देश में उत्पादित इस्पात की माँग घट जाने के कारण कपड़े का मूल्य इस्पात की तुलना में बढ़ जाएगा और इसके फलस्वरूप प्रस्तुत मूल्य रेखा RT विवर्तित हो R_1T_1 के रूप में हो जाएगी। यदि उत्पादन तकनीक यथावत रहे तथा तदनुकूपी उत्पादन सम्भावना वक्र की स्थिति भी वही रहे तो नई मूल्य रेखा R_1T_1 उत्पादन सम्भावना वक्र को E_1 बिन्दु पर स्पर्श करेगी। देश में उत्पादित कपड़े एवं इस्पात का इष्टतम संयोग क्रमशः OC_2 व OS_2 से बदल कर OC_1 तथा OS_1 हो जाएगा। अब देश में कपड़े की आन्तरिक माँग को निकास कर शेष का आवश्यक मात्रा में आयात किए गए इस्पात के बदले निर्यात कर दिया जाएगा। अत्रांकित चित्र में बताया गया है कि देश में कपड़े व इस्पात के इष्टतम उत्पादन (OC_1 एवं OS_1) और उपभोग्य मात्राओं (OC एवं OS) का अन्तर कपड़े के निर्यात तथा इस्पात के आयात द्वारा पाटा जा सकता है।



बढ़ती हुई लागतों के अन्तर्गत विदेशी व्यापार

जैसा कि चित्र में बताया गया है, मूल्यों में परिवर्तन होने पर मूल्य रेखा की स्थिति RT से बदल कर R_1T_1 हो जाती है तथा दोनों वस्तुओं के उत्पादन का साम्य स्तर E से हटकर E_1 पर आ जाता है। देश अब कपड़े का उत्पादन OC_2 से बढ़कर OC_1 एवं इस्पात का उत्पादन OS_2 से घटकर OS_1 कर देता है। अब माना कि देश की जनता इस्पात तथा कपड़े की क्रमशः OS एवं OC इकाइयाँ उपभोग करना चाहती है। फलस्वरूप CC_1 इकाइयाँ वस्त्र की निर्यात की जाकर SS_1 इकाइयाँ इस्पात की आयात की जाएँगी। इसके अतिरिक्त विदेशी व्यापार के कारण देश में कपड़े व इस्पात दोनों ही का अधिक उपयोग होने लगेगा ($\because OC > OC_2$ एवं $OS > OS_2$) तथा देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

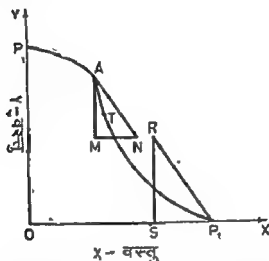
यह भी सम्भव है कि देश वस्त्र के उपयोग की मात्रा पहले जितनी ही OC_2 रहे तथा नए मूल्यों के अनुरूप $<_2 <_1$ माना कपड़े का निर्यात करके S_1S_3 इकाइयाँ इस्पात की बाहर से भेगाएँ अर्थात् विदेशी व्यापार के फलस्वरूप कपड़े का उपभोग यथावत रहने पर भी इस्पात की पूर्वापेक्षा काफी अधिक मात्रा उपलब्ध हो जाती है—इस्पात का उपभोग OS_2 से बढ़कर OS_3 हो जाता है।

घटती हुई लागतों के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (International Trade under Conditions & Diminishing Costs)

घटती हुई लागतें अथवा उत्पाति वृद्धि नियम किसी एक वस्तु के उत्पादन में क्रियाशील हो सकता है अथवा दोनों ही वस्तुओं पर? हम यहाँ दोनों ही स्थितियों का अध्ययन करेंगे।

(अ) किसी एक वस्तु का घटती हुई लागत के अन्तर्गत उत्पादन

बहुत-सी परिस्थितियों में जबकि किसी वस्तु का उत्पादन घटती हुई नियम के अन्तर्गत होता है और दूसरी वस्तु का उत्पादन वृद्धिमान लागत निरन्तर होता है।

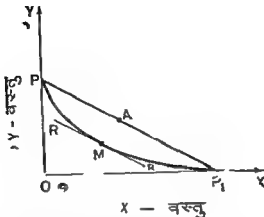


किसी एक वस्तु का घटती हुई लागत के अन्तर्गत उत्पादन

चित्र में PP_1 का उत्पादन सम्भावना वक्र है। प्रारम्भ में यह वक्र मूल से नतोदर है अर्थात् प्रारम्भ में X वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करने पर Y का उत्पादन में बढ़ती हुई कमी करनी पड़ती है अर्थात् A बिन्दु तक यह वक्र वृत्ति प्रवृत्ति लागतों की प्रदर्शित करता है इस सीमा के अन्दर उत्पादन में देश के Y वस्तु के उत्पादन में विनिष्ठीकरण करना लाभप्रद रहेगा। यह देश A बिन्दु साम्य की अवस्था में रहेगा और AM Y-वस्तु के बढ़ने MN X-वस्तु का घट करेगा। परन्तु यदि किसी तरह से X-वस्तु में T बिन्दु के पश्चात् भी उत्पादन आ सके तो यह देश पाएगा कि उत्पादन ह्रासमान प्रवृत्ति लागतों के अन्तर्गत रहा है और इस स्थिति में इस देश के लिए पूर्ण विनिष्ठीकरण करना लाभप्रद और यह देश Y-वस्तु के बढ़ने X-वस्तु का आयात करेगा। अब वह R बिन्दु रहेगा और पहले की अपेक्षा श्रेष्ठ स्थिति में होगा।

(ब) दोनों वस्तुओं के घटती हुई लागतों के अन्तर्गत उत्पादन

जब दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन घटती हुई लागतों के अन्तर्गत होता है उत्पादन सम्भावना वक्र मूल बिन्दु के उन्तोदर होती है जैसा कि अप्रकृत रेखा में दर्शाया गया है।



दोनों वस्तुओं के घटती हुई लागतों के अन्तर्गत उत्पादन

चित्र में PMP_1 उत्पादन सम्भावना रेखा है। यदि रेखा X -वस्तु के रूप में उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ Y वस्तु के उत्पादन में घटती लागतों और Y वस्तु में वृद्धि के साथ-साथ X वस्तु के रूप में घटती लागतों का नियम प्रकट करती है, यदि RR कीमत रेखा है और M साम्य बिन्दु तथा अर्थव्यवस्था में आन्तरिक मिनियमिताओं के कारण घटती लागतें क्रियाशील हैं तो इस स्थिति में यदि किसी कारण से साम्यावस्था भंग हो जाती तो उपरोक्त परिस्थिति के अनुसार या तो वह X वस्तु के उत्पादन में या Y वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा। वह राष्ट्र किस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि शुरू में किस वस्तु के मूल्य में वृद्धि के कारण साम्यावस्था भंग होती है। यदि प्रारम्भ में Y -वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो Y -वस्तु के उत्पादन में वृद्धि की जाएगी और उत्पादन में वृद्धि के साथ उत्पादन लागत में कमी होगी और लाभ की मात्रा बढ़ेगी और अन्ततः सन्तुलन P -बिन्दु पर स्थापित होगा। इसी प्रकार यदि X -वस्तु में किसी कारण से वृद्धि हो जाती है तो उसके उत्पादन में वृद्धि की जाएगी और उत्पादन वृद्धि के साथ उत्पादन लागत में कमी रहेगी और अन्ततः P -बिन्दु पर साम्य स्थापित होगा।

घटती हुई लागतों के नियम की सम्भावना अल्पकाल में बहुत कम रहनी है परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से यह नियम बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीय-व्यापार का महत्वपूर्ण कारण है। यदि दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन घटती हुई लागतों के अन्तर्गत हो रहा है तो इस स्थिति में दोनों देशों की उत्पादन सम्भावना वक्रों को एक ही आधार पर स्थापित करके, समान अवसर लागतों के समान ही सन्तुलन बिन्दु ज्ञात किया जा सकता है।

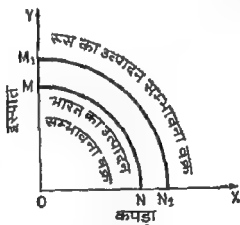
आंशिक विशिष्टीकरण (Partial Specialisation)

स्थिर लागतों के अन्तर्गत देज पूर्ण विशिष्टीकरण के आधार पर केवल उन

वस्तु के उत्पादन में साधनों का उपयोग करता है जिसमें उसे तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है। परन्तु, बढ़ती हुई लागतों के अन्तर्गत ऐसा नहीं होता है। बढ़ती हुई लागतों के सन्दर्भ में एक देश उस वस्तु का भी कुछ मात्रा में उत्पादन करता है जिसमें इसे तुलनात्मक लाभ नहीं है तथा जिसकी पर्याप्त मात्रा का आयात किया जाता है। ऐसी वस्तु के स्वदेशी उत्पादकों को आयातित वस्तुओं की प्रतिप्रेषिता का सामना करना पड़ता है, हालाँकि उन्हें इस वस्तु के उत्पादन लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। यही कारण है कि विदेशी व्यापार प्रारम्भ होने के बाद भी बढ़ती हुई लागतों के अन्तर्गत पूर्ण विनिष्ठीकरण नहीं हो पाता। इसे हम आंशिक विनिष्ठीकरण की स्थिति कहते हैं।

अनुपातिक लागतें (Proportional Costs)

यदि दो देशों की लागतें अनुपातिक हों तो दोनों देशों के बीच विदेशी व्यापार नहीं होगा। उत्पादन लागतें उस स्थिति में अनुपातिक होती हैं जब दोनों वस्तुओं अथवा उत्पादन के सभी क्षेत्रों में देश की रीष्टता प्राप्त हो और इन्हीं लागत अनुपातों पर दूसरा देश भी दोनों वस्तुएँ उत्पादन करने की क्षमता रखता हो। ऐसी स्थिति में दोनों देशों के उत्पादन सम्भावना वक्र समानान्तर होंगे।



चित्र में रूस व भारत के उत्पादन सम्भावना वक्र M_1N_1 एवं MN माने गए हैं। माना कि भारत में इस्पात व कपड़े के उत्पादन हेतु क्रमशः 200 व 180 इकाइयाँ श्रम की आवश्यकता है जबकि रूस में इनके लिए क्रमशः 100 व 90 इकाइयाँ श्रम चाहिए। ऐसी अवस्था में कपड़े व इस्पात की उत्पादन लागतें दोनों ही देशों में अनुपातिक होंगी और इस कारण रूस व भारत में दोनों वस्तुओं के आन्तरिक विनिमय अनुपात भी समान होंगे। इसी कारण दोनों देशों के उत्पादन सम्भावना वक्र समानान्तर होंगे तथा विदेशी व्यापार की कोई सम्भावना नहीं होगी।

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की आधारभूत मान्यताओं की आलोचना (Criticism of the Basic Assumptions of the Theory of Comparative Cost)

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त कुछ मान्यताओं पर आधारित है। उदाहरण के लिए इसके द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि धन का अस्तित्व नहीं होता। केवल दो देश और दो पण्य होते हैं, स्थानान्तरण (यातायात) में कोई लागत नहीं लगती, दोनों ही देशों में होने वाला उत्पादन लगातार प्राप्त होने वाली भाग्य के नियम पर निर्भर है, विभिन्न सामग्रियों की कीमत उनके उत्पादन की वास्तविक लागत से निर्धारित की जाती है, उत्पादन के सभी साधन पूरी तरह से कार्यरत होते हैं तथा स्वतन्त्र प्रतियोगिता कार्यरत रहती है। ये समस्त मान्यताएँ तुलनात्मक मूल्यों के लागत सिद्धान्त का आधार बनी हैं।

70970

उक्त समस्त मान्यताओं की निम्नलिखित आलोचनाएँ की जाती हैं —

(1) धन की आवश्यकता—यह मान्यता गलत थी कि समस्त व्यापार केवल लेन-देन (Barter) से ही होता है। व्यापार में धन की भी पर्याप्त आवश्यकता होती है। वास्तविक सत्तार में हम देखते हैं कि वस्तुओं को न केवल वस्तुओं से बदला जाता है बल्कि धन से भी बदला जाता है। आयात और निर्यात करने वाले लोग व्यापार किये जाने वाले माल की कीमतों के सम्बन्ध में सोचते हैं न कि उनके मूल्यों के सम्बन्धों में। जब हम धन के सम्बन्ध में बात करते हैं तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का स्पष्टीकरण करने वाले तुलनात्मक अन्तर नहीं होते बल्कि निरपेक्ष अन्तर होते हैं। श्रम की लागत में तुलनात्मक अन्तरो के रूप में स्थानान्तरण अधिक कठिन नहीं है। लगा हुआ श्रम धन के रूप में बदला जा सकता है।

देशों में वस्तुओं की लागत का मूल्य निर्धारित करते समय भूजदूरों की भूजदूरी को आधार नहीं बनाया जा सकता। जिस देश में उत्पादन के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ रहनी हैं वहाँ वेतन का सामान्य स्तर प्रायः ऊँचा रहता है। यही कारण है कि विकसित देशों में श्रम बहुत महँगा होता है, जबकि विकासशील देशों में यह सस्ता मिल जाता है। इसी आधार पर कुछ विकसित देश अविकसित देशों द्वारा बनाए गए माल पर पर्याप्त चुंगी लगा देते हैं क्योंकि यह उत्पादन बहुत सस्ते श्रम पर किया गया है और इन देशों के श्रम के उच्च जीवन स्तर के लिए एक महान् चुनौती है।

आलोचकों द्वारा यह कहा गया है कि तुलनात्मक सिद्धान्त चाहे यह मानकर चले कि यातायात में कोई लागत नहीं लगती तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि कोई देश उस वस्तु के उत्पादन में विशेषीकरण प्राप्त कर लेगा जिसमें उसे तुलनात्मक लागत का लाभ है। कई बार ऐसा होता है कि एक देश लाभ पर विचार किए जाने से पूर्व ही एक वस्तु के उत्पादन में विशेषीकरण प्राप्त कर लेता है। उस वस्तु के लिए दोनों देशों में की जाने वाली भाँग पर विचार करने

से पहले ही वह विशेषीकरण का निर्णय ले लेता है। ऐसी स्थिति में दूसरा देश भी इस वस्तु के कुछ अणु का उत्पादन घरेलू रूप से करेगा। ऐसा उम समय भी होता है जब व्यापार करने वाला एक भागीदार बहुत छोटा और दूसरा भागीदार पर्याप्त बड़ा होता है, अथवा जब एक के द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तु महत्वपूर्ण होती है और दूसरे द्वारा उत्पादित वस्तु दोनों के लिए ही कम महत्वपूर्ण होती है।

स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय प्रत्यक्ष रूप से केवल वस्तुओं के साथ ही नहीं किया जाता बरन् मुद्रा द्वारा किया जाता है। अतः स्वाभाविक है कि लोग वस्तुओं के विनिमय के सम्बन्धों पर मुद्रा सम्बन्धी मूल्यों के सन्दर्भ में विचार करते हैं न कि थम लागतों के सन्दर्भ में। ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में धन लागत के निरपेक्ष अन्तरों का प्रभाव पड़ता है।

(2) दो से अधिक वस्तुएँ—तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त अपने प्रापकी केवल दो वस्तुओं के विचार पर केन्द्रित रखता है। इसमें यह मानकर चला जाता है कि व्यापार की जाने वाली वस्तुएँ केवल दो हैं। एक देश उम वस्तु का निर्यात करेगा जिसके उत्पादन में उसे दूसरे देश की अपेक्षा अधिक सापेक्षिक लाभ है और उस वस्तु का आयात करेगा जिसके उत्पादन में उसे दूसरे देश की अपेक्षा कम सापेक्षिक लाभ है। वास्तविक व्यवहार में हम पाते हैं कि व्यापार केवल दो वस्तुओं का ही नहीं होता बरन् आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। अतः आयात प्रदान पर विचार करते समय केवल दो वस्तुओं को ही ध्यान में रखने की अपेक्षा सभी वस्तुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(3) दो से अधिक देश—तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त केवल यह मानकर चलता है कि व्यापार केवल दो देशों के बीच हो रहा है जबकि वास्तविकता यह है कि व्यापार दो से अधिक देशों के बीच भी हो सकता है। इनमें से प्रत्येक देश उन वस्तुओं का निर्यात करेगा जिनकी लागत तुलनात्मक रूप से देश में कम होती है और उन चीजों का आयात करता है जिनकी लागत तुलनात्मक रूप से विदेशों में कम होती है। इस विचार का अपना महत्व है फिर भी प्रत्येक देश जिन विशेष वस्तुओं का आयात-निर्यात करेगा उनको उस देश के उत्पादन की तुलनात्मक लागत के मापकों द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता।

प्रत्येक देश के विशेष आयातों और निर्यातों को निर्धारित करने के लिए विभिन्न देशों में इन वस्तुओं की पारस्परिक मांग के सम्बन्ध में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करना जरूरी है। ऐसा न होने पर हम विशेषीकरण के सम्बन्ध में उपयुक्त निर्णय नहीं ले पाते। उदाहरण के लिए हाँ, क, स, ग, तीन देशों को ले लेंगे हैं जो कपड़ा और गेहूँ दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। मान लीजिए कपड़े की एक इकाई के उत्पादन की थम लागत इन देशों में क्रमशः 3 : 2 : 1 है और गेहूँ की एक इकाई के उत्पादन की थम लागत 2 : 3 : 4 है। इस उदाहरण में 'क' का गेहूँ के उत्पादन में 'स' और 'ग' की अपेक्षा तुलनात्मक साफत लाभ है। दूसरी ओर 'ग' को कपड़े के उत्पादन में 'क' तथा 'स' की अपेक्षा तुलनात्मक लाभ रहेगा। ऐसी

स्थिति में 'क' गेहूँ के उत्पादन में विशेषीकरण प्राप्त करेगा और 'ग' कपड़े के उत्पादन में विशेषीकरण प्राप्त करेगा। यहाँ प्रश्न यह है कि 'ख' किस वस्तु के उत्पादन में विशेषीकरण प्राप्त करेगा? 'ख' का गेहूँ के उत्पादन में 'ग' की प्रपेक्षा और कपड़े के उत्पादन में 'क' की अपेक्षा लाभ है। इनमें से वह किसी वस्तु के उत्पादन में विशेषीकरण प्राप्त करेगा यह उस समय तक ज्ञान नहीं किया जा सकेगा जब तक कपड़े और गेहूँ के बीच की विनिमय दर को ज्ञात न कर लिया जाए। विनिमय दर निर्धारित करने के लिए तीनों देशों की पारस्परिक माँग सूचियों की जानकारी प्राप्त करना जरूरी है।

(4) यातायात व्यय—तुलनात्मक लागत सिद्धान्त मानता है कि यातायात का भुगतान निर्धारित नहीं है। इस मान्यता के आधार पर यह विश्वास है कि यातायात में कोई व्यय नहीं किया जाता जबकि वास्तविकता यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में यातायात का व्यय सबसे ज्यादा महत्त्व रखता है। यातायात व्यय पर विचार करने के बाद ही तुलनात्मक लागत सिद्धान्त का सत्यता जानी जा सकती है। इस दृष्टि से आयात की जाने वाली वस्तु को सौधे निर्यात की जाने वाली वस्तुओं से नहीं बढ़ा जा सकता वरन् इसके लिए यह भी देखना होगा कि यातायात-व्यय के साथ मिनकर किसी वस्तु का मूल्य या लागत कितनी हो जानी है। यदि यातायात का व्यय इतना अधिक हो जाए कि वस्तु की उत्पादन लगत तुलनात्मक रूप से बढ़ जाए तो उसका निर्यात और आयात नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि किसी देश की निर्यात-क्षमता उसकी तुलनात्मक उत्पादन लागत पर ही निर्भर नहीं करती वरन् यातायात के व्यय पर भी आधारित है।

(5) उत्पादन की विभिन्नतापूर्ण लागतें—तुलनात्मक लागत सिद्धान्त यह विश्वास करता है कि व्यापार में रह दानो देशों में निरन्तर लागत नियम (Law of Constant Unit Cost) क्रियाशील रहता है। इस अनुसार किसी वस्तु की अनिश्चित मात्रा सभी उत्पन्न की जाती है जब पहले के बराबर ही प्रति इकाई श्रम व्यय किया जाए। दूसरी ओर वास्तविकता यह है कि निरन्तर लागत केवल असाधारण स्थितियों में ही देखी जा सकती है। सामान्य नियम के अनुसार लागत घटती बढ़ती (Decreasing Costs and Increasing Costs) रहनी है। जब 'क' देश को गेहूँ के उत्पादन में 'ख' देश की अपेक्षा अधिक लाभ है और 'ख' देश को कपड़े के उत्पादन में 'क' देश की अपेक्षा अधिक लाभ है तो ये दोनों देश इन वस्तुओं के उत्पादन में विशेषीकरण प्राप्त कर लेंगे। विशेषीकरण लागत मूल्य को घटाता बढ़ता है।

विशेषीकरण के फलस्वरूप 'क' देश धीरे-धीरे गेहूँ के उत्पादन में अधिक से अधिक लाभ से उत्पादन करने लगेगा और 'ख' देश कपड़े के उत्पादन में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करता जाएगा। इस प्रकार उसकी लागत भी श्रम घटती जाएगी। फलस्वरूप तुलनात्मक लागत में निरन्तरता नहीं रही वरन् वह समय के अनुसार घटती और बढ़ती रही। ज्यों-ज्यों विशेषीकरण बढ़ता जाता है, उत्पादन में उनकी

लागत का अन्तर कम होता चला जाता है। अन्त में एक ऐसी स्थिति आती है जब तुलनात्मक लागत बराबर हो जाती है। इस स्थिति में आगे और विशेषीकरण की सम्भावनाएँ समाप्त हो जाएँगी।

दूसरी ओर जब 'उत्पादन' लागत के ह्रास नियम (Law of Diminishing Cost) के अनुसार होता है तो तुलनात्मक लागत की मात्रा एवं व्यापार का क्षेत्र विशेषीकरण के साथ-साथ बढ़ता जाता है। स्टाई लागतों की प्रमेया ह्रासमान लागतों के अधीन व्यापार की मात्रा अधिक होगी। यह मात्रा वृद्धिशील लागतों की प्रमेया और भी अधिक होगी। ह्रासमान लागतों के अधीन व्यापार की सम्भावनाएँ उस समय भी हो सकती हैं जब व्यापार की स्थापना से पूर्व दो देशों के बीच तुलनात्मक सीमान्त मूल्यों में अन्तर नहीं है। जब एक बार व्यापार प्रारम्भ हो जाता है तब तुलनात्मक सीमान्त मूल्यों में अन्तर व्यापार की वृद्धि के साथ-साथ बढ़ता चला जाता है। निरन्तर और ह्रासमान लागतों के अधीन कम से कम एक देश एक वस्तु के उत्पादन में पूरी तरह से विशेषीकरण प्राप्त करेगा और दोनों देश, यदि वे एक ही प्रकार के हैं तो एक ही वस्तु के उत्पादन में विशेषीकरण प्राप्त कर लेंगे। वृद्धिशील लागत में विशेषीकरण का आंशिक होना सम्भावित है। यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि वृद्धिशील लागतों के अधीन पूर्ण विशेषीकरण भी सम्भव नहीं है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि लागत में हमेशा निरन्तरता नहीं पाई जाती वरन् वह घटती और बढ़ती रहती है। अनेक शहरी परिस्थितियाँ इन लागतों पर प्रभाव डालती हैं और तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त की सत्यता को सन्देह में डालती हैं। उत्पादन की लागत में वृद्धि और कभी थप विभाजन की मात्रा को बदलती रहती है।

तुलनात्मक लागत-सिद्धान्त की आलोचना (The Criticism of Comparative Cost Theory)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की व्याख्या मुख्य रूप से सत्त्वानक अर्थशास्त्रियों द्वारा की गई है। इस सिद्धान्त ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की अनेक व्यावहारिक समस्याओं को सुलझाने में सहायता की। इतने पर भी इस सिद्धान्त में अनेक कमियाँ थी जिनके परिणामस्वरूप यह अर्थशास्त्रियों की आलोचनाओं का विषय बना। एक समय था जब इस सिद्धान्त को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रतिष्ठित तथा सर्वमान्य स्पष्टीकरण समझा जाता था। मि. एल्सवर्थ (Ellsworth) के कथनानुसार, "इस सिद्धान्त को इतना ही निरपेक्ष और निर्विवाद सत्य माना गया जितना कि उत्पत्ति ह्रास नियम एवं श्रम विभाजन आदि को।" असल में सिद्धान्त की आधारशिलाएँ अत्यन्त कमजोर थी और इसलिए इसकी स्फुरचना को हमेशा ही आलोचना का विषय बनाया गया। इस सिद्धान्त के आलोकों में मि. ओर्हलिन तथा ग्राहम आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कुछ प्रमुख आलोचनाएँ प्रतीकित प्रकार हैं—

(1) श्रम सिद्धान्त पर अतिशय जोर

संस्थापक ग्रंथशास्त्रियों ने तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त का प्रतिपादन करके श्रम को विशेष महत्त्व प्रदान किया। उन्होंने उत्पत्ति के मूल्य सम्बन्धी अन्तरों (Price differences) की अपेक्षा सापेक्षिक श्रम लागतों (Labour costs) पर विशेष जोर दिया है। ऐसी स्थिति में श्रम के मूल्य सिद्धान्त की, की जाने वाली समस्त आलोचनाएँ इस सिद्धान्त पर लागू हुईं। रिकार्डों आदि विचारकों ने उत्पादन लागत की गणना मुद्रा के रूप में न करके अकुशल श्रमिक के श्रम दिनों में की। इस बात पर विचार नहीं किया कि उत्पादन में क्या खर्चा किया जा रहा है। वे श्रम के रूप में व्यक्त वास्तविक लागत पर ही विचार करते रहे। इन विचारकों का विश्वास था कि किसी वस्तु के उत्पादन में लगाई गई श्रम की मात्रा ही उस वस्तु का सापेक्षिक मूल्य निर्धारित करती है। तुलनात्मक लागत को ज्ञान करने के लिए इन विचारकों ने विभिन्न मान्यताओं का सहारा लिया। मि. ओह्लिन (Ohlin) का कहना है कि—‘रिकार्डों को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि ये मान्यताएँ तथ्यों के अनुरूप नहीं हैं, किन्तु फिर भी उसने इनको अपनाया।’¹ वस्तुओं का तुलनात्मक विवेचन करने के लिए उत्पादन लागत के एक सामान्य सूचक (Common Denominator) की आवश्यकता थी। यदि यह कार्य मुद्रा से नहीं लिया जाता तो उत्पादन के सबसे महत्वपूर्ण घटक श्रम को अपनाना बहुत जरूरी था।

आलोचकों का कहना है कि समस्त उद्योगों में पूँजी और श्रम की लागत का अनुपात बराबर मान लेना तथ्यों के विपरीत है। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें श्रम की लागत पूँजी के व्यय से कई गुना अधिक होती है जबकि अन्य उद्योगों में पूँजी-व्यय श्रम-लागतों से अधिक होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रकार का श्रम भी एक जैसा नहीं होता। एक पत्थर फोड़ने वाले मजदूर का तथा एक भवन का ढकना बनाने वाले अभियन्ता का श्रम एक जैसा नहीं माना जा सकता।

मूल्य का श्रम सिद्धान्त उत्पादन के अनेक नियमों का विवेचन नहीं करता। उत्पत्ति हानि नियम या उत्पत्ति वृद्धि नियम की व्याख्या इनके द्वारा नहीं की जाती। इस नियम द्वारा उत्पादन-लागतों को स्थिर मान लिया जाता है जबकि वे घटती बढ़ती रहती हैं। उत्पादन लागत को निश्चित मान लेने के कारण उत्पादन के विभिन्न साधनों के सापेक्षिक सम्बन्धों एवं सापेक्षिक मूल्यों के पारस्परिक परिवर्तनों को जानना मुश्किल हो गया। मि. वेस्टेबल द्वारा परिवर्तनशील लागतों (Varying Costs) के विचार को अपना कर इस सिद्धान्त के दोषों को दूर करने का प्रयास किया गया।

मूल्य का श्रम सिद्धान्त यह मुना देता है कि कुछ वस्तुओं का मूल्य होता है किन्तु फिर भी उससे श्रम या तो लागत ही नहीं और यदि लागत भी है तो मूल्य के

1 ‘Ricardo was well aware that these assumptions do not correspond to the facts, but he was obliged to accept them’ —*On n. Inter Regional and International Trade, Appendix III, p 571*

अनुपात में नहीं लगता। उदाहरण के लिए ऐतिहासिक स्मृति की चीजें प्रथम मरे हुए लोगों के हस्तक्षर आदि।

इन विभिन्न तर्कों के आधार पर आलोचकों का कहना है कि श्रम-लागत के दृष्टिकोण को छोड़ देना चाहिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विश्लेषण कीमतों के सन्दर्भ में करना चाहिए। कीमतों के आधार पर यह तय किया जाता है कि कौनसी चीजें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में आएँगी और कौन देश उन्हें उत्पन्न करेगा।

(2) यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार नहीं हो सकता।

आलोचकों का यह मत है कि इस सिद्धान्त में चाहे कितनी ही सत्यता रही हो और विभिन्न दृष्टियों से चाहे इसको कितना ही उपयोगी बताया गया हो किन्तु यह निश्चय ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एक उपयुक्त आधार नहीं बन सकता। यह सिद्धान्त किसी एक बाजार में मूल्य-निर्धारण करने की दृष्टि से प्रपञ्चित है। इसे विभिन्न बाजारों के मूल्यों का अध्ययन या आधार तो बनाया ही नहीं जा सकता। इसके प्रतिरिक्त विभिन्न चीजों के उत्पादन में पूँजी की विभिन्न मात्राओं की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु के उत्पादन पर लागत इस बात पर भी निर्भर करती है कि उस देश में पूँजी पर व्याज की दर क्या है। जिस देश में पूँजी के व्याज की दर कम है वह देश वस्तुओं का उत्पादन कम लागत पर कर सकता है, किन्तु जिस देश में पूँजी की कमी है वह केवल ऊँची चीजों का उत्पादन कम लागत पर कर सकेगा जिनमें कम पूँजी की जरूरत होती है। अथवा पर्याप्त मात्रा में होते हुए भी पूँजी की कमी के कारण एक वस्तु की उत्पादन लागत अधिक हो सकती है। व्याज की दर अलग-अलग होने के कारण विश्वयुद्ध के पश्चात् अनेक देशों का व्यापार एवं उत्पादन प्रभावित हुआ।

जो तत्त्व देश की उत्पादन लागत को प्रभावित करते हैं वे सभी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को भी प्रभावित करते हैं। मि. ओहलिन का कहना है कि "मजदूरी और व्याज की दरों में विरोधी दिशाओं में होने वाले परिवर्तन जो कि पूँजी के अधिक उत्पादन के कारण होते हैं उनका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव होना चाहिए किन्तु यह देखा गया है कि संस्थापक अर्थ-शास्त्री इस बात को स्पष्ट करने में असमर्थ रहे। केवल श्रम की ही लागत की इकाई मान लेना पूर्ण रूप से गलत है। पूँजी पर जो व्याज लगता है उसके अनुसार वस्तु की लागत घटती और घटती रहती है।" प्रो. टासिग के मतानुसार "उत्पादन के अन्य घटक मजदूरी से भिन्न नहीं हैं।" तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त में अन्य तत्वों के प्रभाव से कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त का मूल आधार मूल्य के श्रम सिद्धान्त को ही मानना चाहिए। प्रो. ओहलिन इस मत को नहीं मानते हैं।

(3) श्रम के विभिन्न रूप

संस्थापक अर्थ शास्त्रियों की एक अन्य मान्यता भी आलोचना का विषय बनी है। इनका कहना था कि विभिन्न थेली के श्रमिकों को मजदूरी का मुग्तान एक निश्चित स्केल के अनुसार किया जा सकता है और कुशल श्रम को कभी भी अनुश्रुत

श्रम के दिनों में परिवर्तित किया जा सकता है। वे श्रम का तुलनात्मक महत्व निर्धारित करना चाहते हैं और इसी को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बताते हैं। यह व्याख्या वस्तु के सही मूल्य को ज्ञान करने में अधिक सहायक नहीं बनती क्योंकि प्रत्येक श्रम एक ही प्रकार का नहीं होता है। एक देश में मजदूरी की दर में परिवर्तन होने पर उत्पादन लागत में भी परिवर्तन होना लगते हैं और इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त इसकी अवहेलना नहीं कर सकता।

संस्थापक अर्थशास्त्रियों का कहना था कि विभिन्न श्रेणियों के मजदूरों की मजदूरी में जो अन्तर होता है वह पर्याप्त दीर्घकालीन होता है और इसलिए उसका महत्व कम है। आलोचकों का कहना है कि तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की यह कमी रही कि उसने दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन दोनों प्रकार के परिवर्तनों को नहीं समझाया। इसके अतिरिक्त अनेक मजदूर संघों का अस्तित्व प्रतिस्पर्द्धा विहीन समूहों की रचना करता है, इसके कारण मजदूरों में घट-बढ़ होती रहती है। संस्थापक सिद्धान्त में इन परिवर्तनों के कारणों का पूर्ण विवेचन प्रस्तुत नहीं किया है। यदि हम इन परिवर्तनों का विवेचन करें तो तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा। आजकल उत्पादन लागत की गणना श्रम के रूप में नहीं बल्कि मुद्रा के रूप में की जाती है। प्रो. टॉसिंग इस सिद्धान्त का पक्ष लेते हैं। उनका मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य मजदूरी की अनेक श्रेणियों के सम्बन्ध को परिवर्तित नहीं कर सकती।

(4) पूर्ण विशेषीकरण का अभाव

संस्थापक अर्थशास्त्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के विशेषीकरण की जो बात कही वह पूर्ण रूप से लागू नहीं होती। मि. ग्राहम ने अनेक उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया है कि विशेषीकरण हमेशा अपूर्ण होता है। यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में हम दो ऐसे देशों को लें जिनमें एक छोटा है और दूसरा बड़ा तो ऐसी स्थिति में छोटा देश एक वस्तु के उत्पादन में पूर्ण विशेषीकरण प्राप्त नहीं कर पाएगा। विशेषीकरण प्राप्त कर लेने के बाद भी वह बड़े देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकेगा। इसके अतिरिक्त बड़े देश ने जिस वस्तु में विशेषीकरण प्राप्त किया है उसे छोटा देश खरीद नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में बड़ा देश न तो अपने उत्पादित माल की खपत कर पाएगा और न ही अनुत्पादित माल की खरीद कर सकेगा।

यहाँ एक बात ध्यान में रखने योग्य यह है कि सभी वस्तुओं का मूल्य एक जैसा नहीं होता। जिन वस्तुओं का मूल्य कम है उनमें विशेषीकरण प्राप्त करने वाला देश विनिमय में कठिनाई का अनुभव करेगा क्योंकि उसका निर्यात मूल्य उसके आयात मूल्य से कम होगा। ऐसी स्थिति में एक देश को सस्ती चीज के विशेषीकरण पर निर्भर रहने की अपेक्षा अन्य चीजें भी बनानी होंगी। तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त ने इन बातों की कल्पना नहीं की थी, अतः उसे दोषपूर्ण माना जाता है। प्रो. ग्राहम के कथनानुसार "संस्थापक अर्थशास्त्रियों के मत को केवल तभी सही

ठहराया जा सकता है जब हम यह मान लें कि समान उपयोग की वस्तुओं का समान आर्थिक महत्त्व के दो देशों के बीच व्यापार हो रहा है।¹

(5) श्रम की गतिशीलता

संस्थापक अर्थशास्त्रियों ने यह माना था कि श्रम एक देश के अन्तर्गत पूर्ण रूप से गतिशील और दो देशों के बीच वह पूर्ण रूप से गतिहीन होता है। उनकी यह मान्यता सबसे अधिक आलोचना का विषय बनी। वास्तविकता यह है कि श्रम की गतिशीलता एक देश के विभिन्न प्रदेशों में पूर्ण नहीं होती और न ही यह दो देशों के बीच पूर्ण रूप से अनुपस्थित रहती है। मि. केयरनेस का कहना था कि "प्रतिस्पर्धा-विहीन वर्गों की विशेषता न केवल एक देश की आन्तरिक व्यवस्था में पाई जाती है बल्कि यह विभिन्न देशों के बीच भी मिलती है।" एक देश के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले लोग स्वतन्त्रता एवं सुविधा के साथ स्थानान्तरण नहीं कर सकते। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के साधनों की गतिहीनता मूल रूप से श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण का प्रभाव है। एक देश जब विशेषीकरण प्राप्त कर लेता है तो उसके श्रमिक अन्य ऐसे देश में नहीं जाना चाहते जिसे किसी अन्य कार्य में विशेषीकरण प्राप्त है।

(6) यातायात-व्यय की उपेक्षा

संस्थापक अर्थशास्त्रियों के तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त का एक अन्य दोष यह है कि उसने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर विचार करते समय यातायात-व्यय पर ध्यान नहीं दिया। कुछ वस्तुओं के उत्पादन में यह देखा जाता है कि यातायात का व्यय उत्पादन लागतों की उपेक्षा नहीं अधिक है। किसी वस्तु का आयात या निर्यात केवल तभी किया जा सकता है जब उत्पादन लागत या यातायात व्यय दोनों को मिलाकर देखने पर कुल व्यय कम आए। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस सम्बन्ध में सुझाव दिया है कि उत्पादन लागत में यातायात व्यय को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए और इसे निर्यातकर्ता देश को वहन करना चाहिए। यह मत सही न था।

यातायात व्यय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को इतना प्रभावित करता है कि जो वस्तु देश के एक भाग में बनती है वही दूसरे भाग में आयात की जाती है। यदि उसे देश के दूसरे भाग से मंगाया जाए तो यातायात व्यय मिलाकर लागत उतनी हों जाएगी जितनी अन्य देश से आयात करने पर भी नहीं होती।

(7) सामरिक कारणों की उपेक्षा

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सामरिक महत्त्व के प्रश्नों के प्रभाव की अवहेलना करता है। वर्तमान विश्व में सामरिक कारणों से प्रत्येक देश यह प्रयत्न करता है कि दूसरे देशों पर आर्थिक नियंत्रण रहे और स्वदेशी

1 "The conclusion of the classicist can hold true only if the dice are loaded by assuming trade in two commodities of approximately equal total consumption value and between two countries of approximately equal economic importance"

उद्योगों को प्रोत्साहन दें। इस दृष्टि से कुछ चीजें प्राकृतिक सुविधाओं के अभाव में भी स्वदेश में ही उत्पन्न की जाती हैं। ऐसा न किए जाने पर देश की आत्म-निर्भरता और स्वतन्त्रता खतरे में पड़ जाती है।

(8) सिद्धान्त की जटिलता

आलोचकों ने तुलनात्मक लागत सिद्धान्त को अत्यन्त जटिल एवं अवास्तविक कहकर भी उसे आलोचना का विषय बनाया है। यह अपनी जटिलता के कारण ही विभिन्न देशों में स्थित पूर्ण लागत भिन्नताओं पर प्रत्यक्ष रूप से विचार नहीं कर पाता। इस सिद्धान्त द्वारा हम यह नहीं जान पाते कि यदि कोई चीज सस्ती उत्पन्न हुई है तो कम मजदूरी, कम व्याज, कम धातायात आदि कारणों ने उसके सस्तेपन पर कहाँ तक प्रभाव डाला है। लागत के अन्य सभी तत्वों को छोड़ कर यह केवल श्रम की उत्पत्ति के आधार पर ही विचार करता है। इसके साथ-साथ इस सिद्धान्त की जटिलता में एक बात यह भी है कि इसने दो देशों और दो वस्तुओं के सम्बन्ध में ही अपने विचारों को प्रतिपादित किया है जबकि वास्तविकता यह है कि ससार में हमेशा अनेक वस्तुएँ एवं विभिन्न देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेते हैं।

(9) केवल पूर्ति पर विचार

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त केवल पूर्ण पक्ष पर ही विचार करता है। यह माँग पक्ष पर या तो विचार ही नहीं करता और यदि करता भी है तो बहुत ही कम। इसमें इस बात पर विचार किया जाता है कि एक देश किन वस्तुओं को खरीदेगा और किन वस्तुओं का निर्यात करेगा। यह स्पष्ट नहीं किया जाता कि इन वस्तुओं का व्यापार किन कीमतों पर किया जाएगा। जब तक माँग पक्ष का अध्ययन नहीं किया जाता तब तक केवल पूर्ति का यह अध्ययन अपर्याप्त समझा जाएगा।

(10) लागत की अपेक्षा कीमत का महत्त्व

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त लागत को अधिक महत्त्व देता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार लागतों की भिन्नताओं को मानकर चलता है जबकि वास्तविकता यह है कि आयात कर्ता और निर्यात कर्ता दोनों ही देश लागतों की इतनी चिन्ता नहीं करते, जितना वे उनके द्वारा बुकाई या प्राप्त की जाने वाली कीमतों की करते हैं। इस दृष्टि से कीमतों का अन्तर ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है।

(11) कुछ अन्य दोष

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की उपर्युक्त आलोचनाओं के अतिरिक्त इसके कुछ अन्य दोष भी हैं जो इसे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य परिवर्तनों का अध्ययन करने में असम बना देते हैं। इन दोषों में से कुछ को दूर किया जा सकता है किन्तु फिर भी वे इस सिद्धान्त से घनिष्ठ रूप में जुड़े हुए हैं। इसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारणों का स्पष्टीकरण करते समय अनेक अवास्तविक बातों का सहारा लिया जाता है। यह सरल रूप में इस बात को स्पष्ट

नहीं करता कि एक देश में उत्पादन लागत कम क्यों आई। उत्पादन लागत की कमी के कारणों की खोज के लिए यह जिन तरीकों को अपनाता है वे इतने जटिल होते हैं कि किसी निष्कर्ष पर पहुँचाने की अपेक्षा हमको भ्रम में डाल देते हैं। केवल दो देशों और दो वस्तुओं को घटने अध्ययन का आधार बनाने के कारण यह सिद्धान्त उनके अर्थाध्यनीय निष्कर्षों को जन्म देता है। प्रो. मंगोल्ड (Mangoldt) का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केवल पूर्ति अथवा तुलनात्मक लागत पर ही नहीं वरन् माँग की वशाओं पर भी निर्भर करता है। प्रो. ओहलिन की मान्यता थी कि "तुलनात्मक लागत सिद्धान्त केवल पूर्ति की परिस्थिति का संक्षेप में वर्णन करता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या बहुत कम करता है।"¹ यह सिद्धान्त केवल उसी समय उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहता है जब दो देशों और दो वस्तुओं के बारे में विचार किया जाता है।

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त में किए गए परिवर्तन (Modification in Theory of Comparative Cost)

संस्थापक अर्थशास्त्रियों ने जिस तुलनात्मक लागत सिद्धान्त को प्रतिपादित किया वह केवल कुछ निश्चित परिस्थितियों में ही सत्य सिद्ध हो सकता था। यदि हम इन परिस्थितियों को अमान्य ठहरा दें तो पूरा सिद्धान्त ही महत्वहीन बन जाता है। जिन मान्यताओं के आधार पर इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया उनको यदि हटा दिया जाए अथवा सुधार दिया जाए तो निष्कर्ष या तो बदल जायेंगे या विपरीत आयेंगे।

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की उक्त भालोबनाओं का भय यह नहीं है कि सिद्धान्त पूर्ण रूप से महत्वहीन है। समय-समय पर अर्थशास्त्रियों ने इसमें संशोधन किए और इसे छोड़ने की अपेक्षा सुधार करने की दृष्टि से कुछ सुभाव प्रस्तुत किए। ये निम्न प्रकार हैं—

(1) वस्तु की लागत का मापदण्ड धर्म की अपेक्षा मुद्रा को बनाया जाए। आधुनिक अर्थशास्त्री मूल्य के धर्म सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते। उनका विचार है कि वस्तु की लागत में धर्म के अतिरिक्त अन्य तत्त्व भी होते हैं। आगकल मूल्य को धर्म सिद्धान्त की अपेक्षा सीमान्त लागत (Marginal Cost) के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऐसी स्थिति में तुलनात्मक लागत सिद्धान्त को भी सीमान्त लागत के रूप में प्रकट किया जाना चाहिए।

(2) व्यापार शर्तों में वस्तुओं की तुलनात्मक माँग की लोच द्वारा डाले गए प्रभाव को सम्मिलित करना चाहिए। तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के समर्थकों ने बताया था कि विदेशी व्यापार में विनिमय की दरों की सीमाएँ तुलनात्मक

1 "Hence the comparative cost reasoning alone explains very little about international trade. It is indeed nothing more than an abbreviated account of condition of supply."—Ohlin : *Inter-Regional and International Trade*, p. 586

लागत के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। किन्तु वे यह नहीं बता सके कि लाभ की मात्रा किन बातों पर निर्भर करती है। इन विचारकों का मन था कि विनिमय का अनुपात बाजार में वस्तु के मोलभाव द्वारा तय होता है किन्तु आज के अर्थशास्त्री मानते हैं कि विनिमय की शर्तें मूल भाव पर नहीं बरन् एक देश की माँग की लोच पर निर्भर रहती है। जिस देश में दूसरी वस्तुओं की तुलनात्मक लोच अधिक अनुकूल होती है उसके लिए व्यापार शर्तें अधिक अनुकूल होगी। इस सुझाव से तुलनात्मक लागत सिद्धान्त अधिक व्यावहारिक बन जाता है।

(3) विचारकों का सुझाव है कि उत्पत्ति वृद्धि और उत्पात्ति ह्रास नियमों को भी इस सिद्धान्त पर लागू किया जाए। रिकार्डों आदि सस्यावकों का मत था कि व्यापार में सत्तन दोनों देशों के बीच उत्पत्ति समता का नियम लागू होता है और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में यातायात का खर्च कोई महत्त्व नहीं रखता। आधुनिक अर्थशास्त्री इस बात को स्वीकार नहीं करते। इन विचारकों ने उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पात्ति समता नियम का समान रूप से प्रभावशील माना है। इसके अतिरिक्त वे यातायात व्यय को भी महत्त्व देते हैं। उनके मतानुसार घटती हुई लागतें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देती हैं और बढ़ती हुई लागतें उसे हतोत्साहित करती हैं।

वर्तमान काल में इस सिद्धान्त के अन्तर्गत कुछ नवीन विकास और भी हुए हैं। मि० जे० एस० मिल ने अपनी पुस्तक "प्रिंसोपल्स ऑफ पोलिटिकल इकनामी" में तुलनात्मक लागत सिद्धान्त का विस्तार करके उसमें अन्तर्राष्ट्रीय माँग समीकरण को समाविष्ट कर दिया है। प्रो० माथल इससे सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं को स्पष्ट करने के लिए रेखाचित्रों का सहारा लेते हैं।

कुछ अन्य सशोधन

(Some other Refinements)

विचारकों ने तुलनात्मक लाभ के नियम को सशोधित करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। इन दृष्टिकोणों के अनुसार तुलनात्मक लाभ के सिद्धान्त के मूल रूप में कुछ सशोधन किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित महत्त्व रखते हैं—

पारस्परिक पर-निर्भरता का सिद्धान्त

(The Mutual Inter-dependence Theory)

आधुनिक विचारकों ने मूल्य के श्रम सिद्धान्त को पूर्णतः सन्तोषजनक मानने से अस्वीकार कर दिया और कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त को मूल्य के अन्य सिद्धान्त के रूप में अभिव्यक्त किया जाए। वर्टिल ओह्लिन (Vertil Ohlin) नामक स्वीडिश अर्थ शास्त्री ने पारस्परिक पर-निर्भरता का मूल्य का सिद्धान्त प्रतिपादित किया। यह सिद्धान्त पूँति, माँग और कीमतों की पारस्परिक निर्भरता पर जोर देता है। इसके अनुसार कीमते माँग और पूँति की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा

निर्धारित होती है किन्तु स्वयं भाँति तथा पूर्ति कीमतों से प्रभावित होती है। यह सिद्धान्त यद्यपि सत्स्थापक सिद्धान्त की अपेक्षा कम सरल या फिर भी अधिकोश सीमित मान्यताओं में विश्वास किए बिना ही यह वास्तविक सत्सार के विषयों पर विचार करने में सफल हो सका।

सत्स्थापक सिद्धान्त की भाँति पर-निर्भरता का सिद्धान्त भी इस मान्यता से प्रारम्भ होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार विभिन्न देशों के मध्य स्थित लागत भिन्नताएँ हैं। वस्तुओं के उत्पादन की लागत का अन्तर केवल उनमें लगाए गए धन पर ही निर्भर नहीं है। उत्पादन की अन्तिम लागत एक संयुक्त लागत है जो उत्पादन के विभिन्न तत्त्वों पर निर्भर है। विभिन्न देशों में उत्पादन के साधनों का संयोग भिन्न होता है और इसीलिए यह तथ्य उत्पादन की लागत में अन्तरों का कारण बनता है। मूल रूप से विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में अन्तर उन देशों में उत्पादन के विभिन्न साधनों की सापेक्षिक स्थिति का परिणाम है। यदि दो देशों में उत्पादन के तत्त्वों की स्थिति एक जैसी हो तो उन वस्तुओं की कीमत में सापेक्षिक अन्तर नहीं होंगे और इस प्रकार उनके बीच अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार ही समाप्त हो जाएगा।

उक्त विशेषण को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए भारत में भूमि अपेक्षाकृत अधिक है और धन तथा पूँजी तुलनात्मक रूप से कम है। इस प्रकार भूमि एक सस्ता साधन है जबकि धन और पूँजी महँगी है। इसके परिणामस्वरूप भारत ऐसी चीजों का निर्यात करेगा जिनके उत्पादन में अधिक भूमि और कम धन तथा पूँजी की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर मान लीजिए रूस में पूँजी और धन की अपेक्षा भूमि कम है तो वह भूमि अधिक महँगी पड़ेगी और वह उन चीजों का निर्यात करेगा जिनके उत्पादन में भूमि की अपेक्षा धन पूँजी की अधिक आवश्यकता है। इस प्रकार भारत और रूस दोनों देशों के बीच निर्यात और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार मिल जाता है। दोनों देश एक-दूसरे के पूरक बन जाते हैं और तुलनात्मक लाभ का नियम यथावत् बना रहता है।

अधिकार की सीमाएँ

(Limits of Specialisation)

विशेषीकरण के माध्यम से एक देश चाहे तो लाभ प्राप्त कर सकता है। प्रश्न यह है कि एक देश व्यवहार में केवल उसी क्रिया में विशेषीकरण क्यों नहीं करता जिसमें उसे सबसे अधिक तुलनात्मक लाभ है। देश में विभिन्न उद्योग उत्पादन के साधनों के लिए प्रतियोगिता करते हैं। व्यवस्था की दुनिया में विशेषीकरण कुछ महत्वपूर्ण तत्त्वों के कारण आता है। ये निम्न प्रकार हैं—

1. जो देश प्रशुल्क जैसी नीति अपनाते हैं उनकी प्रतियोगिता में अग्रिम उद्योग पर्याप्त कठिनाई में पड़ जाते हैं। इस प्रकार के मानव-कृत प्रतिवन्धों से उद्योग की जीवन का आश्वासन तो मिल जाता है किन्तु उनके विकास की प्रक्रिया प्रकायंकुशल बन जाती है।

2 विशेषीकरण को बाजार की व्यापकता और यातायात लागत द्वारा भी प्रीमित किया जाता है। दूसरे स्थानों तक माल पहुँचाने में जो यातायात लागत आती है वह इसकी कीमत को बढ़ा देती है। कभी-कभी एक कार्यकुशल उत्पादक के उत्पादन की लागत कम कार्यकुशल उत्पादक की अपेक्षा इसी कारण अधिक प्राती है।

3 कुछ उद्योगों में अपने विकास पर स्वयं सीमा लगाने की प्रकृति होती है। एक सीमा के परे किसी उद्योग को तुलनात्मक लाभ नहीं रहता। इसका कारण यह हो सकता है कि एक विशेष प्रकार का उत्पादन उम्र देश में लागत वृद्धि नियम का विषय हो। ऐसी स्थिति में एक निश्चित उत्पादन के बाद तुलनात्मक लाभ स्वयं ही तुलनात्मक हानि में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि विश्व में गेहूँ की कीमत एक रुपया प्रति किलो है। ऐसी स्थिति में भारत अपनी कुछ भूमि का प्रयोग गेहूँ के उत्पादन के लिए लाभपूर्ण रूप में कर सकता है। यह भूमि इतनी सीमित है कि कुल घरेलू माँग को इस उत्पादन से पूरा न किया जा सके। यदि कम वांछनीय अतिरिक्त भूमि को गेहूँ उपजाने के लिए काम में लाया है तो इसके लिए गेहूँ की ऊँची कीमतें होनी चाहिए। ये कीमतें स्वतन्त्र बाजार में प्राप्ताती से प्राप्त नहीं की जा सकती क्योंकि वहाँ अतिरिक्त पूर्ण को विदेशों में सस्ती कीमत पर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के उदाहरण पर्याप्त सामान्य हैं। जैसे कुछ कोयला अपनी खानों से प्राप्त करता है और कुछ आयात भी करता है, इपूवा में बावल पैदा किया जाता है किन्तु कुछ का आयात भी किया जाता है। समुक्त राज्य अमेरिका में कुछ सोया खानों में से निर्यात आता है किन्तु कुछ का आयात किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी देश को एक सीमा तक ही अपने उत्पादन में तुलनात्मक लाभ रहता है। उसके परे वह हानि की ओर मुड़ जाता है और वह अपने उपभोग के कुछ भाग को घरेलू उत्पादन द्वारा पूरा करता है और गैर के लिए आयात करता है।

बहुदेशीय व्यापार

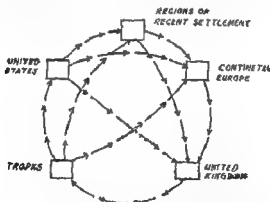
'Multi-country Trade')

जब 'क' और 'ख' दो देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होता है (जो कि जब दो देशों तक ही होता है) तो 'क' देश 'ख' देश को गेहूँ का निर्यात करता है। और बदले में व्याप प्राप्त करता है। 'क' देश इन रूपों का प्रयोग 'ख' देश से खरीदे गए कपड़े की कीमत चुकाने में कर सकता है। यदि दो देशों के कुल आयात और निर्यात इस प्रकार संतुलित रहते हैं तो इसे नेट्रो का द्विपक्षीय संतुलन कहा जाएगा। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की एक अन्य प्रक्रिया भी है जिसमें न केवल दो बरन् न केवल दो देश भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए कॉफी बेचने पर अमेरिका से ब्राजील को डॉलर प्राप्त हुए हैं वह उन्हें ग्रेट-ब्रिटेन से खरीदी जाने वाली मशीनों पर खर्च कर सकता है। ग्रेट-ब्रिटेन ब्राजील द्वारा प्रदान किए गए डॉलरों को दूसरे देश में योगाये स्वीकार कर लेता है। वह इनका प्रयोग अमेरिका से खाद्यान्न खरीदने में कर सकता है। इस प्रकार कुल मिलाकर अमेरिका ने ब्राजील की कॉफी के लिए

सात्वान्न का विनियम किया। जब व्यापार में अनेक देश भाग लेते हैं तो उसे बहुपक्षीय (Multilateral) व्यापार कहा जाता है।

बहुपक्षीय व्यापार के अन्तर्गत होने वाले लेन-देन की तुलना घरेलू अर्थ-व्यवस्था में व्यक्तिगत बैंक लिखने से की जा सकती है। यदि मि. 'क' खरीदे गए माल के लिए व्यक्तिगत बैंक प्रदान करता है तो मि. 'ख' के द्वारा उसे 'क' के बैंक में भुनाया जा सकता है। यदि मि. 'ख' चाहे तो इस बैंक को दूसरी वस्तुओं के भुगतान के रूप में मि. 'ग' को भी दे सकता है और मि. 'ग' इसे मि. 'घ' को दे सकता है और इसी प्रकार घूमता हुआ यह बैंक मि. 'क' के पास लौटकर आ सकता है। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि मि. 'ग' और 'घ' के पास मि. 'क' का बैंक आया किन्तु उन्होंने मि. 'क' से प्रत्यक्ष रूप से लेन-देन नहीं किया था।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की बहुपक्षीय प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए विश्व को कुछ मोटे-मोटे व्यापारिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। ये हैं—अयनवृत (अफ्रीका, एशिया और लेटिन अमेरिका में अयनवृत देश); संयुक्तराज्य अमेरिका, आधुनिक समझौते के देश (दक्षिणी अफ्रीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, चिली तथा दूसरे अनेक देश-महाद्वीपीय यूरोप और ग्रेट-ब्रिटेन)। यदि हम सन् 1928 में इन क्षेत्रों में व्यावसायिक वस्तुओं के व्यापार का विश्लेषण करें तो पाएँगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अयनवृत को छोड़कर सभी क्षेत्रों को प्रतिरक्ष में निर्यात किया। वर्तमान समझौते वाले क्षेत्रों ने महाद्वीपीय यूरोप और ग्रेट-ब्रिटेन को प्रतिरक्ष में निर्यात किया किन्तु अन्य सभी क्षेत्रों से अनिश्चय में आयात किया। इन तथ्यों को निम्नलिखित रेखाचित्र द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है।



The System of Multilateral Trade

बहुपक्षीय व्यापार का आर्थिक लाभ यह है कि इससे प्रत्येक व्यक्ति उन विदेशी स्रोतों से आयात कर सकता है जो व्यावसायिक वस्तुओं की सर्वश्रेष्ठ किस्म कम कीमत पर प्रदान कर सकता है। इस प्रकार बहुपक्षीय व्यापार विश्व उत्पादन के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करता है।

हैकशर-ओहलिन सिद्धान्त एवं साधन मूल्य समानीकरण (HECKSCHER-OHLIN THEORY AND FACTOR PRICE EQUALIZATION)

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार माना परन्तु इन अर्थशास्त्रियों ने केवल मात्र श्रम को ही उत्पादन का एक मात्र साधन माना था।

आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन के अन्य साधनों को भी लागत विभेदण में सम्मिलित किया है। उन्होंने देग के पास उपलब्ध सभी साधनों के आधार पर देश की उत्पादन-क्षमता एवं तुलनात्मक लाभ का निरूपण किया। आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्तों में श्रम की प्रवेक्षा कुल साधन को आधार बनाया गया और प्रत्येक वस्तु की अवसर लागत के आधार पर विशिष्टीकरण एवं विदेशी व्यापार की सम्भावनाओं की समीक्षा की गई है।

इन्हीं आधुनिक अर्थशास्त्रियों में प्रमुख स्थान हैकशर को दिया जाता है। हैकशर के विचारों की विस्तृत व्याख्या ओहलिन ने की और इसी कारण इनके द्वारा प्रस्तुत सिद्धान्त को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का "हैकशर-ओहलिन सिद्धान्त" कहा जाता है।

ग्रली हैकशर का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विचार

ओहलिन की पुस्तक के प्रकाशन से पहले ग्रली हैकशर ने सन् 1919 में एक लेख लिखा था, जिसमें विदेशी व्यापार के प्रभाव की व्याख्या की गई थी, विशेषरूप से भूमि, पूँजी तथा श्रम के बीच आय के वितरण का अनुमान था। हैकशर ने सबसे पहले विभिन्न देशों में तुलनात्मक लागतों के अन्तर के कारण की विवेचना करने का प्रयास किया। यदि दो देशों में उत्पादन के साधनों की सापेक्ष दुर्लभता समान है तो उन दोनों देशों में साधनों की सापेक्ष कीमतें भी समान हागी तथा उनके बीच विदेशी व्यापार असम्भव होगा। हैकशर ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यक शर्तों को इस प्रकार वर्णित किया है—

(i) भिन्न-भिन्न सापेक्ष दुर्लभता, अर्थात् विनिमय की स्थितियों में उत्पादन के साधनों की सापेक्ष कीमतों में भिन्नता ।

(ii) विभिन्न वस्तुओं में प्रयुक्त उत्पादन के साधनों के बीच अनुपातों में भिन्नता ।

(iii) हैबशर ने यह भी मान लिया था कि यह अनुपात (सामान्यतः प्राकृत निरन्तर गुणक के रूप में) अपरिवर्तनीय रहते हैं ।

हैबशर का मत है कि एक और विदेशी व्यापार उत्पादन के उन साधनों को बढ़ती हुई दुर्लभता को उत्पन्न करता है जो कि अन्यथा आयातित वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग किए जा सकते थे । अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या साधनों की दुर्लभता में होने वाली वृद्धि अथवा कमी एक साथ साम्य उत्पन्न करती है ? तथापि हैबशर ने एक उदाहरण से यह स्पष्ट किया कि विदेशी व्यापार से एक नया साम्य तथा भाष का पुनर्वितरण उत्पन्न हो जाता है ।

ओहलिन का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

ओहलिन के मतानुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त मूल्य के सामान्य साम्य सम्बन्धी सिद्धान्त पर आधारित है और इसी का एक विस्तार मान है । मूल्य का सामान्य साम्य सिद्धान्त अर्थशास्त्र में अपना विशेष महत्त्व रखता है, इसके अनुसार यह माना जाता है कि किसी वस्तु की कीमत उसकी माँग और पूर्ति द्वारा निर्धारित की जाती है । एक वस्तु की माँग पर अनेक बातों का प्रभाव पड़ता है । जैसे—उपभोक्ताओं की आवश्यकताएँ, प्राथमिकताएँ, इच्छाएँ, उनकी आय, अन्य वस्तुओं की उपलब्धता और उनकी कीमत आदि । दूसरी वस्तु की पूर्ति उसके उत्पादन के साधनों की उपलब्धि पर निर्भर करती है । जहाँ वस्तु की माँग और पूर्ति के बीच साम्य स्थापित हो जाता है वहाँ उसकी कीमत निर्धारित हो जाती है । वस्तु की कीमत उसकी उत्पादन लागत के बराबर होती है, लाभ का सीमान्त भी लागत में शामिल है । किसी वस्तु की उत्पादन लागत उन सभी साधनों की कीमत का योग होती है जो वस्तु के उत्पादन में सहयोगी बनते हैं ।

ओहलिन ने तुलनात्मक सापेक्ष सिद्धान्त की आलोचना अन्तर्राष्ट्रीय विशेषीकरण और व्यापार की विशेष प्रकृति की आलोचना द्वारा की । ओहलिन ने अन्तर्राष्ट्रीय विशेषीकरण की प्रकृति को निर्धारित करने वाली शक्तियों का स्पष्टीकरण किया है । ओहलिन के अनुसार सामान्य मूल्य सिद्धान्त, एक बाजार सिद्धान्त है तथा समय तत्त्व पर बल देता है । इसके विपरीत, अन्तर्देशीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के इस परम्परागत सिद्धान्त के द्वारा स्थान तत्त्व की अवहेलना की गई है । ओहलिन के मत में स्थान तत्त्व व्यापार में एक महत्वपूर्ण तत्त्व है, विशेषतया, क्योंकि वस्तुओं तथा साधनों की गतिशीलता स्थान तत्त्व द्वारा सीमित होती है । अतः विभिन्न बाजारों में मूल्यों का निर्धारण एक साथ मिला जाना चाहिए । संक्षेप में, लौकिक एक बाजार सिद्धान्त की जगह ओहलिन का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापक सिद्धान्त 'एक बहुबाजार मूल्य सिद्धान्त' को महत्त्व देता है ।

यदि दो वस्तुएँ X व Y हैं तो

$$\frac{K}{L}(X) \text{ in } A = \frac{K}{L}(X) \text{ in } B$$

$$\text{अथवा } \frac{K}{L}(Y) \text{ in } A = \frac{K}{L}(Y) \text{ in } B$$

$$\text{लेकिन } \frac{K}{L}(X) \neq \frac{K}{L}(Y)$$

3. साधनों में समरूपता—दोनों देशों में उत्पादन के साधनों में गुणात्मक समरूपता होनी चाहिए ।

4. साधनों की गतिशीलता—उत्पादन के साधन देश के भीतर पूर्ण रूप से गतिशील हैं परन्तु एक देश से दूसरे देश के बीच साधनों की गतिशीलता सम्भव नहीं है ।

5. शून्य यातायात एवं बीमा व्यय—केवल उत्पादन लागतों के अन्तर के कारण ही तुलनात्मक लाभ प्राप्त होते हैं । इसी कारण इस सिद्धान्त में यातायात व्यय, बीमा व्यय व टटकर व्यय शून्य माने गए हैं ।

6. पैमाने का समान प्रतिक्रम—उत्पादन के एक साधन के सन्दर्भ में तो सीमान्त उत्पादकता घटती है परन्तु सभी साधनों में प्रानुपातिक परिवर्तन करने पर पैमाने का समान प्रतिक्रम प्राप्त होता है ।

7. साधनों की स्थिर मात्राएँ—उत्पादन के साधनों की मात्राएँ दोनों देशों में स्थिर है । भूमि के अतिरिक्त धन व पूँजी की मात्रा स्थिर होने का अर्थ यह है कि जनसंख्या एवं पूँजी-स्टॉक की शुद्ध वृद्धि-दर शून्य मानी जाती है । नवीन पूँजी-निर्माण की इस कारण हम सिद्धान्त में उपेक्षा कर दी गई है । यही नहीं, यह भी माना जाता है कि उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग (Full Employment) हो रहा है ।

8. साधनों व वस्तुओं के बाजारों में प्रत्येक देश में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान है । लाभ ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । इनके फलस्वरूप देश के भीतर एवं दो देशों के मध्य किसी वस्तु के मूल्यों में कृत्रिम अन्तर घटाने की सम्भावना नहीं होगी । केवल साधनों की उपलब्ध मात्रा के कारण उत्पादन लागतों में जो अन्तर है वही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है ।

9. इस मॉडल में दो देशों तथा दो वस्तुओं को ही शामिल किया गया है । साथ ही उत्पादन के दो ही साधनों पूँजी (K) और धन (L) को ही इस सिद्धान्त में लिया गया है ।

10. साधन की माँग—इस सिद्धान्त में दोनों देशों के साधनों में से एक साधन की माँग समान मानी गई है । इसका कारण यह है कि इस सिद्धान्त के अन्तर्गत देश की उपलब्ध साधनों की मात्रा की अपेक्षा उनके सापेक्ष मूल्यों को आधार बनाया गया है ।

उपरोक्त मान्यताओं में सबसे महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि दो देशों में साधन देने (Factor-Endowments) प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हैं। यदि देश A में पूँजी की बहुतायत है तो यह पूँजी-प्रधान वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर उसका निर्यात करेगा। इसके विपरीत थम-प्रधान देश थम प्रधान वस्तुओं का निर्यात करेगा। परन्तु साधनों के मूल्य भी इनकी पूर्ति के अनुरूप भिन्न होंगे। जो साधन किसी देश में प्रचुर मात्रा में है उसका मूल्य अन्यथा लागत दुर्लभ साधन के मूल्य की तुलना में कम होना चाहिए। इसी आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि यथा सम्भव प्रत्यक्ष देश उत्पादन की विधि को भी इस प्रकार से समायोजित करेगा कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध परन्तु कम मूल्य वाले साधन का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग किया जाए। जैसे कि भारत में थम का वाहुल्य होने के कारण पूँजी की अपेक्षा थम सन्ना है और इसी कारण इस सिद्धान्त के अनुसार यहाँ थम प्रधान तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए।

विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन हेतु उत्पादन के साधनों के प्रत्यक्ष संयोग (Combination) लिए जा सकते हैं परन्तु इष्टतम संयोग का निर्धारण साधनों के सापेक्ष मूल्यों द्वारा ही होगा। अब हम उत्पादन फलन के माध्यम से इस सिद्धान्त की व्याख्या करेंगे।

क्योंकि हैवशर-प्रोहलिन सिद्धान्त में दो वस्तुएँ तथा दो ही साधन लिए गए हैं, दोनों वस्तुओं के उत्पादन-फलन का फननिक रूप इस प्रकार होगा।

$$\begin{aligned} Q_x &= f(K, L) \\ Q_y &= F(K, L) \\ \text{जहाँ } Q_x &= X \text{ वस्तु की मात्रा,} \\ Q_y &= Y \text{ वस्तु की मात्रा,} \\ K &= \text{पूँजी} \\ \text{और } L &= \text{थम है।} \end{aligned}$$

परन्तु मान्यता के अनुसार X व Y वस्तु के उत्पादन में साधन के अनुपात भिन्न हैं।

$$\therefore \frac{L}{K_x} \neq \frac{L}{K_y}$$

यदि X थम प्रधान एवं Y पूँजी प्रधान वस्तु है, तो

$$\frac{L}{K_x} > \frac{L}{K_y}$$

परन्तु X के उत्पादन में दोनों देशों में साधनों का अनुपात वही है मत

$$\frac{L}{K}(X) \text{ in A} = \frac{L}{K}(X) \text{ in B}$$

$$\text{और } \frac{L}{K}(Y) \text{ in A} = \frac{L}{K}(Y) \text{ in B}$$

उत्पादन का यह स्तर प्राप्त करेंगे। साम्य बिन्दुओं पर उत्पादन करने पर देश A एवं B को 10 इकाइयों के उत्पादन से 20 रुपए की कुल लागत वहन करनी पड़ती है। परन्तु जैसा कि स्पष्ट है कि P एवं R बिन्दुओं पर न्यूनतम लागत मुक्त उत्पादन केवल उस स्थिति में होना होता है जबकि देश A में पूँजी प्रधान व देश B में श्रम-प्रधान उत्पादन विधि प्रयुक्त की जाए।

अब माना कि A में श्रम प्रधान प्राविधि का उपयोग होने लगता है। उसका साम्य बिन्दु P से P_1 हो जाएगा परन्तु ऐसी स्थिति में उत्पादन की मात्रा वहीं रहने पर भी लागत 20 रु से बढ़कर 40 रु हो जाएगी। इसी प्रकार यदि B में पूँजी प्रधान प्राविधि का उपयोग करना चाहिए तो उसका साम्य स्तर R से R_1 हो जाएगा, परन्तु उत्पादन की मात्रा वहीं रहने पर भी लागत 20 रु से बढ़कर 40 रु हो जाएगी। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह होगा कि प्रवृत्ति ने देशों को जो मापन प्रचुर मात्रा में दिया है, वह वही सन्ता होगा तथा इस मापन का अधिक उपयोग किया जाकर ही न्यूनतम लागत पर उत्पादन किया जा सकता है। इस सिद्धान्त की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अनुसार प्रत्येक देश उस वस्तु का निर्माण करेगा जिसके उत्पादन में उपलब्ध मापन का उपयोग होना हो। इसके विपरीत देशों के वस्तुओं कायापन करनी चाहिए जिनके परे लू उत्पादन में अपेक्षाकृत दुर्लभ एवं अपेक्षाकृत महँगे साधनों का अधिक उपयोग करना पड़ता हो।

साधनों के उपयोग सम्बन्धी निर्णय साधनों की मात्रा एवं इनके सापेक्ष मूल्यों के आधार पर लिए जाते हैं। विभिन्न देशों में विशिष्टीकरण की प्रवृत्ति भी साधनों के मूल्यों पर निर्भर करनी है और यही कारण है कि अलग-अलग वस्तुओं की उत्पादन-लागत भी अलग-अलग होगी। इस सिद्धान्त के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रारम्भ भी इसी आधार पर होगा कि किसी वस्तु को कोई देश उपलब्ध साधनों से न्यूनतम लागत पर कैसे तैयार कर सकता है। न्यूनतम लागत उस स्तर पर होगी जहाँ साधनों के सापेक्ष मूल्यों के आधार पर ही उत्पादन प्राविधि का चुनाव किया जाए।

हैक्शर-ओहलिन सिद्धान्त की आलोचना

(Criticism of the Heckscher-Ohlin Theory)

यद्यपि हैक्शर-ओहलिन सिद्धान्त प्रतिष्ठित सिद्धान्त से श्रेष्ठ है परन्तु इस सिद्धान्त की निम्नलिखित आलोचनाएँ की जाती हैं—

(अ) अवास्तविक मान्यताएँ—यह सिद्धान्त भी अनेक अवधारित मान्यताओं पर आधारित है जैसे—

(i) इस सिद्धान्त में यह माना गया है कि वस्तु बाजार और साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान है परन्तु आधुनिक सन्दर्भ में यह मान्यता पूर्णतया असंगत है।

(ii) इस सिद्धान्त में परिवहन लागतों को शून्य माना जाता है जबकि व्यवहार में ये अन्तर्राष्ट्रीय-व्यापार को काफी प्रभावित करती हैं।

(in) इस सिद्धान्त की यह मान्यता भी अनुचित है कि दोनों देशों में प्रत्येक वस्तु की उत्पादन श्रविधि समान रहती है और केवल साधनों की उपलब्ध निधि (Factor endowment) एवं तदनुसूची साधन मूल्यों के सापेक्ष अन्तर के कारण ही विशिष्टीकरण एवं अन्तर्राष्ट्रीय-व्यापार का जन्म होता है।

(iv) इस सिद्धान्त में यह मान लिया गया है कि उत्पादन के साधन विभाजनशील होते हैं और उत्पादन फलन एक सरल, सतत्, समरूप और उन्नतोदर होता है इसका अर्थ यह है कि एक साधन की मात्रा में वृद्धि करने मात्र से उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि नहीं होगी (उत्पत्ति ह्रासमान नियम की क्रियाशीलता के कारण) परन्तु सभी साधनों में आनुपातिक वृद्धि के द्वारा उत्पादन में भी उतनी ही वृद्धि करना सम्भव है। परन्तु व्यावहारिक जीवन में न तो उत्पादन के साधन पूर्णतया विभाजनीय होते हैं और न ही इस प्रकार के उत्पादन फलन ही देखने को मिलते हैं।

(v) ओहलिन के सिद्धान्त की अन्य मान्यताएँ भी एक स्थैतिक और परम्परागत स्थिति से सम्बद्ध चित्र प्रस्तुत करती हैं। अन्य शब्दों में इस सिद्धान्त की दोष मान्यताएँ भी स्थैतिक हैं। अतः इस सिद्धान्त में प्रार्वेगिकता का अभाव है।

(य) वस्तुओं की कीमतें उत्पादन के साधनों की कीमतों से निर्धारित नहीं होती—प्रो. होल्ड्स ने ओहलिन के सिद्धान्त की आलोचना इस आधार पर की है कि इस सिद्धान्त में यह मान लिया गया है कि वस्तुओं की कीमतें उत्पादन साधन की लागत से निर्धारित होती हैं। प्रो. होल्ड्स के मतानुसार यह विपरीत सम्बन्ध को व्यक्त करता है क्योंकि वस्तुओं की कीमतें उपभोक्ताओं को प्राप्त उपयोगिता के आधार पर निर्धारित होती है और उन वस्तुओं के बनाने में जिन उत्पादन के साधनों का उपयोग किया जाता है उनकी कीमतें स्वयं वस्तुओं की कीमतों पर आधारित होती हैं।

(स) उत्पादन के साधन समान नहीं होते—ओहलिन का सिद्धान्त विभिन्न देशों में उत्पादन के साधनों को खिन्कुल समरूप मानते हैं परन्तु वास्तविकता इससे कहीं भिन्न है। अतः समान उत्पादन के साधन की मान्यता इस सिद्धान्त की व्यावहारिकता को कम कर देती है। एस. सीम्युल्सन के मतानुसार "यह सिद्धान्त उस समय प्रसफल हो जाता है जब दो देशों में उत्पादन फलन भिन्न होते हैं या विभिन्न देशों में उत्पादन के साधन समान नहीं होते।"

(द) दो देशों के बीच एक ही साधन साधन वस्तु का आयात निर्यात सम्भव है—प्रो. बी. एस. मिन्हास का मत है कि दो देशों के मध्य एक ही साधन साधन या प्रधान जैसे थम-प्रधान वस्तुओं में व्यापार सम्भव है जबकि ओहलिन-सिद्धान्त के अनुसार यह सम्भव नहीं है। प्रो. मिन्हास के शब्दों में, "और यह भी स्पष्ट है कि एक थम-प्रधान (पूँजी-प्रधान) देश उसकी पूँजी प्रधान (थम-प्रधान) वस्तु का निर्यात कर सकता है और निर्यात तथा आयात प्रतिस्थापना वस्तुओं की तुलनात्मक घटक सघनता के बारे में निष्कर्ष निकालना, तर्कसंगत नहीं है।"

साधन मूल्य समानिकरण (Factor Price Equalization)-

प्रो हैक्शर के प्रारम्भिक लेखों का उद्धरण देते हुए ओहलिन ने दो निष्कर्ष दिए—

(i) विदेशी-व्यापार में वस्तुओं की स्वतन्त्रता गतिशीलता और साधनों की पूर्ण गतिशीलता के परिणाम अन्ततः एक से होने हैं।

(ii) वस्तुओं के स्वतन्त्र आयात निर्यात के परिणामस्वरूप दोनों देशों में साधनों की कीमतों में समानता हो जाएगी।

हैक्शर-ओहलिन सिद्धान्त के अनुसार विदेशी व्यापार उभी गमय सम्भव होता है जबकि दो देशों में उत्पादन के साधनों में अपेक्ष कीमतों में अन्तर होता है। दोनों देशों के मध्य व्यापार उस समय तक चलता है जब तक कि साधनों की अपेक्ष कीमतों का यह अन्तर विद्यमान रहता है। विदेशी-व्यापार के कारण प्रत्येक देश में उत्पादन के प्रचुर साधन की अधिक माँग हो जाती है और दूसरी ओर दुर्लभ साधन की तुलनात्मक माँग कम हो जाती है। इसका फल यह होता है कि पहले की तुलना में प्रचुर साधन की कीमत में वृद्धि होगी और दुर्लभ साधन की कीमत में कमी की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। हमारे राष्ट्र में भी यही प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। फलतः दोनों देशों में साधनों की कीमत में अन्तर पहले की तुलना में कम हो जाएगा।

विदेशी-व्यापार सभी देशों में उत्पादन के साधनों की कीमतों को समान रूप से प्रभावित नहीं करेगा। प्रो ओहलिन के मतानुसार सम्पूर्ण विश्व में व्यापार दर में सामान्य वृद्धि या मजदूरी की दर में सामान्य वृद्धि विदेशी व्यापार का सबसे अत्यन्त प्रभाव होगा। यदि दोनों देशों में उत्पादन की परिस्थितियाँ समान हैं और यातायात लागतों की उपेक्षा की जाती है तो उत्पादन के साधनों में तुलनात्मक अन्तर व्यापार को लाभदायक बनाएगा। इस प्रकार व्यापार उस समय तक जारी रहेगा जब तक कि विभिन्न देशों में उत्पादन के साधनों की कीमतों में तुलनात्मक समानता स्थापित नहीं हो जाती। अन्य शब्दों में विदेशी व्यापार के कारण उत्पादन के साधनों की अपेक्ष कीमतों का अन्तर अन्ततः समाप्त हो जाएगा। जब तुलनात्मक समानता स्थापित हो जाती है तो अब तक जितने व्यापारिक सम्बन्ध कायम हो चुके हैं वे जारी रहेगे। प्रो ओहलिन के मतानुसार “इस प्रकार यह स्पष्ट है कि देशों के मध्य तुलनात्मक-लागतों में अन्तर व्यापार उत्पन्न करेगा परन्तु इस प्रकार का अन्तर पहले से स्थापित व्यापार को जारी रखने के लिए आवश्यक नहीं है, इसके विपरीत जैसे-जैसे व्यापार का विस्तार होगा वैसे-वैसे इस प्रकार का अन्तर निश्चिन्त रूप से समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार उत्पादन के साधनों की कीमतों में तुलनात्मक अन्तर साधनों के गतिहीन होने की स्थिति में समाप्त हो जाएगा।”

अब प्रश्न यह उठता है कि विदेशी-व्यापार के कारण कीमतों में तुलनात्मक समानता स्थापित होगी या निरपेक्ष समानता। अर्थात् क्या सभी व्यापार करने वाले देशों में समान किस्म के उत्पादन के साधनों का समान, मजदूरी और व्यापार वास्तविक

पैन्ल (घ) में नतोदर वक्र MN कीमत अनुपात $\left(\frac{P_s}{P_c} \right)$ को प्रकट करता है।

इस वक्र की नतोदरता इस बात को प्रकट करती है कि उत्पादन की प्राप्ति ह्रासमान प्रतिफल के अन्तर्गत हो रही है अर्थात् a बिन्दु के दाँयी ओर तथा b बिन्दु के बाँयी ओर किसी वस्तु की बढ़ती हुई पूर्ति को केवल उसकी कम कीमत पर ही बेचा जा सकता है।

अब यदि हम यह मान लें कि बाजार में इस्पात एवं कपड़े के मूल्यों का अनुपात OP है तो इसके अनुसूच साधनों का मूल्य अनुपात A होगा। यदि A बिन्दु से एक रेखा OX—अक्ष के समानान्तर खींची जाए तो यह रेखा इस्पात एवं कपड़े के समोत्पत्ति वक्रों को क्रमशः P_s व P_c पर काटेगी। यदि P_s व P_c बिन्दुओं को मूल बिन्दु O से मिलाकर बढ़ा दिया जाए तो हम OE_s तथा OE_c दो उत्पादन किरण-रेखाएँ (Production rays) प्राप्त होंगी। OE_s तथा OE_c पर स्थित विभिन्न बिन्दु क्रमशः इस्पात एवं कपड़े की उन मात्राओं को दर्शाते हैं जो विभिन्न मूल्य-अनुपातों $\left(\frac{P_s}{P_c} \right)$ पर माँगी एवं उत्पन्न की जाएगी। OX—अक्ष पर लम्ब डाल

कर माँग की इन मात्राओं के उत्पादन हेतु आवश्यक श्रम एवं पूँजी की विभिन्न मात्राओं (स्थिर अनुपातों में) का पता लगाया जा सकता है। इस्पात व कपड़े के मूल्यों का अनुपात P होन पर जब साधनों के मूल्यों का अनुपात A के अनुरूप एवं इस्पात तथा कपड़े के उत्पादन का स्तर SS एवं CC पर क्रमशः P_s एवं P_c पर निर्धारित हो तो श्रम एवं पूँजी का अनुपात इस्पात एवं कपड़ों के उत्पादन हेतु क्रमशः OR_s एवं OR_c होगा। हमारी मान्यता यह है कि इस्पात एवं कपड़े के इन उत्पादन-स्तरों पर उल्लेख श्रम एवं पूँजी का पूर्ण उपयोग हो सकेगा।

$$\text{अर्थात्, } OR_s + OR_c = R = \frac{K}{L}$$

उपरोक्त स्थिति तब ही लागू होगी जबकि यह मान लिया जाए कि कीमन अनुपात स्थिर रहता है। यह आवश्यक भी है क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत अत्यधिक क्षमता उपस्थित नहीं रह सकती। अब प्रश्न यह है कि कुल उत्पादन में श्रम एवं पूँजी का योगदान कितना है? अथवा श्रम एवं पूँजी कार्यक्षमता-कितना पारितोषक होगा? इसके लिए OP_c रेखा जो OY—अक्ष को T बिन्दु पर काटती है पूँजी तथा श्रम के अंश अथवा योगदान को प्रकट करता है। चित्र में OT इस बात को प्रकट करता है कि व्याज मजदूरी अनुपात (r/w) इकाई से अधिक है अथवा इकाई से कम है। यदि इस बिन्दु पर व्याज मजदूरी अनुपात इकाई से अधिक है, अर्थात् $\frac{r}{w} > 1$ ।

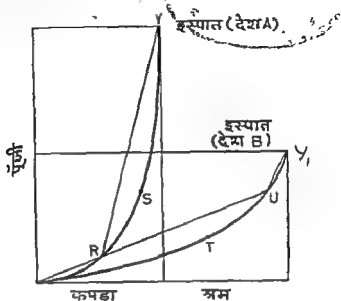
है तो इसका यह अर्थ हुआ कि पूँजी का व्याज, श्रम की मजदूरी-दर की अपेक्षा अधिक है। यदि इसके विपरीत $\frac{r}{w} < 1$ हो, तो व्याज की दर, मजदूरी दर से

अपेक्षाकृत कम है। यहाँ यह मान लिया गया है कि OT की दूरी पर व्याज एवं मजदूरी का अनुपात इकाई के बराबर है, अर्थात् $\frac{r}{w} < 1$ है।

माना कि अब हम मूल साम्य बिन्दु A में परिवर्तन कर देते हैं जिससे कपड़े की तुलना में इस्पात की माँग बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप इस्पात की कामत में वृद्धि हो जाएगी और कपड़े व इस्पात का नया मूल्य अनुपात $\frac{P_1}{P_2}$ एक नया साम्य बिन्दु A_1 पर प्राप्त होगा। इस स्तर पर कपड़े व इस्पात का मूल्य-अनुपात OP_1 होगा। यदि A_1 से OX- अक्ष के समानान्तर रेखा खींची जाए तो इस्पात व कपड़े के समोत्पादन वक्रों (SS एवं CC) को यह रेखा क्रमशः P_{22} एवं P_{21} पर काटेगी। इन बिन्दुओं को यदि मूल बिन्दु O से मिला कर बढ़ा दिया जाए तो हमें OE_{22} तथा OE_{21} उत्पादन किरणें प्राप्त होंगी। OP_{22} एवं OP_{21} की समझाई क्रमशः इस्पात एवं कपड़े के उत्पादन-स्तरों को व्यक्त करेगी। यह स्पष्ट है कि बड़े हुए मूल्य पर भी इस्पात का उत्पादन कम है जबकि कपड़े का उत्पादन अब पूर्वापेक्षा अधिक है ($\because OP_{22} > OP_2$ एवं $OP_{21} > OP_1$)। इस्पात में उत्पादन में कमी का कारण यह है कि इस्पात का उत्पादन करने वाले देश में श्रम की लागत अपेक्षाकृत अधिक है। अथवा उत्पादन की विधि पूँजी प्रधान हो गई है। पूँजी के सस्ते हो जाने के फलस्वरूप इसका प्रयोग श्रम की अपेक्षा अधिक होगा। इसका परिणाम यह होगा कि वे सभी वस्तुएँ, जिनका उत्पादन में पूँजी का अधिक प्रयोग किया जा सकता है, सस्ती हो जाएगी। अतः उन देशों को अधिक लाभ होगा जहाँ पूँजी अधिक है और पूँजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन अधिक होता है। अर्थात् पूँजी प्रधान देशों की तुलनात्मक लागत लाभ प्राप्त होंगे। चित्र में पूँजी के इस सस्तेपन को व्याज मजदूरी अनुपात $\left(\frac{r}{w}\right)$ की गिरावट से दिखाया गया है जो कि OT से कम हो कर OT_1 हो जाता है, अर्थात् इस स्थिति में $\frac{r}{w} < 1$ होगा।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि साम्यावस्था कहाँ प्राप्त होगी। इसके लिए हमने माना कि कोई दो देश A तथा B हैं तथा दो वस्तुओं इस्पात एवं कपड़े का निर्माण करते हैं। प्रत्येक देश के लिए दो उत्पादन सम्भावना पथ हैं। साथ में ही यह भी मान लिया गया है कि सभी बाजारों में पूर्ण प्रतिযোগिता है तथा परिवहन लागत अनुपस्थित रहती है। दोनों देशों में व्यापार के बाद भी दोनों वस्तुओं का उत्पादन चालू रहता है, अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण अपूर्ण रहता है। दोनों ही देशों में उत्पादन फलन समरूप है, अर्थात् सभी उत्पादन साधनों में समान रूप में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन वस्तु के उत्पादन में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के समान होता है। साथ ही यह भी माना गया है कि उत्पादन फलन इस प्रकार का होता है कि दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु हमेशा श्रमप्रधान होती है जबकि

दूसरी वस्तु हमेशा पूँजी प्रधान होती है। चाहे साधनों की सापेक्षिक पूर्ति एवं माधन कीमत अनुपात कैसा ही क्यों न हो। उत्पादन व सभी साधन समरूप हैं, यद्यपि उनकी उपस्थित मात्रा भिन्न हो सकती हैं। उत्पादन माधनों की सख्या वस्तुओं की सख्या से अधिक नहीं होती।



विदेशी मूल्य पार के पश्चात् साधनों का समानोकरण

उपरोक्त चित्र की एजबर्थ-डाउली घापतावार चित्र (Box diagram) कहते हैं। इस चित्र में दोनों देश A एवं B के उत्पादन फलन का उद्गम कपड़ के लिए O पर है परन्तु दोनों वस्तुओं के लिए आवश्यक साधनों की मात्रा में अन्तर होने के कारण इस्पात के लिए दोनों देशों के उद्गम बिन्दु पृथक् पृथक् हैं। देश A के लिए Y तथा देश B के लिए Y¹ है।

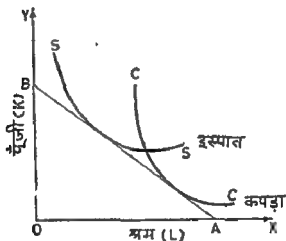
इन भिन्न भिन्न उद्गमों के अन्तर्गत अधिकतम दक्षता के बिन्दु-पथ क्रमशः OY (देश A) और OY¹ (देश B) होंगे। विदेशी व्यापार के पूर्व दोनों देश अधिकतम दक्षता पथ के क्रमशः S एवं T बिन्दुओं पर उपन्यास पूँजी व अम का उपयोग कर रहे थे (दी हुई माँग स्थितियों के आधार पर)।

जब व्यापार सम्भव हो जाता है तो समरूप उत्पादन फलन की मान्यता के कारण तथा उत्पादित वस्तुओं की कीमतों के समान होने पर, उत्पादन-साधनों का पारितोषिक भी आवश्यक रूप से समान होता चाहिए। यह तब ही सम्भव है जबकि व्यापार के फलस्वरूप उत्पादन या तो R बिन्दु पर होता है या U बिन्दु पर। साधन कीमतों की समानता उपरोक्त दो बिन्दुओं R या U में किसी पर भी देखी जा सकती है। यह स्पष्ट है कि R बिन्दु सरल रेखा OU पर अंकित है तथा U बिन्दु

सरल रेखा UY^1 पर अंकित है जो कि सरल रेखा RY के समानान्तर है, अर्थात् RY तथा UY^1 का ढाल समान है।

किण्डल बयॉर का मत है कि ऐसी बहुत-सी बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार के दो बिन्दु R तथा U उत्पन्न नहीं हो सकते। विदेशी व्यापार के बाद एक अथवा दोनों देश पूर्ण रूपेण विशिष्टता अपना सकते हैं। देश B कपड़े का उत्पादन OY तक अथवा देश A इस्पात का उत्पादन OY^1 तक कर सकता है। देश A तथा B में माँग की स्थितियाँ इस प्रकार अलग-अलग हैं कि देश A का उत्पादन बिन्दु S से हटकर O की अपेक्षा Y की ओर जाता है; ताकि इसमें देश A पूर्ण की प्रचुरता होते हुए भी यह अम-प्रधान वस्तुओं का निर्यात करता है।

साधन-मूल्य समानीकरण की विवेचना का दूसरा तरीका प्रो. ए. पी. लॉर ने प्रस्तुत किया है। उन्होंने दो वस्तुओं के सम उत्पाद वक्रों को लिखा है जो उन सापेक्ष कीमतों की अथवा मात्राओं को प्रदर्शित करते हैं जिसमें कि उनका विनिमय दो देशों के बीच होने वाले व्यापार के बाद किया जाता है।



उत्पादन-फलन की सहायता से साधन-मूल्य समानीकरण का स्पष्टीकरण

चित्र में इस्पात तथा कपड़े के क्रमशः SS तथा CC सम उत्पाद वक्र हैं। हम इन समोत्पाद वक्रों द्वारा किसी भी मात्राओं को (मूल्यों को) दिखा सकते हैं, जैसे 60 मीटर कपड़ा तथा 4 टन इस्पात अथवा 600 मीटर कपड़ा तथा 40 टन इस्पात आदि। क्योंकि उत्पादन फलन एक डिग्री के समरूप है, अधिकार्षिक मात्राओं को प्रदर्शित करने वाले उत्तरोत्तर सम उत्पाद वक्रों की रचना या आकार हमेशा समान होगा। अतः इनसे हमें एक सरल रेखीय विस्तार मार्ग प्राप्त होगा। क्योंकि अपनाई

यई इकाइयाँ उत्पत्ति कीमतों को प्रकट करती है जो कि दो देशों में व्यापार के बाद समान होती है। जबकि यह माना गया है कि यातायात लागत अनुपस्थित होनी है तथा पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति प्रचलित है। परन्तु प्रो० किण्डलबर्गर के मतानुसार यह मॉडल उस स्थिति में गलत हो जाता है जबकि समोत्पाद वस्तु एक से अधिक बार त्रांस कर जाते हैं, क्योंकि इसका यह तात्पर्य होगा कि उन वस्तुओं में से कम से कम एक के लिए साधन-प्रतिस्थानापन्न की सीमा की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है।

आलोचना

यह सिद्धान्त अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है जैसे विदेशी-व्यापार में परिवहन-लागत सम्मिलित की जाती है और उस पर कई प्रकार के नियन्त्रण भी होते हैं जिसके परिणामस्वरूप व्यापार से सामान्यतया सम्बन्धित देशों में वस्तु-मूल्य अनुपातों में समानता नहीं आ पाती और इसीलिए साधन मूल्य भी समान नहीं हो पाते हैं।

इसी प्रकार विभिन्न देशों में असमान उत्पाद-फलनों के कारण, साधन प्रतिक्रियों का समानीकरण नहीं हो पाता। उत्पादन-फलनों में विषमता का प्रभाव साधनों के सीमान्त उत्पादों पर पड़ता है जिसके फलस्वरूप विभिन्न साधनों का नतिफल अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर असंग-अलग होता है। साथ ही माँग की स्थितियाँ निर्धारित की जा सकती हैं जिनके अन्तर्गत माँग का पुनर्वितरण होता है और साधनों का भी पुनः आवंटन होता है। इससे स्वतन्त्र विदेशी-व्यापार की कोटियों में समानता स्थापित करने वाले साधन-मूल्य में अस्थिरता उत्पन्न होनी है फलतः साधन-मूल्य समानीकरण नहीं हो पाता।

कुछ आवश्यक मान्यताओं में छूट देने से सिद्धान्त की सगतिता ही प्रभावित हो जाती है और कुछ अवस्थाओं में इस प्रकार की छूट देने के फलस्वरूप साधन मूल्यों का पूर्ण समानीकरण असम्भव हो जाता है, परन्तु समानीकरण की प्रवृत्ति केवल घटती है, पूर्णतः समाप्त नहीं होती। कुछ अन्य दशाओं में व्यापार में साधन-मूल्यों को समान करने की प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाती है और कभी-कभी तो विदेशी-व्यापार से साधन मूल्यों में अन्तर्राष्ट्रीय विषमताएँ बढ़ जाती हैं।

पूर्ण समानीकरण सिद्धान्त के अत्यधिक प्रनिबन्धित स्वरूप पर टिप्पणी करते हुए हैरोड ने लिखा है कि "यह विदेशी-व्यापार सिद्धान्त में एक कौतूहल है।" यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि साधन-मूल्य समानीकरण सूत्र स्पष्ट रूप से पूर्ण-विवक्षितता की शक्ति तथा मान्यता को ही अभिव्यक्त करता है। साथ ही यह शुद्ध सैद्धान्तिक कार्यों की कुछ सम्भार परिसीमाओं पर भी प्रकाश डालता है।

तुलनात्मक लागत एवं हैक्शर-ओहलिन
सिद्धान्त का आनुभाविक् प्रमाणीकरण
अथवा लियनतीफ का विरोधाभास
(EMPIRICAL VERIFICATION OF COMPARATIVE
COST AND HECKSHER - OHLIN THEORY
OR LEONTIEF PARADOX)

नोबल पुरस्कार विजेता डॉ. लियनतीफ ने सन् 1954 में प्रादा-प्रदा मॉडल (Input-Output Model) के आधार पर हैक्शर-ओहलिन सिद्धान्त का आनुभाविक् परीक्षण किया। लियनतीफ ने एक ओर अमेरिकी अर्थ व्यवस्था से सम्बन्ध निर्गत और दूसरी ओर आयात प्रतिस्थापन उद्योग के प्राँवडे लिए। उन्होंने इनके आधार पर निर्गत और आयात उद्योगों में सम्बद्ध उद्योगों का उत्पादन बढ़ाने के लिए पूँजी की आवश्यकता का अनुमान किया। परन्तु लियनतीफ के निष्कर्ष हैक्शर-ओहलिन सिद्धान्त से प्राप्त निष्कर्षों से बिल्कुल विपरीत हैं। कारण यह है कि हम यह मानते हैं कि अमेरिका में श्रम की तुलना में पूँजी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण वहाँ व्याज दर कम है और वहाँ पूँजी प्रधान तकनीक का उपयोग किया जाता है। यदि हम हैक्शर, ओहलिन सिद्धान्त का अनुकरण करें तो अमेरिका से निर्गत की जाने वाली वस्तुएँ पूँजी-प्रधान होनी चाहिए और क्योंकि श्रम वहाँ पर अपेक्षाकृत कम है इसलिए अमेरिका में श्रम-प्रधान उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का आयात करना चाहिए।

परन्तु लियनतीफ ने यह पाया कि अमेरिका से निर्यात अधिक श्रम-प्रधान और आयात अधिक पूँजी-प्रधान है। उनके निष्कर्ष इस प्रकार हैं—

“इस बात पर विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि अमेरिकन माल के निर्यात के प्रति दस लाख डॉलर के पीछे आवश्यक श्रम की मात्रा, निर्यात की समान मात्रा के आयात के पीछे आवश्यक श्रम की तुलना में कहीं अधिक है।” संक्षेप में लियनतीफ के मतानुसार अमेरिका के निर्यात उद्योगों में पूँजी का उपयोग आयात उद्योगों की अपेक्षा कम होता है। लियनतीफ के परिणाम को अर्थात्कि सारणी में एकट किया गया है।

अमेरिका के प्रति दस लाख डॉलर के निर्यात और प्रतियोगिता
 प्रायास में प्रयुक्त धरेलू पूँजी और श्रम की आवश्यकता
 (सन् 1947 की संरचना का औसत)

विवरण	निर्यात	आयात
पूँजी (डॉलरों में)	2550,780	3091,339
श्रम (श्रम वर्ष)	182 313	170 004

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि लियनतीफ के अनुसार अमेरिका व निर्यात
 प्रायासों की तुलना में अधिक श्रम प्रधान है। अन्य शब्दों में अमेरिका विदेशी व्यापार
 में इसलिए शामिल होता है कि वह पूँजी के उपयोग में मितव्ययी होना चाहता है
 और अतिरिक्त श्रम का निर्यात करना चाहता है। वस्तुतः यह निष्कर्ष हैक्शर-
 प्रोहलिन के सिद्धान्त के सर्वथा विपरीत है जिसके अनुसार प्रत्येक देश को वे वस्तुएँ
 निर्यात करनी चाहिए जिनके उत्पादन में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध एवं अपेक्षाकृत
 सस्ते साधन का उपयोग होता हो। यही कारण है कि लियनतीफ द्वारा प्रस्तुत
 स्थिति को "लियनतीफ विरोधाभास" (Leontief Paradox) के नाम से पुकारा
 जाता है। इस विरोधाभास के अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं है कि साधनों की उपलब्धि
 (प्रचुर मात्रा में या न्यून मात्रा में) का आयात-निर्यात व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव
 होता है।

लियनतीफ के उपरोक्त निष्कर्ष के वादजूद हैक्शर-प्रोहलिन सिद्धान्त सामान्य
 एवं तार्किक दृष्टियों से सही प्रतीत होता है। विदेशी व्यापार की संरचना एवं
 आयात व निर्यात की सम्भावनाओं पर साधन विशेष की प्रचुरता एवं लागत-मूल्य
 का काफी प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक देश सामान्यतया उस वस्तु की अधिक मात्रा
 बनाने का प्रयास करता है जिसका उत्पादन वह अधिकांशतः कम लागत पर कर सके
 और बहुधा लागत कम तभी होनी है जब दश प्रचुर, मात्रा में उपलब्ध एवं सस्ते
 साधन का अधिक उपयोग करे। परन्तु हाल ही में कुछ अर्थशास्त्रियों ने "लियनतीफ-
 विरोधाभास" की चर्चा पुनः प्रारम्भ कर दी है। इनके मतानुसार पूँजी की गणना
 कई प्रकार से की जानी चाहिए। भूमि एवं श्रम में भी पूँजी का अंश विद्यमान होता
 है, अतः केवल कार्यशील पूँजी या यन्त्रों को ही नहीं बल्कि मानवीय योग्यताओं आदि
 को भी पूँजी में शामिल किया जाना चाहिए।

वस्तुतः मानवीय योग्यता भी श्रम में निहित एक प्रकार की पूँजी है। किसी
 व्यक्ति के प्रशिक्षण में भी पूँजी का उपयोग होता है, और इसीलिए व्यक्तिगत दक्षता
 को भी पूँजी का एक भाग मानना चाहिए। स्वयं लियनतीफ ने यह स्वीकार किया
 कि प्रशिक्षित व्यक्ति का श्रम वास्तविक रूप में श्रम के रूप में न लेकर पूँजी के एक
 अंश के रूप में लिया जाना चाहिए। तथापि लियनतीफ ने बताया कि मानवीय
 योग्यता को पूँजी के रूप में परिगणित करना एक कठिन कार्य है।

लियनतीफ ने एक अन्य स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी

थमिक अन्य देशों के थमिक की अपेक्षा अधिक कुशल है। इस कारण यदि थम की केवल सामान्य दक्षता को लिया जाए तो भारत के सामान्य थमिकों व अमेरिका के सामान्य थमिकों में कोई अन्तर नहीं होगा, तथा हैक्शर-ग्रोहलिन सिद्धान्त वैध माना जा सकेगा।

कुछ लोग यह तर्क भी देते हैं कि यदि साधनों की निधि (Factor Endowments) की परिभाषा एवं उत्पादन-फलन को सही रूप में व्याख्या की जाए तो हैक्शर-ग्रोहलिन सिद्धान्त को सही सिद्ध करना सम्भव होगा। कुछ प्रबंधशास्त्रियों ने यह भी कहा है कि थम की निपुणता पूँजी के विनियोग द्वारा ही नहीं अपितु घटकों द्वारा भी प्रभावित होती है। परन्तु सही रूप में दक्ष थमिक को थम के रूप में लिया जाए अथवा पूँजी के रूप में, यह प्रश्न अब तक अनिर्णीत है।

लियनतीफ के अध्ययन और निष्कर्षों के पश्चात् अनेक विद्वानों ने इसी प्रकार के अन्य अध्ययन भी किए हैं जिनमें से कुछ प्रमुख अध्ययन निम्नानुसार हैं—
प्रथम अध्ययन

भारत के सम्बन्ध में बम्बई विश्वविद्यालय के प्रो. डॉ. आर. भारद्वाज ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित दो अध्ययन किए हैं—

(i) भारत तथा शेष विश्व—इस सन्दर्भ में प्रोफेसर भारद्वाज ने बताया कि भारत के निर्यात सामान्यतया थम-प्रधान हैं जबकि आयात उन वस्तुओं के हैं जो देश में पूँजी प्रधान उद्योगों द्वारा निर्मित होती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भारत का शेष विश्व के साथ होने वाला व्यापार हैक्शर-ग्रोहलिन सिद्धान्त के ही अनुरूप है।

(ii) भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका—डॉ. भारद्वाज ने बताया कि भारत अमेरिका को पूँजी-प्रधान उद्योगों में निर्मित वस्तुएँ निर्यात करता है जबकि अनाज, कपास आदि ऐसी वस्तुओं का आयात करता है जो यहाँ थम प्रधान उद्योगों में निर्मित होते हैं। इससे यह सिद्ध होता कि भारत और अमेरिका के मध्य होने वाला व्यापार हैक्शर-ग्रोहलिन के सिद्धान्त के अनुरूप नहीं है। परन्तु डॉ. भारद्वाज का यह निष्कर्ष उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। कारण यह है कि भारत में खाद्यान्न, कच्चे माल व अनेक दूसरी वस्तुओं के आयात एवं निर्यात लागतों की भिन्नता पर आधारित होने की अपेक्षा PL-480 एवं दोनों देशों के मध्य हुए अन्य समझौतों के परिणाम थे।

द्वितीय अध्ययन

प्रो. के. एन. प्रसाद ने भी भारत में आदा-प्रदा विश्लेषण के माध्यम से हैक्शर-ग्रोहलिन सिद्धान्त की सत्यता का परीक्षण करने का प्रयत्न किया है। डॉ. प्रसाद का मत है कि लियनतीफ विरोधनाश में एक भारी त्रुटि यह है कि प्राकृतिक साधनों के महत्त्व को स्वीकार करते हुए भी प्रयुक्त उत्पादन घटकों की गणना में उसकी उपेक्षा की गई है। प्रो. प्रसाद के अध्ययन का निष्कर्ष इस प्रकार है 'ये परिणाम यह प्रदर्शित करते हैं कि यदि 100 करोड़ रुपये की कीमत के

आयातों को देश में ही पैदा किए जाएं तो उसके लिए निर्यात की तुलना में 155% अधिक पूँजी की आवश्यकता होगी जबकि निर्यात की तुलना में श्रम की आवश्यकता 3% कम होगी। फिर यदि हम 100 करोड़ रुपये के निर्यात में प्रयुक्त उत्पादन घटकों को लें तो प्रयुक्त पूँजी आयातों की तुलना में 2½ गुणा कम होगी और श्रम के मन्दमं में स्थिति लगभग वही है, अर्थात् आयात की तुलना में प्रयुक्त श्रम की मात्रा 3% के लगभग अधिक है। परन्तु निर्यातों में प्रयुक्त नैसर्गिक साधनों की मात्रा आयातों की तुलना में लगभग दुगुनी है। इसका प्रमुख कारण कृषि है। सन् 1955-56 में भारत में विदेशी व्यापार का गठन इस प्रकार था कि हमारे निर्यातों में प्रमुख स्थान कृषि उपज का था और अब इस प्रकार नैसर्गिक साधनों का है। इसी वजह से यदि हमारे कुल आयातों का जब देश में उत्पादन किया जाएगा तो श्रम और पूँजी दोनों की अधिक आवश्यकता होगी। इसी प्रकार समान उत्पादन फलों की मान्यता के साथ भारत पूँजी का मुगतान नैसर्गिक साधनों के द्वारा कर रहा है।'

तृतीय अध्ययन

जर्मनी के स्तोप् एव रोम्पर ने जर्मनी के विदेशी व्यापार का विश्लेषण करके बताया कि उस सन्दर्भ में हैक्शर-ग्रोहलिन सिद्धान्त सत्य है।

चतुर्थ अध्ययन

जापान के अन्तर्राष्ट्रीय-व्यापार के विषय में एक अध्ययन तो हैक्शर-ग्रोहलिन सिद्धान्त की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है जबकि एक दूसरा अध्ययन इस सिद्धान्त की सत्यता की पुष्टि करता है।

पंचम अध्ययन

कनाडा में किए गए एक अध्ययन के अनुसार हैक्शर-ग्रोहलिन सिद्धान्त के अनुरूप कनाडा का विदेशी व्यापार नहीं होता है। परन्तु यह निष्कर्ष इसलिए अन्तिम नहीं माना जा सकता क्योंकि कनाडा का अधिकांश व्यापार अमेरिका से होता है जहाँ पूँजी प्रधान उद्योगों का अधिक महत्त्व है।

निष्कर्ष

हैक्शर-ग्रोहलिन सिद्धान्त सामान्य एवं सार्थक दृष्टियों से उपयुक्त प्रतीत होता है। विदेश व्यापार की संरचना और आयात एवं निर्यात की सम्भावनाओं पर साधन विशेष की प्रचुरता और लागत मूल्य का बहुत प्रभाव पड़ता है। व्यावहारिक रूप में प्रत्येक देश साधन-समृद्धि उस वस्तु की अधिक मात्रा उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है जिसका उत्पादन वह कम लागत पर कर सकता है और बहुधा लागत कम तभी होती है जब देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध एवं सस्ते साधन का अधिक उपयोग किया जाता है। यही नहीं यदि द्विपक्षीय व्यापार की समीक्षा की जाए तो अधिकांश देशों का विदेशी व्यापार हैक्शर-ग्रोहलिन सिद्धान्त के अनुरूप पाया जाएगा। हैक्शर-ग्रोहलिन सिद्धान्त के विषय में निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्रियों के

पास कोई ठोस प्रमाण इस सिद्धान्त को सही या गलत साबित करने के लिए नहीं है। अतः पर्याप्त एवं विश्वस्तरीय आँकड़ों के आधार पर ही इस सम्बन्ध में कोई प्रन्तिम निर्णय लिया जाना चाहिए। साथ ही एक देश या क्षेत्र के विषय में प्राप्त निष्कर्षों को अन्य देशों के सन्दर्भ में काफी सतर्कतापूर्वक लेना चाहिए।

विदेशी व्यापार के प्रति वर्तमान दृष्टिकोण

गत कुछ वर्षों में दो नवीन सिद्धान्त विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में प्रकाश में आए हैं जो निम्नानुसार हैं—

(प्र) क्रेविस सिद्धान्त (Kravis Theory)

(घ) लिण्डर सिद्धान्त (Linder Theory)

(प्र) क्रेविस सिद्धान्त (Kravis Theory)

इस सिद्धान्त के अनुसार साधनों की निधि की अपेक्षा तीन बातें विदेशी-व्यापार को सम्भव बनाती हैं—

(i) प्राकृतिक साधन

(ii) टेक्नोलॉजी

(iii) वस्तु विशेष की माँग तथा पूर्ति की सोच।

क्रेविस ने अपने एक लेख में यह सिद्ध किया है कि निर्यात उद्योगों में मजदूरी अभाव-प्रतियोगिता वाले उद्योगों व अन्य सभी उद्योगों से अधिक होने की प्रवृत्ति होती है। परन्तु मजदूरी स्तर में यह अन्तर बहुत अधिक नहीं होता। क्रेविस ने अपनी वाद की वार्ताओं में यह तर्क दिया है कि व्यापार का स्वरूप विभिन्न मजदूरी-संरचनाओं से अधिक प्रभावित नहीं होता। उन्होंने लियोनतीफ के विरोधाभास पर विचार करते हुए इस बात पर सन्देह व्यक्त किया है कि अमेरिका में पूँजी की अपेक्षा श्रम की प्रचुरता है। विशेष रूप से वे अमेरिका द्वारा विदेशों को अत्यधिक पूँजी का निर्यात करने की बात कहते हैं। क्रेविस के मतानुसार इसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ पूँजी का अभाव है।

क्रेविस का मत है कि व्यापार का वस्तु स्वरूप निर्धारण अर्थात् कौन देश किस वस्तु का उत्पादन करेगा (मजदूरी अनुपात के सम्बन्ध में) प्रमुख रूप से उपलब्धि एवं उत्पादकता द्वारा किया जाता है। उपलब्धि का अर्थ है, व्यापार उत प्रस्तुतों तक सीमित होगा जो स्वदेश में उपलब्ध नहीं है, जैसे खनिज पदार्थ जो भौतिक कारणों से उपलब्ध नहीं है तथा वे वस्तुएँ जिनका उत्पादन केवल ऊँची लागत से ही बढ़ाया जा सकता है। अन्य शब्दों में इस तथ्य को इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि वस्तु की पूर्ति बेलोचदार रहती है। क्रेविस यह तर्क देते हैं कि माँग की अपेक्षा प्राकृतिक साधनों की कमी के कारण अनुपलब्धि होती है और तकनीकी प्रगति तथा उत्पाद-विभेद किसी नवीन देश को अस्थायी रूप से एकाधिकार शक्तियों का संचय करने की छूट देती है। अतः प्राकृतिक एवं कृत्रिम दुर्लभताओं से अनुपलब्धि पैदा होती है।

(व) लिण्डर सिद्धान्त (Linder Theory)

लिण्डर ने निर्मित वस्तुओं और प्राथमिक वस्तुओं के व्यापार में भेद किया है। लिण्डर का मत है कि प्राथमिक वस्तुओं में वस्तुतः प्राकृतिक साधनों की गहनता है और जिसे अप्रभात उत्पादन के साधन वे अज्ञ दोनों के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है परन्तु निर्मित वस्तुओं का व्यापार इस रूप में स्पष्ट नहीं किया जा सकता। वास्तव में व्यापार के प्रनिरूप और स्वरूप के सम्बन्ध में हम ठीक अविष्यवाणी नहीं कर सकते। हम केवल यह कर सकते हैं कि एक ऐसे सिद्धान्त का प्रतिपादन करें जो दो राष्ट्रों के बीच व्यापार की मात्रा को बढ़ाता है। लिण्डर के मतानुसार व्यापार करने वाले देशों के मध्य माँग के स्वरूप में जितनी अधिक समानता होगी, व्यापार की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। संक्षेप में लिण्डर सिद्धान्त के अनुसार किसी भी देश का निर्मित वस्तु की माँग के स्वरूप पर निर्भर करता है।

यद्यपि लिण्डर ने अपनी परिकल्पना में इस सिद्धान्त का अनुभव अन्य विवेक्षण करने का प्रयत्न किया है परन्तु सिद्धान्त अत्यन्त ही क्लिष्ट है और इसमें काफी विश्लेषण और जाँच करने की आवश्यकता है।

यद्यपि व्यापार सिद्धान्त के प्रति दोनों दृष्टिकोण अधिक सख्त नहीं रहे हैं फिर भी ये प्रयास महत्वपूर्ण और विशिष्ट हैं।



प्रतिपूरक मांग, मार्शल-एजवर्थ का प्रस्ताव वक्र

(RECIPROCAL DEMAND, MARSHALL-
EDGEWORTH OFFER CURVES)

जे. एस. मिल ने तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की प्रतिपूरक प्रथमा पारस्परिक मांग के सिद्धान्त द्वारा व्याख्या की। इस सिद्धान्त में यह स्पष्ट किया गया है कि वस्तुओं का विनिमय किस अनुपात में किया जाता है। मिल द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धान्त की व्याख्या आगे चलकर मार्शल द्वारा की गई है। इसे व्यापार की वास्तविक शक्तों का निर्धारण कर्ता बनाया गया है।

मिल ने बताया कि दो देशों के बीच वस्तुओं की विनिमय दर की सीमाएँ दोनों ही देशों की आन्तरिक विनिमय दरों द्वारा निर्धारित होती हैं। कोई भी देश उस दर से कम अपनी वस्तुओं का विदेशों के साथ विनिमय करने के लिए तैयार नहीं होगा जिस दर पर अन्तर्राष्ट्रीय-व्यापार के अभाव में देश के अन्दर ही वस्तुओं का विनिमय हो रहा होगा।

रिकाडों की भाँति मिल की भी यह मान्यता थी कि देश के भीतर वस्तुओं का विनिमय उनकी उत्पादन लागतों के आधार पर होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय में विनिमय की परिस्थितियों के विश्लेषण के लिए मिल ने भी रिकाडों के समान ही दो वस्तुओं और दो राष्ट्रों का जो समान आकार और आर्थिक शक्ति वाले हैं, उदाहरण लिया है। उन्होंने भिन्न-भिन्न अन्न-उत्पादन लागतों के साथ दो देशों में दो वस्तुओं के दिए हुए उत्पादन के स्थान पर दिए हुए धन की मात्रा के साथ दो देशों में दो वस्तुओं के उत्पादन की भिन्न मात्रा का उदाहरण लिया है। एल्सवर्थ के मतानुसार, “इस प्रकार उनका सिद्धान्त रिकाडों के तुलनात्मक श्रम-लागतों के सिद्धान्त के स्थान पर तुलनात्मक लाभ या श्रम की तुलनात्मक प्रभावशीलता के आधार पर प्रतिपादित किया है।”

प्रतिपूरक मांग का सिद्धान्त (Theory of Reciprocal Demand)

इस सिद्धान्त को मिल का व्यापार शक्तों का सिद्धान्त, पारस्परिक मांग का सिद्धान्त अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मांग या मूल्य मात्रा समीकरण भी कहते हैं।

शर्तें प्रतिपूरक माँगों द्वारा निर्धारित होती हैं, जिससे आयात एवं निर्यात मूल्य में साम्य बना रहता है। मिल के अनुसार “अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य का नियम केवल सामान्य मूल्य नियम का ही विस्तार मात्र है जिसे हम माँग एवं पूर्ति के समीकरण के नाम से जानते हैं।”

अब हम मिल के पारस्परिक माँग के सिद्धान्त को एक काल्पनिक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे। माना कि एक श्रमिक एक दिन में 10 घण्टे कार्य करके निम्न प्रकार से उत्पादन करता है—

धर्म लागत सरचना

देश	उत्पादन (इकाइयों में)		घरेलू विनिमय अनुपात
	शराब (W)	कपड़ा (C)	
अमेरिका	3	3	1 इकाई शराब = 1 इकाई कपड़ा
ब्राजील	1	2	1 इकाई शराब = 2 इकाई कपड़ा

उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि उसी धर्म-लागत (10 घण्टे) के साथ अमेरिका और ब्राजील शराब व कपड़े की भिन्न-भिन्न मात्राओं का उत्पादन करते हैं। अमेरिका की शराब और कपड़ा दोनों वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है। ब्राजील की तुलना में शराब में वह उसी धर्म की मात्रा से एक इकाई के स्थान पर 3 इकाई और कपड़े की 2 इकाई की तुलना में 3 इकाई का उत्पादन करता है। परन्तु कपड़े की तुलना में शराब के उत्पादन में अधिक तुलनात्मक लाभ प्राप्त है। ब्राजील को शराब की तुलना में कपड़े के उत्पादन में तुलनात्मक हानि कम है। अतः यदि अमेरिका शराब के उत्पादन में और ब्राजील कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण करते हैं तो दोनों देश लाभान्वित होंगे।

व्यापार शर्तें—एक्सचेंज के शब्दों में “सम्भाव्य वस्तु विनिमय-शर्तों (विदेशी विनिमय अनुपात) की सीमा घरेलू विनिमय अनुपात से स्थापित होती है। घरेलू विनिमय अनुपात प्रत्येक देश में धर्म की तुलनात्मक कुशलता से निर्धारित होता है।” अर्थात् दो देशों के बीच वस्तुओं की विनिमय दर की सीमाएँ दोनों ही देशों की आन्तरिक विनिमय दरों द्वारा निर्धारित होती हैं।

अमेरिका में घरेलू विनिमय अनुपात—1 इकाई शराब = 1 इकाई कपड़ा

ब्राजील में घरेलू विनिमय अनुपात—1 इकाई शराब = 2 इकाई कपड़ा

अतः सम्भावित व्यापार-शर्त की सीमा एक इकाई शराब = एक इकाई कपड़ा से 2 इकाई कपड़े तक।

अतः वास्तविक विनिमय अनुपात इन दो सीमाओं अर्थात् 1 इकाई शराब = 1 इकाई कपड़ा और 1 इकाई शराब = 2 इकाई कपड़े के बीच कहीं भी निर्धारित हो सकती है।

प्रान्तरिक लागते विदेशी व्यापार में वस्तुओं की विनिमय दर को निर्धारित नहीं करती है। यद्यपि वे विनिमय दर की वे सीमाएँ निर्धारित करती हैं जिनके मध्य ही विदेशी-व्यापार सम्भव होगा। यदि विदेशी व्यापार में वस्तुओं की विनिमय दर उस सीमा को पार करती है तो फिर किसी एक देश के लिए विदेशी व्यापार लाभप्रद नहीं रहेगा।

वास्तविक विनिमय दर के निर्धारण के लिए मिल ने मांग और पूर्ति के नियम का सहारा लिया है। मिल ने कहा कि वास्तविक विनिमय दर का निर्धारण दोनों देशों की पारस्परिक मोल-मोल करने की शक्ति अर्थात् इनकी पारस्परिक मांग की लोच पर निर्भर करेगा। यदि किसी देश के पास अन्य देशों की वस्तुओं की मांग बहुत तीव्र है तो इस देश के लिए विदेशी व्यापार की शर्तें अर्थात् विनिमय दर प्रतिकूल होगी। इसके विपरीत यदि इस देश के पास विदेशी वस्तुओं की मांग कम तीव्र है और इस देश की वस्तुओं के लिए विदेशी मांग अधिक तीव्र है तो व्यापार की शर्तें अर्थात् विनिमय दर इस देश के अनुकूल होगी। इस प्रकार वास्तविक विनिमय दर के निर्धारण में विभिन्न देशों की पारस्परिक मांग की लोच का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है।

प्रालोचना

मिल के सिद्धान्त की निम्नलिखित प्रालोचनाएँ की गई हैं—

1 मिल का सिद्धान्त रिकार्डों के सिद्धान्त का पूरक नहीं है—बहुत से अर्थशास्त्रियों की मिल के योगदान के सम्बन्ध में धारणा यह है कि मिल ने रिकार्डों के तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त में पूरक योगदान दिया है। परन्तु यह धारणा गलत है और कि प्रो० शुम्पीटर का मत है कि मांग व पूर्ति सारणियाँ जिनका पारस्परिक कटाव-बिन्दु प्रतिपूरक मांग के समीकरण का ज्यामितिक चित्र प्रस्तुत करता है। एक ऐसा दृष्टिकोण दर्शाना है जिसे रिकार्डों ने (एकाधिकृत वस्तुओं व अस्पर्ही उच्चावचन को छोड़कर) हमेशा अस्वीकृत किया था। वे एक नवीन तथा अधिक सामान्य सिद्धान्त को ठीक उसी प्रकार प्रस्तुत करते हैं जिस प्रकार विदेशी विनिमय-दरों का सामान्य सिद्धान्त, जो कि इस धारणा की अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के अन्तर्गत विनिमय-दर स्वर्ण-बिन्दुओं के मध्य स्थापित होती है, पूरक से कहीं अधिक है। यही नहीं, सामान्य सिद्धान्त ने पुराने सिद्धान्त को महत्वपूर्ण स्थान से हटा दिया है जिस प्रकार सामान्य सिद्धान्त ने स्वर्ण-बिन्दु सिद्धान्त को विशिष्ट मामले के अनेक साध्यों में से एक साध्य बना दिया है और उसी प्रकार प्रतिपूरक मांग के सिद्धान्त ने तुलनात्मक-लागत सिद्धान्त को व्यापारिक प्रतियोगिता के अन्तर्गत व्यापार के विशिष्ट पहलू के सम्बन्ध में एक साध्य के स्थान पर ला दिया है।" वस्तुतः मिल का प्रतिपूरक मांग का सिद्धान्त रिकार्डों के तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त को गलत मिट्ट कर देता है।

2 अवास्तविक मान्यताएँ—मिल का पारस्परिक मांग का सिद्धान्त अवास्तविक मान्यताओं जैसे पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता, स्वतन्त्र विदेशी व्यापार,

उत्पादन के साधनों में पूर्ण शक्तिशीलता, तुलनात्मक-लागत-सिद्धान्त तथा विशिष्टीकरण, दो देश तथा दो वस्तु मॉडल पर आधारित है। अतः यह सिद्धान्त व्यावहारिक नहीं है।

3. बदल-बदल वाली शर्तें पर आधारित—जेवन्स का मत है कि मिल का सिद्धान्त व्यापार की बदल-बदल वाली शर्तें पर आधारित है पर व्यापार की बदल-बदल वाली शर्तें अन्तर्राष्ट्रीय-व्यापार से उत्पन्न होने वाले लाभ का ठीक माप प्रस्तुत नहीं करती है।

4. स्वयं-सिद्ध कथन—शेडवेल ने मिल के इस दृष्टिकोण की आलोचना की है कि व्यापार की शर्तें का निर्धारण वहाँ होता है जहाँ मायात तथा निर्माण के मूल्य साम्य की स्थिति में हों। शेडवेल का कहना है कि यह स्वयं-सिद्ध है वास्तविक नहीं और यह व्यापार की शर्तें के निर्धारण पर बिल्कुल प्रकाश नहीं डालता है।

प्रो. वेस्टवेल ने इस आलोचना को निराधार बताया। वेस्टवेल का मत है कि मिल का सिद्धान्त केवल साम्य को व्याख्या नहीं करता बल्कि उन शक्तियों पर भी प्रकाश डालता है जो साम्य को स्थापित करने में प्रियाशील होती हैं।

5. पूर्ति सम्बन्धी दशाओं की उपेक्षा—मिल के सिद्धान्त की आलोचना करते हुए प्रो. मार्शल ने कहा है कि उन्होंने पूर्ति सम्बन्धी स्थितियों की उपेक्षा की है। वास्तव में पूर्ति सम्बन्धी दशाएँ भी व्यापार शर्तों को प्रभावित करती हैं। मार्शल ने मतानुसार “विदेशी वस्तुओं के लिए देश की प्रभावपूर्ण माँग की लोच न केवल इसकी सम्पत्ति और उसके लिए इसकी जनसंख्या की इच्छाओं की लोच द्वारा बल्कि इसकी अपनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की पूर्ति को विदेशी बाजारों की माँग के साथ समायोजित करने की क्षमता द्वारा भी प्रभावित होती है।”

6. व्यापार से बड़े देशों की छोटे देशों की अपेक्षा लाभ कम होना अवश्य नहीं—मिल का कथन था कि छोटे देश विदेशी व्यापार पर अधिक निर्भर रहते हैं अतः इस कारण उन्हें बड़े देशों की अपेक्षा विदेशी व्यापार में अधिक लाभ होना है परन्तु मार्शल का कहना है कि एक घनी देश भी (अ) नई वस्तुओं का प्रचलन कर सकता है, (ब) विस्तृत सुसंगठित व्यापारिक सम्बन्धों से लाभान्वित हो सकता है, (स) एक विशेष वस्तु की बिक्री करने के बजाय नए बाजार खोज सकता है, और (द) निर्यात देशों की अपेक्षा यह विभिन्न बाजारों की माँग के अनुसार अपने उत्पादन को समायोजित करने की अधिक अच्छी स्थिति में होता है। अतः यह छोटे देशों की अपेक्षा अधिक लाभ कमा सकता है।

उपरोक्त आलोचनाओं के होते हुए भी यह कहा जा सकता है कि उन्होंने रिकार्डों के समान अपना विश्लेषण दो वस्तुओं और दो देशों तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि उन्होंने सक्षिप्त रूप से दो से अधिक वस्तुओं और दो से अधिक देशों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य की समस्या पर विचार किया। उनका मत था कि दो से अधिक वस्तुओं और देशों के सन्दर्भ में भी वही आधारभूत नियम लागू होते हैं। मिल ने यातायात लागतों के अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव पर भी अपना विचार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि बहुपक्षी विनिमय भी होना है और एक ही साम्य बिन्दु के स्थान पर बहुसाम्य बिन्दु भी हो सकते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के निर्धारण एवं व्याख्या में और भी बहुत से नाजुक प्रश्न उपस्थित हो सकते हैं। अन्त में जेकाबकइनर का यह कथन उल्लेखनीय है कि “यद्यपि पारस्परिक मांग विश्लेषण एक अपूर्ण प्रयास है फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के प्रतिभावो को व्यक्त करने वाला उपलब्ध प्रथम तर्क के विकल्पो से उत्तम है।”

मार्शल-एजवर्थ का प्रस्ताव वक्र (Marshall-Edgeworth Offer Curves)

मिल द्वारा प्रतिपादित व्यापार-शर्तों के सिद्धान्त में मार्शल ने सशोधन करते हुए बताया कि व्यापार की शर्तों का निर्धारण करते समय दो देशों में विद्यमान मजदूरी की दरों का भी दृष्टिगत रखना चाहिए। इसीलिए मार्शल ने व्यापार की शर्तों के निर्धारण हेतु मौद्रिक लागतों को अपने विश्लेषण में शामिल किया। मार्शल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त में निम्नलिखित दो बातें महत्वपूर्ण हैं—

(i) दी हुई व्यापार शर्तों (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य) पर किसी वस्तु की मांग व पूर्ति इस बात पर निर्भर करेगी कि उस देश में उत्पादन एवं (आन्तरिक) उपभोग की क्षमता कितनी है, तथा

(ii) व्यापार की शर्तें स्वयं प्रत्येक वस्तु की मांग व पूर्ति की लोच पर निर्भर करती हैं।

परन्तु मार्शल ने यह स्वीकार किया कि प्रत्येक देश में वस्तुओं की मांग व पूर्ति का सही अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि इन वस्तुओं की मात्रा एवं इनका गठन परिवर्तनशील है। वस्तुतः इनमें मजदूरी के स्तर के साथ माप परिवर्तन होते रहते हैं। इसी कारण मार्शल ने किसी देश के आयात व निर्यात में सम्मिलित वस्तुओं का मूल्य जानने हेतु एक सामान्य (मौद्रिक) माप लेना थोड़ा समझा। उन्होंने यह मान्यता ली कि किसी भी देश में यह माप धर्म की स्थिर इकाई का परिमाण मात्र है। अनेक वैकल्पिक अनुपातों के बीच साम्य स्थिति उस विनिमय अनुपात पर होगी जहाँ वस्तु की निर्यात (पूर्ति) एवं आयात (मांग) मानाएँ समान हैं। इसी विनिमय-अनुपात को व्यापार की शर्तों की सज्जा दी जा सकती है।

मार्शल का सिद्धान्त निम्न मान्यताओं पर आधारित है—

(i) केवल दो देश हैं जो आपस में व्यापार करते हैं और वे किसी अन्य देश के साथ व्यापार नहीं करते।

(ii) प्रत्येक देश वस्तु को दूसरे की सीमाओं तक पहुँचाने की लागत सहन करता है और इसके बाद ही वस्तु की कीमत निर्धारित की जाती है अथवा व्यापार का व्यवहार दो देशों के व्यापारियों के बीच बराबर विभाजित किया जाता है। यह मान्यता यातायात व्यय के विचार-विमर्श को अलग रखने का प्रयास करती है।

(iii) कोई देश व्यापार से उत्पन्न होने वाले भुगतानों के अतिरिक्त किसी भुगतान को करने के लिए बाध्य नहीं है। इस मान्यता के द्वारा पूँजी को गति द्वारा उत्पन्न उधरनों से दूर किया जाता है।

(iv) प्रत्येक व्यापारी अपने निर्यात के बदले प्राप्त होने वाले सामान को अपने देश में वापस लाता है और अपने निर्यात के विरुद्ध कोई बिल नहीं रखता। इससे विदेशी मुद्रा की समस्या हल हो जाती है।

(v) प्रत्येक देश की मुद्रा का मूल्य केवल उसकी घरेलू अर्थ-व्यवस्था में ही है।

मार्शल ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के ढाँचे के निर्धारकों के रूप में माँग व पूर्ति दोनों के समुक्त कार्यबहन पर बहुत बल दिया। मार्शल के मतानुसार, “दो देशों के बीच होने वाले व्यापार में किसी को भी केवल माँग या पूर्ति से ही विशेष रूप से सम्बन्ध नहीं किया जा सकता। प्रत्येक की माँग उसके निवासियों को विदेशों से कुछ वस्तुएँ प्राप्त करने की इच्छा से उत्पन्न होती है और उसकी पूर्ति का मूल (Origin) उन वस्तुओं को, जो कि अन्य देशों के लोग लेना चाहते हैं, उत्पन्न करने की सुविधाओं में छिपा है। परन्तु उसकी माँग व्यापार को जन्म देने में सामान्यतः केवल उसी सीमा तक ही प्रभावशाली है जहाँ तक उसके पीछे उपयुक्त वस्तुओं की पूर्ति की ग्राह्य है और उसकी पूर्ति उस सीमा तक सक्रिय होती है जहाँ तक कि विदेशी वस्तुओं के लिए उसकी माँग विस्तृत है।”

इस सिद्धान्त को निम्न सारणी द्वारा और अच्छी तरह समझा जा सकता है—

अनुमानित व्यापारिक सूची*

(इकाइयों में)

व्यापार की शर्तें (अमेरिका की प्रत्येक 100 इकाई इस्पात के लिए भारत के कपड़े की इकाइयाँ)	भारत के कपड़े के लिए अमेरिका की माँग (भारत के कपड़े की अमेरिका में वास्तविक बिजली)	अमेरिका द्वारा इस्पात की पूर्ति	भारत में अमेरिकी इस्पात की बिजली की माँग (प्रत्येक 100 इकाई इस्पात के कपड़े की इकाइयाँ)	भारत द्वारा अमेरिकी इस्पात के बदले की जाने वाले कपड़े की पूर्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	1,000	1,000	230	23,000
20	4,000	20,000	175	35,000
30	9,000	30,000	143	42,900
35	14,000	40,000	122	48,000
40	20,000	50,000	108	54,000
46	27,600	60,000	95	57,000
55	28,500	70,000	83	60,200
68	54,400	80,000	82.5	66,000
78	70,200	90,000	78	70,200
83	83,000	1,00,000	76	76,000
86	94,600	1,10,000	74.5	81,950
88.5	1,06,200	1,20,000	73.5	88,500

*Based on A. Marshall, Money, Credit and Commerce, p. 162

नोट—कालम 1, 2 तथा 4 अनुमानित हैं।

$$\text{कालम 3} = \frac{\text{कालम 2}}{\text{कालम 1}} \times 100 \text{ तथा } \text{कालम 5} = \frac{\text{कालम 4} \times \text{कालम 3}}{100}$$

सारणी में प्रत्येक देश की अन्य देश की वस्तु के लिए की जाने वाली मांग (आयात) को दिखाया गया है तथा उम देश विशेष द्वारा प्रत्येक विनिमय अनुपात पर की जाने वाली अपनी वस्तु की पूर्ति (निर्यात) को भी दिखाया गया है। उदाहरण के लिए यदि विनिमय-अनुपात (व्यापार की शर्तें) प्रत्येक 100 इकाई इस्पात के लिए 40 इकाई कपड़ा है (कालम 1 के अनुसार) तो भारत द्वारा की जाने वाली कपड़े की पूर्ति (निर्यात) 54000 इकाइयाँ (कालम 5 के अनुसार) होगी। किन्तु इस विनिमय अनुपात पर अमेरिका द्वारा किया जाने वाला कपड़े का उपभोग (मांग) केवल 20 000 इकाइयों के बराबर ही होगा (कालम 2 के अनुसार)। अतः इस विनिमय अनुपात पर भारत के पास कपड़े की अनिश्चित मात्रा बची रहती है। भारत अपनी इस अनिश्चित कपड़े की मांग को बेचने के लिए उमकी कीमत कम कर देता है, अतः सारणी में विनिमय अनुपात बढ़कर माना कि 95 इकाई कपड़ा (प्रति 100 इकाई इस्पात के) हो जाता है (कालम 1 अनुसार)। इस विनिमय अनुपात पर भी भारत द्वारा की जाने वाली कपड़े की पूर्ति (निर्यात) 60,200 इकाई के बराबर है (कालम 5 के अनुसार) जबकि अमेरिका का कपड़े का उपभोग केवल 38,500 इकाइयों का है (कालम दो के अनुसार)। अतः साम्य की स्थिति में विनिमय अनुपात 78 : 100 होगा (कालम 1 अनुसार) इस स्थिति में भारत द्वारा लिया जाने वाला कपड़े का निर्यात 70 200 इकाई का होगा (कालम 5 के अनुसार) जो कि अमेरिका द्वारा की जाने वाली कपड़े की मांग के बराबर है। इस प्रकार उपरोक्त अनुसूचियाँ साम्य में पारस्परिक मांग अनुसूचियाँ ही हैं और इन्हें रेखा चित्रों द्वारा और ज्यादा स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है। पारस्परिक मांग वक्रों को मार्शल एजवर्थ का प्रस्ताव वक्र (Marshall Edgeworth Offer Curve) भी कहते हैं।

प्रस्ताव वक्र (Offer Curve)

प्रस्ताव वक्र किसी भी देश की प्रत्येक वस्तु की मांग व पूर्ति के लिए विभिन्न संधियों को प्रकट करता है। इसीलिए प्रस्ताव वक्र को मांग पूर्ति वक्र (Demand Supply Curve) भी कहते हैं।

अब हम उपरोक्त सारणी को लेकर प्रस्ताव वक्रों के द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे। ये दोनों देश अमेरिका व भारत दो वस्तुएँ इस्पात व कपड़े का आपस में आदान-प्रदान करना चाहते हैं। अमेरिका इस्पात का निर्यात (पूर्ति) करता है तथा कपड़े का आयात (मांग) करता है। इसके विपरीत, भारत कपड़े का निर्यात (पूर्ति) करता है एवं इस्पात का आयात (मांग) करता है। चित्र में OY अक्ष पर कपड़े की पूर्ति अर्थात् भारत द्वारा कपड़े का निर्यात एवं अमेरिका द्वारा कपड़े का आयात को लिया गया है। जो सारणी में कालम 2 पर प्रकट किया गया है जबकि OX अक्ष पर अमेरिका द्वारा इस्पात की पूर्ति अर्थात् भारत द्वारा इस्पात का आयात एवं अमेरिका द्वारा इस्पात का निर्यात लिया गया है जो कि सारणी में कालम 3 का प्रकट करता है।

होने वाले परिवर्तनों या व्यापार से होने वाली प्राप्तियों के साथ एक रूप बना लेते हैं। देश के कल्याण का व्यापार की शर्तों में परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अनुमान लगाना सरल नहीं है, यह विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह उन शक्तियों पर आधारित है जो व्यापार की शर्तों में परिवर्तन का कारण बनती है। जब कभी एक देश के शुद्ध लेन-देन का व्यापारिक शर्तों में परिवर्तन होता है तो इससे यह प्रतीत होता है कि देश की स्थिति पहले की तुलना में अच्छी नहीं है क्योंकि उसे आयात की निश्चित मात्रा के लिए अधिक सामान निर्यात करना पड़ेगा। समस्त चीजें अपरिवर्तित रहते हुए भी यदि एक देश के निर्यात के लिए विदेशों में माँग कम हो जाए तो उस देश के व्यापार की स्थिति बर्बर हो जाएगी। दूसरी ओर यदि तकनीकी परिवर्तनों के कारण उत्पादन लागत घट जाए तो उसे लाभ होगा क्योंकि वह अपने निर्यात के लिए अधिक आयात प्राप्त कर सकेगा।

व्यापार की आय-शर्तें कल्याण में होने वाले परिवर्तनों की विश्वस्तरीय सूचना नहीं देती। हो सकता है कि आयात की कीमत तथा मात्रा अपरिवर्तित रहें और पिछले वर्ष और इस वर्ष दोनों में आयात और निर्यात, का मूल्य बराबर रहे। यदि निर्यात के मूल्य बढ़ते हैं तो देश कल्याण की दृष्टि से अच्छी स्थिति में रहेगा क्योंकि वह अपने निर्धारित निर्यात की मात्रा के बदले अधिक आयात प्राप्त कर सकेगा और इस प्रकार वास्तविक राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगी। व्यापार की आय-शर्तें अपरिवर्तनीय होती हैं और इसलिए वे कल्याणकारी प्राप्तियों को अभिव्यक्त नहीं करती। जब एक देश की शुद्ध लेन-देन की व्यापारिक शर्तें घटती हैं तो उसके व्यापार की आय शर्तें बढ़ सकती हैं निर्यात के मूल्यों में सापेक्षिक कमी होते हुए भी निर्यात की मात्रा के बढ़ने पर व्यापार की आय शर्तों का सूची-पत्र बढ़ सकता है। एक विकासशील देश के लिए आयात की क्षमता उसके विकास कार्यक्रमों एवं कल्याण की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हो सकती है इसके परिणामस्वरूप उसकी स्थिति में सुधार हो सकता है।

विनियम का अनुपात—स्वतन्त्र व्यापार के परिणामस्वरूप विश्व में उत्पादन की मात्रा अधिक से अधिक बढ़ जाती है किन्तु इस बड़े हुए उत्पादन के वितरण की समस्या पर्याप्त महत्वपूर्ण बन जाती है। व्यापार करने वाले देशों के बीच विश्व के उत्पादन का विभाजन एक राष्ट्र के आयात और निर्यात के मध्य स्थित विनियम के अनुपात पर निर्भर करता है। यही विनियम का अनुपात उसके व्यापार की शर्तों को सुधारने में सक्षम हो सकता है और इस प्रकार वह विश्व के उत्पादन में से अधिक से अधिक भाग अपने लिए प्राप्त कर सकेगा। अर्थशास्त्रियों ने सामान्य रूप से इस बात की सम्भावना प्रकट की है कि एक राष्ट्र दूसरे देशों के विरुद्ध शूल से स्वयं लाभ उठा सकता है। इतने पर भी इन अर्थशास्त्रियों ने इसे अधिक व्यावहारिक महत्व प्रदान नहीं किया है। इसके दो कारण हैं। प्रथम यह है कि जो देश प्रशुल्क लगा रहा है वह केवल तभी लाभान्वित हो सकता है जबकि विदेशी पूँति लोचविहीन हो प्रथम विदेशी उत्पादक आयात करने वाले देश को कम सामान बेचने की अपेक्षा अपने

माल की कीमत घटा दे। अधिकांश भागों में हम यह आशा नहीं कर सकते कि विदेशी पूर्ण पूर्ण रूप से सोचहीन होगी।

प्रशुल्क का प्रभाव—विदेशी उत्पादक अपने निर्यात के लिए अन्य रास्ते भी रख सकते हैं अथवा वे दूसरी वस्तु का उत्पादन भी प्रारम्भ कर सकते हैं अथवा वे उत्पादन की मात्रा को भी घटा सकते हैं। प्रशुल्क लगाने वाले देश का आकार भी महत्व रखता है, जो देश विश्व बाजार में छोटा है, व्यापार की शर्तों को सुधारने के उसके अवसर उतने ही कम हो जाते हैं। दूसरे, व्यापार की सुधरी हुई शर्तों से प्राप्त किया जा सकने वाला लाभ उस समय समाप्त हो सकता है यदि विदेशियों के द्वारा प्रशुल्क लगा दिए जाएँ। ऐसी स्थिति में प्रशुल्कों का युद्ध (Tariff War) छिड़ जाएगा। इससे विश्व का सम्पूर्ण व्यापार तेजी से घट जाएगा। विशेषीकरण से प्राप्त होने वाले लाभ समाप्त हो जाएँगे और विश्व का उत्पादन कम हो जाएगा तो प्रत्येक की हानि होगी। कोई भी देश अपने व्यापार की शर्तों को आसानी से खराब करने की अनुमति नहीं देगा और यदि किसी ने ऐसा करने का प्रयास किया तो वह उसका पूरा विरोध करेगा। स्पष्ट है कि व्यवहार में कोई भी एक देश लाभान्वित नहीं होगा।

व्यापार शर्तों के निर्धारक घटक

(Determination of Terms of Trade)

किसी देश की व्यापारिक शर्तें हमेशा अनुकूल या प्रतिकूल नहीं रहती बरन् वे समय-समय पर बदलती रहती हैं। राष्ट्रों की पारस्परिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन, व्यापार की शर्तों का समय-समय पर बदलत रहते हैं। यह हो सकता है कि एक समय व्यापार का संतुलन जिस देश के अनुकूल था वह अन्य समय उनके प्रतिकूल हो जाए। वास्तव में व्यापार शर्तों को प्रभावित करने वाली घनेक बातें हैं। इनमें प्रमुख निम्न प्रकार हैं—

1 माँग में परिवर्तनों के प्रभाव 2 प्रशुल्कों के प्रभाव 3 अनुमूलन का प्रभाव 4 पूँजी की गतिशीलता का प्रभाव 5 आयातक देश के आकार का प्रभाव 6 व्यापार षट्रों का प्रभाव 7 स्थानान्तरणों का प्रभाव 8 प्राथमिक विकास के प्रभाव 9 राजनैतिक स्थिति के प्रभाव।

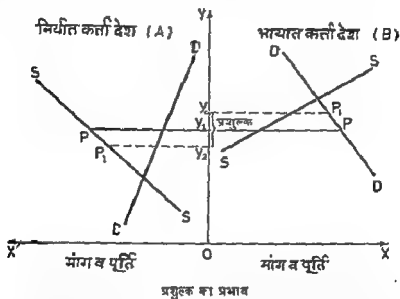
1 माँग में परिवर्तनों के प्रभाव

व्यापार-शर्तों में परिवर्तन का एक कारण किसी देश के आयात या निर्यातों के लिए माँग में परिवर्तन होता है। इस विषय के सैद्धांतिक विश्लेषण में विशेष माँग परिवर्तन के प्रभाव को निर्धारित किया जाता है। इसके मॉडल में A और B दो देश होते हैं तथा X एवं Y दो वस्तुएँ होती हैं। दोनों देशों की अर्थ व्यवस्था में प्रतिযোগिता पूर्ण होती है और वे दोनों हर समय पूर्ण रूप से कार्यरत रहते हैं। विदेशों में माँग की लोच एवं स्वदेश में माँग की लोच के द्वारा व्यापार शर्तों का पर्याप्त रूप से प्रभावित किया जाता है। माँग में होने वाले परिवर्तन विभिन्न रूप धारण कर सकते हैं और उनका प्रभाव भी अलग-अलग तरह से होगा। वास्तविक

व्यवहार में इस सम्बन्ध में कोई अविव्यवहारी नहीं की जाती कि किस प्रकार का परिवर्तन कब होगा और उसका क्या प्रभाव रहेगा। अन्य बातों के समान रहने पर यदि देश द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिए विदेशों में माँग कम है तो देश अनुकूल व्यापारिक शर्तें प्राप्त कर सकता है और यदि विदेशों में माँग की लोच अधिक है तो व्यापार शर्तें उस देश के विरुद्ध अर्थात् प्रतिकूल हो जाएगी।

2 प्रशुल्कों के प्रभाव

आयात पर लगाया गया प्रशुल्क देने के प्रभाव से एक देश की व्यापार शर्तों को बदल देता है। परन्तु प्रशुल्क का विशिष्ट प्रभाव किस प्रकार से पड़ेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशुल्क किस प्रकार से लगाया गया है और प्रस्ताव वस्तु की माँग की लोच किस प्रकार की है। प्रशुल्क नीति के प्रभाव को आंशिक साम्य विशेषण अथवा मार्गल के प्रस्ताव वस्तु की सहायता से अधिक सरलतापूर्वक समझा जा सकता है।

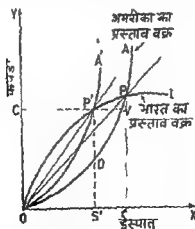


आंशिक साम्य की दृष्टि से—माना कि कोई देश A निर्यातकर्ता तथा देश B आयातकर्ता है। निर्यातकर्ता देश में घरेलू माँग और पूर्ति कम लोचदार है। आयातकर्ता देश B Y_0 Y_2 के दरावर प्रशुल्क लगाता है जिससे प्रत्येक बाजार में मूल्य स्तर P से P_1 हो जाता है तथा आयात की घरेलू कीमत में वृद्धि हो जाने के कारण आयात कम हो जाएगा। प्रशुल्क का कुछ भाग निर्यातकर्ता देश द्वारा और कुछ भाग आयातकर्ता देश द्वारा वहन किया जाएगा। क्योंकि विदेशी निर्यातकर्ता की पूर्ति अधिक है और घरेलू माँग कम है। इसलिए निर्यातकर्ता कीमतें P से घटाकर P_1 कर देगा ताकि वह अधिक वस्तुओं को निर्यात कर सके। चित्र में कुल प्रशुल्क Y_0 Y_2 के Y_1 से लगाया जाता है जिससे Y_1 Y_2 भाग निर्यातकर्ता देश द्वारा और Y_0 Y_1 भाग

आयातकर्ता देश द्वारा बहन किया जाता है क्योंकि $y_1 y_2 < y_1' y_2'$ है, इसलिए प्रमुख का अधिकतम भाग निर्यातकर्ता देश द्वारा बहन किया जाता है। प्रमुख लगाने में देश-B में कीमतों में जो वृद्धि होती है वह उससे कम है जो कि देश-A में कीमतों में कमी होती है अर्थात् देश-B में जो कीमतों में वृद्धि होती है वह निर्यातकर्ता देश में कीमतों में होने वाली कमी की अपेक्षा कम है। ऐसी स्थिति में व्यापार की शक्तें प्रमुख लगाने वाले आयातकर्ता देश (B) के अनुकूल होती हैं।

प्रस्ताव वक्रों के व्यापार पर स्पर्शोत्करण—माना कि भारत तथा अमेरिका में इस्पात और कपड़े के प्रस्ताव वक्र क्रमशः OA तथा OA' हैं। ये वक्र परस्पर P बिन्दु पर काटते हैं। भारत तथा अमेरिका एक दूसरे से यहाँ से क्रमशः इस्पात एवं कपड़े का आयात करते हैं अर्थात् भारत तथा अमेरिका क्रमशः कपड़ा तथा इस्पात का निर्यात करते हैं।

अब माना कि अमेरिका द्वारा इस्पात पर निर्यातकर (प्रमुख) तथा दिया जाता है। इसके फलस्वरूप इसका प्रस्ताव वक्र OA से स्थानान्तरित होकर OA' हो जाता है। इसी प्रकार अमेरिका द्वारा कपड़े का आयात पर प्रमुख लगाने पर भी देश-देश का प्रस्ताव वक्र OA से OA' की स्थिति में ही स्थानान्तरित हो सकता है। चाहे प्रमुख कपड़े के आयात पर लगाए या इस्पात के निर्यात पर प्रमुख का मुख्य दृष्टिकोण यह है कि अब अमेरिका इस्पात के बढ़ने में कपड़े की ब्यादा मांग बाहरी है। माना कि अमेरिका पहले पहले OC मात्र कपड़े के बढ़ने CV इकाइयाँ इस्पात की विनिमय करता था परन्तु प्रमुख के बाद अब $S'P'$ इकाइयों का ही विनिमय करता है। तथा अब $P'V$ इकाइयों प्रमुख के रूप में प्राप्त कर लेता है।



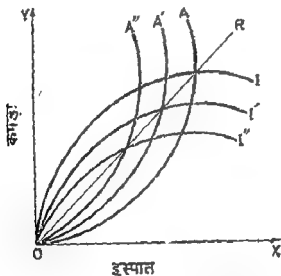
प्रस्ताव वक्र एवं प्रमुख प्रभाव

अर्थात् यहाँ पहले अमेरिका OS' मात्र इस्पात के बढ़ने DS' इकाइयों कपड़े का विनिमय करने को तैयार था अब निर्यात कर लगाने के बाद OS' माना

इस्पात के बदले कपड़े की $P'S'$ इकाइयाँ विनिमय करना चाहता है। इस प्रकार प्रशुल्क लगाने के कारण अमेरिका की प्रस्ताव वक्र के OA से OA' हो जाने से दोनों वस्तुओं का विनिमय अनुपात $\frac{OP}{OS}$ से बदलकर $\frac{OP'}{OS'}$ हो जाता है अर्थात् व्यापार की शर्तें अब अमेरिका के अनुकूल हो गई हैं।

यदि अमेरिका द्वारा कपड़े के आयात पर प्रशुल्क लगाने की प्रतिक्रिया स्वरूप भारत भी इस्पात के आयात पर प्रशुल्क लगा दे तो अमेरिका को प्रशुल्क नीति के कारण लाभ प्राप्त नहीं होगा तथा भारत की प्रतिशोधात्मक (Retaliatory) नीति के कारण अमेरिका की व्यापार-शर्तें उसके लिए प्रतिकूल रहेगी।

यदि भारत व अमेरिका दोनों ही प्रशुल्क की भाड़ में व्यापार करना प्रारम्भ कर दें तो इससे दोनों ही देशों को व्यापार से प्राप्त होने वाले लाभ कम हो जाएँगे। निम्नलिखित चित्र में प्रतिशोध की नीति के प्रभाव व्यक्त किए गए हैं—



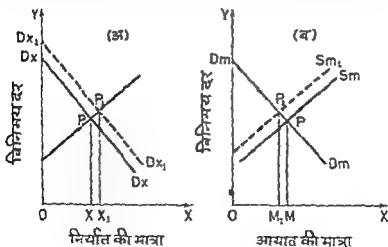
प्रस्ताव वक्र एवं प्रतिशोधात्मक प्रशुल्क नीतियाँ

उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि भारत तथा अमेरिका द्वारा प्रतिशोधात्मक प्रशुल्क नीतियाँ अपनाने के कारण व्यापार की शर्तें अपरिवर्तित रहेगी। इसीलिए दोनों वस्तुओं का विनिमय अनुपात रेखा OR स्थिर है। इस नीति का प्रभाव यह पड़ता है कि इसके फलस्वरूप व्यापार का परिमाण काफी कम हो जाता है। व्यापार की मात्रा में हुई इस कमी के कारण विदेशी व्यापार से दोनों देशों को होने वाले लाभ की मात्रा भी कम हो जाती है। इसी कारण से एडम स्मिथ ने प्रशुल्क नीति का विरोध किया था।

3 अवमूल्यन का प्रभाव

जब अवमूल्यन के राष्ट्रीय भाव पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार किया जाता है तो व्यापार-शर्तों एवं आर्थिक मन्दी के बीच स्थित सम्बन्धों का ज्ञान होता है। अर्थशास्त्रियों की रचि का प्रश्न मुख्य रूप से यह है कि क्या अवमूल्यन के कारण निर्यात मूल्यों की अपेक्षा आयात मूल्य अधिक बढ़ जाता है और इस प्रकार क्या उन देश की वास्तविक प्रामदनी घट जाती है? इस सम्बन्ध में प्रकाशित साहित्य द्वारा यह निश्चित किया गया है कि व्यापारिक शर्तों में विरोधी परिवर्तन वास्तविक प्रामदनी को आवश्यक रूप से नहीं घटाना है। आर्थिक मन्दी और व्यापार शर्तों के मध्य सम्बन्ध रहता है।

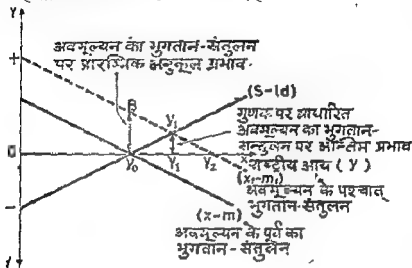
अवमूल्यन के कारण देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के रूप में कम हो जाता है। इसके फलस्वरूप देश की वस्तुओं को विदेशों में माँग अर्थात् देश की निर्यात माँग में वृद्धि होगी। इसके विपरीत अवमूल्यन के कारण विदेशी वस्तुओं का देश की मुद्रा के रूप में अधिक मुगलान करना पड़ना है। इस कारण विदेशी वस्तुओं की माँग अर्थात् देश में विदेशी वस्तुओं की पूर्ति में कमी हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि मुद्रा अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप देश के निर्यातों में वृद्धि और आयातों में कमी हो जाती है। निम्नांकित चित्रों से अवमूल्यन का विदेशी व्यापार पर पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट किया गया है—



अवमूल्यन का आयात व निर्यात की माँग पर प्रभाव

उक्त रेखाचित्र (अ) अवमूल्यन का निर्यात माँग पर पड़ने वाले प्रभाव का प्रकट करता है तथा (ब) में अवमूल्यन के कारण आयातित वस्तुओं की पूर्ति में हुई कमी को प्रकट किया गया है। उपरोक्त चित्रों में स्पष्ट है कि अवमूल्यन के परिणामस्वरूप निर्यात OX से बढ़कर OX_1 हो जाता है जबकि आयात OM से घटकर

OM_1 हो जाता है। निर्यातों में वृद्धि होने और आयातों में कमी होने से व्यापार की शर्तें देश के अनुकूल हो जाती हैं। इसके साथ ही अवमूल्यन आयात में कमी करके और निर्यात में वृद्धि करके भुगतान सन्तुलन पर भी अनुकूल प्रभाव डालता है। यह बात निम्न रेखाचित्र के द्वारा स्पष्ट की गई है—



अवमूल्यन का भुगतान सन्तुलन पर प्रभाव

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान सन्दर्भ में भुगतान सन्तुलन में केवल वस्तुओं के आयात व निर्यात को ही सम्मिलित किया गया है जिससे अवमूल्यन के परिणामस्वरूप जब निर्यात में वृद्धि एवं आयात में कमी हो जाती है तो देश का भुगतान सन्तुलन पहले की अपेक्षा अनुकूल हो जाता है। उपरोक्त रेखाचित्र में Y_0 प्रारम्भिक आय के स्तर को प्रकट करता है जहाँ आयात और निर्यात बराबर हैं। अवमूल्यन के बाद भुगतान सन्तुलन अनुकूल होने के कारण भुगतान सन्तुलन वक्र $(X-M)$ बायीं ओर विवर्तित हो जाता है और Y_0 B राशि का विगुण भुगतान देश को अन्य देशों से प्राप्त होगा परन्तु कालान्तर में निर्यात के आयात से अधिक में कमी होती जाएगी और अन्ततः Y_2 आय पर आयात और निर्यात पुनः बराबर हो जाएँगे। वस्तुतः अवमूल्यन के फलस्वरूप भुगतान सन्तुलन एवं देश की राष्ट्रीय आय पर जिसना अनुकूल प्रभाव पड़ेगा वह इस बात पर निर्भर करेगा कि $(S-Id)$ वक्र का ढलाव अर्थात् गुणक का मूल्य कितना है।

जब एक देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसके निर्यात की विदेशी कीमतें गिर जाती हैं। इसके विपरीत आयात की घरेलू कीमतें साधारणतः बढ़ जाती हैं। इसलिए अनेक लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अवमूल्यन से विदेशी व्यापार अनुकूल हो जाता है। कुछ लेखकों का कहना है कि यह निष्कर्ष व्यापार की शर्तों की गतत परिभाषा पर आधारित है क्योंकि इसमें निर्यात की विदेशी कीमत

घोर आयात की घरेलू कीमत पर विचार किया जाता है। सही प्रक्रिया तो यह होगी कि निर्यात और आयात मूल्यों की एक ही मुद्रा में तुलना की जाए फिर वह चाहे घरेलू हो चाहे विदेशी। अवमूल्यन के फलस्वरूप प्रायः आयात और निर्यात दोनों के मूल्य घरेलू मुद्रा में बढ़ जाते हैं और विदेशी मुद्रा में घट जाते हैं। आयात मूल्यों की अपेक्षा निर्यात मूल्य घटते हैं या इसका निश्चय करने के लिए अधिक जानकारी की आवश्यकता है।

आर्थिक मन्त्री के परिणामस्वरूप आयात और निर्यात की कीमतों पर जा प्रभाव पड़ता है वह पूर्ति की लोच द्वारा निर्धारित होता है। यदि आयात और निर्यात के लिए पूर्ति की लोच असोमिष्ठ हो तो अवमूल्यन द्वारा निर्यात के घरेलू मूल्य में कोई अन्तर नहीं आएगा किन्तु इससे आयात का घरेलू मूल्य अनुपातिक रूप से बढ़ जाएगा। 5% अवमूल्यन करने से व्यापार की शर्तें 5% घट जाएगी। असल में अवमूल्यन का प्रभाव निर्यात और आयात पर तथा निर्यात और आयात के लिए पूर्ति और पूर्ति की लोच पर निर्भर रहता है।

इस सम्बन्ध में दूसरा प्रश्न यह उठता है कि क्या वास्तविक स्थितियाँ अवमूल्यन करने वाले देश को बदतर बना देंगी? श्रीमती रोबिन्स के निष्कर्ष व मनुमार 'क्योंकि देश आयात की अपेक्षा निर्यात में अधिक विशेषीकरण प्राप्त करते हैं इसलिए व्यापार शर्तों का बदतर होना सम्भव है।' इसलिए एक देश जिन वस्तुओं का निर्यात करता है उनकी विश्व पूर्ति में वह अधिक प्रभावशाली रहेगा और जिनका आयात करता है उनकी माँग में कम प्रभावशाली रहेगा। इसके प्रतिनिष्ठ आयात व निर्यात माँग की लोच कम हो जाएगी क्योंकि देश सामान्य रूप से उन प्रत्येक वस्तुओं का आयात करते हैं जिनको वे घरेलू रूप से पैदा नहीं कर सकते। निर्यात के लिए पूर्ति की लोच उतनी समय अधिक होती है जितनी निर्यात करने वाले देश में वैयर्थ्यकारी हो। इन सभी तत्त्वों के मिले-जुले प्रभाव के कारण व्यापार शर्तों के बदतर होने की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं। अवमूल्यन और व्यापार शर्तों के बीच स्थित सम्भावित सम्बन्धों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, किन्तु किसी मत की अनुभववादी जाँच नहीं हो पाई है और इसलिए विचारकों के बीच पर्याप्त मतभेद है।

4 पूँजी की गतिशीलता का प्रभाव

हम यह जानते हैं कि देश में पूँजी की प्राप्ति होने पर मुक्तता मनुस्तर पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है जबकि पूँजी बाहर जाने पर मुक्तता मनुस्तर पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। इस प्रकार के पूँजी स्थानान्तरण देश के निवासियों या विदेशी नागरिकों के स्वतन्त्र अधिकारों को प्रभावित करते हैं। पूँजी की प्राप्ति का अर्थ यह होगा कि देश के लोगों को विदेशी लोच मुक्तता कर रहे हैं जबकि पूँजी के मुक्तता का अर्थ यह होगा कि देश के लोग विदेशियों को मुक्तता कर रहे हैं। इस प्रकार पूँजी की पर्याप्त प्राप्ति देश की व्यापार शर्तों को अनुकूल बनाती है जबकि पूँजी की प्राप्ति में कमी अथवा विदेशियों के देश के नागरिकों पर बढ़ते हुए दावों से व्यापार की शर्तें देश के लिए प्रतिकूल हो जाती हैं।

5 आयातक देश के आकार का प्रभाव

व्यापार की शर्तें आयात करने वाले देश की माँग के आधार पर भी निर्भर करती हैं। एक विशाल देश जैसे भारत या चीन की माँग प्रायः विशाल होती है। एक बड़ा ग्राहक होने के कारण वह अपने लिए लाभप्रद रूप में सौदेबाजी कर सकता है विशेषतः जबकि निर्यातक देश छोटा हो और अपने अतिरिक्त उत्पादन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में दूसरा ग्राहक ढूँढ़ने में असमर्थ हो।

6 व्यापार शर्तों का प्रभाव

देश या विदेश में व्यापक आर्थिक मन्दी या स्फीति का प्रभाव व्यापार-शर्तों पर अवश्य पड़ता है। जिन देशों में कोई देश अपनी वस्तुओं का निर्यात करता है यदि वह देश मुद्रास्फीति से पीड़ित है तो वहाँ आयात की जाने वाली वस्तुओं की माँग बढ़ जाएगी और निर्यातकर्ता देश के पक्ष में व्यापार-शर्तें हो जाएंगी। इसके विपरीत यदि दूसरे देश में व्यापक मन्दी है तो वहाँ आयात की जाने वाली वस्तुओं की माँग कम होगी और निर्यात करने वाले राष्ट्र की व्यापार-शर्तें प्रतिकूल होंगी।

7. स्थानान्तरणों के प्रभाव

जब एक देश से दूसरे देश को भुगतान का हस्तान्तरण हो जाता है तो उसके फलस्वरूप व्यापार शर्तों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। इस प्रभाव के सम्बन्ध में अर्थशास्त्री बहुत समय पूर्व से ही विचार करते रहे हैं। यद्यपि इस विचार-विमर्श का लम्बा इतिहास है किन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा लगने लगा है कि अर्थशास्त्री उपयुक्त विश्लेषण पर किसी प्रकार की सहमति तक नहीं पहुँच सके। सरल रूप में समझा यह है कि जब एक देश दूसरे देश को भुगतान करता है या भुगतान का स्थानान्तरण (Transfer Payment) करता है तो व्यापार-शर्तों के मुद्दे लेन-देन (The Net Barter Terms of Trade) का क्या होगा। भुगतान की निश्चित प्रकृति महत्त्व नहीं रखती। विश्लेषणकर्ता लोग सामान्य रूप से इसे एकपक्षीय प्रपञ्चा अवाधित भुगतान मान लेते हैं, उदाहरण के लिए—मुद्रा की क्षतिपूर्तियाँ। स्थानान्तरण चाहे कर्ज का हो चाहे कर्ज के पुनः भुगतान का हो, चाहे ध्याज के भुगतान का अथवा एक अनुदान का हो किन्तु व्यापार-शर्तों के सम्बन्ध में समान समस्याएँ उठती हैं।

इस सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण हैं—प्रथम दृष्टिकोण के अनुसार स्थानान्तरण को एक वास्तविक समस्या माना जाता है जबकि दूसरे के अनुसार उसे धन-सम्बन्धी समस्या कहा जाता है। वास्तविक शर्तों में एक दृष्टिकोण ऐसे मॉडल भी माँग करता है जो इस संस्थापक मान्यता पर आधारित हो कि अर्थशास्त्र सभी साधनों का हर समय पूरा प्रयोग करता है। इस प्रकार के सभी लेन-देन अदला-बदली के प्रबन्ध पर आधारित होते हैं। धन द्वारा अर्थव्यवस्था के वयार्थ व्यवहार को प्रभावित नहीं किया जाता। केवल मौखिक मात्राएँ ही उपयोगी होती हैं। इसके विपरीत वार्प-विहीन साधन खोजों की कंनिशियन मान्यता पर आधारित मॉडल में स्थानान्तरण के विश्लेषण पर धन सम्बन्धी पहलू का प्रभाव रहता है। पुति की वक रेखाएँ पूर्ण

रूप से लोचनीय होती है और कुल माँग के आधार पर उत्पादन और धातु का स्तर निर्धारित किया जाता है। स्थानान्तरण के प्रभावों के सम्बन्ध में कॅनेशियन एवं सस्थापक अर्थशास्त्रियों के मॉडल विशेष रूप में महत्व रखते हैं। सस्थापक मॉडल (Classical Model) में दोनों देश स्वयं ही मारे साधनों का प्रयोग करते हैं। यह प्रयोग निरन्तर चलता रहता है। इसके विपरीत कॅनेशियन मॉडल (Keynesian Model) की मान्यता यह है कि देशों के पास अनेक साधन स्रोत ऐसे होते हैं जिनको काम में नहीं लिया जाता है। इस प्रकार निश्चित घरेलू कीमन-स्तरों पर पूर्ति की वजह से पूर्ण रूप से लोचनीय बन जाती हैं।

सस्थापक एवं कॅनेशियन व्यवस्थाओं में स्थानान्तरण समस्या के बीच दो प्रमुख अन्तर पाए जाते हैं। प्रथम यह है कि जिस प्रकार सस्थापक मान्यताओं के आधीन स्थानान्तरण की द्वितीय व्यवस्था दोनों देशों में आवश्यक रूप में कुल धन को परिवर्तित करने में सफल होती है उसी प्रकार कॅनेशियन मान्यता के आधीन नहीं होती। मुगतात करन वाला देश स्थानान्तरण को अपनी वचन बरके पूरी तरह या आंशिक रूप से वित्तीय प्रभाव कर सकता है जबकि प्राप्त करन वाला देश अपनी वचन को बढ़ाकर धन को पूर्ण रूप से बढ़ाकर लीच सकता है। दूसरे, स्थानान्तरण के फलस्वरूप व्यय में होने वाला कोई भी परिवर्तन माध्य और मुगतातों के समुत्पन्न पर कई गुने प्रभाव रहेगा।

४. आर्थिक विकास के प्रभाव

सम्बन्धित देशों व आर्थिक विकास के प्रभाव के सम्बन्ध में व्यापार शर्तों पर प्रभाव पड़ता है। अर्द्ध-विकसित देशों की समस्याएँ तथा डॉलर की वमी में सम्बन्धित विचार-धाराओं ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर आर्थिक विकास और तकनीकी परिवर्तन द्वारा डाले गए प्रभाव में विशेष रुचि पैदा की है। आर्थिक विकास का अर्थ सरल रूप में केवल उत्पादन की वृद्धि है। यह वृद्धि तकनीकी प्रगति, पूँजी के समावेशन या श्रम की पूर्ति के कारण हो सकती है। आर्थिक विकास के प्रभावों का अध्ययन करने समय जिस मॉडल को अपनाया जाता है उपरोक्त दो देश, दो साधन स्रोत और दो वस्तुएँ होती हैं। ये दोनों देश अपने सभी मजदूरों को लगातार कार्य पर रखते हैं और इसके साधन स्रोत एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकते। इस मॉडल में धन का कोई स्थान नहीं है और इसलिए विधेयण सम्बन्धित शर्तों में ही होता है।

१९. राजनैतिक स्थिति के प्रभाव

व्यापार की शर्तें सम्बन्धित देशों की राजनैतिक स्थितियों से भी पराजित प्रभावित होती हैं। राजनैतिक कारणों के प्रभाव-स्वरूप वस्तुओं की उपलब्धि सरल या कठिन बन जाती है। यदि राजनैतिक परिस्थितियाँ अनुकूल हैं तो व्यापारिक शर्तें भी सम्बन्धित देश के अनुकूल ही सकती हैं और यदि राजनैतिक परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं तो वे व्यापार की शर्तों को प्रतिवृत्त बना सकती हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि एक देश की व्यापार-शर्तें अनेक ऐसे तत्वों से प्रभावित होती हैं जो उसके प्राचीन भी हैं और नवीं भी। स्वदेश में यदि पूर्ति को लोच अधिक है तो एक देश विदेशों की माँगों के अनुसार शीघ्र ही समायोजन कर लेगा। इसी प्रकार यदि आयात करने वाले देश की माँग का आकार बड़ा है तो उसका भी व्यापार शर्तों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ेगा। एक बड़े आकार वाला देश, जहाँ माँग अत्यधिक है, पूर्ति करने वाले देश के साथ सौदा करते समय सुदृढ़ स्थिति में रहता है क्योंकि वह उसका एक बहुत बड़ा ग्राहक है। दूसरी ओर जब पूर्ति करने वाला देश छोटे आकार का होता है तो उसे सौदेबाजी में भुविष्ठा रहनी है।

व्यापार शर्तों के मापने में दोष

(Defects in Measuring the Terms of Trade)

प्रो० टॉसिंग की भाँति कुछ अन्य अर्थशास्त्री व्यापार शर्तों की सांख्यिकीय रूप में गणना करते हैं। अनेक अर्थशास्त्रियों ने इस प्रकार की गणना की गलत बताया और विभिन्न आलोचनाएँ प्रस्तुत की—

(1) सूचकांकों की समस्या—इस प्रकार की गणना में आयात और निर्यात के प्राथमिकों के कारणों की उपेक्षा कर दी जाती है। जब आयात और निर्यात के वास्तविक मूल्यों की एक सूची बनाई जाती है तो वह निश्चय ही अत्यन्त रोचक लगती है किन्तु इस सूची के अतिरिक्त उन कारणों को स्पष्ट करना भी जरूरी होता है जिनके फलस्वरूप आयात अथवा निर्यात में वृद्धि होती है। कारणों के अनुसार ही आयात और निर्यात का रूप भी बदल जाता है, अतः उनको एक ही ध्रेणी में रखने की अपेक्षा अलग-अलग ध्रेणियों में रखा जाए तो उपयुक्त होगा।

(2) लाभ-हानि का निर्धारण—वास्तविक आयात-निर्यात के मूल्यों का सूचीपत्र अन्तर्राष्ट्रीय लाभ-हानि को स्पष्ट करने में अनुपयुक्त रहता है। यह स्पष्ट है कि हानि के मुग़तानों को हानि माना जाए किन्तु यह हानि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण नहीं हुई। एक देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अतिरिक्त भी अधिक हानि तथा लाभ से प्रभावित हो सकता है। व्यापार शर्तों की मापनता का प्रयोग पहले यह प्रदर्शित करने के लिए किया गया था कि कुल लाभ को दो देशों के बीच किस प्रकार वितरित किया जाता है। अधिक लाभ किस देश को दिया जाए और कम लाभ किस देश को दिया जाए इस प्रश्न का उत्तर व्यापार की शर्तों के आधार पर दिया गया। व्यापार की शर्तें लाभ और हानि को तय कर सकती हैं किन्तु उनके आधार पर लाभ-हानि का पता लगाना मौलिक रूप से असम्भव है।

(3) एकपक्षीय व्यापार मुग़तान—इस प्रकार की गणना करते समय एक-पक्षीय व्यापार मुग़तानों को समाविष्ट कर लिया जाता है जो अपने आप में गलत होता है। इससे अनिश्चित ऋण स्वीकृति के परिणामस्वरूप जो निर्यात बढ़ता वह प्रतिश्रुतता का सूचक नहीं है।

(4) अनेक वस्तुएँ तथा सेवाएँ—व्यापार शर्तों को मापना उस स्थिति में अत्यन्त सरल होता है जब एक देश केवल एक जैसी चीजों का आयात और निर्यात

करता है। वास्तविक व्यवहार में प्रत्येक देश घनत्व वस्तुओं तथा सेवाओं का आयात और निर्यात करता है। ऐसी स्थिति में यदि हम व्यापार शर्तों में होने वाले परिवर्तनों का मापना चाहें तो सत्यापन का सूचीपत्र बनना होगा।

(5) गुणों में परिवर्तन—जिन चीजों का व्यापार किया जा रहा है यदि उनके गुण में प्रायः परिवर्तन होता रहता है तो सांख्यिकी कीमतों में होने वाले परिवर्तन अतिरिक्त लाभदायक नहीं रहते। दशोत्काल में निर्मित मानक गुणों में विषय सुझाव हो सकता है। इनका सुधार प्राथमिक उपायों का एक में नहीं आता है।

(6) रचना में परिवर्तन—अधिकोण माल विभिन्न प्रकारों द्वारा तथा प्रकारों में उपलब्ध होना है। यदि आयात में निर्यात की चीजें बाली वस्तु की कामना में परिवर्तन आता है तो उसी रचना में भी तत्सुसार परिवर्तन आता है।

(7) तोड़ने की समस्या—आयात और निर्यात की कीमतों की रचना परिवर्तित होने के कारण विभिन्न वस्तुओं के तात्कालिक समस्या उठ खड़ा होता है। विभिन्न वस्तुओं की कामना का औसत लगाने का प्रक्रिया में सभी पक्षों का समान महत्त्व नहीं दिया जा सकता। विभिन्न पक्षों का महत्त्व समय समय बदलता रहता है और इसी स्थिति में एक विषय समय में जा तोल प्रतिनिधित्वपूर्ण या यह दूसरे समय में भी हो यह जरूरी नहीं है।

(8) मातापिता तथा बच्चे की कीमत—अधिकोण देश ऐसे प्रायः 120 पक्षों करते हैं जिनमें आयात और आमा के बीच का सम्मिलित रहता है। वे ऐसे नियमों को पक्षों करते हैं जिनमें यह सर्वा सम्मिलित नहीं रहता। जहाँ जहाँ मातापिता से सम्बन्धित काम मुख्य रूप से विकसित देशों के आयात में है और इससे एक अर्थव्यवस्था के देशों के निर्यात के अर्थव्यवस्था पर यह एक अतिरिक्त व्यय होता है। इससे द्विपक्षीय आयात और आमा के सम्मिलित करने पर विवक्षित देशों की आयात कीमतों पर इस लक्ष्य का भी सम्मिलित कर लेती है जो प्रत्येक में अर्थव्यवस्था का आयात नहीं किया जाता। यदि प्रगतिशील देशों के आयातों का कामना बढ़ता है तो यह आयातों तथा कीमा प्राप्ति का लक्ष्य बनने के कारण भी हो सकती है। इस प्रकार बड़ा आयात निर्यात करता अर्थव्यवस्था के देशों को न जाकर घर में ही रहेगा। यदि व्यापार शर्तों में सत्यापन का भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे अतिरिक्त वास्तविक बन सकेंगे। व्यापार शर्तों द्वारा पूर्ण कीमतों की नहीं बरन् कीमतों के अनुपात का मन्वित किया जाता है।

(9) नमूनों की समस्या—नमूनों के आकार में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ व्यापार शर्तों भी बदल जाती हैं। प्रायः यह पाया गया है कि व्यापार शर्तों में परिवर्तनों में पक्षों प्रभावित होती है।

इस प्रकार व्यापार शर्तों के मापन में अनेक मौखिकीय समस्याएँ उठती हैं। इन समस्याओं का उपाय कोई मरन होना नहीं होता जो सुझावों के भी इनका

अर्थ यह नहीं है कि व्यापार शर्तों को मापने के लिए किए गए प्रयास पूरी तरह महत्वहीन हैं। प्रसत में ये विभिन्न योगाएँ एक प्रतिबन्ध का कार्य करती हैं, ताकि व्यापार शर्तों की सौख्यनीयता का स्वेच्छा से प्रयोग न किया जा सके।

व्यापार-शर्तों का व्यावहारिक महत्त्व (Practical Importance of Terms of Trade)

(1) लाभ का अनुमान—व्यापार शर्तों की मान्यता को विभिन्न दृष्टिों से उपयोगी माना गया। इसका व्यावहारिक जीवन में प्रभाव होना है। विचारकों के मतानुसार इन मान्यता का पहला महत्त्व तो यह है कि इनके आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में होने वाले लाभ का अनुमान लगाया जा सकेगा। एक देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विनियम से कितना लाभ प्राप्त करेगा? यह बात व्यापार-शर्तों की सहायता से ही जानी जा सकती है। जब व्यापार शर्तें व्यावहारिक होती हैं तो देश को अधिक लाभ प्राप्त होता है, जब व्यापार शर्तें प्रतिकूल होती हैं तो लाभ कम प्राप्त होता है।

(2) उत्पादन व रोजगार की स्थिति—व्यापार शर्तों के आधार पर यह तथ्य विदित होता है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों का कितना प्रतिशत प्राप्त हो सकेगा तथा रोजगार की कितनी मात्रा कार्यरत रह सकेगी। व्यापार शर्तों के अनुकूल तथा प्रतिकूल रहने पर ही उत्पादन के साधनों का पुनर्धार एवं रोजगार निर्भर करता है। जब व्यापार की शर्तें अनुकूल होती हैं तो निर्यात के उद्योग बहुत कुछ सम्पन्न हो जाते हैं और रोजगार तथा मजदूरी की मात्रा भी बढ़ जाती है।

(3) आर्थिक विकास में सहयोग—व्यापार शर्तों की मान्यता आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करती है। जो देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, यदि उनके अनुकूल व्यापार शर्तें बन जाती हैं तो उनकी औद्योगिक प्रगति एवं आर्थिक विकास तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। ये देश अनुकूल व्यापार शर्तों होने पर ही अपने माल का निर्यात करके अधिक पूंजीगत वस्तु एवं मशीनों का आयात कर सकते हैं। जब व्यापार-शर्तें एक देश के प्रतिकूल होती हैं तो उसे निर्यात का कम से कम पुरस्कार मिलता है और इसलिए सम्बन्धित देश का आर्थिक विकास रुक जाता है।

(4) विदेशी विनियम की आवश्यकता—व्यापार शर्तों के आधार पर विदेशी विनियम की आवश्यकता का अनुमान लगाया जा सकता है। व्यापार शर्तों द्वारा हमारे सम्मुख निर्यात एवं आयात के मूल्य का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है और इनके आधार पर हम विनियमों के मापदंडों पर विचार कर सकते हैं। हम अनुमान के आधार पर एक देश अपनी विदेशी मुद्रा की स्थिति तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों को जान सकता है।

व्यापार शर्तें और अर्द्ध-विकसित देश (Terms of Trade and Under-developed Countries)

प्राथमिक उत्पादन—अर्द्ध-विकसित देश निर्यात वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञ नहीं होते बल्कि वे प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन के विशेषज्ञ होते हैं। इन देशों की

व्यापार शर्तें प्रायः प्रतिकूल होती जा रही हैं। इसका कारण यह नहीं कि इनका उत्पादन खपत की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ रहा है, सब तो यह है कि औद्योगिक देशों में उत्पादन की क्षमता प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादनकर्ता देशों की अपेक्षा अधिक बढ़ गई है। प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले देशों में व्यापार शर्तों के विपरीत होने का कारण मि० सिंगर (Mr W H Singer) न वर्णित किया है। उनके मतानुसार तकनीकी प्रगति के फल या तो अधिक आय के रूप में उत्पादकों को प्रदान किए जाते हैं अथवा कम कीमतों के रूप में उपभोक्तानों को दिए जाते हैं। जहाँ तक निर्माता देशों का सम्बन्ध है, वे तकनीकी प्रगति के फलों को उच्च भ्रामदनी के रूप में उत्पादकों को सौंपते हैं जबकि प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले देशों में यह फल कम कीमतों के रूप में उपभोक्तानों को प्रदान किया जाता है। विचारकों का कहना है कि औद्योगिक देशों में मजदूरों के व्यापार सब अधिक शक्तिशाली होते हैं। कृषि-प्रधान देशों में जहाँ कि मजदूर बिजरा हुआ रहता है, वे ऐसे नहीं होते। प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले देशों में बेरोजगारी और बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव मजदूर की सौदेबाजी करने की शक्ति को घटा देते हैं।

लोचहीनता—औद्योगिक देशों की अर्थ व्यवस्थाएँ प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले देशों की अपेक्षा अधिक लोचशील हैं। जब इनके उत्पादनों की विश्व कीमतें गिरती हैं तो वे अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने लगते हैं। यह बात प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले देशों में सम्भव नहीं है क्योंकि उनकी अर्थ-व्यवस्थाएँ अत्यन्त कठिन होती हैं और उनमें समायोजन करने की क्षमता नहीं होती। यही कारण है कि कुछ प्राथमिक उत्पादन करने वाले प्रगतिशील देश अपनी व्यापार शर्तों में विपरीत स्थिति का सामना नहीं कर पाते।

कृत्रिम कच्चा माल—सम्पन्न देशों में खाद्यान्न और कच्चे माल के घरेलू उत्पादन में वृद्धि होने के कारण उन्हें अब अर्द्ध-विकसित देशों से आयात नहीं करनी होती। तकनीकी विकास के कारण कच्चे माल की आवश्यकता अब पर्याप्त घट गई है। कृत्रिम रेशे का आविष्कार हो जाने के कारण प्राकृतिक कच्चे माल का उत्पादन पर्याप्त प्रभावित हुआ है और इसलिए प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले देशों के निर्यात घट गए हैं। प्राथमिक उत्पादन की निर्यात-कीमतों में अस्थायित्व रहता है और इसलिए सम्पन्न देश अधिक कृत्रिम कच्चे माल की ओर उन्मुख होते जा रहे हैं।

विशेषीकरण—अर्द्ध विकसित देशों ने मुख्य रूप से कृषि और खनिज पदार्थों के निर्यात में विशेषीकरण प्राप्त किया है किन्तु इन वस्तुओं के लिए माँग की लोच अत्यन्त कम है। इसके विपरीत सम्पन्न देशों ने मुख्य रूप से औद्योगिक माल के निर्यात में विशेषीकरण प्राप्त किया है। इसके लिए माँग की लोच अपेक्षाकृत ऊँची है। ज्योंही एक देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है त्योंही निमित्त वस्तुओं पर होने वाले खर्च का अनुपात बढ़ जाता है और भोजन पर होने वाले खर्च का अनुपात

घट जाता है। इस प्रकार विश्व की आय में वृद्धि के साथ-साथ सम्पन्न देशों के निर्यातों की माँग बढ़ जाती है और प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले देशों की माँग इतनी नहीं रहती।

सम्पन्न देशों में घरेलू कृषि उद्योग की रक्षा के लिए कृषि-सम्बन्धी माल के आयात पर प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं। इसके फलस्वरूप कृषक देशों के निर्यात की माँग घटती है। संयुक्तराज्य अमेरिका आदि कुछ सम्पन्न देशों में स्वयं के कृषि उद्योग में बेरोजगारी को दूर करने के लिए न केवल कृषि सम्बन्धी आयातों पर प्रतिबन्ध लगाए हैं बल्कि कृषि सम्बन्धी माल के निर्यात की सहायता करके प्रोत्साहित रूप से कम विकसित देशों के साथ प्रतिप्रोत्साहित भी की है। इसके परिणामस्वरूप कम विकसित देशों के निर्यात विपरीत रूप से प्रभावित हुए हैं।

अर्द्ध-विकसित देशों की जनसंख्या सम्पन्न देशों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ रही है। इसके फलस्वरूप इन देशों में आयातों की आवश्यकताएँ बढ़ गई हैं। दूसरी ओर सम्पन्न देशों में जनसंख्या कम होने के कारण वहाँ अर्द्ध-विकसित देशों से होने वाले निर्यात की माँग का प्रसार रुक गया है। अतीतकाल में अधिकांश विदेशी गैर-सरकारी निवेश निर्यात-उद्योगों में किए जाते थे; यह प्रवृत्ति अभी भी कायम है। प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले देशों में निर्यात उद्योगों का प्रसार होने के कारण उनके निर्यातों की कीमतें घट गई हैं। अर्द्ध-विकसित देश अपने आयातों और निर्यातों के लिए सम्पन्न देशों पर निर्भर हैं। उनमें सौदेबाजी की क्षमता भी कम है। इन समस्त कारणों से अर्द्ध-विकसित देशों की व्यापार-शर्तें उनके विपरीत गतिशील हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ (The Gains from International Trade)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार मूल्यों के बीच भिन्नताएँ होती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व यह प्रमाणित करता है कि एक वस्तु के मूल्यों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय-स्तर पर पर्याप्त अन्तर होंगे। विभिन्न देशों में वस्तुओं की लागत का अन्तर विभिन्न कारणों का परिणाम होता है।

कुछ विचारकों ने धन को विशेष महत्व दिया है। उनका कहना है कि मजदूरी ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण लागत होती है और इसलिए यदि किसी देश में एक वस्तु के उत्पादन में कम मजदूरी लगती है तो निश्चय ही वह कम कीमत में तैयार हो सकेगी। अन्य विचारकों के अनुसार यह स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए संयुक्तराज्य अमेरिका में मजदूरी की दरें बहुत ऊँची हैं, किन्तु इतने पर भी, हमारे निर्यात की, पाट, घाघण्ट, की, नुल्ल, ये, यंत्रिका, हे, १, ऐसी, स्थिति, में, मजदूरी की दरों का अन्तर व्यापार के रूपों का स्पष्टीकरण नहीं कर सकता और इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के किसी अन्य आधार की तलाश करनी पड़ेगी।

वस्तुओं की कीमत और लागत में व्यवस्थित अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरों के कारण देशों के बीच आदान-प्रदान सम्भव बनता है। एक देश जिन चीजों को कम कीमत

मे पैदा कर सकता है उनका निर्यात करेगा और जिन चीजों को मँहेंगी लागत पर पैदा कर सकता है उनका आयात करेगा। यही सामान्यीकरण विदेश-व्यापार के अस्तित्व का आधार है। इसे तुलनात्मक लाभ का सिद्धान्त कहा जाता है।

दो देशों के बीच उत्पादन लागत का अन्तर प्राकृतिक एवं मनुष्यकृत दोनों प्रकार के साधनों का परिणाम है। प्रकृति ने विभिन्न देशों में महत्वपूर्ण तथा स्थायी अन्तरों की स्थापना की है। इनमें से कुछ ताँपे की दृष्टि से सम्पन्न हैं तथा अन्य पैदाल की दृष्टि से। वही घर बड़े-बड़े भरने गिरते हैं तो कहीं उपजाऊ प्रदेश हैं। कुछ देशों में केवल इनकी वरसात होती है कि वहाँ चावल और ऊई की खेती की जा सके जबकि अन्य देशों में इससे भी अधिक वरसात होती है। दूसरे देश वरसात की दृष्टि से शुष्क होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ कुछ प्रमुख कार्यों को सम्पन्न करने के लिए उपयुक्त साधन स्रोतों का योग प्राप्त होता है।

कुछ देशों में बड़े बड़े जटिल उद्योगों को समर्थित करने के लिए बहुत बड़ी जनसंख्या होती है जबकि दूसरों में इतनी कम जनसंख्या होती है कि वहाँ भूमि से पर्याप्त लाभ नहीं उठाया जा सकता। जनसंख्या को एक दृष्टि से तो हम प्राकृतिक साधन कह सकते हैं और दूसरी दृष्टि से उसको मनुष्यकृत साधन कहेंगे। लोगो की संख्या मात्र तो प्रकृति की दैन है किन्तु उनकी कुशलता एवं उनके दृष्टिकोण की रचना मनुष्यकृत विशेषता होती है जो एक देश के तुलनात्मक लाभ को प्रभावित करती है। एक देश जो जनसंख्या में सम्पन्न है किन्तु उसकी कुशलता में गरीब है तो वह कुछ कार्यों के लिए उपयुक्त हो सकता है किन्तु निमित्त माल के उत्पादन एवं निर्यात के लिए उपयोगी नहीं रहेगा। दूसरी ओर जिस देश की जनसंख्या कम है किन्तु लोग पर्याप्त शिक्षित हैं तो उसे उत्पादन में अपेक्षाकृत लाभ रहेगा।

जनसंख्या की कुशलता कई प्रकार की होती है। कुछ देशों में फैक्ट्रियों में काम करने वाली की संख्या अधिक होती है जो आधुनिक मशीनों को चला सकें। दूसरे देशों में इजीनियरों और वैज्ञानिकों की बहुतायत होती है जो शोधपूर्ण कार्य में रत हों। यह कहा जाता है कि संयुक्त राज्ज अमेरिका को अनुसंधान और नवीन प्रयोगों में तुलनात्मक लाभ रहना है किन्तु जब वह प्रयोग पुराना पड़ जाता है तो दूसरे देश अमेरिका से आगे बढ़ जाते हैं। यह हो सकता है कि एक देश का एक भाग कृषि तथा औद्योगिक एवं वैज्ञानिक कुशलता से पूर्ण श्रम शक्ति से युक्त हो और दूसरा भाग भौतिक साधनों जैसे—सड़क, पुत, बाँध, जहाज, फैक्ट्री आदि से सम्पन्न हो। प्राकृतिक एवं मनुष्यकृत साधन परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया करते हैं।

व्यापार और उत्पादन के माँट्रिचरीय अध्ययनों के द्वारा यह प्रदर्शित किया जाता है कि 'तुलनात्मक लाभ का सिद्धान्त' प्रशुल्क एवं अन्य बाधाओं के होते हुए भी व्यापार के वास्तविक रूपों की स्पष्ट कर सकता है। तुलनात्मक लाभ का पता लगाने के लिए कई एक मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें एक द्विभाजन मॉडल (Two Factor Model) भी है। मि० रिक्वाडों ने 'दो देश, दो वस्तु' के मॉडल का प्रयोग 1927 में किया था। इस शताब्दी के अन्तिम दिनों में 'अनेक देश और

अनेक वस्तुओं का मॉडल सामने आया। इस मॉडल के समर्थकों ने रिकार्डों के निष्कर्षों को सन्देह की दृष्टि से देखा।

बहुदेशीय मॉडल (Multipurpose Model) स्वीडन के दो धर्मशास्त्रियों ऐसी हेक्शर (Eli Heckscher) और बर्टिल ओह्लिन (Bertil Ohlin) के कार्यों में मिलता है। धर्म कीमत मॉडल की भाँति यह मॉडल भी यातायात की लागत पर ध्यान नहीं देता तथा यह मानकर चलता है कि प्रत्येक जगह रुनियाँ एक जैसी हैं। धर्म लागत मॉडल से भिन्न इस मॉडल की मान्यता है कि प्रत्येक देश की तकनीकी समान होती है।

हेक्शर तथा ओह्लिन का सिद्धान्त दो मान्यताओं के साथ आगे बढ़ता है—

(1) विभिन्न उत्पादनों में अलग-अलग साधनों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए—एक कार के निर्माण में अधिक मशीन, समय एवं धर्म की आवश्यकता होगी। इतना धर्म एवं समय सूती कपड़े के निर्माण में जरूरी नहीं होगा, (ii) देशों के बीच साधन सम्पन्नता की दृष्टि से अन्तर होता है। कुछ देशों में मजदूरों की अपेक्षा पूँजी अधिक होती है जबकि कुछ देशों में पूँजी की अपेक्षा मजदूर अधिक होते हैं—ऐसी स्थिति में पूँजी सम्पन्न देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशेषीकरण करेंगे जिनमें कि अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए—कार बनाना, हवाई जहाज बनाना आदि। ये देश अपने उत्पादन में से कुछ का निर्यात करेंगे ताकि उस सामान का आयात कर सकें जिसमें अधिक धर्म की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार धर्म की अधिक संख्या वाले देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशेषीकरण करेंगे जिनमें अधिक धर्म सपाने की जरूरत होती है। ये भी अपने उत्पादन में से कुछ का निर्यात करेंगे ताकि पूँजी की बहुतायत वाले सामान का आयात किया जा सके।

उत्पादित वस्तु के मूल्यों एवं उत्पादन के साधनों के मूल्यों के बीच पर्याप्त गहरा सम्बन्ध होता है। इस सम्बन्ध का एक परिणाम यह है कि स्वतन्त्र व्यापार में साधन स्रोतों के मूल्यों को भाग लेने वाले देशों के बीच एक जैसा बनाने का प्रयास किया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख लाभ निम्न प्रकार हैं—

- (1) अन्तर्राष्ट्रीय धर्म विभाजन एवं स्पष्टीकरण
- (2) प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपयोग
- (3) उच्च जीवन स्तर
- (4) उपभोक्ताओं की सस्ती वस्तुओं की प्राप्ति
- (5) प्रकाल प्रथवा संकटकाल में सहायता
- (6) आर्थिक विकास की तीव्रगति
- (7) कच्चे माल की उपलब्धि
- (8) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग
- (9) विदेशी विनिमय की उपलब्धि
- (10) सांस्कृतिक सम्बन्ध

(1) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण—प्रतिष्ठित ग्रंथ-शास्त्रियों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण है। वर्तमान में कोई भी देश आत्म-निर्भर नहीं है। मनुक्तराज्य अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र भी अनेक वस्तुओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं। इस निर्भरता का कारण अधिकाधिक अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन की क्रियाएँ हैं। विशिष्टीकरण के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक देश उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक ध्यान देता है जिनके लिए उसे तुलनात्मक लाभ अधिक प्राप्त होता है अथवा जिनकी उत्पादन-लागत न्यूनतम होती है। ऐसा करने से वे वस्तुएँ उस देश में सस्ती एवं अच्छी उत्पन्न की जा सकती हैं। अच्छी एवं सस्ता उत्पादन होने के फलस्वरूप उन वस्तुओं का बाजार में अधिक विस्तार होता है। बाजार का विस्तार होने पर वस्तु का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर किया जाता है जिससे उस देश की बड़े पैमाने के लाभ या पैमाने की मित-व्ययताएँ भी प्राप्त हो जाती हैं।

(2) प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपयोग—जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक देश केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनके उत्पादन में उस तुलनात्मक लाभ अधिक प्राप्त होने हैं। अतः प्रत्येक देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का पूरा-पूरा प्रयोग किया जाए क्योंकि किसी भी वस्तु के उत्पादन में उत्पादन के विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है, अतः वह देश आवश्यक दुर्लभ साधनों का आयात करके अपने प्रचुर साधन का प्रयोग उत्पादन किया में कर सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अभाव में दुर्लभ साधनों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जिससे अपने प्रचुर साधन का उपयोग भी असम्भव बना रहता है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एक मुख्य लाभ प्राकृतिक साधनों का अनुकूलतम उपयोग भी है।

(3) उच्च जीवन स्तर—जब उपभोक्ताओं को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप वस्तुएँ अच्छी एवं सस्ती उपलब्ध हो जाती हैं तो वे अपनी सीमित आय से अधिक मात्रा में वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ-साथ उन वस्तुओं का भी उपयोग कर सकते हैं जो उस देश में उत्पन्न नहीं की जाती हैं। इस प्रकार उनका जीवन स्तर ऊँचा हो जाता है।

(4) उपभोक्ताओं को सस्ती वस्तुओं की प्राप्ति—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण बाजार प्रतियोगिता में वृद्धि हो जाती है। पुनः विशिष्टीकरण एवं देश के प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग होने से उत्पादन लागत भी कम हो जाती है। अतः उपभोक्ताओं को अच्छी वस्तुएँ कम कीमत में प्राप्त हो जाती हैं। बाजार के विस्तार के फलस्वरूप उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। जिन वस्तुओं का उत्पादन उत्पत्ति वृद्धि नियम के अन्तर्गत हो रहा है उनकी उत्पादन लागत कम हो जाती है। अतः सम्पूर्ण विश्व में उत्पादित की जा रही सभी वस्तुओं की कीमतें कम हो जाती हैं तथा विदेशी व्यापार के कारण वस्तुओं की कीमतों में समानता की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। परिणामस्वरूप सभी देशों की वस्तुएँ सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हो जाती हैं। इससे उपभोक्ताओं को लाभ प्राप्त होता है।

(5) अकाल अववा संकटकाल में सहायता—जब देश में अकाल, भूचाल, महामारी, युद्ध, अथवा अन्य संकट उत्पन्न हो जाते हैं तो उससे सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है। देश में आवश्यक वस्तुओं का अभाव उत्पन्न हो जाता है तथा वस्तुओं की कीमत असमान होने लगती हैं। ऐसे संकटकालीन समय में विदेशी व्यापार उस देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए बरदान सिद्ध होता है। अन्य देशों से आवश्यक वस्तुओं का आयात करके समस्या का समाधान किया जा सकता है। जैसे भारत में गत कुछ वर्षों पहले पड़े अकाल एवं भुवमरी का मुकाबला अमेरिका से PL 480 के अन्तर्गत गेहूँ मंगाकर किया गया।

(6) आर्थिक विकास की तीव्र गति—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप विश्व के गरीब देश भी अपने आर्थिक विकास की गति को तीव्र कर सकते हैं। उनको विदेशी पूंजी प्राप्त हो सकती है जिसकी सहायता से अपने देश में भावी उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं जिससे देश की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तथा देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है। आज विश्व के जितने भी विकसित देश हैं उनके विकास के पीछे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ही एक प्रमुख कारण रहा है। इसी प्रकार आज भारत का जो विकास हुआ है उसमें मुख्य रूप से विदेशी व्यापार का योगदान है।

(7) कच्चे माल की उपलब्धि—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से उन देशों को भी औद्योगीकरण और आर्थिक विकास का अवसर मिल जाता है जिनके पास कच्चे माल के प्रतिरिक्त अन्य साधन उपलब्ध हैं। जैसे ग्रेट ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग अब उनी वस्त्र उद्योग, विदेशी रुई एवं ऊन के बलबूते पर चलते हैं। इसी प्रकार भारत का जूट उद्योग भी बंगलादेश के कच्चे जूट पर निर्भर है अतः विदेशी व्यापार देश के औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करता है।

(8) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप एक-दूसरे पर निर्भरता बढ़ती जाती है। अतः दोनों पक्षों के आपसी सहयोग से ही दोनों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विश्व में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण किया गया है जिनमें मुख्य सरथाएँ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद्, एशियन बैंक आदि। इन सबका मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करना है।

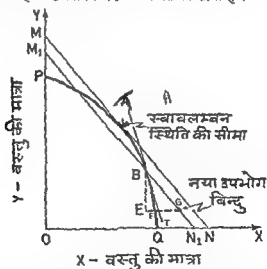
(9) विदेशी विनिमय की उपलब्धि—आजकल विदेशी-विनिमय किसी भी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विशेषकर विकासशील राष्ट्रों के लिए विदेशी विनिमय की अति आवश्यकता होती है। विदेशी विनिमय के द्वारा वे विदेशों से आवश्यक माया में औद्योगिक सामग्री एवं तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी विनिमय अर्जित करने के लिए उस देश को अपने निर्यातों में वृद्धि करनी पड़ती है। जापान, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस आदि देशों ने अपने निर्यातों में वृद्धि करके काफी मात्रा में विदेशी विनिमय का संग्रह कर रखा है।

(10) सांस्कृतिक सम्बन्ध—विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के मध्य व्यापारिक सम्बन्ध ही स्थापित नहीं करता है वरन् विदेशी व्यापार के उद्देश्य से एक देश के व्यक्ति जब अन्य देशों में व्यापारिक जानकारी हेतु जाते जाते हैं तो भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग आपस में मिलते जुलते हैं तो उससे एक-दूसरे के रीति रिवाज, राजनीतिक आचार-विचार, रहन-सहन आदि के बारे में जानकारी मिलती है जिससे वे एक-दूसरे को समझने लगते हैं एवं आपस में सामञ्जस्य स्थापित होता है तथा विश्व एकता को बढ़ावा मिलता है ।

व्यापार से लाभ-एक सरल रेखाचित्रीय विश्लेषण

प्रोफेसर सैम्युअल्सन तथा केम्प के विचारों के आधार पर विदेशी व्यापार से प्राप्त होने वाले लाभों की रेखाचित्रों के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है ।

माना कि किसी अर्थव्यवस्था में केवल दो ही वस्तुएँ X तथा Y का उत्पादन किया जाता है । PQ अर्थव्यवस्था का उत्पादन सम्भावना वक्र है जो मूल्य बिन्दु से नतोदर (Concave) है । व्यापार रहित अवस्था में उपभोग एवं उत्पादन पूर्णतः एक जैसे हैं, अर्थात् स्वावलम्बन की दशा में दिए हुए घरेलू मूल्यों के अनुपात पर देश के सन्तुलन उत्पादन एवं सन्तुलन उपभोग, दोनों ही की अभिव्यक्ति PQ पर A बिन्दु द्वारा होगी । यहाँ PQ स्वावलम्बन की स्थिति की सीमा है ।



स्वतन्त्र व्यापार की दशा में X तथा Y वस्तु के मूल्यों का अनुपात प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे । उपरोक्त चित्र में यह MN रेखा द्वारा व्यक्त किया गया है । व्यापारोपरान्त का सन्तुलन A बिन्दु पर होगा जहाँ से देश MN रेखा के सहारे उपभोग हेतु प्रयत्न करता है । वस्तुतः सैम्युअल्सन के मतानुसार MN रेखा बकट सीमा रेखा अथवा उपभोग सम्भावना रेखा को प्रकट करती है ।

क्योंकि MN रेखा A बिन्दु को छोड़कर प्रत्येक स्तर पर स्वावलम्बन की सीमा रेखा PQ से बाहर स्थित है। इसके सभी बिन्दुओं पर उपभोक्ता PQ की अपेक्षा अधिक मात्रा में X व Y वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। यदि स्वावलम्बन की स्थिति में देश A बिन्दु पर स्थित हो तथा व्यापारोपरान्न भी यही स्थिति रहे तो व्यापार से न तो देश को लाभ होगा और न ही हानि होगी।

परन्तु अब माना कि देश विदेशी व्यापार प्रारम्भ करता है, परन्तु साथ ही X-वस्तु पर मूल्यानुसार प्रशुल्क भी रोपित करता है जिसके फलस्वरूप X, Y-वस्तु के मूल्यों का अनुपात बदल जाता है। माना कि इस अवस्था में नया अनुपात TT के डलाव के बराबर है। अब देश का उत्पादन सन्तुलन B बिन्दु पर होगा जहाँ पूर्वावस्था X-वस्तु का अधिक परन्तु Y का कम उत्पादन होगा। यह मानते हुए कि प्रशुल्क रोपण के बाद भी अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का अनुपात यथावत अर्थात् MN के डलाव के बराबर रहता है, ऐसी स्थिति में देश X-वस्तु का विदेशों से आयात करके Y वस्तु का निर्यात करेगा। विदेशी व्यापार के लिए मूल्यों का अनुपात M_1N_1 के अनुरूप रहेगा जबकि रेखा MN एवं M_1N_1 समानान्तर होने के कारण समान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुपात को प्रकट करेगी।

इस प्रकार देश को उपभोग सम्भावना सीमा M_1N_1 हो जाती है और नया उपभोग बिन्दु G पर स्थित होगा। ऐसी अवस्था में देश Y वस्तु को BE मात्रा का निर्यात करके EG मात्रा में X-वस्तु का आयात करेगा। यहाँ X-वस्तु की EF इकाइयाँ तो उपभोक्ताओं को प्रत्यक्षतः प्राप्त होगी जबकि FG इकाइयाँ सरकार को राजस्व के रूप में प्राप्त होगी। नयी सीमा रेखा M_1N_1 अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के उसी अनुपात (MN के तुल्य) को प्रकट करते हुए भी प्रत्येक स्थिति में MN रेखा के भीतर स्थित है जो कि मुक्त व्यापार की सीमा रेखा है अर्थात् प्रतिबन्धित व्यापार की तुलना में स्वतन्त्र व्यापार की स्थिति में M_1N_1 की तुलना में MN रेखा पर X व Y दोनों ही वस्तुओं की अधिक मात्रा का उपभोग किया जा सकता है। यह मानते हुए कि आवंटन सम्बन्धी दक्षता की अप्रतिभूत हानि रहित आदर्श अन्तरण सम्भव है, अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रतिबन्धित व्यापार की तुलना में मुक्त व्यापार से उत्पन्न का उच्चतर स्तर प्राप्त किया जा सकता है।

लाभ की मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्त्व

(The Factors to Influence the Gain)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त होने वाला लाभ ही उसका मुख्य प्राधान होता है। इस लाभ का विभिन्न देशों के बीच विभाजन कई तत्त्वों द्वारा प्रभावित किया जाता है। इस सम्बन्ध में पहली बात तो यह है कि एक ही वस्तु के उत्पादन में दो देशों की लागत एक जैसी नहीं होती। लागत के अनुसार ही लाभ की मात्रा भी बदल जाती है। उत्पादन की लागतों में जितना अधिक अन्तर रहता है, लाभ की मात्रा भी उसनी ही अधिक हो जाती है। इस सम्बन्ध में प्रो. हेरोल्ड ने लिखा है कि "एक देश विदेश-व्यापार तब करता है जब व्यापारी यह पाएँ कि विदेशों में

व्यापार से होने वाले लाभ का मापक (Measurements of the Gain from Trade)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभों को मापने पर अर्थशास्त्रियों ने समय-समय पर विचार किया है। संस्थापक अर्थ-शास्त्रियों ने इस प्रश्न के सम्बन्ध में तीन दृष्टिकोण अपनाए हैं। प्रथम, एक राष्ट्र की आय को तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त की सहायता से मापा जाए। दूसरे, उसे राष्ट्रीय आय की वृद्धि के आधार पर मापा जाए और तीसरे, उसे अन्तर्राष्ट्रीय वितरण के सूचीपत्र एवं प्राप्ति की प्रकृति के अनुसार मापा जाए। संस्थापक अर्थ-शास्त्रियों ने इन तीनों ही तरीकों का प्रयोग किया है। यदि हम एक ही समय की परिधि में विचार करें तो-पाएँगे कि प्रथम और द्वितीय मापकों के बीच अधिक अन्तर नहीं है। लाभ की इस विशेष माप्रा को या तो आय की प्रति इकाई लागत की कमी के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है अथवा उसे प्रति इकाई लागत की आय में वृद्धि के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि चाहे लागत में कमी हो अथवा कीमत में वृद्धि दोनों स्थितियों में लाभ होगा।

व्यापार के अभाव में होने वाली हानि द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की प्राप्ति को मापा जा सकता है। जब कुछ कारणों से आयातों के उत्पादन का घरेलू मूल्य बढ़ जाता है तो निर्यात के बढ़ने में किए गए आयात से प्राप्त होने वाला लाभ भी बढ़ जाता है क्योंकि राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता इस बढ़ती हुई परिस्थिति में अधिक खतरनाक हो सकती है। यदि देश आत्म-निर्भर रहने का प्रयास करेगा तो उसको अधिक लागत लगाकर वस्तुओं का उत्पादन करना होगा। इन बढ़ती हुई परिस्थिति में यद्यपि देश की राष्ट्रीय आय अर्थात् आयात-निर्यात के बीच बিনিश्व की दर एवं उसके निर्यात का मूल्य एक जैसा ही रहता है फिर भी व्यापार से प्राप्त होने वाला उसका लाभ बढ़ जाता है। दूसरी ओर यदि तकनीकी विकास या अन्य किसी कारण से आयातित वस्तुओं की घरेलू लागत घट जाती है तो व्यापार से होने वाली प्राप्ति घट जाएगी क्योंकि इस बढ़ती हुई परिस्थिति में राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता से प्राप्त होने वाली हानि कम होगी। कहने का अर्थ यह है कि जिस वस्तु का उत्पादन एक देश कम लागत से कर सकता है, उसे विदेशों से मंगाने पर कोई प्राप्ति नहीं होगी। यदि निर्यात के उत्पादन की लागत में होने वाली कमी आयात के उत्पादन की घरेलू लागत में होने वाली कमी के बराबर है तो व्यापार से होने वाली प्राप्ति अप्रभावित रहेगी।

कुछ वस्तुओं को घरेलू स्तर पर उत्पादित करना असम्भव रहता है। २० प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन का घरेलू मूल्य बहुत अधिक होगा। ऐसी स्थिति में इन वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त होने वाला लाभ भी पर्याप्त होगा, यह मत अधिक उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। जिन वस्तुओं को देश में उत्पादित ही नहीं किया जा सकता, उनसे व्यापार में होने वाली प्राप्ति को अधिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार व्यापार से प्राप्ति उस अन्तर

का स्वदेश में ही उत्पादन होगा जिनका आयात प्रतिबन्धित कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप इन वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाएगी और व्यापार की जाने वाली शेष वस्तुओं के विनिमय से प्राप्त लाभ विनिमय की उपयुक्त दर की ओर बढ़ल जाएगा। जब एक देश अपने आयात पर प्रतिबन्ध लगा देता है तो विदेशों में उसके निर्यातों की माँग घट जाती है। ऐसी स्थिति में यदि कच्चे माल प्रयत्न साधनों को दूसरे उद्योगों में नहीं बदला जाएगा तो निर्यात उद्योगों में बेरोजगारी फैलेगी। यदि इन साधन स्रोतों को अन्य उद्योगों में बदल दिया गया तो इनकी उत्पादिकता इतनी ऊँची न हो सकेगी जितनी कि निर्यात उद्योगों की थी। इस प्रकार व्यापार की शर्तों को सुधारने का यह प्रयास अधिक सफल नहीं रहा।

व्यापार शर्तों को सुधारने का एक अन्य तरीका यह है कि कृत्रिम प्राधिक मन्दी की स्थापना की जाए। यह प्राधिक मन्दी की अनेक प्रकार के दुरे परिणामों को उत्पन्न करती है और इस प्रकार व्यापार शर्तों में होने वाले सुधार से प्राप्त लाभों को महत्वहीन बना देती है। यदि निर्यातों के उत्पादन की घरेलू लागत में होने वाली द्वि व्यापार शर्तों में होने वाले सुधार से अधिक है तो व्यापार से होने वाली प्राप्तियाँ व्यापार शर्तों में होने वाले सुधारों के बावजूद भी घट जाएँगी। इसी प्रकार यदि रुबियो में परिवर्तन के कारण या अन्य किन्हीं कारणों से आयातों की उपयोगिता तनी गिर जाती है कि वह विनिमय के अनुपात पे होने वाले सुधार से कम हो जाती है तो व्यापार शर्तों में सुधार होने पर भी व्यापार से होने वाली प्राप्तियाँ घट जाएँगी।

व्यापार से होने वाली प्राप्तियों में परिवर्तन विभिन्न तत्त्वों में परिवर्तन होने कारण आता है। उदाहरण के लिए विनिमय के अन्तर्राष्ट्रीय अनुपात में होने वाले परिवर्तन, निर्यातों के उत्पादन में होने वाली वास्तविक लागत में परिवर्तन, आयातों के उत्पादन की सम्भावित घरेलू लागत में परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार। मात्रा में परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की रचना में परिवर्तन आदि-आदि। विभिन्न तत्त्वों में होने वाले परिवर्तन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाली एक देश प्राप्तियों को बहुत प्रभावित करते हैं। आयात और निर्यात की जाने वाली भिन्न वस्तुओं की प्राप्तियाँ अलग-अलग होती हैं। इसके प्रतिरिक्त उत्पादन की भावित घरेलू लागत और आयात की जाने वाली लागत के बीच वस्तु के अनुसार अंतर रहता है। यदि तुलनात्मक लागत में बड़ा अन्तर रखने वाली वस्तुओं के उन वस्तुओं को ला दिया जाए जो तुलनात्मक लागत में थोड़ा अन्तर और व्यापार का पूर्ण आकार एक जैसा ही रहने दिया जाए तो व्यापार से प्राप्तियाँ बढ़ जाएँगी।

व्यापार से होने वाली प्राप्तियों का वितरण (Distribution of the Gains from Trade)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाली प्राप्तियों को विभिन्न देशों के बीच प्र प्रकार वितरित किया जाए? यह एक प्रमुख प्रश्न है। रिकार्डों का मत था

उत्पादन, वितरण एवं व्यापार की शर्तों पर प्रशुल्क के प्रभाव

(EFFECTS OF TARIFFS ON PRODUCTION,
DISTRIBUTION AND TERMS OF TRADE)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में एक देश विभिन्न कारणों से अपने आयात और निर्यात पर कर लगाना है। यह कर लगाने की प्रक्रिया स्वतन्त्र व्यापार के सिद्धान्त के विपरीत है जिसके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को पूर्णतः स्वतन्त्रतापूर्वक संचालित होना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न रहे। स्वतन्त्र व्यापार की यह नीति आज की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं ठहरती। आर्थिक प्रतियोगिता में विकसित देशों से अपनी रक्षा करने के लिए एक विकासशील देश संरक्षण की नीति का प्रयोग करता है। प्रशुल्क (Tariff) की प्रक्रिया संरक्षण की नीति का ही एक भाग है जिसे अपनाकर एक देश अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपना अस्तित्व बनाए रखता है।

प्रशुल्क सिद्धान्त का इतिहास (The History of Tariff Theory)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में लगाए गए प्रशुल्कों का इतिहास ही मूल रूप से प्रशुल्क सिद्धान्त का इतिहास है। इस इतिहास द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि हम आर्थिक सिद्धान्त की नीति को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं? प्रशुल्क के इतिहास को मुख्य रूप से निम्न भागों में विभाजित किया जाता है—

1. विरोधी प्रशुल्क प्रवृत्तियाँ (1815 से 1860)

(Divergent Tariff Trends)

संयुक्तराज्य अमेरिका में 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में प्रशुल्क के लिए शिशु उद्योगों का जो तर्क दिया जाता था वह पर्याप्त प्रभावपूर्ण रहा। इस समय वहाँ अनेक नए उद्योग आरम्भ हुए जिनको विदेशी प्रतियोगिता के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया जाना जरूरी था। इसी काल में ब्रिट-ब्रिटेन में प्रशुल्कों की स्थिति कुछ भिन्न थी। यहाँ इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि स्थित प्रशुल्कों को कम से कम किया जाए। इस प्रकार एक ओर जहाँ अमेरिका संरक्षण की नीति की दिशा में प्रसर हो रहा था वहाँ ब्रिट-ब्रिटेन स्वतन्त्र व्यापार की ओर बढ़ रहा था।

धरने जन्म काल से ही समुत्तराज्य अमेरिका में प्रभावों पर कर लिए जाते थे। इन प्रारम्भिक प्रभुत्वों का प्रभाव यद्यपि सरलसात्विक था किन्तु इनका मुख्य चरित्र सघीय सरकार के राजस्व को बढ़ाना था। इन दिनों यहाँ कोई प्रायः कर नहीं लगा जाता था और इसलिए सरकार को अपने धन की व्यवस्था के लिए प्रायः करों पर निर्भर रहना पड़ता था। इनमें प्रभुत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। प्रायः कर की उपायना अत्यन्त सरल होता है, इसके लिए केवल पुलिस तथा बन्दरगाहों की आवश्यकता होती है।

सन् 1815 में एक नए प्रभुत्व नानुन का समर्थन किया जाने लगा जिसके द्वारा न्यू दंगेल्ड तथा मध्य अटलांटिक राज्यों के नए उत्पादकों की रक्षा की जा सके। अमेरिकी कांग्रेस ने ऊनी तथा सूती वस्त्रों पर सन् 1816 में अधिक कर लगा दिए तथा कोयल एवं लोहा आदि पर 1824 में करों की मात्रा बढ़ा दी।

प्रभुत्व के प्रश्न पर उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के बीच विवाद था। यह विवाद 1828 में शीर्ष पर पहुँच गया। 1840 में संघीय संसद में प्रतिरिक्त धन की बहुदायत थी और इसीलिए राजकोष सचिव ने सुझाया कि प्रभुत्व को कम करने पर ही वरों से प्राप्त राजस्व को घटाया जा सकेगा। फलतः वर-योग्य प्रभावों पर लगाए गए कर में 26 प्रतिशत की कमी की गई। 1846 तथा 1875 में सरलसात्विक करों को और घटाया गया। इतने पर भी अमेरिका इस दृष्टि से योरोप से भिन्न था क्योंकि वहाँ स्वतन्त्र व्यापार (Free Trade) की व्यवस्था थी।

ग्रेट-ब्रिटेन में स्वतन्त्र व्यापार का प्रचलन एक प्रकार से कुसीनतन्त्र की प्राचीन शक्तियों के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा थी। कर्न लॉन (Corn Laws) के अनुसार आयातित आलू पर लगाए गए प्रभुत्वों का लाभ मुख्य रूप से देशी कुलीन-वर्ग को प्राप्त होता था। धन इनके राजनैतिक प्रभुत्व की समाप्त करने का प्रयास किया गया। ग्रेट-ब्रिटेन में भी अमेरिका की भाँति प्रभुत्व नीति एक सर्वव्यापी प्रश्न बन गई। एडम स्मिथ जैसे प्रगतिवादी के विचारों ने स्वतन्त्र व्यापार की नीति का समर्थन किया। बार्न लॉन पर होने वाले वाद-विवाद से पचास वर्ष पूर्व ही इन्होंने यह कह दिया कि जो आचारण प्रत्येक परिवार के व्यक्तिगत जीवन में महत्त्व रखता है उसे राज्य के स्तर पर मूर्खतापूर्ण नहीं कहा जा सकता।

स्वतन्त्र व्यापार की नीति का समर्थन बाद में डेविड रिकार्डो (David Ricardo) तथा एडम स्मिथ के अन्य अनुयायियों द्वारा भी किया गया। उनका मत था कि कर्न लॉन द्वारा मजदूरों को दो प्रकार का नष्ट पहुँचाया जा सकता है। प्रथम, प्रभुत्व द्वारा साक्षान्त की कीमतें बढ़ा दी जाएँगी तथा कर्मचारियों की क्षमता कम कर दी जाएगी। दूसरे, प्रभुत्व द्वारा व्यापारिक लाभ की कीमत पर भूमि के दिराए को बढ़ाया जाएगा। कम लाभ होने से बहुत कम होगी, व्यय कम होगा और इस प्रकार धन की मात्रा घट जाएगी।

ग्रेट-ब्रिटेन में स्वतन्त्र व्यापार की नीति का प्रारम्भ नेपोलियन ने युद्धों से पूर्व ही हो चुका था। विलियम पिट (William Pitt) ने सन् 1784 में अपने

करो को पहले ही कम कर दिया था। इसके बाद टोरी दल की सरकार ने औद्योगिक कच्चे माल पर से करों को बटा दिया। इन कमियों को ब्रिटेन के उत्पादकों का समर्थन प्राप्त हुआ क्योंकि कच्चे माल पर प्रशुल्कों द्वारा उनकी उत्पादन लागत बढ़ गई थी।

स्वतन्त्र व्यापार की विजय एवं पराजय (1860 से 1914) (The Triumph and Decline of Free Trade)

स्वतन्त्र व्यापार की दिशा में ग्रेट-ब्रिटेन का अग्रणी कदम व्यवस्थापक के स्थान पर नूतनीतिक बन गया। 1860 में ग्रेट-ब्रिटेन तथा फ्रांस के बीच कोब्डेन चिवेलियर (Cobden-Chevalier) की सन्धि हुई जिसके अनुसार दोनों देशों ने प्रशुल्क में पारस्परिक कटौती की। फ्रांसीसी शराब पर से ब्रिटेन ने कर को कम कर दिया। उसके बाद फ्रांस ने अन्य देशों के साथ भी प्रशुल्क सन्धियाँ कीं। 1860 और 1870 के बीच में जो व्यापारिक सन्धियाँ की गईं उनके शेष बहुसंख्यपूर्ण परिणाम हुए—(1) हमारे फलस्वरूप प्रशुल्क में नई कटौतियाँ हुईं और (2) अब तक प्रत्येक देश द्वारा की गई कटौतियों को सामान्यकृत किया गया।

कालान्तर में जब परिस्थितियाँ बदली तथा लोगों के दृष्टिकोण में अन्तर आया तो स्वतन्त्र व्यापार का आन्दोलन टोला पड़ा। सन् 1870 में यूरोप की उपनिवेशवादी नीतियों में भारी परिवर्तन दिखाई दिया। अष्ट-शताब्दी तक साम्राज्यवादी भावनाओं का जोर रहा। 1873 में जर्मनी के बिस्मार्क ने लोहे पर प्रशुल्क हटा दिया और घोषणा की कि 1877 तक लोहे से निर्मित वस्तुओं पर से प्रशुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। परिस्थितिबल बिस्मार्क को सन् 1879 में उद्योगों एवं दृष्टि को संरक्षण प्रदान करने के लिए नए प्रशुल्क लगाने पड़े।

उच्च प्रशुल्कों की नवीन प्रवृत्ति को शिशु उद्योगों के तर्कों द्वारा समर्थित किया गया। इन तर्कों की स्पष्ट व्याख्या जर्मनी के मि० फ्रेडरिक लिस्ट ने की जो कि समुक्तराज्य अमेरिका में रहे थे और उच्च प्रशुल्क शीशुओं के पीछे द्रुतगति से होने वाले आर्थिक विकास से पर्याप्त प्रभावित थे। जर्मनी लौटने पर उन्होंने इस तर्क का अपने देश में प्रचार किया। उनका कहना था कि स्वतन्त्र व्यापार विश्व की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हो सकता है किन्तु एक राष्ट्र के लिए यह उस समय तक लाभदायक नहीं है जब तक वह अपने राष्ट्रीय उद्योगों को पर्याप्त विकसित न करले। मि० लिस्ट का कहना था कि एक देश केवल तभी सम्पन्न हो सकता है जब वह निर्मित माल का निर्यात करे तथा खाद्यान्न का आयात करे।

फ्रांस ने भी 1892 में जर्मनी का अनुगमन किया तथा नेपोलियन तृतीय की कम प्रशुल्क नीतियों को उलट दिया। औद्योगिक विकास के लिए प्रसिद्ध मेलाइन कानून (Melaine Law) बनाया गया। 1890 के बाद फ्रांस की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से आगे बढ़ी किन्तु उसकी प्रगति के लिए प्रशुल्क कानून को श्रेय नहीं दिया जा सकता। यहाँ तक कि इसने लोहे तथा फीताद के उद्योगों की प्रगति को बाधा

पहुँचाई क्योंकि कोयले पर अधिक कर होने के कारण लोहे से निर्मित वस्तुओं की लागत बढ़ गई थी।

सन् 1890 के दौरान जब जर्मनी, रूस, इटली तथा अन्य देशों के बीच प्रभुत्व युद्ध छिड़ा तो सरक्षणवाद की नीति पुनः प्रभाव में आई। 1902 में जर्मनी ने अपनी प्रभुत्व दरो को सचमुच बढ़ा दिया ताकि उसे सौदेबाजी करने का अधिक अवसर प्राप्त हो सके। संयुक्तराज्य अमेरिका के प्रभुत्वों में योरोप की भाँति कमी नहीं आई। 1860 के बाद उनकी दर और भी बढ़ गई। 1861 में कांग्रेस ने मोरिल प्रभुत्व अधिनियम (Morrill Tariff Act) पास कर दिया तथा लोहा एवं फौलाद उद्योग को नए सरक्षण प्रदान किए। 1862 तथा 1864 में इसने अधिकांश अन्य करों में वृद्धि को भी स्वीकार किया। कर की इन नई दरों का लक्ष्य अमेरिकी उद्योगों को सरक्षण प्रदान करना इतना नहीं था जितना कि विदेशी उत्पादकों को अमेरिकी उत्पादकों के विरुद्ध अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकना था।

1900 के बाद रिपब्लिकन दल ने अत्यधिक सरक्षणवाद का विरोध किया। 1908 में दल की ओर से यह घोषणा की गई कि सबसे अच्छा सरक्षण का सिद्धान्त वह है जिसमें देश तथा विदेश की उत्पादन लागत के अन्तरों को समान कर दिया जाता है तथा उचित लाभ की व्यवस्था की जाती है। इस विचार को पर्याप्त उपयुक्त माना गया तथा 1909 के प्रभुत्व कानून में यह अभिव्यक्त हुआ। इस अधिनियम द्वारा कुछ प्रभुत्वों में कटौती की गई थी।

3 पतन एवं पुनर्रचना (1914-1939)

(Collapse and Reconstruction)

प्रथम विश्वयुद्ध के समय संयुक्तराज्य अमेरिका ने प्रभुत्व नीति में बड़े परिवर्तन किए। विल्सन के प्रशासन काल में (1913 में) प्रभुत्वों में भारी कटौती की गई तथा स्वतन्त्र व्यापार की सूची में लोहा, कोयला, कच्चा अन्न, अखबारों कागज आदि भी शामिल कर लिए गए। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद प्रभुत्व सरक्षण के लिए जहाँ-तहाँ भारी दबाव डाले जाने लगे।

युद्ध एवं उसके बाद किए जाने वाले शान्ति समझौते ने अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को क्षिप्त-मिश्र कर दिया। सामान्य अव्यवस्था के परिणामस्वरूप भारी प्राथिक मन्दी आई। यह कहा जाता है कि सन् 1923 में एक जर्मन गृहिणी बाजार से सामान लाने वाले घेले में घन रखकर से जाती थी और बदले में खरीदे गए सामान को अपने बटुए में रखकर लाती थी। इस नवीन परिस्थिति से प्रभावित होकर विभिन्न देशों की सरकारों ने नए प्रभुत्व लगाए। केन्द्रीय यूरोप के नए देशों में आयात कोटा (Import Quotas) निर्धारित कर दिए। जर्मनी ने 1825 में नया कृषि प्रभुत्व लगाया। लेटिन अमेरिका के राज्य भी प्रभुत्वों तथा कोटा का प्रयोग प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्रतापूर्वक करने लगे थे। ब्रिटेन ने 1919 में स्वतन्त्र व्यापार को अन्तिम रूप से छोड़ दिया। 1931 तक वह एक व्यवस्थित सरक्षण की नीति अपनाने लगा था।

युद्ध के बाद यह आवश्यकता हुई कि संयुक्तराज्य अमेरिका अपने प्रशुल्कों को घटावे ताकि विश्व के देश अधिक डॉलर कमा सकें और इसके कर्ज को उतार सकें। इसके विपरीत युद्ध के बाद पहले तो कांग्रेस ने अधिक करों का प्रस्ताव पाम किया। 1922 का फोर्डनी भँकम्बर प्रशुल्क (Fordney Moberly Tariff) किसानों की सहायता के लिए लगाया गया था किन्तु इसका लक्ष्य रासायनिक उद्योग एवं युद्ध के जिज्जों की सहायता करना भी था। कृषि सुरक्षा की प्रवृत्ति एवं मात्रात्मक व्यापार नियन्त्रण इस दशान्दी के उत्तरार्द्ध तक बने रहे।

सन् 1929 में किसानों की सहायता के लिए ही कांग्रेस ने पुनः प्रशुल्क पर विचार करना प्रारम्भ कर दिया किन्तु सभी गलत बाजार विफल हो गया तथा अर्थव्यवस्था, आर्थिक मन्दी की ओर बढ़ने लगी। एक के बाद एक उद्योग ने रोजगार की व्यवस्था के लिए संरक्षण की माँग की और इसलिए जब नया प्रशुल्क कानून कांग्रेस के सामने विचारार्थ आया तो अनेक दबाव समूह सक्रिय होकर प्रभाव डालने लगे। विचार-विमर्श के बाद कांग्रेस ने इतने प्रशुल्क स्वीकार किए जिनका उदाहरण इतिहास में प्राप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में दूसरे देशों ने भी बाध्य होकर अमेरिका से होने वाली आयात पर अतिरिक्त प्रतिबन्ध लगाए। राष्ट्र-संघ में प्रशुल्क युद्ध-विराम के लिए प्रयास किया गया।

1930 के प्रारम्भ में व्यापार नियन्त्रणों की नवीन सन्तति को जन्म मिला। आर्थिक मन्दी का प्रसार रोकने के लिए एक के बाद एक देश ने अपने आयात पर प्रतिबन्ध लगाए तथा विदेशी प्रतिस्पर्द्धा के विरुद्ध अपने घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। प्रत्येक प्रयास ने अपने पक्षी की निराशा दी क्योंकि एक देश के आयात में निरावट हुई। जब 1931 में ब्रेट-विल्सन ने पौण्ड का और 1934 में अमेरिका ने डॉलर का अवमूल्यन किया तो फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय देशों ने अपनी मुद्रा की रक्षा के लिए आयात नियन्त्रणों का प्रयोग किया।

1932 के बाद संयुक्तराज्य अमेरिका का आयात-कर घटने लगा। इसका एक कारण वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि था। इसके अतिरिक्त यह घटाव इसलिए भी हुआ क्योंकि नीति में भारी मोड़ आ गया था। रोजगारों की वृद्धि के मार्ग ढूँढते हुए रूजवेल्ट का प्रशासन विश्व-बाजारों की ओर मुड़ा तथा व्यापार के बाधकों को हटाने का आन्दोलन प्रारम्भ किया ताकि अमेरिका का व्यापार अधिक से अधिक हो सके। 1934 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कांग्रेस को ऐसे द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते की वार्ता करने की शक्ति देने की कड़ा जिसके अनुसार दूसरे देशों के प्रशुल्कों में कटौती कराने के लिए वे स्वयं प्रशुल्क में आधी कटौती कर सकें।

राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने वायदा किया कि प्रशुल्कों की कटौतियाँ अमेरिकी उत्पादकों पर गलत प्रभाव नहीं डालेंगी, अर्थात् वे प्रतिद्वन्द्वी आयातों के लिए अमेरिकी बाजार को नहीं छोटीगी। अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति को शक्तियाँ प्रदान की और संयुक्तराज्य अमेरिका ने दूसरी सरकारों के साथ 31 व्यापार समझौते किए। व्यापार समझौतों के कार्यक्रम के अनुसार प्रशुल्क की विश्वव्यापी वृद्धि पर रोक लगाई गई कारण विश्व व्यापार कुछ रक-सा गया था। इसके फलस्वरूप अमेरिका को

भी अपने प्रशुल्क घटाने पड़े। 1945 तक औसतन अमेरिकी प्रशुल्क 1919 के स्तर तक नीचा था।

स्वतन्त्र व्यापार और प्रशुल्क (Free Trade and Tariff)

स्वतन्त्र व्यापार के समयन में अनेक तर्क दिए गए किन्तु अनेक लेखकों ने उसको स्वीकार नहीं किया। प्रशुल्क नीति के बारे में पिछले 500 वर्षों में जो भी लिखा गया है वह एक अच्छे पुस्तकालय की रचना करता है। इन रचनाओं में बहुत कुछ दाहाराय हुआ है। प्रशुल्क के सम्बन्ध में जो तर्क दिए गए, उनमें प्रमुखता से आर्थिक तर्कों की रही किन्तु ये भी कम महत्त्व के नहीं थे।

प्रशुल्क नीति अर्थव्यवस्था के किसी न किसी समूह विशेष को अन्धी लगती है। यदि साइकिल, नारंगियों या कपड़ों पर से प्रशुल्क हटाने का प्रस्ताव किया जाए तो इनके उत्पादकों एवं निर्माताओं द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध किया जाएगा। इन पक्षों के मजदूरों एवं स्वामियों के अतिरिक्त वे लोग भी इसका विरोध करेंगे जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। कभी कभी एक नगर, राज्य अथवा देश का बार्ड क्षेत्र इस बात में रुचि लेता है कि प्रशुल्क में कमाई न की जाए और एक विशय प्रशुल्क का बनाए रखा जाए। ये समूह के प्रभावों को रोकना चाहते हैं। वे साबित करते हैं कि यदि प्रशुल्क में कटौती की गई तो उनके व्यक्तिगत हितों का नुकसान पहुँचेगा।

व्यावहारिक दृष्टि से यह सत्य है कि प्रशुल्क में होने वाली कटौती एक विशेष समूह के हितों का स्रण्डन करती है और इसलिए प्रशुल्क में कटौती की प्रक्रिया अत्यन्त धीमी होती है। जो व्यक्ति किन्हीं विशेष प्रशुल्कों से प्रभावित होते हैं वे एक प्रजातन्त्रात्मक देश में अपनी स्थिति की रक्षा के लिए पूरी शक्ति के सार्थक होते हैं। ऐसा करते समय वे उन विभिन्न समूहों के साथ मिलकर एक हो जाते हैं जो प्रशुल्क को बनाए रखना चाहते हैं। जब प्रशुल्क का प्रभाव एक छोटे समूह पर होता है तो वह अत्यन्त मजबूत तथा राजनैतिक दृष्टि से प्रभावशील बन जाता है।

प्रशुल्क सम्बन्धी बाद विवाद का सर्वाधिक कठिन पहलू यह है कि व्यक्तिगत और राष्ट्रीय हितों के बीच अन्तर किया जाना चाहिए। प्रशुल्क नीति के समर्थक इसका व्यापक औचित्य बताते हैं। वे उसे सही-सही आत्म हित पर निर्भर नहीं रखते। कभी-कभी प्रभावित समूह द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि जो हमारे लिए अच्छा है वह देश के लिए भी अच्छा होगा। प्रशुल्क नीति के विपरीत स्वतन्त्र व्यापार का पक्ष लेने वाले लोगों के तर्क स्पष्ट एवं प्रभावशील हैं। उनके कथनानुसार व्यापार में लिया गया हस्तक्षेप भौगोलिक विशेषीकरण की सम्भावनाओं को कम कर देगा और इस प्रकार स्वतन्त्र व्यापार में साधनों की वांछित कुशलता के साथ नहीं लगाया जा सकेगा। प्रशुल्क के समर्थन में अनेक तर्क दिए जाते हैं।

प्रशुल्क सिद्धान्त की मान्यताएँ (Assumptions of Tariff Policy)

अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतन्त्र व्यापार का सिद्धान्त बहुत समय तक त्रिधाशील

रहा। यह सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित था कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार इसलिए होता है क्योंकि उसमें सम्बन्धित दोनों पक्ष लाभान्वित होते हैं। जब तक व्यापार से प्राप्तियों की सम्भावना नहीं रहती तब तक दो देशों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध कायम नहीं हो पाते। कहा जाता है कि यदि सम्बन्धित दोनों पक्षों को पारस्परिक लाभ होता है तो उनके बीच व्यापार होना अत्यन्त कठिन है। इस दृष्टिकोण के अनुसार एक पक्ष हमेशा दूसरे पक्ष के विरुद्ध स्वयं लाभ प्राप्त करता है। तुलनात्मक लागत सिद्धान्त ने यह स्पष्ट किया कि व्यापार से दोनों पक्षों को लाभ हो सकता है; चाहे उनमें एक पक्ष दूसरे की अपेक्षा उत्पादन की सभी शाखाओं में अधिक कार्यकुशल क्यों न हो। इस प्रकार तुलनात्मक लागत सिद्धान्त ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के पारस्परिक लाभ की बात कही।

व्यापार द्वारा उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है। इसलिए कोई व्यापार न होने की अपेक्षा कुछ व्यापार होना ही श्रेष्ठ है। कहा जाता है कि यदि व्यापार को पूर्ण रूप से स्वतन्त्र छोड़ दिया गया तो कुछ समय बाद व्यापार असम्भव बन जाएगा, क्योंकि प्रत्येक देश के साधन-स्रोत सीमित होते हैं और ऐसी स्थिति में स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एक देश की स्वतन्त्रता, आत्म-निर्भरता और ऐसी ही विभिन्न बातों को जतरे में डाल सकता है। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि व्यापार पर कुछ नियन्त्रण लगाए जाएँ।

प्रशुल्क के द्वारा उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने की चेष्टा की जाती है, किन्तु उन उद्योगों को नहीं जो तुलनात्मक रूप से अकुशल होते हैं और विदेशी उद्योगों की प्रतियोगिता में ठहरने की क्षमता नहीं रखते। इसका प्रयोग प्रायः ऐसे उद्योगों की रक्षा के लिए किया जाता है जो प्रतियोगिता की क्षमता रखते हैं किन्तु पर्याप्त मात्रा में नहीं। देश के उद्योग विदेशी उद्योगों की तुलना में अधिक सशक्त नहीं हैं उनको संरक्षण प्रदान करने की नीति लाभदायक नहीं होती। उदाहरण के लिए—यदि अमेरिका केले तथा चीनी के स्वतन्त्र व्यापार के स्थान पर 20 प्रतिशत प्रशुल्क लगा दे, तो भी इन वस्तुओं का व्यापार होता रहेगा; क्योंकि इनका कोई स्थानापन्न (Substitute) नहीं है।

प्रशुल्क नीति से सम्बन्धित सिद्धान्त कुछ मान्यताओं पर आधारित हैं—

(1) इसकी पहली मान्यता प्रतियोगिता से सम्बन्धित है, जिसके अनुसार यह कहा जाता है कि सापेक्षिक कीमतें वास्तविक अवसरगत लागतों को अभिव्यक्त करेंगी। यदि विभिन्न उद्योगों के बीच प्रतियोगिता की मात्रा भिन्न है तो सापेक्षिक कीमतें तुलनात्मक लागतों को अभिव्यक्त नहीं करेंगी। ऐसी स्थिति में स्वतन्त्र व्यापार एक देश को ऐसे माल के उत्पादन में विशेषीकरण प्राप्त करने के लिए प्रभावित कर सकता है जिसमें उसे तुलनात्मक हानि हो। इस प्रकार व्यापार विश्व के उत्पादन को घटाएगा।

(2) यह सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि व्यापार से घरेलू उत्पादन की सम्भावनाएं प्रभावित नहीं होंगी। यदि 20 प्रतिशत प्रशुल्क हटा दिया

यथा तो पड़ीमी देश के साथ व्यापार होने लगेंगा किन्तु मजदूरों के साथ इस नीति का विरोध कर सकते हैं और अपने असन्तोष को हड़ताल के रूप में जाहिर कर सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक कर्मचारी का प्रति घण्टा उत्पादन कम हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में व्यापार द्वारा दो देशों के कुल उत्पादन को कम किया जा सकता है।

(3) प्रशुल्क सिद्धान्त पूर्ण रोजगार की धारणा पर आधारित है। अधिकांश लोग इस बात से सहमत हैं कि यदि स्वतन्त्र व्यापार के कारण व्यापक बेरोजगारी फैलती है तो इस नहीं अपनाया जाए। स्वतन्त्र व्यापार इन मान्यताओं पर आधारित है कि यदि प्रशुल्क को को हटा दिया गया तो प्रति व्यक्ति उत्पादन नहीं घटगा और बेरोजगारी का स्तर नहीं बढ़ेगा। इन मान्यताओं के सम्बन्ध में बहुत कम व्यावहारिक प्रमाण हैं।

इस प्रकार स्वतन्त्र व्यापार बनाम प्रशुल्क पर विचार करने के बाद यह कहा जा सकता है कि व्यापार को सम्भव बनाने के लिए स्वतन्त्र व्यापार की नीति को त्याग कर प्रशुल्क नीति अपनाया उपयोगी रहेगा। दूसरी ओर यह भी सब है कि व्यापार की मात्रा को बढ़ाने के लिए स्वतन्त्र व्यापार की नीति उपयोगी है।

प्रशुल्क की ऊँचाई का माप

(Measuring the height of Tariff)

यदि हम विभिन्न देशों की प्रत्येक एक ही देश की विभिन्न कालों में प्रशुल्क व्यवस्था का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए उसकी ऊँचाइयों का माप करना परमावश्यक है। एक प्रशुल्क की ऊँचाई मापना पर्याप्त जटिल है। ऐसा कोई सूत्र नहीं है जो स्पष्ट रूप से इसे माप सके। सांख्यिकी कठिनाइयों के प्रतिरिक्त एक कठिनाई यह है कि प्रशुल्क की ऊँचाई की धारणा अधिक स्पष्ट नहीं है।

प्रतिशत का आधार—प्रशुल्क दीवार की ऊँचाई मापने के लिए प्रतिशत का आधार बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए कर-योग आयातों और स्वतन्त्र आयातों की तुलना की जाती है। इस मापक का दोष यह है कि एक कर जितना प्रतिरोधात्मक होता है वह माप की दृष्टि से उतना ही कम महत्वपूर्ण बन जाता है। इसे स्पष्ट करने के लिए हम एक कल्पनात्मक उदाहरण ले सकते हैं—

उदाहरण के लिए यदि एक देश प्रशुल्क व्यवस्था लागू करने से पहले एक सौ वस्तुओं का आयात कर रहा था। अब 99 वस्तुओं के आयात पर इनका उच्च प्रशुल्क लगा दिया कि इन वस्तुओं का आयात पूर्ण रूप से रोकना पड़ा। 100वीं वस्तु का आयात किया किन्तु कर के स्वीकार किया गया। इस स्थिति में प्रशुल्क दीवार की ऊँचाई कुछ भी नहीं है किन्तु वास्तव में प्रशुल्क दीवार इतनी ऊँची है कि वह आयातों को प्रायः पूरी तरह रोक देती है। इस प्रकार प्रशुल्क की ऊँचाई को मापने के लिए प्रतिशत का सूत्र कई बार गलतफहमी का कारण बन जाता है।

औसतन भार—प्रशुल्क की दीवार की ऊँचाई का एक दूसरा माप आयात वरों का औसतन भार है। यह औसतन भार वह प्रतिशत है जो समस्त आयातों के

कुल मूल्य और सग्रह किए गए कुल आयात करों के बीच निकाला जाता है। इस मापक में यह दोष है कि प्रतिरोधात्मक करों की प्रशुल्क की दीवार की ऊँचाई के सूची-न्यत्र में पूरी तरह नहीं गिना जाता।

मूल्यों का अनुपात—एक तीसरा मापक वह अनुपात है जो करविहीन आयातों और कुल आयातों के मूल्यों के बीच रहता है। इस मापक में भी उपर्युक्त मापक के समान दोष हैं। जो देश कुछ वस्तुओं पर बहुत थोड़ा कर लगा रहा है वह भी ऐसा दिखाई देगा जैसे कि उसने अत्यन्त ऊँची प्रशुल्क दीवार खड़ी कर दी हो। दूसरी ओर जिस देश ने अधिकांश वस्तुओं पर प्रतिरोधात्मक कर लगा दिया है और केवल कुछ वस्तुओं को कर से स्वतन्त्र छोड़ा है, वह ऐसा दिखाई देगा मानो उसकी प्रशुल्क दीवार बहुत नीची है।

करों का औसत—प्रशुल्क की ऊँचाई मापने के लिए एक अन्य मापक आयातों के मूल्य का वह औसत प्रतिशत है जो चुंगी अधिकारियों द्वारा कर के रूप में संग्रहित किया जाता है। इस मापक में अनेक कठिनाइयाँ तथा उलझने हैं।

स्पष्ट है कि प्रशुल्क की ऊँचाई को मापने के लिए विभिन्न मापक हैं किन्तु उन सभी की अपनी कमजोरियाँ और समस्याएँ हैं। इनमें से किस विकल्प को चुना जाए यह तय करने के लिए धेरेना होगा कि हमारा उद्देश्य क्या है ?

प्रशुल्क नीति के साधों पर विचार करते हुए विद्वानों ने यह मत प्रकट किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रशुल्क लगाना सामान्यतः एक देश के लिए हितकर होता है। इसके साथ ही यह भी सही है कि विश्व की दृष्टि से स्वतन्त्र व्यापार एक सर्वश्रेष्ठ नीति है। जब प्रत्येक देश का प्रतियोगितापूर्ण व्यवहार अन्य देशों के लाभ को कम करने का प्रयास करता है। स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय कल्याण की वृद्धि के लिए एक देश द्वारा किए गए प्रयास दूसरे सभी देशों के कल्याण को कम करेंगे। यदि स्वतन्त्र व्यापार की व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्ण रोजगार की स्थिति रह सके तो विश्व के साधन स्रोतों का सर्वश्रेष्ठ आवंटन हो सकेगा। स्वतन्त्र व्यापार की व्यवस्था द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की सभी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। इसमें व्यापार अधिक होगा और इसलिए विभिन्न समस्याएँ अधिक अनुपात में उठ खड़ी होंगी। इसके लिए सन्तोषजनक अन्तर्राष्ट्रीय मापक तथा रोजगार का स्थायी-स्तर बनाए रखने में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की समस्याएँ रहेंगी और जब तक इनका समाधान नहीं किया जाता तब तक सभी धर्मों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सन्तोषजनक रूप से कार्य नहीं कर सकता।

प्रशुल्क नीति को प्रारम्भ करने वाला देश शुरू में लाभ की स्थिति में रहता है किन्तु जब प्रशुल्क दीवारें चारों ओर बँध जाती हैं तो प्रारम्भकर्ता देशों को यह अनुभव होता है कि शुरू में जो लाभ उन्होंने अपने देश के हित में प्राप्त किया था, इतने पर भी वे देश प्रशुल्कों को बढ़ाने में अपने लाभ देख सकते हैं। प्रशुल्क की दीवारें ज्यों-ज्यों उठती हैं, त्यों-त्यों अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा में कमी आती है। प्रशुल्क प्रवृत्ति को रोकने के लिए विभिन्न सम्मेलन किए जाते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय दबावों द्वारा इस प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास किया जाता है।

प्रशुल्कों की तीन श्रेणियाँ (Three Categories of Tariffs)

प्रशुल्क (Tariff) कर को निर्मित वस्तु पर उस समय लगाया जाता है जबकि वह राष्ट्रीय सीमाओं को पार करती है। राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाले माल की स्थिति एवं जन्म के अनुसार प्रशुल्क (Tariff) को सामान्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है—आयात कर (Import Duties), निर्यात कर (Export Duties) और पारगमन कर (Transit Duties)। ये तीनों प्रशुल्क एक देश द्वारा इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वह अन्तराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में अपनी स्थिति को संतुलित बनाए रख सके।

(1) आयात कर

(Import Duties)

आयात कर प्रशुल्क के तीनों रूपों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा सामान्य है। इसका उद्देश्य राजकोष के लिए धन प्राप्त करना होता है। इसके लिए विदेशी व्यापार को एक साधन बनाया जाता है। यदि प्रशुल्क का उद्देश्य केवल राजस्व एकत्र करना हो तो यह कर इस प्रकार लगाना चाहिए कि विदेशी व्यापार कम न हो। मान लीजिए किसी लोचशील वस्तु पर अधिक आयात कर लगा दिया गया तो निश्चय ही उसकी मांग घट जाएगी और इसलिए उससे प्राप्त होने वाला राजस्व भी कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रशुल्क कम होना चाहिए और उस वस्तु पर लगाना चाहिए जो अपेक्षाकृत लोचहीन है। यदि आयात कर एक ऐसी वस्तु पर लगाया जा रहा है जिसका उत्पादन देश में भी हो रहा है तो स्वदेशी वस्तु पर भी इतना कर लगाना चाहिए ताकि प्रतिस्पर्धा की शर्तें बराबर हो सकें और राजस्व भी प्राप्त हो सके। यदि ऐसा न किया गया तो वस्तु का आयात लाभदायक नहीं रहेगा और प्रशुल्क से बहुत कम राजस्व प्राप्त होगा।

आयात कर के रूप में प्रशुल्क घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने की दृष्टि से अत्यन्त प्रभावशाली होता है। इस प्रकार यह देश के विकास के लिए परमावश्यक है। घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतियोगियों के प्राक्रमणकारी एवं अन्यायपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध सुरक्षा की आवश्यकता होती है। भाजकल व्यापारिक सीदेवाजी के लिए प्रशुल्क का अधिक प्रयोग किया जाने लगा है। जब एक देश अन्य देश से अपने निर्यात के लिए सुविधाएँ माँगता है तो वह स्वयं भी उसके निर्यात के लिए सुविधाएँ प्रदान करता है। प्रशुल्क का प्रयोग प्रतिस्पर्धा के रूप में भी किया जा सकता है। जब एक देश दूसरे देश के निर्यात कर प्रशुल्क लगा देता है तो दूसरा देश भी बदले की भावना से उसके निर्यात पर प्रशुल्क लगा देता है।

आयात कर और मूल्य

(The Import Duties and Prices)

आयात कर एक वस्तु की कीमत एवं उत्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि किसी आयातित वस्तु पर जितना

आयात कर लगाया जाता है उसकी कीमत उतनी ही बढ़ जाती है। यह मान्यता सही नहीं है क्योंकि सम्भव है वस्तु की कीमत अधिक कम अथवा ज्यों की त्यों रहे। तीनों परिस्थितियाँ सम्भव हैं।

यदि लगाया गया कर विदेशी उत्पादकों द्वारा सहन कर लिया जाता है तो वस्तु की कीमत बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहती। यह प्रायः उस समय सम्भव होता है जब निर्यात करने वाला देश उसका उत्पादन एकाधिकार की परिस्थितियों में कर रहा हो और आयात करने वाला देश उसका सबसे बड़ा खरीददार हो। कुछ समय के लिए विदेशी उत्पादक द्वारा लगाए गए कर का सारा भार स्वयं सहन कर सकता है, ताकि वह अपने माल की खपत कर सके। यदि आवश्यक हुआ तो वह कीमत कम भी कर सकता है किन्तु ज्योंही निर्यात करने वाले देश का माल पूरा होगा त्योंही वह अपने माल की कीमत बढ़ा देगा।

यदि वस्तु का उत्पादन स्थिर लागत के नियम के अनुसार हो रहा है तो आयात करने वाले देश में वस्तु की कीमत उतनी बढ़ जाएगी जितना कि आयात कर लगाया गया है। जब आयात कर लगाने से वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो उसकी कुल घरेलू माँग घट जाएगी। यदि यह कीमत इतनी बढ़ जाए कि उस वस्तु की घरेलू लागत से भी अधिक हो जाए तो उसका आयात भी बन्द हो जाएगा क्योंकि उसे विदेश से खरीदने पर कोई लाभ नहीं रहेगा। ऐसा होने पर निर्यात-कर्त्ता देश को कुछ हानि होती है। जब सम्बन्धित वस्तु की माँग को घरेलू उत्पादन द्वारा पूरा किया जाता है तो उपरोक्त तो समान कीमत देता है किन्तु राजकोष को कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता।

तीसरी स्थिति में वस्तु की कीमतें आयात कर की मात्रा से कम बढ़ती हैं। यदि लगाया गया आयात कर आयात-कर्त्ता और निर्यात-कर्त्ता देशों के मध्य स्थित वस्तु लागत के अन्तरों से अधिक है और उत्पादन स्थिर लाभ के नियमों के अनुसार हो रहा है तो आयात पूर्ण रूप से रुक जाएगा। ऐसी स्थिति में मूल्य-वृद्धि केवल उतनी ही होगी जितना आयात-कर्त्ता और निर्यात-कर्त्ता देशों के बीच लागत का अन्तर है। यह लागत का अन्तर प्रायः कर की मात्रा से कम होता है। यदि कीमतें इस अन्तर से अधिक बढ़ जाती हैं तो असाधारण लाभ होने लगेगा। इस लाभ के कारण घरेलू उत्पादक अपनी पूर्ति को बढ़ा देंगे और पूर्ति की यह वृद्धि कीमत को गिरा देगी। वस्तु की कीमत लगाए गए कर से कम उस समय बढ़ती है जब उत्पादन और बाजार की शक्तें ठीक वैसे ही हों जैसे कर का सारा भार विदेशी उत्पादक या निर्यात-कर्त्ता देश पर डालते समय होती है। इन परिस्थितियों में सारा भार विदेशियों पर डालने की अपेक्षा केवल अंश मात्र ही डाला जा सकता है।

यदि उत्पादन वृद्धिशील लागत के अनुसार हो रहा है तो कर के साथ वस्तु की विदेशी कीमत घरेलू कीमत से भिन्न होगी। यदि वस्तु का मूल्य कर की मात्रा से अधिक होगा तो आयात कम कर दिया जाएगा और इस प्रकार घरेलू कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि मूल्य का अन्तर कर के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार स्थायी

स्थिति वह होगी जहाँ विदेशी एवं घरेलू मूल्यों के अन्तर दो कारणों अर्थात् घरेलू कीमतों बढ़ने या विदेशी कीमतों घटने से हो।

यदि अन्य बातें समान रहें तो निर्यात-कर्त्ता देश में वस्तु की माँग जितनी अधिक तथा लोचशील होगी वहाँ वस्तुओं के मूल्य में उतनी ही कमी होगी और दूसरी ओर आयात-कर्त्ता देश में कीमत उतनी ही बढ़ जाएगी। यदि आयातित वस्तु की कीमत थोड़ी भी कम हुई तो उसकी घरेलू माँग बढ़ जाएगी और इस प्रकार कर द्वारा विदेशी बाजार में जो हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। इस प्रकार निर्यात-कर्त्ता देश अपनी कीमत में थोड़ी ही कमी करेगा। आयात-कर्त्ता देश का अपना घरेलू उत्पादन बढ़ाना होगा ताकि उस माँग की पूर्ति की जा सके जिसे पहले विदेशी निर्यात-कर्त्ता द्वारा पूरा किया जाता था। ऐसी स्थिति में उत्पादन लागत बढ़ जाएगी और आयात-कर्त्ता देश में वस्तु की कीमत भी बढ़ेगी। दूसरी ओर यदि आयात-कर्त्ता देश में माँग बड़ी और लोचशील है तो उसमें वस्तु के मूल्य की वृद्धि अपेक्षाकृत कम होगी और निर्यात-कर्त्ता देशों में मूल्य की कमी अधिक हो जाएगी। यदि माँग लोचशील है तो वस्तु की कीमत थोड़ी बढ़त ही आयात-कर्त्ता देश में उसकी खपत घट जाएगी। इस स्थिति में आयात-कर्त्ता देश में उत्पादन तथा मूल्य की वृद्धि बहुत कम होगी। जब आयात कर लगाने से आयात-कर्त्ता देश में अन्य देश के निर्यातों की माँग कम हो जाती है तो निर्यात-कर्त्ता देश में उनका उत्पादन घट जाता है। इससे परिणामस्वरूप उत्पादन लागत घटेगी और इसलिए निर्यात-कर्त्ता देश में वस्तु की कीमत घट जाएगी।

यदि अन्य बातें समान रहें तो निर्यात-कर्त्ता देश की पूर्ति जितनी अधिक तथा लोचशील होगी उसमें मूल्य की कमी उतनी ही कम होगी और आयात-कर्त्ता देश में मूल्य की वृद्धि उतनी ही हो जाएगी। कीमतों में कमी होने पर निर्यात-कर्त्ता देश में उनका उत्पादन कम हो जाएगा। आयात में भारी कमी होने पर घरेलू उत्पादन बढ़ाना होगा और इसलिए वस्तु की उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। साथ ही आयात-कर्त्ता देश में कीमतें भी घट जाएँगी। इस प्रकार यदि कर लगाने से आयात थोड़ा कम होता है तो इसके परिणामस्वरूप निर्यात-कर्त्ता देश में वस्तु की कीमतें कम हो जाएँगी और आयात-कर्त्ता देश में कीमतें बढ़ जाएँगी। दूसरी ओर यदि आयात-कर्त्ता देश में पूर्ति लोचशील है तो उसमें कीमत की वृद्धि तुलनात्मक रूप से कम होगी और निर्यात-कर्त्ता देश में कीमतें घट जाएँगी।

कभी कभी वस्तु की कीमतें लगाए गए आयात कर की मात्रा से अधिक बढ़ जाती हैं। अन्तिम उपभोक्ता के पास पहुँचने से पूर्व वस्तु अनेक विचालियों के हाथ से निकलती है। ये सभी लाभ कमाते हैं। ये वस्तु पर अपने लाभ का कुछ प्रतिशत सम्मिलित कर लेते हैं।

आयात-कर के कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव
(Some Indirect Effects of Import Duty)

किसी वस्तु पर लगाए गए आयात-कर के परिणामस्वरूप कीमतों में जो वृद्धि

होती है वह उसका प्रत्यक्ष प्रभाव है। इसके अतिरिक्त आयात कर के कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव भी होते हैं। इन सब का वर्णन करना यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। इनकी सामान्य प्रकृति का उल्लेख किया जा सकता है। किसी एक आयात कर को लगाने की वांछनीयता का अध्ययन करते समय इन प्रभावों को ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है।

किसी वस्तु के आयात पर कर लगाया जाता है तो सामान्यतः उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है और मांग घट जाती है। ऐसी वस्तु से अलग होने वाली क्रय-शक्ति (Purchasing Power) को घरेलू सामान अथवा अन्य आयातित वस्तुओं पर खर्च किया जा सकता है। सामान्यतः इस क्रय-शक्ति को अतः घरेलू सामान पर और अतः आयातित वस्तुओं पर खर्च किया जाता है। जब क्रय-शक्ति का कुछ भाग आयातित वस्तु से घरेलू वस्तुओं की ओर मुड़ जाएगा तो सम्बन्धित वस्तु को निर्यात करने वाले देश की भुगतानों की संतुलन स्थिति बदल आएगी। भुगतानों के असंतुलन को ठीक करने के लिए निर्यात-कर्त्ता आयातों की मात्रा को घटा देता है। आयातों की यह कमी या तो घन सम्बन्धी घन द्वारा अपने आप ही कर ली जाती है अथवा इसके लिए राज्य स्वयं नीति निर्धारित करता है। इसका अन्तिम परिणाम यह होगा कि विश्व-व्यापार की मात्रा कम हो जाएगी और दोनों देशों में क्रय शक्ति आयातित-वस्तु से घरेलू वस्तु की ओर मुड़ जाएगी। इससे घरेलू वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा और जिन वस्तुओं का व्यापार किया जाता है उनका उत्पादन घट जाएगा। उत्पादन के विभिन्न साधनों के मूल्यों में तुलनात्मक परिवर्तन विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन का कारण बन आएंगे।

जिस वस्तु पर आयात कर लगाया जाता है उसकी कीमत में होने वाली वृद्धि अन्य वस्तुओं की कीमत को बढ़ा देगी। यदि वह वस्तु अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयुक्त की जाती है तो इससे उत्पादन की लागत और उन वस्तुओं की कीमत प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगी। आयात कर जिस वस्तु पर लगाया गया है यदि वह उपभोग-वस्तु है तो उसकी कीमतों में वृद्धि होने के कारण मजदूर अधिक वेतन की मांग करेंगे ताकि वे (महंगी वस्तुओं) महंगाई का सामना कर सकें और इस प्रकार वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी।

(II) निर्यात कर

(Export Duties)

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्यकाल से पूर्व निर्यात करों का प्रयोग एक सामान्य बात थी। उस समय यह लोकप्रिय विश्वास था कि निर्यात करों को आयात करने वाले देश के उपभोक्ताओं द्वारा सहन किया जाता है। बाद में यह समझा जाने लगा कि निर्यात कर सामान्य रूप से राष्ट्रीय हित में नहीं होता है क्योंकि इससे देश का निर्यात रुकता है।

निर्यात कर लगाने का उद्देश्य भी सामान्यतः राजस्व की प्राप्ति होता है। निर्यात कर प्रायः उन देशों द्वारा लगाया जाता है जो मूलभूत उत्पादों का निर्यात

करने हैं अर्थात् अच्छा माल बेचते हैं। यह निर्मित वस्तुओं पर बहुत कम लगना है। इसका एक कारण यह है कि अच्छे माल का उत्पादन करने वाले देश विद्युत् दूए हाते हैं। उन देशों में घरेलू धातु, उत्पादन एवं लागू पर कर लगाने वाला प्रशासकीय तन्त्र इतना विकसित नहीं होता जितना कि विदेशी व्यापार पर कर लगाने वाला देश है। इन देशों के लोग अधिकतर अघिषित होते हैं और इसलिए वे व्यवस्थित लक्ष्य नहीं रख पाते। इन देशों की जनमत्तया प्रायः देशाती क्षेत्रों में बितरी हुई होती है। ऐसी स्थिति में प्रायः कर अथवा उत्पादन कर को एकत्रित करने में भारी खर्चा आता है। दूसरी ओर निर्यात करों का समग्र करने के लिए प्रशासकीय व्ययों का होना केवल बन्दरगाहों पर ही पर्याप्त होना है तथा इसके लिए केवल धातु से ही लोगों की आवश्यकता होती है।

निर्यात कर संरक्षण की नीति का एक हथियार है। इसे प्रायः घरेलू उत्पादकों की रक्षा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कई बार एक साम्राज्यवादी देश अपने उपनिवेशों को इस बात के लिए मजबूर करता है कि वे निर्यात कर लगाएँ ताकि वह देश अपने घरेलू उद्योगों का उपनिवेशों की प्रतिस्पर्धा से बचा सके। कभी-कभी निर्यात करों का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है, ताकि प्राकृतिक माधनों का घरेलू उद्योगों के लिए रखा जा सके। एक देश निर्यात की प्रोत्साहन देने की विभिन्न विधियों में घन लक्ष्य करता है तो इसके बदले वह निर्यात कर लगा देता है। निर्यात कर प्रायः उन वस्तुओं पर भी लगा दिया जाता है जिनकी पूर्ति कम होती है और जिनके लिए एक देश दूसरे देशों से अधिक कीमत प्राप्त करना चाहता है।

निर्यात कर एवं कीमते

(Export duties and Prices)

आज का संसार एक प्रतिस्पर्धापूर्ण स्थिति में है और इसलिए निर्यात करों का भार स्वयं निर्यातकर्ता देश के उत्पादकों द्वारा ही वहन किया जाना चाहिए। विश्व बाजार में निर्यात कर लगाने वाले देश के उत्पादक किसी वस्तु की कीमत उममें अधिक प्राप्त नहीं कर सकने जिनकी में अन्य देश उसे आपानी में देने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार इन उत्पादकों को अपने निर्यात की कीमत विश्व की कीमत से कम मिलेगी क्योंकि उममें से लगा हुआ निर्यात कर घट जाएगा। यह मूल्य की कमी लाभ को कम कर देगी और इस प्रकार उत्पादन तथा निर्यात की मात्रा घट जाएगी।

यदि निर्यात कर लगाने वाला देश उम वस्तु का प्रमुख पूर्तिकर्ता है तथा उम वस्तु की पूर्ति पर्याप्त लोचनीय है तो निर्यात कर का एक भाग आयातकर्ता देश के उपभोक्तार्थों से वसूल किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उम वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी।

विश्व माँग की लोचनीयता जितनी अधिक होगी, दुनिया की कीमतें उतनी ही कम बढ़ेंगी। इस प्रकार कर लगाने वाले देश के उत्पादकों को उतनी ही कम कीमत प्राप्त होगी। जब विश्व की माँग लोचनीय है तो कीमतों में थोड़ी सी वृद्धि

भी माँग की कमी का कारण बन जाती है। माँग में अधिक कमी होने के कारण कीमतें घट जाती हैं, इसके विपरीत यदि विश्व की माँग लोचहीन है तो मूल्य में वृद्धि अधिक नहीं होगी और इस प्रकार मूल्य प्रायः अधिक प्रभावित रहेगा। ऐसी स्थिति में निर्यात कर का भार घरेलू उत्पादकों के कंधों पर पड़ेगा।

(III) पारगमन कर (Transit Duty)

19 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में व्यवसायवाद के काल में इस प्रकार के कर अत्यन्त सामान्य थे। उस समय यातायात अत्यन्त धीमा और महंगा था। इसके लिए छोटे रास्ते का होना जरूरी था। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए अनुकूल भौगोलिक स्थिति से सम्पन्न देशों ने अपने क्षेत्र में से गुजरने वाले व्यापारियों पर कर लगाए। 19वीं शताब्दी के दौरान यातायात के क्षेत्र में होने वाले विभिन्न विकासों ने इस कर की सम्भावनाओं को कम कर दिया। इसके प्रतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की भावना पैदा हुई उसके फलस्वरूप भी पारगमन कर समाप्त हो गए। इस प्रकार के करों का भार आयातकर्ता देश के उपभोक्ताओं अथवा निर्यातकर्ता देश के उत्पादकों पर पड़ेगा, इसका निश्चय दोनों देशों में माँग और पूर्ति की परिस्थितियों द्वारा होता था। अन्य करों की भांति ये कर विश्व-व्यापार के आकार को रोकने का कार्य करते थे।

दो दृष्टिकोण (Two Approaches)

प्रशुल्कों को विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उनको वर्गीकृत करने के दो प्रमुख दृष्टिकोण हैं। एक के अनुसार इनके उद्देश्य पर जोर दिया जाता है और दूसरे के अनुसार इनके द्वारा अपनाई गई दर को महत्वपूर्ण माना जाता है। इन दोनों का अध्ययन निम्न प्रकार किया जा सकता है—

(1) करों का उद्देश्य—कोई भी प्रशुल्क या तो राजस्व एकत्रित करने के लिए लगाया जाता है अथवा रक्षा की दृष्टि से। जो प्रशुल्क राजस्व की दृष्टि से लगाए जाते हैं उनकी सामान्यतः अपेक्षाकृत कम दर होती है क्योंकि ये आयातों को बाहर रखने के उद्देश्य से नहीं लगाए जाते। ये मुख्य रूप से घरेलू उपभोग की उन वस्तुओं पर लगाए जाते हैं जिनका उपयोग व्यापक होता है। दूसरी ओर रक्षात्मक प्रशुल्क वे होते हैं जो विदेशी आयात में कटौती करने के लिए लगाए जाते हैं ताकि घरेलू उत्पादों को प्रतियोगिता में बचाया जा सके। पूर्ण रक्षात्मक प्रशुल्क आयात को पूर्ण रूप से रोक देते हैं और इस प्रकार का राजस्व प्राप्त नहीं करते। अधिकांश रक्षात्मक प्रशुल्क ऐसे होते हैं जो समस्त आयातों को पूर्णतया नहीं रोकते और इसीलिए वे कुछ राजस्व प्रदान करते रहते हैं। इस प्रकार के प्रशुल्कों में रक्षात्मक और राजस्व दोनों प्रकार के शुण पाए जाते हैं। कई मामलों में तो यह विशिष्ट करना कठिन हो जाता है कि प्रशुल्क का उद्देश्य क्या है ?

(2) कर की दरें—कर की दरें या तो विशेष हो सकती हैं भयवा प्रतिगमन के हिसाब से हो सकते हैं। विशेष दरों के अनुसार प्रति भौतिक इकाई पर कर लगाए जाएंगे, जैसे—एक मन गेहूँ पर 10 पैसे या 10 टन ताँहे पर दो रुपए आदि। इसके विपरीत वस्तुओं की कीमत के प्रतिगमन के हिसाब से भी कर लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए एक मजदूर की कीमत पर 10 प्रतिशत आयान के बढतन से इस प्रकार के कर की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता जब कि बिना कर की मात्रा कीमतों में परिवर्तन के साथ बदलती रहती है।

प्रशुल्क का भुगतान कौन करता है ?

(Who pays the Tariffs?)

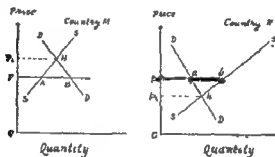
लगाया गया प्रशुल्क किसके द्वारा बढ़ा किया जाता है—यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सम्बन्ध में एक प्रतिशयपूर्ण दृष्टिकोण यह है कि प्रशुल्क विदेशी पूर्णिकता पर लगाया गया एक कर है जबकि दूसरा प्रतिशयपूर्ण दृष्टिकोण यह है कि प्रशुल्क का भुगतान अन्तिम उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। यदि दोनों दृष्टिकोणों के उदाहरण हैं किन्तु सामान्य रूप से वस्तु स्थिति दोनों के बीच में रहनी है। इस स्थिति को सामान्यतः चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। लगाया गया कर हो सकता है कि घरेलू कीमतों पर किसी प्रकार का प्रभाव न डाले। यह घरेलू कीमतों को बढ़ा सकता है किन्तु यह वृद्धि कर की मात्रा से कम या बराबर भयवा भविष्य हो सकती है।

(1) कभी कभी लगाया गया प्रशुल्क घरेलू कीमतों का बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। ये वस्तुएँ प्रायः ऐसी होती हैं जिनकी पूर्ण सामान्य घरेलू माँगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होती हैं तथा निर्यात के लिए भी प्रतिरोक बच जाता है। इस स्थिति का कारण ऐतिहासिक उदाहरणों के सम्बन्ध में समझा जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रति बुशल (Bushel) गेहूँ पर 42 सेंट कर लगा दिया ताकि घरेलू कीमतों को विश्व के स्तर तक बढ़ाया जा सके। इस समय अमेरिका में गेहूँ का निर्यात किए जाने घोष्य नियमित प्रतिरोक था। ऐसी स्थिति में प्रशुल्क सम्बन्धी यह बढतन असफल होना स्वाभाविक था। यदि घरेलू कीमतें विश्व स्तर से अधिक बढ़ जाती तो घरेलू उत्पादकों को अपना मारा गेहूँ घर में ही बेचने में लाज था। गेहूँ की माँग देश में निश्चित थी और इसलिए व्यापक विप्री होने के कारण कीमतों को पुनः गिरना होता। कहने का अर्थ यह है कि जब कभी निर्यात योग्य प्रतिरोक रहता है घरेलू उत्पादक अपने उत्पादन के लिए विश्व कीमत से अधिक प्राप्ति नहीं कर सकते—इसके लिए वह चाहे प्रशुल्क लगाए भयवा न लगाए।

(2) उमरा कर देय वस्तु का उत्पादन यदि लागत वृद्धि के अनुसार किया जाता है तो उनकी घरेलू कीमत कर की अपेक्षा कम बढ़ती है, क्योंकि इसमें पूर्ण की प्रतिरक्त इकाइयों का उत्पादन प्रति इकाई अधिक लागत लगा कर हो गया या सकता है। स्वतन्त्र बाजार की परिस्थितियों में वस्तुओं की कीमतों के

बीच समानता रहती है चाहे उनमें यातायात का व्यय कितना ही अधिक क्यों न किया गया हो ? कर लगने पर वस्तु की घरेलू और विदेशी कीमतों में कर के बराबर अन्तर आ जाएगा। आयातकर्त्ता देश को जब अधिक कीमत में माल मिलने लगेगा तो वह आयात की मात्रा घटा देगा और घरेलू उत्पादन को बढ़ाएगा। यह कदम तब ही उठाया जाएगा जबकि प्रति इकाई लागत की मात्रा अधिक होगी। निर्यातकर्त्ता देश में इसका प्रभाव यह होगा कि उसका निर्यात घट जाएगा। इससे उत्पादन की मात्रा घट जाएगी, लागत भी घटेगी और सम्भवतः उपभोग बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर परिणाम यह होगा कि आयातकर्त्ता देश में वस्तु की कीमत पहले से कुछ अधिक हो जाएगी किन्तु यह अधिक मात्रा लगाए गए कर की मात्रा से थोड़ी कम होगी।

इस प्रकार के समायोजन को निम्न रेखाचित्र द्वारा समझाया जा सकता है—

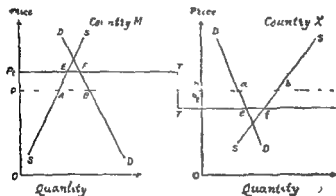


Incidence of a Tariff

उपर्युक्त रेखाचित्र में उस वस्तु की माँग-पूर्ति और कीमत को लिया गया है जो दो देशों में लागत-वृद्धि के नियम के प्राचीन उत्पादित की जाती है। ये देश हैं—'M' और 'X'। व्यापार न करने वाले विश्व में प्रत्येक देश विशेष वस्तु का उत्पादन करता है। 'M' देश P_1H की मात्रा को OP_1 की कीमत पर उत्पादित करता है और X देश P_1b की मात्रा को Op_1 कीमत पर उत्पादित करता है और उपभोग करता है। मान लीजिए व्यापार प्रारम्भ होता है और कीमतों कम होने के कारण X निर्यात करता है और कीमत अधिक होने के कारण M आयात करता है। यहाँ यदि हम यातायात लागत को सम्मिलित न करें तो दोनों देशों में समान कीमतें रहेगी। यह कीमतें ऐसी होगी कि X और M की संयुक्त पूर्ति X तथा M की संयुक्त माँग के बराबर हो जाएगी। M की कीमत के स्तर को घाड़ी रेखा Pp द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। उसमें ab निश्चय ही AB के बराबर रहेगा अर्थात् X की अतिरिक्त पूर्ति M की अतिरिक्त माँग के बराबर हो जाएगी। इस प्रकार व्यापार शुरू होने का प्रभाव M पर यह पड़ेगा कि Op_1 कीमतों Op पर आ जाएगी और उत्पादन P_1H से घट कर PA तक आ जाएगा। दूसरी ओर उपभोग P_1H से बढ़कर PB पर आ जाएगा। आयातों की मात्रा AB हो जाएगी।

दूसरी ओर X पर प्रभाव यह पड़ेगा कि वह कीमतों को Op_1 से Op तक बढ़ा देगा। वह उत्पादन को Pib से pb तक बढ़ा देगा और उपभोग को Pib से pa तक घटा देगा, इस प्रकार निर्यात $ab (= AB)$ हो जाएगा।

उपयुक्त परिस्थितियों में यदि M द्वारा आयात कर लगा दिया जाता है और यह पूर्ण रूप से रक्षात्मक है तो परिणामस्वरूप दोनों देशों के बाजार पृथक् हो जाएंगे और वह परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी जो व्यापार शुरू होने से पूर्व थी। ऐसी स्थिति में हम यह कहना करते हैं कि लगाया गया कर पूर्णतया रक्षात्मक से कम है। इसमें जो स्थिति उत्पन्न होगी उसे निम्न रेखाचित्र में प्रदर्शित किया गया है—



इस रेखाचित्र में कर TT है। यदि M और X देशों के बीच व्यापार होना है तो यह जरूरी है कि M में कीमतें X की अपेक्षा TT से अधिक हों। X के द्वारा अपनी मांग से अधिक ज़िम्मा मात्रा की पति की जाएगी वह M की घरेलू पूर्ति में अधिक मांग के बराबर होगी। नव स्थापित सन्तुलन टूटी फूटी रेखा PtT Tip के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यह उस समय तक ऊपर और नीचे होता है जब तक कि EF अन्य ef के बराबर न हो जाए। इस बिन्दु पर X के निर्यात M के आयातों के बराबर हो जाते हैं। यहाँ हम टूटी हुई रेखा Pp को भी जोड़ सकते हैं ताकि स्वतंत्र बाजार की परिस्थितियों में और प्रशुल्क की परिस्थितियों में बाजार की तुलना की जा सके। यह स्पष्ट है कि M पर प्रशुल्क का प्रभाव कीमतों को Op से Op_1 पर बढ़ाने का है और उत्पादन को PA से PtE तक बढ़ाने का है, किन्तु इसके आयात AB से EF तक घटा दिए जाते हैं और उपभोग को PB से PtF तक घटा दिया जाता है। X देश पर इसका जो प्रभाव होगा उसके अनुसार कीमतों को Op से Op_1 तक और उत्पादन को pb से pt तक घटा दिया जाएगा। इसके निर्यात ab में ef तक घटा दिए जाएंगे किन्तु इसका उपभोग pa में Ptc तक बढ़ा दिया जाएगा।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि आयातकर्ता देश पर प्रशुल्क का प्रभाव यह होगा कि उसकी कीमतें और उत्पादन बढ़ जाएंगे किन्तु आयात और उपभोग घट जाएंगे। निर्यातकर्ता देश में कीमतें उत्पादन और निर्यात घट जाएंगे तथा उपभोग

बढ़ जाएगा। यद्यपि दोनों देशों में कीमत का अन्तर कर की पूर्ण मात्रा के बराबर है किन्तु फिर भी आयातकर्ता देश में कीमत कर की मात्रा से कम बढ़ती है। उपर्युक्त स्थिति में कीमत-अभाव मूल रूप से पूर्ति और माँग के आकार तथा लोचशीलता पर निर्भर करता है।

(3) जिस वस्तु पर कर लगाया जा रहा है यदि उसका उत्पादन स्थिर लागत के अनुसार किया जा रहा है तो प्रशुल्क के कारण घरेलू कीमतें लगाए गए कर के बराबर बढ़ जाएँगी। ऐसी स्थिति में कर लगने के कारण उसकी कीमतें ऊँची होने और आयात की मात्रा घटने पर भी सम्पूर्ण पूर्ति का आयात किया जाएगा।

(4) यह भी सम्भव है कि एक वस्तु की घरेलू कीमत उस मात्रा से अधिक बढ़ जाए जिसमें कर लगाया गया है। यह इसलिए सम्भव है क्योंकि आयातित माल उपभोक्ता के पास सीधा नहीं पहुँचता बल्कि विचोलिएँ के हाथों में होकर निकलता है। प्रत्येक मध्यस्थ व्यक्ति उसकी कीमत को कुछ न कुछ बढ़ा देता है। इस प्रकार जब वस्तुएँ अनेक हाथों में होकर निकलती हैं तो दिया गया कर वास्तविक उपभोक्ता तक पहुँचते-पहुँचते कई गुना बढ़ जाता है।

प्रशुल्क के प्रभाव (Effects of Tariff)

किङलवर्गर के अनुसार प्रशुल्क लगाने से निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं—

(1) निर्यातों की मात्रा पर प्रभाव—आयातों पर जो कर लगाया जाता है वह निर्यातों को घटा देता है। यह तथ्य पारस्परिक माँग की मान्यता पर आधारित है। एक देश द्वारा लगाया गया प्रशुल्क उसके आयातों को घटा देगा और इसलिए विदेशी निर्यातकर्ताओं को विदेशी विनिमय की आमदनी कम हो सकेगी। ऐसी स्थिति में प्रशुल्क लगाने वाले देश के माल का निर्यात बाजार घट जाता है। जब प्रशुल्क लगाने से एक देश के किसी विशेष घरेलू उद्योग अथवा उद्योगों को प्राप्तिमान होती है तो बदले में अन्य घरेलू उद्योगों (निर्यात उद्योगों) को नुकसान भी होता है। इस प्रकार सम्भावित निर्यात घट जाने से उत्पादन के तत्त्व पहले की अपेक्षा कम आमदनी प्राप्त कर पाते हैं।

(2) व्यापार शर्तों पर प्रभाव—प्रशुल्क नीति अपनाने का एक प्रभाव देश की व्यापार शर्तों पर भी पड़ता है। उस देश की व्यापार शर्तें उस समय सुधर जाती हैं जब कि प्रशुल्क लगाने वाला देश की विदेशी वस्तुओं की माँग अपेक्षाकृत अधिक और लोचशील है। प्रशुल्क के प्रभाव के कारण देश के आयात घट जाते हैं और इसलिए देश के माल को खरीदने के लिए विदेशों के पास साधन उपलब्ध नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में विदेशी की अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, ताकि प्रशुल्क वाले देश को वे पूर्ववत् निर्यात कर सकें और इससे आवश्यक वस्तु खरीदने में साधन प्राप्त कर सकें। यहाँ प्रशुल्क का प्रभाव यह हुआ कि आयात की कीमतें निर्यात की कीमतों से कम हो गई और इस प्रकार प्रशुल्क लगाने वाले देश की व्यापार शर्तें सुधर गई।

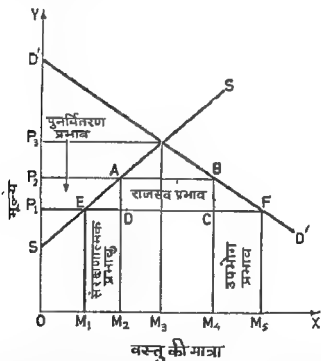
यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि व्यापार शक्तों में इस प्रकार होने वाला सुधार आयात की मात्रा में कमी के साथ होता है। इस प्रकार एक देश दूसरे देश के दम पर लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह स्थिति कभी भी चुनौती का विषय बन सकती है। एक देश द्वारा ऐसा कदम उठाए जाने पर दूसरे देश में उसकी प्रतिक्रिया होगी और दूसरे देश भी प्रतिबन्ध लगाने की नीति को अपना लेगा। इस प्रकार राष्ट्रीय लाभ प्राप्त करने के लिए एक देश द्वारा किए गए प्रयास सभी देशों के लिए हानिप्रद बन जाएंगे क्योंकि नवीन प्रतिबन्धों के कारण उत्पादन के साधनों का पूर-पूर प्रयोग नहीं हो पाएगा। प्रतिक्रियास्वरूप कदम न उठाए जाने पर भी प्रगुल्क लगाने वाला देश यह अनुभव कर सकता है कि व्यापार की मात्रा घटने के कारण उस पर्याप्त हानि रही है। इसका विस्तृत वर्णन व्यापार की शक्तों के निर्धारण घटक शीर्षक में किया गया है।

(3) भुगतान में सन्तुलन पर प्रभाव—प्रगुल्क के अधिक महत्वपूर्ण प्रभावों में भुगतान सन्तुलन भी एक है। एक देश जो अन्यथा अपने भुगतान सन्तुलन में घाटे की स्थिति में रह सकता है वह प्रगुल्क प्रतिबन्धों के माध्यम से समतुल्यता प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से प्राप्त समतुल्यता की अनेक प्रकार से प्रालोचना की जाती है—(1) यह कहा जाता है कि समतुल्यता व्यापार को सीमित करके लाई जाती है इसलिए व्यापक विश्व व्यापार से होने वाली प्राप्तियों के प्रकाश में यह स्वरूप दिखता है। (2) समापोजन का यह तरीका एक औपचारिक और बाहरी तरीका है तथा यह समतुल्यता के मूल कारण पर विचार किए बिना ही कदम उठाता है। भुगतान सन्तुलन की घाटे की स्थिति को दूर करने के लिए और अच्छे तरीके भी हाथ हैं उन्हें अपनाया जाना अपेक्षाकृत अधिक श्रेष्ठ है।

दूसरी ओर नए या उच्च प्रगुल्को का लगाना असमतुल्यता की स्थिति को चिन्तनीय बना सकता है। उदाहरण के लिए सयुक्त राज्य अमेरिका ने बहुत समय तक निर्माण अनिर्णय का अनुभव किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में माल और सेवा का निर्माण-आयात में अधिक बढ़ गया। ऐसी स्थिति में भुगतान को मजबूत करने के लिए नए तथा ऊँचे प्रगुल्क लगाए गए। इस प्रकार सयुक्त राज्य अमेरिका के आयात प्रतिबन्धित हो गए और यहाँ से आयात करने वाले दूसरे देश डॉलर कमाने में कठिनाई का अनुभव करने लगे। यह स्थिति उन समय और भी जटिल हो गई जब एक ऋणदाता के रूप में सयुक्त राज्य अमेरिका विदेशियों से ऋण, सामाजिक और पूँजी के पुनर्भूतन की मांग करने लगा। इन चीजों का हस्तान्तरण केवल तब ही हो सकता था जब ऋणदाता आयात-अनिर्णय स्वीकार करने के लिए तैयार हो। मान की गतिशीलता भुगतान का एक साधन हो सकती थी किन्तु प्रगुल्को की नीति ने उसके मार्ग को अवरोध कर दिया।

(4) सरसण पर प्रभाव—प्रगुल्क एक प्रतिरोधात्मक उपाय है जिसके द्वारा आयात की मात्रा को नियन्त्रित किया जाता है ताकि स्वदेशी उद्योगों का मरझण प्राप्त हो सके। अन्य शब्दों में, प्रगुल्क देश के अन्दर विदेशी वस्तुओं के आगमन का

विभिन्न अंशों तक रोकने के लिए लगाए जाते हैं ताकि स्वदेशी उद्योग विदेशी प्रतियोगिता से बच सके। एक प्रशुल्क कर उस समय पूर्णतया संरक्षणात्मक हो जाता है जबकि कर की दर इतनी अधिक रखी जाती है जिसके कारण वस्तुओं का आयात बिल्कुल ही बन्द हो जाता है किन्तु सामान्यतया अधिकांश प्रशुल्क पूर्णतया संरक्षणात्मक नहीं होते अर्थात् प्रशुल्क कर कितना ही ऊँचा क्यों न हो, कुछ न कुछ वस्तुओं का आयात होता ही है। प्रशुल्क का संरक्षणात्मक प्रभाव इसमें भी देखा जा सकता है कि इसके द्वारा देश में वस्तुओं के उत्पादन का विस्तार होता है क्योंकि प्रशुल्क के लग जाने के कारण स्वदेशी बाजार में वस्तुओं का दाम बढ़ जाता है जिसके कारण देशी उत्पादकों के लिए अधिक उत्पादन पर होने वाली बढ़ती हुई सीमांत लागतों को पूरा करना सम्भव हो जाता है। प्रशुल्क के संरक्षणात्मक प्रभाव को रेखाचित्र निम्नोक्त की सहायता से समझाया जा सकता है।



माना कि प्रशुल्क से पूर्व मूल्य P_1 है और OM_3 वस्तु का उपभोग होता है। इस मात्रा में से OM_2 का उत्पादन स्वदेश में होता है और M_1M_3 का आयात किया जाता है।

अब माना कि उस वस्तु पर P_1P_2 के बराबर प्रशुल्क लगा दिया जाता है जिससे कीमत OP_1 से OP_2 हो जाती है। कीमतों में इस बढ़ोतरी के कारण घरेलू उत्पादन OM_1 से बढ़ कर OM_2 हो जाता है तथा आयात M_1M_3 से घट कर

M_2M_4 हो जाता है। अतः घरेलू उत्पादन में M_1M_2 की वृद्धि प्रशुल्क का 'संरक्षण-प्रभाव' है।

यदि सम्बन्धित वस्तु पर अधिक प्रशुल्क अर्थात् P_1P_3 वर दिया जाए तो कीमतें बढ़ कर OP_3 हो जाएँगी। इस स्थिति में घरेलू उत्पादन बढ़कर MO_3 हो जाएगा और उपभोग भी घटकर OM_3 हो जाएगा। इस प्रकार घरेलू उत्पादन घरेलू उपभोग के बराबर हो जाएगा। जिससे आयात शून्य हो जाएगा। P_1P_3 प्रशुल्क निषिद्धकारी का उदाहरण है अर्थात् इतने अधिक प्रशुल्क से वस्तु का आयात बिल्कुल समाप्त हो जाएगा।

(5) उपभोग पर प्रभाव—प्रशुल्क सामान्यतया वस्तुओं के कुल उपभोग को घटा देता है क्योंकि प्रशुल्क के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। जब मूल्य OP_1 रहना है तो वस्तु का उपभोग OM_1 रहता है। इसके पश्चात् जब प्रशुल्क लगा देने से कीमत OP_2 हो जाती है तो घरेलू बाजार में वस्तु की कीमत बढ़ जाने से उपभोग OM_1 से घट कर OM_2 हो जाता है। M_1M_2 की मात्रा के तुल्य उपभोग में कमी प्रशुल्क के उपभोग प्रभाव को प्रकट करती है। इस प्रकार प्रशुल्क लगाने से उपभोक्ता की सन्तुष्टि में एक प्रकार की हानि होती है।

(6) पुनर्वितरण पर प्रभाव—प्रशुल्क लगाए जाने से घरेलू कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति रहती है। जिससे उत्पादकों की आय में वृद्धि हो जाती है, जबकि उपभोक्ताओं का प्रतिरेक उस सीमा तक घट जाता है, अर्थात् कीमतों में वृद्धि के कारण उत्पादकों की आय में तो वृद्धि हो जाती है लेकिन उपभोक्ताओं की वास्तविक आय में कमी हो जाती है। इसे ही पुनर्वितरण प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार आय में बढ़ौनरी जो सीमान्त लागतों के ऊपर होती है वह उत्पादकों के लिए आर्थिक लगान है जिन्हें उपभोक्ता की बचत में से घटाकर निकाला जाता है। रेखाचित्र में P_1EAP_2 क्षेत्र पुनर्वितरण प्रभाव को निरूपित करता है।

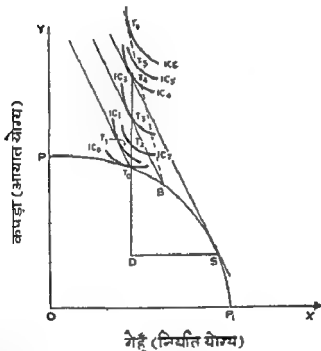
अतः यह स्पष्ट है कि प्रशुल्क के कारण वस्तु के घरेलू मूल्य में वृद्धि होने पर आय का पुनर्वितरण उपभोक्ताओं से उत्पादकों के लिए हो जाता है।

(7) उत्पादन पर प्रभाव—हम जानते हैं कि एक देश विशिष्टीकरण और वस्तुओं के विनिमय के द्वारा विदेशी व्यापार से लाभान्वित होता है। जब एक देश द्वारा अपने आयातों पर प्रशुल्क लगाया जाता है तब उस देश में आयात-प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन मिलता है और निर्यातक देश के निर्यात-क्षेत्र का संकुचन होता है। निर्यात-क्षेत्र के संकुचन से विदेशी व्यापार के विशिष्टीकरण से होने वाला लाभ उत्पादन पर प्रभाव कहलाता है तथा वस्तुओं के विनिमय में होने वाला लाभ उपभोग प्रभाव कहलाता है।

माना कि किसी देश A में कपड़े और गेहूँ का उत्पादन होता है। साथ ही देश A गेहूँ का निर्यात और कपड़े का आयात करता है।

माना कि P_1P_2 उत्पादन सम्भावना वक्र है। विदेशी व्यापार की अनुपस्थिति में A देश में दोनों वस्तुओं का उत्पादन व उपभोग T_0 बिन्दु पर होता

है। जहाँ उत्पादन सम्भावना वक्र $P_1 P_2$ और उदासीनता वक्र IC_0 एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ST_4 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त रेखा है जो यह प्रदर्शित कर रही है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कपड़ा गेहूँ के सन्दर्भ में सस्ता है। इस व्यापार की शर्त पर यदि A देश T_0 बिन्दु के अनुसार कपड़े और वस्त्र का उत्पादन करता है तो वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय द्वारा A देश को लाभ होगा और वक्र T_1 बिन्दु पर पहुँच जाएगी। T_1 बिन्दु अपेक्षाकृत ऊँचे उदासीनता वक्र IC_1 पर स्थित है जो



अधिक सन्तोष का परिचायक है क्योंकि विदेशी बाजार में गेहूँ की सापेक्ष कीमत अधिक है इसलिए A देश गेहूँ के उत्पादन को S बिन्दु तक बढ़ाएगा। S बिन्दु पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त रेखा ST_4 उत्पादन सम्भावना वक्र $P_1 P_2$ की स्पर्श रेखा हो जाती है। ST_4 व्यापार की शर्त पर देश A, DT_4 कपड़े की इकाइयों के लिए DS गेहूँ की इकाइयों का निर्यात करके T_4 बिन्दु पर पहुँच जाता है जो कि अपेक्षाकृत और ऊँचे उदासीनता वक्र IC_4 पर स्थित है।

अब यदि A देश कपड़े के आयात पर प्रशुल्क लगा देता है तो कपड़ा महंगा हो जाएगा। कपड़े के महंगे हो जाने से A देश के उत्पादक गेहूँ का उत्पादन कम करके कपड़े का उत्पादन बढ़ाएंगे। फलतः ससाधनों का अंतरण गेहूँ के उत्पादन से कपड़े के उत्पादन की ओर होगा।

अब हम यह मान लेते हैं कि उत्पादन सम्भावना वक्र $P_1 P_2$ के B बिन्दु पर उत्पादन हेतु यदि प्रशुल्क नहीं लगाया जाता और उत्पादन B बिन्दु पर होता

है तो A देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा गेहूँ और कपड़े के उस संयोग का उपभोग करेगा जिसे उदासीनता वक्र IC_3 पर T_3 बिन्दु प्रकट कर रहा है। BT_3 रेखा ST_4 रेखा के समानान्तर है इसलिए यदि प्रशुल्क लगाया जाता है तो आयात महंगा हो जाएगा। फलतः A देश उपभोग कम करेगा और वह उदासीनता वक्र IC_3 पर पहुँच जाएगा जो व्यापार शर्त रेखा BT_3 को T_2 पर काटती है। इस प्रकार A देश का T_4 से T_3 बिन्दु पर गतिमान होना प्रशुल्क के उत्पादन प्रभाव के कारण हुआ है और T_3 से T_2 बिन्दु पर जाना उपभोग प्रभाव के कारण घटित हुआ है।

परन्तु यदि देश इतना बड़ा है कि वह आयात और निर्यात को घटाकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त रेखा को प्रभावित कर सकता है तो प्रशुल्क के कारण उसकी स्थिति खराब नहीं होगी। यदि गेहूँ के कम निर्यात के कारण विदेशी बाजार में गेहूँ की कीमत बढ़ जाती है तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त रेखा BT_6 हो जाएगी ऐसी स्थिति में प्रशुल्क लगाने के बाद देश T_5 बिन्दु पर उपभोग करेगा, जो कि स्पष्टतः प्रशुल्क लगाने के पूर्व के साम्य बिन्दु T_4 की प्रपेक्षा ऊँचे उदासीनता वक्र पर है।

प्रशुल्क के समर्थन में दिए गए तर्क (The Arguments in favour of Tariff)

प्रशुल्क की नीति के सम्बन्ध में दिए गए तर्क बहुत कुछ वे हैं जो सरक्षण की नीति के समर्थन में दिए जाते हैं तथा जिनका अध्ययन हम आगे के अध्याय में करेंगे। ये निम्नलिखित प्रकार से हैं :—

(1) इससे सस्ता विदेशी श्रम प्राप्त किया जा सकता है। विभिन्न देशों में श्रमिक की मजदूरी भिन्न-भिन्न होती है। जैसे कि अमेरिका में मजदूरी इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की प्रपेक्षा तीन गुनी, जापान से चार गुनी और भारत से दस गुनी तथा उससे भी अधिक होती है। अमेरिका में मजदूरी की दर इतनी अधिक होने के कारण यहाँ के उत्पादन उन उत्पादकों से प्रतियोगिता नहीं कर सकते जिनमें सस्ता श्रम लगाया गया है। ऐसी स्थिति में यदि प्रशुल्क की दीवारें खड़ी न की गयीं तो अमेरिका के उत्पादक गम्भीर स्थिति में हो जाएंगे। वहाँ मजदूरी की दर घट जाएगी और रहन-सहन का स्तर कम हो जाएगा। इस प्रकार प्रशुल्क (Tariff) की नीति सस्ते विदेशी श्रम के विरुद्ध अमेरिकी उत्पादकों की सहायता करती है।

यद्यपि यह तर्क अमूर्ण प्रतीत होता है किन्तु राजनैतिक दृष्टि से इसका पर्याप्त समर्थन किया जाता है। विचारकों का कहना है कि विदेशी व्यापार में तुलनात्मक लाभ केवल सापेक्षिक भूत्यों के अन्तर पर निर्भर करता है। यदि एक वस्तु के भूत्यों में दो देशों के बीच अन्तर है तो विशेषीकरण होना और द्विपक्षीय व्यवहार किया जाएगा। विदेशी व्यापार में यह बात कोई महत्व नहीं रखती कि एक वस्तु के उत्पादन में कितना महंगा या सस्ता श्रम लगा है वरन् महत्वपूर्ण बात तो यह होती है कि विदेशी उत्पादक अपनी वस्तुओं को कितनी अनुकूल शर्तों पर

देने को तैयार है। मजदूरी की दर कम होते हुए भी कठोर व्यापारिक शर्तों के कारण एक वस्तु की कीमत आयात करने वाले देश में ऊँची पड़ेगी।

मजदूरों को अधिक वेतन केवल इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनकी उत्पादन क्षमता अधिक होती है। यह उत्पादन क्षमता कार्यकर्ताओं की कुशलता, शक्ति एवं उद्योग पर निर्भर करती है। जब कुशल और उद्योगशील मजदूरों को पर्याप्त पूँजी प्राप्त होती है तो उनकी उत्पादनशीलता बढ़ जाती है और मजदूरी की दरें अधिक होते हुए भी प्रति इकाई की लागत कम रहती है। जहाँ मजदूरी की दर कम होती है वहाँ उत्पादन की क्षमता भी कम होती है। जिन वस्तुओं के उत्पादन में अधिक कुशल श्रम की आवश्यकता होती है उनको ये देश पैदा नहीं कर सकते।

(ii) प्रशुल्क नीति के समर्थन में एक दूसरा तर्क यह दिया जा सकता है कि इससे शिशु उद्योगों की रक्षा की जाएगी। इन विचारकों का कहना है कि जब एक नया उद्योग शुरू किया जाता है तो उसे कुशलता का विकास करने के लिए, नई तकनीकी सीखने के लिए और योग्यता को बढ़ाने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है ताकि वह प्रति इकाई लागत कम कर सके। दूसरे शब्दों में प्रारम्भ होने वाले उद्योगों को बच्चे, कार्यकुशल और स्थापित विदेशी फर्मों की प्रतियोगिता से बचाना चाहिए। जब तक इस प्रकार का संरक्षण नहीं दिया जाएगा तब तक एक नया उद्योग आगे नहीं बढ़ पाएगा और वह कार्यकुशल बनने से पूर्व ही समाप्त हो जाएगा।

संरक्षण की आवश्यकता केवल अस्थायी होती है। जब शिशु उद्योग परिपक्व हो जाते हैं वे विश्व-बाजार में प्रतियोगिता कर सकते हैं तब प्रशुल्क को समाप्त किया जा सकता है। यह कहा जाता है कि प्रशुल्क नीति के सम्बन्ध में दिया गया शिशु उद्योग का तर्क विश्लेषण की दृष्टि से पर्याप्त सही है। यह उन देशों पर बहुत लागू होता है जो औद्योगीकरण की प्रारम्भिक अवस्था में हैं और नवीन उद्योगों को विकसित करना चाहते हैं। ऐसे देशों को यह भय रहता है कि नए उद्योगों को विकसित करने के उनके प्रयास जब औद्योगिक दृष्टि से प्रगतिशील देशों के स्थापित उद्योगों के मूल्यों की प्रतियोगिता में आएं तो समाप्त हो जाएंगे। इस तर्क को विकसित देशों में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता किन्तु विकास की प्रारम्भिक अवस्था में इस पर पर्याप्त जोर दिया जाता था। अलेक्जेंडर हैमिल्टन (Alexander Hamilton) ने इस तर्क का समर्थन किया। उनका यह मत अर्द्धविकसित देशों पर पूरी तरह लागू होता है। इस तर्क से सम्बन्धित विभिन्न कठिनाइयों का वर्णन हम यथा-स्थान पीछे कर चुके हैं।

(iii) प्रशुल्क-नीति के सम्बन्ध में एक अन्य तर्क व्यवसाय की शर्तों को अनुकूल बनाने की दृष्टि से दिया जाता है। यह कहा जाता है कि स्वतन्त्र व्यापार के कारण विश्व का उत्पादन अधिक से अधिक हो जाता है किन्तु इस उत्पादन का

प्राधित देशों के बीच बराबर का बंटवारा निर्यातकर्त्ता एवं आयातकर्त्ता देशों के मध्य स्थित विनिमय अनुदान पर निर्भर करता है जिसे सामान्यतः ध्वसाय की शर्तें कहा जाता है। एक देश यदि अच्छी व्यापार शर्तें स्थापित करने की क्षमता रखता है तो उसका उत्पादन बढ़ जाएगा। इनक अर्थ-शास्त्रियों का विचार है कि प्रशुल्क द्वारा एक देश दूसरे देशों की कीमत पर लाभान्वित हो सकता है किन्तु यह लाभ अधिक व्यावहारिक महत्व नहीं रखता क्योंकि पहली बात यह है कि प्रशुल्क लगाने वाला देश केवल तभी लाभ में रहेगा जब विदेशों में पूर्ण लोचहीन होगी। इसके प्रतिरिक्त प्रशुल्क लगाने वाले देश का आकार भी महत्व रखता है। यदि वह देश विश्व बाजार में छोटा है तो उसकी व्यापार की शर्तों को सुधारने के अवसर कम होंगे। हमारे अच्छी व्यापार शर्तों से एक देश का जो लाभ प्राप्त होता है वह उस समय समाप्त हो जाएगा जबकि विदेशों में भी प्रतिस्पर्धा स्वरूप प्रशुल्क लगा दिया जाएगा। यह स्थिति ऐसे प्रशुल्कों के युद्ध छेड़ सकती है जिसमें विश्व का व्यापार एकदम घट जाता है तथा विशेषीकरण से होने वाली प्राप्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। साथ ही विश्व का उत्पादन कम हो जाता है। प्रशुल्क से किसी एक देश का लाभ होना कुछ अव्यावहारिक-सा प्रतीत होता है।

(iv) प्रशुल्क के समर्थन में एक तर्क यह दिया जाता है कि प्रशुल्क द्वारा विभिन्न अनाधिक लाभ प्राप्त किए जाने का प्रयास भी किया जाता है। इसके माध्यम से कुछ ऐसे उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है जो लाभ से सम्बन्ध नहीं रखते बल्कि अपने आप में लक्ष्य होते हैं। उदाहरण के लिए, एक विशेष उद्योग को राष्ट्र की सैनिक शक्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इस प्रकार का उद्योग यद्यपि अकार्यकुशल है और इसमें प्रति इकाई लागत पर्याप्त ऊँची है किन्तु फिर भी वह देश इन मौलिक चीजों के उत्पादन को बनाए रखने के लिए कुछ भी मूल्य चुकाने को तैयार होगा। कोई भी अर्थ-शास्त्री इन मौलिक उद्योगों के महत्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। प्रायः सभी अर्थ-शास्त्रियों ने इस प्रकार के उद्योगों को स्वतन्त्र व्यापार का अपवाद माना है। स्वयं एडम स्मिथ (Adam Smith) भी सुरक्षा को पर्याप्त महत्व देते थे। इस सम्बन्ध में एक कठिनाई यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से कौनसा उद्योग आवश्यक है, इसे तय करना अत्यन्त कठिन होता है। नीति निर्माताओं को विभिन्न उद्योगों की इस आधार पर की गई सुरक्षा की मांगों पर ठण्डे दिमाग से ध्यान देना चाहिए क्योंकि प्रत्येक उद्योग का स्वामी इस प्रकार के दावे करता है।

प्रशुल्क नीतियों के समर्थन में कुछ अन्य तर्क भी दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए यह कहा जाता है कि एक विभिन्नतापूर्ण अर्थ व्यवस्था के लिए सुरक्षा प्रदान करने के हेतु प्रशुल्क लगाए जाएँ। इसके लिए यह भी कहा जाता है कि प्रशुल्क के द्वारा घरेलू व्यवहार की स्थिति को सुधारा जाएगा और देश को बेरोजगारी की समस्या में राहत प्रदान की जाएगी। यह सच है कि निम्न उद्योगों का आयात प्रतिस्पर्धा करनी होती है उनमें उच्च प्रशुल्क लगाने से रोजगार की स्थिति बढ़ेगी

किन्तु यह प्राप्ति उस समय समाप्त होगी जब निर्यात भी गिर जाएँगे क्योंकि विदेशियों द्वारा या तो प्रतिनिधियों के रूप में प्रशुल्क लगाया जा सकता है अथवा क्रय शक्ति के घटने के कारण ऐसा कदम उठाया जा सकता है। परिणामस्वरूप विश्व व्यापार की मात्रा कम हो जाएगी और विभागीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के लाभ मिलने से रुक जाएँगे।

इस सम्बन्ध में एक अन्य तर्क यह दिया जाता है कि प्रशुल्क लगाकर घर और विदेश में उत्पादन लागत को समान बनाया जाता है ताकि घरेलू और विदेशी उत्पादक बराबर के आधारों पर प्रतियोगिता कर सकें। इस प्रकार के प्रशुल्क देश और विदेशों में सापेक्षिक मूल्यों को समान करके एक प्रकार से विदेश व्यापार के आधार को ही समाप्त कर देते हैं। प्रशुल्क के सम्बन्ध में जो विभिन्न तर्क दिए जाते हैं वे मुख्य रूप से राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यद्यपि क्षेत्रीय सघर्ष हो जाते हैं फिर भी सामान्य रूप से यह स्वीकार किया जाता है कि राष्ट्र के अन्तर्गत स्वतन्त्र व्यापार होना चाहिए। यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना महत्त्व नहीं रखता।

प्रशुल्क के उपयोग एवं दुरुपयोग (Use and Misuse of Tariffs)

सामान्य रूप से अर्थशास्त्रियों द्वारा यह विश्वास किया जाता था कि स्वतन्त्र व्यापार विश्व के उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ा देता है। इसमें भाग लेने वाला प्रत्येक देश लाभान्वित होता है। आज के अर्थशास्त्रियों का विश्वास है कि स्वतन्त्र व्यापार को इतनी प्रशंसा के साथ नहीं देता जा सकता और इसलिए सरक्षणवादी नीतियों के सम्बन्ध में उनके द्वारा विभिन्न तर्क प्रस्तुत किए गए। स्वतन्त्र व्यापार सम्पूर्ण संसार की दृष्टि से श्रेष्ठ हो सकता है किन्तु यह एक देश की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नहीं है। प्रशुल्क एवं अन्य व्यापारिक प्रतिरोधों का व्यापार की प्राप्तियों को एक देश के पक्ष में पुनः वितरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा घरेलू रोजगार को अच्छा बनाया जाता है तथा आर्थिक विकास की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

प्रशुल्क नीति का प्रयोग करते हुए एक देश अपने भाषकों विश्व बाजार में टिकाए रखता है, वह अपने उत्पादन को विदेशी प्रतियोगियों से संरक्षण प्रदान करता है और इस प्रकार अपनी अर्थ-व्यवस्था को सन्तुलित करने का प्रयास करता है। प्रशुल्क (Tariff) नीति का दुरुपयोग करते हुए कई बार विभिन्न देशों के बीच युद्ध की सी स्थिति बना दी जाती है। इसके अतिरिक्त प्रशुल्क की नीति द्वारा दूसरे देश के व्यापार एवं अर्थ-व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने का प्रयास भी किया जाता है। यदि एक देश किसी मूल आवश्यकता की वस्तु का उत्पादन कर रहा है तो वह अपने उत्पादन के निर्यात में अन्य देश को हर प्रकार से दबा सकता है तथा निर्यात कर लगाकर आयातकर्ता देश के उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य के भार से दबा सकता है।

राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रशुल्क की नीति का दुस्प्रयोग करते हुए कुछ विशेष उद्योग अपने दूसरे प्रतियोगियों को दबाने का प्रयास कर सकते हैं।

प्रशुल्क नीति का समर्थन करने के लिए दिया गया प्रत्येक तर्क अधिक प्रायः करो को न्यायोचित सिद्ध करता है। इनमें से कुछ तर्क तो उन लोगों द्वारा भी दिए जाते हैं जो स्वतन्त्र व्यापार के पक्षपाती हैं।

श्रेष्ठतम कर (Preferential Duties)

श्रेष्ठतम करो द्वारा प्रशुल्क दीवार में प्रवेश के लिए स्थान बनाया जाता है। इसके फलस्वरूप प्रशुल्क के स्तर में कमी आती है जिसे अन्य किसी साधन द्वारा नहीं लाया जा सकता था। श्रेष्ठतम करो का औचित्य स्वतन्त्र व्यापार सिद्धान्त के आधार पर ठहराया जाता है। श्रेष्ठतम कर का कम लगाया जाना तथा प्रशुल्क में सामान्य रूप से कमी कर देना बहुत कुछ एक जैसी ही बातें हैं। दोनों के बीच केवल मात्रा का अन्तर है। श्रेष्ठतम कर को उस समय उचित नहीं माना जाता जब इसे अन्य देशों के विरुद्ध कर बढ़ाने के बढ़ाने के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। असल में इसका प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की भडकनों को कम करने के लिए किया जाना चाहिए। इस प्रकार करो को स्वतन्त्र व्यापार का समर्थन करने वाले तर्कों के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है।

इन करो की कई प्रकार से आलोचना की गई—(1) यह कहा गया कि प्रत्येक परिस्थिति में प्राथमिक कटौती कोई भी कटौती न होने की अपेक्षा अच्छी होनी हो, यह बात नहीं है। जब दो देशों के बीच भेदभाव लाने या हटाने की सम्भावनाएँ बढ जाती हैं तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अनिश्चितता और जोखिम पैदा हो जाती है। (2) यह कहा जाता है कि चाहे कर अधिक लपा दिए जाएँ किन्तु वे समान होने चाहिए। जब इस सम्बन्ध में गैरपूर्ण नीति अपनाई जाती है तो इससे भ्रम पैदा होता है। यह आलोचना राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से नहीं किन्तु अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से अत्यन्त महत्व रखती है।

एक तर्क प्रो. टॉसिंग द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उनका कहना है कि जब 'क' देश द्वारा 'ख' देश के करो में प्राथमिक कमियाँ की जाती हैं और यदि 'ख' देश इस स्थिति में नहीं होता कि 'क' की समस्त आवश्यकताओं को पूरा कर सके तो ऐसी स्थिति में करो की कटौती 'ख' के उत्पादकों के लिए 'क' के खजाने से दी जाने वाली एक सहायता मान्य कही जाएगी क्योंकि 'क' के आयातों की कमी 'ख' से पूरी नहीं हो सकती और इसलिए उसे विश्व बाजार की सहायता लेनी होगी। इस प्रकार 'क' देश में स्वदेश वस्तुओं के मूल्य परिवर्तित नहीं होंगे और 'ख' देश को प्राथमिक तर्क की सुविधा देने के बाद भी इसके उपभोक्ताओं से भार कम नहीं होगा।

जिन प्राथमिक करो द्वारा गृह मूल्य को ज्यों का त्यों रहने दिया जाता है वे इन्हें स्वीकार करने वाले देश के व्यापार की मात्रा को नहीं बढ़ाते हैं और न ही

इससे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन में वृद्धि होती है। इससे एक देश का आयात नहीं बढ़ता, यही कारण है कि इनको व्यापारिक नीति के रूप में बेकार माना जाता है। प्रशुल्कों (Tariffs) में की जाने वाली कमी के अनुरूप इन्हें नहीं कहा जा सकता। "अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र से इन्हें केवल इसलिए लोकप्रियता प्राप्त हुई क्योंकि ये व्यापार नीति के उदार विचारों के प्रति झुंठी रियायतें दे सकते हैं।"

जिस देश के पक्ष में इस प्रकार के कर लगाए जाते हैं उस देश के अधिक निर्यात कर सकने की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन अधिक तीव्र हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि यदि दो देश एक दूसरे को प्रशुल्क प्राथमिकताएँ प्रदान करें तो दोनों को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का लाभ प्राप्त होगा। ऐसा होने के लिए प्राथमिक करों की द्विपक्षीय स्वीकृति आवश्यक है, इसके अभाव में इसका कोई प्रभाव नहीं होता। इन करों की एक-तरफा स्वीकृति मूल्य में किसी प्रकार की कमी नहीं करती।



नियतांश के प्रभाव

(EFFECTS OF QUOTAS)

नियतांश प्रणाली भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की एक विशेषता है। इसके सम्बन्ध में ए स्नाइडर (Delbert A Snider) लिखते हैं कि “नियतांश उस माल की मात्रा पर सीमाएँ है जिसका एक निश्चित काल में आयात या निर्यात किया जा सकता है।” जब वस्तुओं के आयात के लिए एक निश्चित मात्रा निर्धारित कर दी जाती है तो उसे आयात नियतांश (Quota) कहते हैं। दूसरी ओर जब निर्यात की मात्रा को निर्धारित कर दिया जाता है तो वह निर्यात नियतांश कहलाता है। इसके अनिश्चित कुछ खुली नियतांश (Customs Quotas) भी होते हैं। जब वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा पर कम प्रशुल्क लगाया जाता है और उस मात्रा से अधिक वस्तु पर सामान्य कर लगाया जाता है तो इसे खुली नियतांश व्यवस्था के संरक्षण की प्रणाली का ही एक रूप कहा जा सकता है।

नियतांश द्वारा एक वस्तु के मूल्य और मात्रा पर सीमा लगाई जाती है। इस वस्तु का एक विशेष समय में निर्यात अथवा आयात किया जाता है।

नियतांश व्यवस्था के उद्देश्य (Objectives of the Quota System)

नियतांश व्यवस्था को कई उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनाया जाता है। इसका मूल उद्देश्य आयात और निर्यात को तुरन्त और प्रभावशाली रूप से विनियमित करना होता है। ऐसा करने की आवश्यकता अनेक कारणों से पैदा होती है—

(1) नियतांश व्यवस्था का प्रयोग आयात को प्रतिबन्धित करने के लिए किया जा सकता है ताकि भुगतान के सन्तुलन में स्थित असन्तुलन को सुधारा जा सके।

(2) इस व्यवस्था द्वारा विदेशी प्रतिद्वन्द्वितापूर्ण उत्पादन के आयात को प्रतिबन्धित करने धरेलू उद्योगों की रक्षा का उपाय किया जाता है। नियतांश द्वारा आन्तरिक मूल्य स्तर बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। आर्थिक मंदी के समय जब मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव होता है तब कुछ देश अपने आन्तरिक मूल्यों

की यथावत बनाए रखने के लिए आयातों पर नियतांश की सहायता से प्रतिबन्ध लगाते हैं।

(3) नियतांश का प्रयोग व्यावसायिक सौदेबाजी के लिए भी किया जा सकता है। एक देश दूसरे देश में निर्यात करने के लिए निर्यात प्राप्त करने के बदले उस देश को आयात के लिए नियतांश सौंप सकता है। इसके अतिरिक्त नियतांश का प्रयोग उन देशों के प्रतिकार के रूप में भी किया जा सकता है जिन्होंने आयात नियतांश लागू किया है।

(4) नियतांश द्वारा विभिन्न देशों के बीच लेन-देन के व्यवहार तथा अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात समझौतों को क्रियान्वित किया जाता है। इन समझौतों के अधीन प्रत्येक देश नियतांश की एक निश्चित मात्रा का ही निर्यात कर सकता है।

(5) जब एक देश में होने वाले आयात की बहुतायत को रोकना हो तो प्रशुल्क व्यवस्थापन की आवश्यकता होगी किन्तु इसमें समय लगता है। इस संक्रमण काल में आयात को प्रतिबन्धित करने का कार्य नियतांश द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के नियतांश अस्थायी होते हैं और प्रशुल्क व्यवस्थापन के होते ही वे समाप्त कर दिए जाते हैं।

(6) निर्यात नियतांश (Export Quotas) का उद्देश्य यह है कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को खरीदारों के बीच बराबर की मात्रा में वितरित किया जाए। 1930 के दौरान व्यावसायिक सन्धियों के दायित्वों का निर्वाह करने की दृष्टि से नियतांश प्रणाली को अपनाया गया था। समझौता करने वाले पक्षों ने यह माना कि प्रशुल्क को एक विशेष स्तर से ऊँचा उठाया जाए। इन शर्तों का पालन करने में आर्थिक मन्दी के दौरान देशों को कठिनाइयों का अनुभव होते लगा। इस कठिनाई का समाधान उन्होंने नियतांश प्रणाली को अपनाकर किया क्योंकि किए गए समझौतों में मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्धों का उल्लेख नहीं किया गया था। नियतांश प्रायः सकटकालीन स्थिति का मुकाबला करने के लिए होता है। यह प्रभावशील सभी हो सकता है जब उसे तुरन्त लागू किया जाए। नियतांशों को प्रायः कार्यपालिका द्वारा प्रशासित किया जाता है। कार्यपालिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे इसके लिए कभी-कभी विधायी प्रतिबन्ध भी लगा दिए जाते हैं।

नियतांश का नियतिकरण (Fixation of Quotas)

नियतांशों को मात्रा या मूल्य अथवा दोनों के योग के बराबर नियत किया जा सकता है। एक नियतांश किस इकाई में नियत किया जाएगा। यह बात सम्बन्धित वस्तु की प्रकृति और नियतांश व्यवस्था के उद्देश्य पर निर्भर करती है। यदि कोटा व्यवस्था का उद्देश्य मुगतानों के सन्तुलनों में घाटे की स्थिति को दूर करना है तो आयातों पर मूल्य की दृष्टि से सीमा लगाना अधिक उपयुक्त रहेगा। यदि आयातों

को मात्रा की दृष्टि से सीमित किया गया है तो इससे विदेशी विनिमय की आवश्यकता का सही अनुमान लगाया जा सकता है किन्तु इससे घाटे की व्यवस्था को नहीं सुचारु जा सकता, क्योंकि मात्रा पर लगाए गए प्रतिबन्ध का प्रभाव आयातों की आयातीन मूल्य वृद्धि द्वारा महत्वहीन बना दिया जाएगा। यह भी हो सकता है कि इस प्रतिबन्ध द्वारा आयात की कीमतों का गिरा कर जो चाहिए उससे भी अधिक कर लिया जाए। यदि नियन्तांश का उद्देश्य आयातों को देश की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रतिबन्धित करना है तो यह उपयुक्त रहेगा कि नियन्तांश को मात्रा के रूप में निरूपित किया जाए। मात्रा के रूप में निश्चित नियन्तांश से घरेलू उत्पादकों को यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाएगा कि विदेशी पूति की मात्रा क्या है? और उसी के अनुसार वे घरेलू उत्पादन को समायोजित कर लेंगे। मात्रा के स्थान पर यदि आयातों पर भूख की सीमाएँ लगायी जाएँ तो इससे आयातकर्त्ता देशों को प्रेरणा मिलेगी।

कभी कभी नियन्तांशों द्वारा केवल उन मात्राओं को सीमित किया जाता है जिसका आयात वित्त कर अथवा न्यूनतम कर पर किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई उच्च कर का भुगतान कर सके तो वह असिमित मात्रा में प्रतिरिक्त आयात कर सकता है। इस प्रकार के प्रबन्धों को प्रशुल्क नियन्तांश कहा जाता है। ये पूर्ण नियन्तांशों से भिन्न होने हैं क्योंकि पूर्ण नियन्तांशों में एक विशेष मात्रा से अधिक की अनुमति किसी शर्त पर नहीं दी जाती। वास्तविक व्यवहार में प्रशुल्क नियन्तांश में प्रथम प्रतिरिक्त आयात केवल तभी हो सकेगा जबकि प्रशुल्क की उच्च दर उस अन्तर से कम होगी जो निर्यातकर्त्ता और आयातकर्त्ता देशों के बीच उस वस्तु की कीमतों में है। जिस प्रकार प्रतिरिक्त आयात प्रशुल्क नियन्तांश के अन्तर्गत आते हैं, उसी प्रकार आयातकर्त्ता देश में वस्तु की माँग की कीमत गिरती है और निर्यातकर्त्ता देश में पूति की कीमत बढ़ जाती है। अन्त में एक स्थिति ऐसी आती है जब आयातकर्त्ता देश में माँग की कीमत और निर्यातकर्त्ता देश में पूति की कीमत सर्वोच्च करके बराबर हो जाती है। ऐसा होने पर आगे का आयात रुक जाएगा। प्रशुल्क नियन्तांश उन गरीबों को अलग हटा देते हैं जो कि कर की उच्च दर प्रदान कर सके। केवल धनिक लोग ही उस प्रतिरिक्त आयात का लाभ उठा पाते हैं जिसके लिए कर की ऊँची से ऊँची दर देनी पड़ती है। राज्य द्वारा प्रायः उस नियन्तांश (Quota) की मात्रा कम से कम रखी जाती है जिसे कर की कम दर के साथ खरीदा जा सके। ऐसा करने से उसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है। इस व्यवस्था में खतरा यह है कि देश के बहुमूल्य विदेशी विनिमय का उन भाराम्भायक वस्तुओं पर अव्यय किया जाएगा जिनका भार केवल धनवान लोग ही उठा सकते हैं। इस प्रकार उस मास या सेवाओं के लिए यह विदेशी विनिमय प्रयुक्त नहीं किया जाएगा जो विकास कार्यों की क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक होते हैं। प्रशुल्क नियन्तांश (Tariff Quota) बाजार की शक्तियों को कुछ सीमा तक स्वतन्त्र रूप से कार्य करने का अवसर देते हैं और इस प्रकार अर्थव्यवस्था को एक सीमित मात्रा में लोचशीलता प्रदान करते हैं। जिस दर पर प्रतिरिक्त आयातों की अनुमति दी

व्यापार शर्तें उसके विपरीत हो जाती हैं। नियन्त्रण की मात्रा पूरी न होने तक प्रायानकर्त्ता प्रायात करने की जल्दी में रहते हैं और इस प्रकार वे पूर्ति का मन्त्र से मन्त्रा खोत नहीं खोज पाते। इसके अनिश्चित मौमार्मिक नियन्त्रण उन देशों के साथ भेदभाव करने हैं जो दूर स्थित हैं। प्रायानकर्त्ता देश के निर्यातकों को देश का मान प्रतिब जल्दी पहुँच सकता है। कभी-कभी प्रायानकर्त्ताओं का पराप्त हानि उठाकर भी अपने समझौते रह करने होते हैं क्योंकि समझौता करने के बाद ज्ञान होता है कि पूरा नियन्त्रण बंद चुका है तथा सीमाएं अनिश्चित प्रायान के लिए बन्द हो चुकी हैं। इस प्रकार का नियन्त्रण कीमतों के उन्नेत्रनीय उतार चढ़ाव का कारण बनता है। जब नियन्त्रण की घोषणा की जाती है तो आदानों की ग्राह्यता होती है और कीमता बढ्न गिर जाती हैं, सिन्तु उन्ने ही नियन्त्रण पूरा होता है, त्या ही मान रखन बात, कीमतों को बढा देने हैं। इससे उस वस्तु के घरेलू उत्पादकों पर विपरीत प्रभाव पडता है जा मौमार्मिक नियन्त्रण के अनुसार प्रायानिन की जाती है। इन वस्तुओं की कीमते घटने पर घरेलू उत्पादकों का अपना उत्पादन बन्द करना पडता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि नियन्त्रण का यह रूप घरेलू उत्पादनों की सुरक्षा के लिए कोई प्रबद्धा साधन नहीं है क्योंकि कोई भी मरक्षण तभी मरन हो पाता है जबकि वह नियमित हो।

2 नीलामी

(The Auction)

नियन्त्रण आकटित करने का एक दूसरा तरीका नीलामी (Auction) है। इस दृष्टि से नियन्त्रण निर्धारित करने मरय अनुज्ञप्तियों (Licences) का खुली नीलामी में उच्चतर गौरी लगाने वालों को देना जाना है। यह नीलामी मभी के लिए समान शर्तों पर खुली रहती है। इस अवस्था में न कोई घुँमवारी पक्षपात, भ्रष्टाचार और न ही व्यापार के अनैतिक होने के अवसर रहते हैं। इस प्रकार यह व्यवस्था अनुज्ञप्ति को दूर करेगी। इस व्यवस्था से जिनको अनुज्ञप्तियाँ प्राप्त होगी, वे सर्वाधिक कुशल म्पत्ति होंगे क्योंकि उन्होंने अपने कम कुशल प्रतियोगियों को पीछे छोड़ दिया है। इस व्यवस्था के अधीन घरेलू और विदेशी कीमत के बीच जो सीमान्त रहेगा वह कुछ व्यापारियों को घनवाने बनाने की अपेक्षा पूरे राज्य को लाभदायक होगा। इस व्यवस्था पर यह दोष भी नहीं लगाया जा सकता कि विभिन्न प्रायानकर्त्ताओं के साथ कोई भेदभाव किया गया है।

नीलाम प्रणाली के सभ्य संचालन के लिए व्यापारियों के बीच पर्याप्त प्रतियोगिता का होना आवश्यक है। अधिकांश अर्द्ध-विकसित देशों में प्रायानकर्त्ताओं की मख्या घोडी सी होती है। वे आपस में मिलकर नीलामी को अमरन कर सकते हैं। इस प्रकार उपभोक्ताओं और राज्य की कीमत पर वे मरय लाभ कमा सकते हैं। उससे कीमत का स्तर स्थिर नहीं हो मकेगा। जब एक बार अनुज्ञप्ति का नीलाम कर दिया जाएगा तो इसके बाद निर्यातकर्त्ता कुछ भी कीमत वसूल करने के लिए स्वतन्त्र होगा क्योंकि उसके बाद होने वाले परिवर्तनों से या तो वे पूरी तरह

लाभ उठाएंगे अथवा उनसे नुकसान उठाएंगे। इस प्रकार से नीलाभी आयातकर्ताओं के दुर्भाग्य और सोभाग्य पर अधिक आश्रित होगी। अपेक्षाकृत किसी नियम अथवा व्यवस्था के यह एक प्रकार से आयातकर्ताओं के सामने जोखिम का द्वार खोलता है। इस प्रकार का जोखिम उस व्यवस्था में नहीं रहता जहाँ घरेलू मूल्य नियन्त्रण और राशनिंग आदि की व्यवस्था होती है। यहाँ बिजो की कीमत आयात की कीमत के साथ आयातकर्ता के लिए कुछ बुद्धिपूर्ण सीमान्त जोड़कर तय कर दी जाती है। यह नीलाम का तरीका उन वस्तुओं के आयात पर लागू नहीं हो सकता जिनकी कीमतें कम रखना उपभोक्ताओं या उत्पादकों की दृष्टि से वांछनीय है। उदाहरण के लिए—खाद्य सामग्री, दवाइयाँ, मशीनें या आवश्यक कच्चा माल आदि। इस तरीके की मुख्य रूप से भारामदायक चीजों के आयात पर ही लागू किया जा सकता है। इसे एक विकासशील व्यवस्था सहन नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ विकास कार्यक्रमों को घसाने के लिए आवश्यक वस्तु खरीदने के हेतु भी विदेशी विनिमय की कमी रहती है।

निर्यातकर्ता देशों के बीच भी नियतांश का आवंटन किया जाता है। सांसारिक नियतांश में अनेक हानियाँ रहती हैं। इसलिए नियतांश सम्बन्धी विनिमयों को लागू करने वाला देश आयात की जाने वाली सम्पूर्ण मात्रा को विभिन्न निर्यातकर्ता देशों के बीच निर्धारित कर देता है। यह कहा जाता है कि ऐसा करते समय यदि भेदभाव करने से बचना है तो सम्पूर्ण नियतांश को सभी निर्यात करने वाले देशों के बीच बराबर-बराबर बाँट दिया जाए। यह प्रणाली दिखने में तो समानतापूर्ण प्रतीत होती है किन्तु इससे बड़े देशों के विरुद्ध छोटे निर्यातकर्ता देशों के बीच भेदभाव रहेगा। यह भी हो सकता है कि छोटे निर्यातकर्ता देश अपने लिए सौंपे गए पूरे नियतांश का निर्यात न कर पाएँ और इस प्रकार नियतांश का कुछ भाग बेकार ही रह जाए। ऐसा होने पर आयात की मात्रा निश्चय ही उस मात्रा से कम होगी जो कि आयातकर्ता देश द्वारा वांछित समझी गई है।

3. अनुज्ञप्तिपत्राँ (Licences)

नियतांशों को निर्धारित करने में भेदभाव को हटाने के लिए एक अन्य तरीका यह अपनाया जाता है कि आयातकर्ताओं को अनुज्ञप्तिपत्राँ दे दी जाएँ और जहाँ से उनको फायदा हो, वही से आयात करने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दिए जाएँ। इस व्यवस्था में भी एक खतरा है कि सरकार आयातकर्ताओं पर किन्हीं विशेष देशों से आयात करने के लिए द्रिपे रूप से दबाव डाल सकती है। आयातकर्ताओं को अनुज्ञप्तिपत्राँ प्रदान करते समय यह विचार ध्यान में रखा जा सकता है कि वे विशेष देशों से आयात करेंगे। यदि यह आशा पूरी नहीं होती है तो अविष्य में आयातकर्ताओं को अनुज्ञप्तिपत्राँ प्रदान करने से मना किया जा सकता है।

भेदभाव को दूर करने का एक अन्य तरीका भी है कि नियतांश निर्धारित करते समय देखा जाए कि पहले किसी विशेष समय में देश के सम्पूर्ण आयात का

कितना भाग किस देश से प्राप्त होता था ? इस विशेष समय का सूत्र नियन्त्रण के निर्धारण में जानबूझ कर किए जाने वाले भेदभाव पर रोक लगा देगा किन्तु किसी विशेष समय का चयन करते समय भेदभाव किया जा सकता है। इस समय को निर्धारित करने का कोई वस्तुगत अथवा निश्चित मापदण्ड नहीं हो सकता। किसी देश से कम से कम आयात का निषेध करने के लिए उसका इतिहास देखना होगा। यह एक उलझा हुआ तरीका है जिसमें सांख्यिकी तरीके से पर्याप्त सहायता लेना आवश्यक है। यह सांख्यिकी सही है अथवा गलत, इसके सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय विवाद भी छिड़ सकता है। इस प्रकार इस प्रनिया में जानबूझ कर भेदभाव करने के अवसर भी रहते हैं।

एक विशेष समय के सूत्र के आधार पर नियन्त्रण का निर्धारण करना कुछ देशों के लिए अन्यायपूर्ण रहगा। इसके अतिरिक्त निर्यातकर्त्ता देशों में यदि उत्पादन में अचानक ही परिवर्तन हो जाएँ तो इससे नियन्त्रण व्यवस्था का सरल कार्य संचालन कठिन बन जायेगा। यह विशेष रूप से कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के बारे में अधिक सही है जिनका उत्पादन प्रकृति की दया पर निर्भर करता है। जिस देश को अधिक नियन्त्रण सौंपा गया है उसमें यदि फसल बिगड़ जाती है तो वह पूरी निर्धारित मात्रा की पूर्ति नहीं कर सकता। दूसरी ओर जिसको कम नियन्त्रण सौंपा गया है उस देश की फसल अच्छी हो जाती है तो वह अपने लिए निर्धारित नियन्त्रण से अधिक मात्रा की पूर्ति कर सकेगा। इसके अतिरिक्त आयातकर्त्ता देश के उपभोक्ताओं की रुचियों और फैशनो में परिवर्तन होने के कारण माँग की यह वस्तुओं की किस्मों तथा गुणों में भी परिवर्तन हो सकता है। हो सकता है कि एक समय जित वस्तुओं की बहुत माँग थी, थोड़े समय पश्चात् उन वस्तुओं की कोई माँग न रहे और जिनकी पहले कोई माँग ही नहीं थी उनकी अधिक बढ़ जाएँ। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इस आधार पर जिस देश को नियन्त्रण सौंपा गया है उसमें सम्बन्धित वस्तु की कीमतें इतनी बढ़ जाएँ कि आयातकर्त्ता देश के लिए लाभदायक न रहे। फलतः आयातकर्त्ता देश इस स्रोत से आयात नहीं करेगा और इस प्रकार नियन्त्रण का वह भाग अछूना रहता रहेगा।

जब एक देश के निर्यातकर्त्ताओं को यह ज्ञात हो जाएगा कि वे निर्धारित नियन्त्रण से ज्यादा निर्यात नहीं कर सकते तो वे आपस में मिलकर स्वीकृत सीमित निर्यात की अधिक से अधिक कीमत वसूल करने का प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार आयातकर्त्ता देश का शोषण होगा और व्यापार शर्तें उसके विरुद्ध चली जाएँगी। यह शोषण उस समय नहीं हो सकता जब आयातकर्त्ताओं को किसी भी स्रोत से आयात करने की स्वतन्त्रता दे दी जाती है अर्थात् निर्यातकर्त्ता देशों के बीच नियन्त्रण निर्धारित नहीं किया जाता। नियन्त्रण सम्बन्धी विनियमों को सामान्य रूप से अनुज्ञप्ति व्यवस्था द्वारा प्रशासित किया जाता है। नियन्त्रण द्वारा निश्चित की गई सीमाओं में माल का आयात करने से पूर्व आयातकर्त्ताओं को एक अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होती है। कुछ देशों में स्वीकृत नियन्त्रण और विभिन्न आयातकर्त्ताओं के बीच किए गए इसके निर्धारण को पहले से ही प्रकाशित कर दिया जाता है।

कुछ देश आयात किए जाने वाले माल की मात्रा को घोषित नहीं करते और अनुज्ञप्तियों को किसी लोचनीय योजना के अनुसार आयातकर्ताओं को देते हैं। इन्हें देते समय जो मापदण्ड अपनाया जाता है उसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं की जाती। अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक प्रार्थना-पत्र को उसके स्वयं के लाभ के आधार पर मापा जाता है। सम्बन्धित अधिकारियों को स्वेच्छा की व्यापक शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। नियतांशों के प्रशासन को अनुज्ञप्तियों के माध्यम से चलाने पर अधिकारियों का कार्य सरल बन जाता है और इससे नियतांशों में कुशलता बढ़ती है। व्यक्तिगत आयातकर्ता के प्रश्नों को प्रमाणित करना किसी वस्तु के सभी स्रोतों से होने वाले कुछ आयातों की कुल दर को नियन्त्रित करने में अधिक सरल है। अनुज्ञप्ति व्यवस्था आयात को नियतांश के पूरे काल तक बनाए रखती है और इस प्रकार सांसारिक नियतांशों की भाँति इसमें कीमतों का उतार-चढ़ाव नहीं होता।

अनुज्ञप्तियों को सामान्य रूप से मान्य आयातकर्ताओं के बीच इस आधार पर विपरीत किया जाता है कि एक विशेष समय में उनके आयात का भाग कितना था। समय गुजरने के साथ-साथ विभिन्न फर्मों का भाग्य बदलता रहता है। कुछ फर्म अपने व्यापार को बढ़ा लेती हैं जबकि दूसरी फर्म उसे घटा लेती हैं। कुछ नई फर्म जन्म लेती हैं। जब एक समय विशेष को आधार बनाकर अनुज्ञप्तियों को वितरित किया जाता है तो इससे प्रसार करने वाली और स्थापित फर्मों के विरुद्ध भेदभाव होता है तो इसके द्वारा आयात व्यापार में नया खून, जो इसकी कुशलता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, नहीं आ पाता; इसमें कुछ निहित स्वार्थ पैदा हो जाते हैं। प्रतिस्पर्धा को समाप्त करके यह एकाधिकार को महत्व देता है जिसमें अपनी अनेक बुराईयाँ होती हैं।

अनुज्ञप्तियों को अधिक न्यायपूर्ण रूप से निर्धारित करने के लिए विशेष समय के सूत्र के साथ-साथ होने वाले परिवर्तनों को भी ध्यान में रखा जाता है। विकसित फर्मों को कुछ अधिक और पतनोन्मुख फर्मों को कुछ कम नियतांश सौंपा जाता है। नियतांश का एक भाग नवानुसुक्तों के लिए सुरक्षित रख लिया जाता है।

कभी-कभी आयातकर्ता देश अनुज्ञप्तियों के वितरण का काम निर्यातकर्ता देशों की सरकारों, उत्पादकों या निर्यातकर्ताओं को सौंप देता है। यह प्रक्रिया कई दृष्टियों से उपयुक्त समझी जाती है। आयातकर्ताओं के बीच नियतांश का निर्धारण करना एक अच्छा खासा सर दर्द होता है। इस कार्य में भेदभाव, पक्षपात और भाई-भतीजेवाद आदि के दोष लगने की सम्भावनाएँ रहती हैं। ये दोष न केवल देश के अन्तर्गत ही लगते हैं वरन् विदेशों के द्वारा भी लगाए जाते हैं। जब नियतांश का प्रशासन निर्यातकर्ता देश को दे दिया जाता है तो देश को कई आर्थिक व प्रशासनिक लाभ प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आयात-व्यापार की अपेक्षा निर्यात-व्यापार अधिक केन्द्रीयकृत है तो निर्यातकर्ता देश द्वारा नियतांश विनियमों का प्रशासन अधिक कुशल और मितव्ययतापूर्ण रहेगा। नियतांश विनियमों के प्रशासन में निर्यातकर्ता देशों का योगदान इन देशों के लाभ में रहता है। वे अपने दृष्टिकोण

को व्यक्त करने का अवसर पाते हैं और अधिक अनुकूल शर्तों के लिए बातचीत कर सकते हैं। इन विभिन्न कारणों से निर्यातकर्ता देश आयातकर्ता देशों में नियतांशों के प्रशासन का साथ देने के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। यह व्यवस्था आयातकर्ता देश के हित में काम होती है। अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आयातकर्ता देश कुछ परिस्थितियों में निर्यातकर्ता देश का अनुज्ञप्तिपत्रों का अधिकार सौंप देता है। इसमें पहली बात तो यह है कि कुल आयात मान्य नियतांश से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरे, निर्यात को आयातकर्ता देश की आवश्यकताओं के अनुसार पूरे नियतांश बाल में वितरित हुआ जाना चाहिए। तीसरे, निर्यातकर्ता देश वस्तुओं की कीमतों को नहीं बढ़ा सके।

आयात-नियतांशों के रूप (The Types of Import Quotas)

आयात-नियतांशों को पांच विभिन्न रूपों में विभाजित किया जा सकता है। यह है—प्रशुल्क नियतांश, एक पक्षीय नियतांश, द्विपक्षीय नियतांश, संयुक्त नियतांश और आयात अनुज्ञप्तिपत्र। इनमें से प्रथम चार रूप आयातों के भौतिक आकार का सीमित रखने का उद्देश्य रखते हैं जबकि आयात अनुज्ञप्तिपत्र प्रायः विनिमय नियन्त्रण के प्रशासन के साथ प्रयुक्त की जाती है। आयात नियतांशों के इन सभी रूपों का अध्ययन करना उपयुक्त रहेगा।

1 प्रशुल्क नियतांश (The Tariff Quota) — प्रशुल्क नियतांश के अधीन एक निश्चित मात्रा तक किसी वस्तु का आयात कम दर के कर के साथ स्वीकार किया जाता है किन्तु यदि इस निश्चित मात्रा से अधिक आयात किया गया तो इसके लिए अधिक दर से कर प्रदान करना होगा। इस प्रकार प्रशुल्क नियतांश में प्रशुल्क की विशेषताएँ भी शामिल होती हैं।

प्रशुल्क नियतांशों का लाभ यह है कि वे प्रायः लोचनीय होते हैं। किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा की विशेषता अनुकूल शर्तों पर आयात करने की आज्ञा होती है किन्तु प्रतिरिक्त आयात को अस्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि उसकी कम अनुकूल शर्तों पर स्वीकार किया जाता है। इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण दोष यह बनाया जाता है कि प्रारम्भ में जो दरें निर्धारित की गई हैं उनके अनुसार अधिक से अधिक लोग शीघ्र आयात करने का प्रयास करेंगे और ऐसी स्थिति में मूल्यों की लोचनीयता अधिक बढ़ जाएगी।

2 एकपक्षीय नियतांश (The Unilateral Quota) — एकपक्षीय नियतांश के अन्तर्गत एक देश एक निर्धारित समय में आयात-योग्य वस्तु की मात्रा की पूर्ण सीमा निश्चित कर देता है। इस प्रकार का नियतांश या तो सांसारिक (Global) रूप में निर्धारित किया जा सकता है या आवंटित रूप से। सांसारिक नियतांश के अधीन किसी भी देश या देशों से उतने आयातों को अनुमति दी जाती है जो नियतांशों द्वारा निर्धारित की गई है। इस प्रक्रिया की अनेक आलोचनाएँ की जाती हैं। सम्भवतः इसकी सबसे महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि इस व्यवस्था में छोटे या कम

संगठित पूरककर्ता देश नुकसान में रहेंगे। जब तक आयात-कर्ताओं को छोटे पूरककर्ता देशों से आयात करने से कोई स्पष्ट लाभ नहीं है तब तक वे उनसे आयात नहीं करेंगे।

घावटित नियतांश के अधीन कुल नियतांश को विभिन्न पूरककर्ता देश में घावटित कर दिया जाता है। ऐसा करते समय पूर्व अनुभव का लाभ उठाया जाता है। इस प्रक्रिया की आलोचना करते हुए कहा जाता है कि इसमें दुर्भाग्य से व्यापप्रिय और विशेष पूरककर्ता देशों के प्रति अन्याय होगा। अतीतकाल में यदि फसल के खराब होने के कारण अथवा अन्य किसी भी कारण से देश सन्तोषजनक मात्रा में निर्यात नहीं कर पाया तो इसके आधार पर उसके वर्तमान महत्व को भी असमर्थ समझा जाएगा। ऐसी स्थिति में नियतांश घावटित करते समय जो आधारभूत ममय छाँटा जाए वह प्रतिनिधित्व करने वाला और अभेदमाय पूर्ण होना चाहिए।

3. द्विपक्षीय नियतांश (The Bilateral Quota)—द्विपक्षीय नियतांश, आयातकर्ता और एक विशेष पूरककर्ता देश द्वारा निश्चित किया जाता है। एक बार जब इस प्रकार का समझौता सम्बन्धित सरकारों द्वारा कर लिया जाता है तो आयातकर्ता देश अन्य देशों को नियतांश निर्धारित करते समय उनके सापेक्षित महत्व को आधार बनाता है। द्विपक्षीय नियतांश के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि यह एक पक्षीय रूप से निर्धारित नहीं किया जाना और इसलिए यह इतना स्वेच्छाचारी नहीं होना। इसके विपक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि जब निर्यातकर्ता समूह समझौते का एक भाग होता है तो वह निर्णय लेते समय अपने विशेष हितों से प्रभावित होगा।

4. मिला-जुला नियतांश (The Mixing Quota)—अनेक देशों में ऐसे विनियम होते हैं जिनके अनुसार माल को बढ़ाने के लिए घरेलू कच्चे माल का प्रयोग करने के हेतु प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। इन सम्बन्ध में जो विनियम बनाए जाते हैं उनके अनुसार आयातों को घरेलू उत्पादन के अनुपात के अनुसार सीमित किया जाता है। इस प्रकार इन विनियमों का प्रभाव नियतांशों जैसा ही होता है। उदाहरण के लिए, युद्ध से पूर्व जर्मनी ने यह नियम बनाया था कि देश में जितना घाटा पीना जाता है, उसमें घरेलू गेहूँ का निश्चित अनुपात होना चाहिए। इसी प्रकार ग्रेट-ब्रिटेन में भी यह नियम बनाया गया कि घरेलू गेहूँ के साथ आयातित गेहूँ को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए। संयोग से सम्बन्धित विनियोग सामान्य रूप से दो उद्देश्य रखते हैं—

(i) वे घरेलू उत्पादकों की सहायता के लिए स्वीकार किए जा सकते हैं। इस प्रकार के नियमों द्वारा घरेलू उत्पादकों के लिए बाजार का आश्वासन दिया जाता है; चाहे उनका उत्पादन आयातित माल की तुलना में अधिक महंगा और घटिया स्तर का हो तो भी उसका एक निश्चित अनुपात अवश्य बिक जाएगा।

(ii) इस प्रकार के नियम आयातों को कम करते हैं और इसलिए विदेशी मुद्रा की कमी को राहत प्रदान करने हैं। इन नियमों का उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, आलोचना से परे नहीं होते। परिणामस्वरूप विश्व के साधन स्रोतों और शक्तियों का

के रूप में। प्रो. काज के कथनानुसार, “आयात अनुज्ञप्तियाँ आयातों की मात्रा को नियन्त्रित करने का एक शक्तिशाली प्रयास हैं। यह आयात चाहे किसी विशेष वस्तु का हो अथवा कुछ वस्तुओं को मिला-जुला कर। इस व्यवस्था की कुछ अपनी कमजोरियाँ हैं। इनमें प्रथम उल्लेखनीय कमी यह है कि अनुज्ञप्तिओं को स्वतन्त्रतापूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए कुछ व्यक्तियों द्वारा इसे प्राप्त करना और अन्य समान रूप से योग्य व्यक्तियों को इससे वंचित रखना, स्पष्टतः अनुचित है। आयातों पर प्रतिबन्ध कुछ व्यापारियों को एकाधिकार प्रदान करता है और वे इसका प्रयोग करते हुए मन चाहा लाभ कमाने का प्रयास कर सकते हैं।”

नियतांश के प्रभाव (Effects of Quotas)

नियतांश के कारण निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं—

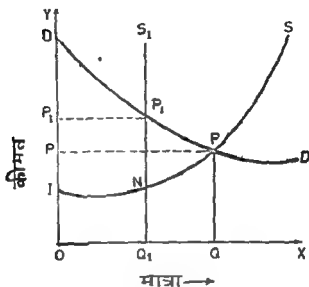
(1) कीमत पर प्रभाव—जिन वस्तुओं के सम्बन्ध में आयात नियतांश लगाए जाते हैं, उन वस्तुओं पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध लग जाने के कारण उनकी कीमतों में वृद्धि हो जाती है। परन्तु जब आयात पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं तो ‘कीमत-अन्त’ के स्वतन्त्र संचालन में होने वाला हस्तक्षेप प्रशुल्कों की अपेक्षा अधिक गम्भीर होता है। अधिकतर प्रशुल्क द्वारा आयातित वस्तुओं में होने वाली कीमत-वृद्धि आरोपित कर (Duty) की राशि से सीमित रहती है, अर्थात् कीमतों में अधिकतम वृद्धि आयात कर की राशि के बराबर हो सकती है। इसके विपरीत मात्रात्मक प्रतिबन्धों, अर्थात् आयात नियतांशों के अन्तर्गत चूँकि आयात की जाने वाली वस्तु की अधिकतम मात्रा की निश्चित रूप में उल्लेखित कर दिया जाता है, इसलिए ऐसी स्थिति में कीमतों में वृद्धि की कोई सीमा नहीं होती, अर्थात् नियतांश कीमतों में कितनी भी वृद्धि कर सकता है। अतः नियतांश का कीमत प्रभाव दो तत्त्वों से सम्बन्धित है—

(अ) आयातित वस्तु की पूर्ति (या मात्रा), और (ब) आयातित वस्तु की माँग। आयात नियतांश के अन्तर्गत आयात की जाने वाली वस्तु की मात्रा निश्चित रहने के कारण उस वस्तु की देश में जितनी अधिक माँग होगी, उसकी कीमतों में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। इस प्रकार नियतांशों के कारण कीमत में होने वाले परिवर्तन अनिश्चित हैं।

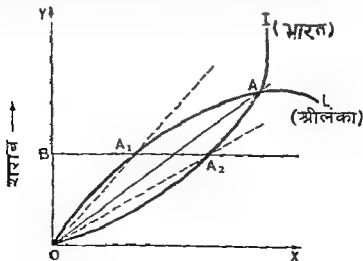
रेखाचित्र P के द्वारा आयात नियतांशों के कीमत पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रकट किया गया है—

माना कि DD_1 घरेलू माँग वक्र है। स्वतन्त्र व्यापार की स्थिति में साम्य बिन्दु P है जहाँ माँग व पूर्ति वक्र एक-दूसरे को काटते हैं। इस साम्य बिन्दु पर कीमत PQ होती है और वस्तु की OQ मात्रा का व्यापार किया जाता है। अब माना कि आयातक देश आयात की जाने वाली वस्तु का नियतांश OQ_1 निर्धारित कर देता है तो ऐसी स्थिति में आयातपूर्ति वक्र INS_1 हो जाता है जो यह प्रकट करता है कि OQ_1 मात्रा के बाद पूर्ति-वक्र पूर्णतया बेलोचदार हो जाता है। ऐसी

स्थिति में माँग वक्र DD_1 व पूर्ति वक्र INS_1 एक-दूसरे का P_1 बिन्दु पर काटते हैं, अतः कीमत PQ से बढ़कर P_1Q_1 हो जाती है। पूर्ति स्थिर होने के कारण जैसे-जैसे माँग में वृद्धि होती जाएगी कीमतें भी बढ़नी जाएँगी।



(2) व्यापार शर्तों पर प्रभाव—आयात नियंत्रण निर्धारित करने के परिणामस्वरूप एक देश के व्यापार की शर्तों में परिवर्तन हो जाता है। नवीन व्यापार शर्तों नियंत्रण लगाने वाले देश के अनुकूल भी हो सकती हैं और प्रतिकूल भी। यदि वस्तु के निर्यात करने वाले देश पर्याप्त समृद्ध है और उनका प्रस्ताव-वक्र कम लोचदार



है तो व्यापार की शर्तें आयात नियतांश लगान वाले देश के प्रतिवृत्त जा सकती हैं। इसके विपरीत यदि विदेशी प्रस्ताव-वक्र अधिक लोचदार है तो व्यापार की शर्तें आयात-नियतांश वाले देश के अनुवृत्त जा सकती हैं। इसी तथ्य को रेखाचित्र के द्वारा समझाया गया है।

माना कि भारत को कि कपड़े का निर्यात कर रहा है उसका प्रस्ताव वक्र OA_1 है। श्रीलंका का प्रस्ताव वक्र OL है जो शराब का निर्यात करता है। स्वतन्त्र व्यापार की स्थिति OA रेखा व्यापार की शर्त को निरूपित करेगी। अब यदि हम यह मान लें कि भारत श्रीलंका से आने वाली शराब की मात्रा OB तक सीमित कर देता है तो ऐसी स्थिति में व्यापार की शर्तों में परिवर्तन हो जाएगा। अब भारतीय कपड़ा व श्रीलंका की शराब के मध्य नवीन व्यापार की शर्तें OA_2 , अथवा OA_2 अथवा इन दोनों कीमतों के बीच श्रीलंका के शराब के प्रस्ताव वक्र की माँग की लोच के अनुसार कोई भी कीमत, अर्थात् व्यापार की शर्तें हो सकती है। स्पष्टतः भारत के लिए OA_1 , व्यापार की शर्तें अनुवृत्त हैं और OA_2 प्रतिवृत्त है।

(3) भुगतान-सन्तुलन पर प्रभाव—आयात नियतांश के द्वारा एक देश आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबन्धों के माध्यम से अपने भुगतान-सन्तुलन में स्थित असाम्यता को दूर कर सकता है क्योंकि आयात-नियतांश के द्वारा आयात को नियन्त्रित कर दिया जाता है। इसलिए इसका प्रभाव भुगतान-सन्तुलन पर अनुकूल पड़ता है। परन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों में नियतांश का भुगतान-सन्तुलन पर प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा—

(क) यदि नियतांश लगाने पर निर्यातक देश इसी प्रकार के प्रतिबन्ध लगा देते हैं तो नियतांश लगाने वाले देश को लाभ नहीं होगा।

(ख) यदि नियतांश लगाने से देश के महँगे कच्चे माल का उपयोग होने से वस्तु की लागत बढ़ जाती है तो निर्यात हतोत्साहित होंगे।

(ग) यदि नियतांश लगा देने से निर्यातक देशों की आयात-क्षमता कम हो जाती है तो फिर निर्यात कम हो जाएगा।

(4) सरक्षणरत्मक प्रभाव—आयात नियतांश पूर्णतया सरक्षणरत्मक होते हैं क्योंकि ये आयातों की एक निश्चित मात्रा तक नियन्त्रित कर देते हैं। आयात नियतांश इस प्रकार स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करते हैं।

(5) उपभोग प्रभाव—आयात नियतांश सामान्यतया वस्तुओं के कुल उपभोग को घटा देते हैं क्योंकि आयात नियतांशों के कारण घरेलू कीमतें बढ़ जाती हैं। यह उपभोग प्रभाव है। आयात नियतांश आयातित वस्तुओं के उपभोग और ऐसी घरेलू वस्तुओं के उपभोग जिनमें विदेशी कच्ची सामग्री प्रयुक्त है, निरुत्साहित करते हैं क्योंकि आयात-प्रतिबन्ध इन वस्तुओं का कृत्रिम अभाव उत्पन्न करके इनकी कीमतें बढ़ा देते हैं।

(6) पुनर्वितरण प्रभाव—आयात नियतांश के कारण जब कीमतों में वृद्धि होती है तो उत्पादकों की आय में तो वृद्धि होती है लेकिन उपभोक्ताओं की वास्तविक

प्रायः में कमी हो जाती है । जब कीमतें बढ़ती हैं तो घरेलू उत्पादकों की आयों में वृद्धि होती है परन्तु उपभोक्ताओं की उन वस्तुओं पर उपभोक्ता बचन कम हो जाती है यही आयात नियतांश का पुनर्वितरण प्रभाव है ।

नियतांश एवं प्रशुल्क (Quotas and Tariffs)

जब सम्बन्धित देशों में उत्पादन की तुलनात्मक लागत और माँग तथा पूर्ति की परिस्थितियाँ माँग करती हैं तो ऐसा कर लगाया जा सकता है जो आयातों को उस स्तर तक प्रतिबन्धित करदे जहाँ उन्हें विशेष नियतांश द्वारा प्रतिबन्धित किया जा सके । इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि नियतांश और प्रतिबन्धित कर का प्रभाव बराबर हो । समान रूप से प्रतिबन्धित लगाने वाले नियतांशों और प्रशुल्कों के प्रभाव अलग-अलग हो सकते हैं । नियतांशों और प्रशुल्कों से सापेक्षिक लाभ और हानियाँ होती हैं ।

जब आयात पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं तो कीमतें यन्त्र के स्वतन्त्र संचालन में होने वाला हस्तक्षेप प्रशुल्कों की अपेक्षा अधिक गम्भीर होता है । मात्रात्मक प्रतिबन्धों के अन्तर्गत आयात की जाने वाली अधिक से अधिक मात्रा को निश्चित रूप से उल्लेखित कर दिया जाता है । प्रशुल्क की व्यवस्था में प्रारम्भ में तो इतना ही प्रतिबन्ध होने है किन्तु बाद में वे अन्य बातों में परिवर्तन होने के साथ-साथ स्वयं बदलते रहते हैं । विदेशों में कीमतें गिरने देश में कीमतें उठने घरेलू माँग के बढ़न तथा ऐसे ही अन्य कारणों से प्रशुल्क के अधीन आयातों पर प्रभाव पड़ता है ।

मात्रात्मक प्रतिबन्धों द्वारा मुग्तानों के सन्तुलन यन्त्र की लोचशीलता को नुकसान पहुँचाया जाता है । यदि अतिरिक्त माल वाला देश मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगा कर सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयातों का नियन्त्रण करे तो घाटे वाले देश को अतिरिक्त उत्पादन वाले देश के लिए अपना निर्यात बढ़ाने में बहुत कठिनाई होगी । आर्थिक मन्दी के समय कड़दार देशों को मुग्तानों के परिवर्तन में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि लेनदार देशों में कठोर मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगे हुए थे । इन्होंने आयातों को कठोर बना दिया क्योंकि आयातों की घरेलू और विदेशी कीमतों के बीच पर्याप्त अन्तर रहना था । प्रशुल्क के अन्तर्गत आयातों और निर्यातों की मात्रा लानशील होती है । मुग्तानों के सन्तुलन की स्थिति में होने वाले परिवर्तन आयातों और निर्यातों की मात्रा पर भी प्रभाव डालने हैं । इस प्रकार प्रशुल्कों के अन्तर्गत मुग्तानों के सन्तुलन यन्त्र की लोचशीलता बनाए रखी जाती है ।

लगाए गए मात्रात्मक प्रतिबन्ध प्रायः एकाधिकार का कारण बनते हैं । ऐसी स्थिति में घरेलू आयातकर्त्ता या उत्पादक विदेशी प्रतिस्पर्द्धा से स्वतन्त्र रहने हैं तथा उपभोक्ताओं का शोषण करने हैं । प्रशुल्क व्यवस्था में एकाधिकार रखने वाले लोग कीमतों को प्रशुल्क सहित आयात कीमत से ऊँची नहीं चढ़ा सकते । प्रशुल्कों तथा मात्रात्मक प्रतिबन्धों के प्रभावों को केवल तभी समान कहा जा सकता है जब प्रशुल्क अन्तर्गत ऊँचे हो कि उन्हें मिनाकर आयात कीमतें एकाधिकार के कुल राजस्व से भी अधिक ऊँची हो जाएँ ।

नियतांशों द्वारा एकाधिकार की प्रकृति को न केवल आयातकर्ता देशों में वढाया जाता है वरन् निर्यातकर्ता देशों में भी बढाया जाता है। यदि कोई तीसरा देश प्रतिस्पर्धा को धमकी न दे अथवा प्रत्येक देश से किए जाने वाले आयात की मात्रा को निश्चित कर दिया जाए तो निर्यातकर्ता देश आपस में मिल कर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मानात्मक प्रतिबन्ध बहुत कुछ स्वेच्छापूर्ण होते हैं और इसलिए वे पूर्ति के विभिन्न स्रोतों के बीच भेदभाव करते हैं। इनके फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में मनमुटाव होने लगता है। यह कहना गलत होगा कि नियतांश हमेशा ही भेदभाव-पूर्ण होते हैं और प्रशुल्क हमेशा भेदभाव-हीन होते हैं। यदि उचित रूप से निर्धारित किया जाए तो नियतांश पूर्ण रूप से गैर-भेदभाव पूर्ण हो सकता है। फिर भी यह सच है कि यदि भेदभाव करना है तो इसके लिए नियतांश व्यवस्था प्रशुल्क व्यवस्था की अपेक्षा सुविधाजनक रहेगी। इसके विपरीत अतीत का इतिहास यह बताता है कि प्रशुल्कों की अपेक्षा नियतांश अधिक भेदभाव पूर्ण रहे हैं।

इन प्रकार देखा जाए तो कोई भी ऐसा निर्धारण का तरीका नहीं है जिसको निष्पक्ष कहा जा सके तथा जिसमें किसी को भी प्राथमिकता प्रदान करने का अवसर न हो। इसके अतिरिक्त नियतांश के निर्धारण के आधार को प्रायः गुप्त रखा जाता है और इसलिए यह तय करना सम्भव नहीं होता है कि एक नियतांश व्यवस्था भेदभाव विहीन है अथवा नहीं। जो प्रशुल्क बाजार के अवैयक्तिक घन के माध्यम से कार्य करता है वह अन्तर्राष्ट्रीय भेदभाव के लिए बहुत कम अवसर रहने देता है। यदि कभी बिना किसी उद्देश्य के ही कहीं भेदभाव होने लगे तो उसका इतना विरोध नहीं किया जाता जितना मात्रात्मक प्रतिरोधों के आधार पर किए गए अन्तर्राष्ट्रीय भेदभाव का होता है।

आयात पर लगाए गए प्रतिबन्धों के फलस्वरूप घरेलू मूल्य की कीमत तथा विदेशी पूर्ति की कीमत के बीच कुछ सीमान्त पैदा होता है। यदि आयातों पर प्रशुल्कों के कारण प्रतिरोध लगाए जाएं तो इस सीमान्त का विनियोग सरकार द्वारा किया जाता है और इस प्रकार एकत्रित किए गए धन को समाज की भलाई के लिए खर्च किया जाता है। जहाँ आयात को मात्रात्मक प्रतिरोधों द्वारा सीमित किया जाता है वहाँ सीमान्त का लाभ आयात-कर्ताओं, सरकार, घरेलू उपभोक्ताओं, विदेशी निर्यात-कर्ताओं या नियतांश प्रशासन के अधिकारियों के लिए प्राप्त होगा। इसमें से कौन इससे लाभान्वित होगा, यह बात उस तरीके पर निर्भर करती है जिससे कि घरेलू बाजार को संगठित तथा नियतांश को प्रशासित किया जाएगा। यदि सरकार सीमित मात्रा में आयात करने की अनुमति देने समय अनुज्ञप्ति प्रसारित करने की कोई कीमत वसूल न करे और वस्तु का आयात करने के बाद आयातकर्ता उस वस्तु की किसी भी कीमत पर बाजार में बेचने के लिए स्वतन्त्र हो तो सीमान्त की प्राप्ति आयातकर्ताओं को होगी। दूसरी ओर यदि देश में कीमतों का नियन्त्रण और राशन है तो सीमान्त की प्राप्ति उपभोक्ताओं को होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि आयातकर्ता अपने राशन ऊँचे दामों पर दूसरों को बेच देते हैं और इस प्रकार सीमान्त उस वस्तु के वास्तविक उपभोक्ताओं को नहीं मिल पाता।

मानात्मक प्रतिबन्धों के अन्तर्गत एक बड़ी नौकरशाही द्वारा व्यक्तिगत उद्योगों के कार्यों में हस्तक्षेप किया जाता है। जब व्यक्तिगत व्यापारियों को आयात और निर्यात का नियन्त्रण निर्धारित किया जाता है तो व्यक्तिगत व्यापार का नियन्त्रण और नियमन अधिक से अधिक करना आवश्यक बन जाता है। मानात्मक प्रतिबन्धों के द्वारा सरकारी अधिकारियों को व्यापार के निर्देशित करने तथा नियमित करने की अधिक स्वेच्छा प्राप्त हो जाती है। उन्हें राजनीति से अलग नहीं रखा जा सकता।

यह सच है कि प्रशुल्कों एवं मानागत प्रतिबन्धों द्वारा आयातों या निर्यातों की किसी भी सीमा तक रोका जा सकता है, फिर भी ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर यह कहना होगा कि नियन्त्रण, प्रशुल्कों की अपेक्षा अधिक नियन्त्रकारी रहे हैं। जब माँग की कमी हो जाती है तो नियन्त्रण पूर्ण रूप से प्रभावहीन बन जाता है, किन्तु प्रशुल्क भी ऐसी स्थितियों में अधिक प्रतिबन्ध रखने लगता है।

नियन्त्रण व्यवस्था का समर्थन (The Case for Quota System)

सामान्यतः यह माना जाता है कि गारे सत्तार को ध्यान में रखते हुए प्रशुल्क व्यवस्था मानागत प्रतिबन्धों से अधिक उच्च है किन्तु राष्ट्रीय दृष्टिकोण से मानागत प्रतिबन्ध कई प्रकार से प्रशुल्कों की अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से मानागत प्रतिबन्ध अस्वीकृत हैं किन्तु राष्ट्रीय दृष्टि से उनको पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त होती है। जब तक विश्व की आयात को विनियमित करने के लिए कोई अभिकरण नहीं है उस समय तक विभिन्न देश विश्व के व्यापक हित के लिए अपने राष्ट्रीय हितों को नहीं छोड़ सकते। नियन्त्रण व्यवस्था के समर्थन में जो तर्क दिए जाते हैं उनमें से प्रमुख निम्न प्रकार हैं—

1. अर्द्ध-विकसित देशों के लिए उपयुक्त—अर्द्धविकसित देशों में प्रशुल्क प्रभावशील नहीं होते। इन देशों की समस्याएँ विकसित देशों की अपेक्षा भिन्न होती हैं। विकसित देशों में आयात को हतोत्साहित करने के लिए घरेलू वस्तु की कीमत में थोड़ी-सी भी वृद्धि काफी होती है। दूसरी ओर अर्द्धविकसित देशों में उपभोक्ता घरेलू माल से पर्याप्त ऊँची कीमत होने पर भी विदेशी वस्तु को लेना पसन्द करता है। यह केवल इसलिए नहीं होता कि उन वस्तुओं के गुणों में कोई मौलिक अन्तर है। ऐसी वस्तुओं के उदाहरण भी हैं जो कि अपने देश में लोकप्रियता नहीं रखती लेकिन अर्द्ध-विकसित देशों में वहाँ की बनी वस्तुओं के साथ प्रतियोगिता करती हैं। अर्द्धविकसित देशों में घरेलू चीज मूल रूप से अच्छी होने पर भी विदेशी उत्पादन से घटिया मानी जाती है। ऐसी स्थिति में आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए उच्च प्रशुल्कों का लगाना आवश्यक है जो न केवल आयातकर्त्ता देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाएँगे वरन् नियमितकर्त्ता देश की अर्थव्यवस्था पर भी घुरा घमर डालेंगे।

2. तरकास प्रभावशील—प्रशुल्कों का प्रयोग जब कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है तो सभी वस्तुओं के आयातों और निर्यातों की माँग तथा पूर्ति की लोचशीलता का ज्ञान जरूरी है। इसके अभाव में जो प्रशुल्क निर्धारित किया जाएगा वह वांछनीयता से कम या अधिक स्तर का हो सकता है। प्रशुल्कों द्वारा

चुंगी संघ प्रणाली प्राथमिक करों की व्यवस्था पर आधारित रहती है। जब दो या दो से अधिक सम्प्रभु राज्य एक-दूसरे के माल को बिना करों के घटी हुई कर मात्रा के साथ एक-दूसरे के क्षेत्र में आने-जाने की अनुमति से सम्बन्धित सम्मिलित निर्णय करते हैं तो यह कहा जाता है कि उन्होंने एक चुंगी क्षेत्र (Custom Area) अथवा चुंगी संघ (Custom Union) का निर्माण कर लिया है। इस प्रकार चुंगी संघ दो प्रकार के हुए— (1) वे जिनमें करों को पूरी तरह हटा दिया है, और (2) वे जिनमें सम्बन्धित देशों का सामान घटी दर से कर देकर निर्यात सकता है। स्वतन्त्र व्यापार के समर्थकों ने इन दोनों को उचित माना है।

चुंगी संघ के परिणामस्वरूप अन्तर्गोष्ठीय अर्थ-विभाजन एवं तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के अनुसार आर्थिक लाभ प्रदान किए जाते हैं। ये लाभ सम्बन्धित देशों के सांस्कृतिक, राजनैतिक या जाति सम्बन्धी अन्य किसी प्रकार के सम्बन्धों पर निर्भर नहीं रहते। क्लेमेंट (Clement) तथा अन्य ने चुंगी संघों को क्षेत्रीय व्यापार-क्षेत्र का एक रूप माना है। उनके मतानुसार इसके अन्य रूप स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (Free Trade Area) और सामान्य बाजार (Common Market) हो सकते हैं। इन क्षेत्रों की अपनाने पर प्रशुल्क के सम्बन्ध में भेदपूर्ण नीति अपनाई जाने लगती है। क्षेत्रीय व्यापार क्षेत्रों के सदस्य प्रशुल्कों को एक-दूसरे के माल पर कम करने या समाप्त करने के लिए राजी हो जाते हैं किन्तु यह सभी गैर-सदस्य देशों से आयातित माल पर नहीं की जाती। इसका परिणाम यह होगा कि सदस्य देशों में आयातित माल को प्राथमिक (Preferential) प्रशुल्क दिया जाएगा जो गैर-सदस्य देशों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार माना जाएगा। प्रशुल्कों में ये भेदभावपूर्ण नीतियाँ अतिरिक्त आर्थिक सम्बन्धों को अस्त-व्यस्त कर सकते हैं। उनके परिणामस्वरूप उत्पादन और उद्योग के तरीकों में, व्यापार की शर्तों में, मुद्रताम के सन्तुलन में और सम्भवतः उन्नति की दर में भी परिवर्तन किए जा सकते हैं। चुंगी संघों का सिद्धान्त उन विभिन्न परिवर्तनों से सम्बन्ध रखता है जो प्रशुल्कों की भेदपूर्ण नीति से पैदा होते हैं।

चुंगी संघों का सिद्धान्त

(The Theory of Custom Unions)

चुंगी सघों का सिद्धान्त जेकब वाइनर (Jacob Vinar) की पुस्तक 'The Custom Union Issue' में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है। यह पुस्तक 1950 में प्रकाशित हुई थी। इसमें चुंगी सघों के कुछ प्रभावों का पहली बार महत्वपूर्ण अध्ययन किया गया था। इस विचार विमर्श का प्रारम्भिक प्रभाव बहुत कुछ मौलिक हुआ और इससे यह निष्कर्ष निकाला जाने लगा कि चुंगी सघ स्वतन्त्र व्यापार की दिशा में एक कदम है इसलिए वह विश्व कल्याण की अभिवृद्धि करेगा। वाइनर ने यह प्रतिपादित किया कि चुंगी सघों की रचना का प्रभाव लाभदायक और नुकसानदायक दोनों प्रकार का हो सकता है। इस प्रकार शुद्ध प्रभाव इस बात पर आधारित है कि दोनों विरोधी प्रभावों में से कौनसा प्रभाव बड़ा है। बाद में इस विषय से सम्बन्धित रचनाओं में वाइनर के योगदान का अधिक स्वीकारण किया गया। उन्होंने प्रभावों पर विचार करते सिद्धान्त को व्यापक रूप दिया जिन पर वाइनर ने विचार नहीं किया था और इस प्रकार उन्होंने आर्थिक एकीकरण की एक सामान्य तथा सशोचित विचारधारा निमित्त की।

व्यावहारिक प्रभाव—चुंगी सघों में केवल विचारों की ही रूचि नहीं रही बल्कि इसका पर्याप्त व्यावहारिक प्रभाव भी हुआ। यूरोपीय आर्थिक समुदाय (European Economic Community) की उत्पत्ति सफलतापूर्वक चुंगी सघों के सिद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों पहलुओं की आकर्षण का केन्द्र बनाया। आज इस सिद्धान्त की मूल मान्यताओं से अधिकांश विश्व के राजनैतिक नेता और सरकारी अधिकारी परिचित हैं। इसके आधार पर किसी भी भेदभावपूर्ण व्यापारिक व्यवस्था का विश्लेषण किया जा सकता है। अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धान्त को स्थित सघों या साझा बाजारों के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करने में उपयोगी पाया है जो अतीतकालीन आर्थिक या राजनैतिक एकीकरण का परिणाम है।

दो दृष्टिकोण—चुंगी सघों का सिद्धान्त एकीकरण के आर्थिक प्रभावों का स्पष्टीकरण से सम्बन्ध रखता है। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक विचारधारा के क्षेत्र में इस सिद्धान्त की स्थिति पर दो दृष्टियों से विचार किया जा सकता है। एक ओर चुंगी सघों का सिद्धान्त एक विशेष प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धान्त है जो परम्परागत व्यापार सिद्धान्त से अधिक व्यापक एवं सामान्य है। अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मॉडल केवल दो देशों के व्यापार पर विचार करते हैं जबकि चुंगी सघों के मॉडल में सम्भवतः तीन या अधिक देश होने चाहिए क्योंकि दो या इससे अधिक देश तो इसकी रचना करते हैं और गैर-सदस्य देश जेप सत्तार का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे, चुंगी सघों का सिद्धान्त शुल्क सिद्धान्त की एक विशेष शाखा है या व्यापारिक प्रतिबन्धों में भौगोलिक अनेकरूपता के परिवर्तनों के प्रभाव पर विचार करती है। इससे विपरीत प्रशुल्कों पर जो सामान्य विचार किया जाता है उसका सम्बन्ध भेदभाव-विहीन प्रशुल्कों से रहता है अर्थात् ऐसे प्रशुल्कों से जो सभी आयातों पर लगाए जाएँ चाहे वे किसी भी देश से किए जा रहे हों।

उपयोगिता—चुंगी संधी का सैद्धान्तिक विश्लेषण दूसरे श्रेष्ठ सिद्धान्त के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान करता है। चुंगी संधि द्वारा स्वतन्त्र व्यापार के क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है इसलिए हम इसे सामान्य स्वतन्त्र व्यापार की दिशा में एक कदम कह सकते हैं क्योंकि इसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ सुभाव के नवदीक संसार को लाकर कुल कल्याण को आवश्यक रूप से बढ़ावा नहीं दिया जाता। यह विचार चुंगी संधि सिद्धान्त के लिए वाइनर का मुख्य योगदान था। उन्होंने द्वितीय श्रेष्ठ (Second best) के सिद्धान्त में इस विरोध का उल्लेख किया। उनका विचार था कि जब तक श्रेष्ठ समाधान के लिए सभी शर्तें पूरी नहीं होतीं, तब तक जो शर्तें पूरी होती हैं वह आवश्यक रूप से कल्याण को प्रोत्साहन नहीं देती।

चुंगी संधी का अध्ययन अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्जतीय व्यापार के बीच स्थित कुछ अन्तरी का उल्लेख करता है। यद्यपि एक चुंगी संधि के विभिन्न सदस्यों के बीच किसी प्रकार का प्रशुभक नहीं होता फिर भी उत्पादित माल और उत्पादन के साधन उनके बीच उतनी स्वतन्त्रता से गति नहीं करते जितना कि अन्तर्जतीय व्यापार में करते हैं। चुंगी संधि के सदस्यों के बीच भाषा, रीति-रिवाजों और परम्पराओं, रूचि, संस्था, वर व्यवस्था आदि के आधार पर जितने अन्तर होते हैं उतने एक राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों के बीच नहीं होते। इन्हीं अन्तरों के कारण माल और साधनों की गति में बाधा पहुँचती है। इसके अनिरिक्त एक देश के विभिन्न क्षेत्र केन्द्रीय सत्ता द्वारा लागू की गई सामान्य नीतियों के विषयो के धनरूप होते हैं जबकि चुंगी संधि के विभिन्न सदस्य अलग-अलग प्रकार के स्वतन्त्र और कभी-कभी संधिपूर्ण कानूनों के विषय होते हैं।

सिद्धान्त का इतिहास—द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस सम्बन्ध में पर्याप्त विचार-विमर्श हुआ कि पश्चिमी यूरोप के लिए किस प्रकार का सामान्य आर्थिक एकीकरण किया जाए? इस एकीकरण की दिशा में पहला कदम बेनेलक्स चुंगी संधि (Benelux Customs Union) का संगठन था। उसके बाद यूरोपीय कोयला और फौलाद समाज (European Coal and Steel Community) की रचना की गई। 1957 में रोम में एक सन्धि पर हस्ताक्षर हुए और यूरोपीय आर्थिक समाज (European Economic Community) या यूरोपीय सामां बाजार (European Common Market) की रूप रचना प्रस्तुत की गई। यद्यपि अतीत में भी अनेक वास्तविक एवं प्रस्तावित चुंगी संधि रहे हैं किन्तु अर्थशास्त्रियों का ध्यान इनके अध्ययन की ओर युद्ध के बाद ही गया है। जब यूरोपीय आर्थिक समाज के सदस्य देशों एवं अन्य संधि के सफल कार्य संचालन को देखा गया तो इन संधियों की ओर विशेष रुचि भावपित होने लगी।

यदि तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त की अपेक्षा चुंगी संधि के सिद्धान्त का इतिहास अधिक पुराना नहीं है। जेकब वाइनर से पहले इनके सैद्धान्तिक अध्ययन की ओर किसी ने गम्भीर रूप से प्रयास नहीं किया। किसी ने न तो एकीकरण के प्रभावों का विवेचन किया और न इस मत

की सत्यता को माना जिसके अनुसार चुंगी सघ की स्वतन्त्र व्यापार की दिशा में एक ऐसा आन्दोलन माना गया था जिसके परिणामस्वरूप विश्व कल्याण की अभिवृद्धि होती है। मि० वाइनर की प्रमुख देन यह थी कि उन्होंने प्रभावी दृष्टिकोण की असत्यता का दिग्दर्शन कराया और बताया कि कुछ परिस्थितियों में चुंगी सघ विश्व के कल्याण को कम करते हैं। इसीलिए उन्होंने दूसरे श्रेष्ठ (Second best) सिद्धान्त की खोज की।

चुंगी सघों के अधिकांश सैद्धान्तिक अध्ययनों ने उत्पादन और उपभोग के परिवर्तनों से कल्याण पर पड़ने वाले प्रभाव पर ही अपना ध्यान केन्द्रित किया है। जीवन व्यवहार, भुगतान सन्तुलन तथा राजगार के स्तर आदि की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। यूरोप में एकीकरण के प्रभावों का मात्रात्मक अनुमान लगाने के लिए भी कुछ प्रयास किए गए। कम विकसित देशों में भी चुंगी सघों के प्रयोग की पर्याप्त रीच देखी गई है।

चुंगी सघ का अर्थ—चुंगी सघ शब्द के अर्थ की अनेक व्याख्याएँ प्रयुक्त अर्थ प्रस्तुत किए गए हैं। एक सघ अनेक रूप धारण कर सकता है। इसका सर्वाधिक सीमित रूप वह होता है जिसके अनुसार कुछ देश केवल एक ही वस्तु पर सुरक्षामक प्रयासों का प्रयोग करते हैं। इसके विपरीत सर्वाधिक पूर्ण सघ वह होता है जिसमें माल एवं उत्पादन के साधनों की गति पर से प्रत्येक प्रतिबन्ध को हटा लिया जाता है तथा सामान्य घन सम्बन्धी एक प्रगल्भ सम्बन्धी नीतियाँ अपनाई जाती हैं। सदस्य देश सामान्य मुद्रा का प्रयोग भी कर सकते हैं। पूर्ण सघ के लिए राजनैतिक एवं आर्थिक दोनों प्रकार के एकीकरणों का होना आवश्यक है। चुंगी सघों की एक सामान्य विशेषता यह है कि इसके सभी सदस्य देश अपने मध्य स्थित व्यापार को पारस्परिक रूप से उधार बना लेते हैं जबकि गैर-सदस्यों से होने वाले आयात पर प्रतिबन्ध लगाते हैं।

चुंगी सघों से सम्बन्ध रखने वाले साहित्य में आर्थिक एकीकरण की विभिन्न मानाओं के लिए अलग-अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है यद्यपि कहीं-कहीं दो शब्दों के बीच विरोध भी हुआ है। एक स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (A Free Trade Area) में सदस्यों के बीच सभी व्यापारिक प्रतिबन्धों एवं प्रशुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है किन्तु गैर-सदस्य देशों के साथ प्रत्येक देश अपने प्रशुल्क स्वयं लगाता है। दूसरे शब्दों में सघ के बाहर से होने वाले आयात पर ये देश सामान्य प्रशुल्क नहीं लगाते। चुंगी सघ (Custom Union) एक कदम और आगे बढ़ जाता है। इसके सभी सदस्य गैर-सदस्यों के साथ व्यापार पर सामान्य प्रशुल्क लगाते हैं। एक सामान्य बाजार (Common-Market) में सदस्य-गण अपने व्यापार एवं साधनों की गति पर से सभी प्रतिबन्धों को हटा देने हैं। इसके अतिरिक्त गैर-सदस्यों पर सामान्य व्यापार प्रतिबन्ध लगाते हैं। एक आर्थिक सघ (Economic Union) या भाग बाजार ही होता है। अन्तर केवल यह है कि इसमें राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों का कुछ समन्वय भी किया जाता है। पूर्ण आर्थिक एकीकरण (Total Economic

Integration) में एक उच्चतर राष्ट्रीय अभिकरण की स्थापना की जाती है। यह अपनी सत्ता के आधार पर सदस्य देशों के लिए सामान्य आर्थिक, प्रशुल्क सम्बन्धी तथा सामाजिक नीतियों को निर्धारित करती है।

इस प्रकार चुंगी संधों की दो सामान्य विशेषताएँ मानी जा सकती हैं—(1) एकीकरण के परिणामस्वरूप सदस्यों के बीच सभी प्रशुल्कों एवं व्यापारिक प्रतिवन्धों को समाप्त कर दिया जाता है, तथा (2) बाहर होने वाले आयात पर सामान्य प्रशुल्क लगाए जाते हैं। एकीकरण (Integration) एवं चुंगी संध शब्दों को कई बार समानार्थक के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है।

कल्याणकारी प्रभावों के मूल्यांकन की समस्याएँ (The Problems of Assessing Welfare Effects)

चुंगी संध की बाध्यनीयता का आधार उसका वह प्रभाव है जो इसके द्वारा जनकल्याण पर डाला जाता है। मूल्य रचि का विषय एक देश, सभी सदस्य देशों, सभी गैर सदस्य देशों अथवा सम्पूर्ण संसार का कल्याण हो सकता है। सामान्यतः अर्थशास्त्री कल्याण के अनाधिक तत्त्वों को बाहर रखते हैं। इतने पर भी आर्थिक कल्याण के प्रभाव को निर्धारित करना अत्यन्त कठिन है इस पर पढ़ने वाला कुल प्रभाव ज्ञात नहीं हो पाता। प्रत्येक परिवर्तन कुछ व्यक्तियों के लिए शुभ तथा अन्य के लिए अशुभ होता है। एक या अधिक व्यक्तियों के कल्याण की अभिव्यक्ति से उस समय कुल कल्याण की वृद्धि मानी जाएगी जबकि अन्य लोगों का कल्याण कम न हो अथवा प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जा सके। आधुनिक कल्याणकारी सिद्धान्त का कठोर पालन उन सत्र निष्कर्षों को बाहर रखता है जो राष्ट्रों और व्यक्तियों के बीच आय वितरण में होने वाले परिवर्तनों के कल्याणकारी प्रभावों से सम्बन्धित हैं।

चुंगी संध की रचना अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन, खपत और व्यापार की मात्रा एवं प्रकृति में भी अन्तर ला देगी। इसके द्वारा राष्ट्रों के बीच तथा प्रत्येक राष्ट्र के अन्तर्गत व्यक्तियों के बीच आय के वितरण को बदल दिया जाएगा। यदि संध के कारण साधनों का अधिक कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा सके तथा उत्पादन में वृद्धि की जा सके तो मानना होगा कि कल्याण में अभिवृद्धि हुई है। सामान्यतः संध की रचना के कारण उत्पादन के कुछ क्षेत्रों में कुशलता बढ़ेगी और कुछ में घटेगी। इस वृद्धि और कमी की तुलना के बाद ही इसके शुद्ध प्रभाव को जाना जा सकेगा। जब प्रशुल्कों में भेदभाव की पूर्ण कमी की जाती है तो इससे खपत पर

व पड़ता है क्योंकि सदस्य देशों से आयातित माल धरेलू उत्पादन तथा संध के देशों से आयातित माल से भी सस्ता होता है। खपत में होने वाले कुछ परिवर्तन विनिमय की कुशलता को बढ़ाकर कल्याण की अभिवृद्धि करेंगे जबकि दूसरों द्वारा इसे घटाया जाएगा। वही पर भी शुद्ध प्रभाव की जानकारी कमी और वृद्धि आदि की तुलना करने के बाद ही प्राप्त हो सकती है।

चुंगी संधों के प्रभाव दो प्रकार के होते हैं—स्थायी प्रभाव और गतिशील

(Dynamic) प्रभाव उत्पादन तथा विनिमय की कुशलता में होने वाला परिवर्तन स्थायी प्रभाव है जबकि प्रगति की दर में होने वाला परिवर्तन गतिशील प्रभाव है। स्थाई प्रभावों में हम उत्पादन, सप्लाय तथा व्यापार की शर्तों के परिवर्तन आदि को ले सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि स्थाई और गतिशील प्रभाव कल्याण को एक ही दिशा में परिवर्तित करें। सघ की रचना स्थायी कल्याणों को कम करते हुए भी गतिशील कल्याण को बढ़ा सकती है। इसका विपरीत प्रभाव भी सम्भव है। कई विचारकों ने यह मत प्रकट किया है कि जब एकीकरण के परिणामस्वरूप उत्पादन और विनिमय की कुशलता में सुधार होता है तो कल्याण में अभिवृद्धि होती है। यहाँ कल्याण से ग्रह विश्व के कल्याण से है। चुंगी सघों की रचना के विभिन्न प्रभाव निम्नलिखित हैं

(1) उत्पादन पर प्रभाव (Production Effects)—चुंगी सघों की रचना कई प्रकार से उत्पादन की कुशलता को प्रभावित कर सकती है। इसके द्वारा उत्पादन की अच्छी परिस्थितियों प्रदान करके कुशलता को बढ़ाया जा सकता है तथा श्रम विभाजन दृष्टि रूप में किया जा सकता है। यह बिनी में आन्तरिक तथा बाह्य मितव्ययता द्वारा प्रतियोगिता बढ़ाकर और अनिश्चितता को घटाकर कार्य कुशलता को बढ़ा सकती है। चुंगी सघों का उत्पादन पर पर्याप्त स्थायी प्रभाव पड़ता है। मि० वाइनर ने चुंगी सघों के कल्याणकारी पहलुओं का व्यापार रचना और व्यापार-विभाजन की दृष्टि से विश्लेषण किया है। सघ द्वारा कुल वस्तुओं के उत्पादन के राष्ट्रीय धरु को बदल दिया जाता है। यदि इसके द्वारा उत्पादन को उच्च लागत स्रोत से कम लागत स्रोत में बदल दिया जाता है तो यह व्यापार को जन्म देकर स्वतन्त्र व्यापार की स्थिति की ओर धागे बढ़ती है। दूसरी ओर यदि यह कम लागत स्रोत से अधिक लागत स्रोत की ओर धागे बढ़ती है तो यह व्यापार को रोकती है और स्वतन्त्र व्यापार की स्थिति से उसे दूर रखती है। उत्पादन में इस प्रकार के परिवर्तन, साधनों के प्रयोग की स्थायी कार्यकुशलता को प्रभावित करते हैं।

चुंगी सघ की रचना व्यापार और व्यापार रचना को रोकने का कारण बनती है। इसके विभिन्न प्रभावों को नापना सम्भव है। जब चुंगी सघ की रचना के विघापी प्रभाव उसके नियेधात्मक प्रभावों से अधिक होते हैं तो साधनों के प्रयोग की कुशलता बढ़ जाती है। कुशलता बढ़ने का अर्थ मरस रूप में यह होता है कि समान साधनों द्वारा अधिक उत्पादन किया जा सकता है अथवा कम साधनों द्वारा समान उत्पादन किया जा सकता है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि इससे कल्याण में अभिवृद्धि होती है क्योंकि उत्पादन की स्थिति का परिवर्तन कुछ अर्थों में यह कुछ देशों को लाभ पहुँचाता है वह अन्य को हानि भी पहुँचाता है। कार्यकुशलता में वृद्धि को कल्याण की वृद्धि मानने वाले यह भूल जाते हैं कि वितरण की समस्या का अपना महत्त्व होता है। वितरण के प्रश्न पर विचार किए बिना ही यह मान लेना गलत होगा कि कुशलता की अभिवृद्धि वांछनीय स्थिति को ला देगी।

व्यापार की कमी या वृद्धि के कारण होने वाले लाभ तथा हानि की तुलना

करना अधिक सरल नहीं है। लाभ का अनुमान लगाने के लिए पहले की प्रति इकाई लागत और धाज की प्रति इकाई लागत के बीच तुलना करके देखा जाता है। इसी प्रकार हानि का भी पता लगाया जाता है। इन दोनों भाषकों की तुलना करके यह देखा जा सकेगा कि शुद्ध प्रभाव उत्पादन में कार्य-कुशलता को घटाने का हुआ या बढ़ाने का। यह तरीका केवल तभी उपयुक्त रहेगा जब विचारणीय माल की लागत स्थायी हो और उसकी खपत निश्चित हो। लाभ और हानियों की तुलना करना इसलिए अत्यन्त कठिन है क्योंकि एक देश की उत्पादन वृद्धि एवं कमी स्वतः के प्रयास की अपेक्षा अन्य देशों के उत्पादन पर निर्भर करती है।

यद्यपि लाभ और हानि की मात्रा को निर्धारित करने का कोई सन्तोषजनक तरीका नहीं है फिर भी लागत वृद्धि के उदाहरण से दो गुणात्मक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं—(1) यदि व्यापार रचना के अनुकूल प्रभाव अधिक होंगे तो 'क' देश में लोचशीलता अधिक होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यापार रचना इसलिए अधिक होगी क्योंकि अधिक लागत वाली घरेलू प्रक्रियाएँ समाप्त हो जाएँगी। (2) 'क' देश में यदि घरेलू पूँति की लोचशीलता अधिक है तो उत्पादन की कार्य-कुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। स्थिर मूल्य की स्थिति में व्यापार-रचना की प्राप्तिवाँ केवल संघ के सदस्यों को ही होगी। इस सरल मॉडल के अन्तर्गत संघ के सदस्यों के साथ किए जाने वाले भायात और निर्यात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। व्यापार की कमी के कारण संघ के अन्तर्गत और सम्भवतः उसके बाहर वाले देशों में भी उत्पादन की कार्य-कुशलता घट जाएगी। संघ के अन्तर्गत इसके परिणामस्वरूप साधन स्रोत उन उद्योगों में चले जाएँगे जो शेष ससार के उद्योगों की तुलना में हानिप्रद है। संघ के बाहर के देशों के नियति में जो कमी हुई है उसके परिणाम-स्वरूप इन देशों के साधन-स्रोत उन वस्तुओं के उत्पादन साधनों की ओर मुड़ जाएँगे जिनमें अपेक्षाकृत कम लाभ होता है।

यदि वृद्धिशील-लागत का प्रभाव रहना है तो भी व्यापार रचना सदस्य देशों को लाभान्वित करेगी। व्यापार की रचना के कारण गैर-सदस्य देशों का व्यापार या कल्याण प्रभावित नहीं होता किन्तु व्यापार की कमी निर्धारित रूप से सदस्यों तथा गैर-सदस्यों के उत्पादन को प्रभावित करती है। संघ के सदस्यों के बीच व्यापार-रचना प्रभावित उद्योगों की लागत को कम करके अधिक प्राप्तियों का कारण बनेगी।

(2) उपभोग पर पड़ने वाले प्रभाव (Effects on Consumption)--- वाइनर ने अपने प्रारम्भिक विश्लेषण में केवल उत्पादन के प्रभावों पर ही विचार किया तथा खपत में होने वाले परिवर्तनों की छवहेलना की थी किन्तु बाद के विश्लेषणों से यह स्पष्ट हो गया कि चुंगी संघ के साथ-साथ होने वाले भेदभाव पूर्ण प्रशुल्क सापेक्षिक कीमतों को बदल देंगे और इस प्रकार खपत के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। इस सम्बन्ध में लिप्से (Lipsy) का कहना है कि "कुछ प्रावश्यक वस्तुओं की निश्चित अनुपात में ही खपत होती है चाहे उनकी सापेक्षिक कीमत

मुद्ध भी हो ।" इस मान्यता का अर्थ यह हुआ कि किसी भी उत्पादन के लिए माँग की लोच शून्य होगी किन्तु क्योंकि माँग पूर्ण रूप से लोचहीन नहीं होती इसलिए सघ की रचना खपत में परिवर्तन लाएगी और इस प्रकार कल्याण को प्रभावित करेगी । खपत में कुशलता कल्याण के लिए इतनी ही आवश्यक सगत है जितनी कि उत्पादन की कार्य कुशलता हानी है । खपत पर सघ की रचना का उत्पादन की भाँति विधयात्मक एवं निषेधात्मक प्रभाव पड़ता है । मीडे (Meade) ने एक माडल में खपत पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया है । य वाइतर की मान्यताओं को उलट देने हैं । मीडे के कथनानुसार उत्पादन का एक निश्चित तरीका होना है किन्तु खपत का तरीका सघ की रचना के साथ बदलता रहता है । उत्पादन का तरीका इसलिए निश्चित होना है क्योंकि क 'ख' और 'ग' तीनों देश एक वस्तु की केवल निश्चित मात्रा का ही उत्पादन कर सकते हैं और इस प्रकार पूर्ति की लोचशीलता शून्य बन जाती है । इस प्रकार चुंगी सघ की रचना सार्वजनिक कीमता प्रत्येक देश में खपत के तरीकों और देशों के बीच व्यापार को परिवर्तित कर देती है । मीडे ने घरेलू कीमत अनुपात (Domestic Price Ratio) के आधार पर प्रत्येक देश के अन्तर्गत उत्पादन की सीमाएँ प्रतियोगिता के अनुपातों की तुलना की है और इस प्रकार प्रत्येक देश के आयातों और निर्यातों के परिवर्तनों का मूल्यांकन करने का प्रयास किया है ।

मीडे ने यह निष्कर्ष निकाला है कि कल्याण अथवा रहन-सहन के स्तरों पर पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव प्रशुल्कों की प्रारम्भिक रूप रचना एवं माँग की लोचशीलताओं पर निर्भर है । इस दृष्टि से बाहर के देशों के प्रशुल्कों की तुलना में सघ के सदस्यों का मौलिक प्रशुल्क जितना अधिक होगा, निमित्त व्यापार की मात्रा उतनी ही अधिक होगी और बड़े हुए व्यापार में खपत की प्रति इकाई की प्राप्ति भी उतनी ही अधिक होगी । इतने पर भी सघ के सदस्यों के बीच जब पहले पहल प्रशुल्कों को कम किया जाएगा तब उनको अधिक प्राप्ति होगी । ये प्राप्ति ब्राद में कम हो जाएँगी ।

(3) कुल प्रभाव (The Total Effects) — उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि चुंगी सघों द्वारा उत्पादन और खपत के माध्यम से कल्याण को प्रभावित किया जाता है । यद्यपि उत्पादन और खपत दोनों पर विचार विमर्श अलग अलग किया गया है फिर भी इनको स्वतन्त्र नहीं माना जाता क्योंकि उत्पादन में होने वाला परिवर्तन खपत के रूप में बदलता है और खपत में होने वाला परिवर्तन भी उसी प्रकार उत्पादन को बदलता है । दोनों को मिलाकर एक नए माँडल के अनुसार अध्ययन का विषय बनाया जाए तो भी हमारे निष्कर्ष यही आएँगे कि चुंगी सघों का प्रभाव खपत और उत्पादन दोनों पर समान रूप से पड़ता है ।

प्रभावों के निर्धारणकर्ता

(Determinants of the Effects)

चुंगी सघों का उत्पादन और उपभोग पर जो प्रभाव पड़ता है उसका निर्धारण करने वाले कई तरीके हैं । सघ की रचना से पूर्व सदस्य देशों में जिन

वस्तुओं का व्यापार हो रहा है उनकी माँग और पूर्ति की लोचशीलता जितनी अधिक है उतना ही उनके बीच व्यापार होगा। इसी प्रकार प्रशुल्क को समाप्त कर देने पर जिन वस्तुओं का व्यापार किया जाएगा वे भी अपेक्षाकृत अधिक होगी। सघ के सदस्यों में आयात की जाने वाली वस्तुओं की माँग और पूर्ति की लोचशीलता जितनी कम होती है, व्यापार की भिन्नता भी उतनी ही कम होती है। संघ की रचना के बाद व्यापार की मात्रा बढ़ने पर कल्याण में अभिवृद्धि की आशा की जाती है। इस सम्बन्ध में एक सामान्यीकरण यह किया जाता है कि सघ का आर्थिक आकार जितना बड़ा होता है उत्पादन की पुनर्व्यवस्था के आधार से प्राप्तियाँ भी उतनी ही अधिक होती हैं। सघ का आकार जितना बड़ा होता है उसमें आन्तरिक धन-विभाजन की सम्भावनाएँ उतनी ही अधिक बढ़ जाती हैं क्योंकि अनेक साधन स्रोत एवं बड़े बाजार उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त संघ जितना बड़ा होगा व्यापार में घटाव के उतने ही कम अवसर होते हैं। यदि सघ में संसार के सभी देश सम्मिलित हो जाएँ तो इससे व्यापार कम नहीं होगा बरन् बढ़ेगा ही।

चुंगी सघों के बनने से वे प्राप्तियाँ भी प्रभावित होंगी जो प्रशुल्कों के परिवर्तन पर आधारित हैं। प्रशुल्कों के हट जाने से देशों के व्यापार पर अनुकूल प्रसर पड़ेगा। संघ के बनने से पहले प्रशुल्कों की मात्रा जितनी अधिक थी, सघ बनने के बाद उसके सदस्यों के बीच का व्यापार उतना ही अधिक बढ़ जाएगा। सघ के सदस्य जिस माल का निर्यात करते हैं उस पर गैर-सदस्यों द्वारा प्रशुल्क लगाया जाएगा। इस प्रशुल्क की मात्रा जितनी कम होगी उतना ही अधिक संघ के सदस्यों के व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। उनके पारस्परिक व्यापार में भी कमी नहीं आएगी। दूसरी दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि सघ के सदस्य सघ के बाहर के सदस्यों को जो निर्यात करते हैं उससे जितना अधिक प्रशुल्क लिया जाता है व्यापार के कम होने के अवसर उतने ही कम हो जाते हैं। असल में इस समस्या के सम्बन्ध में सामान्य रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता और विशेष परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद ही निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकेगा क्योंकि यह प्रश्न माँग और पूर्ति की लोचशीलता पर भी उतना ही निर्भर है जितना कि प्रशुल्क पर।

जो परिस्थितियाँ एक विशेष चुंगी सघ की रचना करने वाले देशों में रहती हैं, वे निश्चय ही कुछ लाभदायक एवं कुछ निर्धारणकर्ता रूप में उत्पादन तथा उपभोग में परिवर्तन लाती हैं। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि चुंगी सघ की रचना में किन देशों को शुद्ध लाभपूर्ण प्रभावों की अनुभूति होती है और किस प्रकार के देश हानिकारक प्रभावों की अनुभूति करते हैं? इस सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद हैं। जो भी विचार-विमर्श किया जाता है उसका मुख्य केन्द्र व्यापार की रचना भयवा कमी होता है। उसमें उपभोग के प्रभावों की ओर इशारा नहीं किया जाता। कुछ विश्लेषणकर्त्ताओं का विश्वास है कि खराब (Consumption) के प्रभाव उत्पादन के प्रभावों से कम महत्वपूर्ण होते हैं। 1950 में मि० वाइनर की पुस्तक प्रकाशित होने से पूर्व सामान्य दृष्टिकोण यह था कि 'चुंगी संघ' विरोधी अर्थ-व्यवस्थाओं की अपेक्षा

पूरक अर्थ व्यवस्थाओं में अधिक लाभकारी रहेंगे। पूरक अर्थ व्यवस्थाओं को साधारणतया ऐसी अर्थ-व्यवस्था बनाया गया जिसमें उत्पादन के विभिन्न रूप होते हैं ताकि उनमें से प्रत्येक विभिन्न उत्पादनों में विशेषीकरण प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत विरोधी अर्थ व्यवस्थाओं में उत्पादन का रूप एक जैसा होता है। उत्पादन माल के प्रकारों में पर्याप्त अतिराव रहता है। तर्क यह दिया जाता था कि विरोधी अर्थ व्यवस्थाओं की अपेक्षा पूरक अर्थ व्यवस्थाओं में विशेष वस्तुओं के उत्पादन के मूल्य का अन्तर अधिक होता है। इस प्रकार एक पूरक देशों का सघ मूल्य की अधिक बचत कर सकता है। वाइनर ने इस दृष्टिकोण का विरोध किया और यह तर्क दिया कि विरोधी अर्थ व्यवस्थाओं में चुंगी सघ अधिक लाभदायक हो सकते हैं क्योंकि उनके द्वारा अधिक व्यापार की रचना की जाएगी। उदाहरण के लिए दो उत्पादन समूह हैं जिन पर चुंगी सघ में सम्मिलित होने वाले सभी देशों द्वारा प्रशुल्क लगाया जाता है। प्रथम समूहों में वे वस्तुएँ हैं जो सघ में सम्मिलित प्रत्येक देश द्वारा उत्पादित की जाती हैं और दूसरे में वे हैं जिन्हें सघ के केवल एक ही देश के द्वारा पैदा किया जाता है। जब अन्तर्संघ व्यापार पर से प्रशुल्क हटा दिया जाएगा तो प्रथम समूह में प्रत्येक वस्तु को सबसे अधिक कुशलता के साथ पैदा करने वाला देश सघ के बाजार में अधिकांश भाग पर अधिकार कर लेगा। उत्पादन में यह परिवर्तन व्यापार की रचना है और इसके द्वारा साधनों के प्रयोग की कुशलता को सुधारा जाता है।

इसी प्रकार दूसरे समूह में जो एक देश प्रत्येक वस्तु का उत्पादन कर रहा है वह निश्चय ही सघ बाजार के अधिकांश भाग को अधिकार में कर लेगा किन्तु ऐसा करते समय वह सघ के अन्य सदस्यों के उस घायात को समाप्त कर देगा जो सघ के बाहर के देशों से किया जाता था। ऐसी स्थिति में व्यापार कम होगा और इसके द्वारा स्रोतों के प्रयोग की कुशलता घट जाएगी। विरोधी अर्थ व्यवस्थाओं में प्रथम समूह के अन्तर्गत अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होगा और इसलिए उनके बीच निमित्त सघ अधिक व्यापार रचना का कारण बनेगा।

वाइनर के विपक्षियों पर किए गए विचार-विमर्श में विरोधी और पूरक की परिभाषाओं के प्रयोगों की अस्पष्टता पर प्रभाव डाला गया। ये पूरक अब सामान्यतः तुलनात्मक लागतों में अन्तर को इंगित करते हैं। आज विरोधी अर्थ व्यवस्थाएँ उनको कहा जाता है जो कि उत्पादनों के गुणों के बीच समान लागत अनुपात रखती हैं और पूरक अर्थ व्यवस्थाएँ वे होती हैं जिनमें लागत अनुपात समान नहीं होते। मि० मैकोवर (Mr Makower) एव मोर्टन (Morton) ने विरोधी और पूरक अर्थ व्यवस्थाओं की परिभाषित करने की तकनीकी कठिनाइयों का विरोध किया है। उनके मतानुसार लागत की बहुविधा पूर्ण प्रकृति के कारण लागत अनुपातों में समानता या असमानता की मात्रा का कोई एक मापक नहीं होता। दोनों विचारकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि एक सघ व्यापार की रचना करता है तो प्राप्तियाँ इस व्यापार-रचना में निहित माल के लागत अनुपात की असमानता की भाँति बढ़ी होगी।

असल में इन दोनों विचारकों के निष्कर्ष वाइनर के निष्कर्षों से विरोध नहीं रखते। यदि उत्पन्न वस्तुओं के प्रकारों में बहुत कम अतिराव है और इस प्रकार दो अर्थ-व्यवस्थाएँ एक दूसरे की पूरक हैं तो उनका सघ व्यापार रचना की अपेक्षा व्यापार में कमी करेगा। इसके विपरीत यदि दो अर्थ-व्यवस्थाएँ प्रतियोगितापूर्ण हैं तो उनके बीच बनाए गए सघ में अधिक कुशल देश सघ के बाजार के अधिक भाग को अधिकार में कर लेगा। इस प्रकार वह व्यापार की रचना करेगा और कार्य-कुशलता को बढ़ाएगा। दूसरी ओर वाइनर का निष्कर्ष था कि यदि अर्थ-व्यवस्थाएँ प्रतियोगी हैं तो व्यापार रचना अधिक हो सकेगी।

यूरोपीय साझा बाजार (European Common Market) के देश अपने लाभ के प्रभावों द्वारा हानि के प्रभावों को दवाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं। सघ बनने से पहले इनके बीच पर्याप्त व्यापार होता था। इनके विदेश व्यापार और औद्योगिक उत्पादनों में पर्याप्त अतिराव और विरोध था। अतः यूरोपीय आर्थिक समाज की रचना की गई। रोम में सन्धि पर हस्ताक्षर के बाद इस समाज के व्यापार का तीव्र गति से विकास हुआ है। कुछ विचारक लिखते हैं कि सदस्य देशों के बीच उत्पादन-लागत के अन्तर कम हैं इसलिए व्यापार रचना के लाभ अधिक नहीं होंगे। दूसरे विचारक तर्क करते हैं कि अन्तर पर्याप्त महत्वपूर्ण है और व्यापार रचना की कुशलता को बढ़ाने में अत्यन्त लाभदायक रहेंगे। निर्मित माल के व्यापार की कुछ कमी भी हो सकती है क्योंकि सघेतर उत्पादक देश इस प्रकार की बहुत सी चीजों को यूरोपीय आर्थिक समाज के बाजार में सदस्य देशों के उत्पादनों से प्रतियोगिता करते हुए बेचेंगे। कच्चे माल में व्यापार की कमी थोड़ी होगी क्योंकि इस समाज के देश जितने कच्चे माल का उपभोग करेंगे उसमें से थोड़ा ही वे पैदा कर पाएँगे।

यूरोपीय आर्थिक समाज के देशों और पूर्व समुद्र पार के उपनिवेशों के बीच कृषि में पूर्ण सम्बन्ध है। ऐसी स्थिति में यदि साझा बाजार (Common Market) बनाया गया तो इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादनों में व्यापार की कमी हो जाएगी। विशेष रूप से जो सदस्य पहले लैटिन अमेरिका से उत्पादनों का आयात करते थे वे अब इनमें से अधिकांश उत्पादनों को अफ्रीका के फ्रांसीसी उपनिवेशों से मगाना उचित समझेंगे क्योंकि सह-सदस्य होने के कारण उनको प्रशुल्क के व्यवहार में प्राथमिकता प्राप्त होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका भी इनमें से कुछ उत्पादनों को कम कीमत पर प्रदान कर सकता है। अतः उसके व्यापार में भी कटौती हो जाएगी। उत्पादन के समान रूपों वाले औद्योगिक देशों के बीच जल सघ बनाया- जाएगा तो स्रोतों के प्रयोग की कुशलता में वृद्धि होगी। यद्यपि यह कुछ व्यापार की कमी का कारण बन सकता है।

यूरोपीय आर्थिक समाज के सदस्यों की तुलना में यूरोपीय स्वतन्त्र व्यापार संस्था (European Free Trade Association) के साथ देशों में अधिक पूरक तथा कम प्रतियोगिता पूर्ण सम्बन्ध है। इस समूह के देशों में ग्रेट-ब्रिटेन सबसे बड़ा

निर्माता है। आस्ट्रिया एवं स्विट्जरलैंड भी कुछ निम्नित वस्तुओं का निर्यात करते हैं किन्तु दूसरे देश खाद्यान्न तथा कच्चे माल के महत्वपूर्ण निर्यात कर्ता हैं। एफ्टा (EFTA) के सदस्यों के बीच जो कुल व्यापार होता है उसका अनुपात यूरोपीय आर्थिक समाज के लोगों की तुलना में कम है।

जिन अर्द्धविकसित देशों के बीच चुंगी सघ बनाने के लिए प्रस्ताव किए जाते हैं वे परस्पर अधिक व्यापार नहीं करते। यद्यपि उनका विदेश व्यापार उनकी राष्ट्रीय आय से बहुत सम्बन्ध रखता है फिर भी उनके व्यापार का बड़ा अनुपात विकसित देशों के साथ है। इस स्थिति से हानिकारक उत्पादन एवं खपत के प्रभावों का प्रमाण प्राप्त होता है। ये देश क्योवि मुख्य रूप से भोजन और कच्चे माल का निर्यात करते हैं इसलिए सामान्यतः अनुपूरक नहीं हैं यद्यपि वे निर्यातों की वस्तुओं की दृष्टि से भिन्नता रखते हैं। इन देशों द्वारा जो प्रारम्भिक उत्पादन किए जाते हैं उनमें व्यापार रचनाओं की सम्भावनाएं कम होती हैं। सघ का एक प्रमुख प्रभाव यह है कि वह सरक्षित धरेलू रचना के स्थान पर बाहर में आयात करने लगता है फलतः व्यापार में कमी आ जाती है। इस प्रकार अर्द्धविकसित देशों में यदि चुंगी सघ बनाए गए तो वे साधनों के प्रयोग की स्थायी कुशलता को बढ़ाने की बजाए अटार्केंगे।

इस सम्बन्ध में एक प्रश्न यह उठता है कि विकास के विभिन्न स्तरों पर स्थित देशों के बीच यदि चुंगी सघ बनाया गया तो उसका सम्भावित प्रभाव क्या होगा ? उदाहरण के लिए यदि यूनान, जो कि अपेक्षाकृत अर्द्धविकसित देश है, यूरोपीय आर्थिक समाज का पूर्ण सदस्य बन जाता है तो इससे उसके यूरोपीय आर्थिक समाज के, और दुनिया के कल्याण पर क्या प्रभाव होगा ? इस प्रश्न का सन्तोषजनक और पूरा उत्तर पाने के लिए लम्बे विचारविमर्श की आवश्यकता है जो यहाँ अभीष्ट नहीं है।

चुंगी सघ की रचना द्वारा इसने सदस्यों का पारस्परिक एवं बाहर वाले देशों के साथ मुगतात सन्तुलन प्रभावित किया जाता है। जिन सदस्यों के कर एकीकरण से पहले सर्वोच्च वे वे अपने मुगतातों के सन्तुलन में उन देशों के साथ विपरीत परिवर्तन का अनुभव करेंगे जिनके कर सबसे कम हैं।

चुंगी सघ की रचना से यद्यपि आर्थिक सम्बन्धों को बढ़ावा मिलता है फिर भी इस व्यवस्था की अपनी कुछ समस्याएँ तथा कठिनाइयाँ हैं। दो देश पारस्परिक प्रशुल्क को घटा देते हैं तो उनके बीच प्रत्यक्ष प्रतियोगिता प्रारम्भ हो जाती है, इसके भलावा यह प्रणाली दूसरी कठिन राजनैतिक एवं प्रशासनिक समस्या की जन्म देने का भी कारण बनती है। प्रो. हैबरलर ने इन समस्याओं का उल्लेख किया है। उनके अनुसार दो देश, दो सदस्य, निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों के दो समूह तथा सगठन एक प्रशुल्क के सूचीपन पर सहमत होने चाहिए, यह कार्य सरल नहीं है। व्यावहारिक दृष्टि से एक ही राज्य में विभिन्न सम्बन्धित क्षेत्रों के स्वार्थों के विरोध तथा इच्छाओं के संघर्ष के परिणामस्वरूप प्रशुल्क निश्चित करना बहुत कठिन होता है। पुराने आस्ट्रिया-हंगरी का उदाहरण हमारे सामने है। इस राज्य के दो भागों का

एक ही राज्य था, एक ही सेना थी किन्तु फिर भी दोनों के बीच व्यापार की समस्या गम्भीर रहती थी। इस प्रकार उत्पन्न समस्याओं का हल करना लगभग अमम्भव सा लगता है। इनके अतिरिक्त चुंगी से प्राप्त होने वाले राजस्व के बँटवारे तथा उसके प्रशासन की समस्या भी महत्त्वपूर्ण बन जाती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि चुंगी संघ बनाने के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं और इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना सरल नहीं होता। यही कारण है कि लाभदायक होने के बाद भी चुंगी संघों की संख्या बहुत कम है। प्रो. हैबरलर ने इन संघों का एक दोष यह भी बताया है कि इनका उद्देश्य जिसे वे आदर्श मानकर चलने हैं, अत्यन्त सीमित होता है। चुंगी संघों का व्यावहारिक अध्ययन करने की दृष्टि से यदि यूरोपीय सभा बाजार का उल्लेख किया जाए तो उपयोगी रहेगा।

सटकरो एव व्यापार पर सामान्य समझौता

[GENERAL AGREEMENT ON TARIFF AND
TRADE (GATT)]

GENERAL AGREEMENT ON TARIFF AND TRADE (GATT)

सटकर तथा व्यापार पर सामान्य समझौता अथवा गैट (GATT) एक बहुपक्षीय सन्धि है जिसमें पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों को महत्व दिया जाता है। इसकी स्थापना जनवरी, 1948 में हुई। गैट (GATT) के अन्तर्गत जो विस्तृत उद्यम लिए गए हैं तथा समझौता करने वाले देशों ने जो सम्बन्धित नियम बनाए हैं वे मध्य देशों के व्यापारिक सम्बन्धों को प्रायः सम्पूर्ण क्षेत्र में समन्वित करते हैं। इस समझौते की 1954-55 में पुनरीक्षा की गई और इसमें कुछ संशोधन किए गए, ताकि कम विकसित देशों के व्यापार तथा आर्थिक विकास से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान खोजा जा सके। गैट द्वारा आयोजित हेयरलर-प्रतिवेदन में इन समस्याओं के महत्व को वर्णित किया गया। इसे 1957 में व्यापार मन्त्रियों की बैठक में स्वीकार किया गया। इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए तीन समितियाँ स्थापित की गईं। इनमें एक समिति का सम्बन्ध कम विकसित देशों के निर्यात से होने वाली आय को बढ़ाने से था। समिति ने व्यापार प्रतिरोधी तथा व्यापार प्रभाव पर सूचना एकत्रित की तथा कम विकसित देशों में निर्यात की क्षमता रखने वाले क्षेत्रों को पहचाना। समिति ने अपनी क्रियाओं के क्षेत्र को व्यापक बनाया और व्यापार प्रोत्साहन तथा विकास योजनाओं को भी अपने अध्ययन में शामिल किया। इसने 1961 के अन्त में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिस पर इसी वर्ष मन्त्रियों की बैठक में विचार लिया गया। 1961 की बैठक का महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि इसमें कम विकसित देशों के व्यापार को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में घोषणा की गई। समझौता करने वाले पक्ष इस बात पर सहमत थे कि उनकी सरकारें घोषणा में दिए गए सिद्धान्तों का पालन करेंगी ताकि कम विकसित देशों के निर्यातों के मार्ग की बाधाओं को दूर किया जा सके।

व्यापार की बाधाओं को समाप्त करने के लिए 1963 में मन्त्रियों की बैठक में आठ-सूत्रीय कार्यक्रम बनाया गया। इस कार्यक्रम द्वारा अर्द्ध-विकसित देशों की प्रत्येक-व्यवस्था को अनेक रूपों में बनाने, उनकी निर्यात क्षमता को मजबूत करने और

समुद्र पार की बित्री से उसकी घामदनी को बढाने का प्रयास भी किया गया । इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में सहायता करने के लिए तीन उप-समितियाँ बनाई गईं । हवाना में जिन सिद्धान्तों व नियमों को प्रतिपादित किया गया था ग़ौर गैट (GATT) में जिनको संयुक्त किया गया था उनका मुख्य उद्देश्य पूर्ण रोजगार तथा वास्तविक आय और प्रभावशील भाँग की मात्रा को व्यापक करना था न कि विकास पर ध्यान देना ।

अर्द्ध-विकसित देशों के मुग़तात सन्तुलन की स्थिति विरोधी होने के कारण वे विकासशील देशों द्वारा दी गई प्रगल्भ सम्बन्धी छूट का पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा सके । गैट के कार्यों का मूल्यांकन करने के बाद यह कहा जा सकता है कि इसने विकासशील देशों की इतनी सेवा नहीं की जितनी विकसित देशों की की है । यद्यपि विश्व व्यापार बड़ा है किन्तु उसमें विकासशील देशों का भाग घटा है । विकासशील देशों द्वारा किया गया निर्यात जो 1950 में विश्व का एक तिहाई भाग था, 1962 में 1/5 से कुछ अधिक रहा । निर्यात की इस कमी के कारण कुछ विकसित देशों में भेदभावपूर्ण तथा सरक्षणवादी नीतियाँ थीं । इसके अतिरिक्त विकासशील देशों में व्यापार की वस्तुएँ भी उपयुक्त नहीं थीं ।

निर्यातों की कमी एक ऐसे समय में हुई जबकि विकासशील देशों को अपने विकास के लिए अधिक आयातों की ज़रूरत थी । यही कारण है कि 1950 में उनके निर्यातों की अपेक्षा आयात अधिक थे किन्तु 1962 में 23 बिलियन डॉलर का घाटा रहा । उनकी आयात की आवश्यकताओं और निर्यात की आय के बीच दूरी निरन्तर बढ़ती जा रही है । संयुक्त राष्ट्रक्षेत्र के सचिवालय के एक अनुमान के अनुसार यह दूरी सन् 1970 तक 20 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष तक हो सकती है ।

तटकरों एवं व्यापार पर सामान्य समझौता

(General Agreement on Tariff and Trade)

लिप्से तथा स्टार्नर (Lipsey and Stiner) के कथनानुसार, युद्धोत्तर विश्व की सर्वाधिक उल्लेखनीय प्राप्ति में तटकरों एवं व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT) महत्वपूर्ण है इसके अन्तर्गत सभी देश समय-समयपर मिलते हैं और प्रगल्भों में कड़ीती के प्रश्न पर द्विपक्षीय रूप से समझौता वार्ता करते हैं ताकि सभी को लाभ हो सके । गैट (GATT) के इतिहास की जानकारी के लिए हम संयुक्तराज्य अमेरिका द्वारा विश्व व्यापार एवं रोजगार के लिए रखे गए प्रस्तावों का उल्लेख कर सकते हैं ।

विश्व व्यापार के प्रसार के लिए अमेरिकी प्रस्ताव—जब द्वितीय विश्व-युद्ध अपनी प्रगति के चरम-स्तर पर था तो अमेरिकी सरकार ने उन आर्थिक एवं वित्तीय परिस्थितियों की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जो विश्व-युद्ध के बाद भी कायम रहनी थी । अमेरिका ने उन नीतियों एवं प्रक्रियाओं का भी उल्लेख किया जो सभी देशों के हितों में प्रयुक्त की जानी चाहिए ।

1945 के अन्तिम दिनों में ब्रिटिश तथा अमेरिकी अधिकारियों के बीच अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक एवं वित्तीय विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रुमैन (Truman) और प्रधानमन्त्री एटली (Attlee) ने एक संयुक्त-विज्ञप्ति प्रसारित की जिसमें अमेरिका के प्रस्तावों का उल्लेख किया गया। बाद में अमेरिका ने अन्य सरकारों के साथ भी इन समस्याओं के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया। प्रस्तावित सुझावों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सभा के तत्वावधान में व्यापार और रोजगार पर शीघ्र ही एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाने वाला था। फरवरी, 1946 में संयुक्त राष्ट्र सभा की आर्थिक और सामाजिक परिषद् ने अपनी प्रथम बैठक में इस प्रकार का सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन की समिति ने प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के चार्टर का प्रारूप तैयार किया। यह चार्टर संशोधित होते हुए मार्च, 1948 में अन्तिम रूप प्राप्त कर पाया। इसे हवाना चार्टर (Havana Charter) का नाम दिया जाता है।

अमेरिकी सरकार ने इस हवाना चार्टर को स्वीकार नहीं किया क्योंकि इसमें व्यापार को भारी प्रतिबन्धों, असमानताओं आदि से मुक्त करने के लिए सन्तोषजनक कदम नहीं उठाए गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका का यह मत था कि यदि ससार में स्वस्थ तथा प्रसार-पूर्ण व्यापार एवं उच्च जीवन स्तरों की स्थापना करनी है तो प्रतिबन्धों एवं नियन्त्रणों की कम से कम मात्रा तो अवश्य रहनी चाहिए किन्तु ये प्रतिबन्ध एवं नियन्त्रण केवल वे ही होने चाहिए जो बुद्धि के अनुकूल हैं दूसरी ओर अन्य दूसरे देशों का मत अमेरिका से भिन्न था। परिणामस्वरूप समझौतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया। इसके अनुसार चार्टर को स्वतन्त्र उद्योगों की बाधनीयता बुद्धिपूर्ण प्रतिस्पर्धा और बहुपक्षीय व्यापार पर आधारित रखते हुए अनेक उन्मुखियों एवं अपवादों की रचना की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में इन अपवादों के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण नहीं रहा और इसलिए इस चार्टर को अमेरिका की स्वीकृति प्राप्त न हो सकी।

गैट की स्थापना

(Establishment of GATT)

1947 में जेनेवा में 23 देशों ने एक बहुपक्षीय समझौते पर विचार-विमर्श किया और तटकर एवं व्यापार पर सामान्य समझौता किया। यह 1948 के प्रारम्भ से लागू किया गया। यह विचार-विमर्श उस समिति के साथ-साथ हुआ जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के चार्टर का प्रारम्भिक प्रारूप तैयार करने में सलग्न थी। समिति के सदस्य-देशों ने ही इस समझौते की वार्ताएँ की।

सामान्य समझौता होने के परिणामस्वरूप यह तय किया गया कि भाग लेने वाले देश तटकर एवं अन्य व्यापारिक बाधाओं में उल्लेखनीय रूप से कटौती कर लेंगे। इस समझौते में व्यापारिक नीतियों एवं प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में भी सामान्य उपबन्ध रखे गए और व्यापारिक सम्बन्धों में न्यायपूर्ण व्यवहार से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से स्वीकृत एक आचारसंहिता स्थापित की गई। इससे नियतांशों,

प्राथमिकताओं, आन्तरिक नियन्त्रणों, चुंगी, विनिमयों, राज्य व्यापार एवं सहायता आदि पर विचार किया गया। इसके प्रावधान मुख्य रूप से वे हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (ITA) चार्टर के चतुर्थ अध्याय में दिए गए हैं।

तटकरो एवं व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT) एक विधि न होकर ढीला-ढाला एक संगठन है जो कि सदस्यों की स्वेच्छापूर्ण सामूहिक स्वीकृति पर आधारित है। इसकी सदस्य संख्या प्रारम्भ में 23 थी जो बढ़ कर अब 83 हो गई है। यह उल्लेखनीय है कि नए देश को सदस्य केवल उसी स्थिति में बनाया जा सकता है जब दो तिहाई वर्तमान सदस्य इसके लिए अपनी सहमति दे देते हैं। सभी सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समझौते में दी गई आचार-संहिता का पालन करेंगे। इस समझौते के सदस्यों में विश्व के प्रमुख देश शामिल हैं, परन्तु सोवियत रूस, लालचीन एवं अधिकांश साम्यवादी देशों ने इसकी सदस्यता स्वीकार नहीं की है।

व्यापार एवं प्रशुल्क विषयक सामान्य समझौता एक ऐसी सन्धि है जिसके प्रति सभी सदस्य देशों का दायित्व रहता है। समय-समय पर सदस्य देशों के प्रतिनिधि मिलकर आपस में विचार-विमर्श करते हैं। यह एक ऐसी सन्धि है जो निम्नलिखित चार महत्वपूर्ण सिद्धान्तों पर आधारित है—

- (i) बिना किसी भेद-भाव के विभिन्न देशों के बीच विदेशी-व्यापार किया जाए,
- (ii) विदेशी-व्यापार को प्रभावित करने हेतु केवल तटकरों का ही सहारा लिया जाए,
- (iii) एक देश दूसरे देश के लिए दातिप्रद नीति अपनाने से पूर्व उस (दूसरे) देश से विचार-विमर्श करे तथा
- (iv) ऐसे कदम उठाए जाएँ जिनसे तटकरों (Tariffs) में परस्पर विचार-विमर्श के माध्यम से कमी की जा सके।

इस 'समझौते' को चार भागों में विभक्त किया गया है—पहले भाग में सदस्य देशों के प्रमुख कर्तव्यों का विवरण है, दूसरे भाग में न्यायपूर्ण व्यापार के लिए आचार-संहिता दी गई है, तीसरे भाग में सदस्य बनने एवं सदस्यता के परिस्त्राप से सम्बन्धित नियमावली दी हुई है और अन्तिम भाग में विकासशील देशों को दी जाने वाली विशेष रियायतों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परन्तु यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बदले में विकासशील देशों के लिए तटकरों में कमी करना आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त इन देशों को यह भी सुविधा दी गई है कि वे भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी कारणों से आयात कोटा निश्चित कर सकते हैं।

तटकरों एवं व्यापार के सामान्य समझौते के उद्देश्य (Objectives of GATT)

इस समझौते का मुख्य लक्ष्य तटकरों में पर्याप्त कमी करना एवं व्यापार के विस्तार में आने वाली बाधाओं को कम करके परस्पर लाभ पहुँचाने वाले निम्न-लिखित उद्देश्यों की पूर्ति करना है—

- (1) सदस्य देशों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना,

- (2) पूर्ण रोजगार की स्थापना हेतु अर्थव्यवस्था को अग्रसर करना,
- (3) वास्तविक आय और प्रभावशीलता के परिमाण में वृद्धि करना,
- (4) उत्पादन और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रसारण करना,
- (5) विश्व के स्रोतों का पूरा-पूरा उपयोग करना ।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्रकृति अत्यन्त सामान्य है । इस समझौते द्वारा इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रत्यक्ष रूप से कोई कार्यवाही नहीं की जाती है । जैसे कि गैट के किसी भी अनुच्छेद में उपरान्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कोई प्रावधान नहीं है । ऐसी मांगता की गई है कि विश्व के विभिन्न देशों के बीच व्यापार को बहुमुखी पद्धति पर आधारित करके इस प्रकार समायोजित किया जाए कि तटकरो में कटीनी करने इन्हें न्यूनतम स्तर पर ले आया जाए ताकि इन देशों के आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बल मिलता रहे तथा आय एवं रोजगार के स्तर में पर्याप्त सुधार हो ।

गैट के उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित तीन सिद्धान्त स्वीकार किए गए हैं—

1 विभेदात्मक नीति की समाप्ति या सत्रसे अधिकांश प्रिय देश का सिद्धान्त

विदेशी-व्यापार में विभिन्न देशों के मध्य विभेदात्मक नीति न अपनाई जाए इस हेतु समझौते में भाग लेने वाले राष्ट्रों ने सबसे प्रिय राष्ट्र का सिद्धान्त सभी आयातों और निर्यातों पर लागू करना स्वीकार किया है । इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा जैसा कि सबसे प्रिय राष्ट्र के साथ किया जाता है और किसी एक सदस्य देश को दी गई रियायत स्वयं ही अन्य सदस्य देशों के लिए भी उपलब्ध हो जाती है । इस प्रकार प्रशुल्क सम्मेलनों में यद्यपि दो देशों के बीच मन्त्रणा होती है तथापि इसके अन्तर्गत प्रशुल्क दरों में दी जाने वाली छूट समझौते के सभी सदस्य देशों को प्राप्त हो जाती है ।

फिर भी विशिष्ट मामलों में कठिनाइयाँ कम करने के उद्देश्य से कुछ परिस्थितियों में विभेदात्मक नीति अपनाने की छूट दी गई है । परन्तु ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसी भी नई प्राथमिकता का निर्माण नहीं किया जाएगा और न ही व्यापार में प्रचलित प्राथमिकताओं में ही वृद्धि की जाएगी । यद्यपि नई प्राथमिकताओं के अपनाने पर नियन्त्रण लगाया गया है, परन्तु पूर्ण प्राथमिकता वाली प्रस्तावी अपनाने वाली व्यवस्थाएँ—जैसे खुंगी सध, स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र आदि के निर्माण की अनुमति दी गई है, वशर्ते कि इनका उद्देश्य सदस्य देशों के मध्य व्यापार को प्रोत्साहित करने का हो न कि अन्य देशों के विरुद्ध व्यापार प्रतिबन्धों में वृद्धि करने का ।

2. आयात पर मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध

सिद्धान्त के रूप में सामान्य समझौता आयात कोटा के उपभोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाता है, परन्तु तीन अपवाद स्वरूप स्थितियों में इनकी छूट दी जाती है—

(अ) प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन वाले राष्ट्र आयात कोटा का आश्रय ले सकते हैं । परन्तु इनका उपयोग भुगतान सन्तुलन में गम्भीर प्रतिकूलता या ऐसी

प्रतिबलता को घटाने से रोकने के लिए ही किया जाना चाहिए, परन्तु आयात कोटों का इस रूप में उपयोग केवल अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अनुमति लेकर ही किया जा सकता है।

(ब) सामान्य समझौते की स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार विकासशील राष्ट्र आर्थिक विकास के उद्देश्य से मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगा सकते हैं।

(ग) कृषि एवं मत्स्य वस्तुओं के लिए आयात कोटों का निर्धारण केवल उस स्थिति में किया जाए जब इनका देश में उत्पादन उतने ही प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जा रहा हो।

3. तटकरों में कटौती या तटकर मन्त्रणाएँ

इस समझौते (GATT) के अन्तर्गत तटकरों में भी कमी करने का प्रावधान है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह आवश्यक है कि अनुबन्ध से सम्मिलित देश इस सिद्धान्त में विश्वास रखते हों कि तटकरों का व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विभिन्न देशों के बीच आयात और निर्यात सम्बन्धी मन्त्रणाओं द्वारा तटकरों एवं अन्य करों में कमी की जा सकती है। तटकर मन्त्रणाएँ सामान्यतः निम्नलिखित सिद्धान्तों पर आधारित होती हैं—

(i) आदान-प्रदान एवं परस्परता—ये मन्त्रणाएँ आदान-प्रदान के सिद्धान्त पर प्रत्येक वस्तु के लिए की जाती हैं। आदान-प्रदान से तात्पर्य उस भावना है जिसके अनुसार एक देश द्वारा यदि मन्त्रणा के दौरान कोई रियायत दी जाए तो उसे भी छूट प्राप्त करने का नैतिक अधिकार मिल जाता है।

(ii) तटकरों को सीमित करना—इन मन्त्रणाओं का प्रयोजन ऊँची प्रशुल्क दरों को कम करना और नीची प्रशुल्क-दरों के स्तर को बनाए रखना होना चाहिए। यह प्रावधान उन देशों के हितों की रक्षा हेतु रखा गया है जिनकी प्रशुल्क-दरें पहले से कम हैं और जो मन्त्रणाओं के दौरान कोई भी छूट देने में असमर्थ हैं।

(iii) प्राथमिकता दरें और प्राथमिकता मार्गिन—प्राथमिकता का मार्गिन नापने के लिए सबसे अधिक प्रिय देश के लिए निर्धारित प्रशुल्क-दर और उसी वस्तु के लिए प्राथमिकता दर के बीच विद्यमान वास्तविक अन्तर को देखना चाहिए न कि इन दोनों दरों का अनुपातिक सम्बन्ध। इस प्रकार यदि सबसे अधिक प्रिय देश की दर कम कर दी जाए तो प्राथमिकता का मार्गिन स्वतः ही कम हो जाएगा। इसके विपरीत यदि सबसे अधिक प्रिय देश की प्रशुल्क-दर बढ़ाई जाए तो प्राथमिकता का मार्गिन बढ़ जाएगा।

(iv) बंधी एवं खुली दरें—एक बार प्रशुल्क की जो दर अनुसूची में सम्मिलित कर ली जाती है तो उसमें किसी प्रकार की वृद्धि की गुंजाइश नहीं रह जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि GATT के परिशिष्ट में जिन प्रशुल्क रियायतों का वर्णन है—जिन्हें सामान्यतः बंधी हुई दरें कहा जाता है—वे 1948 से दिसम्बर 1950 तक प्रचलित रही। तीन वर्ष की इस अवधि के समाप्त होने पर यह नियम

अनुबन्ध से सम्बद्ध देश पर छोड़ दिया गया कि यह दूसरे पक्ष के साथ मन्त्रणा एव समझौते के माध्यम से उस रियायत को वापस ले ले अथवा उममे सशोधन कर दे। अब तक यही देखा गया था कि अनुमूची की अवधि बढ़ाने के लिए सभी सम्बन्धित पक्ष सहमत होते रहे हैं। परन्तु नई अवधि प्रारम्भ होने से पूर्व सम्बन्धित पक्षों को यह अवसर दिया जाता है कि वे प्रशुल्क दरों में छूट या सशोधन के लिए मन्त्रणा कर सकें।

गैट द्वारा जो तटकर सम्बन्धी कटौती की गई है वह जिन उत्पादनों पर लागू होती है वे समझौता करने वाले देशों के लगभग 2/3 आयात एव सम्पूर्ण विश्व-आयातों के लगभग आधे भाग की पूर्ति करते हैं। इस समझौते द्वारा कुछ करोड़ को पूरी तरह मिटा दिया गया है, कुछ को कम कर दिया गया है और जैसे के तंत छाड़ दिए गए हैं। तटकर सम्बन्धी प्राथमिकताओं को या तो घटा दिया गया है अथवा पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। समझौता करने वाला प्रत्येक पक्ष अन्य पक्षों को सभी प्रकार की रियायतें प्रदान करता है। सभी पक्षों के लिए समस्त तटकर कटौतियों का एक रूप में व्यवहार अत्यन्त लाभदायक है।

सामान्य समझौते में तटकर सम्बन्धी रियायतें पहले सा द्विपक्षीय रूप से वाता का विषय बनी थीं। प्रत्येक देश ने एक वस्तु को लिखा और उसका प्रमुख पूर्तिकर्ता देश के साथ विचार-विमर्श किया। इस प्रकार जिन रियायतों पर विचार किया गया उन्हें समझौते की अनुमूची में स्थान दे दिया गया और उसे सभी देशों पर लागू किया गया। संयुक्तराज्य अमेरिका ने इससे पहले भी उन विभिन्न देशों के साथ पारस्परिक व्यापारिक समझौते कर रखे जा चुके थे सामान्य समझौते के पक्ष में हैं। ऐसी स्थिति में इसके सारे पूर्व समझौते अब स्थानान्तरित हो चुके हैं। सामान्य समझौते के गैर सदस्यों के साथ अमेरिका ने जो समझौते किए थे वे अब भी कायम हैं।

सामान्य समझौता प्रावधिक रूप से 1 जनवरी, 1948 से व्यवहार में आया। यह संयुक्तराज्य अमेरिका और 8 अन्य देशों के बीच लागू हुआ और तुरन्त बाद ही कुछ अन्य देश भी इसमें सम्मिलित हो गए। 1951 में इसके सदस्यों की संख्या 31 थी तथा अब 83 हो गई है।

सामान्य समझौता किसी ऐसे स्थायी संगठन या सचिवालय की स्थापना नहीं करता जो एक प्रविण्य का कार्य कर सके। इसके विपरीत समझौता करने वाले पक्ष बैठकें करते रहते हैं और आवश्यकता के अनुसार समझौते को सशोधित करते रहते हैं। इस प्रकार की बैठकों में अतिरिक्त तटकर सम्बन्धी कटौती पर विचार-विमर्श किया गया। 1949 में ऐनेसी (Annecy, France) और 1950-51 में टोरक्ये (Torquay, England) में विचार-विमर्श किए गए। इनमें नए देशों ने भी भाग लिया।

सामान्य समझौते में एक ऐसा प्रावधान (Most Favoured Nation Clause) है जो इसका आधारभूत तत्त्व माना जा सकता है। इस प्रावधान का उद्देश्य

किसी भी राज्य के विरुद्ध भेद-भाव अथवा उसके साथ पक्षपात करने के लिए प्राथमिकताओं की स्थापना को रोक रखा जाता है। यह प्रावधान प्रत्येक राज्य के लिए अत्यन्त महत्व रखता है क्योंकि दूसरे राज्य के लिए भी यदि रियायत अथवा गारण्टी इस प्रकार की होती है कि विश्व बाजारों में उसे तुलनात्मक रूप से हानि न रहे।

तटकरों में कटौती

तटकरों में कटौती सामान्य समझौते का एक महत्वपूर्ण भाग है जो व्यापक लक्ष्यों की प्राप्ति का एक प्रमुख साधन है। तटकरों में कटौती करने की दृष्टि से जो समझौते किए गए उनमें 1947 (जेनेवा में), 1949 (एनेसी में), 1951 (टोरके में), 1956 (जेनेवा में), और 1960-61 (जेनेवा में) में किए गए समझौते मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। इन समझौतों के प्रतिरिक्त कुछ अन्य छोटे स्तर की समझौता-वार्ताएँ भी हुई हैं। इन वार्ताओं के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की हजारों वस्तुओं पर से तटकरों को काट दिया गया। इसके प्रतिरिक्त अनेक समझौते करने वाले पक्षों ने व्यापार के व्यापक क्षेत्र पर प्रशुल्क दरों को एक जैसा रखने के बारे में सहमति प्रदान की ताकि तटकर की दरों में अचानक वृद्धि के भय को दूर किया जा सके।

वर्तमान काल में विनिमय नियन्त्रण एवं अनुज्ञापिका तथा नियन्त्रण आदि के कारण विश्व व्यापार की बाधाओं के रूप में तटकरों का महत्व बहुत कुछ घट गया है। समझौता करने वाले पक्षों ने जो रियायतें प्रदान की हैं उनका अधिकांश प्रभाव मात्रागत प्रतिबन्धों के व्यापक प्रयोग के कारण बेकार सिद्ध हुआ। इस दृष्टि से देखने पर यह लगता है कि तटकरों को कम करने में गैट की प्राप्ति जितनी दिखती है वास्तव में उतनी नहीं है। इतने पर भी प्रशुल्कों के सामान्य स्तर को नीचा करने से जो लाभ प्राप्त हो सकते हैं उनको नहीं मिलाया जा सकता। जो देश मात्रागत प्रतिबन्धों का प्रयोग नहीं करते उनके लिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इसके प्रतिरिक्त इसने जिस वातावरण की रचना की वह मात्रागत नियन्त्रणों और विश्व व्यापार की अन्य बाधाओं में कटौती के लिए अत्यन्त सहायक रहा है।

तटकर सम्बन्धी वार्ताओं के महत्वपूर्ण नियम (Important Rules of Tariff Negotiations)

तटकरों की कटौती सम्बन्धी वार्ताओं में कुछ नियमों का पालन किया जाना जरूरी समझा गया है ताकि वह अधिक से अधिक फलदायक सिद्ध हो सके। इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण नियम निम्न प्रकार हैं—

1. जब कभी तटकरों में कटौतियों से सम्बन्धित वार्ताएँ की जाएँ तो वे पारस्परिक लाभों के आधार पर होनी चाहिए। इस सामान्य समझौते में किसी पक्ष से यह नहीं कहा जाता कि वह तटकरों में एकपक्षीय कटौतियाँ करें।
2. जिस समय समझौता-वार्ता की जाती है वे या तो कुछ विशेष उत्पादनों को छूटकर उन पर की जाती हैं अथवा उन तकनीकों पर की जाती हैं जिन्हें सम्बन्धित समझौते के पक्ष स्वीकार करते हैं। अभी तक जो वार्ताएँ की गई हैं वे

प्रायः चुने हुए उत्पादनों के आधार पर की गई हैं। इस प्रक्रिया में समझौता करने वाले पक्ष विशेष उद्योगों को ध्यान में रख सकते हैं। अन्तिम निर्णय तक पहुँचने में प्रत्येक समझौता करने वाला पक्ष प्रस्तावित रियायतों से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करके देखता है। यदि समस्त उत्पादनों की दृष्टि से उसे लाभ होता है तो वह प्रस्तावित कर्तवियों को स्वीकार कर लेता है।

3 तटकरो की कटौतियों से सम्बन्धित वार्ताएँ तटकरो को घटाने के लिए अथवा निम्न तटकर रखने के लिए अथवा तटकर की सीमा निर्धारित करने के लिए की जाती है। जिस प्रकार उच्च करो को घटाना महत्वपूर्ण समझा जाता है उसी प्रकार निम्नतर करो को बनाए रखना भी महत्वपूर्ण समझा जाता है। यह प्रावधान उन निम्न तटकर वाले देशों के हितों की रक्षा करता है जिनके पास समझौता-वार्ता में देने के लिए कुछ भी नहीं होता। निम्न तटकरो की वाध्यता का एक लाभ यह है कि इससे व्यापारियों को यह आश्वासन रहता है कि निम्न तटकर जारी रहेंगे और वे अपने उत्पादन को बढ़ाने की योजनाओं को प्रशुल्को की अचानक वृद्धि के जालिम के बिना क्रियान्वित कर सकेंगे।

4 प्राथमिकता के सीमान्त में वृद्धि को निषिद्ध बना दिया गया है। यदि प्राथमिक दर को घटाया जाता है तो उसके साथ सर्वाधिक पक्षपात पूर्ण राष्ट्र की दर में भी कमी करना जरूरी बन जाता है। किसी भी एक पक्ष में कटौती नहीं की जा सकती।

5 जब एक समझौते का पक्ष तटकरो के नए स्तर पर राजी हो जाता है तो वह उसे अपनी अनुसूची में सम्मिलित कर लेता है। उसके बाद वह उसमें वृद्धि नहीं कर सकता। जो मई अनुसूची के बाहर हैं उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा और परिस्थितियों के अनुसार इन तटकरो को बढ़ाया जा सकता है। जहाँ तक समझौता करने वाले पक्षों का प्रश्न है उनके साथ किसी प्रकार का असमानता का व्यवहार नहीं किया जा सकता।

■ सामान्य समझौते के आधार पर यह विश्वास किया जाता है कि समझौता करने वाला प्रत्येक पक्ष सद्-विश्वास के साथ कार्य करेगा और अपनी सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रशुल्क समझौतों को विरुद्ध सर्वपक्षपूर्ण वार्यवाही नहीं करेगा।

तटकर सम्बन्धी समझौतों के बारे में उपर्युक्त नियमों का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि तटकरो एव व्यापार के सामान्य समझौते (GATT) के अन्तर्गत विभिन्न देश अपने तटकरो में कटौतियाँ करते समय किन किन नियमों का पालन करेंगे? इन नियमों के अतिरिक्त कुछ अन्य बातें भी हैं जो कि इस सामान्य समझौते द्वारा उपयुक्त समझी जाती हैं। यह आशा की जाती है कि समझौता करने वाले पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर से मात्रागत प्रतिबन्धों को समाप्त करेंगे। यदि वे मुक्तानों के सन्तुलन की कठिनाइयों से पीड़ित हैं तो बात दूसरी है। वास्तविक व्यवहार को देखने से प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि मुक्तान सन्तुलन की कठिनाइयाँ इतनी गम्भीर हैं जितनी गैट (GATT) के स्थापकों ने सोचा भी न था।

गैट ने मानागत प्रतिबन्धों की समस्या पर यथार्थवादी तरीके से विचार किया है। ये अव्यावहारिक कठोर योजनाओं की अपेक्षा दवावों और निरन्तर विचार-विमर्श के बाद मानागत प्रतिबन्धों को कम करने में प्रयत्नशील हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ अनुचित व्यवहार होने पर भी आयात और निर्यात प्रतिबन्धित हो जाता है। यदि आयातित माल पर कर बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रभाव भी वही होगा जो तटकर की दरों को बढ़ाने का होता है; इस प्रकार के अनुचित व्यापार के व्यवहारों को रोकने की दृष्टि से सामान्य समझौते में उचित व्यवहारों की एक व्यापक व्यापारिक आचार-संहिता को सम्मिलित किया गया है। इस संहिता ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में द्वितीय विश्व-युद्ध द्वारा निमित्त अराजकता एवं अव्यवस्था को मिटा कर व्यवस्था की स्थापना की है।

तटकरों एवं व्यापार पर सामान्य समझौते ने समझौता करने वाले पक्षों के बीच झगड़ा निपटाने में भी पर्याप्त योगदान किया है। समझौते के अनुच्छेद 23 के प्रावधानों के अनुसार समझौते का कोई पक्ष अन्य पक्षों के सामने यह शिकायत कर सकता है कि प्रमुख पक्ष ने समझौते की शर्तों के प्रतिकूल व्यवहार किया। यदि समझौते के पक्षों को यह विश्वास हो जाए कि सम्बन्धित समझौते के पक्ष प्रत्यक्ष विचार-विमर्श के बाद किसी निराय पर नहीं पहुँच पाए हैं और उन्हें सफलता नहीं मिल पाई है तो दुरन्त ही वे विषय की छान-बीन और उचित सिफारिशें करके अथवा विषय के सम्बन्ध में अपना मत प्रस्तुत करेंगे।

समझौते के पक्ष प्रत्यक्ष रूप से शिकायतों पर विचार करने की अपेक्षा यह काम एक पैनल को सौंप देते हैं। वह पैनल कोई स्थायी संस्था नहीं होती और न इसका कोई पूर्व-निर्धारित सविधान होता है। यह प्रत्येक मामले के लिए सामयिक रूप से स्थापित की जाती है। समझौते में भाग लेने वाले देश चार या पाँच ऐसे व्यक्तियों को पैनल का सदस्य घोषित कर देते हैं जिनकी सेवाएँ गैट में काफी मांगता प्राप्त कर चुकी हैं। ये सदस्य प्रायः छोटे देशों के प्रतिनिधि होते हैं क्योंकि वे ही अधिक वस्तुगत और निष्पक्ष हो सकते हैं। बड़ी शक्तियों के राष्ट्रीय हित इतने व्यापक होते हैं कि वे विश्व के किसी भाग में घटने वाली किसी भी घटना से प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थिति में उनके निष्पक्ष होने का प्रश्न नहीं उठता। पैनल में झगड़ा करने वाले देशों को सम्मिलित नहीं किया जाता। यह दोनों पक्षों तथा किसी भी इच्छुक तीसरी पार्टी को सुनती है। प्रायः पैनल की कार्यवाही के दौरान झगड़ों का सुलझा दिया जाता है। यदि ऐसा नहीं हो पाता तो सम्बन्धित पक्षों को सुनने के बाद पैनल की कार्यवाहियाँ गुप्त रूप से होती हैं और वह एक प्रारूप प्रतिवेदन के रूप में निराय पर पहुँचती है। सम्बन्धित पक्षों को इस प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार प्रकट करने के लिए आमन्त्रित किया जाता है और इन विचारों के प्रकाश में पैनल अपने प्रतिवेदन को बदल सकता है।

यह प्रक्रिया जगती तो ऐसी है जैसे न्यायिक हो, किन्तु यह उससे कई बातों में भिन्नता रखती है क्योंकि यहाँ झगड़ा करने वाले पक्षों को प्रतिवेदन तैयार होने पर

(i) इसके द्वारा समझौता करने वाले पक्षों को यह शक्ति प्रदान कर दी जाती है कि वे चुनौतीपूर्ण संघों के नाम पर प्राथमिकतापूर्ण समझौते के विकास को रोक सकें।

(ii) वे सम्बन्धित पक्षों को संघ की स्थापना एवं कार्य-प्रणाली में निर्देशित कर सकते हैं।

सामान्य समझौते में वर्णित भाषण के अनुसार परीक्षा करने के बाद समझौते के पक्षों ने कुछ चुनौतीपूर्ण संघों की रचना की सम्मति प्रदान की। इस दृष्टि से यूरोपीय आर्थिक समाज (European Economic Community), यूरोपीय स्वतन्त्र व्यापार संस्था (European Free Trade Association), लैटिन अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार संस्था (Latin American Free Trade Association) आदि का नाम लिया जा सकता है।

स्पष्ट है कि गैट ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं तटकर्णों के सम्बन्ध में अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की विभिन्न समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा को बढ़ाने में उल्लेखनीय कार्य किया है।

विकासशील देशों पर प्रभाव

गत 16 वर्षों में सामान्य समझौते के तहत विकासशील देशों की विशेष व्यापार समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस सम्बन्ध में एक तो अर्द्ध-विनसित अर्थात् विकासशील देशों के लिए समझौतों के उत्तरदायित्वों को पूरा करने में अधिक शोचदार दृष्टिकोण अपनाया गया है तथा दूसरे व्यापार विकास कार्यक्रम की भी विशेष व्यवस्था की है। लोगों की यह आलोचना, कि अर्द्ध-विकसित देशों को लाभान्वित करने की दिशा में गैट का कार्य सीमित रहा है और गैट केवल विकसित तथा धनी देशों का ही सपना रहा है जो अपनी इच्छानुसार इनके समझौते के रूप को मोड़ देते रहे हैं, निरर्थक है। 8 फरवरी, 1965 को गैट की एक विशेष बैठक हुई जिसमें व्यापार एवं विकास के एक नए अध्याय की स्वीकार किया गया। इस अध्याय के अनुसार विकसित और विकासशील दोनों देशों को एक स्तर पर रखा गया है और यह निश्चित किया गया कि गैट एक अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच समन्वय व सहयोग स्थापित किया जाए जिससे विकास में सहायता प्राप्त की जा सके। संक्षेप में विगत कुछ वर्षों में गैट के सदस्यों ने अपना अविकसित समय व्यापार और आर्थिक विकास के मध्य सम्बन्धों का अध्ययन करने में व्यतीत किया है।

गैट द्वारा प्रकाशित धाँकडों के अनुसार मार्च 1968 से लेकर जून 1968 तक विकासशील देशों के निर्यातों में सन्तोषजनक वृद्धि हुई थी। गैट के सचिवालय के अनुमानों के अनुसार इन देशों के निर्यातों में 1968 के प्रथम 6 मास में लगभग 8% की वृद्धि हुई थी जबकि 1967 की अवधि में यह वृद्धि 2% से भी कम थी। दूसरी ओर विकासशील देशों के आयातों में केवल 5% की ही वृद्धि हुई थी। यह प्रवृत्ति विकासशील देशों के लिए हितकर सिद्ध होगी तथा विकासशील देशों का आर्थिक विकास तीव्र गति से हो सकेगा।

परन्तु विकासशील देशों के सम्बन्ध में गैट के अन्तर्गत बहुत ही धीमी गति से प्रगति होती है। आज भी गैट में वणिज्य व्यापार पात्रनिर्धार विद्यमान हैं। विकसित देश न तो तटकरो में कटौती हेतु कोई स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने को तैयार हैं और न ही विकासशील देशों में सम्बन्धित आर्थिक समस्याओं के सम्बन्ध में कोई स्थायी समाधान करना चाहते हैं।

वैसे गैट की व्यापार एवं विकास समिति ने विकासशील देशों की समस्याओं को अनुभव करते हुए और अधिक प्रभावपूर्ण प्रयास करने की दृष्टि से कई कार्यों का शुभारम्भ किया है जैसे त्रिभुज देशों की विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करना। इन समीक्षाओं से योजनाओं में आवश्यक सुशोधन करने, विदेशी सहायता एवं निर्यात नीति में समन्वय स्थापित करने तथा विकासशील राष्ट्रों को एक दूसरे की आयात सम्बन्धी जरूरतों और निर्यात के लक्ष्यों से अवगत कराने आदि में सहायता मिलती है।

गैट एवं भारत—प्रारम्भ से ही भारत गैट का एक सक्रिय सदस्य रहा है। भारतीय प्रतिनिधियों ने न केवल गैट के अन्तर्गत आयोजित तटकर मन्त्रणियों में भाग लिया है वरन् विकासशील देशों की समस्याओं को भी समितियों की बैठक में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। परन्तु भारत जैसे विकासशील देश अपनी प्रतियोगितात्मक शक्ति बढ़ाकर ही गैट से पूर्णतः लाभान्वित हो सकते हैं, चाहे यह शक्ति आन्तरिक आर्थिक अनुशासन से प्राप्त की जाए अथवा विदेशों में हमारी विनय-कला के श्रेष्ठतम प्रदर्शन द्वारा प्राप्त की जाए। यह भी आवश्यक है कि देश में बढ़ती हुई उत्पादन लागत और कीमतों को नियन्त्रित किया जाए।

सामान्य समझौते के दोष (Defects of GATT)

तटकरो एव व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT) के उद्देश्य काफी अच्छे होने पर भी इसमें ऐसे अनेक दोष हैं जिनके कारण निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। ये दोष निम्न प्रकार हैं—

(1) सामान्य नियम का बनाना असम्भव—गैट की सदस्यता बहुत विस्तृत होने के कारण सामान्य नियम बनाना सम्भव नहीं है। आर्थिक उद्देश्यों की राजनीतिक उद्देश्यों के साथ टकराव होने के कारण उचित नियमों का विरोध भी सदस्यों द्वारा किया जाता रहा है।

(2) मात्र अच्छे आचरण की संहिता—यद्यपि यह सत्य है कि गैट सदस्यों के आपसी झगड़ों का निवटारा व बातचीत करने का अवसर प्रदान करता है परन्तु उसको किसी प्रकार का कोई सार्वभौम प्रभुत्व प्राप्त नहीं है। जिससे सदस्यों द्वारा छूट धाराओं का अपने निजी स्वार्थों को सुरक्षित रखने के हेतु दुरुपयोग किया गया है। सदस्यों के बीच झगड़ें निबटाने में असफलता का सबसे उत्तम उदाहरण अमेरिका का है जिसने गैट के लगातार कहने पर भी दूध व मक्खन से बनी हुई वस्तुओं के आयातों पर लगे प्रतिबन्धों को समाप्त नहीं किया। इन असफलताओं के कारण ही यह कहा जाता है कि गैट अच्छे आचरण की संहिता मात्र बनकर रह गया है।

(3) परिमाणात्मक प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में असफलता—उन परिमाणात्मक प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में, जिन्हें कोई देश अपने सीमित विदेशी विनिमय कोषों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से लगाता है, गैट को अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। प्रायः ऐसा देखने में आया है कि देश की मुग्तान स्थिति में सुधार हो जाने के पश्चात् भी आयातों पर परिमाणात्मक प्रतिबन्ध पहले के समान विद्यमान रहते हैं। गैट की इस असफलता का मुख्य कारण यह है कि इसके पास समझाने के प्रतिरिक्त दूसरा कोई प्रभावशाली हथियार नहीं है जिसका उपयोग करके यह सदस्य देश को उसकी मुग्तान-सन्तुलन स्थिति में सुधार हो जाने पर प्रतिबन्धों को समाप्त करने पर विवश कर सके।

(4) भेद-भाव उत्पन्न करना—सदस्यों के बीच वास्तविक वस्तु से वस्तु पर आधारित होने के कारण परस्पर व्यापार के पक्ष में और तीसरे पक्ष के विपक्ष में भेदभाव स्वाभाविक परिणाम के रूप में पैदा हो जाता है।

(5) प्रतिनिधि संस्था नहीं—चूंकि साम्यवादी गुट के अधिकांश देश तथा अधिकांश नए स्वाधीनता-प्राप्त विकासशील देश इस संस्था के सदस्य नहीं होने के कारण गैट विश्व की प्रतिनिधि संस्था नहीं बन पाई है।

(6) विकासशील देशों के हितों की उपेक्षा—विकासशील देशों का विचार है कि गैट केवल विकसित और धनी देशों का ही ऐसा संघ रहा है जिसमें अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखा जाता रहा है। विकासशील देशों को लाभान्वित करने की दिशा में गैट का कार्य सीमित रहा है।

गैट के नियम विकासशील देशों के लिए विशेष महत्व की वस्तुओं के सम्बन्ध में लागू नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए सूती कपड़े के निर्यातों का नियमन 1962 में बनाए गए विशेष नियमों के अन्तर्गत किया जाना है। इन नियमों के अनुसार विकासशील देशों को अपने निर्यातों पर आयातकर्त्ता देश के कहने पर ऐच्छिक प्रतिबन्ध लगाने के लिए बाध्य किया जा सकता है।

गैट का भविष्य

यद्यपि गैट की उपसन्धियाँ कम रही हैं फिर भी इसका भविष्य अच्छा है। परन्तु इस सम्बन्ध में ज्यादा आशावादी नहीं हुआ जा सकता है। कारण यह है कि भविष्य में जिन समस्याओं का गैट को समाधान करना होगा वे सरल नहीं हैं। गैट के समान संगठन द्वारा, जिसके सदस्य विकसित व अविकसित देश, कृषि-प्रधान तथा औद्योगिक देश, अनुभूत व प्रतिकूल मुग्तान-सन्तुलन वाले देश हैं तथा जिनके आर्थिक हित ज्यादातर परस्पर विरोधी हैं, अपनी नीतियों द्वारा भिन्न सदस्यों के भिन्न हितों के मध्य समन्वय करना कठिन कार्य है। फिर भी गत 31 वर्षों के गैट के कार्य-निष्पादन को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि गैट सदस्यों की

आवश्यकताओं और उनके हितों के प्रति जागरूक है तथा कुशल अधिकारियों द्वारा अपनी नीति को कार्यान्वित करके सन्तुलित विश्व व्यापार और आर्थिक विकास के कार्य में बहुमूल्य अश्रदान दे सकेगा।

भारत सरकार की 1977-78 की रिपोर्ट के अनुसार गैट-कार्यकलाप

भारत सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 1977-78 के अनुसार समीक्षाधीन वर्ष में गैट (GATT) के कार्यकलाप निम्नानुसार रहे—

गैट का वार्षिक सत्र

गैट के सविदाकारी पक्षकारों का 33 वाँ सत्र 29 और 30 नवम्बर 1977 तक जेनेवा में हुआ था। इस सत्र से सविदाकारी पक्षकारों को यह अवसर मिला कि वे नवम्बर 1976 में हुए 32 वें सत्र के बाद अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में हुई मुख्य गतिविधियों की समीक्षा कर सकें तथा उन प्रतिवेदनो पर विचार कर सकें जिन्हें गैट परिषद्, व्यापार तथा विकास सम्बन्धी समिति और वस्त्र समिति ने, जो कि गैट के मुख्य कार्यपालक अंग हैं, सविदाकारी पक्षों को प्रस्तुत किया था। भारत ने सत्र की चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया।

"18" का गैट परामर्शी समूह

जुलाई 1975 में स्थापित "18" का गैट परामर्शी समूह बार-बार बैठकें करता रहा है। जब से विशेषज्ञ समूह गठित हुआ है, तभी से भारत इसका सदस्य रहा है। यह समूह सामान्य करार के उद्देश्यों तथा सिद्धान्तों के अनुकूल व्यापार नीतियों का पालन करने तथा उन्हें बनाए रखने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक स्थिति में हुई घटनाओं की समीक्षा करता है। इस समूह द्वारा जिन मुख्य विषयों पर विचार-विमर्श किया गया, उनमें से एक मुख्य विषय विश्व व्यापार की चलाने की अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से कुछ गैट नियमों तथा प्रक्रियाओं में परिवर्तन ही की सम्भावनाओं से सम्बन्धित है। इन विचार-विमर्शों के फलस्वरूप बहु-पक्षीय व्यापार वार्ताओं के अन्तर्गत एक व्यवस्था समूह की स्थापना हुई।

वस्त्रों (चतुर्दशा प्रबन्ध) में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बन्धित गैट प्रबन्ध

वस्त्रों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रबन्ध का नवीनीकरण और आगे के चार वर्षों के लिए किया गया है। यह चतुर्दशा प्रबन्ध के नाम से प्रसिद्ध है तथा 31 दिसम्बर 1977 को समाप्त हो गया था। यह नवीकरण 1977 में आयातक एवं निर्यातक देशों के बीच अनेक बैठकों के परिणामस्वरूप हुआ और भारत इन वार्ताओं में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है क्योंकि उसे वस्त्र तथा वस्त्र उत्पादों के निर्यात में अत्यधिक दिलचस्पी है। वार्ताएँ इस पृष्ठभूमि पर आयोजित की गई थी कि कुछ आयातक देशों ने तीव्र मन्दी के कारण, जिससे वस्त्र उद्योग में बहुत बेरोजगारी

फैल गई थी, वस्त्रों के बारे में संरक्षणात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया था। नवीनीकृत एम. एफ. ए. को स्वीकार करके विकासशील देशों ने प्रबन्ध में निर्धारित सिद्धान्तों को प्रभावहीन होने से रोकने में सफलता प्राप्त की है और साथ ही प्रांतीय देशों के वस्त्र उद्योग में चल रही मंदी की स्थिति के प्रभाव का मानकर प्रांतीय देशों को सुविधाएँ देने की व्यवस्था की है। सन्तुसार विकासशील देश इस बात के लिए सहमत हो गए हैं कि कुछ मामलों में जो मुख्यतः वृद्धि दर से सम्बन्धित हैं, सिद्धान्तों से अस्थायी रूप से हट जाना इस समझौते के आधार पर स्वीकार्य होगा कि यह केवल छोटी अवधि के लिए होगा तथा मूलतः अस्थायी समस्याओं से निपटने के लिए होगा।

सं० रा० अमेरिका तथा यूरोपीय प्रांथिक समुदाय दोनों के साथ अपनी द्विपक्षीय वार्ताओं में, जिन्हें स्वयं एम. एफ. ए. पर बिहार-विमर्श करने के लिए साँघ-साँघ प्रारम्भ किया गया था, इन आधार स्तरो से सम्बद्ध सिद्धान्तों और हाथ-करघा उत्पादों को दिए गए व्यवहार को सफलतापूर्वक ज्यों की त्यों रख सकें। संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले में हम एम.एफ. ए. में निश्चित वृद्धि दर से ऊँची दर प्राप्त करने में समर्थ रहे हैं जबकि यूरोपीय प्रांथिक समुदाय के मामले में कुछ नाजुक वर्गों के विषय में वृद्धि दर कम है। इस बात को मान भी लिया जाए कि कोटे में सभी देशों से निर्मित माल शामिल होगा, तब भी क्लाइड, कमीजें, टी-शर्ट, स्कर्ट, पोशाक, टेरि-टावेनिंग, विस्तर तथा मेजपोश आदि जैसी प्रमुख निर्यातमदों के लिए इन देशों से जो कोटे हमने प्राप्त किए हैं वे इन मदों के हमारे पिछले निर्यातों की अपेक्षा काफी अधिक हैं। उदाहरण के लिए, यूरोपीय प्रांथिक समुदाय के मामले में कमीजों तथा क्लाइडों के सम्बन्ध में 1978 के लिए कोटा लगभग 525 लाख अर्द्ध का होगा जबकि पिछले वर्ष के अन्तर्गत 400 लाख अर्द्ध का कोटा उपलब्ध होता था। संयुक्तराज्य अमेरिका के मामले में भी परिधान तथा बने बनाए वस्त्रों के लिए 1978 में कोटा 1862 लाख वर्ग गज होगा जबकि 1976-77 में हमारे निर्यात 1187 वर्ग गज थे।

इसी प्रकार आस्ट्रिया, फिनलैंड, नार्वे तथा स्वीडन आदि देशों के साथ वस्त्रों के बारे में द्विपक्षीय करार करने के लिए वार्ताएँ चल रही हैं।

विकासशील देशों के बीच अधिमान्य व्यापारिक प्रबन्ध

विकासशील देशों के बीच अधिमान्य व्यापारिक प्रबन्धों के बारे में जोनाल सलेव 1973 में लागू हुआ था, भारत उसका सदस्य है। 16 विकासशील देश इस समय विनिर्दिष्ट मदों पर टैरिफ रियायतों का आदान-प्रदानकरके अधिमान्य प्रबन्ध में भाग ले रहे हैं। हमने 27 मदों पर रियायतों का आदान-प्रदान किया है। अन्य भाग लेने वाले देशों ने भारत को जो रियायतें देनी स्वीकार की हैं, सामान्यतः गैर परम्परागत क्षेत्र के विषय में हैं जैसे स्टीम टर्बाइन, जनरेटर ट्रान्सफार्मर, सांकेतिक टेलीफोन सट, हाइड्रोलिक सीमेंट, विटामिन, कुछ रसायन, एल्युमिनियम छड़ें तथा शीट, हाथ के ओजार, स्टीम बायलर आदि रियायतों की दर एम. एफ. एन. दरों के 10 से 50

प्रतिफल के बीच हैं। भारत की निर्यात स्वर्धन परिपक्व और अन्य निर्यात स्वर्धन संगठनों ने विनिर्दिष्ट मंदों के विषय में सम्बन्धित बाजार को हमारे निर्यात बढ़ाने के लिए मलेख के अन्तर्गत उपलब्ध रियायतों का व्यापक प्रचार करने का कार्य सम्भाला है।

तब से अनेक अन्य विकासशील देशों ने हम बीच विकासशील देशों के मध्य गैट व्यापार वार्ताओं में सम्मिलित होने की अपनी दिलचस्पी प्रकट की है और उनमें से कुछ देशों ने पहले ही अपने निर्यात हित की अनुरोध सूची में परिचालित कर दी हैं। ऐसा एक देश रूमानिया है जिसने सलेख में प्रवेश के लिए सक्रिय वार्ताएँ आरम्भ कर दी हैं। भारत ने रूमानिया के साथ दिसम्बर 1977 में बातचीत पूरी की जिसमें रूमानिया हमारी दिलचस्पी की 26 मंदों पर टैरिफ रियायत देने के लिए सहमत हो गया, जबकि हमने ऐसे मंदों के सिवाय जोकि पहले ही सलेख के अन्तर्गत हमारी रियायत सूची में विद्यमान हैं, किसी भी अन्य मंद पर रियायत नहीं दी है। भारत ऐसे अन्य विकासशील देशों के साथ जो बाद में वार्ताओं में शामिल हो जाए, उन रियायतों का आदान-प्रदान करना चाहता है पर यह इस बात पर निर्भर है कि हमें उससे जितना व्यापारिक लाभ होगा।

ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि विकासशील देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए तथा उनके बीच वर्तमान आर्थिक सहयोग सुदृढ़ करने के लिए अधिमान्य करार का उपयोग किया जाए। सलेख के अन्तर्गत आने वाले उत्पादों की संख्या बढ़ाने के लिए और टैरिफ कटौतियों को बढ़ाने के लिए वार्ताओं का एक और दौर करने का प्रस्ताव है।

बहु-पक्षीय व्यापार वार्ताएँ

सितम्बर, 1973 में टोकियो में आयोजित गैट सदस्य देशों की मन्त्रिस्तरीय बैठक के फलस्वरूप बहुपक्षीय व्यापार वार्ताएँ आरम्भ हुईं। 14 सितम्बर, 1973 को इस बैठक में एक घोषणा स्वीकार की गई जो टोकियो घोषणा के नाम से जानी जाती है। इन वार्ताओं का उद्देश्य विश्व व्यापार का विस्तार करना तथा उसे और अधिक उदार करना और विकासशील देशों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रतिरिक्त लाभ प्राप्त कराना है ताकि अन्य बातों के साथ साथ उनकी विदेशी मुद्रा आय में काफी वृद्धि हो सके तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके।

यद्यपि 1975 के अन्त तक वार्ताएँ पूरी करने का इरादा था, तथापि विकसित देशों में मन्त्री की जो प्रवृत्ति 1974 में दिखाई दी उसके कारण आज तक अधिकांश क्षेत्रों में प्रगति बहुत थोड़ी हुई तथापि जुलाई 1977 में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने बहुपक्षीय व्यापार वार्ताएँ चालू करने के लिए संयुक्त रूप से प्रारम्भिक कार्यवाही शुरू की तथा 1978 के मध्य तक वार्ताएँ पूरी करने के उद्देश्य से समय-सारणी तैयार की। परिणामस्वरूप वार्ताओं में कुछ प्रगति आई है।

सम्मत समय-अनुसूची के अनुसार विकसित देशों ने जनवरी, 1978 में टैरिफ समूह तथा कृषि समूह दोनों में अपने आँफर प्रस्तुत किए हैं। टैरिफ समूह में तो वार्ताएँ चतुर्दिक कटौती के आघार पर होगी, पर कृषि समूह में मदवार कार्यविधि अपनाई जाएगी जो आँफर दिया गया है उनके आघार पर कटौती करने के लिए टैरिफ फार्मूला औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है, तथापि यह दिखाई देता है कि सामान्यतः 40 प्रतिशत की कमी की जाएगी। विकासशील देशों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विकसित देश फार्मूला कटौतियों से अधिक कटौती लागू करके विकासशील देशों के पक्ष में विशेष तथा भिन्न व्यवहार प्रदान करने के लिए सहमत हैं।

अन्य क्षेत्रों में, विशेषकर संरक्षण तथा सरकारी खरीद में जहाँ संहिताएँ तैयार करने पर विचार किया जा रहा है, वार्ताओं की गति तेज करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

बहु-पक्षीय व्यापार वार्ताएँ अब निश्चय की स्थिति में पहुँच गई हैं। भारत के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करने के निमित्त सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं।



उद्देश्य से कुछ राष्ट्र परस्पर व्यापार करना आरम्भ कर दें तो उनके मुक्त अथवा स्वतन्त्र व्यापारिक आदान-प्रदान में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उन्हें इस लाभ से वंचित कर देगा। वास्तव में मुक्त व्यापार के सिद्धान्त को हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अर्थ-विभाजन के सिद्धान्त का विस्तार मात्र कह सकते हैं। एडम स्मिथ ने कहा था कि "व्यक्ति विशेष अपने उद्योगों का इस तरह उपयोग करते हैं ताकि उन्हें अपने पड़ोसियों से कुछ अधिक सुविधाएँ प्राप्त हो सकें। जो बात किसी घर के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण हो सकती है वह किसी बड़े राष्ट्र के लिए वेवकूफी नहीं बन सकती।" कहने का सार यह हुआ कि मुक्त व्यापार की नीति के समर्थकों के अनुसार प्रत्येक देश, इस नीति के अन्तर्गत, अपने उन उद्योगों को उन्नत कर सकता है जो तुलनात्मक रूप से उसके लिए अधिक अनुकूल हों।

उल्लेखनीय है कि मुक्त व्यापार के क्षेत्र में नेतृत्व इंग्लैण्ड का रहा था। नेपोलियन-युद्धों के बाद 19वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड में मुक्त व्यापार बनाम संरक्षण का संघर्ष छिड़ा जिसमें मुक्त व्यापार का पक्ष विजयी हुआ। 19वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड में मुक्त व्यापार का बोल-बाला रहा। उसने मुक्त व्यापार की नीति को भारत और अपने अन्य उपनिवेशों पर भी लागू किया। लेकिन जहाँ औद्योगिक क्रान्ति के क्षेत्र में अग्रगण्य होने के कारण, इंग्लैण्ड की मुक्त व्यापार नीति से भारी लाभ हुआ वहीं यह नीति अन्य देशों के पक्ष में उपयोगी सिद्ध नहीं हुई। मुक्त व्यापार का अनुसरण करके अन्य देशों के लिए अपना औद्योगिक विकास करना सम्भव नहीं था। अतः संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस आदि ने संरक्षण की नीति का पक्ष-पोषण किया और भारत ने भी 1923-24 में विभेदनात्मक संरक्षण (Discriminating Protection) अपनाया। चारों ओर की इन परिस्थितियों ने मुक्त व्यापार के पक्ष में इंग्लैण्ड का पासा पलट दिया और भयानक महान् मन्दो के समय इंग्लैण्ड की बाध्य होकर इस नीति को तिलांजलि दे देनी पड़ी।

इस पृष्ठभूमि के उपरान्त हमें उन तर्कों को देखना चाहिए जो संस्थापक अर्थ-शास्त्रियों ने मुक्त व्यापार के समर्थन में दिए हैं। उनके मुख्य तर्क ये हैं—

(1) उत्पादन के साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग—मुक्त व्यापार के अन्तर्गत उत्पादन के साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग सम्भव है। प्रत्येक देश वह वस्तु पैदा करता है जिसमें उसे प्राकृतिक लाभ हो। मुक्त व्यापार में वस्तुओं की माँग और पूर्ति में प्रतियोगिता होने से प्रत्येक देश का यह प्रयत्न रहता है कि वह विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करे। इस तरह वह देश के अधिकतम लाभ देने वाली और श्रेष्ठतम वस्तुओं का ही उत्पादन करता है और इस प्रयत्न में अपने प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग कर पाता है। वह प्रत्येक वस्तु का सर्वाधिक आवश्यक कार्य में ही प्रयोग करने की ओर प्रवृत्त होता है। इस प्रकार देश में उत्पादन के साधनों का श्रेष्ठतम प्रयोग होने लगता है।

(2) श्रेष्ठतम उत्पादन इकाइयों—मुक्त व्यापार में स्वतन्त्र प्रतियोगिता होती है, अतः उत्पादन की घटिया, अलाभदायक व अनावधिक इकाइयाँ क्रमशः स्वतः समाप्त

हा जाती है। कबल व उत्पादन इकाइयाँ ही सक्रिय रहनी हैं जो कम से कम लागत पर अच्छे से अच्छा माल बनाने में सक्षम हों। इस स्थिति का यह स्वाभाविक परिणाम होता है कि उत्पादन स्तर उठ हा जाना है और पूँजी तथा श्रम माघना का दुःखपात नहीं हा पाता।

(3) भौगोलिक अर्थ विभाजन— मुक्त व्यापार में प्रत्येक देश की प्रज्ञात उन वस्तुओं का उत्पादन करने की रहनी है निम्न बिन्दु से उसे अधिकतम लाभ मिले। फलस्वरूप भौगोलिक अर्थ विभाजन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। इस तरह ससार के विभिन्न देशों का अर्थ-विभाजन के विभिन्न लाभ प्राप्त होन हैं।

(4) एकाधिकार पर रोक—मुक्त व्यापार एकाधिकारी मनों के निमाण अथवा उदय की शक्त है क्योंकि यह स्वतंत्र प्रतियोगिता पर आधारित होता है। देशी उद्योगों की विदेशी प्रतियोगिता का खुला सामना करना पड़ना है अतः वे एकाधिकारी सभा की स्थापना नहीं कर पाते।

(5) पारस्परिक सहयोग व सहभावना—मुक्त व्यापार ससार के देशों को एक दूसरे पर निर्भर बनाकर उनमें बीच पारस्परिक सहभावना और सहानुभूति पैदा करता है। परस्पर घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित होने में उनमें मैत्रीपूर्ण वातावरण बनता है।

(6) बाजार के क्षेत्र का विस्तार—मुक्त व्यापार के अन्तर्गत विदेशी व्यापार की वस्तुओं का क्षेत्र निम्न दूर-दूर के विभिन्न देशों में होने जाता है। इस तरह एक मात्र ही बाजार का क्षेत्र विस्तृत होता है और दूसरी ओर वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ जाते हैं। बाजार के विस्तृत होने में उत्पादक विज्ञान पैमाने पर उत्पादन करने लगते हैं जिससे वस्तुओं की उत्पादन लागत कम हो जाती है और उपभोक्ताओं का अर्थोत्पादक सत्त दामों पर वस्तुएँ मिलने लगती हैं।

(7) उपभोक्ताओं को लाभ—जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है मुक्त व्यापार का अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं का वस्तुएँ सत्त दामों पर मिलने सानी है। ऐसा मुख्यतः तीन कारणों से होता है—(अ) विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने के लिए देशी उद्योगपति वस्तुओं की उत्पादन लागत कम करने लगते हैं (ब) बाजारों के विस्तृत होने में वस्तुओं के उत्पादन का पैमाना बढ़ता है जिससे उत्पादन लागत घटती है एवं (स) आयात की जाने वाली वस्तुओं पर कर न लगने से वस्तुओं के मूल्य नहा घटते हैं।

(8) उत्पादन विधि में सुधार—मुक्त व्यापार के अन्तर्गत आयाती प्रतियोगिता बढ़ती है। फलस्वरूप प्रत्येक देश अपनी अपनी उत्पादन विधियों में सुधार करने रहने के प्रति जागरूक रहता है। इन सुधारों द्वारा उद्योगपति अपनी उत्पादन लागतों का कम करने का प्रयत्न करते हैं। कभी कभी विदेशी प्रतियोगिता का मुकाबला करने के लिए देशी उद्योगपतियों द्वारा उद्योगों के उद्योगों का युक्तिवरण (Rationalisation) कर दिया जाता है जिससे उपभोक्ताओं को काफी लाभ होता है।

(9) **आविष्कारों को प्रोत्साहन**—मुक्त व्यापार में प्रतियोगितापूर्ण स्थिति होने से उत्पादक अपना माल बेचने की किराक में माल के नए-नए नमूने और डिजाइन तैयार करते हैं तथा नयी-नयी वस्तुएँ पंदा करते हैं। इस तरह आविष्कार प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है।

उपरोक्त सभी लाभों के कारण संस्थापक अर्थ-शास्त्रियों ने मुक्त व्यापार की नीति का समर्थन किया था। लेकिन आज का युव आर्थिक राष्ट्रवाद (Economic Nationalism) और नियोजित अर्थ-व्यवस्था (Planned Economy) का है। आज की परिस्थितियों में मुक्त व्यापार के अनेक लाभ केवल काल्पनिक रह गए हैं। फलस्वरूप मुक्त व्यापार की नीति का व्यावहारिक महत्त्व समाप्त हो चुका है। आज अत्यन्त विकसित देशों ने भी इस नीति का परित्याग कर दिया है। वर्तमान में इसने स्थान पर सभी देशों ने संरक्षण की नीति को अपनाया।

संरक्षण का सिद्धान्त (Theory of Protection)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षण की नीति का अपना महत्त्व है। इसका अर्थ उस सरकारी नीति से है जिसके आधीन एक सरकार विदेशी प्रतिस्पर्धा के अर्थ-उद्योगों की रक्षा करने के लिए प्रशुल्क (Tariff) द्वारा विदेशी व्यापार पर रोक लगाती है। इस नीति की सर्वप्रथम व्याख्या करने का श्रेय अमेरिकी राजनीतिज्ञ एवं अर्थशास्त्री जेम्स जेम्स हेमिल्टन को दिया जाता है। उन्होंने संरक्षण की नीति को दण के उद्योग धंधों का विकास करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए स्वीकार किया। बाद में इस सिद्धान्त की व्याख्या मि० हैनरी सी० केरे तथा जर्मनी के मि० फ्रेड्रिक लिस्ट द्वारा की गई। उन्होंने इस विचार के समर्थन में अनेक तर्क प्रस्तुत किए। इस प्रकार संयुक्त-राज्य अमेरिका और जर्मनी इस विचार के मुख्य माने जा सकते हैं। यहीं से यह विचार अन्य देशों को गया। 17वीं शताब्दी में स्वतन्त्र व्यापार का अधिक प्रचलन था और उस पर ये सीमाएँ नहीं लगाई जाती थी, किन्तु प्रथम महायुद्ध के बाद स्वतन्त्र व्यापार को प्रतिबन्धित किया जाना प्रारम्भ हो गया, यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे स्वतन्त्र व्यापार के समर्थक देश ने भी इन प्रतिबन्धों को महत्त्व देना प्रारम्भ किया।

19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए अनेक देशों ने प्रशुल्क नीति को अपनाकर विदेश-व्यापार को विनियमित किया। यद्यपि इस काल में भी यूरोप के अनेक देश स्वतन्त्र व्यापार का पक्ष ले रहे थे किन्तु 20वीं शताब्दी की दूसरी दशक में स्वतन्त्र व्यापार प्रायः पूरी तरह नष्ट हो गया। विश्व के अनेक प्रमुख देशों ने पर्याप्त ऊँचे प्रशुल्क लगाए। ग्रेट-ब्रिटेन ने भी अपनी स्वतन्त्र व्यापार नीति को त्याग दिया और अपने देश के उद्योगों का विकास करने के लिए शुल्क की सीढ़ियाँ में सुविधा प्राप्त करने के लिए तथा साम्राज्य में प्राथमिक

व्यवस्था लागू करने के लिए संरक्षण की नीति को अपना लिया। इस नीति के अनुसार व्यापार पर अनेक प्रकार के नियन्त्रण लगाए गए।

संरक्षण की नीति के अन्तर्गत उपभोक्ताओं अथवा उत्पादकों के एक वर्ग को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं। इस नीति के अन्तर्गत प्रतिबन्धों का इतना महत्त्व नहीं होता जितना उन के उद्देश्यों का होता है। आर्थिक क्षेत्र में प्रायः प्रत्येक सरकारी हस्तक्षेप किसी न किसी के लिए लाभदायक रहता है और उसे प्रतियोगिता में राहत प्रदान करता है। इसी प्रकार व्यापार प्रतिबन्ध भी, चाहे वह किसी भी उद्देश्य से क्यों न लगाया गया हो, किसी न किसी आर्थिक हित को कुछ मात्रा में संरक्षण प्रदान करता है। संरक्षण की नीति या संरक्षणवाद का अर्थ ये आकस्मिक घटनाएँ तथा इनसे प्राप्त होने वाला लाभ नहीं है बल्कि इसमें व्यापार प्रतिबन्ध की तकनीकों का विस्तार के साथ अध्ययन किया जाता है। संरक्षणवाद का मुख्य रूप प्रशुल्क है और संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों में तो प्रशुल्क तथा संरक्षण को एक रूप ही माना गया है। इतने पर भी इन देशों में संरक्षणवाद को केवल प्रशुल्क तक ही सीमित नहीं किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में संरक्षणवाद का एक लम्बा इतिहास है। कुछ समय पूर्व तक विश्व के विभिन्न देशों में संरक्षण से सम्बन्धित विवाद अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति का एक महत्त्वपूर्ण विषय था। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त में संरक्षणवाद के समर्थन और विरोध में विभिन्न तर्क प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान काल में कुछ अन्य नीतियों का भी विकास हुआ है जो कि संरक्षणवाद के साथ प्रतिद्वन्द्विता रखती हैं, उदाहरण के लिए, विनिमय की दरें और अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, विदेशी सहायता कार्यक्रम, आर्थिक कल्याण, व्यापार शर्तों का समायोजन आदि।

संरक्षण की नीति के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के स्वाभाविक प्रवाह को रोक दिया जाता है और अनेक कृत्रिम प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं। ये प्रतिबन्ध आर्थिक अथवा पूर्ण हो सकते हैं और ये विभूत रूप से आर्थिक या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए लगाए जा सकते हैं। जो नीति विदेशी व्यापार की स्वाभाविक गति में बाधा डालती है, वह मूल रूप से संरक्षण की नीति का भाग है। उसका रूप आर्थिक भी हो सकता है और अनार्थिक भी।

संरक्षण के तरीके (The Methods of Protection)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वाभाविक गति में अनेक तरीकों से प्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैं। इन तरीकों में से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं—

(1) वैधानिक विषय (The Legal Prohibition)—इस रीति के अनुसार कानून बनाकर सरकार द्वारा किसी वस्तु के आयात और निर्यात पर रोक लगा दी जाती है। इसे प्रायः तब काम में लिया जाता है जब व्यापार संतुलन एक देश के पक्ष में न हो अथवा व्यापारिक दृष्टि से दुःखदायी समय हो। ये प्रतिबन्ध प्रायः छोटे समय के लिए ही लगाए जाते हैं। जिस समय अर्जेंटीना के पशुओं में बीमारी फैली

थी, उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने वहाँ से गांस भेजने पर कानूनी प्रतिबन्ध लगा दिया ।

(2) प्रशुल्क अथवा आयात-निर्यात कर (The Tariffs)—संरक्षण की यह पर्याप्त पुरानी और प्रचलित प्रणाली है । जब देश के आयात पर संरक्षण की दृष्टि से कर लगाए जाते हैं तो इनको संरक्षण कर कहा जाता है । आजकल निर्यात करों की अपेक्षा आयात करों का महत्त्व अधिक है । प्रशुल्क कर के अनेक रूप हो सकते हैं—(i) समान कर प्रणाली जिसके अनुसार एक देश अन्य सभी देशों की एक जैसी वस्तुओं के प्रति समानतापूर्ण व्यवहार करता है । (ii) परम्परागत प्रशुल्क प्रणाली जिसके आधीन एक देश सामान्य कर लगाते समय उन देशों की ध्यान रखता है जिनके साथ विशेष प्रकार की सन्धियाँ की हैं अथवा जिसके साथ विशेष परम्परागत सम्बन्ध है । (iii) प्रशुल्क प्रणाली की दूरें अधिकतम या न्यूनतम हो सकती हैं । जिन देशों के साथ विशेष सन्धि की जाती है उनको आयात करों में न्यूनतम तथा बाकी के देशों के लिए अधिकतम दरों में प्रशुल्क लगाने की व्यवस्था की जाती है । (iv) विशेषाधिकार युक्त प्रशुल्क प्रणाली होती है जिसके अन्तर्गत उन देशों को व्यापार सम्बन्धी रियायतें दी जाती हैं जो राजनैतिक, जातिगत या क्षेत्रीय आधार पर परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं ।

करारोपण गणना के आधार पर भी विभिन्न प्रकार के होते हैं । जो कर वस्तु की भौतिक इकाई पर लगाए जाते हैं उनको विशेष प्रशुल्क कहा जाता है । यदि इन्हे वस्तु के मूल्य के आधार पर लगाया जाए तो ये मूल्यानुसार प्रशुल्क कहे जाएंगे । जब देशी उत्पादकों की हानि से बचाने के लिए कोई कर लगाया जाता है तो उसे क्षतिपूर्ति प्रशुल्क कहा जाता है ।

प्रशुल्क कर लगाने से कई उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है । इनके परिणामस्वरूप विदेशी वस्तुओं की महँगा बनाकर उनका आयात घटाने का प्रयास किया जाता है ताकि स्वदेशी उद्योगों का तीव्र गति में विकास होने लगे, देश के रोजगार में वृद्धि हो, मजदूरी की दर बढ़ जाए और देश आत्म-निर्भरता की दिशा में अग्रसर हो । प्रशुल्क का एक खतरा यह होता है कि इससे अन्य देश प्रतिकार के रूप में आयात कर लगाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं । ऐसी स्थिति में इनका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता । राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्ध बिगड़ जाते हैं और उनके बीच अनबन हो जाती है । इन सबके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अवांछनीय दिशाओं की ओर मुड़ जाता है । ये प्रशुल्क राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर ही लगाए जाते हैं और इसलिए प्रायः इनका अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ही विरोध किया जाता है ।

(3) आर्थिक सहायता (The Financial Aid)—इस नीति के अनुसार एक देश की सरकार आयातों एवं निर्यातों पर कोई कर न लगाकर अपने उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको विशेष सहायता देती है । यह सहायता विशेष छूट, ऋण, अनुदान, उपदान (Subsidies) अथवा भविष्य (Bounties) के रूप

है। (3) कोटा प्रणाली का एक अन्य रूप द्वि-पक्षीय कोटा प्रणाली (Bilateral Quota System) कहा जाता है। इसके अनुसार सरकार द्वारा एक देश से निश्चित भाग में ही आयात करने की अनुमति दी जाती है। जब कोई आयातकर्ता उस मात्रा से अधिक आयात करता है तो दण्ड-स्वरूप उसे अधिक आयात कर का भुगतान करना होगा।

लाभ—कोटा प्रणाली द्वितीय विश्व युद्ध के समय में अत्यन्त लोकप्रिय थी। इसके अपने कुछ लाभ होते हैं—(1) इस प्रणाली के अन्तर्गत अन्य देशों के साथ लाभप्रद रूप में सौदे किए जा सकते हैं। (2) यह प्रणाली अत्यन्त लोचनीय होती है और आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। (3) इसमें पक्षपात की गुंजाइश कम रहती है और जिस प्रकार आयात कर का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध किया जाता है, उस प्रकार इसका विरोध नहीं किया जाता। (4) जब वस्तुओं के आयात की मात्रा निश्चित हो जाती है तो स्वदेशी व्यापारी आसानी से अपने उत्पादन को व्यवस्थित रूप से नियोजित कर सकते हैं।

दोष—कोटा प्रणाली के अपने कुछ दोष भी हैं—(1) इससे सरकार की आय कम हो जाती है। यह कमी आयात करों के आधार पर आई कमी से कहीं अधिक होती है। (2) इस प्रणाली से वस्तुओं के मूल्यों में अस्थिरता रहती है क्योंकि जब आयात बन्द रहता है तो मूल्य बढ़ जाते हैं और जब आयात खुल जाता है तो वस्तुओं के मूल्य कम हो जाते हैं। इस कमी और वृद्धि के फलस्वरूप व्यापारियों को पर्याप्त लाभ होता है किन्तु सरकार और उपभोक्ता इससे कष्ट उठाते हैं। (3) कोटा प्रणाली सम्बन्धित अधिकारियों के हाथ में शक्ति सौंपकर भ्रष्टाचार के अधिक अवसर प्रदान करती है। (4) इस प्रणाली के अन्तर्गत विदेशों में वस्तुओं की कीमत गिर जाने पर भी उपभोक्ता लाभान्वित नहीं होता।

(5) **विनिमय नियन्त्रण (Exchange Control)**—कोटा प्रणाली को प्रायः विनिमय नियन्त्रण की नीति के अनुरूपक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और ऐसी स्थिति में यह अत्यन्त प्रभावशाली बन जाती है। विनिमय नियन्त्रण के अन्तर्गत सरकार आयात और निर्यात के लिए विदेशी विनिमय के क्रय-विक्रय को नियमित करती है। जब विदेशी विनिमय की मात्रा निश्चित हो जाएगी तो केवल सीमित आयात किए जा सकेंगे। इस नीति को अपनाते हुए सरकार विनिमय की दर भी निर्धारित कर देती है।

विनिमय-नियन्त्रण की प्रणाली का विकास मुख्यतः आर्थिक मन्दी के समय हुआ। 1930 में जब आर्थिक मन्दी आई तो अनेक देशों ने यह अनुभव किया कि विदेशी विनिमय कोष का होना परम आवश्यक है और इसलिए उन्होंने विदेशी विनिमय के क्रय-विक्रय पर नियन्त्रण लगाने की नीति अपनाई। विनिमय-नियन्त्रण की प्रणालियों द्वारा आयातों को प्रतिबन्धित किया जा सकता है। इसके द्वारा एक ओर तो विदेशी मुद्रा कोष सुरक्षित रखने में सहायता मिलती है और दूसरी ओर इसके

परिणामस्वरूप विदेशी वस्तुओं को देश के बाहर रखने में भी सफलता प्राप्त होती है। इन प्रणालियों के महत्वपूर्ण राजनैतिक प्रभाव होते हैं।

(6) भेदपूर्ण व्यवहार (Preferential Treatment)—विभिन्न देशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर जब कर लगाया जाता है तो कई बार सरकार भेदपूर्ण व्यवहार भी करती है। ऐसा करते हुए कुछ देशों के सम्बन्ध में कर की दरें कम और आय के सम्बन्ध में अधिक कर दी जाती हैं। व्यापार को विनियमित करने का प्रयास किया जाता है।

(7) आयात-निर्यात का एकाधिकार (Import Export Monopoly)—कभी-कभी सरकार आयात और निर्यात के काम को स्वयं अपने हाथ में ले लेती है। ऐसी स्थिति में स्वयं सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि किन वस्तुओं का किस मात्रा में आयात या निर्यात किया जाएगा? इस प्रक्रिया द्वारा सरकार स्वदेशी उद्योगों को सरक्षण देने का प्रयास करती है और विदेशी व्यापार को नियन्त्रित करती है।

विदेशी व्यापार को विनियमित करने तथा स्वदेशी उद्योग-धन्धों को सरक्षण प्रदान करने के उपर्युक्त तरीकों में से किमको प्रमुख माना जाए? यह एक विवादपूर्ण प्रश्न है। कोई ऐसा निश्चित मापदण्ड नहीं है जिसके आधार पर इस प्रश्न को तय किया जा सके। द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद जो आर्थिक राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई उसका फलस्वरूप विभिन्न देशों ने अपने उद्योगों को सरक्षण प्रदान करने के लिए उपर्युक्त में से विभिन्न नीतियों का प्रयोग किया।

सरक्षण की नीति की आवश्यकता एवं महत्व (The Necessity and Importance of the Protection)

विदेशी व्यापार में सरक्षण की नीति को अपनाया जाना क्यों आवश्यक है तथा यदि इसे न अपनाया जाए तो क्या कठिनाई उत्पन्न हो सकती है? इसे जानने के लिए हमें उन तर्कों का अध्ययन करना होगा जो प्रायः स्वतन्त्र व्यापार की नीति के विरुद्ध दिए जाते हैं। सरक्षण की नीति के पक्ष में प्रस्तुत विभिन्न तर्कों को सैद्धान्तिक दृष्टि से स्वीकार करना सरल होता है किन्तु उनको व्यावहारिक रूप देना कठिन है।

स्वतन्त्र व्यापार के सम्बन्ध में प्रायः यह कहा जाता है कि इसमें आन्तरिक और बाह्य व्यापार में कोई भेद नहीं होना, अतः यह नीति उचित है। सरक्षण की नीति के सम्बन्ध में कोई ऐसी सामान्य बात नहीं की जाती। सरक्षण की नीति के पक्ष में जो अनेक तर्क दिए गए हैं, उनमें से कुछ वैज्ञानिक हैं, अन्य को आसानी से गलत सिद्ध किया जा सकता है। उनके बीच कई बार असंगतियाँ दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त जब इन तर्कों को स्वीकार करके क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाता है तो अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरक्षण की नीति के समर्थन में दिए गए तर्क अग्रलिखित शीर्षकों में वर्णित किए जा सकते हैं।

1. अनार्थिक तर्क

(Non-Economic Arguments)

ये तर्क देश के आर्थिक जीवन से बहुत कम सम्बन्ध रखते हैं। इनमें उल्लेखनीय ये हैं—

(i) राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आत्म-निर्भरता (National Defence and Self Sufficiency)—कहा जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक उद्योगों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे उद्योग स्वतन्त्र बाजार में प्रतियोगिता का सामना कर सकें। अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में सदैव युद्ध की सम्भावनाएँ बनी रहती हैं और इसलिये प्रत्येक शासन को राष्ट्रीय सुरक्षा का पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए। जब तक युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री का उत्पादन देश में नहीं किया जाता उस समय तक देश आत्म-निर्भरता का अनुभव नहीं कर सकेगा। संकटकाल में कई वस्तुओं का आयात कठिन बन जाता है और इसलिये ऐसी वस्तुओं के उत्पादन का राज्य का संरक्षण प्रदान करना परम आवश्यक होता है। यदि आत्म-निर्भरता की प्राप्ति के लिए देश को कुछ आर्थिक नुकसान उठाना पड़े तो गुरा नहीं है।

इस तर्क को व्यावहारिक रूप देते समय यह प्रश्न उठता है कि सुरक्षा की दृष्टि से कौन से उद्योग अधिक महत्वपूर्ण हैं जिन्हें संरक्षण दिए जाने चाहिए? आवश्यक उद्योगों में सामान्य रूप से ऐसे उद्योगों को लिया जाता है जिन पर युद्ध सम्बन्धी कार्य पूर्ण रूप से निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए सैनिक उत्पादन, सैनिक वायुयान, विस्फोटक पदार्थ, राइफल जैसी वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग आदि। इस प्रकार के उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना परम आवश्यक है। कभी-कभी सुझाव दिया जाता है कि सरकार इन आवश्यक उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने की अपेक्षा स्वयं ही चलाए और ऐसा करने में जो खर्च आता है उसे करों द्वारा प्राप्त किया जाए ताकि सारी जनता उसके भार को समान रूप से सह सके। इस प्रक्रिया में यह लाभ है कि इससे अनता जाग्रत होती है।

(ii) राष्ट्रीय आचार की सुरक्षा (Preservation of National Ethic)—संरक्षण की नीति द्वारा एक देश अपने विशेष आचार-विचार को सुरक्षित रख सकता है। यदि इस प्रकार का संरक्षण प्रदान न किया जाए तो वे नष्ट हो जाएंगे क्योंकि विभिन्न देशों के लोग एक-दूसरे के निवृत्त सम्पर्क में आएँगे। यदि राष्ट्र के विशेष गुणों को सुरक्षित रखना है तो इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर अत्यधिक निर्भरता को रोकना चाहिए।

(iii) कुछ व्यवसायों को सुरक्षित रखने के लिए (To Preserve certain Occupations)—कई बार संरक्षण की नीति का प्रयोग जनसंख्या के कुछ वर्गों या व्यवसाय विशेषों को सुरक्षित रखने के लिए भी किया जाता है। स्वतन्त्र व्यापार की नीति के अन्तर्गत इन व्यवसायों के समाप्त होने का भय था। राजनैतिक एवं सामाजिक दृष्टि से इन व्यवसायों एवं वर्गों को संरक्षण दिया जाना आवश्यक प्रतीत

होता है उदाहरण के लिए, कृषक वर्ग को लिया जा सकता है। इन वर्ग के लोग मुख्यतः रुढ़िवादी किन्तु समाज के प्रति निष्ठावान होते हैं। यदि इनको सुरक्षा प्रदान न करके स्वतन्त्र व्यापार की प्रतियोगिता में छोड़ दिया गया तो इनके समाप्त होने का डर रहता है। कीमतों पर कुछ नियन्त्रण किया जाना कभी-कभी आवश्यक होता है क्योंकि इसके बिना कृषि का विकास रुक जाएगा। शारीरिक व मानसिक दृष्टि से उसके उत्पादन में बाधा उत्पन्न होगी।

2. आर्थिक तर्क

(Economic Arguments)

सरक्षण की नीति के समर्थन में अनेक आर्थिक तर्क प्रस्तुत किए गए किन्तु इन तर्कों को सही रूप में परिभाषित करना अत्यन्त कठिन था। अनेक ऐसे उद्योग होते हैं जिनका आर्थिक दृष्टि से कोई उपयोग नहीं होता अर्थात् वे देश की आय में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करते बल्कि अनावश्यक कार्यों से सम्बद्ध रहते हैं उदाहरण के लिए संनिध महत्त्व के उद्योगों को यदि सरक्षण प्रदान किया जाता है तो वह आर्थिक दृष्टि से इतना उपयोगी एवं प्रभावशील नहीं माना जाएगा। जो उद्योग राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय सम्पत्ति अथवा सामाजिक उत्पादन की वृद्धि में सहायक बनते हैं, उनको सरक्षण प्रदान करना आर्थिक दृष्टि से उल्लेखनीय होता है। सरक्षण पक्ष में दिए जाने वाले विभिन्न तर्कों को इसी आधार पर आर्थिक कहा जाता है। इन तर्कों का अर्थ यह है कि कुछ परिस्थितियों में सरक्षण द्वारा सामाजिक उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। विभिन्न आर्थिक तर्क निम्नलिखित हैं—

(i) अल्पकालीन और दीर्घकालीन तर्क (Short run and Long run Arguments)—सरक्षण की नीति द्वारा अल्पकालीन सफलता की स्थिति का सामना किया जा सकता है। इस नीति के समर्थन में दिए गए जिन तर्कों का विवेचन किया जा सकता है वे प्रायः अल्पकालीन होते हैं। दीर्घकालीन तर्क वे हैं जिनके फलस्वरूप प्रागे चलकर देश के उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी।

(ii) सन्तुलन तथा असन्तुलन पर आधारित तर्क (Arguments based on Balance and Imbalance)—सरक्षण नीति के समर्थक दीर्घकालीन तर्क सन्तुलन सिद्धान्त पर आधारित रहते हैं। जब एक देश विश्व व्यापार में भाग लेता है तो उसकी अर्थव्यवस्था बाहरी तत्वों से पर्याप्त प्रभावित होती है, उसके सामने अनेक कठिनाइयाँ आ सकती हैं। इनके प्रभाव को कम करने के लिए सरक्षण की नीति आवश्यक बन जाती है।

(iii) एकाधिकार के विरुद्ध सरक्षण (The Protections against Monopoly)—स्वतन्त्र व्यापार की स्थिति में एक देश की अर्थव्यवस्था पर कई विदेशी उत्पादकों का एकाधिकार हो जाता है। यह ऊँची कीमतें एवं शोषण को जन्म देता है। अतः सरक्षण की नीति अपनाना आवश्यक होगा ताकि एकाधिकार उस देश की अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त न कर सकें।

(iv) आर्थिक विकास के लिए संरक्षण (Protections for Economic Development)—स्वतन्त्र व्यापार की स्थिति में एक देश की गति अनियन्त्रित रूप से आगे बढ़ती है। संरक्षण द्वारा उत्पादन तथा विनिमय की क्रियाओं को जब बदल दिया जाता है तब उत्पादन बढ़ने की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं।

(v) प्रतिकार के रूप में संरक्षण (The Protection in Retaliation)—कहा जाता है कि जब एक देश संरक्षण की नीति अपनाए हुए हो तो उसे स्वतन्त्र नीति का समर्थन नहीं करना चाहिए वरना वह साधनात्मक सोदेबाजी की स्थिति में नहीं रहेगा क्योंकि उसके द्वारा पड़ोसी देशों को सुविधा नहीं दी जा सकेगी; परिणामस्वरूप वह सुविधा भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसके अनिश्चित एक तरफ़ा स्वतन्त्र व्यापार हानिकारक रहेगा क्योंकि विदेशी प्रतियोगियों द्वारा ऐसे देश के बाजारों का क्षोभण किया जाएगा।

3. निरर्थक तर्क

(Non-sense Arguments)

संरक्षण की नीति के पक्ष में अनेक ऐसे तर्क दिए जाते हैं जो अर्थ की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होते फिर भी इस नीति का समर्थन करने के लिए उपयोगी माने जाते हैं। ये निम्न प्रकार हैं—

(1) रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाना (Maintenance of the Standard of Living)—संरक्षण की नीति के समर्थन में एक महत्वपूर्ण तर्क यह दिया जाता है कि इसके माध्यम से एक देश अपने जीवन-स्तर को बनाए रख सकेगा। संसार में विभिन्न देशों की मजदूरी का स्तर अलग-अलग होता है। विकासशील देशों में मजदूरों को बहुत कम मजदूरी प्रदान की जाती है। कहा जाता है कि एशिया में, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ देशों में श्रमिकों की दैनिक मजदूरी अमेरिका के मजदूरों की प्रति घण्टे मजदूरी से भी कम होती है। स्वयं विकसित देशों के बीच मजदूरी की दृष्टि से भारी अन्तर पाया जाता है। इन अन्तरों को देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि जिन देशों में श्रम की कीमत कम है वहाँ के आयातित माल पर नियन्त्रण रखा जाए क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो स्वदेशी उत्पादन सड़क में पड़ जाएगा। स्वदेश में श्रमिकों की दर अधिक होने के कारण यह उत्पादन महँगा पड़ता है। विदेशी प्रतियोगिता में स्वदेशी माल पीछे न पड़ जाए इसलिए संरक्षण की नीति को अपनाना परम आवश्यक है।

आलोचना—कहा जाता है कि यह तर्क गम्भीर नहीं है क्योंकि वास्तविक व्यवहार में विश्व-बाजार में अधिक मजदूरी वाले देशों द्वारा उत्पादित वस्तुएँ प्रतियोगिता में पूर्णतः टिकती हैं। कई वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनमें मजदूरी की दर अधिक होने से उत्पादन लागत अधिक नहीं आती। जिन देशों में ऊँची मजदूरी होती है वहाँ श्रमिक की उत्पादन क्षमता भी अधिक होती है। अतः उत्पादन व्यय अधिक नहीं होता। इसके अनिश्चित संरक्षण का यह तर्क अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त के साथ भी अनुकूलता नहीं रखता। ऊँची दर वाला श्रम निम्न दर वाले श्रम से

ही बना हुआ माल खरीदते हैं तो हमको माल तो मिलना ही है और धन भी मिलता है ।'

आलोचना—यह तर्क भी कुछ अधिक महत्व नहीं रखता । इस भाष्यना का साधारण यह विश्वास है कि आयातों के कारण मुद्रा की हानि होती है । यह दोष पूर्ण है । वास्तविकता यह है कि आयातों के लिए विदेशों को भेरा गया धन शीघ्र ही स्वदेश में लौट आता है । लौटते समय वह विदेशी धन को भी अपने साथ लाना है ।

(iv) उत्पादन-लागत में समानता लाने के लिए (To equalize the Cost of Production)—सरक्षण की नीति का समर्थन करने वाले विचारकों का कहना है कि एक वैज्ञानिक आयात-कर उसे कहा जाता है जो उत्पादन-लागत को देश और विदेश में समान कर लेता है । संयुक्त राज्य अमेरिका में इस तर्क को पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुआ । इसे पक्षपात-हीन तथा आपत्तिहीन माना गया ।

आलोचना—यह तर्क भी अधिक सम्मोहता नहीं रखता क्योंकि हम राष्ट्रीय स्तर पर ही प्रायः उत्पादन लागत को समान नहीं कर सकते तो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे कर सकेंगे । इसके अतिरिक्त यदि सभी वस्तुओं में देश-विदेश की वस्तुओं की लागत समान हो गई तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी क्योंकि व्यापार का कारण तुलनात्मक लागतों में अन्तर होता है । ।

(v) क्रय शक्ति का तर्क ('The Argument of Purchasing Power')—यह कहा जाता है कि जब सरक्षण की नीति को अपनाया जाता है तो इनसे प्रायः सभी देश लाभान्वित होते हैं क्योंकि उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ जाती है और इसलिए विभिन्न उद्योगों का अधिक माल खप सकता है । औद्योगिक संरक्षण के परिणामस्वरूप कृषि-उपज के उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी और कृषि-उपज के संरक्षण के परिणामस्वरूप औद्योगिक वस्तुओं की क्रय-शक्ति बढ़ जाएगी, फलतः दोनों ही लाभान्वित होंगे ।

आलोचना—फ्रेडरिक बेस्टियट (Frederic Bastiat) ने इस प्रकार के तर्कों का मजाक रिया है । उन्होंने ससद् में यह प्रार्थना की कि मोमबत्ती बनाने वालों के लिए सूर्य की विनाशकारी प्रतियोगिता के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया जाए । उनके इस कथन का अर्थ केवल यही था कि एक व्यवसाय को अन्य व्यवसाय के विरुद्ध संरक्षण दिया जाना न तो सम्भव है और न उपयोगी ।

(vi) व्यापार सन्तुलन का सुधार (Improvement of the Balance of the Trade)—सरक्षण की नीति के समर्थन में एक तर्क यह दिया जाता है कि इसे अपनाने पर व्यापार सन्तुलन में सुधार हो जाएगा । मुद्रा स्थिति एवं ऐसी अन्य सफटों के समय सरक्षण को पर्याप्त महत्त्वपूर्ण माना गया । सन् 1930 की आर्थिक मन्दी के परिणामस्वरूप पूर्व और मध्य यूरोप के अनेक देशों ने व्यापार सन्तुलन को सुधारने के उद्देश्यों से ही प्रशुल्कों की सख्या में वृद्धि की । ,

आलोचना—आलोचकों के मतानुसार यह तर्क मुद्रा सम्बन्धी एवं विदेशी विनिमय मन्त्र को न समझने के कारण दिया जाता है । यह स्वयमेव सुगतान

सन्तुलन मे साम्य ला देता है। ऐसी स्थिति मे प्रशुल्क लगाने से कोई लाभ नहीं।
आर्थिक मन्दो की स्थिति मे प्रशुल्क लगाने से जा आयात कम होगा वह आयात-
आधिक्य को समाप्त नहीं कर सकता।

(vii) बहुमुखी सरक्षण का तर्क (The Argument of all Round Protection) -- जब एक वस्तु पर प्रशुल्क लगाने से अन्य की नय-शक्ति बढ़ती है और इस प्रकार उत्पादन की प्रत्येक शाखा को लाभ पहुँचता है तो यह उपयोगी होगा कि प्रत्येक शाखा को सरक्षण प्रदान किया जाए। इस तर्क के अनुसार 1879 मे जर्मनी ने सरक्षण को अपनाते हुए यह नारा बुलन्द किया कि प्रत्येक गाँव और देश में राष्ट्रीय उद्योगों को सरक्षण दिया जाए।

आलोचना--यह तर्क वैज्ञानिक नहीं है। जब उत्पादन की सभी शाखाओं को सरक्षण प्राप्त हो जाना है तो आवश्यक नहीं कि हर प्रणाली अच्छी हो जाएगी। इसने अतिरिक्त प्रशुल्क प्रणाली जितनी अधिक व्यापक होती है, उससे उस उद्योग को उतना ही कम लाभ मिलेगा जिसके हित में मूल रूप से प्रशुल्क लगाया गया है। प्रशुल्क की बीवार जितनी अधिक व्यापक होती है, सम्भावित देश विश्व मध्य व्यवस्था में उतना ही अधिक कट जाता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय धन विभाजन के लाभों से वंचित हो जाता है। परिणामस्वरूप सामाजिक उत्पादन घट जाएगा।

(viii) प्रतिकारात्मक सरक्षण (Retaliatory Protection) -- दूसरे देश द्वारा लगाए गए प्रशुल्कों के हानिप्रद प्रभावों से बचन के लिए जो प्रशुल्क लगाए जाते हैं उनको प्रतिकारात्मक प्रशुल्क कहा जाता है। इस नीति के समर्थन में यह कहा जाता है कि जब एक देश चारों ओर में सरक्षण नीति से घिरा हुआ है तो वह स्वतन्त्र व्यापार नीति का पालन नहीं कर सकता। ऐसा देश सौदेबाजी करने की दृष्टि से भी कमजोर रहता है क्योंकि इस देश के पास सरक्षित देशों को बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं होता। जब एक देश द्वारा दूसरे देश के निर्यात पर रोक लगाई जाती है तो उसकी अर्थ-व्यवस्था बिगड़ जाती है और बदले में दूसरा देश भी पहले देश पर नियन्त्रण लगा देता है। एक पक्षीय स्वतन्त्र व्यापार हमेशा हानिप्रद रहता है। इस नीति को मानने वाला अकेला दम विदेशी प्रतियोगिताओं के बीच दुरी तरह सँपम जाता है। यदि वह अन्य देशों पर लगाए गए प्रशुल्कों का जवाब नहीं देता तो पर्याप्त हानि उठानी पड़ती है।

आलोचना--इस तर्क के समर्थन में बहुत कुछ कहा गया फिर भी इसने प्रयोग तथा महत्त्व के सम्बन्ध में अधिक कहना शक्य है। आलोचकों का कहना है कि प्रतिकार के रूप में जब एक देश दूसरे देश के निर्यात पर रोक लगाता है तो इससे दोनों देशों को अधिक हानि होगी और प्रतिकार का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हैबरलर आदि के अनुसार 'यह विचार बहुत पुराना पड़ चुका है कि विरोधी प्रशुल्क दीवारों से घिरा एक दम अपन भुगतान सन्तुलन को कायम नहीं रख सकता और इसलिए इसे छोड़ देना ही अच्छा रहेगा।'¹

4. कुछ गम्भीर तर्क

(Some Serious Arguments)

इस सम्बन्ध में विचारकों ने कुछ गम्भीर तर्क भी प्रस्तुत किए हैं। ये निम्न प्रकार हैं—

(i) शिशु उद्योगों की संरक्षण (Infant Industry Protection)—संरक्षण की नीति का समर्थन करते हुए कुछ विचारकों ने यह तर्क भी दिया है कि इससे बाल उद्योगों को लाभ प्राप्त होता है। यह तर्क सर्वप्रथम अलेक्जेंडर हैमिल्टन द्वारा प्रस्तुत किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस विचार का प्रभाव उल्लेखनीय रहा और बाद में फ्रेडरिक लिस्ट द्वारा इसे अपना लिया गया। इन्होंने अपनी पुस्तक (The National System of Political Economy, 1840) में उस तर्क का व्यापक रूप से स्पष्टीकरण किया है। मि. लिस्ट का विचार था कि प्रत्येक देश अपनी आर्थिक प्रगति के लिए विभिन्न दिशाओं में होकर गुजरता है। कुछ देश दूसरों की प्रेरणा अधिक विकास कर लेते हैं किन्तु इसका कारण यह नहीं होता कि वे प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न थे वरन् यह कि अनेक ऐतिहासिक परिस्थितियाँ उनके अनुकूल थी जिन्होंने विकास की गति को बढ़ाया। दूसरे देशों में परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी और इसलिए उनका विकास रुक गया।

अनुकूल ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण ओ देश भीघ ही अपना विकास कर लेते हैं वे विश्व-बाजार में नेता बन जाते हैं जबकि अन्य देश पिछड़ जाते हैं। इन नेता राष्ट्रों द्वारा अन्य देशों के औद्योगिक विकास में रूकावटें डाली जाती हैं जिनके परिणामस्वरूप उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। छोटे देशों को जीवित रखने के लिए यह जरूरी है कि इन्हे देशी बाजार में संरक्षण दिया जाए। यदि ऐसा न किया गया तो विदेशी प्रतिযোগिता उनको समाप्त कर देगी। इस सम्बन्ध में फ्रेडरिक लिस्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अधिक प्रगतिशील देशों के साथ पूर्ण स्वतन्त्र प्रतियोगिता करते समय कम प्रगतिशील देश स्वयं के निजी उद्योगों को कायम नहीं रख सकेंगे चाहे निर्माण की समस्त सुविधाएँ उन्हें प्राप्त हैं। यह ठीक उनी प्रकार है जैसा एक बालक किसी पहलवान के साथ दूस्ती में नहीं जीत सकता और न ही उसका सबल विरोध कर सकता है।

एक नए और अर्द्ध-विकसित देश के उद्योगों की तुलना में विकसित देश के पुराने उद्योगों को अनेक लाभ प्राप्त होने हैं; उदाहरण के लिए उसे कम मजदूरी पर अनुभवों एवं कुशल श्रमिक आसानी से प्राप्त हो सकते हैं—(i) उसके पास समीप आवश्यक मशीनें सस्ते दामों में उपलब्ध रहती हैं, (ii) उसके अयु-विवरण में पर्याप्त मितव्ययिता होती है, (iii) उसके पास यातायात के सस्ते साधन होते हैं, (iv) वह क्रय-विक्रय में सबसे अधिक मितव्ययिता बरतता है, (v) उसके पास अच्छे प्रोजार और पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध हो सकता है एवं (vi) उसे कम से कम व्याज पर अधिक से अधिक पूंजी मिल जाती है आदि-आदि। इन्हीं सब कारणों के परिणामस्वरूप प्राचीन फर्मों को नई फर्मों की अपेक्षा प्रायः अधिक लाभ प्राप्त होता

हानिर्घा—शिशु उद्योगों की रक्षा का तर्क चाहे सैद्धान्तिक रूप से कितना ही स्पष्ट एवं मान्य प्रतीत होता हो किन्तु यह व्यावहारिक दृष्टि से अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है। हम यह आसानी से निर्धारित नहीं कर सकते कि कौनसा उद्योग संरक्षण के उपयुक्त है और कौनसा नहीं। सैद्धान्तिक रूप से यह कहा जा सकता है कि संरक्षण केवल उसी देश को दिया जाए जो सम्भवतः प्रारम्भ में कुछ हानि उठाएगा और संरक्षण बिना जिसे स्थापित ही नहीं किया जा सकता। यह बात सैद्धान्तिक रूप से सही है किन्तु व्यावहारिक रूप में इस प्रकार के उद्योगों का ज्ञात करना अत्यन्त कठिन है।

इस सम्बन्ध में एक अन्य जटिल प्रश्न यह भी उठता है कि किस उद्योग को कितना संरक्षण प्रदान किया जाए। किसी भी उद्योग के भविष्य को नापने की समस्या जटिल है जिसे आसानी से नहीं सुलझाया जा सकता। यह ज्ञात करना बहुत कठिन है कि कौनसा उद्योग भविष्य में असफल होने की गुंजाइश रखता है और किन उद्योगों के सफल होने के अवसर हैं। धन की समस्या उस समय जटिल बन जाती है जब हम देखते हैं कि प्रत्येक नया उद्योग शिशु उद्योग का तर्क देकर संरक्षण प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है। उसकी इस प्रार्थना को अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उद्यम आर्थिक दृष्टि से कितना लाभदायक है इसका निर्धारण तो केवल भविष्य ही कर पाएगा। जब नवीन उद्योगों के विकास की सभी आशाएँ समाप्त हो जाती हैं तो किमी अन्य तर्कों के आधार पर उसके संरक्षण को जारी रखने की सिफारिश की जाती है। फलतः संरक्षण को एक बार प्रदान करने के बाद उसे रोकना असम्भव बन जाता है। इस सम्बन्ध में टायले का यह कहना पर्याप्त महत्वपूर्ण है कि "एक बार यदि संरक्षण के दैत्य को जीवन प्रदान कर दिया गया तो यह कीड़े की तरह आर्थिक शरीर का भक्षण करने लगता है और शीघ्र ही अपने निश्चित कार्य से छोट कर अमरत्व प्राप्त कर लेता है।"¹

संरक्षण की नीति के विरुद्ध एक बात यह भी कही जाती है कि इसके फलस्वरूप अनुचित स्वार्थ की भावना को जन्म मिलता है और इससे प्रभावित होकर संरक्षण को हटाने का विरोध किया जाता है। कुछ लेखकों के अनुसार शिशु उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने की नीति और कुछ नहीं लेकिन अपनी प्रयोग्यता को ठकने का एक इरादा मात्र है। जब एक उद्योग संरक्षण हटा लेने के बाद भी बचता रहता है तो स्पष्ट है कि संरक्षण उसका मूल आधार नहीं था। संरक्षण के सहारे अनेक असमर्थ फर्मों को जिन्दा रखने का प्रयास किया जाता है जो उसके हटते ही लड़खड़ाकर गिर पड़ती हैं।

(ii) बेरोजगारी कम करने के लिए संरक्षण (Protection to reduce unemployment)—संरक्षण की नीति को अपनाने का एक कारण यह भी हो सकता है कि इसके सहारे देश के विभिन्न उद्योगों में फैली हुई बेकारी को दूर किया

जाए। जहाँ पर उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु को विदेशों से आयात की गई वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है और इन वस्तुओं की माँग पूर्ण लोचदार नहीं होती या उद्योग को रात-बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आयात की वस्तुओं पर प्रशुल्क लगाकर उस बेरोजगारी को कम करने का प्रयास किया जाता है। यह धाशा की जाती है कि प्रशुल्क का परिणामस्वरूप उद्योग के उत्पादन का विकास होगा और उनके रोजगार में वृद्धि होगी। स्वतन्त्र व्यापार का समर्थन करने वाले लोगों ने भी इन तर्कों को स्वीकार किया है। यहाँ सम्भावना यह भी है कि आयात उद्योगों में ब्रिजनी बेकारी घटती उनकी हो वह निर्यात उद्योगों में बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में सरक्षण की नीति लाभदायक होने की अपेक्षा हानिकारक बन जाती है।

बेरोजगारी की स्थिति में अल्पकालीन सरक्षण दीर्घकालीन सरक्षण की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है। सरक्षण नीति को अपनाते ही एक देश की बेरोजगारी की स्थिति में निश्चय ही सुधार हो जाएगा और आयात की मात्रा कम होने में देशी उत्पादन बढ़ेगा, बेजार लोगों के एक बहुत बड़े भाग को रोजगार प्राप्त होगा। हेवल्स के मतानुसार यह प्रशुल्क का केवल प्रारम्भिक प्रभाव होता है। स्वतन्त्र व्यापार के समर्थकों ने इस तर्क का विरोध करते हुए बताया है कि ऐसा सरक्षण कुल बेकारी में कमी नहीं करेगा। उनके मतानुसार आयातों पर प्रतिबन्ध लगने से निर्यातों में कमी हो जाएगी और इसलिए निर्यात उद्योगों में बेरोजगारी बढ़ेगी। सरक्षण के परिणामस्वरूप कुल बेकारी में कमी नहीं लाई जा सकती। यदि प्रत्याधी रूप से ही प्रबन्ध करने की समस्या हो तो सरक्षण की नीति अनाकर बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है किन्तु इसमें अधिक धाशाएँ करना गलत होगा।

आलोचकों ने स्वतन्त्र व्यापार के समर्थकों के तर्कों का भी खण्डन किया है। उनके अनुसार यह मानना गलत होगा कि आयातों पर प्रतिबन्ध के परिणामस्वरूप निर्यातों में भी एकदम उनकी ही मात्रा में कमी आयेगी। मरत लीजिए कमी आती है तो भी इसका अर्थ यह नहीं होता है कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी क्योंकि पहले देश के माल की खपत विदेशों में होती थी किन्तु अब निर्यात के घटने से वह स्वदेश में ही होने लगेगी। इस प्रकार विदेशी माँग का स्थान स्वदेशी माँग द्वारा ले लिया जाएगा। विरोधी तर्कों के होते हुए भी यह कहा जा सकता है कि प्रशुल्क लगाने से अनेक ऐसे लोगों को रोजगार मिलता है जो अभी तक बेरोजगार थे।

सर्वमान्य मत यह है कि सरक्षण का रोजगार की दृष्टि से अल्पकालीन परिणाम अल्पकालीन होता है। इसका दीर्घकालीन परिणाम जिस रूप में होता है उस हम तीन भागों में विभाजित करते हैं क्योंकि बेरोजगारी भी तीन प्रकार की होती है। प्रथम प्रकार की बेरोजगारी मध्यम से पैदा होती है। दूसरे प्रकार की बेरोजगारी व्यापार-चक्र से उत्पन्न होती है और तीसरे प्रकार की बेरोजगारी स्थायी बेरोजगारी होती है। इन तीनों पर प्रशुल्क लगाने का अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा।

(घ) संघर्ष से उत्पन्न बेरोजगारी (Unemployment due to Friction)—ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब प्रतस्पर्धा की अकुशलता के कारण या मांग के घट जाने के कारण या फर्म के दुर्भाग्य के कारण एक फर्म को अपना कारोबार बन्द करना पड़ता है। परिणामस्वरूप श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। इसी प्रकार तकनीकी विकास और नई संस्थाओं तथा नए उद्योगों के विकास के कारण पुराने उद्योगों की प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति कमजोर हो जाती है और उनके श्रमिक बेरोजगार होने लगते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी को तकनीकी बेरोजगारी भी कहते हैं। एक काम को छोड़ने के बाद दूसरा काम प्राप्त करने में समय लगता है, वह तत्काल नहीं मिल जाता। कभी-कभी काम की तलाश में दूर प्रदेशों में जाना होता है और इसमें पर्याप्त समय लगता है। परिणामस्वरूप इतने दिनों तक श्रमिक बेरोजगार रहता है। इस प्रकार की बेरोजगारी यद्यपि अस्थायी होती है किन्तु यह प्रायः प्रत्येक अर्थ-व्यवस्था में हर समय पर्याप्त मात्रा में रहती है।

विचारकों का कहना है कि इस बेरोजगारी को दूर करने में प्रशुल्क नीति पर्याप्त महत्वपूर्ण है। विदेशों में वस्तुओं की पूर्ति को रोकने के लिए और देशी उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए जब आयात पर लगवा दिया जाता है तो इसके परिणामस्वरूप उद्योग में फैली बेरोजगारी कम होती है। इस साधन का प्रयोग केवल कभी-कभी ही किया जा सकता है। यदि प्रत्येक बार प्रशुल्क का सहारा लेकर ही बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया गया तो इससे देश को स्थायी रूप से नुकसान होगा। अस्थायी बेरोजगारों को दूर करने के लिए जब प्रशुल्क लगाया जाता है तो उन लोगों का मिलना रुक जाता है जो अन्तर्राष्ट्रीय विभाजन के माध्यम से मिल सकते थे। यदि सभी देश इस नीति को ग्रहण करने लगे तो परिणामस्वरूप किसी को भी लाभ नहीं होगा। यह तरीका केवल अस्थायी समस्याओं को दूर करता है।

(ङ) व्यापार चक्र से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी (Cyclical Unemployment)—प्रत्येक पुँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में व्यापार-चक्र चलता रहता है और इसके परिणामस्वरूप देश में बेकारी फैल जाती है। इस प्रकार की बेरोजगारी (बेकारी) प्रायः सभी देशों के सभी उद्योगों में पाई जाती है। हम प्रशुल्क नीति अपनाकर यद्यपि बेरोजगारी को थोड़ा कम कर सकते हैं फिर भी इसमें स्थायी हानि होने की सम्भावना रहती है। संरक्षण की नीति व्यापार चक्रों द्वारा होने वाली बेरोजगारी को पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाती है।

(च) स्थायी बेरोजगारी (Permanent Unemployment)—स्थायी बेरोजगारी की समस्या को संरक्षण की नीति द्वारा कुछ मात्रा तक हल किया जा सकता है। स्थायी बेरोजगारी प्रायः अल्पदूरी की अत्यधिक ऊँची दर के कारण होती है और इसलिए बहुत ऊँचे प्रशुल्क लगाकर ऐसी बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। स्थायी बेरोजगारी को दूर करने के लिए अनेक उद्योगों को संरक्षण देना जरूरी हो जाता है किन्तु इससे खतरा यह है कि अन्य देश प्रतिकारात्मक उपाय अपना सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले लाभ कम हो जाएँगे। संरक्षण की

नीति प्रायः उस समय प्रभावशील होती है जब बेरोजगारी निर्यात उद्योगो मे हो। जब निर्यात उद्योगो मे बेरोजगारी फैलती है तो उसे समाप्त करने के लिए प्रायः नीति अधिक प्रभावशील नहीं रहती क्योंकि इसके परिणामस्वरूप निर्यातो मे कमी होकर बेकारी अधिक बढ़ जाती है।

सरक्षण की नीति और बेरोजगारी के बीच स्थित सम्बन्ध पर विचार करने के बाद निम्न यह आता है कि यदि बेरोजगारी सामान्य और स्थायी है तो उसे दूर करने के लिए या तो मजदूरी का स्तर गिराया जाए अथवा तकनीकी प्रगति हाने तक प लिए प्रतीक्षा की जाए। दूसरे, यदि बेरोजगारी व्यापार चक्र से पैदा हुई है तो कुछ समय बाद वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तीसरे, यदि बेरोजगारी किसी एक उद्योग मे है तो उसे दूर करने के लिए अर्थ व्यवस्था के दूसरे भागो की सहायता ली जा सकती है।

✓ (iii) व्यापार कीमतों मे सुधार के लिए सरक्षण (Protection to Improve the Terms of Trade)—सरक्षण नीति का समर्थन इसलिए भी किया जाता है ताकि जिन देशो के माल का आयात किया जाता है उनमें कीमतों को गिराया जा सके। ऐसा हो जाने पर वह देश अधिक अच्छी शर्तों पर आयात करने मे समर्थ हो सकेगा। आयात के मूल्य की कमी उसकी पूर्ति की दशाओ पर निर्भर करती है। जब निर्यातकर्ता देश मे वस्तुओ की पूर्ति अधिक लोचदार होती है तो आयात पर लगाए गए कर के परिणामस्वरूप उनकी कीमतों मे बहुत कम कमी आती है अथवा आती ही नहीं है। पूर्ति के बेलोचदार होने पर भी आयात कम होने से कीमते कम हो सकती हैं।

सरक्षण की नीति अनुकूल व्यापार शर्तों को प्राप्त करने मे सहायक होगी, यह निश्चिन नहीं है। आयात कर में वृद्धि के परिणामस्वरूप यह भी हो सकता है कि उत्पादन के साधन अनाधिक उत्पादन की ओर बढ जायें अथवा उपभोक्ताओ की सन्तुष्टि कम हो जाए। ऐसी स्थिति मे आयात-कर लगाने का लाभ बहुत कम हो जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान मे रखने की और भी है—यदि हमने अन्य देशो से होने वाले आयात पर ज्यादा प्रशुल्क लगाया तो इसकी प्रतिक्रिया के रूप मे दूसरे देश भी अपने आयातों पर प्रशुल्क लगा सकते हैं।

✓ (iv) सौदेबाजी के लिए सरक्षण (The Protection for Bargaining)—सरक्षण की नीति के पक्ष मे एक तर्क यह दिया जाता है कि इसके माध्यम से एक देश अन्य देश से रियायतें प्राप्त करने मे सफल हो जाता है। यदि एक देश ने सरक्षणात्मक कर लगा रखे हैं तो वह इनका प्रयोग करते हुए दूसरे देश को कुछ रियायतें दे सकता है और इस प्रकार उसे अपने अनुकूल प्रभावित कर सकता है, किन्तु जिस देश के पास इन रियायतों के बदले देने के लिए कुछ नहीं रहना उसने लिए विदेशी बाजार बन्द हो जाता है। सरक्षण की नीति के रहने पर ही लेन-देन के समय एक देश द्वारा दूसरे देश के आयात करों मे कमी की माँग की जा सकती है।

आलोचकों का कहना है कि इससे प्राप्त होने वाला लाभ या तो केवल स्वतन्त्र व्यापार वाले देशों को होना है अथवा उन देशों को जिनमें आयात कर कम हैं। सौदेबाजी के लिए लगाए जाने वाले इस प्रकार के करों के फलस्वरूप कुछ निहित स्वार्थ पैदा हो जाते हैं जो इन करों का विरोध करते हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के सरक्षणों का प्रयोग विदेशों से रियायत प्राप्त करने की अपेक्षा स्वदेशी सरकार से अधिक सरक्षण प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है।

(v) संकटकाल एवं बाजार की सुरक्षा के लिए संरक्षण (Protection in Emergency and to Ensure the Market)—विचारकों का कहना है कि सरक्षण की नीति उद्योग की किसी विशेष शाखा में आने वाले अस्थायी संकट को कम या समाप्त करने के लिए अपनाई जा सकती है। अनेक बार विभिन्न कारणों से देश में आर्थिक संकट पैदा हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि विश्व में कृषि-उत्पादन मजबूत हुआ है और देश में कम तो इससे संकट की स्थिति उत्पन्न होगी। इसका निपटारा करने के लिए करों को भौना बंटाई जा सकती है। किसी कारण से जब एक उद्योग के हानि से विदेशी व्यापार घट जाता है अथवा आयात की मात्रा बढ़ जाती है तो संकट काल प्रारम्भ हो जाता है। इसे आयात-कर लगाकर कम किया जा सकता है।

आलोचकों का कहना है कि संकटकाल का सामना करने के लिए अस्थायी रूप से जिस सरक्षण की रचना की जाती है उसको बाद में समाप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। अतः सरक्षण की स्थापना करते समय पर्याप्त सजगता तथा बुद्धिमता से काम लिया जाए। कई बार यह कहा जाता है कि संकटकालीन संरक्षण लाभ की अपेक्षा हानि का कारण अधिक है और इसलिए इसका प्रयोग पर्याप्त सावधानी से करना चाहिए।

(vi) राशिपातन को रोकने के लिए संरक्षण (Protection to Prevent Dumping)—कई बार विदेशी व्यापारी स्वदेशी उत्पादन को नीचा दिलाने के लिए राशिपातन की नीति अपनाते हैं। इसके अनुसार वे विदेश में किसी वस्तु को ऐसे मूल्य में बेचते हैं जो स्वदेशी की अपेक्षा कम होता है। इस प्रकार स्वदेशी उद्योग प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते। इस प्रकार का तर्क वे व्यापारी देते हैं जो प्रतिस्पर्धा नहीं चाहते।

इस तर्क के सम्बन्ध में भी कुछ कठिनाइयाँ हैं—(1) राशिपातन का अर्थ स्पष्ट नहीं है। (2) यदि राशिपातन स्थायी है तो यह नुकसानप्रद होने की अपेक्षा उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक हो सकता है। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि राशिपातन की प्रकृति पर विचार करने के बाद ही प्रशुल्क लगाना चाहिए। राशिपातन जब कभी यन्त्रतान्त्रिक (Sporadic) होता है तो वह देश की अर्थ-व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर सकता है। दूसरी ओर यह स्थानीय फर्मों के लिए घातक है। राशिपातन के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाला लाभ अस्थायी और छोड़े समय के लिए होता है किन्तु व्यवसायों पर इसका प्रभाव दीर्घकालीन होता है।

(iii) असन्तुलित अर्थ व्यवस्था के लिए सरक्षण (Protection for an Unbalanced Economy)—असन्तुलित अर्थ व्यवस्था बढ्ती है जिसमे निम्न वस्तुओं के उत्पादन एवं कृषि उत्पादन मे पर्याप्त अन्तर रहता है तथा देश के आयात निर्यात व बौध गहरी खाई रहती है। इस असन्तुलन का दूर करने के लिए सरक्षण की नीति को अपनाया जाता है। जब कृषि-प्रधान देशों का औद्योगिकरण किया जाता है तो इनके व्यापार सन्तुलन मे परिवर्तन आ जाने हैं। यह औद्योगिकरण बड़े स्तरों मे प्राप्त किया जाता है। प्रारम्भ मे प्राप्त घटिया स्तर की चीजें बनती हैं जिनमे कुशल धर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसा देश अपरिपक्व कच्चे माल या मंगाता है और बदल म अर्द्ध-निर्मित वस्तुएँ भेजता है। इस प्रक्रिया मे आयात-व्यय बहुत कम लगता है। नए देश के आर्थिक विकास के साथ साथ पुराने औद्योगिक देशों में भी तकनीकी विषय चलता रहता है और ऐसी स्थिति में विकासशील देश को उत्तम विश्व की चीजें अन्य आदि का आयात करना होता है। यह कहा जाता है कि पूजा तथा उत्पादन व साधनों का निर्यात किसी देश की औद्योगिक बलों का प्रयोग नहीं है वरन् यह एक लाभदायक विनिमय है।

कुछ विचारकों का कहना है कि निर्मित वस्तुएँ तथा कच्चे माल का आदान-प्रदान एक दिन समाप्त हो जाएगा। यदि कृषि-प्रधान देशों ने सरक्षण की नीति अपनाई तो स्वाभाविक विकास की यह गति और भी बढ़ जाएगी। इस प्रकार पुराने औद्योगिक बन्द कम निर्यात करने लगेंगे।

(iv) उत्पादों के आयात के लिए सरक्षण (Protection for import of means of Production)—सरक्षण द्वारा दान व पूँजी का आयात किया जा सकता है। इसके समर्थन में अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं। इस सरक्षण व परिणामस्वरूप ही समुत्क्रान्त्य अमेरिका व ब्रिटिश कर्मों ने अपनी शालाएँ खोली। इस प्रकार यह सही है कि सरक्षण को लागू करने पर या उसकी मात्रा बढ़ा देने पर देश में पूँजी का आयात होता है। मि० शूलर ने यह विचार प्रकट किया है कि स्वतन्त्र व्यापार सिद्धान्त की यह कल्पना पूर्ण गलत थी कि सरक्षण द्वारा उत्पादन का सर्व ही अविवेकपूर्ण व्यापारिकरण किया जाना है तथा इसका द्वारा स माजिक उत्पादन में वृद्धि नहीं की जाती।

शूलर का मत था कि सरक्षण द्वारा उत्पादन के उपलब्ध साधनों का बढ़ावा जा सकता है। सरक्षण की नीति उन साधनों के उपयोग का अवसर प्रदान करती है जो अभी तक बकाय पड़े थे। इसके अनिश्चित सरक्षण द्वारा उत्पादन के विभिन्न साधनों को विदेशों से आयात भी किया जाता है। शूलर लिखते हैं कि किसी भी देश में धर्म शक्ति का आकार निश्चित नहीं होता क्योंकि धर्मिकों की सहा उत्पादन की मृतिधा के अनुसार अधिक और कम होती रहती है। देश के उत्पादन का आकार केवल देश की पूँजी तक ही सीमित नहीं रहता वरन् विदेशों की पूँजी भी आवश्यकता व अनुसार आ सकती है किन्तु अभी जबकि देश में उसके अनुकूल वातावरण हो। यद्यपि पूँजी के आवासमान के साथ अनेक कठिनाइयाँ जुड़ी हुई हैं फिर भी वास्तविक व्यवहार में इसका आयात सम्भावित मात्रा में होता है।

कुछ सम्भावित हानियाँ (Some Probable Demerits)

संरक्षण की नीति के पक्ष में दिए जाने वाले तर्कों का अध्ययन करने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि यह नीति एक अर्थ-व्यवस्था की रक्षा एवं विकास के लिए जरूरी है। इतने पर भी आलोचकों ने इसकी जिन विभिन्न कमियों का उल्लेख किया है उनको ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि संरक्षण की नीति कोई आदर्श नीति नहीं है वरन् यह विशेष परिस्थितियों में अपनाई जाने वाली एक मजबूरी का प्रतीक है। इस नीति के विभिन्न लाभों एवं उपयोगों के अतिरिक्त अनेक हानियों का भी वर्णन किया जा सकता है—

(1) इसके द्वारा अधिकतम सामाजिक उत्पादन असम्भव बन जाता है क्योंकि यह देश के उद्योगों को केवल नकारात्मक सहयोग प्रदान करती है। आयात की वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगाकर यह स्वदेशी वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा को कम करती है। इसके कारण स्वदेशी उद्योग अपनी कुछ समस्याओं से मुक्ति अवश्य पा सकते हैं किन्तु वे अपने उत्पादन को विधायी रूप से नहीं बढ़ा सकते।

(2) संरक्षण की नीति दुर्बल उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करती है। यह असमर्थ एवं प्रतिस्पर्धा में टिकने की शक्ति न रखने वाले उद्योगों को सहारा प्रदान करके उन्हें जैसे-तैसे बने रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। यदि इन दुर्बल उद्योगों से संरक्षण हटा लिया जाए तो वे समाप्त हो जाएंगे। असमर्थ उद्योगों को बनाए रखना निश्चय ही समर्थ उद्योगों के हित के विपरीत है।

(3) संरक्षण की नीति के फलस्वरूप आयात की वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार देश के उपभोक्ताओं की हानि होती है।

(4) यह नीति देश में विभिन्न प्रकार से भ्रष्टाचार को जनपने का अवसर देती है।

(5) इसके फलस्वरूप एकाधिकारों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि प्रतिस्पर्धा में विदेशी व्यापार को पीछे हटा दिया जाता है और देशी उत्पादन चाहे किसी भी स्तर का और किसी भी कीमत का हो, सामने लाया जाता है। एकाधिकार की प्रवृत्ति अनेक प्रकार से हानिकारक सिद्ध होती है। इससे स्वदेशी व्यापारियों को मनमानी करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

(6) जब निश्चित लाभ की मात्रा सुरक्षित हो जाती है तो उद्योगों में शिथिलता आने लगती है अर्थात् संरक्षण की नीति को अपनाकर जब विशेष उद्योगों की प्रतिस्पर्धा के तीखे प्रहारों से बचाने का प्रयास किया जाता है तो वे उद्योग स्वयं को आगे बढ़ाने में शिथिलता का अनुभव करने लगते हैं। उनके सामने कोई चुनौती या प्रतियोगिता नहीं रहती जिसके कारण वे अपने उत्पादन के स्तर को ऊँचा उठाने की सोचें। जब उन्हें यह ज्ञात है कि लाभ की एक निर्धारित मात्रा सरकारी संरक्षण की छाया में उनको मिलकर रहेगी तो वे अपने विवास की चिन्ता करने की सक्तीफ नहीं उठाते।

(7) यह नीति घट्ट करों की मात्रा का बढ़ाकर निर्यात व्यक्तियों के कर भार को कई गुना कर देती है और इस प्रकार मन्त्रालय में घन विवरण की असमानता बढ जाती है।

(8) इस नीति के कारण राष्ट्रों के बीच के सम्बन्ध बढू बन जाते हैं। उनकी प्रतिस्पर्धिता मधीपूर्ण सम्बन्धों में अहम घोल देती है। इन सबके अनिर्दिष्ट सरक्षण की नीति का एक गलत प्रभाव यह भी होता है कि इसके द्वारा विदेशी व्यापार की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि जब एक देश अपने आयात पर प्रतिबन्ध लगाता है तो दूसरे देश में प्रतिक्रिया स्वल्प उनके निर्यात पर प्रतिबन्ध लग जाना है। इन सबका परिणाम यह निकलना है कि विदेश व्यापार की मात्रा घट जाती है।

स्पष्ट है कि सरक्षण की नीति बहुत उपयोगी नहीं है वरन् इसका विपरीत पक्ष भी है। यदि इसका अनुचित रूप से प्रयोग किया गया तो यह नीति आर्थिक विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया को अस्त-व्यस्त कर सकती है। निकलन के मतानुसार, स्वतन्त्र व्यापार इमानदारी की भाँति अभी भी सर्वश्रेष्ठ नीति है। एगवथ न लिखा है कि सरक्षण की नीति कुछ मामलों में उपयोगी हो सकती है यदि वहाँ की सरकार उनको प्रसंग करने की बुद्धि तथा तदनुसार व्यवहार करने का साहस रखती हो। यह बात प्रायः पूरी नहीं हो पाती।

उपभोक्ता वस्तुओं पर यदि आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिए जाएँ तो मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इस प्रकार सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था का स्थायित्व मनरे में पड़ जाता है। आयात की वस्तुओं पर होने वाला व्यय परलू प्रयत्न निर्यात योग्य वस्तुओं की ओर मुड़ जाता है। प्रथम से मुद्रा-प्रसार और द्वितीय से विदेशी मुद्रा की प्रायः में कमी हो जाती है। विश्व-व्यापार में होने वाली प्राप्ति कम हो जाती है और विश्व के आर्थिक कल्याण की क्षति होती है। यदि घरेलू तथा निर्यात योग्य वस्तुओं की पूर्ति पर्याप्त लोचनीय है तो मुद्रा प्रसार प्रयत्न निर्यात में गिरावट नहीं होगी।

आयात-प्रतिबन्धों में यदि समय-समय पर परिवर्तन आते रहते हैं तो इसका फलस्वरूप आयात-कर्ता पहले से ही बहुत बड़ी खरीददारियाँ कर लेते हैं। इससे न केवल भुगतान सन्तुलन की समस्या उत्पन्न होती है वरन् निवेश भी उत्पादक उद्यमों में हट जाता है। सरक्षण अपने आप में पर्याप्त नहीं है। यह विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। उद्योगों की स्थापना एवं वृद्धि संचालन द्वारा इन अवसरों का प्रयोग करके ही वास्तव में विकास किया जा सकता है। नए उद्योगों के संचालन के लिए बड़ी पूँजी चाहिए, अधिकतर घट्ट विकसित देशों में यह नहीं होती। फलतः सरक्षण की नीति हानिप्रद सिद्ध होती है। रोजगार वृद्धि की दृष्टि से भी ये प्रतिबन्ध अधिक सहायक नहीं होते। इनसे विकसित देशों के भुगतान सन्तुलन का आधिक्य कम होता है और घट्ट विकसित देशों में निवेश नहीं कर पाते।

घट्ट विकसित अर्थ-व्यवस्था में सरक्षण के कारण
(The Cause for Protection in Less Developed Economies)

विकसित अर्थ-व्यवस्था घट्ट-विकसित अर्थ-व्यवस्था की आर्थिक समस्याएँ भिन्न भिन्न होती हैं और विकसित तथा घट्ट-विकसित देशों के सम्बन्ध में अपनी

जाने वाली आर्थिक नीति मौलिक रूप से परस्पर भिन्न होती है। अतः विकासशील देशों में अपनाई जाने वाली व्यापारिक-नीति अर्द्ध-विकसित देशों में प्रत्यारोपित नहीं की जा सकती। इन देशों की प्रमुख समस्या आर्थिक विकास की है। इसलिए इन देशों के सन्दर्भ में वही व्यापारिक-नीति अधिक उपयुक्त होगी जो कि आर्थिक विकास की गति को तीव्र कर सके।

अर्द्ध-विकसित देशों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आर्थिक-विकास के सन्दर्भ में व्यापारिक-नीति की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है—“व्यापारिक-नीति आर्थिक-नीति का वह अंग है जिसका सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय-आर्थिक-सम्बन्धों के इस प्रकार नियमन से है जिससे (अ) अन्तर्राष्ट्रीय-व्यापार में अधिकाधिक लाभ मिल सके, (ब) देश में औद्योगीकरण को प्रोत्साहन मिले, (स) पूँजी-निर्माण की दर में वृद्धि हो, तथा (द) भुगतान के संतुलन में अत्यधिक निर्यात के स्तर पर साम्य की स्थिति प्राप्त हो सके।”

नीति का स्वरूप

अब प्रश्न यह उठता है कि अर्द्ध-विकसित देशों में स्वतन्त्र-व्यापार नीति का अनुकरण किया जाए या संरक्षण-नीति का। स्वतन्त्र व्यापार नीति का प्रतिपादन प्रतिष्ठित अर्थ-शास्त्रियों ने किया था। उनका मत था कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो तो सम्पूर्ण विश्व के उत्पादन में वृद्धि होगी। प्रतिष्ठित अर्थ-शास्त्रियों का यह मत मुख्यतः तुलनात्मक सागत सिद्धान्त पर आधारित है। तुलनात्मक सागत का सिद्धान्त कुछ मान्यताओं पर आधारित है। इन सिद्धान्त की ये मान्यताएँ उचित नहीं हैं कि विकास के प्रसंग में संसाधनों की पूर्ति निश्चित है। रचिदा स्थिर हैं, तकनीकी ज्ञान पहले से ही विद्यमान है, पूँजी का अन्तर्राष्ट्रीय आवागमन शून्य है, पूर्ण रोजगार व पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति विद्यमान है तथा इसके साथ-साथ आयात और निर्यात परस्पर बराबर हैं। इस सिद्धान्त की मान्यताएँ ही इसकी स्थैतिक रूप प्रदान करती हैं और यह स्पष्ट करती हैं कि यह सिद्धान्त व्यवहार से बहुत दूर है। स्पष्टतः चूँकि तुलनात्मक-सागत का सिद्धान्त आर्थिक-विकास की पृष्ठभूमि पर आधारित नहीं है, इसलिए इसे विकासशील देशों में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सत्य तो यह है कि इस सिद्धान्त की मान्यताएँ ही अर्द्ध-विकसित राष्ट्र की समस्याएँ हैं। इन देशों में बेरोजगारी की समस्या बड़ी विकराल है, इसलिए समस्या पूर्ण रोजगार की प्राप्ति की है, अतः पूर्ण रोजगार की मान्यता सर्वथा गलत है। इन देशों की समस्या एक निश्चित उत्पादन-फलन पर चलने की नहीं है बल्कि उमी में परिवर्तन की है। इन देशों में उत्पादन के साधनों का उचित विदोहन नहीं हो पाता, इसलिए प्रयास रुदेव यही रहना है कि नई तकनीकी के द्वारा उत्पादन के साधनों का विकास हो।

संक्षेप में, चूँकि स्वतन्त्र-व्यापारिक-नीति जिन मान्यताओं पर आधारित है वे आर्थिक-विकास के सन्दर्भ में नहीं बल्कि एक अर्थ में आर्थिक-विकास के पश्चात् की अवस्था की प्राप्ति के ऊपर आधारित हैं, इसीलिए स्वतन्त्र-व्यापारिक-नीति का अर्द्ध-विकसित देशों के विकास के सन्दर्भ में कोई महत्त्व नहीं है।

है। अमेरिकन उद्योगों के जिशु प्रवस्था में होने के कारण वहाँ की प्राथिक स्थिति अन्य देशों की अपेक्षा उतनी अच्छी नहीं थी। इसीलिए उसने अमेरिका के लिए सीमित सरक्षण की नीति का समर्थन किया था। वस्तुतः देश में निर्माण उद्योगों के विकास के लिए सरक्षण के पक्ष में गम्भीर व तार्किक तर्क फेडरिक लिस्ट ने ही प्रस्तुत किया था। अमेरिकन सरक्षण-नीति के आधार पर लिस्ट ने जर्मनी में निर्माण उद्योगों के विकास के लिए सरक्षण-नीति का समर्थन किया। औद्योगीकरण के लिए आवश्यक साधन पर्याप्त मात्रा में होते हुए भी जर्मन उद्योगों के अविकसित प्रवस्था में बने रहने का एकमात्र कारण यह था कि इन उद्योगों को इंग्लैण्ड के विकसित उद्योगों से प्रतियोगिता करनी पड़ती थी। लिस्ट इस सत्य से भली-भाँति परिचित थे कि जो स्वतन्त्र व्यापार की नीति इंग्लैण्ड के लिए समृद्धि का स्रोत थी वही नीति जर्मनी के प्राथिक तथा औद्योगिक विकास के लिए अभिशाप ही रही थी। लिस्ट के विचारानुसार सरक्षण एक घटते-विकसित राष्ट्र के औद्योगिक तथा प्राथिक विकास की कुञ्जी है। लिस्ट के अनुसार, "राष्ट्र के उत्पादक-माधनों में निर्माण उद्योग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं से राष्ट्र की नैतिक-शक्तियों का भन्ततः विकास होता है। उसके अनुसार उसके समय की सबसे बड़ी आवश्यकता यह थी कि निर्माण उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए।" लिस्ट के लिए उद्योग एक महान् सामाजिक शक्ति है जो पूँजी और श्रम को जन्म देती है। यदि इनकी स्थापना के लिए राष्ट्र को वर्तमान में त्याग भी करना पड़े तो यह मूल्य अधिक नहीं है। उसने बार-बार कहा है कि केवल निर्माण उद्योगों की समृद्धि पर ही जहाजराती प्रान्तरिक एवं विदेशी-व्यापार तथा कृषि की समृद्धि निर्भर करती है। लिस्ट का विश्वास था कि यदि कोई देश उचित समय पर निर्माण उद्योगों का संचार कर देता है तो कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन-शक्ति एक-दूसरे को बढ़ावा देने में सहायता करेगी। लिस्ट ने कृषि पर निर्भर रहने वाले राष्ट्रों की तुलना केवल एक हाथ रखने वाले व्यक्ति से की है। निर्माण उद्योग विज्ञान तथा ललितकलाओं के जिशु भी हैं और साथ ही उसका पालन-पोषण भी करते हैं।

प्रश्न यह उठता है कि निर्माण उद्योगों का विकास किस प्रकार होगा? एडम स्मिथ एवं प्रतिष्ठित लेखकों का मत था कि श्रम तथा वस्तु से उद्योग उत्पन्न होते हैं और वे कुछ समय बाद स्वयं विकसित हो जाएंगे। किन्तु लिस्ट ने संरक्षण साधनों की सहायता से एक नियोजित आधार पर निर्माण उद्योगों का विकास करने को कहा।

इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा है, "यह सत्य है कि अनुभव यह सिखाता है कि हवा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बीजों को उड़ाकर ले जाती है और इस प्रकार वनर स्थान घने जंगलों में परिवर्तित हो गए, किन्तु क्या जंगल के अफसर के लिए यह उचित होगा कि वह उस समय तक प्रतीक्षा करता रहे जब तक कि हवा के चलने से पर्याप्त समय में यह परिवर्तन सम्भव हो सके?"

लिस्ट का मत है कि संरक्षण नीति साधारण प्रकार की प्राथिक-नीति नहीं है जिसकी सुविधा सभी देशों को अथवा किसी देश को सब समय प्राप्त हो सकती

है। विकसित देशों का इस सरक्षण से कोई सम्बन्ध नहीं है। केवल ग्रहं विकसित देश ही इस सरक्षण की सुविधा को प्राप्त करके इसके द्वारा अपना औद्योगिक विकास कर सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि ग्रहं विकसित देशों को भी यह अधिकार सदा के लिए प्राप्त नहीं है। यह सुविधा एक शर्त युक्त सुविधा है, जिसका प्रयोग केवल उसी समय तक किया जा सकता है जब तक राष्ट्र के उद्योग सुदृढ़ नहीं हो जाते हैं। इस प्रकार लिस्ट के अनुसार विकास को निम्न अवस्था से निकाल कर, उच्च अवस्था तक पहुँचाने के लिए सरक्षण एक महत्वपूर्ण साधन है। लिस्ट ने स्वयं अपने इस सरक्षण की विवेचनाओं की निम्नलिखित प्रकार की व्याख्या की है—

(अ) सरक्षण-प्रणाली उसी समय न्यायसंगत हो सकती है जबकि उसका उद्देश्य राष्ट्र को औद्योगिक शिक्षा प्रदान करना हो। ऐसी दशा में यह स्पष्ट है कि इंग्लैंड जैसा विकसित राष्ट्र, जहाँ औद्योगिक शिक्षा का पूरा प्रसार हो चुका है, के लिए यह नीति उपयुक्त नहीं है।

(ब) सरक्षण-नीति केवल उन्हीं राष्ट्रों को अपनानी चाहिए, जो शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्रों से बड़ी प्रतियोगिता का सामना कर रहे हों।

(स) किसी भी राष्ट्र की आर्थिक-नीति में सरक्षण को एक स्थायी स्थान नहीं प्रदान किया जाना चाहिए अर्थात् सरक्षण केवल उनही समय तक प्रदान किया जाना चाहिए जब तक वह उद्योग सुदृढ़ नहीं बन जाता है।

(द) कृषि को कभी भी सरक्षण नहीं देना चाहिए क्योंकि एक ओर तो कृषि सम्पन्नता स्वयं औद्योगिक सम्पन्नता पर निर्भर करनी है और दूसरी ओर यदि कृषि को सरक्षण प्रदान किया जाएगा तो खाद्य सामग्री तथा अन्य औद्योगिक कच्ची सामग्री की कीमतों में वृद्धि होगी, जो स्वयं राष्ट्र के उद्योगों के विकास के लिए घातक सिद्ध होगी।

(2) शिशु उद्योग—विकासशील देश में शिशु उद्योगों का सरक्षण एक अनिवार्यता है, क्योंकि सरक्षण के बिना वे उद्योग कभी भी विकसित होने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने स्वतन्त्र व्यापार का समर्थन करते हुए भी शिशु उद्योगों के लिए सरक्षण आवश्यक माना है। पीगू के मतानुसार 'ऐसी कृषि प्रधान अर्थ-व्यवस्था में, जिसमें उद्योगों के लिए प्राकृतिक सुविधाएँ उपलब्ध हों, उत्पादन-शक्ति के निर्माण के दृष्टिकोण से सरक्षण के पक्ष में दी गई दलील मजबूत और ठोस है। ऐसे देश में विदेशी वस्तुओं के साथ देशी वस्तुओं का विनिमय पर रोक लगाने से होने वाली हानि की अपेक्षा यह लाभ अधिक होगा जो देश की औद्योगिक शक्ति के अधिक तीव्र विकास से उत्पन्न होगा।' अतः यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाकर देश के उद्योगों के लिए विदेशी-प्रतियोगिता न्यूनतम की जा सके और पिछड़े हुए कृषि प्रधान देश अपना औद्योगिक विकास कर सकें तो अन्तर्राष्ट्रीय-व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाना युक्तिपूर्ण और तर्कसंगत होगा। वास्तव में सरक्षण ने आधुनिक औद्योगिकरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया है। अधिकशतक प्रत्येक औद्योगिक राष्ट्र को अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए एक अत्यन्त हीन अवधि तक अपने उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से

संरक्षण द्वारा ही बचाया जाता है। अतः यह धारणा से कहा जा सकता है कि संरक्षण के द्वारा प्राकृतिक साधनों, मानवीय योग्यता व दूरदर्शिता को भली प्रकार उपयोगी बनाता है।

एनके व सनेरा के मतानुसार शिशु-उद्योगों के संरक्षण प्रदान करने के लिए तीन शर्तें आवश्यक होती हैं—

(i) वे उद्योग संरक्षण के लिए योग्य हैं, जो कि दीर्घकाल में आत्म-निर्भर हो जाएँगे,

(ii) ऐसे उद्योगों जिन्होंने प्रारम्भिक काल में काफी दुर्घटन उठाया हो, तथा

(iii) ऐसे उद्योग जिनका संरक्षण के प्रभाव में स्थापित करना ही प्रसम्भव हो। परन्तु विकासशील देशों में प्रत्येक उद्योग के लिए पृथक् से संरक्षण की माँग का अध्ययन करना उचित नहीं माना जाता है क्योंकि संरक्षण के लिए यदि प्रत्येक उद्योग का व्यक्तिगत तौर पर अध्ययन किया जाएगा तो दीर्घकाल में भी उनके अपने पैरों पर खड़े होने की सम्भावना बहुत ही कम हो जाएगी। विकासशील राष्ट्रों में उद्योग अपने पैरों पर सभी खड़े हो सकते हैं जबकि बहुत से उद्योगों का एक साथ विकास किया जाए तथा देश की आर्थिक संरचना व सामाजिक वातावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाएँ क्योंकि प्रत्येक उद्योग कुछ न कुछ ऐसी बाहरी मितव्ययिताएँ उत्पन्न करता है, जो किसी दूसरे उद्योगों के विकास व सफलता के लिए अवसर प्रदान करती है। जैसे कि लोहा, इस्पात, रेल तथा उर्वरक आदि उद्योगों के विकास से अन्य उद्योगों को सस्ती दरों पर कच्चे माल आदि अन्य साधन कम मूल्य पर प्राप्तानी से उपलब्ध होने लगेंगे जिससे इनका विकास तीव्र गति से होने लगेगा। जिससे वे जल्दी ही अपने पैरों पर खड़े हो जाएँगे। इसीलिए प्रो. लकड़ावाला ने विकासशील राष्ट्रों में किसी उद्योग विशेष की अपने पैरों पर खड़े होने की सम्भावना के आधार पर पृथक् से संरक्षण की माँग का अध्ययन का विरोध करते हुए उन्हीने कहा कि संरक्षण का अध्ययन उस औद्योगिक वातावरण में करना चाहिए जिसमें कि उद्योगों के लिए बाहरी मितव्ययिताएँ उपलब्ध होती हैं। परन्तु निकोलस कालडोर का मत है कि “जब तक उत्पादन-लागतें एवं बाह्य-मितव्ययिताओं की मात्राएँ अनिश्चित बचती रहेंगी तब तक उपयुक्त शिशु-उद्योगों का सही चुनाव करना अनिश्चित ही रहेगा। अतः कुछ विशेष उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए काफी मात्रा में चयनात्मक टैरिफ लगाने से अधिक कार्य साधक बात यह होगी कि सारे औद्योगिक-उत्पादनों पर समान रूप से यथा-मूल्य-गुल्क (Ad valorem duties) लगा दिया जाए और उसके बाद शिशु-उद्योगों के चुनाव का वाजार के बल पर छोड़ दिया जाए।”

(3) व्यापार शर्तों में सुधार—आर्थिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था में संरक्षण के फलस्वरूप व्यापार की शर्तों में सुधार होता है। एक विकासशील देश के पक्ष में व्यापार शर्तों में सुधार राष्ट्रीय आय की वृद्धि के समान है। यदि कोई देश तटवर लगा देता है तो इसके फलस्वरूप आयात का मूल्य कम हो जाएगा

अर्थात् निर्यात का कुल मूल्य बढ़ जाएगा तो ऐसी अवस्था में देश की व्यापार शक्तों में सुधार हो जाएगा और आर्थिक विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय साधनों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार सरक्षण की नीति से पूंजी निर्माण में मदद मिलती है।

(4) आर्थिक नियोजन—भद्र विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक-नियोजन एक आवश्यक अंग माना गया है। आर्थिक-नियोजन के अन्दर देश की सरकारें उत्पादन, उपभोग, वितरण व विनियोग आदि क्रियाओं पर नियन्त्रण और नियमन करती है। अतः यह स्वाभाविक है कि अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने अन्तर्राष्ट्रीय-व्यापार पर भी नियन्त्रण करने के लिए सरक्षण-नीति को अपनाएँ।

(5) विनियोजन में वृद्धि—व्यापार-नियन्त्रण द्वारा अनावश्यक वस्तुओं के आयात पर नियन्त्रण लगाने से बचन में वृद्धि होती है और लाभदायक विनियोग के अवसरों में भी वृद्धि होती है। देश में जितनी अधिक बचन होगी, पूंजी निर्माण की मात्रा उतनी ही अधिक बढ़ेगी, जिसे आर्थिक विकास के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

(6) राशिपातन से सुरक्षा—राशिपातन की सहायता से विकसित देश विकासशील देशों में अपने माल की बिक्री के लिए एक स्थायी बाजार बनाने का प्रयत्न करत है अतः राशिपातन से बचाव के लिए व्यापार का सरक्षण करना आवश्यक होता है।

(7) मजदूरी प्रमाण की सुरक्षित करना—समाजवाद की भावना का बनाए रखन एवं साम्यवाद से बचाव हेतु अनेक विकासशील देशों ने बर्खास्तकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य रखा हुआ है। विश्व मूल्यों के आधार पर विकसित राष्ट्रों के समान विकासशील राष्ट्रों के श्रमिकों ने भी अपनी सीमान्त-उत्पादकता से अधिक मजदूरी की मांग की है। अतः आयात पर नियन्त्रण आवश्यक है, जिससे सीमान्त उत्पादकता से अधिक मजदूरी मुक्तान करने से उद्योगों को सुरक्षित रखा जा सके।

(8) तकनीकी परिवर्तनों से उद्योग की सुरक्षा—विकासशील राष्ट्रों में आयात-नियन्त्रण विदेशों में होने वाले तकनीकी परिवर्तनों से उद्योगों को बचाने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं क्योंकि इससे उपभोक्ता को लाभ कम होते हैं जबकि उत्पादकों का अधिक हानि सहन करनी पड़ती है। ऐसे प्रसिद्ध कथन पूंजी वाले विकासशील राष्ट्रों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है विशेषकर जहाँ (घ) प्लान्ट का जीवन लम्बा हो, (ब) विशेष प्रकार का प्लान्ट हो जिसमें कि गतिशीलता का अभाव हो, तथा (ग) स्वदेशी माल और आयातित माल के बीच मूल्यों में बहुत कम अन्तर हो।

(9) वर्तित परिस्थितियों के अनुकूल—विकासशील राष्ट्रों के लिए सरक्षण नीति को वर्तमान शताब्दी की परिवर्तित-परिस्थितियों के आधार पर उचित ठहराया जाती है। क्योंकि आजकल विश्व-ग्रंथ व्यवस्था की भावना समाप्त

हो गयी है और सम्पूर्ण विश्व पारस्परिक मन मुटाव और संघर्षों से परिपूर्ण हो गया है। ऐसी अवस्था में किसी देश को अनिवार्य वस्तुओं के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर रहना खतरे से खाली नहीं है। अतः वर्तमान युग में सरक्षण नीति की व्यवस्था करना एक अनिवार्यता हो गई है जिससे देश शीघ्र ही आत्मनिर्भरता तथा पूर्ण-रोजगार की अवस्था प्राप्त कर सके।

(10) सरकारी आय का स्रोत—तटकर सरकारी आय का एक प्रमुख स्रोत है। तटकर से सरकार को आय प्राप्त होती है और साथ में उद्योगों को सरक्षण भी प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे कर प्रायः विदेशियों द्वारा भुगतान किए जाते हैं। यदि तटकर की दर कम होती है तो सरकार की आय में तो वृद्धि हो सकती है परन्तु धरेलू उद्योगों को इससे ज्यादा सरक्षण प्राप्त नहीं हो पाता है।

अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में निर्यात की व्यापारिक रुकावटें
(Trade Barriers to Export of Less-Developed Economies)

अर्द्ध-विकसित विश्व विभिन्न प्रकार के देशों का समूह है। इन देशों की अर्थ-व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के अन्तर पाए जाते हैं किन्तु इतना सच होने हुए भी इन अर्द्ध-विकसित देशों में एक आधारभूत समानता पाई जाती है। यद्यपि किसी एक देश को प्रतिनिधि अर्द्ध-विकसित देश की सजा देना कठिन है किन्तु फिर भी कुछ ऐसे सामान्य कारणों को अवश्य ही बनाया जा सकता है जो कि ग्रामनीय पर इनके द्वारा किए जाने वाले निर्यातों में रुकावटें उत्पन्न करते हैं वे निम्नानुसार हैं—

1. औद्योगीकरण का अभाव—अर्द्ध-विकसित देशों में आधुनिक ढंग के बड़े पैमाने के उद्योगों का अभाव रहता है। यद्यपि इन देशों में उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग तो यज्ञ-तन स्थापित होने लगते हैं, परन्तु आधारभूत उद्योगों जैसे मशीन, यन्त्र, इस्पात आदि उद्योगों का लगभग अभाव रहता है और शेष उद्योगों के लिए भी ये मशीनें आदि के लिए आयात पर निर्भर रहते हैं। परिणामस्वरूप इन देशों से कच्चा माल भारी मात्रा में निर्यात किया जाना है और यह निर्यात भी मुख्य रूप से एक दो पदार्थों पर ज्यादा निर्भर करता है जिससे इनकी अर्थ-व्यवस्था एकान्गी हो जाती है। यदि इन वस्तुओं की विदेशी माँग कम हो जाती है तो इन देशों के निर्यात की अवस्था और भी खराब हो जाती है अतः जब तक आधारभूत निर्यात-उद्योगों का निर्माण नहीं होता है तब तक इनके निर्यात में वृद्धि नहीं हो पाती है।

2. आय प्रभाव और कोमत प्रभाव—विकास कार्यक्रमों में किए जाने वाले भारी विनियोग के भी परोक्ष रूप से आय-प्रभाव और कोमत प्रभाव उत्पन्न होते हैं वे भी निर्यात को कम कर देते हैं। कारण यह है कि आर्थिक-विकास की योजनाओं पर सरकार भारी मात्रा में विनियोग करती है, जिससे समाज में क्रय-शक्ति का प्रसार होता है और लोगों की आय बढ़ती है। अर्द्ध-विकसित देशों में सीमान्त-उपभोग-प्रवृत्ति अधिक होने के कारण वस्तुओं की माँग में वृद्धि होती है परिणामस्वरूप निर्यात घट जाते हैं क्योंकि कुछ वस्तुएँ जिनका पहले निर्यात किया जाता था अब आय बढ़ने के कारण देश में ही वे वस्तुएँ उपभोग की जाने लगती हैं।

भारी विनियोजन का कीमतों पर भी प्रभाव पड़ना है, जिनके कारण निर्यात की मात्रा प्रभावित होती है। घट्टे विकसित देशों में सामान्यतया विनियोजन ऐसी दीर्घकालीन प्रयोजनाओं पर किया जाता है जिनमें एक लम्बी अवधि के पश्चात् प्रतिकूल प्राप्त होने हैं। फलतः सरकार के व्यय में तो वृद्धि वर्तमान समय में होती है लेकिन उस व्यय के परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि काफी समय के पश्चात् होती है। इसका तात्कालिक प्रभाव यह होता है कि कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों में वृद्धि के कारण आयात प्रोत्साहित होने हैं, और निर्यात निरुत्साहित। साथ ही अर्थ-व्यवस्था में कीमत स्तर ऊँचा होने के कारण उत्पादकों को वस्तुओं निर्यात करने के लिए प्रोत्साहन नहीं रहता है क्योंकि उन्हें आन्तरिक बाजार में ही वस्तुओं की अच्छी कीमत मिल जाती है। फलतः निर्यात की मात्रा आयात की प्रेरणा और कम हो जाती है।

3. विशिष्टीकरण—घट्टे-विकसित देशों ने मुख्य रूप से कृषि और खनिज पदार्थों के निर्यातों में विशिष्टीकरण प्राप्त किया है, जिनकी माँग की प्रायः लाच बहुत कम होती है। इसके विपरीत, समर्थन देशों ने मुख्य रूप से पूँजीगत व औद्योगिक वस्तुओं के निर्यात में विशिष्टीकरण प्राप्त किया है। इन वस्तुओं के लिए माँग की प्रायः लोच अपेक्षाकृत ऊँची होती है। ज्यों ही एक देश की राष्ट्रीय-माँग बढ़ती है त्यों ही निम्न वस्तुओं पर हाने वाले खर्च का अनुपात बढ़ जाता है, परन्तु साधन आदि पर व्यय का अनुपात घट जाता है। इस प्रकार विश्व की प्रायः में वृद्धि के साथ-साथ औद्योगिक देशों के निर्यातों की माँग बढ़ जाती है और प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले देशों की निर्यात की माँग कम हो जाती है।

4 जनसंख्या—विकासशील देशों की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन देशों में आयातों की आवश्यकताएँ भी बढ़ गई हैं। दूसरी ओर विकसित देशों में जनसंख्या में अधिक वृद्धि न होने के कारण वहाँ घट्टे-विकसित देशों में होने वाले निर्यातों की माँग का प्रसार रुक गया है। साथ ही अतीत काल में अधिकांश विदेशी गैर सरकारी विनियोग घट्टे-विकसित देशों में निर्यात उद्योगों में लिए जाते थे। यह प्रवृत्ति अभी भी बनी हुई है। प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले देशों में अर्थात् घट्टे-विकसित देशों में निर्यात उद्योगों का प्रसार होने के कारण उनके निर्यातों की कीमतें घट गई हैं।

5 आयात नियन्त्रण—औद्योगिक-देशों में प्रायः घरेलू कृषि-उद्योगों की रक्षा के लिए कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं फलतः इन देशों में कृषक देशों के निर्यातों की माँग घटती है। अमेरिका आदि कुछ विकसित देशों में स्वयं के कृषि उद्योग में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने के लिए न केवल कृषि सम्बन्धी आयातों पर प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं, बल्कि कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के निर्यातों की सहायता करके अनुचित रूप से कम विकसित देशों के साथ प्रतियोगिता भी की जाती है। इससे परिणामस्वरूप घट्टे विकसित देशों के निर्यात विपरीत रूप से प्रभावित होते हैं।

6. नीची निर्यात साख—विकासशील देशों के निर्यात की साख बहुत नीची होती है, जबकि विकसित देशों के माल की साख विश्व-बाजारों में पहले से ही जम चुकी होती है। अतः अर्द्ध-विकसित देशों के वस्तुओं की माँग कम होती है।

7. कमजोर विक्रय शर्तें—विकासशील देशों का माल अच्छी किस्म का होने पर भी कमजोर विक्रय-शर्तों के कारण विकसित देशों की प्रतिस्पर्धा में नहीं विक पाता है क्योंकि विकसित देश बड़ी मात्रा में साख सुविधाएँ, माल की सुपुर्दगी और विक्रय के बाद की अन्य सुविधाएँ दे सकते हैं, जो सामान्यतया विकासशील देशों द्वारा सम्भव नहीं होती हैं।

8. विकसित देशों में उत्पादन वृद्धि—अनेक विकसित देशों में घरेलू तीर पर लाघानों और अन्य कच्चे मालों का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया है, जिससे विकासशील देशों के निर्यात कम हो गए हैं।

9. विदेशों में बित्री करने वाली समस्याएँ—विकासशील राष्ट्रों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए विदेशों में जो सस्यागत रूप रचना इस समय स्थित है वह अनुपयुक्त है। अधिक वस्तुओं की माँग होने पर वह दोष और भी अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। निर्यात-ध्यापार को अच्छी तरह से चलाने के लिए विदेशी बाजारों में इन देशों के उपयुक्त संगठनों का होना अति आवश्यक होता है।¹

विकासशील देशों के इन संगठनों में निर्यातक फर्मों का प्रतिनिधित्व भी बहुत जरूरी होता है। जब तक विदेशी बाजारों में प्रतिनिधित्व नहीं रखा जाएगा, तब तक निर्यातक फर्में विदेशी खरीददारों की बढती हुई माँगों को पूरा नहीं कर पाएँगी। इनके अभाव में विकासशील राष्ट्रों के निर्यातकों को विदेशी आवश्यकताओं के परिवर्तनों की तुरन्त जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है जिससे वे विकसित राष्ट्रों की प्रेषणा पिछड़ जाते हैं।

10. अनुचित व्यवहार—विकासशील राष्ट्रों के निर्यातकर्त्ताओं के अनुचित व्यवहार के विरुद्ध अनेक शिकायतें की जाती हैं। जैसे कि माल भेजने में देरी, माँगे गए माल के गुण और भेजे गए माल के गुण में अन्तर, खराब पैकिंग तथा मार्किंग आदि। अतः निर्यातकर्त्ताओं के गलत व्यवहार से भी निर्यात की मात्रा प्रभावित होती है।

11. पैकिंग—विकासशील राष्ट्रों के द्वारा जो वस्तुएँ निर्यात की जाती हैं उनकी पैकिंग की तरफ इन राष्ट्रों द्वारा विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इन राष्ट्रों के निर्यातकर्त्ता इसे फालतू का खर्चा समझते हैं। इसी कारण से इन राष्ट्रों का जब प्रायातकर्त्ता देश के पास पहुँचता है तब वह बड़ा ही अव्यवस्थित हो जाता है।

विपरीत विकसित राष्ट्रों से जो माल निर्यात किए जाते हैं उनके पैकिंग बड़े ही अच्छे तथा आकर्षक होते हैं। इस कारण से भी विकासशील राष्ट्रों के निर्यात की मात्रा के बढ़ने में रुकावट आती है।

**प्राथमिक उत्पादक मूल्यों का
स्थिरीकरण एवं विकासशील
अर्थव्यवस्था के मध्य क्षेत्रीय
आर्थिक सहयोग का भूमिका
(STABILISATION OF PRIMARY PRODUCT
PRICES AND ROLE OF REGIONAL
ECONOMIC COOPERATION BETWEEN
LESS DEVELOPED ECONOMIES)**

सन् 1929 से 1933 की मन्दी के बाद मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मूल्य-स्तर में स्थिरता और व्यापारिक चक्रों की स्थिरता बन गया है। प्रायःकल अधिकांश अर्थ-शास्त्रियों, मुख्यतः कैमिल और कीन्स का मन है कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य देश के आन्तरिक मूल्य को स्थिर बनाए रखना होना चाहिए। यहाँ पर प्राथमिक उत्पादक मूल्यों के स्थिर रखने का प्राणय यह नहीं है कि सभी प्रलग-प्रलग और सामूहिक कीमतें स्थायी रहे बल्कि इसका मतलब केवल मात्र यह है कि थोके कीमत निर्देशक द्वारा सूचित औसत मूल्य स्तर को मामूली सीमाओं में अधिक घटने-बढ़ने नहीं देना चाहिए।

मौद्रिक नीति के अन्तर्गत मूल्य स्थिरता का उद्देश्य अमेरिका की न्यू डील योजना में सरकार द्वारा 6 जनवरी, 1937 को अनाया गया जबकि तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रूजवेल्ट ने अमेरिकी संसद को अपने वार्षिक ध्यादेशन में बताया कि "यह राष्ट्र के हित में है कि वह सरकार से प्राइवेट साहस की सहायता करने का वही जिससे सामान्य स्तर को पुनः प्राप्त किया जाए तथा प्राप्त होने वाले स्तर को व्यापक खतरे तथा उतार-चढ़ाव से बचाया जा सके।"

स्थिरीकरण के पक्ष में तर्क

प्राथमिक उत्पादक मूल्यों में अस्थिरता के कारण बहुत-सी बड़नाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं जैसे कि—

1. गिरते हुए मूल्यों की अवधियों में व्यापार चौकट हो जाता है और रोज़गार व उत्पादन में भारी कमी हो जाती है।
2. बढ़ती हुई कीमतें प्रायः के विनरण में असमानता को बढ़ावा देती है।

3. आन्तरिक मूल्यों में अस्थिरता स्वभाव में संचयी होती है अर्थात् एक बार प्रारम्भ होने के पश्चात् यह दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाती है और उससे सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के टूटने का भय उत्पन्न हो जाता है और अनेक राजनीतिक क्रान्तियाँ जन्म लेती हैं जैसा कि लिण्डन बर्नेन्सन ने कहा था कि “मुद्रा प्रसार का प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षा के पश्चात् दूसरे नम्बर के महत्त्व का है।”

स्थिरीकरण के विपक्ष में तर्क

प्राथमिक उत्पादक मूल्यों में स्थिरीकरण की नीति का महत्त्व बहुत थोड़े समय तक ही रहा और शीघ्र ही इसका स्थान पूर्ण रोजगार के उद्देश्य ने ले लिया। मूल्य स्थिरीकरण के विरोध में निम्न बातें कही जाती हैं—

1. किन मूल्यों में स्थिरता लाई जाए—मूल्य स्थिरता की नीति के विरुद्ध यह आपत्ति की जाती है कि यह नीति स्पष्ट रूप से यह बताती है कि कौन-सा मूल्य स्थिर रखा जाए—थोक मूल्यों को स्थिर रखा जाए या फुटकर मूल्यों को स्थिर रखा जाए? इसके अतिरिक्त एक अन्य कठिनाई यह भी है कि जब तक मूल्यों में सापेक्षिक स्थिरता न हो तब तक सामान्य मूल्य-स्तर में स्थिरता स्थापित करना अर्थहीन होता है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या मूल्यों में सापेक्षिक स्थिरता स्थापित की जाए? इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आलोचकों के अनुसार मौद्रिक नीति का उद्देश्य मूल्य स्थिरता नहीं होना चाहिए।

2. मूल्यों में परिवर्तन आर्थिक जीवन के परिवर्तनों का परिणाम होते हैं—आलोचकों का कहना है कि आर्थिक जीवन की अस्त-व्यस्तता के कारण ही मूल्यों में परिवर्तन होते हैं अर्थात् आर्थिक जीवन की अस्त-व्यस्तता ही मूल्यों में परिवर्तन का कारण होती है। अतः मूल्य स्थिर रहते हुए भी आर्थिक सम्बन्धों एवं उत्पादन में अस्त-व्यस्तता होना सम्भव है, इसलिए मूल्यों में स्थिरता स्थापित करने की मौद्रिक नीति से कोई लाभ नहीं हो सकता है।

3. मूल्य-स्तर में स्थिरता स्थापना करना कठिन है—मूल्य-स्तर में स्थिरता स्थापित करने के लिए एक ओर तो धन की पूर्ति को अस्थिर रखना चाहिए और दूसरी ओर वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परन्तु ये दोनों बातें ही अत्यन्त कठिन हैं।

4. मूल्य-स्तर में स्थिरता सदैव वांछनीय नहीं होती है—बीन्स के मतानुसार पूर्ण रोजगार की दशा को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि देश में थोड़ी-थोड़ी मूल्य वृद्धि होनी रहे, इससे उत्पादक के साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अतः पूर्ण रोजगार की वृद्धि से पूर्व मूल्य-स्तर में स्थिरता देश की अर्थव्यवस्था के लिए वांछनीय नहीं होती। प्रो. हेयक ने मन् 1932 में अपनी पुस्तक में लिखा है कि “मूल्य स्थिरता की मौद्रिक नीति को अपनाकर भी तेजी तथा मन्दी की घटनाएँ पहले के समान अब भी समाज के लिए आर्थिक कठिनाइयों के उत्पन्न होने के कारण बनी हुई हैं। गठ छः से आठ वर्षों में ससार के विभिन्न देशों में विशेषकर अमेरिका में केन्द्रीय बैंकों ने मूल्य-स्थिरता की नीति के समर्थकों के

प्रधान मन्त्री ने कहा था कि "बैंक एशियायी राष्ट्रों की दीर्घकालीन महत्वाकांक्षाओं का पूर्ति-बिन्दु है और एशियायी राष्ट्रों की स्व-सहायता भावना और समवाय का सकेतक है।"

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के मध्य-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के लाभ (Merits of Regional Economic Co-operation between Less Developed Economies)

विकासशील राष्ट्रों के मध्य वर्तमान में जो आर्थिक सहयोग हो रहा है उसकी इन राष्ट्रों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन राष्ट्रों में आर्थिक सहयोग से निम्न लाभ प्राप्त हुए हैं—

1. पूँजी निपोजन—आर्थिक सहयोग के कारण विकासशील राष्ट्रों को अपने विकास कार्यों के लिए आवश्यक पूँजी प्राप्त करने तथा कम व्याज पर शीघ्र ही उपलब्ध हो जाती है।

2. उपलब्ध-साधनों का सदुपयोग—आर्थिक सहयोग के द्वारा विकासशील राष्ट्र अपने उपलब्ध साधनों का इस प्रकार से प्रयोग करते हैं जिससे कि सम्पूर्ण सहयोग वाले देशों का सामञ्जस्यपूर्ण तथा सुव्यवस्थित आर्थिक विकास हो सके तथा छोटे एवं कम विकसित देशों को विशेष सहायता मिल सके।

3. विकास का मार्ग रक्षित करना—आर्थिक सहयोग द्वारा विकासशील राष्ट्र सामूहिक तथा प्रत्यक्ष आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हैं।

4. विकास नीतियों में सहयोग—आर्थिक सहयोग द्वारा इन देशों को अपनी प्रायोजनाओं तथा नीतियों में समन्वय स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त होती है ताकि इनकी अर्थव्यवस्था अधिक सन्तुलित बन सके और विदेशी व्यापार का सम्यक् विस्तार हो सके।

5. तकनीकी सहायता—आर्थिक सहयोग द्वारा सदस्य देशों के विकास के लिए प्रायोजनाएँ तैयार करने, उनके लिए धन जुटाने तथा उनको कार्यान्वित करने के लिए तकनीकी सहयोग भी प्राप्त होता है।

6. अन्य संगठनों से सहयोग—क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग द्वारा विकासशील राष्ट्र संयुक्तराष्ट्र के तत्वावधान में स्थापित तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अपने विकास कार्यों के लिए सरलतापूर्वक सहयोग प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, तथा अपनी बात को ज्यादा आसानी से समझा सकते हैं।

7. अन्य कार्य—आर्थिक सहयोग से विकासशील राष्ट्र वे सभी कार्य सरलतापूर्वक कर सकते हैं जिनसे कि इन राष्ट्रों के आर्थिक विकास में आर्थिक व तकनीकी सहायता प्राप्त होती हो या प्राप्त की जा सकती है।

एक देश की अर्थव्यवस्था को यह अनुभव हो सकता है कि उसकी विदेशी मुद्रा की वह आय जो उसे अपने माल और सेवा बेचने पर प्राप्त होती है, सोने या विदेशी मुद्रा के भण्डार के रूप में होती है और दूसरे देशों के साथ उनकी साख कुल मिलाकर इतनी नहीं होती कि वह उन वस्तुओं को खरीद सके जिन्हें वह चाहता है। इसके लिए देश अपने आयातों पर प्रत्यक्ष या कृत्रिम नियन्त्रण रखता है अथवा वह अपनी राष्ट्रीय आय में इतनी कमी कर सकता है कि आयातों की माँग स्वाभाविक रूप से घट जाए। यदि मान लीजिए किसी देश के आयात विदेशी मुद्रा की कमी के कारण आवश्यकता से अधिक गिर जाए तो उसका भुगतान सन्तुलन यद्यपि सन्तुलित रहेगा किन्तु सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकेगा। असन्तोषजनक स्थिति ही असमतुल्यता (Disequilibrium) कहलाती है।

एक देश पर्याप्त स्तर तक अपने माल और सेवाओं को उसी समय ला सकता है जबकि वह अपने सुरक्षित कोष का उपयोग करे। इसके लिए उसे अपना सोना बाहर भेजना होगा और विदेशी मुद्रा के संग्रह को कम करना होगा। जब उस देश के भुगतान खाते में यह स्थिति आ जाए तो भुगतान सन्तुलन असमतुल्यता से बाहर माना जाएगा। अब यह माना जाए कि देश की सुरक्षित कोष की स्थिति शीघ्र ठीक हो जाएगी और की गई कमी केवल अस्थायी है तो इसे कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता। इसी प्रकार यदि की गई कमी सुरक्षित कोष के आकार की तुलना में बहुत थोड़ी है तो असमतुल्यता अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगी। हम इसे असमतुल्यता केवल तभी कहेंगे जबकि एक अर्थव्यवस्था लम्बे समय तक अपने सुरक्षित कोष दूसरों को प्रदान करती रहे।

असमतुल्य अर्थव्यवस्था की एक निगानी यह है कि सम्बन्धित देश अपने उपयोग का प्रबन्ध प्रायः बड़ी मात्रा में कर्जा लेकर कर पाता है। जैसे यह मापदण्ड प्राप्त कठिन प्रतीत होता है क्योंकि यदि एक देश का भविष्य उनके लिए अस्थिर अनुकूल है तो भारी ऋण भी उचित हो सकता है किन्तु यदि भविष्य उसके प्रतिकूल है तो किसी भी प्रकार का कर्जा अव्युत्तरी रहेगा। इस सम्बन्ध में प्रायः कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। जब कभी यह मालूम हो कि कर्जा एक व्युत्तरी मात्रा से अधिक बढ़ रहा है और कर्ज लेने वालों की परिस्थितियों को देखते हुए कर्जा गलत रूप से भारी है तो इसे एक असन्तोषजनक स्थिति कहा जाएगा और उसके भुगतानों का सन्तुलन असमतुल्यता से बाहर माना जाएगा।

अर्थव्यवस्था की उस स्थिति को भी असन्तोषजनक कहा जाता है जिसमें वह दूसरे देशों की सौगातों और दान पर बहुत कुछ निर्भर रहती है तथा उन्हीं के माध्यम से अपने भारी खर्चों को चलाने का प्रयास करती है। इस सम्बन्ध में भी परिस्थितियों पर बहुत कुछ अवलम्बित है। यदि यह मालूम पड़ जाए कि सौगात और दान को प्राप्त करने वाला देश अधिक समय तक उन पर आश्रित नहीं रहेगा तो इसे हम उस देश की कमजोरी का प्रतीक नहीं कह सकते किन्तु यदि यह आश्रयता अस्थायी नहीं दिखती है तो निश्चय ही इस स्थिति को असन्तोषजनक कहा जाएगा।

जब एक देश वज्र या दान प्राप्त करता है और ऐसा लगता है कि इन स्रोतों पर उसकी माध्यमता समाप्त नहीं होगी तो यह असंतुलनजनक स्थिति मानी जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह विश्वास नहीं होता कि दान देने वाला और कर्म देने वाला भविष्य में हमेशा ही देता रहेगा। जब वही उनका दान की इच्छा समाप्त होगी तभी वह दान पगु बन जाएगा। ऐसी स्थिति में जब हम यह जानना चाहें कि वज्र लेना या श्रम लेना असमनुष्यता माना जाए अथवा नहीं तो हमको प्रश्न यह पड़ता चाहिए कि वज्र या दान दान वाला जब तक अनिच्छुक बनाया उस समय तक क्या वह देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकता है? यदि इस प्रश्न का उत्तर निष्पक्षमक आता है तो मानना होगा कि स्थिति मुगनान सन्तुलन की असमनुष्यता का परिणाम है। यदि उत्तर "हाँ" में आता है तो यह माना जाएगा कि प्रत्येक देश की कार्यक्षमता नहीं है।

असमनुष्यता के स्रोत (The Sources of Disequilibrium)

मुगनानों के सन्तुलनों में असमनुष्यता अनेक कारणों से पैदा होती है। जब कभी चालू लेन के विनिमयों की अनुसूची में माँग और पूर्ति के अनुरूप परिवर्तन होने हैं तो इन परिवर्तनों के पीछे काम करने वाली शक्ति ही असमनुष्यता का स्रोत होती है। यह पूर्ण स्पष्ट है कि एक देश की समनुष्यता को अनेक तरीकों में प्रभावित किया जाता है। जब कभी मुगनानों के सन्तुलनों में असमनुष्यता पैदा होती है तो यह अनेक परस्पर सम्बन्धित तरीकों का परिणाम होती है जिनको एक दूसरे से प्रभाव नहीं किया जा सकता। मुगनानों के सन्तुलन में आने वाली असमनुष्यता को उनके स्रोतों के अनुसार मि० स्नाइडर (Delbert A. Snider) ने दो भागों में बाँटा है—रचना सम्बन्धी (Structural) और चक्रवर्त तथा मौद्रिक (Cyclical and Monetary)। इन दोनों प्रकार के असन्तुलनों के बारे में कुछ संक्षेप में जानकारी प्राप्त करना उपयुक्त रहेगा—

(1) रचना सम्बन्धी असमनुष्यता (Structural Disequilibrium)

तकनीकी विकास और उपभोक्ताओं की प्रगतिशीलता के इस युग में प्रत्येक देश को आयात और निर्यात का सहारा लेना होता है। यह आयात और निर्यात जब माँग और पूर्ति की शक्तों के मूल रूप में होता है तो इसे समनुष्यता की अवस्था कहा जाता है किन्तु यदि उत्पादन के साधनों या माल अथवा सेवाओं की मापदंड अन्तर्राष्ट्रीय माँग और पूर्ति में बदलाव आता है तो इससे पूर्व स्थिति मन्तुलन सम्बन्ध बिगड़ जाते हैं और इसमें रचना सम्बन्धी असमनुष्यता जन्म लेती है। रचना सम्बन्धी असन्तुलन वर्षों या दशान्दियों तक बना रह सकता है और इस प्रकार मुगनान मन्तुलन में लगातार असमनुष्यता का स्रोत बना रहेगा। रचना सम्बन्धी असमनुष्यता के अनेक स्रोत होते हैं, इनमें से कुछ ये हैं—

(क) पूँजीगत हानियाँ (Capital Losses)—पूँजीगत भारी हानियों के

परिणामस्वरूप रचना सम्बन्धी असमतुल्यता की स्थिति पैदा हो सकती है और इसके फलस्वरूप उत्पादित एवं वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में भी कमी आ जायेगी। जब युद्ध या अन्य किसी कारण से थोड़े ही समय में पूंजीगत हानियाँ हो जाती हैं तो उनका परिणाम अत्यन्त भयानक होता है। युद्ध के समय पर्याप्त भौतिक संहार और भुक्कसान होते हैं।

पूँजीगत हानियों के परिणामस्वरूप आयात की माँग प्रभावधारण रूप से बढ़ जाती है क्योंकि देश में पैदा होने वाली उपभोग की वस्तुएँ तथा कच्चे माल भी कम हो जाते हैं और पूँजीगत पुनर्रचना की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर इस स्थिति में सम्बन्धित देश निर्यात करने वाले माल, सेवाओं को उत्पादित नहीं कर पाता।

(ख) उत्पादन का तरीका (The Pattern of Production)—अन्तर्राष्ट्रीय विशेषीकरण के माध्यमों और उत्पादन के साधनों में होने वाला परिवर्तन धीरे-धीरे होता है और यह रचना सम्बन्धी असमतुल्यता का कारण बनता है। विभिन्न देशों के मध्य जिन सापेक्षिक तत्वों का बँटवारा होता है वह स्थायी नहीं होता और उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। उनमें घाने वाले मशीन परिवर्तन निश्चय ही पूर्व स्थित असमतुल्यता को बदल देते हैं।

प्रौद्योगिकीकरण के परिणामस्वरूप भी रचना सम्बन्धी गलत समायोजन हो सकता है क्योंकि इससे उत्पादित माल के निर्यात में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और प्रौद्योगिकीकृत देशों में बने हुए माल के आयात की माँग घट जाती है।

(ग) माँग का रूप (Pattern of Demand)—समतुल्यता की स्थिति के लिए यह जरूरी है कि उत्पादन के साधनों का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि यह माल और सेवाओं की माँग के रूप के साथ मेल खाता रहे। पूर्ति की दिशाओं में होने वाले परिवर्तन भी असमतुल्यता के कारण बनते हैं। जब प्रति व्यक्ति की वास्तविक आय में तीव्र गति से वृद्धि होती है या आय के वितरण में परिवर्तन होते हैं तो माँग के रूप में उल्लेखनीय परिवर्तन होने का अवसर मिलता है। यदि उत्पादन के साधन पूर्ण रूप से गतिशील हैं तो वे माँग के बदले हुए रूप के अनुसार शीघ्र ही पुन निर्धारण कर लेंगे। बहुत समय से अधिकांश देशों में यह एक सामान्य प्रवृत्ति रही है कि श्रम प्राथमिक उत्पादनों (Primary Productions) से निर्मित उद्योगों की ओर बढ़ रहा है। जब एक देश का जीवन स्तर यहाँ के उद्योगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है तो विभिन्न वस्तुओं की माँग साधारण रूप से बढ़ने लगती है। इन माँगों की पूर्ति के लिए विदेशों का आश्रय लेना पड़ता है।

(घ) व्यापार शर्तें (Terms of Trade)—व्यापार शर्तों का अर्थ आयातों की उस मात्रा से है जो निर्यातों की एक इकाई के लिए प्राप्त की जाती है। जब एक देश के निर्यात की कीमतें अपेक्षाकृत धीरे-धीरे बढ़ती हैं और आयातों के लिए किए जाने वाले भुगतान की मात्रा बढ़ जाती है तो यह माना जाता है कि व्यापार शर्तें अनुकूल नहीं हैं। एक देश की व्यापार शर्तें वहाँ के आयातों और निर्यातों की माँग तथा पूर्ति में होने वाले सापेक्षिक घन्तरो के कारण परिवर्तित होती रहती हैं। इस

(ii) चक्रवत और मौद्रिक असमतुल्यता

(Cyclical and Monetary Disequilibrium)

भुगतान सन्तुलन में असमतुल्यता व्यापार चक्र के कारण भी पैदा हो जाती है। इतिहास साक्षी है कि प्रायः और उत्पादन में होने वाली प्रगति वृद्धिशील प्रवृत्तियों का साथ नहीं दे पाती। फलतः अल्पकालीन मुद्रा प्रसार या मन्दी की स्थिति पैदा हो जाती है। व्यापार चक्र स्वमेव असमतुल्यता का कारण नहीं बनता बल्कि इसके लिए कुछ शर्तें आवश्यक हैं। जैसे—(1) विभिन्न देशों में मुद्रा-प्रसार अथवा मन्दी की व्यापकता भिन्न हो, (2) विभिन्न देशों में चक्र के विभिन्न पहलुओं का समय भिन्न हो, (3) विभिन्न देशों में आयात के लिए माँग की प्रायः लोचशीलता में भिन्न हो, इत्यादि। चक्रवत असमतुल्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सम्पूर्ण चक्र के दौरान भुगतान सन्तुलन समतुल्य बने रहते हैं।

उक्त परिस्थितियों में असमतुल्यता का उल्लेख निम्न प्रकार किया जा सकता है—

(1) अन्य बातें यथावत् हों और व्यापार चक्र 'क' देश में 'ख' देश की अपेक्षा अधिक गहन हो तो 'क' में प्रमार (Boom) के समय प्रभाव की और मन्दी के समय आधिक्य की स्थिति रहेगी। 'ख' देश में इसके विपरीत होगा। प्रमार के समय प्रायः 'क' देश में 'ख' देश की अपेक्षा बढ़ जाएगी। फलतः 'क' के आयातों में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होगी। मन्दी के समय 'क' की प्रायः अपेक्षाकृत अधिक घटेगी और इसलिए उसके आयातों में अधिक कमी हो जाएगी।

(2) चक्र के विभिन्न पहलू यदि अलग देशों में अलग समयों पर होते हैं तो भुगतान सन्तुलन में असमतुल्यता पैदा हो जाती है। इस आधार पर एक देश के आयातों में कमी अथवा वृद्धि हो जाती है।

(3) आयातों के लिए माँग की प्रायः लोचशीलताओं में अन्तरों के कारण भी चक्रवत असमतुल्यता पैदा हो जाती है। अन्य बातों के यथावत् रहते हुए यदि 'क' देश में आयातों की माँग की प्रायः लोचशीलता 'ख' देश की अपेक्षा अधिक है तो वृद्धि के दौरान 'क' देश घाटे से प्रस्त बन जाएगा और मन्दी के समय अतिरेक का उपभोग करेगा। आयातों के लिए तुलनात्मक रूप से अधिक लोचशीलता होने के कारण 'क' देश में आयातों के उतार-चढ़ाव अपेक्षाकृत अधिक होंगे।

(4) विभिन्न देशों में माँग की कीमत लोचशीलता में अन्तरों से भी चक्रवत असमतुल्यताएँ जन्म लेती हैं। साधारणतः वृद्धि के समय कीमतें बढ़ती हैं और मन्दी के समय घट जाती हैं। अन्य बातों के यथावत् रहने पर यदि 'क' में आयातों के लिए माँग की कीमत लोचशीलता यदि 'ख' से उच्चतर है तो 'क' को वृद्धि के समय अतिरेक प्राप्त होगा और मन्दी के समय घाटे की स्थिति रहेगी। 'क' देश में आयातों के लिए होने वाले उतार-चढ़ाव भी अपेक्षाकृत अधिक होंगे।

उपर्युक्त महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ भुगतान सन्तुलनों में चक्रवत असमतुल्यता का कारण बनती हैं। ये सम्पूर्ण परिस्थितियाँ ही नहीं हैं इनके अतिरिक्त अन्य कुछ भी उल्लेखनीय हैं।

मौद्रिक असमतुल्यता उस समय पैदा होती है जब दूसरे देशों की प्रवेक्षा एक देश की कीमतों तथा धन के सामान्य स्तर में परिवर्तन आते हैं। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि चक्रवर्त आय और सापेक्षिक राष्ट्रीय कीमत तथा लागत स्तरों में होने वाले परिवर्तन परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित होते हैं। मौद्रिक राष्ट्रीय आय में सामान्य वृद्धि का अर्थ यह है कि माल और सेवाओं की कुल माँग में वृद्धि हुई है। यदि वर्तमान मूल्यों पर माल और सेवाओं की पूर्ति बड़ी हुई माँगों के लिए पर्याप्त नहीं है तो इसके परिणामस्वरूप मुद्रा स्फीति जन्म लेगी। विफलपणात्मक रूप में आय और कीमत के मुग्तान सन्तुलन पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान दिया जा सकता है। एक सीमा तक मौद्रिक राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तन वास्तविक आय परिवर्तनों की अभिव्यक्ति होते हैं। यह मुग्तान सन्तुलन पर आय का प्रभाव है।

दूसरी ओर सीमा तक ये मूल्य स्तर के परिवर्तनों की अभिव्यक्ति, ये मुग्तान सन्तुलन पर कीमत का प्रभाव दिखाते हैं। दोनों प्रभाव एक ही दिशा में कार्य करते हैं। कीमतों और लागतों के अन्तराष्ट्रीय स्तर में सापेक्षिक वृद्धि के कारण न केवल आयातों में वृद्धि होती है बल्कि निर्यातों में कमी भी हो जाती है। इसी प्रकार राष्ट्रीय कीमत और लागत-स्तर पर होने वाली सापेक्षिक वृद्धि से न केवल आयात गिर जाते हैं बल्कि निर्यातों में भी वृद्धि हो जाती है। राष्ट्रीय कीमत एवं लागत स्तर में सापेक्षिक वृद्धि होने के कारण मुग्तान सन्तुलन के बालू खाने में घाटे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

मौद्रिक असमतुल्यता की एक विशेष स्थिति के रूप में विनिमय दर (Exchange Rate) की असमतुल्यता का नाम भी लिया जा सकता है। किसी देश की विनिमय दर में होने वाली कमी के सापेक्षिक मूल्य स्तरों पर पड़ने वाले प्रभाव घरेलू कीमतों में वृद्धि या विदेशी कीमतों में कमी के बराबर होते हैं। जब कभी आयातों को प्रोत्साहन देकर निर्यातों में कमी करके मुद्रा का अत्यधिक मन्थन किया जाता है तो इसके फलस्वरूप मुग्तानों के सन्तुलन में उत्पादन की घाटे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

स्पष्ट है कि एक देश की अन्तराष्ट्रीय व्यापिक स्थिति का निर्धारण करने में अनेक तत्वों का महत्त्व है जैसे—उत्पादन के साधनों की सापेक्षिक पूर्ति, आय के वितरण और स्तर, लागतों और कीमतों का स्तर, विनिमय दर आदि-आदि। इनमें से कुछ तत्वों की प्रवृत्ति तो रचना सम्बन्धी है जबकि अन्य में तीव्र गति से परिवर्तन हो सकता है। असमतुल्यता न केवल अन्तराष्ट्रीय माँग और पूर्ति की मूल शक्तियों में परिवर्तनों द्वारा ही पैदा हो सकती है बल्कि चक्रवर्त आय और सापेक्षिक कीमत परिवर्तनों से भी हो सकती है।

मुग्तान सन्तुलन के लेखे

(The Accounts of Balance of Payments)

विभिन्न देशों की सरकारें दूसरे देशों के साथ किए गए वास्तविक वित्तीय प्रभिनियम रखती हैं ताकि वे यह जान सकें कि अन्तराष्ट्रीय व्यापार की स्थिति

स्थिति क्या है ? भुगतान सन्तुलनों के लेखों में उन कारणों का उल्लेख किया जाता है जिनके लिए भुगतान किए गए हैं। इन्हें देखकर हम यह कह सकते हैं कि भारतवासियों को भारतीय माल की खरीद के लिए, या भारतीय सेवाओं के प्रयोग के लिए कितना भुगतान किया गया ? ये सेंसे यह भी बता सकते हैं कि भारत के द्वारा विदेशी माल की खरीद के लिए, विदेशी सेवाओं के प्रयोग के लिए और विदेशियों को उधार देने के लिए कितना भुगतान किया गया ? जो मद विदेशी मुद्रा की खरीद को आवश्यक बनाती है उसे सेंसे के नाम पक्ष की ओर लिखा जाता है। दूसरी ओर जो मद विदेशी मुद्रा की बिक्री को प्रदर्शित करती है उसे जमा खाते की ओर लिखा जाता है।

यह सच है कि विदेशी विनिमय बाजार में खरीदे गए रुपये की संख्या बेचे गए रुपये की संख्या के बराबर होनी चाहिए किन्तु यह बात एक विशेष चीज की खरीदारी या बिक्री पर लागू नहीं होती। कभी-कभी आयात के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के हेतु बहुत से रुपये बेच दिए जाते हैं।

भुगतान सन्तुलन के लेखों के अनेक रूप होते हैं, उनमें प्रमुख ये हैं—चालू खाता (The Current Account), पूंजी खाता (The Capital Account), एक पक्षीय हस्तान्तरण (Unilateral Transfer), स्वर्ण खाता (Gold Account) आदि। “इनमें से भुगतान सन्तुलन खाते में अधिकांश महत्वपूर्ण विभाजन चालू खाते और पूंजी खाते के बीच होता है। चालू खाते में वे सभी भुगतान आते हैं जो सामान और सेवाओं के मास के खरीददारी के लिए किए गए हैं।”¹ इस सम्बन्ध में स्पष्टतः कुछ नहीं कहा जा सकता कि चालू खाते के भुगतानों को क्यों सन्तुलित होना चाहिए ? हो सकता है कि एक देश अधिक आयात करने के लिए अपनी मुद्रा को अधिक बेचे और उसकी यह मात्रा निर्यातों को बिक्री से प्राप्त होने वाली मुद्रा से कम हो। यदि ऐसा है तो देश को कहीं से भी मुद्रा का प्रबन्ध करना होगा और चालू खाते में जो खरीददारी का प्रतिशय हुआ है उसे पूंजी खाते में होने वाली बिक्रियों की बहुतायत के द्वारा मिलाना होगा। पूंजी खाते में दीर्घकालीन विनियोग, अल्पकालीन विनियोग और चलन के आवागमन की मदें सम्मिलित की जाती हैं। मि. लिप्से और स्टेनियर (Lipsey and Stenier) के कथनानुसार, “पूंजीगत खाते में उस प्रत्येक लेन-देन को रखा जाता है जिस चालू खाते में नहीं रखा गया है।”² पूंजीगत खातों में जिन मुख्य मदों को रखा जाता है उनमें पूंजीगत हस्तान्तरण और बिक्री आदि को लिया जाता है। जब कोई भारतीय नागरिक विदेशों में विनियोग करना चाहता है तो उसे सम्बन्धित देश की विदेशी मुद्रा प्राप्त करनी होगी। उसे रुपये बेचकर विदेशी मुद्रा खरीदनी होगी। इनको भुगतान सन्तुलन में घाटे की दर के रूप में लिया जाता है क्योंकि लेन-देन में डॉलर का उपयोग किया गया है।

1 “The balance of payments on current accounts includes all payments made because of current purchases of goods and services”

—Richard G. Lipsey and Peter O. Stenier, *Economics*, p. 430.

2 “The capital accounts records transactions for every thing other than what is recorded in the current account.”

—*Ibid*, p. 431.

आयातों की अपेक्षा अधिक होने वाले निर्यात की कीमत को केवल तभी चुकाया जा सकता है जब विदेशी ग्रन्थ स्रोतों से रुपया प्राप्त करें। यहाँ उनके सम्मुख दो सम्भावनाएँ हैं—(1) भारतीय रुपया उन निवेशकर्ताओं द्वारा प्रदान किया जा सकता है जो विदेशी माल खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के इच्छुक हैं। ऐसी स्थिति में आयातों की अपेक्षा निर्यातों के अतिरिक्त को विदेशों में भारतीय कर्ज के रूप में सन्तुलित किया जाएगा। (2) विदेशी सरकारें अपने भारतीय रुपये के खजाने को कम करें और उसे उन लोगों को बेच दें जो अमेरिकी माल खरीदना चाहते हैं। बदले में सरकार घरेलू मुद्रा ग्रहण कर लेती। चालू खाते में अतिरिक्त को पूँजी खाते के घाटे द्वारा बराबर बनाया जाता है। इसके लिए या तो विदेशों को कर्ज देना पड़ेगा अथवा विदेशी केन्द्रीय सत्ताओं द्वारा रखे गए सोने और विदेशी विनिमय के सुरक्षित भण्डार को काम में लेना होगा।

चालू खाते का खनाना—चालू खाते को प्रायः दृश्य और अदृश्य व्यापार के रूप में विभाजित किया जाता है। दृश्य व्यापार का सम्बन्ध वस्तुओं में रहता है अर्थात् कार, कॉफी, चाय, लोहा, अल्पमूल्य, सड़की के सटूठे आदि वे सारी चीजें जिनको अन्तर्राष्ट्रीय सीमाएँ पार करते समय हम देख और छू सकते हैं। अदृश्य व्यापार के अन्तर्गत वे सेवाएँ तथा चीजें आती हैं जिनको हम छू नहीं सकते। उदाहरण के लिए बीमा, जहाज का शुल्क आदि। बीमा सेवाओं के लिए मुग्तान प्रायः मुग्तानकर्ता देश की मुद्रा में ही किया जाता है और इसलिए यह प्राप्त करने वाले देश के लिए आयात और मुग्तान करने वाले देश के लिए निर्यात है।

पूँजीगत खाते का खनाना—पूँजीगत खाते में विदेशी पूँजी की समस्त गतियों का अभिलेख रखा जाता है। यदि भारतीय निवेशकर्ता विदेशों में निवेश करते हैं तो उन्हें भारतीय रुपया देना होगा ताकि विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सके। इस प्रकार यह विदेशी विनिमय के घाटे की स्थिति को सुधारने में योगदान करता है क्योंकि इसमें विदेशी मुद्रा का प्रयोग होता है। भारत में जब विदेशी स्रोतों द्वारा विनियोग किया जाता है तो पूँजी लेखों में अतिरिक्त पैदा होता है। पूँजी के आवागमन को दीर्घकालीन पूँजीगत आवागमन, अल्पकालीन आवागमन और विनिमय सुरक्षितों के परिवर्तनों आदि के रूप में विभाजित किया जा सकता है। इस प्रकार के आवागमन क्यों होते हैं, यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। निवेशकर्ता ओखिम उठाकर वहाँ विनियोग करना चाहता है जहाँ से उसे अधिक से अधिक प्राप्ति हो सके। जिस प्रकार देश के अन्तर्गत पूँजी एक उद्योग से दूसरे उद्योग में आती-जाती रहती है, ताकि उसका अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सके उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पूँजी का आवागमन चलता रहता है। इस प्रकार के पूँजीगत आवागमनों का अर्थ यह होता है कि एक देश के रहने वाले लोग तथा फर्म दूसरे देश के उद्योगों में निवेश कर रहे हैं और इनको मुग्तान लेखों में दीर्घकालीन आवागमन में दिखाया जाएगा।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अस्तित्व का तथ्य व्यापारियों को धन का सन्तुलन रखने के लिए बाध्य करता है। व्यापारियों की प्राप्तियाँ एवं खर्चे पूर्ण रूप से एक

समय नहीं होने फिर भी वे सन्तुलन बनाए रखते हैं। प्रेरकों में थोड़ा और परिवर्तन लाने वाली प्रतिक्रिया व परिणामस्वरूप या मभी प्रचार के वास्तविक या कल्पनात्मक भयों के द्वारा राशिपों द्वारा से ऊपर आवागमन कर सकती हैं। इस प्रकार की राशिपों की बड़ी मात्रा अन्तर्राष्ट्रीय अस्थायित्व का एक सम्भावित स्रोत है क्योंकि जब एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में प्रत्यक्षात्मीन पूँजी की एकदम मोड़ लग जाती है तो विदेशी मुद्रा के लिए माँग और पूर्ति में गम्भीर परिवर्तन हो जाते हैं।

पूँजीगत राशियों में अन्तिम तत्त्व केन्द्रीय सत्ताओं के पास स्थित सोने और विदेशी विनिमय व मुराजित भण्डारों में परिवर्तन हैं। अधिकांश देशों की केन्द्रीय सत्ताएँ सोने और विदेशी विनिमय की पूर्ति को इसलिए रखती हैं ताकि वे विदेशी विनिमय के बाजारों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए हस्तक्षेप कर सकें। इस दृष्टि से सोने का बहुत महत्व रहता है क्योंकि उसे बड़ी आसानी से और तत्काल किसी भी बाह्यीय विदेशी मुद्रा में बदला जा सकता है। यदि एक देश प्राप्त की गई मुद्रा से अधिक का प्रयोग करता है तो इस घाटे की पूर्ति उसे अपने विदेशी विनिमय और सोने के मुराजित भण्डार में कमी करके करनी होगी। संयुक्तराज्य अमेरिका में ये मुराजित भण्डार मुख्य रूप से सोने के रूप में रक्खे जाते हैं और उसे सभी अन्य मदों पर मुगलान सन्तुलन के घाटे को सोने के निर्यात द्वारा पूरा करना होता है।



विनिमय दरें एवं मुद्रातान सन्तुलनों का समायोजन

(EXCHANGE RATES AND THE ADJUSTMENT MECHANISMS UNDER GOLD STANDARD. FIXED EXCHANGE RATES AND FLEXIBLE EXCHANGE RATES)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार के बीच एक मुख्य अन्तर यह होता है कि राष्ट्रीय व्यापार में केवल एक ही मुद्रा काम में आती है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने वाले विभिन्न देशों की मुद्राएँ अलग-अलग होती हैं। जब एक देश अपने माल का निर्यात करना है तो बदले में उसे दूसरे देश की मुद्रा प्राप्त होती है। इसका देश में उस समय तक कोई महत्त्व नहीं होता जब तक कि उसकी विनिमय दरें निश्चित न की जाएँ। किसी मुद्रा का विनिमय इच्छित मुद्रा में करने के लिए एक आसान तरीका यह बताया जाता है कि आयात-कर्ता और निर्यातकर्ता मिलकर इस समस्या को सुलझाएँ। यह सुभाव अधिक उपयोगी प्रतीत नहीं होता। आयातकर्ता और निर्यातकर्ता एक दूसरे से धन्यज्ञ भी रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त हो सकता है कि आयातकर्ता को इतनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता न हो जितनी कि निर्यात-कर्ता देना चाहता है। इसके अतिरिक्त आयात-कर्ता देश की मुद्रा खरीदने का अधिकार पाने के लिए केवल अल्पकालीन साधन की जरूरत होती है जबकि निर्यात करने वाला देश इस प्रकार के निर्यात करने के बदले यह चाहता है कि मुद्रातान सुरक्षित किया जाए। संसार में इस समय अनेक मुद्राएँ प्रचलित हैं और इसलिए मुद्रा के विनिमय की सफलता के बारे में सन्देह-विहीन दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता है। यह बात सम्भव प्रतीत नहीं होती कि आयात-कर्ता और निर्यात-कर्ता देश परस्पर सम्पर्क बनाए रख सकेंगे।

विनिमय की समस्या को सुलझाने के लिए विदेशी विनिमय बाजार की स्थापना की गई है जहाँ विदेशी मुद्रा के अधिकारी को देशी मुद्रा में खरीदा और बेचा जा सकता है। विदेशी विनिमय के अर्थ के सम्बन्ध में अनेक विचार हैं। स्नाइडर के कथनानुसार—“जिन साधनों का उपयोग अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रातान में किया जाता है उनको विदेशी विनिमय कहते हैं।” एन्साइक्लो-पीडिया ब्रिटानिका (Encyclopaedia Britannica) के अनुसार “विदेशी विनिमय एक ऐसी कार्य प्रणाली है

विनिमय की दर के अर्थ के सम्बन्ध में अभिव्यक्त उपर्युक्त विचारों का अन्तर बहुत कुछ शब्दों का है मूल भाव का नहीं। निष्कर्ष यह है कि विनिमय दर विदेशी विनिमय की कीमत है। इनका महत्त्व यह है कि ये व्यापार करने वाले देशों की सागत-मूल्य की वनावटों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने वाली कड़ियाँ हैं। विनिमय दर का पर्याप्त महत्त्व है। किसी विशेष वस्तु का आयात या निर्यात किया जाएगा अथवा नहीं किया जाएगा यह बात घरेलू माँग और पूर्ति के बीच, सम्बन्धों पर निर्भर करती है। इसके लिए यह तय करना होगा कि उस वस्तु की विषय कीमत और घरेलू कीमत के बीच क्या अन्तर है। इस बात का निर्धारण विनिमय दर द्वारा ही किया जा सकता है। विदेशी कीमतों को घरेलू कीमतों में बदलते समय यदि दर बहुत ऊँची चढ़ जाती है तो यह कहा जाएगा कि विनिमय दर ऊँची है। दूसरी ओर यदि विदेशी वस्तु को कम घरेलू कीमत पर बिक्री जा सके तो विनिमय दर नीची मानी जाएगी। इस प्रकार एक देश की वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भुगतानों के समतुलन की तुल्यभारिता की सफलता प्रत्यक्ष रूप से विनिमय दरों से प्रभावित होती है।

विनिमय दरों के बीच पारस्परिकता का सम्बन्ध रहता है। अपनी प्रकृति अनुसार विनिमय दर एक ही साथ विदेशी मुद्रा की एक इकाई की घरेलू मुद्रा में कीमत है तथा साथ ही घरेलू मुद्रा की विदेशी मुद्रा में भी कीमत है। दूसरे शब्दों में विनिमय की दर यह निश्चित करती है कि 'क' देश की एक मुद्रा के बदले 'ख' देश को अपनी मुद्रा की कितनी इकाइयाँ देनी होंगी। दूसरी ओर इनसे यह भी पता लग जाता है कि 'ख' देश की कितनी मुद्राओं के बदले 'क' देश द्वारा कितनी मुद्राएँ प्रदान की जाएँगी।

विनिमय दर का निर्धारण

(Determination of the Exchange Rate)

विनिमय की दर का निर्धारण मुद्रा की माँग और पूर्ति से सम्बन्धित परिस्थितियों द्वारा किया जाता है। विभिन्न विनिमय की दरें परस्पर सम्बन्धित रहती हैं। यह सम्बन्ध इस बात का प्रमाण है कि विनिमय की दर के निर्माण में कोई न कोई सामान्य सिद्धान्त काम करता है।

विनिमय की दर को निर्धारित करते समय जो विभिन्न तत्त्व प्रभाव डालते हैं उनके अनुसार वह या तो समान होती है या अधिक होती है अथवा कम होती है। किस देश में विनिमय दर का कौनसा रूप महत्त्वपूर्ण रहेगा यह विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करता है। विनिमय की दर का निर्धारण स्वतन्त्र बाजार में विभिन्न शक्तियों द्वारा किया जाता है। एक देश की सरकार प्रायः स्वयं यह निर्धारण कर देती है कि उसके निवासी किस दर पर एक विशेष प्रकार के विदेशी धन को खरीदेंगे तथा देश का कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा को किस दर पर सरकार को बेचेगा।

हो सकता है कि पूंजीगत माल के आयात पर भुगतान के लिए प्रयुक्त डॉलर की कीमत अमानत की सरीददारी के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले डॉलरों से भिन्न

विनिमय की दर जितनी कम होती है किए जाने वाले आयात देशी मुद्रा की दृष्टि से उतने ही सस्ते पड़ते हैं। अतः किए जाने वाले आयातों की माँग बढ़ जाती है। फलतः किए जाने वाले आयातों की माँग बढ़ने से विदेशी मुद्रा की मात्रा भी अधिक हो जाएगी।

विनिमय के लिए माँग की अनुसूची की दर, माँग की लोचशीलता से पर्याप्त सम्बन्ध रखती है। माँग की लोचशीलता का अर्थ उस प्रक्रिया की मात्रा से है जो विनिमय की दर में कमी या बढ़ोतरी के कारण विनिमय की मात्रा में आवश्यक समझी जाती है। माँग की लोचशीलता को परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि यह विनिमय दर के परिवर्तन के प्रतिशत और वाञ्छित विनिमय की मात्रा में परिवर्तन के प्रतिशत का अनुपात है। उदाहरण के लिए, यदि विनिमय दर में एक प्रतिशत की कमी हो जाए और इसके परिणामस्वरूप विनिमय की माँग की मात्रा में एक प्रतिशत की वृद्धि हो जाए तो माँग की लोचशीलता एकरूप होगी। यदि मात्रा के परिवर्तन का प्रतिशत 'दर' के परिवर्तन की अपेक्षा अधिक है तो माँग अपेक्षाकृत लोचशील होगी अर्थात् यह एक रूप से अधिक होगी। इससे विपरीत स्थितियों में माँग लोचहीन होगी।

विनिमय की चालू माँग की लोचशीलता अनेक तत्वों पर निर्भर करती है। खाद्य सामग्री की माँग प्रायः लोचहीन होती है और इसलिए जिस देश के आयातों में खाद्य सामग्री की मात्रा अधिक होती है उस देश में इनका भुगटान करने के लिए विनिमय की माँग लोचहीन होती है। दूसरी ओर जब एक देश के आयातों में लोचशील माँग वाली बहुत सी वस्तुएँ होती हैं या जिनके घरेलू विकल्प होते हैं यदि उनकी विनिमय दर में परिवर्तन किया गया तो वाञ्छित आयातों की मात्रा की प्रतिक्रिया अधिक होगी और विनिमय के लिए माँग की लोचशीलता अधिक हो जाएगी।

विनिमय की चालू पूर्ति

(The Current Supply of Exchange)

विदेशी विनिमय की चालू पूर्ति माल और सेवाओं के चालू निर्यात से प्राप्त की जाती है। एक देश की चालू विनिमय की आय वही है जो दूसरे देश उसके सामान और निर्यातों पर चालू खर्च करते हैं। इस प्रकार विदेशी विनिमय की पूर्ति अनुसूची की लोचशीलता और उसकी स्थिति उस देश की मुद्रा के लिए विदेशी माँग की स्थिति और लोचशीलता पर निर्भर करती है। एक देश के विनिमय की माँग किस प्रकार दूसरे देश के विनिमय की पूर्ति में बदल जाती है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इस सम्बन्ध में यह कहना उपयुक्त रहेगा कि एक देश में विदेशी विनिमय की चालू पूर्ति की वक्र रेखा उस समय तक बाएँ से बाएँ की ओर बढ़ती है जब तक कि उसकी मुद्रा की वैदेशिक माँग अपेक्षाकृत लोचशील है।

घटती-बढती दर-व्यवस्था मे दर निर्धारण (Rate Determination in a Freely Fluctuating Rate System)

यदि एक क्षण के लिए हम यह मान लें कि चालू खाते के लेन देन ही विदेशी विनिमय की माँग और पूर्ति के एकमात्र स्रोत हैं और पूँजी के आवागमन, सोने के बहाव तथा एक पक्षीय हस्तान्तरण का कोई महत्त्व नहीं माना तो विनिमय की दर चालू खाते की माँग तथा पूर्ति के सम्बन्धों में परिवर्तन के अनुसार स्वतन्त्र रूप से घटती-बढती रहनी । चालू अन्तर्राष्ट्रीय खर्चा, चालू अन्तर्राष्ट्रीय प्राप्तिदा से अधिक नहीं बढ सकता, क्योंकि आयातों का मुग्तान करने के लिए हमारी मान्यता के अधीन कोई अन्य साधन नहीं रहेगा । विनिमय के लिए बड़ी हुई माँग अथवा विनिमय के लिए घटी हुई पूर्ति भोज्य ही विनिमय की दर की वृद्धि का कारण बन जाएगी और यह वृद्धि उस समय तक होगी जब तक कि विनिमय की दरें तथा माँग और पूर्ति बराबर न हो जाएँ । इस सम्बन्ध में एक प्रश्न यह उठ सकता है कि माँग में होने वाली कोई वृद्धि या पूर्ति में होने वाली कोई कमी विनिमय की दर को कितना बढा देती है ? अनुभवों की लोचशीलता का इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण योगदान होता है ।

विदेशी विनिमय की पूर्ति जितनी अधिक लोचशील होती है, बड़ी हुई माँग के परिणामस्वरूप दर की वृद्धि भी उतनी ही ऊँची हो जाती है ।

दर का स्थायित्व (The Stability of Rate)

एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि स्वतन्त्र रूप से घटन-बढने वाली दर व्यवस्था में विनिमय बाजार का स्थायित्व कितना रहेगा ? यदि आयातकर्ताओं द्वारा दर की वृद्धि को अस्थायी समझा जाता है तो वे अपनी दी गई आजायों को उस समय तक रोक देंगे जब तक कि दर गिर न जाए । दूसरी ओर यदि विदेशी प्रामाणिकता भी उसे अस्थायी मानते हैं तो वे बढती हुई दर का अधिक से अधिक लाभ उठाने की जल्दी में रहेंगे और अपने आयातों को बढा देंगे । जब एक देश की विनिमय दर में वृद्धि होती है तो दूसरे देशों की मुद्राओं की दरों में भी कमी हो जाती है । इनका दर पर एक स्थायित्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा ।

हम एक अन्य स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जिसमें अल्पकालीन पूँजी के आवागमन शामिल होंगे । यह मान्यता गलत है कि विनिमय विधेना अपने विदेशी सन्तुलनों में झुड कमी या बढोतरी करने के अनिच्छुक होंगे । इसके अनिश्चित जब हम यह मान लेते हैं कि दर की वृद्धि केवल अस्थायी है और शीघ्र ही गिर जाएगी, तो उसे स्थिरता देने के लिए अल्पकालीन पूँजीगत प्रवाह अस्तित्व में आ सकता है । विनिमय के सौदागर इस उच्च दर का लाभ उठाते हुए अपने विदेशी सन्तुलनों को साधारण स्तरों से भी नीचे ले आते हैं । किन्तु जिस देश में दर ऊँची चढ गई है वहाँ विनिमय के सौदागर अपने विदेशी सन्तुलनों को सामान्य से ऊपर रखेंगे । दरों में स्थायित्व लाने के लिए आयात और निर्यात का समायोजन किया जाता है ।

निश्चित विनिमय दरें (Fixed Exchange Rates)

रिगेत स्वतन्त्र बाजार की विनिमय व्यवस्था में दरें स्वतन्त्रतापूर्वक घटती-बढ़ती रहती हैं। इसके विपरीत विनिमय दर की एक निश्चित व्यवस्था होती है जिसे अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान (International Gold Standard) कहा जाता है। इसके अन्तर्गत विनिमय दरें एक सीमा से आगे नहीं घटती-बढ़ती।

अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान की व्यवस्था में प्रत्येक देश अपनी मौद्रिक इकाई को एक निश्चित स्वर्ण की मात्रा के रूप में कानूनन परिभाषित कर देता है। 1930 में संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड, दोनों ने स्वर्णमान अपनाए। डॉलर को 23 22 ग्रेन शुद्ध सोने के बराबर माना गया और ब्रिटिश पाँड को 113 ग्रेन शुद्ध सोने के बराबर। स्वर्ण के रूप में मुद्रा का मूल्य निर्धारित करने के प्रतिरिक्त स्वर्णमान की व्यवस्था में मौद्रिक सत्ताएँ स्वतन्त्रतापूर्वक निर्धारित कीमत पर प्रसीमित मात्रा में सोना खरीद और बेच सकती हैं। इससे बाजार, भाव और सोने के सरकारी टंक भाव समान हो जाते हैं। इसके प्रतिरिक्त स्वर्णमान के अन्तर्गत दो देशों के बीच विनिमय दर का निर्धारण उनके स्वर्ण भण्डार के अनुपात में होता है। सोने की कीमत का अनुपात उनमें से प्रत्येक देश में एक जैसा रहता है।

स्पष्ट है कि स्वर्णमान वाली मुद्राओं के बीच विनिमय की वास्तविक दर उस व्यय से अधिक नहीं बढ़ सकती जो उनको यहाँ से वहाँ ले जाने पर आता है। यदि दर इससे अधिक बढ़ती है तो सौदा करने वालों को आयात या निर्यात करने में बहुत लाभ रहेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान की कुछ विशेषताएँ होती हैं। एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें स्वतन्त्र बाजार की शक्तियों के संचालन से विनिमय की स्थायी दरें स्वतः ही कायम हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान पर किसी प्रकार का कृत्रिम प्रतिबन्ध लगाए बिना जिस विनिमय व्यवस्था में स्थायी विनिमय दरें कायम होती हैं उनको स्वर्ण मापक कहा जाता है।

लोचशील विनिमय दरें (Flexible Exchange Rates)

लोचशील विनिमय दर के अर्थात् मुद्रा के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य को किसी वस्तु के रूप में निश्चित नहीं किया जाता और न उसे व्यक्तिगत बाजार की शक्तियों की प्रतिक्रिया में स्वतन्त्रतापूर्वक घटने-बढ़ने दिया जाता है। इस प्रकार 'लोचशील दर-व्यवस्था' निश्चित और स्वतन्त्रतापूर्वक घटने-बढ़ने वाली दर-व्यवस्था के बीच की स्थिति है। एक लोचशील दर-व्यवस्था के अर्थात् विनिमय दर का निर्धारण दिन-प्रतिदिन के स्वतन्त्र बाजार की माँग तथा पूर्ति द्वारा होता है। जब सरकार विनिमय दर को नियन्त्रित करती है तो ऐसा करने के लिए उसे व्यक्तिगत बाजार को दबाना या बदलना नहीं होता बल्कि उसे प्रयोग में लाना होता है।

लोचनीय दर-व्यवस्था को मंचालित करने के लिए बाजार में आवश्यक हस्तक्षेप केन्द्रीय बैंक या राजकोष अथवा इसी लक्ष्य के लिए नियुक्त विशेष अधिकरण द्वारा किया जा सकता है। 1930 के दौरान ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस में विनिमय स्थायीकरण कोष रखे गए थे। इस कोष की प्राप्ति की अनुपत्ति में परिवर्तन होने के कारण मुद्रा की अन्तर्राष्ट्रीय कीमन बढ़ती रहती है। जब किसी विनिमय दर का उंचा उठाना हो अथवा उसे गिराने से रोकना हो तो कोष द्वारा विदेशी विनिमय को कम दर पर खरीद लिया जाता है। यह कोष अपने कार्यों को गोपनीय रखना है ताकि केवल अनुमानों के आधार पर विनिमय बाजार की कार्यवाही मंचानि की जाए।

विनिमय दर को नियन्त्रित करने की शक्ति सम्भवतः इस कोष की प्राप्ति की मात्रा पर निर्भर करती है।

लोचनीय दर-व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके द्वारा प्रतिक घटाव-बढ़ाव के बिना ही स्वतन्त्र बाजार को मुगम बनाया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ प्रत्येक देश की लोचनीय विनिमय दर की नीति अपनाते सहायता करती हैं।

माँग और पूर्ति का सन्तुलन (Balance of Demand and Supply)

माँग और पूर्ति के सन्तुलन द्वारा विनिमय दर निश्चित की जाती है। इस सन्तुलन में अन्तर के साथ विनिमय दर में भी परिवर्तन आ जाते हैं। विदेशी मुद्रा की माँग जब उसकी पूर्ति के बराबर होती है तो विनिमय की दर में समता आ जाती है। जब विदेशी मुद्रा की माँग उसकी पूर्ति से अधिक हो, जाती है तो विदेशी मुद्रा का मूल्य समता से ऊपर आ जाता है और स्वदेशी मुद्रा का मूल्य समता से नीचे गिर जाता है। ऐसी स्थिति में विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए अधिक देरी मुद्रा देनी होगी। जब किसी विदेशी मुद्रा की माँग उसकी पूर्ति से कम हो जाती है तो उसकी कीमत समता से कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में विदेशी मुद्रा या उसके बिलों का मुद्रातान करने के लिए हमें पहले की अपेक्षा में कम देरी मुद्राएँ देनी होगी। इस प्रकार माँग या पूर्ति में असन्तुलन होता है तो विनिमय दर की समता ऊपर या नीचे चली जाती है। विनिमय दर के बढ़ने या घटने की सीमा जानने के लिए विभिन्न मुद्रा सम्बन्धी परिस्थितियों पर अलग में विचार करना होता है। ये निम्न प्रकार हैं—

(1) जब दोनों देश स्वर्णमान (Gold Standard) पर हों—जब दो देशों में स्वर्णमान होना है तो उनके बीच विनिमय ममाना प्राप्त करने के लिए उनके प्रामाणिक मिक्को की विमुद्र स्वर्ण से समानता स्थापित की जाती है। इसे टक समता दर (Mint Par of Exchange) कहा जाता है। इस व्यवस्था में उतार-चढ़ाव उन सीमाओं के बीच होते हैं जो उच्चतम और निम्नतम स्वर्ण विन्दुओं द्वारा निर्धारित होती है।

निश्चित दिन को ही देने के समझौते किए जाते हैं। मुद्रा की कीमत समझौते के समय निर्धारित कर दी जाती है। बदले में भुगतान विदेशी मुद्रा देने के समय किया जाता है। अग्रिम बाजार यथास्थान विनिमय बाजार (Spot Exchange Market) से भिन्न होते हैं जिनमें विदेशी मुद्रा तुरन्त भुगतान के लिए दी जाती है।

तदनुसार अग्रिम विनिमय दर वह कीमत है जो भविष्य में निर्धारित समय दी जाने वाली मुद्रा के लिए तय की जाती है। सुविधा के लिए अग्रिम विनिमय वास्तविक कीमत के रूप में नहीं बरन् उनकी प्रीमियम या कटौती के रूप में वर्णित किए जाते हैं जो यथास्थान दर के ऊपर होती है। इस प्रकार ये वास्तविक कीमतें नहीं हैं बरन् यथास्थान दरों पर प्रीमियम या कटौती की दर हैं।

अग्रिम विनिमय सुविधाएँ अधिकतर बैंकों द्वारा प्रदान की जाती हैं। बैंक इन सुविधाओं के लिए कमीशन लेते हैं। माधारणतः वे इनकी कोई जोखिम नहीं उठाते। अनेक आयातकर्ता भावी जोखिम से बचने के लिए अग्रिम रूप से विनिमय खरीद लेते हैं। इसी उद्देश्य से निर्यातकर्ता उसे बेचते हैं। श्रेता और विव्रेता के मध्य विचौलियों का कार्य सम्पन्न करने के कारण बैंक कमीशन कमाती है। यदि कोई बैंक किसी आयातकर्ता को अग्रिम विनिमय बेचने का समझौता करती है तो उसी समय किसी निर्यातकर्ता से खरीदने का समझौता भी कर लेती है। बैंक की खरीद और बिक्री समान होती है इसलिए किसी जोखिम का प्रश्न नहीं उठता। बैंक सट्टेबाजी में न पड़कर केवल कमीशन से प्रयत्न लाभ कमाती है। इसलिए विनिमय दर की कीमत के उत्तार-चढ़ावों से वह अपने-प्राप्त को प्रत्यक्ष बनाए रखती है। बैंक अनेक विकल्पों से जोखिम को दूर रखने का प्रयास करती है। आवश्यकता के समय बैंक सट्टेबाजों से विनिमय खरीद लेती है अथवा यदि किसी स्रोत से उसे मुद्रा न मिल सके तो वह प्रतिरिक्त अग्रिम विनिमय बेचना प्रसवीकार कर देती है।

अग्रिम विनिमय दरों का निर्धारण

(Determination of Forward Exchange Rates)

अग्रिम विनिमय दरें अग्रिम विनिमय की माँग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती हैं। यदि उनकी 'पूर्ति' माँग की अपेक्षा अधिक बढ़ जाती है तो अग्रिम विनिमय दर यथास्थित विनिमय दर से नीची होती है। दूसरी ओर यदि उनकी 'माँग' पूर्ति की अपेक्षा बढ़ जाती है तो अग्रिम विनिमय दरें यथास्थान विनिमय दरों (Spot Exchange Rates) की अपेक्षा ऊँची होगी। अग्रिम विनिमय की माँग मुख्य रूप से आयातों, पूँजी के वहिर्गमन, सट्टेबाजी आदि द्वारा पैदा होती है। विदेशी माल को प्राप्त करने वाला यदि भविष्य में भुगतान करे तो विनिमय दरों से परिवर्तन के जोखिम से बचने के लिए वह अग्रिम रूप से विदेशी विनिमय खरीदने का सौदा कर सकता है। जब सट्टेबाज विनिमय दर बढ़ने की आशा करते हैं तो वे अग्रिम विनिमय खरीदने के लिए समझौता कर लेते हैं। अग्रिम विनिमय की पूर्ति के स्रोत मुख्यतः पूँजी के निर्यातकर्ता, सट्टेबाज, व्यापारिक वस्तुओं के निर्यातकर्ता आदि होते हैं।

कटौती की दर बढ़ती चली जाएगी। इस प्रकार भारत से लन्दन के लिए प्रतिरिक्त कोष के परिवर्तन की प्रेरणा समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जब भारत से पूँजी लन्दन की ओर जाएगी तो भारत में व्याज की दरें बढ़ जाएँगी और लन्दन में कम हो जाएँगी। दोनों देशों के बीच व्याज की दरों के अन्तर कम हो जाएँगे। अन्त में एक समतुल्य स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसमें अग्रिम विनिमय दर कटौती व्याज की दर के अन्तर के बराबर हो जाएगी और इसलिए पूँजी के हस्तान्तरण की प्रेरणाएँ समाप्त हो जाएँगी।

अग्रिम विनिमय बाजार के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह केवल कुछ मूलभूत शक्तों के साथ ही कार्य कर सकता है। प्रमुख शक्तें ये हैं— (1) विदेशी मुद्रा में व्यापार, सट्टेबाजी आदि पर अनुचित प्रतिबन्ध नहीं होने चाहिए। (2) मुद्रा-चलन को विनिमय की निश्चित दर पर कठोर रूप से स्थिर नहीं करना चाहिए। (3) सम्बन्धित मुद्रा-चलन पर्याप्त महत्वपूर्ण है, अर्थात् इसमें किए जाने-वाले लेन-देन नियमित और पर्याप्त होने चाहिए। विनिमय नियन्त्रण के होने पर अग्रिम समझौतों में बाधा आएगी और इस प्रकार अग्रिम बाजारों का कार्य रक जाएगा। कुछ बेश अग्रिम विनिमय लेन-देनों पर पूरी तरह रोक लगा देते हैं।

क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त

(Purchasing Power Parity Theory)

इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वीडन के अर्थशास्त्री गुस्ताव कॅसिन (Gustav Cassel) ने किया। उसने विभिन्न देशों की मुद्राओं के बीच सही विनिमय दर को निर्धारित करने के लिए यह सिद्धान्त आनाया। सिद्धान्त के दो रूप हैं— पूर्ण एवं तुलनात्मक। इसके पूर्ण रूप के अनुसार विनिमय दर उस समय समतुल्य होगी जब व्यापार करते वाले सभी देशों में मुद्रा की क्रय-शक्ति समान होगी। अपने तुलनात्मक रूप में यह क्रय-शक्ति के परिवर्तनों एवं विनिमय दरों में होने वाले परिवर्तनों के बीच सम्बन्ध स्थापित करता है। यह एक विशेष समय विभिन्न देशों की मुद्राओं के बीच सही विनिमय दर को निर्धारित करता है। सिद्धान्त के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर कीमत स्तर में होने वाली वृद्धि या कमी विनिमय दर में प्रानुपातिक कमी या वृद्धि का कारण बनती है।

आलोचना—(1) आलोचकों का कहना है कि यह सिद्धान्त केवल सभी उपयुक्त ठहरता है जब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की जाने वाली वस्तुओं पर ही लागू किया जाता है तथा सामान्य कीमत-स्तर पर लागू करते समय सही सिद्ध नहीं होता। व्यापार न की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से स्वतन्त्र रहती हैं। ऐसी वस्तुओं की घरेलू और विदेशी कीमतों के बीच कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रहता। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें विनिमय दर में होने वाले परिवर्तनों के साथ आवश्यक रूप से सहाय्योन्नत हो जाती हैं। वस्तुओं की घरेलू कीमतें विनिमय दरों के परिवर्तनों को निर्धारित करने की अपेक्षा उन्हें स्वीकार करती हैं। कॅसिल का मत था कि यदि इसे अन्तर्राष्ट्रीय

व्यापार की जाने वाली वस्तुओं पर लागू किया गया तो सिद्धान्त अधिक उपयुक्त नहीं रहेगा ।

(2) सभी घटना क्रमों एवं आकस्मिक सम्बन्धों के बीच घन्तर किया जाना चाहिए । घरेलू कीमन-स्तर और विदेशी विनिमय की दर के बीच विरोधी गति का ग्रथं आवश्यक रूप से यह नहीं हाना कि बाद वाले का परिवर्तन प्रथम क परिवर्तन का परिणाम है । प्रायः दूसरे कारणों से भी इन दोनों में परिवर्तन हो जात हैं । कभी-कभी विनिमय दर के कारण वस्तुओं की कीमतें बदल जाती हैं । विनिमय दर में होने वाली कटौती घरेलू मुद्रा की दृष्टि से आयात और निर्यात की जान वाली वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा देगी । यह वृद्धि उन घरेलू वस्तुओं की कीमता को बढ़ाएगी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की स्थानापन्न बन सकती हैं । घरेलू तथा व्यापार की जाने वाली वस्तुओं के लिए प्रयुक्त उत्पादन के साधन बहुत कुछ एक जैसे होते हैं । यदि व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी तो घरेलू वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाएंगी इस प्रकार विनिमय दर में होने वाली कमी सामान्य कीमन स्तर को बढ़ा देगी ।

(3) कीमन-स्तर में परिवर्तन की मान्यता पर्याप्त व्यापक है । सभी वस्तुओं की कीमतें कभी एक ही दिशा में गति नहीं करती । कुछ वस्तुओं की कीमतें दूसरों की प्रपक्षा अधिक तेजी से घटती या बढ़ती हैं । ऐसी स्थिति में विभिन्न देशों के बीच कीमन गतियों की तुलना नहीं की जा सकती । इन प्रकार की कोई तुलना निश्चित नहीं हो सकती, केवल अनुमान मात्र हो सकती है ।

(4) इस सिद्धान्त का पूर्ण रूप वस्तुओं के स्थानान्तरण की लागत का मना देता है । सिद्धान्त केवल सभी सही रहगा जब विभिन्न देशों के बीच वस्तुएं स्वतन्त्रता पूर्वक बिना किसी लागत के आती-जाती रहें । वास्तविक व्यवहार में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें दो देशों के बीच स्थानान्तरण लागत के कारण भी बदल सकती हैं । इसके अनिश्चित सूचना का अभाव, नए माचार में विषय-लागत, पहल का आयात आदि विभिन्न कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वस्तुओं की कीमतें विभिन्न देशों में अलग-अलग हो सकती हैं ।

(5) दो देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय दर नय शक्ति समता (Purchasing Power Parity) द्वारा ही निर्धारित नहीं होती बल्कि एक दूसरे की वस्तुओं के बीच देशों की पारस्परिक माँग (Reciprocal Demand) द्वारा भी होती है । वस्तुओं की पारस्परिक माँग में रुचि, पंशन, आय इत्यादि के कारण परिवर्तन आते हैं । यह परिवर्तन कीमन स्तरों के अपरिवर्तित रहने पर भी विनिमय दर में परिवर्तन ला देते हैं । कमिश्न ने प्रोजेक्चर वाइनर के साथ वाद विवाद के समय विनिमय दर के निर्धारण में पारस्परिक माँग के योगदान को स्वीकार किया है ।

(6) कंसिल का कहना था कि बागजी मुद्रा की मात्रा में होने वाला कोई परिवर्तन उसके आन्तरिक और बाहरी मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन का कारण बनेगा । इस गतिशील ससार में मुद्रा का आन्तरिक और बाहरी मूल्य उसके आकार

में परिवर्तन से अधिक या कम हो सकता है। मुद्रा का बाहरी और आन्तरिक मूल्य निर्धारित करने में आजाएँ और अनुमान महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। विनिमय-दर प्रायः वास्तविक की अपेक्षा अनुमानित क्रय शक्ति समता से प्रभावित होती है।

(7) यह देखना अत्यन्त कठिन है कि किस समय विनिमय-दर समतुल्य होगी। इसलिए किसी विशेष समय सही विनिमय-दर निर्धारित करने के लिए आधारभूत समय कैसे माना जाए यह समस्या उत्पन्न हो जाती है।

(8) क्रय शक्ति समता केवल एक वस्तु कीमत समता है। यह वस्तुओं के व्यापार में उत्पन्न विदेशी मुद्रा की माँग और पूर्ति को ध्यान में रखती है। यह दीर्घकालीन निवेश के प्रभाव, व्याज और लाभांश के स्थानान्तरण और विदेशी विनिमय की माँग तथा पूर्ति पर पूँजी की अल्पकालीन गतियों की प्रवृत्तियों पर करती है। दो देशों में कीमत-स्तर के अग्रवर्धित रहने पर भी उनके पूर्वोक्त आवागमन दोनों देशों की विनिमय-दर में परिवर्तन ला देते हैं।

क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त सर्वप्रथम विनिमय दरों में होने वाली उन गतियों को स्पष्ट करने के लिए बनाया गया जो प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान हुई थी। विश्व-युद्धों के मध्यवर्ती काल में इस सिद्धान्त की कटु आलोचनाएँ हुईं और इसे बहुत कुछ ठुकरा दिया गया। अनेक आलोचनाओं के बाद भी यह कहा जा सकता है कि सिद्धान्त निरर्थक नहीं है। यह एक दम निश्चित (Exact) नहीं हो सकता, किन्तु सही विनिमय दर निर्धारित करने में महत्वपूर्ण पथ-प्रदर्शक हो सकता है।

विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के कारण

(The Causes of Fluctuations in Rates of Exchange)

मुद्राओं की विभिन्नता के कारण विदेशी व्यापार की जटिलताएँ पर्याप्त बढ़ जाती हैं। प्रत्येक देश यह चाहता है कि भुगतान उसी की मुद्रा में किया जाए प्रयत्न ऐसी मुद्रा में किया जाए जो सभी देशों में महत्व रखती हो। जिस समय स्वर्णमान (Gold Standard) का प्रभाव था, उस समय प्रत्येक देश अपना भुगतान सोने के रूप में कर सकता था और इसलिए विदेशी मुद्रा की समस्या कोई गम्भीर नहीं थी। आजकल स्वर्णमान (Gold Standard) छूट चुका है। इसके प्रतिरिक्त सोने को भेजना भी पर्याप्त खर्चीला होता है। अतः कोई भी देश अपने स्वर्णकोष को खाली करना पसन्द नहीं करता।

उपयुक्त स्थिति के कारण विनिमय दर की आवश्यकता महसूस हुई। इसके द्वारा दो देशों की मुद्राओं के विनिमय-अनुपात को प्रकट किया जाता है। विनिमय दरों में समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं जो विभिन्न कारणों का परिणाम है। यह परिवर्तन किसी देश के लिए अधिक फलदायी नहीं होता और प्रायः प्रत्येक देश का मुद्राधिकारी यह प्रयास करता है कि दीर्घकाल में विनिमय दर स्थिर रहे। एक देश जिस प्रक्रिया द्वारा दीर्घकालीन विनिमय स्थिरता प्राप्त करता है वह भिन्न-भिन्न देशों के मुद्रा-मानों के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। विनिमय दर पर जिन विभिन्न तत्वों का प्रभाव पड़ता है वे अनेक हैं। इनमें विदेशी मुद्रा की माँग और पूर्ति तथा राजनैतिक परिस्थितियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है।

किसी देश की माँग और पूर्ति विभिन्न कारणों से प्रभावित होती है—

(1) इसका प्रथम कारण व्यापारिक है। इसके अनुसार यदि एक देश का निर्यात उसके आयात से अधिक है तो उस देश की मुद्रा की माँग उसकी पूर्ति की अपेक्षा बढ़ जाएगी और इसलिए विनिमय की दर उस देश के पक्ष में हा जाएगी। इसके विपरीत जब एक देश का 'आयात' निर्यात की अपेक्षा अधिक होता है तो वहाँ विदेशी मुद्रा की 'माँग' पूर्ति की अपेक्षा बढ़ जाएगी। अतः, व्यापार और लाभार्जन आदि द्वारा भी विनिमय दर पर पर्याप्त प्रभाव डाला जाता है।

(2) जब एक देश, विदेशों में प्रतिभूतिपूर्ण खरीदता है तो विदेशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा देने के लिए विदेशी मुद्रा की माँग बढ़ जाती है। दूसरी ओर यदि विदेशी लोग उस देश में प्रतिभूतिपूर्ण खरीद रहे हैं तो उन्हें भुगतान करने के लिए देशी मुद्रा जुटानी होगी। फलतः विदेशी मुद्रा की पूर्ति उसकी माँग की अपेक्षा बढ़ जाएगी। माँग और पूर्ति के इस परिवर्तन से विनिमय दर में भी उतार-चढ़ाव आता रहेगा।

(3) बैंकों से सम्बन्धित कुछ कारण होने हैं जो विदेशी विनिमय में उतार-चढ़ाव लाते रहते हैं। जब बैंकों द्वारा विदेशी बिलों भ्रष्टाचार यात्रियों के साख-पत्रों का क्रय-विक्रय किया जाता है तो पूँजी का एक देश से दूसरे देश को स्थानान्तरण होना रहता है। यह स्थानान्तरण विनिमय दर के परिवर्तन का कारण बनता है। बैंक दर में वृद्धि या बढोत्तरी होने के कारण पूँजी से आवागमन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है और इसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की माँग और पूर्ति भी प्रभावित होती है।

(4) मुद्रा सम्बन्धी विभिन्न कारणों का भी विनिमय दर पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए जब मुद्रा का प्रसार होता है तो पूँजी विदेशों को जाने लगती है। मुद्रा प्रसार (Inflation) होने से उसका अवमूल्यन हो जाता है। परिणामस्वरूप मुद्रा की क्रय-शक्ति कम हो जाती है तथा विनिमय दर देश के प्रतिबल हो जाती है। मुद्रा संकुचन (Deflation) का भी विनिमय दर पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि ऐसा होने पर विदेशियों द्वारा लाभ के लोभ में देशी मुद्रा खरीदी जाती है।

(5) राजनैतिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप भी विनिमय दर प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए सरकार की सरकार नीति जिसके द्वारा आयात को संकुचित और निर्यात को वृद्धिशील किया जाता है, विनिमय दर पर पर्याप्त प्रभाव डालती है। इस प्रभाव के कारण भुगतान सन्तुलन देश के अनुकूल हो जाता है और विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है। दूसरे, युद्ध और शान्ति की स्थितियाँ भी इस दृष्टि से अत्यन्त महत्व रखती हैं। देश में जब शान्ति रहती है तो सरकार स्थायी, निष्पक्ष एवं कुशल बन जाती है और इससे विदेशियों का उसमें विश्वास बढ़ जाता है। वे अपनी पूँजी देशी उद्योगों के विकास में लगाने लगते हैं। इसके फलस्वरूप विनिमय दर अनुकूल दिशा में प्रभावित होती है। तीसरे, एक देश की वित्तीय नीति भी उसकी विनिमय दर का प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए, यदि सरकार द्वारा उसके बजट में घाटे की धर्म-धरस्या घपनाई जाती है

तो इसके फलस्वरूप विनिमय दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि देश में वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जो मुद्रा-प्रसार के समय होती है। चौथे, सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक द्वारा विनिमय नियन्त्रण के विभिन्न साधनों को अपनाकर विनिमय दर को प्रभावित किया जा सकता है।

अनुकूल एवं प्रतिकूल विनिमय दरें (Favourable and Unfavourable Exchange Rates)

यदि हम विनिमय दरों की अनुकूलता या प्रतिकूलता पर विचार करना चाहे तो इसके लिए हमें यह जानना चाहिए कि विनिमय दर स्वदेशी मुद्रा में प्रकट की जा रही है अथवा विदेशी मुद्रा में। जब हम विनिमय दर को स्वदेशी मुद्रा में प्रकट कर रहे हैं तो उसका गिरना या कम होना स्वदेश के पक्ष में होता है और उसका बढ़ना या ऊँचा होना स्वदेश के विपक्ष में होता है। दूसरी ओर यदि विनिमय दर को विदेशी मुद्रा में प्रकट किया जा रहा है तो बढ़ती हुई विनिमय दर स्वदेश के पक्ष में और घटती हुई विपक्ष में होती है।

अनुकूल विनिमय दरें विभिन्न व्यक्तियों पर अनेक प्रकार से प्रभाव डालती हैं। इनसे आयात को प्रोत्साहन मिलता है और निर्यात घटता है। इससे आयात कर्त्ताओं तथा उपभोक्ताओं को लाभ होता है और निर्यातकर्त्ताओं एवं उत्पादकों को हानि होती है तथा बेरोजगारी बढ़ती है।

विनिमय दर प्रतिकूल होने पर आयात घट जाते हैं और निर्यातों को प्रोत्साहन मिलता है। इससे निर्यातकर्त्ता एवं उत्पादक लाभ में रहते हैं, किन्तु आयातकर्त्ताओं एवं उपभोक्ताओं को हानि उठानी पड़ती है और अर्थिकी का रोजगार बढ़ता है।

विनिमय दर के प्रभावों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक विनिमय दर समाज के एक वर्ग पर यदि अनुकूल प्रभाव रखती है तो वह अन्य वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव भी रखती है और इस प्रकार किसी विशेष समय पर विनिमय को अनुकूल या प्रतिकूल कहना एक विरोधाभास सा प्रतीत होता है। कुल मिलाकर विनिमय दर का उतार-चढ़ाव लाभदायक नहीं होता; इससे व्यापार एवं व्यवसाय की क्षति पहुँचती है। जब विदेशी विनिमय दर बढ़ जाती है तो उसके परिणामस्वरूप होने वाली हानि को भरने के लिए व्यापारी वर्ग इस वृद्धि को ठहराए रखने का प्रयास करता है।

भुगतान सन्तुलनों का समायोजन

(The Adjustment Mechanisms under Gold Standard, Fixed Exchange Rates and Flexible Exchange Rates)

भुगतान सन्तुलनों में समायोजन करना परम आवश्यक है क्योंकि विनिमय की दर एक ऐसी कीमत होती है जिसे विदेशी विनिमय की माँग और पूर्ति की त्रिया प्रतित्रिया द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। इसके अलावा विनिमय दर एक ऐसा तत्व भी है जो विदेशी विनिमय की माँग और पूर्ति को प्रभावित करती है। इस प्रकार विनिमय-दर (Rate of Exchange) कारण और कार्य दोनों हैं। यहाँ

यह विषय महत्वपूर्ण है कि भुगतान सन्तुलन में विदेशी विनिमय की मांग और उसकी पूर्ति के बीच किस प्रकार सन्तुलन स्थापित किया जाता है।

समायोजन की आवश्यकता

(The necessity of Adjustment)

भुगतान सन्तुलन में जब असन्तुलितता आ जाती है तो एक देश के माल और सेवाओं का निर्यात उसके आयातों की अपेक्षा घट जाता है। समायोजना की आवश्यकता प्रायः इसलिए होती है क्योंकि एक देश में विदेशी मुद्रा की पूर्ति सन्तुलित रहती है। इस सम्बन्ध में किंडलेबर्गर (Kindleyberger) का कहना है कि "ब्रिटिश सरकार जब चाहे तब पौण्ड छाप सकती है अथवा बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से उन्हें बना सकती है किन्तु वह अमेरिकी डालर नहीं बना सकती।"¹ ऐसी स्थिति में यह ज़रूरी हो जाता है कि सामग्र्यत्व की किसी व्यवस्था द्वारा भुगतान सन्तुलन की असमन्वयता को दूर किया जाय। जब एक देश की विदेशी विनिमय की पूर्ति उसकी वर्तमान आवश्यकताओं को देखने हुए कम रहती है तो उसे अपनी विनिमय की प्रतिभूतियों (Reserves) और सोने की काम में लेना होता है और इस प्रकार उसकी विदेशी सम्पत्ति कम हो जाती है तथा उसके विदेशी दायित्व बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में उसका भुगतान सन्तुलन घाटे की अवस्था में माना जाएगा। दूसरी ओर यदि भुगतानों की प्राप्ति का स्तर भुगतानों के दायित्व से अधिक है तो यह कहा जाएगा कि भुगतानों के सन्तुलन में अतिरिक्त है और समन्वयता का अभाव है।

भुगतान सन्तुलन में कमी अथवा अतिरिक्त कोई असाधारण बात नहीं है बल्कि यह तो प्रायः होता ही रहता है। वस्तुओं की कीमत के घटने बढ़ने से अथवा उसकी मांग कम या अधिक होने से भुगतान सन्तुलन आगे-पीछे चलता रहता है।

इस प्रकार विभिन्न कारणों से देश का भुगतान सन्तुलन बिगड़ सकता है। इनमें प्रकृति का प्रकोप, आर्थिक मन्दी, व्यापार चक्र (Business Cycle), युद्धजनित उत्पादनों का जन्म, पुराने उत्पादनों की रचना के नए तरीके तथा अन्य कई कारण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। किंडलेबर्गर के शब्दों में "अन्तर्राष्ट्रीय समायोजन की समस्या एक प्रदत्त कीमत पर एक प्रदत्त विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति के बीच स्थित अन्तरों में समझौता करना है।"²

जब एक देश का भुगतान सन्तुलन अस्त-व्यस्त होता है तो उसे किम प्रकार स्थापित किया जाए यह एक समस्या है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त शास्त्रियों ने इस प्रश्न पर बहुत समय पूर्व ही विचार करना प्रारम्भ किया और इस विषय पर पर्याप्त साहित्य मिलता है। इस साहित्य का सक्षिप्तीकरण करते हुए वाल्टर वॉत्र

1 "The British Govt can print Pounds Sterling any time it choses (or create them through the Banking System), it can not however, create U S Dollars"—Charles P Kindleyberger, International Economics, p 63.

2 "The problem of International Adjustment is that of reconciling the differences between the demand for and the supply of a given foreign exchange at a given price"—C P Kindleyberger.

(Walter Krause) ने लिखा है कि स्वतन्त्र व्यापार की स्थितियों में (या तो स्वयं मान के अधीन या परिवर्तनीय कागज के अधीन) जब विनिमय दरों (Exchange Rates), कीमतों (Prices) और आय (Incomes) में परिवर्तन होते हैं तो भुगतान सन्तुलन में सामन्जस्य स्वतः ही होता रहता है। इसके विपरीत जो देश स्वतन्त्र व्यापार की स्थितियों में सामन्जस्य नहीं लाता चाहता है वह घाटे की स्थिति में अपने अन्तर्राष्ट्रीय लेखों को सन्तुलित बनाने के लिए विनिमय नियन्त्रण (Exchange Control) लागू कर सकता है। इसका उद्देश्य विदेशी विनिमय की मांग को जबरदस्ती इतना घटा देना है कि उसकी मात्रा उपलब्ध पूर्ति से अधिक न होने पाए।¹ इस सम्बन्ध में मि. हेबरलर का यह कहना पर्याप्त सही है कि “भुगतान सन्तुलनों का सामन्जस्य करने वाले यन्त्र से सम्बन्धित सिद्धान्त इनका ही पुराना है जितनी कि स्वयं आर्थिक विचारधारा है।”²

समायोजन की व्यवस्थाएँ (The Systems of Adjustment)

उक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भुगतानों के अन्तर्राष्ट्रीय सामन्जस्य की स्थापना के लिए विभिन्न प्रक्रियाएँ अपनाई जा सकती हैं। सामन्जस्य की इन प्रक्रियाओं अथवा व्यवस्थाओं को प्रस्तुतीकरण की सरलता के लिए मि. क्राउज़ (Mr. Crause) ने तीन प्रमुख भागों में विभाजित किया है—

- (1) स्वयंमान की स्थितियों के अधीन सामन्जस्य (The Adjustment under conditions of the Gold Standard);
- (2) अपरिवर्तनीय कागजी मुद्राओं के अधीन सामन्जस्य (Adjustment under inconvertible-Paper Currencies) तथा
- (3) विनिमय नियन्त्रण की व्यवस्थाओं के अधीन सामन्जस्य।
(Adjustment under Systems of Exchange Control)

प्रो० किटलेडजर ने भी अन्तर्राष्ट्रीय सामन्जस्य की ऐसी ही तीन व्यवस्थाओं का वर्णन किया है। उनके मतानुसार इनमें से प्रथम दो की प्रकृति अन्तर्राष्ट्रीय है जबकि अन्तिम की राष्ट्रवादी है। उनके द्वारा वर्णित व्यवस्थाएँ निम्न प्रकार हैं—

(1) स्वर्णमान या निश्चित विनिमय दर (Gold Standard or Fixed Exchange Rates)—इस व्यवस्था का मूल तत्त्व यह है कि विदेशी विनिमय की दरों को स्थिर रखा जाए और व्यवस्था के अन्य आन्तरिक नस्लों जैसे धन की मात्रा,

1 Walter Krause - The International Economy, Constable and Co., Ltd., London, 1955, p. 85

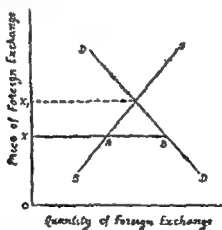
2 “The Theory of the adjustment mechanism of the balance of payments is as old as economic theory itself”—Gottfried Heberler, A survey of International Trade Theory, International Finance Section, Dept. of Economics, Princeton University, 1961, p. 33.

राष्ट्रीय धाय, कीमतों का स्तर तथा बैंकिंग और प्रशुल्क नीति आदि के द्वारा राष्ट्रीय धर्ष व्यवस्था को अन्तर्राष्ट्रीय सन्तुलन में बनाए रखने की आशा की जाए।

(2) कागजो मान या लोचशील विनिमय दर (Paper Standard or Fluctuating Exchange Rate)—इस व्यवस्था क अधीन धरनाई गई स्थिति पूर्व वर्णित की प्रपेक्षा विपरीत हानी है। इसमें राष्ट्रीय धाय, धरेनू कीमत स्तर, मोडक तथा बैंकिंग नीति और प्रशुल्क सम्बन्धी व्यवहारों को यथावत् रखा जाना है और विनिमय दरों में परिवर्तन लाकर अन्तर्राष्ट्रीय समायोजन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है।

(3) विनिमय नियन्त्रण (Exchange Control)—इस व्यवस्था में उपयुक्त दानो व्यवस्थाओं के सत्त्वों का मिला दिया जाता है। इसमें राष्ट्रीय धाय और धन की मात्रा आदि को यथावत् रखा जाना है और एक स्थाई विनिमय दर कायम की जाती है। धर्षन उद्देश्य को प्राप्त क लिए इसमें आयातों को प्रत्यक्ष रूप में नियंत्रित क स्तर पर सीमित कर दिया जाता है या निर्यातों को आयातों के स्तर पर लाया जाता है अथवा दोनों को मोश मोश बदला जाता है।

इन तीनों व्यवस्थाओं के बीच मूल-भूत अन्तर को निम्न रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है—



इस रेखाचित्र में यह अर्शित किया गया है कि विदेशी मुद्रा की माँग (D, D) विदेशी मुद्रा की पूर्ति (S, S) से अधिक बढ जाती है। निश्चिन् विनिमय दर के अधीन धरेनू नीतियाँ बदली जाएँगी ताकि पूर्ति और माँग स्वतन्त्र बाजार में O, X कीमत पर समन्वय बनाई जा सके। एक लोचशील विनिमय दर के अधीन धरेनू नीतियों में परिवर्तन को अनावश्यक समझा जाएगा और पूर्ति तथा माँग की शक्तियों को समन्वय कीमत O, λ_1 लाने की स्वतन्त्र अनुमति दी जाएगी। विनिमय नियन्त्रण के अधीन O, λ कीमत को X-Y मात्रा को

माँग करने वाले लोगो में उपलब्ध पूँति $X A$ को आवंटित करके बनाए रखा जाएगा। इस प्रकार $A B$ द्वारा प्रस्तुत की गई माँग का भाग अपूर्ण बना रहेगा।

स्वर्णमान के अधीन विनिमय दर स्वर्ण-बिन्दुओं की सीमाओं में रहकर लोचशील होने के लिए स्वतन्त्र रहती है। इस प्रकार सामन्जस्य की प्रक्रिया कीमतों और आय में परिवर्तन के द्वारा सम्पन्न की जाती है। आय और कीमतों में परिवर्तन व्यापार को और इस प्रकार विदेशी विनिमय की पूँति और माँग को प्रभावित करते हैं। मुग्तानों के सन्तुलन में समतुल्यता केवल तभी मानी जा सकती है जब विदेशी विनिमय की पूँति और माँग दोनों का अनुपात बराबर हो। अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा के अधीन विनिमय की दर असंमित रूप से लोचशील रह सकती है। इस दर में परिवर्तन एवं कीमतों तथा आय के परिवर्तन मिलाकर विदेशी विनिमय की माँग और पूँति को बराबर बनाने का प्रयास करते हैं। जो देश स्वतन्त्र बाजार की परिस्थितियों में समायोजन की स्थापना नहीं करता वह विदेशी विनिमय की माँग को उपलब्ध पूँति की मात्रा तक सीमित करने के लिए विनिमय नियन्त्रण लगा सकता है। यहाँ विनिमय दर स्थिर बनी रहने दी जाती है। इस प्रकार सन्तुलन बाध्यकारी तरीके से प्राप्त किया जाता है न कि स्वतन्त्र बाजार की शक्तियों के माध्यम से।

इस प्रकार असमतुल्यता (Disequilibrium) की स्थिति में सामन्जस्य स्थापित करना परमावश्यक होता है। तारशिस (Tarshis) का कहना है कि "जब मुग्तान सन्तुलन समतुल्यता से बाहर है तो कुछ न कुछ होना चाहिए। यदि कुछ भी न करने की नीति अपनाई गई तो भी समायोजन होकर रहेगा।"¹ जब यह जानबूझ कर समायोजन नहीं किया जाता तो जो समायोजन होना है, वह अनिच्छापूर्ण होता है और ऐसी स्थिति में सम्बन्धित व्यक्तियों को अपनी खरीददारी कम करनी पड़नी है।

समायोजन जिन परिस्थितियों में किया जा सकता है उनका वर्णन हम पहिले कर चुके हैं। इन परिस्थितियों में किए जाने वाले प्रयासों का उल्लेख हम पृथक् से कर सकते हैं। ये प्रयास समायोजन की परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। जिस समय मुग्तानों का सन्तुलन सन्तुलित रहते हुए भी सन्तोषजनक स्तर पर नहीं रहता उस समय सन्तुलन की नवीन एवं आकर्षक स्थिति प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए सरकार और मौद्रिक संस्थाएँ अपनी आय के स्तर को बढ़ाने का लक्ष्य अपना लेती हैं अथवा आय प्रतिबन्धों को छूट दे देती हैं या उन्हें सीमित कर देती हैं अथवा पूँजीगत बाजार को स्वतन्त्र कर देती हैं। असमतुल्यता की स्थिति को सुधारने के लिए जो विभिन्न प्रयास किए जाते हैं उनको तारशिस (Tarshis) ने तीन समूहों में वर्गीकृत किया है—(1) अपरम्परागत किन्तु अप्रत्यक्ष उपाय (2) परम्परागत किन्तु प्रत्यक्ष उपाय और (3) धीमी गति वाले प्रयास।

इनमें से कुछ प्रयासों का उल्लेख निम्न प्रकार किया जा सकता है—

(1) निर्यातों में वृद्धि—असमतुल्यता को दूर करने का एक तरीका यह है कि पहले व्यापार सन्तुलन प्राप्त किया जाए। इसके लिए निर्यातों में वृद्धि की जाएगी

1 "When the Balance of Payment is out of equilibrium, something must happen... even if a policy of complete inaction is adopted an adjustment will have to take place"—*Lorie Tarshis, Introduction to International Trade and Finance, 1955, p. 300.*

करने में सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा यदि हमारे देश इस नीति की प्रतिक्रिया स्वरूप अपने देश में मुद्रा के मूल्य एवं वस्तुओं के मूल्य को कम कर दें तो यह नीति अधिक फलदायक नहीं होगी।

(4) मुद्रा का अवमूल्यन (Devaluation of Currency)—यह एक अन्य प्रक्रिया है जिसे मुग्तान सन्तुलन में समानता लाने की गरज से प्रयुक्त किया जाता है। अवमूल्यन में एक देश अपनी मुद्रा के बाहरी मूल्य को कम कर देता है जिसके परिणामस्वरूप वह मुद्रा पहले की अपेक्षा विदेशों से कम वस्तुएँ खरीद पाती है और विदेशी वस्तुओं को खरीदने में पहले की अपेक्षा अधिक खर्च देना होता है। अवमूल्यन हो जाने से विदेशी मुद्रा पहले की अपेक्षा अब अधिक देशी माल की खरीद कर सकती है इसलिए निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है।

अवमूल्यन का प्रभाव और सफलता बहुत कुछ दूसरे देशों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करते हैं। यदि दूसरे देश इससे नाराज होकर अपने भायातों पर कर अधिक या कम कर दें तो इस नीति के सफल होने की सम्भावनाएँ कम हो जाती हैं। अवमूल्यन की नीति को अपनाने से पहले यह देख लेना चाहिए कि विदेशों में उसकी वस्तुओं की माँग और स्वदेश में विदेशी वस्तुओं की माँग लोचदार है या नहीं। वस्तुओं की माँग के लोचशील होने के कारण मुद्रा का अवमूल्यन करने से कोई लाभ नहीं होता और न ही मुग्तान सन्तुलन की असमत्वता को दूर करने का लक्ष्य पूरा हो सकता है। इस स्थिति में अवमूल्यन की नीति को अपनाने से पहले भी पर्याप्त मजबूती रखनी चाहिए।

मुग्तान सन्तुलन में समतुल्यता न होना अन्तर्राष्ट्रीय चिन्ता का विषय है और इसलिए कुछ अन्तर्राष्ट्रीय संगठन इसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इस स्थिति में एक देश की सहायता की जाती है। वह मुग्तान सन्तुलन में समतुल्यता लाने के लिए असमतुल्यता की स्थिति को दो वर्गों में विभाजित करता है—मौलिक असमतुल्यता (Fundamental Disequilibrium) और अस्थायी असमतुल्यता (Temporary Disequilibrium)। इन दोनों स्थितियों में अलग-अलग उपाय बरतने का परामर्श दिया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने देश में उत्पन्न असमतुल्यता को दूर करने के लिए कोई भी कदम उठाने से पहले कोष से सहमति प्राप्त करें। कोष द्वारा अपने सभी राष्ट्रों की मुद्राओं का सम्बन्ध स्वर्ण अथवा डालर से स्थापित कर दिया गया है और इस प्रकार उनकी आपसी विनिमय दरें भी निर्धारित कर दी गई हैं। इन विनिमय दरों में यदि कोई परिवर्तन करना हो तो वह कोष की अनुमति लिए बिना नहीं किया जा सकता। जब एक देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो भी उसे आवश्यक रूप से कोष से पूछना होता है।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि मुग्तान सन्तुलन एक देश की
 : 1. मौलिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना के लिए यदि कोई

जब मुद्रा प्रसार की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो देश के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और मुद्रा संकुचन की स्थिति समाप्त हो जाएगी।

(4) मूल सुधार के लिए—कभी-कभी एक देश विभिन्न कारणों से प्रभावित होकर अपनी मुद्रा को जबरन से ज्यादा बाह्य कीमत प्रदान कर देता है। इस गलती को सुधारने के लिए वह मुद्रा का अवमूल्यन करता है।

(5) मुद्रा के आन्तरिक और बाह्य मूल्य में समानता लाने के लिए—जब एक देश की मुद्रा का आन्तरिक मूल्य कम हो जाता है और बाह्य मूल्य ऊँचा बना रहता है तो दोनों के बीच समानता स्थापित करने के लिए देश में उत्पादन लागत एवं मूल्य स्तर को नीचे गिराना होता है अथवा मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम करना होता है अथवा यह स्थिति देश की अर्थ-व्यवस्था और विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव डालती रहती है। इससे निर्यात कम हो जाते हैं और आयात बढ़ने लगते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन करके मुद्रा की आन्तरिक तथा बाह्य कीमत में समानता लाना अधिक सरल तथा लाभदायक है। इस प्रकार मुद्रा का अवमूल्यन विनिमय दर के उच्चावचनों को रोकने या उनमें समायोजन स्थापित करने के लिए किया जा सकता है।

मुद्रा के अवमूल्यन की नीति अपने विभिन्न उद्देश्यों को केवल तभी प्राप्त कर सकती है जबकि उसका प्रयोग पर्याप्त सजगता के साथ किया जाए। यदि अवमूल्यन की नीति को अपनाने पर दूसरे देश भी अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में उस देश को वांछनीय लाभ प्राप्त नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि जिस देश ने अवमूल्यन किया है उसके लागत मूल्य की संरचना विपरीत दिशा में परिवर्तित न हो अर्थात् निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों अवमूल्यन से पूर्व की कीमतों से अधिक न हो जायें। यदि कीमतों में वृद्धि होती है तो जिस सीमा तक यह वृद्धि हुई है, उस तक अवमूल्यन कोई भ्रष्टा परिणाम प्राप्त नहीं कर सकेगा। अवमूल्यन का प्रभाव शीघ्र होना चाहिए। यह जरूरी है कि निर्यातों को प्रोत्साहित एवं आयातों को हतोत्साहित करने के लिए अवमूल्यन का प्रभाव शीघ्र हो। ऐसा न होने पर विदेशों की माँग और लोच में परिवर्तन आ जाता है और वांछनीय परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते।

अवमूल्यन से लाभ

अवमूल्यन की नीति अर्थ-व्यवस्था के दोषों को सुधारने का एक अस्थायी साधन है। इस नीति द्वारा जो लाभ प्राप्त होते हैं वे ऐसे ही प्राप्त नहीं होते। ये लाभ केवल उसी समय तक मिलते हैं जब तक धरलू तथा विदेशी बाजारों में लागत मूल्य संरचनाएँ अवमूल्यन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली नवीन विनिमय क्षमता के अनुसार स्वयं को समायोजित नहीं कर लेतीं। सामान्यतः यह देखा गया है कि अवमूल्यन के लाभ एक देश को केवल 2-3 वर्ष तक प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार यह एक अस्थायी समायोजन है और कुछ समय तक के लिए एक देश को इससे राहत मिलती है। इतने पर भी अवमूल्यन की नीति को बार-बार नहीं अपनाना चाहिए।

निर्यात दूसरे देश के आयातों के बराबर होते हैं जिसको निम्नानुसार प्रकट किया जा सकता है—

$$m_A = x_B \quad \text{जहाँ } p_x^* = p_x/r \quad \dots(5)$$

$$\text{तथा } x_A = m_B \quad \text{जहाँ } p_m^* = p_m/r \quad \dots(6)$$

माना कि देश A तथा B के निर्यात तथा आयात के फलनिक सम्बन्ध निम्नानुसार हैं—

$$x_A = f_{Ax}(p_x) \quad \dots(7)$$

$$m_A = f_{Am}(p_m) \quad \dots(8)$$

$$x_B = f_{Bx}(p_m/r) \quad \dots(9)$$

$$m_B = f_{Bm}(p_x/r) \quad \dots(10)$$

हमने यह मान रखा है कि दोनों देशों के निर्यात तथा आयात आपस में बराबर हैं अतः ये निर्यात एवं आयात इनके मूल्यों पर निर्भर करेंगे जो कि यहाँ पर p_x तथा p_m हैं। परन्तु इन मूल्यों की विनिमय दर को अर्थात् r के आधार पर समायोजित किया जाता है। और यहाँ पर r वस्तुतः देश B की मुद्रा का देश A की मौद्रिक इकाइयों में प्रकटीकरण है। परन्तु क्योंकि $x_B = m_A$ है अतः समीकरण (9) तथा (10) के अनुसार x_B तथा m_B भी r पर निर्भर करेंगे इसलिए देश A की व्यापार शर्तों $\frac{p_x}{p_m}$ के तुल्य होगी। उपरोक्त विस्तारण में यह भी माना गया है कि A तथा B दोनों देशों के निर्यात पूँज तथा आयात माँग वक्र सामान्य हैं अर्थात् इनके ढलान क्रमशः घनात्मक तथा ऋणात्मक हैं इसलिए $f'_{Ax} > 0$ व $f'_{Bx} > 0$ होंगे तथा $f'_{Am} \leq 0$ व $f'_{Bm} \leq 0$ होंगे।

अवमूल्यन का देश A के व्यापार सन्तुलन (B की मुद्रा में व्यक्त) पर प्रभाव

माना कि देश B की मुद्रा में व्यक्त A का व्यापार सन्तुलन B_f है तो

$$B_f = \left(\frac{p_x}{r} \right) m_B - p_m^* - m_A \quad \dots(11)$$

समीकरण (11) से स्पष्ट होता है कि निर्यातों से प्राप्त आय (V_x) का उसके द्वारा आयातित वस्तुओं के मूल्य (V_m) पर आधिक्य व्यक्त करता है। यहाँ पर V_m तथा V_x दोनों ही B की मुद्रा का अर्थ है अर्थात्

$$V_m = p_m m_A = p_m x_B \quad \dots(12)$$

$$V_x = p_x x_A = p_x m_B \quad \dots(13)$$

जब A की मुद्रा का अवमूल्यन होता तो r का मूल्य बढ़ जाएगा अर्थात् देश B की मुद्रा की प्रत्येक इकाई के बदले देश A को अधिक मुद्रा देनी होगी। अवमूल्यन के परिणामस्वरूप देश B की मुद्रा में व्यक्त देश A का व्यापार सन्तुलन B_f उस

स्थिति में घटकर हो जाएगा जबकि $\frac{dB_f}{dr} > 0$ है तथा B_f उस समय घटकर हो जाएगा जबकि $\frac{dB_f}{dr} < 0$ हो अथवा B_f उस स्थिति में अपरिवर्तित रहगा जबकि

$\frac{dB_f}{dr} = 0$ होगा। यदि $\frac{dB_f}{dr} > 0$ है तो जितना उसका प्रथम अवचरण गुणांक

(First derivative) अधिक होगा देश A के व्यापार संतुलन में निम्न घाट को दूर करने हेतु देश A की मुद्रा का उनका ही कम अनुपात में अवमूल्यन करना उचित होगा।

यदि समीकरण (11) को एक सन्नत में अवचलन करने पर

$$\begin{aligned} \frac{dB}{dr} &= \frac{P_x}{r} m_p - \frac{P_x}{r} f_{pm} \frac{P_x}{r} - p_m^* f_{Am} p_m^* \\ &= \frac{V_x}{r} \left[-1 - \frac{f_{pm}}{f_{Bm}} \frac{P_x}{r} - \frac{f_{Am}}{f_{Am}} \times \frac{V_m}{V_x} p_m \right] \quad (14) \end{aligned}$$

यदि नियोजित तथा आगत की माँग लोच के समीकरण (1) से (4) को समीकरण (14) के साथ समायोजित करने पर हम निम्न समीकरण प्राप्त होगा—

$$\frac{dB_f}{dr} = \frac{V_x}{r} \left[-1 - e_{Bm} - \frac{V_m}{V_x} e_{Am} \right] \quad (15)$$

अवमूल्यन से A की व्यापार घने उस स्थिति में घटकर हो जाएगी जब समीकरण (15) के कोष्ठक में अन्तिम मूल्य इकाई से अधिक (>1) हो अर्थात् $\frac{dB_f}{dr} > 0$ हो तो A की व्यापार घने एवं व्यापार संतुलन उस देश में घटकर जाये। जब

$$-1 - e_{Bm} - \frac{V_m}{V_x} e_{Am} > 0$$

$$\text{अथवा} \quad -e_{Bm} - \frac{V_m}{V_x} e_{Am} > 1 \quad (16)$$

इस ही मामले-सन्दर्भ में कहना है। इस जगह से यह बात होता है कि विदेशी मुद्रा के रूप में अवमूल्यन में व उस स्थिति में लाभप्रद होता है जब दोनों माँग लोच का योग इकाई से अधिक हो ($e_{Bm} + e_{Am} > 1$)। परन्तु इस सन्नत में हमारी माँगना यह रहनी है कि अवमूल्यन से पूर्व आयात व निर्यात के मूल्य समान थे अर्थात् $V_m = V_x$ है।

यदि देश A के निर्यातों के लिए देश B की आयात माँग लोच इकाई से अधिक हो अर्थात् $e_{Bm} < -1$ हो तो अवमूल्यन का देश A के व्यापार संतुलन पर घटाने प्रभाव होगा। यदि $e_{Bm} > -1$ हो तो देश A के व्यापार संतुलन पर

का प्रभाव होगा, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है क्योंकि समीकरण (14) तथा (16) से स्पष्ट होता है कि अवमूल्यन से पूर्व का व्यापार सन्तुलन अथवा $\frac{V_m}{V_x}$ इस सन्दर्भ में अधिक महत्वपूर्ण है। यह अनुपात जितना अधिक होता है तथा देश A की आयात माँग जितनी सोचदार होती है, अवमूल्यन के फलस्वरूप व्यापार सन्तुलन में सुधार की उतनी ही अधिक सम्भावना रहती है।

$$-e_{Bm} - \frac{V_m}{V_x} e_{Am} > -e_{Am} - e_{Bm} \dots (17)$$

किण्डलबर्जर की मान्यता है कि देश A की स्वयं की मुद्रा के रूप में व्यक्त देश A के व्यापार सन्तुलन पर होने वाले प्रभाव को देखने हेतु हमें देश B की मुद्रा के रूप में व्यक्त व्यापार सन्तुलन B_f को निम्न प्रकार से बदलना होगा—

$$B_d = r B_f \dots (18)$$

समीकरण (18) में B, देश A की घरेलू मुद्रा के रूप में व्यक्त व्यापार सन्तुलन है। पूर्व की भाँति B_f देश A का देश B की मुद्रा के रूप में व्यक्त व्यापार सन्तुलन है जबकि r दोनों मुद्राओं की विनिमय दर है जो देश A की मुद्रा के रूप में व्यक्त की जाती है। समीकरण (18) का अवकलन करने पर

$$\frac{dB_d}{dr} = B_f + r \frac{dB_f}{dr} \dots (19)$$

यदि व्यापार सन्तुलन प्रारम्भ में ही सन्तुलन में हो तो समीकरण (19) बदल कर निम्नानुसार हो जाएगा—

$$\frac{dB_d}{dr} = r \frac{dB_f}{dr}$$

इसलिए जब $B_d = B_f = 0$ हो तो $\frac{dB_d}{dr}$ घनात्मक होगा। ऐसा तभी होगा जबकि $\frac{dB_f}{dr}$ भी घनात्मक हो। परन्तु व्यापार सन्तुलन प्रारम्भ में प्रतिकूल हो तो B_f में सुधार का यह भी अर्थ है कि B_d में भी सुधार होगा। B_f तथा $\frac{dB_f}{dr}$ को समीकरण (19) में समाधोजित करने तथा समीकरण (19) को पुनः समीकरण 14 एवं 15 की मदद से लिखने पर

$$\begin{aligned} \frac{dB_d}{dr} &= \frac{V_x}{r} - \frac{V_m}{r} + \frac{V_x}{r} \left(-1 - e_{Bm} - \frac{V_m}{V_x} e_{Am} \right) \\ &= \frac{V_m}{r} \left(-1 - e_{Am} - \frac{V_x}{V_m} e_{Bm} \right) \dots (20) \end{aligned}$$

इस प्रकार अवमूल्यन के फलस्वरूप व्यापार सन्तुलन केवल उस स्थिति में अनुकूल होगा जब

$$-\left(\frac{V_x}{V_m}\right) e_{Bm} - e_{Am} > 1 \dots (21)$$

पूर्वोक्त समीकरण में ΔY आय के परिवर्तन को तथा $\Delta X - \Delta M$ शेष व्यापार में हुए परिवर्तन को प्रकट करते हैं जबकि $\frac{1}{MPS+MPM}$ व्यापार गुणक का प्रतीक है। जैसा कि अपेक्षित है, अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यातों में वृद्धि तथा आयातों में कमी होगी जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि होगी यह काफी सीमा तक गुणक के मूल्य पर निर्भर करेगा अर्थात् राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के कारण रोजगार के स्तर में भी वृद्धि होगी। परन्तु विदेशी मुद्रा के अर्थ में वृद्धि या स्वदेशी मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप यह भी सम्भव है कि किस सीमा तक घरेलू मूल्य स्तर में भी वृद्धि हो जाए क्योंकि अनेक आयातित वस्तुओं के द्वारा हम औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, अवमूल्यन के कारण आयात जब महंगे होंगे तो वे औद्योगिक वस्तुएँ महँगी हो जाएँगी। दूसरी ओर यदि खाद्यान्नों का आयात किया जाता है तो आयातित खाद्यान्नों की बड़ी हुई कीमतों के फलस्वरूप मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि करना भी आवश्यक होगा तथा इससे भी उत्पादन लागतों में वृद्धि होगी।

अवमूल्यन के फलस्वरूप उत्पादन लागतों तथा मूल्यों की यह वृद्धि दो बातों पर निर्भर करेगी—

- (1) वस्तुओं के उत्पादन में आयातित वस्तुओं का अनुपात, तथा
- (2) अवमूल्यन करने वाले देश में सरकार की मूल्यों की नियन्त्रित करने की नीति।

यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अवमूल्यन के पश्चात् यदि सरकार अत्यन्त कठोर मूल्य नीति अपनाती है तो इससे आयातित वस्तुओं अर्थात् उन पर आधारित वस्तुओं की काला बाजारी प्रारम्भ हो जाएगी। यदि देश अपनी वस्तुओं के उत्पादन में पर्याप्त आयातित वस्तुओं का उपयोग करता है तो इनके मूल्यों में वृद्धि होने पर निर्यातित वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि हो जाएगी तथा अवमूल्यन का निर्यात-आय पर होने वाले प्रभाव की अनुकूलता कम हो जाएगी। इसके लिए सरकार को सजग एवं प्रभावपूर्ण नीति अपनानी होगी।

जहाँ अवमूल्यन का मूल्य स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है वही साधनों के आवंटन पर इसके प्रभाव काफी अनुकूल होते हैं। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात हेतु वस्तुएँ बनाने वाले तथा आयात प्रतिस्थापन वाले उद्योगों में साधनों का अधिक आवंटन होगा। अवमूल्यन के फलस्वरूप मूल्य वृद्धि अपेक्षाकृत उन्हीं क्षेत्रों में अधिक होती है जहाँ निर्धन श्रेणी अथवा आयात प्रतिस्थापन हेतु वस्तुओं का उत्पादन होता है। इन उद्योगों में साधनों का अधिक आवंटन होने के साथ ही इन उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धाशील बनाने हेतु इनकी दक्षता में वृद्धि करने का प्रयास किया जाएगा और इसका भी देश की अर्थ-व्यवस्था पर कुल मिलाकर अनुकूल प्रभाव ही पड़ेगा।

आय गुणांक या बैकवाश प्रभाव (Income Multiplier or Backwash Effect) कहते हैं।

घरेलू एवं विदेश की आय में परिवर्तनों के कारण आयातों एवं निर्यातों में होने वाले परिवर्तनों की माप हम सीमान्त आयात प्रवृत्ति (Marginal Propensity to Import) अथवा आयातों की आय लोच से कर सकते हैं। इकाई आय परिवर्तन के परिणामस्वरूप आयात में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को सीमान्त आय प्रवृत्ति कहते हैं। अर्थात् यदि कुल आय को Y से तथा कुल आयात को M से प्रकट करें तो

$$\text{सीमान्त आय प्रवृत्ति (MPM)} = \frac{dM}{dY} \text{ होगा।}$$

इसी प्रकार हम आयातों की आय लोच भी ज्ञात कर सकते हैं जो निम्नानुसार होगी—

$$\text{आयातों की आय लोच } (e_m) = \frac{dM}{dY} \cdot \frac{Y}{M}$$

हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय तथा भुगतान सन्तुलन में इतना अधिक सम्बन्ध होता है कि किसी एक चर में परिवर्तन होने पर दूसरे चर में भी परिवर्तन हो जाता है। एक खुली अर्थ-व्यवस्था में कुल आय उस देश के कुल उपभोग (C), कुल निवेश (I) के साथ साथ कुल निर्यात तथा आयात के अन्तर पर भी निर्भर करती है जिसको निम्नानुसार प्रकट किया जा सकता है—

$$Y = C + I + (X - M) \quad \dots(1)$$

समीकरण (1) में $(X - M)$ का मान भुगतान सन्तुलन के बालू खाते को प्रकट करता है। जब निर्यात एवं आयात का अन्तर घनात्मक होता है अर्थात् $(X - M) > 0$ होता है तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय आय की वृद्धि में सहायक होता है इसके विपरीत जब यह अन्तर ऋणात्मक होता है अर्थात् $(X - M) < 0$ होता है तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय आय में कमी करता है तथा जब $X - M = 0$ होता है तब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का राष्ट्रीय आय पर प्रभाव उदासीन रहता है अर्थात् कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

समीकरण (1) में से कुल आयात (M) का मान शून्य माना जाए तो समीकरण होगी—

$$Y = C_d + I_d + X_d \quad \dots(2)$$

यहाँ पर d अन्तर्राष्ट्रीय के घरेलू साधनों को इंगित करता है। हम यह भी जानते हैं कि कुल राष्ट्रीय आय अपने विभिन्न मौद्रिक प्रयोगों के योग के बराबर भी होती है अर्थात् घरेलू वस्तुओं एवं सेवाओं पर किया गया व्यय/आयातों पर किया गया व्यय एवं अग्रयुक्त आय (वचन) के योग के बराबर होती है अर्थात्

$$Y = C_d + M + S \quad \dots(3)$$

समीकरण (2) तथा (3) के अनुसार

$$C_d + I_d + X_d = C_d + M + S$$

$$\text{अथवा } I_d + X_d = M + S$$

$$\text{अथवा } X_d - M = S - I_d \quad \dots (4)$$

उपरोक्त समीकरण (4) से स्पष्ट होता है कि चालू खाते का मुग्तान मन्तुलन $(X-M)$, घरेलू बचत एवं घरेलू विनियोग के अन्तर $(S-I_d)$ के तुल्य होता है। इन चार चरों में से किसी एक में भी होने वाला परिवर्तन, कुल राष्ट्रीय आय के परिवर्तन को प्रभावित कर देता है।

अब हम बैकवास प्रभाव देखने हेतु निम्न मान्यता लेते हैं—

$$Y_a = f(Y_b)$$

$$\text{तथा } Y_b = f(Y_a)$$

यहाँ Y_a = देश A की कुल राष्ट्रीय आय है

तथा Y_b = देश B की कुल राष्ट्रीय आय है।

उपरोक्त फलनों से स्पष्ट होता है कि देश A की राष्ट्रीय आय देश B की आय पर एवं देश B की राष्ट्रीय आय देश A की आय पर निर्भर करती है। अतः किसी देश की विदेशी व्यापार नीति में कोई भी परिवर्तन करते समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि इस प्रकार के परिवर्तन का दूसरे राष्ट्र की आय पर क्या प्रभाव पड़ता है।

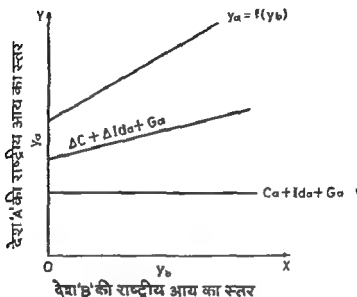
उदाहरण के लिए, यदि विकसित देश विकासशील देशों को अपने निर्यात बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें विकासशील देशों में विद्यमान प्रति व्यक्ति आय को भी ध्यान में रखना होगा। यदि विकासशील देशों पर ये निर्यात वस्तुएँ थोप दी जाएँ तो उन देशों की राष्ट्रीय आय के स्तर में होने वाले प्रतिकूल प्रभाव धीरे-धीरे विकसित राष्ट्रों की आय को भी प्रतिकूल प्रभावित करेंगे।

कोई देश जितना बड़ा होता है उसके विदेशी व्यापार भी उतना ही अधिक बैकवास प्रभाव डालते हैं। जैसे कि अमेरिका को विश्व की मौद्रिक आय का एक बड़ा भाग लगभग 40% प्राप्त होता है। यदि अमेरिका की राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है तो अन्य देशों से इसके आयात बढ़ जाएँगे जिससे अन्य देशों की मौद्रिक आय बढ़ जाएगी और इनके अमेरिका से होने वाले आयात भी बढ़ जाएँगे।

यह प्रक्रिया कहाँ बन्द होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिका एवं अन्य देशों में सीमान्त आयात प्रवृत्तियों का मूल्य कितना-कितना है।

अब माना कि कोई दो देश A तथा B हैं जिनकी कुल राष्ट्रीय आय Y_a तथा Y_b है तथा $Y_a = f(Y_b)$ है एवं $Y_b = f(Y_a)$ है अतः यदि Y_b शून्य हो तो Y_a का अनुमान देश A के उपभोग (C_a) विनियोग व्यय (I_a) तथा सरकारी

व्यय (G_A) से लगाया जा सकता है अर्थात् $Y_A = C_A + I_A + G_A$ होगा। यहाँ पर सभी चर स्वतन्त्र हैं जिनका देश B में होने वाले परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।



इस प्रवृत्ति को उपरोक्त चित्र में एक समान्तर रेखा द्वारा प्रकट किया गया है जो कि देश A के उपभोग, विनियोग तथा सरकारी व्यय के योग अर्थात् $C_A + I_A + G_A$ को प्रकट करती है। यह इस बात को व्यक्त करती है कि इस सीमा तक देश A की राष्ट्रीय आय देश B की राष्ट्रीय आय के सभी स्तरों पर स्थिर रहती है।

अब माना कि देश A के निर्यात उसकी आय में वृद्धि करते हैं जिसका आकार देश B की आय-स्तर से स्वतन्त्र नहीं होता। उपरोक्त चित्र में यह मान लिया गया है कि देश B अपनी आय शून्य होते हुए भी देश A से आयात करता है। इसके फलस्वरूप देश A में प्रत्यक्ष रूप से आय में वृद्धि होती है जिसे Y-अक्ष पर Y_0 द्वारा प्रकट किया गया है। इसके साथ-साथ देश A में विदेशी व्यापार गुणक के द्वारा उपभोग में पुनः वृद्धि (ΔC_A) को प्रोत्साहन मिलेगा। जिस तरह देश B की आय में वृद्धि होती है उसी तरह देश A के निर्यातों में भी वृद्धि होती है तथा उनके साथ-साथ सरकारी व्यय में वृद्धि होती है। इस प्रकार इन तीनों तरह से होने वाली कुल वृद्धि देश B की आय के विभिन्न स्तरों पर देश A की आय को व्यक्त करती है जिसे चित्र में $Y_A = f(Y_B)$ से दिखाया गया है। इसी प्रकार का प्रकटीकरण देश B की आय को देश A की आय के फलन के रूप में भी प्रकट किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों को जिसमें दो देशों के आय के परस्पर सम्बन्धों को समझाया गया है उसे निम्न रूप से भी गणितीय सूत्रों से प्रकट किया जा सकता है—

$$K_1 = \frac{\Delta Y}{\Delta X}$$

$$= \frac{1}{MPS_A + MPM_A + MPM_B \left(\frac{MPS_A}{MPS_B} \right)}$$

MPS_A = देश A में सीमान्त वचत प्रवृत्ति है,

MPS_B = देश B में सीमान्त वचत प्रवृत्ति है,

MPM_A = देश A में सीमान्त आयात प्रवृत्ति है, तथा

MPM_B = देश B में सीमान्त आयात प्रवृत्ति है,

देश A में विदेशी व्यापार गुणक अधिक होगा यदि—

- (1) देश A में $MPM_A < MPM_B$ हो,
- (2) देश A में $MPS_A < MPS_B$ हो,
- (3) देश B में $MPM_B > MPS_A$ हो,
- (4) देश B में $MPS_B > MPS_A$ हो ।

इसके विपरीत मूल्य रखने पर देश B के लिए गुणक का आकार बड़ा होगा ।

परन्तु साधारणतया हम एक ही देश के लिए विदेशी व्यापार गुणक का विश्लेषण करते हैं ।



विनिमय दर का नियन्त्रण आज पर्याप्त महत्त्व रखता है। वर्तमान युग को योजना, नियन्त्रण, प्रतिबन्ध और कमी का युग भी कह दिया जाता है। अनेक कारणों से देश की योजनाओं पर दिन-प्रतिदिन घातक नियन्त्रण एवं प्रतिबन्ध बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में विदेशी विनिमय बाजारों पर भी सरकार का नियन्त्रण रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है बल्कि एक स्वाभाविक बात है। प्रायः प्रत्येक देश इसी प्रकार विनिमय नियन्त्रण की नीति अपनाता है। विनिमय दर का इतिहास अधिक पुराना नहीं है। प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान विभिन्न देशों ने यह महसूस किया था कि उन्हें अर्थ-व्यवस्था पर अधिक से अधिक प्रशासकीय नियन्त्रण बढाना चाहिए। इसी काल में जर्मन मार्क (German Mark) की कीमत बहुत घट गई। इसके दुष्परिणामों से बचने के लिए अर्थशास्त्रियों ने विनिमय नियन्त्रण के विज्ञान को जन्म दिया। इसकी सहायता से युद्ध के बाद जर्मन सरकार ने कुछ समय तक जर्मनी की विनिमय दर को स्थिरता प्रदान की। दूसरे कुछ देशों ने भी इस प्रणाली को अपनाया। पॉल एन्ज़िग (Paul Enzig) ने लिखा है कि “विनिमय नियन्त्रण की यह प्रणाली विभिन्न देशों के समाजवादियों तथा फासीवादियों का, कौशे के अन्तर्राष्ट्रीय आवागमन को अपनी राजनैतिक तथा आर्थिक योजनाओं के हित में पूर्ण रूप से नियन्त्रित करने का स्वप्न था।”¹

विनिमय नियन्त्रण के प्रशासन में केन्द्रीय बैंक या सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी अधिकरण द्वारा किए गए उन सभी हस्तक्षेपों को लिया जाता है जो विनिमय दर को प्रभावित करते हैं। प्रो. हैबरलर (G.V. Haberler) के कथानुसार “स्वतन्त्र आर्थिक प्रभावों के अतिरिक्त विदेशी विनिमय बाजार के नियमन में जो प्रशासकीय हस्तक्षेप होता है वह विनिमय नियन्त्रण है।” यदि किसी देश की सरकार यह

1 “The dream of Socialists and Fascists in various countries secure complete control over the International movement of funds in the interest of their Political and Economic Plan”. —Paul, Enzig : Exchange Control, p. 8.

अनुभव करे कि मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित की हुई स्वतन्त्र विनिमय दर देश के हित में है तो वह किसी प्रकार के विनिमय नियन्त्रण को जरूरी नहीं समझेगी किन्तु यदि सरकार ऐसा नहीं समझती है तो वह देश के हित की दृष्टि से विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति में आवश्यक सशोधन करके विनिमय दर को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास कर सकती है। इस दृष्टि से वाल्टर क्राउज (Walter Krause) का यह कथन उल्लेखनीय है कि 'विनिमय नियन्त्रण एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा विदेशी विनिमय की सीमित पूर्ति को एकत्रित करके पुन विनिरित किया जाता है। इसका यह उद्देश्य होता है कि विदेशी मुद्रा की मांग को उसकी उपलब्ध पूर्ति तक ही सीमित रखा जाए। इस प्रकार विनिमय दर को स्थायी बना दिया जाता है। यद्यपि यह दर मुद्रा के अधिमूल्यत स्तर पर ही हो सकती है।'¹ विनिमय नियन्त्रण को प्रो. स्नाइडर ने एक ऐसी पद्धति माना है जिसमें 'स्वतन्त्र बाजार की शक्तियों के ध्यान पर सरकारी विनियमों को रखा जाता है।'²

यदि कोई देश अपनी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभूतियों (Reserves) को खोता जा रहा है और यदि सरकार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं करना चाहती है अथवा अपने आन्तरिक मूल्यों और आर्थिक क्रियाओं को मौद्रिक एवं प्रशुलक नीतियों से अधिमूल्यत नहीं करना चाहती है तो उस अपने अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन को प्रत्यक्ष रूप से विनियमित करना चाहिए। विदेशी विनिमय की मांग को प्रतिबन्धित किया जा सकता है और इसकी पूर्ति पर राशन लगाया जा सकता है। वैसे तो प्रत्यक्ष नियन्त्रण, अवमूल्यन तथा अधिमूल्यन करने वाली मौद्रिक एवं प्रशुलक नीतियाँ आदि सभी में थोड़ा बहुत सरकारी हस्तक्षेप जरूरी होता है। सरकारी हस्तक्षेप के अन्य प्रकारों एवं प्रत्यक्ष नियन्त्रणों के बीच एक मुख्य अन्तर इस प्रकार से सम्बन्धित है। प्रत्यक्ष नियन्त्रण के अधीन एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारी को यह विचार करना चाहिए कि एक प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन लाभदायक है या नहीं और सरकार को इसकी अनुमति देनी चाहिए अथवा नहीं किन्तु अवमूल्यन या अधिमूल्यन में केवल उसकी लाभदायकता की ही देखा जाता है।

विनिमय नियन्त्रण के उद्देश्य (The Objects of Exchange Control)

विनिमय नियन्त्रण सरकार द्वारा इसनिए किया जाता है ताकि विनिमय दर को स्थिर रखा जा सके। सरकार चाहती है कि उसके द्वारा निर्धारित दर पर ही सोल विदेशी मुद्रा खरीदे और बेचे। प्रो. एल्नवर्थ ने माना था कि "विनिमय नियन्त्रण किसी भी देश को प्रतिकूल भुगतान संतुलन के विरुद्ध सुरक्षित रखने वाली

1 Walter Krause • The International Economics, p 80

2 'Exchange control with the system in which Government regulations are substituted for free market forces'

—Delehart, A Snider Introduction to International Economics p 252

प्रणाली है।¹ विनिमय नियन्त्रण द्वारा ऐसी विनिमय दर निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है जो बाजार की स्वतन्त्र शक्तियों के माध्यम से निर्धारित नहीं हो सकती। जब सरकार माँग और पूर्ति की स्वतन्त्र शक्तियों द्वारा निर्धारित विनिमय दर से सन्तुष्ट होती है तो विनिमय नियन्त्रण की कोई जरूरत नहीं रहती किन्तु जब वह स्वतन्त्र रूप से स्थापित विनिमय दर को न चाह कर स्वयं उसको स्थापित करना चाहती है तो नियन्त्रण रखना जरूरी बन जाता है। विनिमय दर पर सरकारी नियन्त्रण के उद्देश्य काउंटर के अनुसार तीन हो सकते हैं—प्रथम, स्थित विनिमय दर की अपेक्षा नवीन विनिमय दर स्थापित करना; दूसरे, कम विनिमय दर स्थापित करना; तीसरे, विनिमय दर की मात्रा को कम या अधिक न करके केवल विनिमय दर में गल्दी-जल्दी होने वाले उच्चावचनों को रोकने का प्रयास करना। इस प्रकार अधिमूल्यन, ध्रुवमूल्यन और उच्चावचनों की रोकथाम के लिए सरकारी नियन्त्रण की नीति को अपनाया जाता है।

विनिमय नियन्त्रण के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारण निम्नलिखित हैं—

1 पूँजी के बहाव को रोकना (To Check Capital Flights)—

विनिमय नियन्त्रण पूँजी के बहाव को रोकने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। जब जर्मनी, अर्जेंटीना और दूसरे कुछ देशों में इसे प्रयुक्त किया गया तो मुख्य रूप से यही उद्देश्य सामने था। विनिमय नियन्त्रण के अधीन सम्बन्धित सत्ताएँ विदेशी-मुद्रा को बेचने से मना कर देती हैं और इस प्रकार पूँजी देश से बाहर नहीं जा पाती। पूँजी के व्यापक बहाव को रोकने के अतिरिक्त आन्तरिक विभिन्न देशों द्वारा विनिमय नियन्त्रण की प्रक्रिया को दिन-प्रतिदिन के पूँजीगत आवागमन को रोकने के लिए भी अपनाया जाता है। इस रूप में विनिमय नियन्त्रण का लक्ष्य यह होता है कि घरेलू बचत को प्रोत्साहन दिया जाए या विदेशों में स्थित पूँजी को वापस खींच लिया जाए। इस प्रकार के नियन्त्रण विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। ये केवल औपचारिकता से लेकर पूर्ण प्रतिबन्ध तक होते हैं। पूँजी को बाहर जाने से रोकने के लिए विनिमय नियन्त्रण की प्रक्रिया दो कारणों से अपनायी जाती है। प्रथम, यदि पूँजीगत बहाव व्यापक स्तर पर हुआ तो इसके परिणामस्वरूप सम्बन्धित देश के सामने भुगतान सन्तुलन की कठिनाइयाँ पैदा हो जाएँगी। इन कठिनाइयों के परिणामों को भुगतने की अपेक्षा एक देश यह सोचता है कि पूँजी के बहाव पर रोक लगाई जाए। दूसरे, कुछ देश विशेषतया पूँजी की दृष्टि से गरीब और अर्द्धविकसित देश व्यापक स्तर के पूँजीगत बहाव पर रोक लगाते हैं। ये देश विनिमय नियन्त्रण के माध्यम से पूँजी को घर पर रखने का प्रयास करते हैं और स्वामियों को इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं देते कि वे घर में ही पूँजी का निवेश करें।

1 "A Method of Safeguarding a country against adverse balance of payment."

—P. T. Ellsworth : The International Economy, p. 347.

2. मुद्रा की स्थिरता (Stability of the Currency)—विनिमय नियन्त्रण के विभिन्न उद्देश्यों में से एक यह भी है कि इसके माध्यम से कोई देश अपनी मुद्रा को एक अधिमूल्य स्तर (Over value level) तक बनाए रख सकता है। यह एक मूल उद्देश्य है और दूसरे उद्देश्य मुख्यतया इस मूल लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करते हैं। विनिमय नियन्त्रण द्वारा विदेशी मुद्रा के उन स्रोतों पर राशान लगा दिया जाता है जो अपेक्षाकृत अभाव की स्थिति में होने हैं। इसके द्वारा कुछ माँगों को पूर्ण छोड़ दिया जाता है और कुल माँग इतनी रखी जानी है कि वे उपलब्ध विदेशी मुद्रा द्वारा पूरी की जा सकें। इस प्रकार विनिमय नियन्त्रण माँगों में कटौती करके अधिमूल्य स्तर (Over value level) करने में भी सफल हो पाता है। जैसे मुगलान सन्तुलन को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं किन्तु विनिमय नियन्त्रण की प्रक्रिया की प्राथमिकता प्रदान की जाती है। जब कभी स्थिर विनिमय दरें इतनी हो जाएँ कि उपलब्ध विदेशी मुद्रा तत्सम्बन्धी माँग को पूरा करने में असमर्थ रहे तो विनिमय नियन्त्रण अपनाया जाता है।

3 घरेलू कार्यक्रमों की सुरक्षा के लिए (To Safe-guard Domestic Programmes)—विनिमय नियन्त्रण द्वारा एक देश अपनी मुद्रा स्थिति व विरोधी घरेलू नीतियों को अपनाए रह सकता है और इसका कोई विपरीत अन्तर्राष्ट्रीय परिणाम नहीं होता। उदाहरण के लिए यदि एक देश सामान्य स्थिति को रोकने के लिए पूर्ण रोजगार प्रदान करने के कार्यक्रम को प्रारम्भ करने वाला है तो इसके कुछ परिणाम हो सकते हैं। जैसे—उस देश की आय और कीमतों का स्तर विदेशों की अपेक्षा बढ़ जाएगा। इसके प्रतिरिक्त आयातों में वृद्धि होगी और निर्यात घट जाएँगे। जब व्यापार का प्रवाह विपरीत दिशा में होता है तो घरेलू प्रसार पर निरन्तराहतनक प्रभाव पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में देश की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभूतियाँ (International Reserves) भी प्रभावित होती हैं। यदि अन्तर्राष्ट्रीय समायोजन की शक्तियों को स्वतन्त्र रूप से संचालित होने दिया जाए तो एक देश के घरेलू प्रसार के लिए किए जाने वाले प्रयास रुक जाएँगे। यदि वह देश विनिमय नियन्त्रण की नीति को अपना ले तो आयातों को तथा दूसरे ऐसे लेन-देनों को नियन्त्रित करने में सफल हो सकता है जो कि उसकी विदेशी मुद्रा की माँग को बढ़ाते हैं। इस सम्बन्ध में विनिमय नियन्त्रण का महत्त्व यह है कि आयातों के कम होने से विदेशी व्यय कम हो जाएगा और देश की आय बढ़ने से रुक जाएगी। इसके द्वारा देश की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभूतियों पर अनुचित दबाव पड़ने से रुक जाते हैं।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि विनिमय नियन्त्रण एक देश की अर्थ-व्यवस्था का कवच होता है जो कि उसे अस्थिर विरोधी कार्यक्रम अपनाने में समर्थ बनाता है तथा किसी प्रकार का जोखिम नहीं भोगे देना। एक सुरक्षित साधन होने के कारण ही विनिमय नियन्त्रण उन देशों के युद्धागार का एक महत्वपूर्ण हथियार रहा है जो राष्ट्रीय नियोजन का उद्देश्य लेकर चल रहे हैं।

4. व्यापार को नियन्त्रित करने के लिए (To Control Trade)—जब एक देश यह अनुभव करता है कि स्थित विनिमय दर पर उसे सभी सम्भव मार्गों की पूर्ति के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं मिल पाएगी तो वह उन्सब्ध पूर्ति को विनिमय नियन्त्रण द्वारा मर्यादित करता है। विभिन्न फर्मों में विदेशी मुद्रा को आवंटित करते समय यदि वस्तुगतता को बनाए रखना है तो इसके लिए कुछ मापदण्ड तथा जागरूक प्रशासन की व्यवस्था परमावश्यक है अन्यथा यह खतरा रहता है कि एक विशेष आयातकर्ता के साथ उसके प्रतियोगियों की तुलना में पक्षपात किया जाएगा और एकाधिकार प्रथवा अद्वैत-एकाधिकार स्थापित किया जाएगा। विभिन्न देशों के बीच विदेशी मुद्रा को आवंटित करते समय विनिमय नियन्त्रण रहने से कुछ देशों से आयात को अन्य देशों से आयात की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसी स्थिति में आयातों के स्त्रोत का निर्णय केवल कीमत या वस्तु के गुण पर नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा की विभिन्न श्रेणियों की सापेक्षिक पूर्ति पर भी निर्भर रहेगा।

विदेशी मुद्रा को आवंटित करने की प्रक्रिया में व्यापार स्वतः ही नियन्त्रित हो जाता है। यह नियन्त्रण आयातकर्ता और निर्यातकर्ता दोनों के व्यापारों को प्रभावित करता है। आयात करने वाले देश में विनिमय नियन्त्रण द्वारा यह छान-बीन की जाती है कि घरेलू उत्पादन की किन दिशाओं को समुप्रेत किया जा सकता है। यदि एक उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्त करने योग्य है तो उसे आयात करने में प्राथमिकता दी जाएगी और यदि दूसरा देश इतना योग्य नहीं है तो उसे प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इस प्रकार विनिमय नियन्त्रण के माध्यम से कुछ उद्योगों को एक प्रकार से सरकारी सहायता प्रदान की जाती है यद्यपि यह सहायता अस्थायी होती है। इस सहायता के परिणामस्वरूप निश्चय ही यह उद्योग सम्पन्न और विकसित बन जाएंगे और घरेलू साधन स्रोत एवं मानव शक्ति इनकी ओर मुड़ने लगेगी। संक्षेप में विनिमय नियन्त्रण घरेलू अर्थ-व्यवस्था को ढालने का एक साधन माना जा सकता है। यह उस समय विशेष रूप से सच है जबकि घरेलू अर्थ-व्यवस्था आयातित माल पर निर्भर रहती है।

5. भुगतान समुतलन सही करने के लिए (To Correct a Disequilibrium in the Balance of Payments)—एक देश के विनिमय नियन्त्रण के प्रयास अन्य देशों को गम्भीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, विनिमय नियन्त्रण का प्रयोग करके एक देश अन्य देशों के साथ अपने व्यापार में भेद-भाव पूर्ण व्यवहार कर सकता है और ऐसा करते हुए वह कुछ मुद्रा वाले देशों को कम उदारतापूर्वक देखे अथवा उन्हें विदेशी विनिमय के लिए पूर्ण रूप से अनुपयुक्त ठहराए। इस प्रकार व्यापारिक भेद-भाव विभिन्न देशों के बीच आर्थिक कड़ी बनाने के लिए अथवा विशेष देशों पर आर्थिक आश्रितता को कम करने के लिए किया जा सकता है। ग्रेट-ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद के वर्षों में विनिमय नियन्त्रण लगाया ताकि अपने आयातों को ढालर क्षेत्र से पौंड क्षेत्रों की ओर मोड़ सके क्योंकि उस समय ढालर क्षेत्र के साथ ब्रिटेन का व्यापार घाटे में चला रहा था और अन्य के साथ वह तुलनात्मक रूप से घाटे की स्थिति में नहीं था।

6 घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए (To Protect Domestic Industries)—विनिमय नियन्त्रण द्वारा एक देश विदेशी मुद्रा का आवंटन उत्पादन देश कर करने में सक्षम होना है। इस प्रकार कुछ आयातों को अन्य की अपेक्षा अधिक प्रोत्साहित किया जा सकता है। जब आयातों को विभिन्नतापूर्ण दृष्टि से देखा जाता है तो त्रिन् वस्तुओं का आयात कम महत्वपूर्ण माना गया है उन पर बड़ी प्रभाव होगा जो प्रशुल्क अथवा नियन्त्रण का होता है। जब विशेष आयातों को बाहर रक्ष दिया जाना है अथवा उनके प्रवेश पर सख्तता के साथ नियन्त्रण रखा जाता है तो हमसे प्रतियोगी घरेलू उत्पादकों की रक्षा होती है।

घरेलू उत्पादकों की रक्षा के लिए कई कारणों से इस प्रकार का नियन्त्रण लगाया जाता है—

(अ) एक तर्क तो यह दिया जा सकता है कि कृषि सम्बन्धित अथवा औद्योगिक शिशु उद्योगों को यदि विकास का अवसर देना है तो उनकी रक्षा की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए विनिमय नियन्त्रण का प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें यह देखना चाहिए कि जिन शिशु उद्योगों को संरक्षण के लिए चुना गया है, वे दीर्घकाल में उत्पादन के प्रयोगों का गतत आवंटन न कर दें।

(ब) आयातों की मात्रा में बढ़ती की कभी-कभी घरेलू उत्पादन और रोजगार की कुल वृद्धि का साधन माना जाता है। नियन्त्रण की नीति का समर्थन करने वाले लोग इस सम्बन्ध में यह अन्तर नहीं कर पाते कि एक विशेष उद्योग एवं सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था पर इसका अलग-अलग क्या प्रभाव होगा। यह हो सकता है कि विनिमय नियन्त्रण का प्रयोग करने से कुछ उद्योगों में उत्पादन और रोजगार बढ़ जाएँ किन्तु सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में इसे निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता। तथ्य यह है कि व्यापार पारस्परिक होता है और जब आयातों में कटौती कर दी जाती है तो निर्यात में भी स्वतः ही कटौती होने लगती है।

कभी-कभी विशेष घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विनिमय नियन्त्रण के स्थान पर बहुविनिमय दर-व्यवस्था को अपनाया जाता है। यहाँ भेदभावपूर्ण व्यवहार केवल यही नहीं होता कि कुछ विदेशी मुद्राओं को स्वीकार किया जाए और कुछ को न किया जाए किन्तु इस प्रक्रिया में दो या अधिक विनिमय मुद्रा दरों की भी विदेशी मुद्रा की खरीद या बिक्री के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कुछ प्रकार के आयातों की अधिक अनुकूल दरों पर विदेशी मुद्रा प्रदान की जाती है। इसी प्रकार कुछ विशेष प्रकार के निर्यातों को दूसरों की अपेक्षा बिक्री की अधिक अनुकूल दरें प्रदान की जा सकती हैं। आयातों पर कम अनुकूल विनिमय दरें अप्रत्यक्ष प्रशुल्क मानी जाएँगी। दो या दो से अधिक बिक्री दरों में अधिक अनुकूल दरों को निर्यात सहायता माना जा सकता है। अर्जेंटीना और चिली जैसे अनेक अर्द्ध-विकसित देशों में 'बहुविनिमय दर' विनिमय नियन्त्रण व्यवस्था की सामान्य विशेषताएँ हैं क्योंकि ये अपने आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना चाहते हैं।

प्रारम्भ में जब विनिमय नियन्त्रण शुरू किया जाता है तो इसका उद्देश्य प्रायः घरेलू वस्तुओं की रक्षा करना नहीं होता। यह उद्देश्य कुछ समय बाद पैदा होता है। एक बार जब विनिमय नियन्त्रण प्रारम्भ हो जाता है तो उसके साथ विभिन्न हित जन्म ले लेते हैं और वे उसे समाप्त होने से रोकने हैं। विनिमय नियन्त्रण की सुरक्षा के कारण जो नए उद्योग जन्म लेते हैं वे उसे जारी रखने पर जोर देंगे। इसके अतिरिक्त पहले से ही स्थापित उद्योग जब नियन्त्रण के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त करने लवेंगे तो वे भी नियन्त्रण को हटाने का प्रयास करेंगे। दोनों स्थितियों में ही एक बार विनिमय नियन्त्रण के कुछ समय तक लागू होने के बाद उसको हटाना मुश्किल हो जाएगा।

7. राजस्व प्राप्त करने के लिए (To Acquire Revenue)—विनिमय नियन्त्रण का एक अन्य उद्देश्य यह भी हो सकता है कि सरकार उसके माध्यम से राजस्व प्राप्त करना चाहे। अर्जेंटीना और बिली जैसे अनेक देश विनिमय नियन्त्रण का प्रयोग किसी उद्योग के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए बिली ने खरीददारी के लिए 12 विनिमय दरों को अपनाया है। सरकार द्वारा इस प्रकार जो राजस्व प्राप्त किया जाता है उसे देश के आर्थिक विकास के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है।

8. विनिमय दरों को स्थिर बनाने के लिए (To Stabilise the Exchange Rates)—दिन-प्रतिदिन की घटनाओं एवं सट्टेबाजीपूर्ण लेन-देन के कारण विनिमय दरों में गम्भीर उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। ये विषय व्यापार के प्रसार के मार्ग की बहुत बड़ी बाधा है। कुछ देश अपनी विनिमय दरों को एक निर्धारित स्तर पर बनाए रखने के लिए विनिमय नियन्त्रण लागू करते हैं।

9. आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए (To Import Essential Goods)—जिस देश में विदेशी मुद्रा की कमी है वह प्रत्येक वस्तु का आयात नहीं कर सकता। उसे अपने सीमित साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करना होगा और इसके लिए नियन्त्रण की नीति अपनाना आवश्यक है। आरामदायक और श्रृंगार की वस्तुओं के आयात को रोक कर आवश्यक वस्तुओं के आयात में अपने साधनों को कोई देश विनिमय नियन्त्रण की नीति अपना कर ही लगा सकता है। अधिकांश विकासशील देश विनिमय नियन्त्रण की नीति अपनाकर अपने सीमित साधनों का प्रयोग पूंजीगत माल, तकनीकी ज्ञान तथा आवश्यक कच्चे माल की खरीद में कर रहे हैं।

10. राष्ट्रीय प्रतिभूतियों की कीमत कम करने के लिए (To Lower the Prices of National Securities)—कुछ राज्य विनिमय नियन्त्रण का प्रयोग विदेशों में स्थिर राष्ट्रीय प्रतिभूतियों को खरीदने पर रोक लगाने के लिए करते हैं। ऐसा करके वे विदेशियों को इन प्रतिभूतियों की कीमत कम करने के लिए दबा सकते हैं।

11 विदेशी ऋणों का भुगतान रोकने के लिए (To Prevent the Payment of Foreign Debts)—कभी कभी विनिमय नियन्त्रण की नीति का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है ताकि एक देश अपने राष्ट्रियों को विदेशी ऋणों का भुगतान करने से रोक सके। इस उपलब्ध विदेशी विनिमय का प्रयोग वह माल और सेवाओं का आयात करने के लिए कर सकता है।

12 बर्जंदारों से भुगतान प्राप्त करने के लिए (To Obtain Payment from Debtor)—ऋणदाता राज्य अपने बर्जंदारों का प्रभावित करने के लिए विनिमय नियन्त्रण का प्रयोग कर सकता है ताकि वे अपने कर्ज का भुगतान कर सकें। इस प्रकार प्राप्त मुद्रा का प्रयोग वह सेवाओं तथा माल की खरीददारी के लिए कर सकता है।

13 सरकारी ऋणों को चुकाने के लिए (To Pay Governmental Debts)—विदेशों से सरकार द्वारा जो ऋण लिया जाता है उसका भुगतान करने के लिए भी विनिमय नियन्त्रण की नीति अपनाई जाती है। विदेशी ऋणों का भुगतान न किया जाना एक देश की सरकार के लिए अत्यन्त गम्भीर विषय है। एक बार यदि सरकार समय पर विदेशी ऋण न चुका पाए तो भविष्य के लिए उसकी साक्ष बली जानी है। इसके प्रतिरिक्त वह देश दुनिया की नजरों में गिर जाना है। अतः सरकार आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए विनिमय नियन्त्रण लगा देती है।

14 आर्थिक नियोजन के लिए (For Economic Planning)—आयात निर्यातों की मात्रा तथा कीमतों में होने वाले अस्थायित उतार-चढ़ाव घरेलू नियोजन को खतरे में डाल देते हैं। ये उतार चढ़ाव किसी भी देश के नियन्त्रण से परे हैं। विनिमय नियन्त्रण की नीति द्वारा अस्थायी प्रकृति की बाहरी घटनाओं के प्रभावों पर रोक लगाई जा सकती है।

15 व्यापारिक सौदेबाजी—विनिमय नियन्त्रण की नीति को अपनाकर एक राज्य भेदभाव पूर्ण व्यवहार कर सकता है। वह उन देशों को विनिमय रियायतें देगा जो उस देने के लिए तैयार हैं और उनको नहीं जो उसे नहीं दे रहे। इन प्रकार वह प्रभावपूर्ण सौदेबाजी करने की स्थिति में आ जाता है।

विनिमय नियन्त्रण के तरीके (Methods of Exchange Control)

विनिमय नियन्त्रण के तरीकों को मोटे रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष।

अप्रत्यक्ष तरीके (Indirect Methods)

(1) विदेशी व्यापार नियन्त्रण—इस तरीके में सरकार द्वारा आयात और निर्यात पर कुछ कर लगा दिए जाते हैं। आयात कर का उद्देश्य यद्यपि आयातित वस्तुओं की मात्रा को कम करना होना है फिर भी यह विनिमय नियन्त्रण के रूप में

प्रतिफलित होता है। आयात कर लग जाने के कारण आयातित वस्तुओं के भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा के बदले देशी मुद्रा कम देनी पड़ेगी। यह नीति उस समय असफल हो जाती है जब दूसरे देश भी इसका अनुसरण करने लगते हैं।

(2) व्याज की दरों में परिवर्तन—जब एक देश व्याज की दरों में परिवर्तन कर देता है तो विनिमय दर प्रभावित होती है। व्याज की दर अधिक होने पर विदेशी पूँजी आकर्षित होने लगती है ताकि वह अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। इसके प्रतिरिक्त देशवासी भी अपनी सम्पत्ति को स्वदेश में ही रखना चाहते हैं। फलतः देश में मुद्रा की माँग बढ़ जाती है और विनिमय दर ऊँची होने लगती है।

विनिमय नियन्त्रण की उपयुक्त रीतियाँ विनिमय नियन्त्रण के उद्देश्य को लेकर नहीं चलती बरन् इनका मूल सक्षय देश की आन्तरिक स्थिति, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं पूँजी के आवागमन की परिस्थितियों को प्रभावित करना होता है। विनिमय की दर पर पड़ने वाला इनका प्रभाव प्रासंगिक होता है। यही कारण है कि इनको विनिमय नियन्त्रण की परोक्ष रीतियाँ कहा जाता है। इनका प्रभाव सीमित होता है। आयात अथवा निर्यात को ये केवल एक सीमित मात्रा में ही प्रभावित करती हैं।

प्रत्यक्ष तरीके (Direct Methods)

विनिमय नियन्त्रण के कुछ प्रत्यक्ष तरीके भी हैं जो प्रायः संकटकाल में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में राज्य के हस्तक्षेप का सर्वाधिक प्रतिशयवादी रूप राज्य द्वारा किया गया व्यापार है। सरकार द्वारा निर्यात और आयात में व्यक्तिगत उद्यमों का स्थान स्वतः से लिया जाता है। सरकारी अभिकरण घरेलू व्यापारियों के उत्पादनों को देशी मुद्रा का भुगतान करके स्वयं खरीद लेते हैं। वे उन्हें विदेशों में विदेशी मुद्रा के बदले बेचते हैं। इसी प्रकार ये सरकारी अभिकरण विदेशों से माल खरीदकर अपने देश में बेचते हैं।

इस प्रकार के हस्तक्षेप तथा स्वयं आयात-निर्यात के कार्यों को सम्पन्न करने की अपेक्षा सरकार उसकी मात्रा नियंत्रित करने का काम भी अपने हाथ में ले सकती है। इस कार्य को राज्य प्रत्यक्ष नियमन द्वारा करता है।

प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा जितने नियन्त्रण रखे जाते हैं उनको ऐसे गैर-सरकारी व्यक्तियों एवं फर्मों पर रखा जाता है जो विदेशी विनिमय के व्यय और प्राप्तियों का कार्य करते हैं। विदेशी विनिमय प्राप्त करने वाले लोग उसे सरकार को इसके अधिकृत अभिकरणों को बेच देते हैं। सरकार द्वारा व्यय योग्य विदेशी मुद्रा की मात्रा निर्धारित की जाती है। इसके अनिश्चित सरकार मात्रा या मूल्य सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाकर विदेशी विनिमय के प्रयोग को निर्दिष्ट करती है। प्रत्यक्ष तरीकों में कुछ महत्वपूर्ण निम्न प्रकार हैं—

(1) हस्तक्षेप करना (Intervention)—हस्तक्षेप करने की नीति द्वारा विनिमय की दर को प्रायः ऊँची अथवा नीची रखने का प्रयास किया जाता है।

प्रायः यह नीति विनिमय दर को ऊँचा रखने के काम आती है। जब इस नीति का उद्देश्य मुद्रा के मूल्य को ऊँचा रखना होता है तो यह ऊँचा टाँगने (Pegging up) की नीति कहलाती है।

पहले प्रकार के अन्तर्गत सरकार विनिमय दर को एक उच्च स्तर पर निश्चित कर देती है जबकि दूसरे में विनिमय दर नीचे स्तर पर निर्धारित करनी है। विदेशी विनिमय को ऊँचे स्तर पर बनाए रखने में सरकार तभी सफल हो सकती है जबकि उसकी विदेशी मुद्रा का कोष पर्याप्त सम्पन्न हो। विनिमय दर को ऊँचा टाँगना अधिक कठिनाईपूर्ण होता है क्योंकि इसके लिए विदेशी मुद्रा की पूर्ण बढ़ानी होती है। कई बार विदेशी मुद्रा की पूर्ति विदेशों से कर्जा लेकर की जाती है किन्तु यह तरीका ऋण की मात्रा एवं समय की दृष्टि से अनेक सीमाएँ रखता है। इसके अतिरिक्त किसी अनुत्पादक उद्देश्य के लिए ऋण लेना उपयुक्त भी नहीं होता। स्पष्ट है कि एक सरकार विनिमय दर को केवल उतना ही ऊँचा टाँग सकती है जितने उसके पास विदेशी मुद्रा कोष है।

विनिमय दर को नीचे घटकाने की सीमाएँ इतनी सकीर्ण नहीं होती क्योंकि इसके लिए विदेशी मुद्रा का नहीं बल्कि देशी मुद्रा का कोष पर्याप्त होना चाहिए। यह काम अपेक्षाकृत सरल होता है। यद्यपि सीमाएँ इसमें भी हैं क्योंकि देशी-मुद्रा की जनता पर कर लगाकर जनता से ऋण लेकर या नए नोट छापकर बढ़ाया जा सकता है। ये तीनों तरीके असंशोधित नहीं हैं। यह सच है कि विनिमय दर को नीचे घटकाने की नीति उसे ऊँचा घटकाने की अपेक्षा कम कठिनाईपूर्ण होती है किन्तु यह खर्चीली अधिक होती है। अतः इसे स्थायी रूप से नहीं अपनाया जा सकता। यह नीति आर्थिक परिणामों की दृष्टि से भयंकर और अपने आप में खर्चीली होती है। इसे अपनाने समय पर्याप्त सज्जता रखनी होती है।

(2) विनिमय प्रतिबन्ध (Exchange Restrictions) — जब एक सरकार अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों के आकारों और रचना को स्वतन्त्र बाजार में निर्धारित होने देने के स्थान पर उसमें स्वयं हस्तक्षेप करने का निर्णय लेती है तो उसे उन प्रश्नों का जवाब बूँडना होता है जिनको स्वतन्त्र बाजार द्वारा स्वयमेव तय किया जाता रहा या अर्थात् सरकार को यह तय करना होगा कि कौन-सा माल और सेवाएँ आयात की जानी चाहिए? प्रत्येक आयात पर कितना खर्च किया जाए? पूँजी का निर्यात किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाए? इन सबका लेन-देन करने की अनुमति किसे दी जाए? पूँजी का प्रसार किन देशों को किया जाए? आदि-आदि।

कुछ देशों में इन प्रश्नों के समाधानार्थ विदेशी विनिमय का बजट बनाया जाता है। यह बजट प्रत्येक छ माह या बारह महीनों के बाद बनाया जाता है। अपने सरल प्रारंभ में विनिमय प्रतिबन्ध की नीति वह है जिसमें एक देश अपनी मुद्रा की पूर्ति विदेशी विनिमय बाजार में कम कर देता है। जो सरकार विनिमय नीति अपनाती है तो वह सारे व्यापार को स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधियों द्वारा नियन्त्रण में रखती है। इसके अतिरिक्त जब कोई व्यक्ति देशी मुद्रा के बदले विदेशी मुद्रा

प्राप्त करने का प्रयत्न करता है तो उसे सरकार की आज्ञा लेनी होती है। प्रतिवन्ध की यह नीति सबसे पहले 1931 में आस्ट्रिया-जर्मनी ने लागू की थी। जर्मनी को इस नीति का जनक कहा जाता है।

प्रतिवन्ध दो प्रकार के हो सकते हैं—मात्रागत और लागत सम्बन्धी। मात्रागत प्रतिवन्धों द्वारा विदेशों में खर्च की जाने वाली या वहाँ से प्राप्त की जाने वाली मुद्रा की मात्रा पर संस्थात्मक सीमाएँ लगाई जाती हैं। दूसरी ओर, लागत प्रतिवन्धों पर विभिन्न लेन-देनों के लिए प्रयुक्त विदेशी विनिमय की अलग-अलग कीमतें बमूल की जाती हैं।

मात्रागत प्रतिवन्धों में सरकार यह निश्चित कर देती है कि किन उद्देश्यों के लिए कितने विदेशी विनिमय का प्रयोग किया जाएगा ? इसे ज्ञात करने के लिए 'व्यक्तिगत लेन-देनों पर नियन्त्रण' रखा जाता है। आयात नियंत्रण, आयात लाइसेंस या विनिमय लाइसेंस के रूप में हो सकता है। एक नियंत्रण द्वारा आयात किए जाने वाले उत्पादन की कुल मात्रा की सीमा निर्धारित की जाती है। इसके अनेक रूप होते हैं।

विनिमय प्रतिवन्ध की नीति के कई रूप हैं। इनमें से अवरोध खाते (Blocked Accounts) और बहुविनिमय दर (Multiple Exchange Rate) प्रमुख हैं। अवरोध खाते की नीति में विदेशी मुद्रा की निकासी पर प्रतिवन्ध लगा दिया जाता है। केन्द्रीय बैंक में जमा की गई रकम को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित नहीं किया जाता, उसको अवरोध कर दिया जाता है। इससे विदेशी अणुदाताओं को पर्याप्त कठिनाई का अनुभव होता है क्योंकि वे अपनी मुद्रा का प्रयोग और वहाँ नहीं कर सकती और मजबूर होकर सम्बन्धित देश से ही उन्हें माल खरीदना होता है। खाते की इस प्रकार अवरोध करने वाला देश पर्याप्त लाभ में रहता है। जब हिटलर के शासकों से तग आकर यहूदियों ने जर्मनी को छोड़ा तो वहाँ उनकी करोड़ों की सम्पत्ति रह गई। जर्मन सरकार ने उस समस्त सम्पत्ति को अवरोध खाते में लिख लिया। यहूदी उसे इंग्लैंड में प्राप्त नहीं कर सकते थे। अवरोध की नीति काला बाजारी के प्रचुर खोलती है। मुद्रा को विदेशों में जाने से रोक दिया जाता है अतः इससे विनिमय की दर में होने वाले उच्चावचन स्वतः ही रुक जाते हैं।

(3) बहुविनिमय दरें (Multiple Exchange Rates)—विनिमय प्रतिवन्धों का तीसरा रूप बहु-विनिमय दरें हैं। इस प्रणाली के जन्म का श्रेय भी जर्मनी को ही दिया जाता है। स्टाईंडर के कथनानुसार बहुविनिमय दर का अर्थ विभिन्न प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देनों की विभिन्न प्रकार की विनिमय दरों का प्रयोग करना है। इस प्रणिया द्वारा आन्तरिक भूतन्त्र एवं आपके समायोजनों में परिवर्तन किए बिना ही आयातों को नियन्त्रित किया जाता है और निर्यातों को प्रोत्साहन दिया जाता है। बहु विनिमय के तरीकों को सरल रूप में निम्नलिखित विनिमय बाजार में ही प्रयुक्त किया जा सकता है। आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर अलग-अलग विनिमय दर निर्धारित करने आयातों की भूतन्त्र

और निर्यातों को अधिकतम किया जाता है ताकि अधिक से अधिक विदेशी विनिमय कमाया जा सके ।

जिस देश में बहु विनिमय दरों को अपनाया जाता है वहाँ लाइसेंस प्रणाली मायागत प्रतिबंधों के लगाने की आवश्यकता नहीं रहती । इस प्रणाली का दोष यह है कि इसके कारण विनिमय दरों का रूप अत्यन्त अटिल बन जाता है । इसके अनिर्दिष्ट जब विनिमय दरों प्रणाली प्रत्यक्ष विनिमय दर पर आयात व निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को सदैव बदलत रखा जाता है तो देश में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । इस प्रणाली के अन्तर्गत देश और विदेश के साधनों का प्रयोग अनाधिक रूप से किया जाता है और इसलिए देश के नियोजित विकास में पर्याप्त बाधा पहुँचती है । अनेक वस्तुएँ विदेशों से आयातित की जाती हैं और इसलिए देश आत्मनिर्भर नहीं रह पाता । जिन विभिन्न देशों में इस प्रणाली को अपनाया गया उनको बहुत हानि उठानी पड़ी है । वहाँ कृषि उत्पादन का विकास अवरुद्ध हो गया है ।

(4) विनिमय निष्ठा समझौते (Exchange Clearing Agreement) —

यह अन्तराष्ट्रीय लन-देन की अधिक सरल एवं विस्तृत पद्धति मानी जाती है । इसके अनुसार प्रत्येक देश एक समझौता करता है कि वह अपने केन्द्रीय बैंक में एक खाता खोलेंगे और इस खाते के माध्यम से वह देश के सारे आयातों एवं निर्यातों का मुगतान करेगा । यह प्रणाली विदेशी विनिमय की परवाह किए बिना ही अन्तराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करती है । इस व्यवस्था में विदेशी मुद्रा का महत्व समाप्त हो जाता है । इसे 1930 के आर्थिक संकट में अधिक अपनाया गया था । उस समय अनेक प्रतिबंध लगाने के बाद भी मुगतान सन्तुलन में विपत्ति थी और यह विपत्ति इतनी अधिक थी कि इसे रोकने के लिए किए गए सारे प्रयास प्रभावहीन सिद्ध हो रहे थे । कई देशों ने इस स्थिति से तंग आकर अपने आपको दिवालिया घोषित कर दिया । तत्कालीन परिस्थितियों में विदेशों से ऋण लेने की सम्भावनाएँ भी समाप्त प्रायः हो चुकी थी । इन सब कारणों से प्रभावित होकर जर्मनी ने इस प्रणाली का आविष्कार किया ।

विनिमय निष्ठा समझौते द्वारा लाल-क्रीताशाही की मात्रा पर्याप्त कम हो जाती है क्योंकि इनके बाद आयात लाइसेंस जारी करना और आयात या निर्यात के मूल्यों का परीक्षण करना आवश्यक नहीं रह जाता ।

इस प्रणाली के कुछ दोष भी हैं । इसमें एक समृद्ध देश कमजोर देश की कमजोरी का फायदा उठाते हुए उभरा प्रोत्साहन कर सकता है । इसमें आयात केवल उसी देश से किया जा सकेगा जिससे निर्यात किया जा रहा है । ऐसी स्थिति में सम्भव है कि एक देश को अनावश्यक वस्तुएँ भी खरीदनी पड़ें । इस प्रकार से किए गए समझौतों का जब पूर्ण रूप से पालन किया जाना है तो विदेशी बाजारों की आवश्यकता नहीं रह जाती ।

(5) स्वर्ण नीति (Gold Policy)—सरकार सोने की विप्री और सरीद पर प्रतिबन्ध लगाकर तथा उनके नियमन द्वारा विनिमय को नियन्त्रित कर सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 1933 में विनिमय नियन्त्रण की दृष्टि से स्वर्ण त्रय-कार्यक्रम की कार्यान्वित किया। इस प्रकार के उपायों को अपनाते का स्वर्ण बिन्दुओं पर प्रभाव होता है और इस तरह विनिमय दरें भी प्रभावित होती हैं।
कुछ अन्य तरीके (Some other Methods)

उपरोक्त प्रणालियों के अतिरिक्त विनिमय नियन्त्रण के लिए कुछ अन्य प्रणालियाँ भी प्रयुक्त की जाती हैं। पाल एन्जिंग ने विनिमय नियन्त्रण की 4। विभिन्न रीतियों का वर्णन किया है उपर्युक्त प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रीतियों के अतिरिक्त जो अन्य रीतियाँ इस दृष्टि से महत्व रखती हैं वे निम्नलिखित हैं—

(1) भुगतान समझौते (Payments Agreements)—भुगतान समझौते के अन्तर्गत साधारण विनिमय के तरीकों को ही काम में लिया जाता है। इनमें एक विनिमय नियन्त्रित देश से स्वतन्त्र विनिमय वाले देश को जोड़ा जाता है। ये भुगतान समझौते दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के समझौते ऋण के भुगतान में सहायता करते हैं जबकि दूसरे व्यापार के विकास के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं।

(2) पयास्थिति समझौते (Stand-still Agreements)—यह प्रणाली छाते अवरुद्ध करने की प्रणाली की विकल्प है। इसके अनुसार दो देशों के बीच सम्पत्ति के आवागमन पर रोक लगा दी जाती है। ऋणों के भुगतान को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है और इस प्रकार कर्जदार देश को इतना समय दिया जाता है कि वह अपनी वार्षिक स्थिति को सुदृढ़ बना ले। इस प्रकार यह प्रणाली पारस्परिक सहयोग एवं पूँजी के आवागमन पर रोक लगाकर विनिमय दर को नियन्त्रित करने का प्रयास करती है।

(3) निजी मुआवजा समझौते (Private Compensation Agreement)—ये समझौते वस्तुओं के आदान-प्रदान की भाँति होते हैं। इस प्रणाली के अन्तर्गत एक देश दूसरे देश को उतनी ही मात्रा एवं मूल्य की वस्तुएँ निर्यात करता है जितना वह बदले में सम्बन्धित देश से आयात करता है। इस प्रकार आयातों का भुगतान निर्यातों द्वारा स्वयमेव ही कर दिया जाता है और किसी प्रकार का भुगतान करना शेष नहीं रह जाता। इस व्यवस्था के अन्तर्गत एक निर्यातकर्ता देश को आयातकर्ता और आयातकर्ता देश को निर्यातकर्ता भी होना चाहिए। इस प्रकार विनिमय दर के बीच सम्य बनार रहता जाता है।

(4) अव्यवस्थित भेदक दरें (Disorderly Crossed Rates)—विनिमय नियन्त्रण केवल वहाँ लागू किया जाता है जहाँ द्विपक्षीय व्यापार हो रहा है। इसके अतिरिक्त कभी कभी विनिमय दरों के मध्य एक व्यवस्थापूर्ण सम्बन्ध के स्थान पर अव्यवस्थित दरें भी निर्धारित हो जाती हैं। पहले जब विभिन्न देशों की मुद्राएँ परिवर्तनशील थीं तो उनकी पारस्परिक विनिमय दरें प्रायः स्थायी होती थीं। उस समय विनिमय दरों में परिवर्तन की प्रवृत्ति को विनिमय का लाभ प्राप्त करने का

क्रियाओं द्वारा प्रभावशील होने से रोक दिया जाता था किन्तु अब विनिमय नियन्त्रण एवं अपरिवर्तनीयता के कारण लाभ प्राप्त करने से सम्बन्धित क्रियाएँ प्रायः असम्भव बन गई हैं। आज मुद्रा की दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और अनेक प्रतिद्वन्द्व लगाकर उसे बनाए रखा जाता है। ऐसी स्थिति में जब तक विभिन्न विपरीत विनिमय दरों को हम व्यवस्थित एवं स्थायी रूप प्रदान न करें तब तक वे अव्यवस्थित रहती हैं। अव्यवस्थित दरों में देश की मुद्रा का मूल्य व्यापार शक्तों की अनुकूलता और प्रतिकूलता के साथ घटता-बढ़ता रहता है।

विनिमय नियन्त्रण की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता

(The Advantage and Disadvantage of Exchange Control)

विनिमय नियन्त्रण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से कितना उपयोगी है और इसका महत्त्व क्या है इस प्रश्न के सम्बन्ध में अर्थशास्त्री बहुत समय से विवाद करते रहे हैं। अमेरिकी दृष्टिकोण के अनुसार विनिमय नियन्त्रण की नीति व्यापार के मार्ग को अवरोध करती है। इसलिए ऐसे नियन्त्रणों को जितनी जल्दी हो सके हटा लेना चाहिए। दूसरी ओर ग्रेट ब्रिटन जैसे देशों की मान्यता है कि इस नीति ने अनेक मूल्यवान् सेवाएँ प्रदान की हैं और इसलिए जब कभी इनको हटाया जाए तो पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। दोनों पक्ष अपने समर्थन में अनेक तर्क प्रस्तुत करते हैं।

उपयोगिता

(1) विनिमय नियन्त्रण द्वारा अर्थ-व्यवस्था को बाहरी अशान्ति से बचाए रखा जाता है। यह व्यवस्था चालू खाते के असन्तुलन को बिना कीमत या आय का अवमूल्यन किए या बिना विनिमय मन्दी का सहारा लिए ही सुधार सकती है। विनिमय नियन्त्रण के माध्यम से प्रसारवादी मौद्रिक एवं प्रशुल्क नीतियाँ मुगलान् सन्तुलन पर विचार किए बिना ही संचालित की जा सकती हैं।

(2) विनिमय नियन्त्रण का एक लाभ यह है कि यह स्वचालित अथवा समायोजन से स्वतन्त्र बाजार की प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। नियन्त्रण करने वाली सत्ताएँ यह चयन कर सकती हैं कि किस विशेष आयात को कम करना है और किन विदेशी मुद्राओं की सबसे अधिक बचत करनी है? इस प्रकार यह निर्णय लिया जा सकता है कि सामाजिक दृष्टि से उपयोगी अल्प वस्तुओं के अधिक आयात को बनाए रखने के लिए आरामदायक चीजों के आयातों को हटाया जाए। दूसरी ओर स्वतन्त्र बाजार में आरामदायक वस्तुओं का आयात बहुत कम प्रभावित होता है।

(3) विनिमय नियन्त्रण द्वारा एक सर्वाधिक, निश्चित और प्रभावशील प्रक्रिया प्रदान की जाती है ताकि पूँजी के आदान प्रदान के असन्तुलन को कम किया जा सके।

विनिमय नियन्त्रण के समर्थकों का कहना है कि स्वतन्त्र बाजार प्रणाली के सभी परिणाम उचित नहीं होते। इन विचारकों का मत है कि विनिमय नियन्त्रण द्वारा अर्थ-व्यवस्था के बाहरी उद्वेगों को चाहे पूरी तरह मिटाया न जा सके किन्तु

उनकी विभिन्न समस्याओं का निदान भी प्रकार किया जा सकता है। विनिमय नियन्त्रण द्वारा उस पूँजी के आवागमन पर नियन्त्रण रखा जाता है जो भ्रमणशील एवं विपत्ताग्रो को बढ़ाने वाली होती है।

अनुपयोगिता (हानियाँ)

विनिमय नियन्त्रण के उक्त लाभों के अतिरिक्त उसकी कुछ हानियाँ भी हैं। सामान्य रूप से विनिमय नियन्त्रण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकारी विनिमयों को स्वतन्त्र बाजार की शक्तियों के स्थान पर रख दिया जाता है। इस व्यवस्था से यह मानकर चला जाता है कि प्रत्यक्ष नियन्त्रण अधिक प्रभावशाली कार्य करेगा। इसमें प्रदीक्षनीय बातें कम होंगी और मूल आय के परिवर्तन या विनिमय दर की विभिन्नताओं के कारण गलत प्रभाव नहीं पड़ेंगे।

विनिमय नियन्त्रण के प्रति सबसे गम्भीर आर्थिक आपत्ति यह की जाती है कि इसके द्वारा अल्प सख्या में स्थित उत्पादन के साधनों के निर्धारण में कार्य-क्षमता नहीं रह पाएगी। सैद्धान्तिक रूप से नियन्त्रण पूँजी की गति को गलत स्थितियों को रोकने के लिए किए जाते हैं किन्तु व्यवहार में इन्होंने उत्पादन और व्यापार के रूप में प्रायः प्रत्येक बार उत्पादन के निम्नो को ठोड़ा है। स्वतन्त्र बाजार की व्यवस्थाओं में एक देश उस माल और सेवा को खरीदता है जिनकी उत्पादन लागत देश की अपेक्षा विदेशों में कम आती है। इस दृष्टि से उत्पादन के साधनों का अधिक से अधिक निर्धारण करके विश्व की वास्तविक आयदनी को बढ़ा दिया जाता है।

एक स्वतन्त्र विनिमय बाजार आन्तरिक और बाह्य लागतों तथा मूल्यों को जोड़ने वाली कड़ी है। यदि एक कड़ी टूट जाए तो लागत-कीमत की तुलना का आधार और साधनों के निर्धारण का कुशल मन्त्र भूट हो जाएगा। अधिकांश देशों में विनिमय नियन्त्रण का इतिहास यह प्रदर्शित करता है कि ऐसी व्यवस्थाओं में यह कड़ी प्रायः टूट गई है। एक स्वतन्त्र बाजार में व्यापार की गई वस्तुओं का मूल्य सभी देशों के अन्तर्गत एक जैसा रहेगा, उनके बीच केवल यातायात की लागत का अन्तर होगा। विनिमय नियन्त्रण की स्थिति से ऐसा नहीं होता। जब आयात लाइसेंस जारी करके प्रतिवन्ध लगा दिए जाते हैं तो कीमतों को समान करने के सभी प्रयास असफल हो जाते हैं।

विनिमय नियन्त्रण की योजना में विनिमय की जो कृत्रिम दर एक देश में निर्धारित की जाती है उसकी अपेक्षा विदेशों में प्रायः सभी वस्तुएँ सस्ती होती हैं। देश का निर्यात ऊँची कीमत पर होने के कारण प्रतिवन्धित हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि जिन साधनों को निर्यात करने वाली वस्तुओं के अधिक उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता था वे अब उन वस्तुओं के उत्पादन की ओर लगाई जाती हैं जो विदेशों में अधिक कुशलतापूर्वक उत्पादित की जा सकती थीं। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में थम विभाजन का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। इस व्यवस्था के अन्तर्गत किसी देश में किए जाने वाले आयात का निर्णय इस आधार पर

नहीं किया जाता कि वहाँ माल सस्ता मिलेगा वरन् इस आधार पर किया जाएगा कि वहाँ से माज मिन भी सकेगा या नहीं। इसके परिणामस्वरूप व्यापार न केवल कम कुशल रह जाता है वरन् इसका आकार भी कम हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोपीय देश के बीच का व्यापार बहुत कुछ द्विपक्षीय व्यापार एवं मुगनान समझौते के माध्यम से हुआ जिनकी सस्या दो सौ से भी अधिक थी। इन पर अनेक व्यापक एवं कठोर विनिमय नियन्त्रण लगे हुए थे। इन्हीं के कारण मुख्य रूप से यूरोपीय ग्रंथ व्यवस्था न आत्म निर्भर बन सकी और न ही अपना विकास कर सकी।

यद्यपि विनिमय नियन्त्रण की नीति का विरोध किया जाता है किन्तु यह विरोध तथा की गई समस्त आलोचनाएँ उस समय महत्वहीन प्रतीत होनी हैं जब हमारे सामने यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि क्या इनके स्थान पर स्वतन्त्र बाजार की नीति की अपनाया जाए? आज प्रायः अधिकांश लोग इस बात में सहमत हैं कि यदि किसी देश के मुगनान सन्तुलन की बिपमताओं को दूर करना है तो इसके लिए कुछ उपाय अवश्य अपनाए जाने चाहिए। अमल में विनिमय को स्थायित्व प्रदान करने के लिए विनिमय नियन्त्रण की सेवाएँ पर्याप्त महत्वपूर्ण होती हैं।

विनिमय नियन्त्रण का व्यावहारिक रूप (An applied form of Exchange Control)

विनिमय नियन्त्रण से सम्बन्धित मूल सिद्धान्तों, रूपों तथा पक्ष और बिपक्ष में दिए जाने वाले तर्कों का अध्ययन करने के बाद यह उपयुक्त है कि किसी देश विशेष में इसके व्यावहारिक अनुभव का अध्ययन किया जाए ताकि सम्बन्धित सिद्धान्तों को समझा जा सके। अपने अध्ययन के लिए हम ग्रेट ब्रिटेन की चुनते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में विनिमय नियन्त्रण की व्यवस्था की ओर दो कारणों से विशेष ध्यान गया है। पहला कारण यह है कि इस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग (Pound Sterling) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त में एक मुख्य स्थान रखती है। ग्रेट-ब्रिटेन की मुद्रा होने के अलावा यह दूसरे अनेक देशों की मुद्राओं का भी सहारा है। ग्रेट ब्रिटेन तथा उसकी मुद्रा से सम्बन्धित दूसरे देशों को मिलाकर पाँच क्षेत्र कदा जाता है। इन देशों में विश्व की जनसंख्या का लगभग एक तिहाई भाग रहता है। दूसरे, स्टर्लिंग में किए जाने वाले व्यापार और वित्त की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है। यह विश्व के कुल व्यापार और वित्त का प्राचा भाग है। जब स्टर्लिंग जैसी किसी मुद्रा के सम्बन्ध में विनिमय नियन्त्रण लागू किया जाता है तो इस व्यवस्था का कुछ ज्ञान अन्तर्राष्ट्रीय प्रायिक गतिविधियों को समझने के लिए परमावश्यक है।

ग्रेट ब्रिटेन तथा स्टर्लिंग क्षेत्र के अन्य देशों में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारम्भ में ही विनिमय नियन्त्रण लागू कर दिया गया था। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि ग्रेट ब्रिटेन और राष्ट्रमण्डल के देशों पर युद्धकालीन परिस्थितियों का प्रभाव न पड़े अथवा कम से कम पड़े। मूल रूप से ग्रेट ब्रिटेन ने विनिमय नियन्त्रण को इसलिए अपनाया ताकि वह अपने स्वर्ण और डॉलर के अपेक्षाकृत अल्प कोष को सुरक्षित बनाए रख सके या अपने कोष का अधिकतम प्रयोग कर सके। युद्ध से पूर्व स्टर्लिंग

क्षेत्र की जो मुख्य विशेषताएँ थी वे युद्ध के दौरान भी बचावत बनी रहीं। केवल दो विकास हुए—प्रथम, यह कि स्टर्लिंग क्षेत्र के सभी देशों ने विनिमय नियन्त्रण लागू कर दिया और दूसरे, सभी सदस्य देश अपनी गैर-स्टर्लिंग क्षेत्र की मुद्रा और स्वर्ण को लन्दन में रखने को राजी हो गए। इस काल में भारत ने अपनी आवश्यकताओं से अधिक डॉलर कमाया। उसने इन डॉलरों को पौण्ड के बदले ग्रेट-ब्रिटेन को दे दिया। इस प्रक्रिया से ग्रेट-ब्रिटेन ने ब्रिटेन डॉलर कमाए थे उनसे अधिक उसे मिल गए किन्तु प्रतिरिक्त डॉलर प्राप्त करने में उसे भारत को स्टर्लिंग प्रदान करने पड़े। ग्रेट-ब्रिटेन को इस व्यवस्था में यह लाभ हुआ कि वह अब गैर-स्टर्लिंग क्षेत्र से अधिक मात्रा में आयात कर सकता था।

सम्पूर्ण स्टर्लिंग क्षेत्र में विनिमय नियन्त्रण को सामान्य बनाने और लन्दन में डॉलर एवं अन्य गैर-स्टर्लिंग क्षेत्रीय मुद्राओं को रखने का परिणाम यह हुआ कि एक व्यापक नियन्त्रण-विहीन क्षेत्र व्यापार के लिए खुल गया। किन्तु स्टर्लिंग क्षेत्र के बाहर वाले देशों के साथ विशेष प्रतिबन्ध लगाए गए। युद्ध के बाद भी स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों में विनिमय नियन्त्रण की व्यवस्था बनी रही।

विनिमय नियन्त्रण का संज्ञासूचक

ग्रेट-ब्रिटेन में विनिमय नियन्त्रण 1939 में प्रारम्भ किया गया। इसके बाद के वर्षों में अनेक परिवर्तन व्यापक रूप से किए गए, किन्तु इसकी मूल बातें अपरिवर्तनीय रही। 1947 के विनिमय नियन्त्रण अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार थे—

1. क्षेत्र (Coverage)—यह प्रतिबन्ध स्टर्लिंग क्षेत्र के अन्य देशों के साथ किए जाने वाले लेन-देन पर लागू नहीं होगा। ये केवल उन्हीं के साथ किए जाने वाले विनिमय पर लागू होंगे जो कि स्टर्लिंग क्षेत्र से बाहर हैं।

2. विनिमय दर (Exchange Rate)—यह व्यवस्था इकहरी दर व्यवस्था (Single Rate System) है जिसमें समस्त लेन-देनों के लिए एक दर निर्धारित कर दी गई है।

3. प्रशासन (Administration)—विनिमय नियन्त्रण का प्रशासन राजकोष (Treasury) की ओर से बैंक ऑफ इंग्लैंड (Bank of England) द्वारा किया जाता है। दिन-प्रतिदिन के अधिकांश कार्य कॉमिशियल बैंकों द्वारा किए जाते हैं। ये सभी बैंक इन कार्यों को सम्पन्न करने का अधिकार रखते हैं।

4. अनुज्ञप्ति (Licencing)—विनिमय नियन्त्रण के अधीन जब व्यक्तिगत लेखों पर आयात किया जाता है तो उसके लिए आयात अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है किन्तु सरकारी लेखों पर किए जाने वाले किसी आयात पर अनुज्ञप्ति जरूरी नहीं होती। निर्यात अनुज्ञप्ति भी होती है किन्तु वे विनिमय नियन्त्रण से सम्बन्ध नहीं रखती। सभी प्रकार की अनुज्ञप्ति व्यापार मण्डल (Board of Trade) में सम्बन्ध रखती है।

5. विनिमय प्राप्ति (Exchange Receipts)—किसी भी विशेष मुद्रा में

हीने वाली समस्त विनिमय प्राप्तियाँ एक अधिकार प्राप्त बैंक को देव दी जानी चाहिए। ये बैंक गैर-स्टलिंग क्षेत्रों से प्राप्त मुद्रा के बदले पौण्ड प्राप्त कर लेंगे।

6. विनिमय भुगतान (Exchange Payments)—ब्रिटिश विनिमय नियन्त्रण की व्यवस्था वह तरीका है जिसमें वापसी को प्रभावित किया जाता है। बैंकों के माध्यम से किए जाने वाले सभी हस्तान्तरणों को कुछ प्रमुख शीपों में वर्गीकृत किया जाता है और बैंक उनको स्थित विनिमय सम्बन्धी विनिमयों द्वारा संचालित करती हैं। ये प्रमुख शीपें हैं—

- (1) निवासी लेखे (Resident Accounts)
- (2) गैर-निवासी लेखे (Non-resident Accounts)

इनमें बाद वाले शीपों का तीन मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। ये हैं—

- (1) अमेरिकी लेखे (American Accounts)
- (2) परिवर्तनीय लेखे (Transferable Accounts)
- (3) द्विपक्षीय लेखे (Bilateral Accounts)

7. व्यावसायिक वस्तुओं के आयात (Merchandise Imports)—स्टलिंग क्षेत्र के दूसरे भागों से किए जाने वाले आयातों का भुगतान स्वतन्त्रतापूर्वक स्टलिंग में या स्टलिंग क्षेत्र की किसी भी अन्य मुद्रा में किया जा सकता है। स्टलिंग क्षेत्र के बाहर से किए जाने वाले आयातों का भुगतान आयात अनुज्ञप्ति व्यवस्था के माध्यम से स्वीकृति का विषय है।

8. अदर्शनीय (Invisibles)—अदर्शनीय व्यापारिक मदों का भुगतान करने के लिए एक विनिमय अनुज्ञप्ति देना आवश्यक है। इस प्रकार की अनुज्ञप्तियाँ बिना किसी भेदभाव के दी जाती हैं।

9. पूँजीगत स्थानान्तरण (Capital Transfer)—स्टलिंग क्षेत्र के बाहर वाले देशों के लिए किए जाने वाले पूँजी के सभी स्थानान्तरण स्वीकृति की आवश्यकता रखते हैं। स्वीकृति के बाद ही इस प्रकार के स्थानान्तरण किए जा सकेंगे।

10. लक्ष्य (Overall Objective)—उपरोक्त विनिमयों का मुख्य उद्देश्य स्वर्ण और डॉलर की रक्षा करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ऐसे प्रयास किए गए हैं कि व्यापार डॉलर क्षेत्र से दूसरी ओर मुड़ जाए तथा उन देशों की ओर प्रवृत्त हो जाए जो स्टलिंग क्षेत्र में आते हैं या जिनके बीच स्टलिंग सामान्य रूप से परिवर्तनीय है। प्रो क्रॉउ (Prof Krause) का कहना है कि “ब्रिटेन में विनिमय नियन्त्रण का यही मुख्य उद्देश्य था।”

विनिमय नियन्त्रण बनाम प्रशुल्क और नियन्त्रण (Exchange Control Vs Tariffs and Quotas)

विनिमय नियन्त्रण की भाँति प्रशुल्क और नियन्त्रण भी प्रतिबन्ध के तरीके हैं। उल्लेखनीय है कि भुगतान सन्तुलन की कुछ मदों पर विनिमय नियन्त्रण दूसरे

प्रतिबन्धों की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक रूप से लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सैलानियों का व्यय (Tourist Expenditures) इस पर केवल तभी कर लगाया जा सकता है जब विदेशों में व्यय की गई मात्रा ज्ञात हो। यह तब हो सकता है जबकि कठोर विनिमय नियन्त्रण लगाए जाएं और विदेशों में व्यय किए धन की स्वीकृति नियन्त्रणकारी सत्ता से ग्रहण की जाए।

प्रतिबन्ध के दूसरे तरीकों की अपेक्षा विनिमय नियन्त्रण विशेषतापूर्ण है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं—

1. लोचनीयता (Flexibility)—विनिमय नियन्त्रण का प्रशासन घाम रूप से कार्यपालिका द्वारा किया जाता है इसलिए यह प्रशुल्कों की अपेक्षा अधिक लोचनीय होता है जिनमें व्यवस्थापिका की स्वीकृति आवश्यक होती है। वस्तुतः हुई परिस्थितियों के अनुसार इसका शीघ्र समायोजन किया जा सकता है।

2. भेदभाव का उच्चतर साधन (Superior Instrument of Discrimination)—भेदभाव की नीति को अपनाने के लिए प्रशुल्कों की अपेक्षा विनिमय नियन्त्रण अधिक श्रेष्ठ है। प्रशुल्कों द्वारा वस्तुओं के केवल भेदे-भेदे वर्गों के बीच ही भेदभाव किया जा सकता है। विनिमय नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा प्रत्येक लेन-देन की स्वीकृति दी जाती है। अतः वे देशों, वस्तुओं, आयातकसंघों और निर्यातकर्ताओं के बीच अधिक अच्छा भेदभाव बरत सकते हैं। एक विशेष बात यह है कि विनिमय नियन्त्रण के अन्तर्गत यह स्पष्ट रहता है कि भेदभाव किया जा रहा है किन्तु इसके अस्तित्व की सिद्ध करने या न करने के लिए कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं होता।

3. व्यापारिक सौदेबाजी का प्रभावशील साधन (Effective Instrument of Commercial Bargaining)—विनिमय नियन्त्रण प्रशुल्कों की अपेक्षा व्यापारिक सौदेबाजी के लिए अधिक प्रभावशील होता है। इनके द्वारा आयातों को सुरक्षित नियमित किया जा सकता है। विनिमय नियन्त्रण के समझौते गुप्त रहे जा सकते हैं। प्रशुल्कों में व्यवस्थापिका की स्वीकृति आवश्यक होने के कारण उन्हें गुप्त नहीं रखा जा सकता।

4. व्यापक क्षेत्र (Wider Scope)—विनिमय नियन्त्रणों का क्षेत्र नियतांश अथवा प्रशुल्कों की अपेक्षा पर्याप्त व्यापक होता है। इसमें सेवाओं, पर्यटकों के व्यय, कूटनीतिक व्यय, पूंजीगत वस्तियों इत्यादि को भी शामिल किया जा सकता है जो प्रशुल्कों एवं नियतांश के विषय नहीं होते।

ट्रिफिन योजना (Triffin Plan)

ट्रिफिन योजना के अनुसार निर्यातकर्ताओं एवं आयातियों से नियन्त्रण योग्य स्रोतों द्वारा कमाई जाने वाली समस्त विदेशी मुद्रा विनिमय की सरकारी दर पर केन्द्रीय बैंक में जमा की जानी चाहिए। महत्वहीन तथा नियन्त्रण से परे स्रोतों से प्राप्त विनिमय को ही स्वतन्त्र विनिमय बाजार में खरीदा और बेचा जा सकता है।

विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाले सभी लेन-देनो को समाज के लिए उनके महत्व के आधार पर दो भागो में विभाजित किया जा सकता है—(1) पूर्ण अनिवार्यताएँ और (2) आरामदेह वस्तुएँ। प्रथम श्रेणी की वस्तुओं के लिए विदेशी मुद्रा निम्नतम दर पर प्रदान की जानी चाहिए ताकि आम जनता को उच्च कीमतों या उच्च जीवन-स्तर की परेशानी न महती पड़े। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद शेष विदेशी मुद्रा को एक या कुछ नीचामी बाजारों में बेचना चाहिए ताकि आरामदेह वस्तुओं के आयात को एवं ऐसी ही दूसरी आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें।

ट्रिफिन योजना को साधारण अनुज्ञप्ति व्यवस्था की प्रथा निम्न कारणों से श्रेष्ठ माना जा सकता है—

(1) इसमें प्रशासनिक स्वेच्छा के स्थान पर कीमन मन्त्र की स्थापना की गई है और इस प्रकार भ्रष्टाचार, पक्षपान, रिश्तेबाजरी एवं व्यापार की घर्षितिकता आदि को कम कर दिया गया है। प्रशासनिक स्वेच्छा का प्रयोग विभिन्न श्रेणियों में आयात की जाने वाली वस्तुओं को विभाजित करने के लिए किया जाता है। इसके सम्बन्ध में निर्णय उच्च स्तर पर लिए जाते हैं जहाँ भ्रष्टाचार के अवसर अधिक महत्वपूर्ण नहीं होते।

(2) यह योजना सरकार को राजस्व प्रदान करती है जिसे समाज के सामान्य कल्याण के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

(3) यह धनवानों की श्रम-शक्ति को घटाएगी जो नीचामी में विदेशी मुद्रा खरीदने हैं। इस प्रकार मुद्रा सकुचन का मार्ग खुल जाता है।

(4) व्यापार और विनिमय नियन्त्रण के पीछे नीकरशाही प्रशासन और घननिहित स्वाधों का समन्वय रहना है। जो व्यापारी नियन्त्रण से पर्याप्त लाभ प्राप्त करते हैं वे उसे जारी रखने में रुचि लेते हैं और प्रशासन को तदनुसार प्रभावित करने के लिए उचित और अनुचित सभी तरीके अपनाते हैं।

अथर्व ट्रिफिन योजना के उपर्युक्त लाभ हैं फिर भी इसमें सन्देह है कि योजना विशेष रूप से अर्द्ध-विकसित देशों के लिए अधिक लाभदायक हो सकेगी। योजना की प्रमुख हानियाँ निम्न प्रकार हैं—

(1) अर्द्ध-विकसित देशों में पंजीगत वस्तुओं, तकनीकी ज्ञान और आवश्यक कच्चे माल की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में ये देश आरामदेह और गर आवश्यक वस्तुएँ नहीं खरीद सकते। विकास के लिए इच्छुक देश अपने व्यय पर पूरा नियन्त्रण रखना है और आवश्यकताओं के बाद बचाए गए एवं ऐसे को भी विकास कार्यों में सफल है। अन्ततः, स्वतंत्र और चीन के विकास का इतिहास यह सिद्ध करता है कि तीव्र आर्थिक विकास के लिए नियन्त्रण किन्ना आवश्यक है। यदि धनवान लोग गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की अवहेलना करके आरामदेह चीजें खरीदने लग जाएँ तो गरीब लोग आर्थिक विकास के लिए आवश्यक कष्ट सहना अस्वीकार कर सकते हैं और ऊँची मजदूरी की माँग कर सकते हैं। प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले देश अपनी अधिकांश विदेशी मुद्रा उन

वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त करते हैं जो निर्यात वर्ग के लोगों के परिश्रम का परिणाम है। ये लोग कभी यह पसन्द नहीं करेंगे कि उनके पसीने की कमाई पर धनवान लोग मोज उड़ाएँ। यदि ये देश आरामदेह और गैर-आवश्यक वस्तुओं का आयात नहीं कर सकते तो नीलामी का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) योजना के कुशल मंचालन के लिए आयातकर्ताओं में पर्याप्त प्रतिযোগिता होनी चाहिए। अधिकांश विकासशील देशों में आयातकर्ताओं की संख्या बहुत कम होती है। वे आपस में मिलकर नीलामी के उद्देश्य को निरर्थक बना सकते हैं, वे उपभोक्ताओं और सरकारी राजस्व के हितों को हानि पहुँचाकर प्रतिशय लाभ कमा सकते हैं।

(3) सरकार योजना का दुरुपयोग करते समय आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से माल की नीलामी की श्रेणी में स्थानान्तरित करके अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति का प्रयास कर सकती है। अर्द्धविकसित देशों में इसकी सम्भावनाएँ अधिक हैं क्योंकि वहाँ सरकारें कमजोर होती हैं और राजस्व एकत्रित करने के ऐसे तरीके तलाश करती हैं जिनका जनता में कम से कम विरोध हो। इसके फलस्वरूप बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का आरामदेह वस्तुओं की खरीदारी में दुरुपयोग होगा।

(4) सभी आयातों को दो प्रथवा कुछ श्रेणियों में विभाजित करना वैज्ञानिक नहीं है। प्रत्येक आयात की श्रेणी में भिन्न प्रकृति और महत्व के विषय होते हैं। यदि श्रेणियों की संख्या बढ़ा दी जाए तो योजना की सरलता समाप्त हो जाएगी।

(5) विदेशी मुद्रा की माँग और पूर्ति के अनुसार नीलामी बाजार में विदेशी विनिमय की दर समय-समय पर बदलती रहेगी और इसलिए कीमत स्तर अस्थिर बन जाएगा। एक बार विदेशी मुद्रा नीलाम हो जाने के बाद आयातकर्ता कोई भी कीमत वसूल कर सकते हैं क्योंकि बाढ़ में कोई कीमत नियन्त्रण नहीं रहता। नीलामी के बाद होने वाले परिवर्तनों के सारे लाभ प्रथवा हानि का दायित्व उन्हीं पर रहता है। इस प्रकार आयातकर्ताओं का जोखिम बढ़ जाता है।

(6) जहाँ तक अष्टाचार का सम्बन्ध है, यह अनुज्ञप्ति प्रणाली का अन्तर्निहित भाग नहीं है। यह सरकारी यन्त्र के दोषों का परिणाम है। इन दोषों को दूर करने की अनेका अनुज्ञप्ति प्रणाली का ही बहिष्कार करना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता।

द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व-युद्ध के मध्यवर्ती काल से ससार के देशों ने यह महसूस किया कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग जरूरी है। इसके अभाव में एक देश अपना समुचित आर्थिक विकास करने में प्रायः असमर्थ रहता है। 1939 में युद्ध छिड़ने से पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त के क्षेत्र में अत्यन्त स्थिति उत्पन्न हो गई थी और इसलिए यह अनुभव किया गया कि विश्व बाजार में आई हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई महत्त्वपूर्ण कार्य किया जाए। इस काल में ससार के देशों ने अपनी आर्थिक अस्थिरता एवं अन्य गम्भीर परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए अनेक सम्मेलन बुलाए। तत्कालीन परिस्थितियों ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्राप्ति तैयार करने में महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाला।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की पृष्ठभूमि

(Back ground of International Monetary Fund)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जन्म जिस पृष्ठभूमि का परिणाम है, उसने इसके प्राप्ति को निश्चिन्त करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। 1930 की आर्थिक मन्दी के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत कुछ कम हो गया था क्योंकि विश्व के विदेशी विनिमय बाजारों में विभिन्न मुद्राओं की माँग और पूर्ति के सम्बन्ध में गम्भीर परिवर्तन हो गए थे। मुद्राओं की माँग पूर्ति की असन्तुलित परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए सरकारों ने इन तीन में से किसी एक को अपनाया—

- (1) जिस देश में पर्याप्त सोने और विदेशी मुद्रा का भण्डार था उसने इन्हीं के रूप में बड़े-बड़े भुगतान किए ताकि स्थायी विनिमय दर को प्राप्त किया जा सके।
 - (2) विनिमय दरों को मन्द एवं लोचहीन बनने दिया जाए, और
 - (3) विनिमय की सख्त और बिनी पर अनेक प्रतिबन्ध लगा दिए गए।
- इन तीनों प्रक्रियाओं को क्रमिक रूप से काम में लिया गया। जब सुरक्षित भण्डार समाप्त होने लगता था तो विनिमय दरों को लोचशील होने दिया जाता था अथवा विनिमय प्रतिबन्ध लगाए जाते थे।

अनुकूल परिस्थितियाँ

(1) जिन देशों में सोने अथवा विदेशी विनिमय के भण्डार अधिक थे, उनकी स्थिति काफी मजबूत थी इसलिए उनकी विदेशी विनिमय की दर में स्थायित्व बना रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस आदि को ऐसे देशों का उदाहरण माना जा सकता है। इन देशों के अतिरिक्त दूसरे देशों में विदेशी विनिमय की दरों का स्थायित्व नहीं रह सका। यही कारण है कि विभिन्न देशों को यह महसूस होने लगा कि मुद्रा के बड़े भण्डार न केवल राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए बल्कि संकटकालीन स्थिति में देश को विदेशों की असाधारण माँगों का सामना करने के लिए तथा विनिमय दरों को स्थायी बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। समय-समय पर इन सुरक्षित भण्डारों की सहायता के लिए विदेशी कर्ज और साख की भी सहायता ली जाती है किन्तु इस सहायता का पहले से अधिक महत्व नहीं रहता। ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्था की आवश्यकता महसूस की गई।

(2) दूसरी परिस्थिति यह थी कि प्रथम विश्व-युद्ध के बाद विभिन्न देशों ने आर्थिक स्थिरता और रोजगार के क्षेत्र में जो नीति अपनाई वह स्वर्णमान (Gold Standard) के अनुकूल नहीं थी। युद्ध के कारण विभिन्न देशों के स्वर्ण कोष कम हो जाने से अपरिवर्तन पत्र मुद्रा को प्रारम्भ किया गया। इसके परिणाम-स्वरूप मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव आने लगे और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर्याप्त प्रसुविधाजनक बन गया। ऐसी स्थिति में विभिन्न देशों द्वारा पारस्परिक समझौतों के माध्यम से मुद्राओं की दरें तय की गईं। उदाहरण के लिए, सितम्बर, 1936 में अमेरिका, फ्रांस और ब्रेट-विल्डेन ने एक दूसरे की सहमति के बिना अपनी विनिमय दरों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया।

(3) आर्थिक अस्थिरता की स्थिति में विभिन्न देशों के बीच गलाकाट प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ हो गई। जब कोई देश मुद्रा का प्रवर्धन करके अपने निर्यात में वृद्धि करने का प्रयास करता था तो दूसरे देश द्वारा उसके उद्योगों को सरक्षण प्रदान करने के लिए आयात कर लगा दिए जाते थे। इसके परिणामस्वरूप भी विनिमय दर पर्याप्त अस्थिर बन गई और सभी देशों का विदेशी व्यापार घटने लगा।

(4) द्वितीय विश्व-युद्ध ने विभिन्न देशों की अर्थ-व्यवस्था को और भी खराब बनाकर स्थिति को बदतर कर दिया।

(5) युद्ध के कारण पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण की जो गम्भीर समस्याएँ उत्पन्न हुईं उनको सुलझाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग आवश्यक था। विदेशी व्यापार के सन्तुलित विकास एवं अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों के सन्तुलित प्रवाह द्वारा ही ये समस्याएँ सुलझाई जा सकती थीं।

1930 की आर्थिक मन्दी से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न देशों ने विदेशी विनिमय की विन्नी और खरीद पर अनेक प्रतिबन्ध लगाए। इनका उद्देश्य विनिमय का स्थायित्व प्राप्त करना एवं राशन व्यवस्था के माध्यम से भूखभूत आयातों के लिए विनिमय प्रदान करना था। विनिमय सम्बन्धी प्रतिबन्धों के परिणामस्वरूप

कुछ देशों के माल के प्रति स्वाभाविक रूप से असमानता स्थापित हो गई। जिनके पास विदेशी मुद्रा की कमी थी उनके विपक्ष में व जिनके पास नहीं थी, उनके पक्ष में नीतियाँ अपनाई गईं। इन प्रतिबन्धों द्वारा घरेलू उद्योगों की रक्षा भी की जा सकती थी तथा राजनीतिक एवं अन्य प्रकार के लक्ष्यों की साधना भी। विनिमय पर लगाए गए प्रतिबन्ध इतने दोषपूर्ण थे कि उनके स्थान पर अन्य प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय उपाय की आवश्यकता महसूस करना स्वाभाविक था, यद्यपि किसी भी अन्य उपाय द्वारा समस्त बुराइयों को दूर करने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी।

1930 के दौरान विभिन्न देशों में यह व्यवहार अपनाया गया कि लेन-देनों के लिए अलग-अलग विनिमय दरें लागू करने की पद्धति अपनायी गई। कुछ मूलभूत आयातों के लिए उपयुक्त दरें और आरामदायक वस्तुओं के लिए अनुपयुक्त रखी गईं। इस प्रक्रिया में भी अनेक बुराइयों के पैदा होने की सम्भावना थी। इनको अपनाने से व्यापार में पर्याप्त अटिलता पैदा हो गई और एक जैसी दर पर आधारित स्वतन्त्र विनिमय व्यवस्था पर लौटना असम्भव बन गया।

1930 के शरवर्ती काल में प्रशुल्को के अनिश्चित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर अनेक नए प्रतिबन्ध और सीमाएँ लगाई गयीं। व्यापार की समस्याएँ विभिन्न आर्थिक समस्याओं का एक रूप बन गयीं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि 1930 के दौरान जब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार घटा और उसमें विभिन्न समस्याएँ आईं तथा उन समस्याओं की सुनभूने के लिए विभिन्न सरकारों ने जो तरीके अपनाए उनके फल-स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय मुग्तान यन्त्र के उपयुक्त कार्य की आवश्यकता स्पष्ट हो गई। मुग्तान सन्तुलन की गलत व्यवस्था के कारण और कुछ मुद्राओं की अपरिवर्तनीयता के कारण भी विश्व उत्पादन और व्यापार कम हुआ। जब मुग्तानों की समस्याओं के फलस्वरूप माल का व्यापार कठिन हो गया तो उमका उत्पादन भी प्रभावश्यक समझा गया। जब कोई एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की इकाई नहीं थी तो मुग्तानों की बहुत व्यवस्था को जहरी समझा जाने लगा। निर्मातकर्त्ताओं एवं व्यव-कर्त्ताओं को आश्वामन दिया जाना जहरी था कि वे बिना अधिक कठिनाई के विभिन्न कोषों को अपनी मुद्रा में परिवर्तित कर सकें। यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में एक व्यापारी को ऐसी मुद्रा प्राप्त होती है जिसे वह अपनी मुद्रा में परिवर्तित नहीं कर सकता तो इससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रति उसकी अभिरुचि कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में एक ऐसे वित्तीय यन्त्र की स्थापना की आवश्यकता समझा गया जो अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सयुक्त कार्यवाही पर आधारित हो।

ब्रेटनवुड्स सम्मेलन

(Brettonwoods Conference)

द्वितीय विश्व-युद्ध से पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त के क्षेत्र में असन्तोद-जनक स्थितियों को देखने के बाद विभिन्न विचारकों ने स्थिति को सुधारने की दृष्टि से सम्भीगतापूर्वक विचारने की आवश्यकता का अनुभव किया। सयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध से पूर्व ही अन्य देशों की सरकारों के साथ मिलकर नवीन अन्तर्राष्ट्रीय स्थापना

उपयुक्त दोनों योजनाओं में अनेक समानताएँ हैं किन्तु कुछ महत्वपूर्ण मामलों में वे भिन्न भी हैं। दोनों का मुख्य लक्ष्य विनिमय दरों को स्थायित्व प्रदान करना था। दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि विनिमय दरों में जो भी परिवर्तन किए जाएँ वे प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय सगठन के बाद ही किए जाने चाहिए। इन योजनाओं के अन्तर्गत व्यक्तिगत देशों को उनकी आन्तरिक वित्तीय एवं प्रभुत्व सम्बन्धी नीति निर्धारित करने की स्वतन्त्रता को मान्यता दी गई।

दोनों योजनाओं के अन्तर्गत सोने के रूप में परिभाषित एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा इकाई की व्यवस्था की गई। कीन्स योजना में इसे बैंकर (Bancor) और ह्वाइट योजना में इसको यूनीटास (Unitas) कहा जाता है। इससे प्रतिरिक्त प्रत्येक सदस्य को उसके आर्थिक महत्त्व के आधार पर नियतांश देने की बात बही गई। प्रस्तावित सगठन के स्रोत क्या हों और सदस्यों को व किस प्रकार प्राप्त हो सकेंगे, इस सम्बन्ध में दोनों योजनाएँ भिन्न-भिन्न थीं। अमेरिकी योजना में एक योगदान के रूप में कोष प्रदान करने की व्यवस्था की गई जिसमें प्रत्येक सदस्य अपने दिए गए नियतांश के आधार पर साधनों का भ्रम प्रदान करेगा। यदि किसी सदस्य के सामने मुश्किलों के सन्तुलन में घाट की सम्भावनी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उसका मुकाबला करने के लिए कुछ शर्तों के अधीन इन धनो का काम में ले सकता था। दूसरी ओर, ब्रिटिश योजना का आधार भिन्न था और इसमें यह कहा गया कि व्यापार करने वाले देश चालू अन्तर्राष्ट्रीय खातों पर अपने कर्जदारों में समायोजन सब की किताबों पर साथ सन्तुलन प्राप्त करेंगे जो नवीन मुद्रा इकाई (Bancor) के रूप में होगा। बैंकर को सभी सदस्य देशों द्वारा स्वीकार किया जाना था और वे उसे आसानी से हस्तान्तरित कर सकते थे। इस दृष्टि से एक कर्जदार देश अपने आयातों के लिए सगठन की पुस्तक में अपने विरुद्ध 'दण्ड' सन्तुलन के द्वारा मुगतान कर सकता था। अपने मौलिक रूप में ब्रिटिश प्रस्ताव ने व्यापारिक देशों द्वारा प्रसारित साख की मात्रा पर कोई सीमा नहीं लगाई। इस प्रस्ताव का सयुक्तराज्य अमेरिका द्वारा विरोध किया गया। उसके सुझाव ग्रेट-ब्रिटेन ने प्रसवीकार कर दिए।

कीन्स योजना (Keynes Plan) के अनुसार जिस साख सन्तुलन का कुछ समय तक काम में नहीं लाया जाता वह अग्रिम घाप ही रह जाँता है। इस प्रकार यदि एक देश अपने चालू खाते में आयातों की अपेक्षा भारी निर्यात करना रहेगा तो उसने पाम साखों का समग्र होना रहेगा किन्तु उसे यह साख एक निश्चित तारीख से पूर्व खर्च कर देनी चाहिए नहीं तो वह इतकी छोटा देगा। इसका कारण यह बताया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय लेखों को सन्तुलित बनाए रखने के लिए समायोजन का भार खर्च देने वाले पर पहले की अपेक्षा ज्यादा डाला जाना चाहिए। सयुक्तराज्य अमेरिका ने कीन्स योजना को अस्वीकार कर दिया।

उपयुक्त दोनों योजनाओं के अन्तर्गत जो प्रमुख भेद थे उनको मिलाने के लिए 1944 में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने बीच कई बैठकों का आयोजन किया गया।

इसके अतिरिक्त लगभग बीस अन्य देशों के प्रतिनिधियों से भी विचार-विमर्श किया गया। इस सम्बन्ध में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने की योजना बनाई गई ताकि एक मौद्रिक संस्था तथा सम्भवतः एक बैंक के बारे में सहमति प्राप्त की जा सके। अमेरिका और ग्रेट-ब्रिटेन ने यह माना कि यदि इस प्रकार के सम्मेलनों को वे सफल बनाना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं सभी प्रमुख मसलों पर समझौता करना होगा। फलतः दोनों देश के प्रतिनिधियों के बीच वार्शिंगटन में अनेक बैठकें हुईं। ब्रिटिश दल का विश्वास था कि प्रस्तावित संस्था के एक सदस्य को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने नियतांश के अनुसार संस्था से धन ले सके। ब्रिटिश दल का नेतृत्व लॉर्ड कीम्स ने किया था। दूसरी ओर संयुक्तराज्य अमेरिका का यह विश्वास था कि संस्था को समस्त सैनदारियों पर नियन्त्रण रखना चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि साधनों का प्रयोग सही उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है अथवा नहीं।

दोनों देशों के बीच अन्य विचारणीय विषयों में एक देश का अपनी ओर से विनिमय दर को बदलने का अधिकार, स्वर्ण में भुगतान योग्य नियतांश की मात्रा, कोप से लिए जाने वाले ऋण का पुनर्भुगतान आदि-आदि थे। ग्रेट ब्रिटेन तथा अन्य देश संयुक्तराज्य अमेरिका में आर्थिक मन्त्री और व्यापक बेरोजगारी से भयभीत थे। उन्होंने यह अनुभव किया कि यदि वे अपनी मुद्रा को स्वर्ण अथवा डालर से जोड़ देंगे तो वे आर्थिक मन्त्री का विरोध करने में असमर्थ बन जाएंगे और इस प्रकार वे अपनी आय को अमेरिकी पतंग की पूँछ से बाँध लेंगे। इसी कारण उन्होंने विनिमय दरों को बदलने के सम्बन्ध में लोचनीय उपबन्धों की इच्छा प्रकट की।

संयुक्तराज्य अमेरिका, ग्रेट-ब्रिटेन और अन्य कुछ प्रमुख देशों के बीच समझौता अप्रैल, 1944 में हुआ। इसको अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के बारे में विशेषज्ञों का संयुक्त वक्तव्य (The Joint Statement by experts on the establishment of an International Monetary Fund) कहा जाता है। इसमें उस योजना की रूपरेखा थी जिसे बाद में ब्रेटनवुड्स (Brettonwoods) में पूरी तरह से क्रियान्वित किया गया। जुलाई, 1944 में आयोजित किए गए एक सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 44 देशों को प्रतिनिधि भेजने हेतु आमन्त्रित किया। यह सम्मेलन संयुक्त वक्तव्य पर आधारित एक योजना पर विचार करने के लिए ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशिर में होने वाला था। इससे पूर्व ही सत्रह देशों के प्रतिनिधि कुछ अनसुलझे प्रश्नों पर विचार करने के लिए अटलांटिक नगर में मिले। ब्रेटनवुड्स सम्मेलन में विभिन्न देशों ने यथासम्भव अधिक नियतांश प्राप्त करने में विशेष रुचि दिखाई क्योंकि नियतांश द्वारा ही ऋण लेने के अधिकारों एवं मन देने की शक्ति का निर्धारण किया जाना था। नियतांश का आकार एक देश के आर्थिक महत्त्व का मापदण्ड बन गया और इसलिए राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न बना दिया गया।

दो सप्ताह तक विभिन्न प्रकार के मतों में समझौते के प्रयास किए जाते रहे और अन्त में सम्मेलन ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समझौते के अनुच्छेद तैयार किए। इन अनुच्छेदों ने कोष का मूल चार्टर तैयार किया। इनके प्रभावशाली होने

से पूर्व व्यवस्थापिका निकायो की औपचारिक स्वीकृति आवश्यक थी। जुलाई, 1945 को अमेरिकी कांग्रेस ने इस कोष में संयुक्तराज्य अमेरिका के सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान कर दी। 27 दिसम्बर, 1945 को तीस देशों द्वारा इन अनुच्छेदों पर हस्ताक्षर कर दिए गए। बाद में अन्य देश भी इसमें सम्मिलित हो गए और इस प्रकार कोष औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। ब्रैटनवुड्स के सम्मेलन में दो अन्तर्राष्ट्रीय मॉडिफ सस्याओं की रचना की गई। प्रथम तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक अथवा विश्व बैंक थी। यंग (Young) के कथनानुसार "अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का विकास भी कोष के साथ-साथ हुआ और इसके समझौते के अनुच्छेदों पर हस्ताक्षर भी उसी समय हो गए।"¹ इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दिसम्बर, 1945 को अस्तित्व में आया।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लक्ष्य (The Objects of I. M. F.)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कई उद्देश्यों को लेकर बना। उसका मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रसार की सन्तुलित प्रगति को समायोजित करना था। साथ ही इसे विनिमय की अस्थायी दरों के कुप्रभावों से बचाना और विदेशी विनिमय के प्रतिबन्धों को खीला करना था। इसके अतिरिक्त यह प्रत्येक देश में वास्तविक आय एवं रोजगार के उच्च-स्तरों की स्थापना के लिए भी प्रयत्नशील था।

समझौते के अनुच्छेद—। में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विभिन्न लक्ष्यों को स्पष्ट किया गया। इसमें मुख्यतः तीन लक्ष्यों को मान्यता प्रदान की गई है।

(1) विनिमय स्थायित्व को प्रोत्साहन देना, सदस्यों के बीच अर्थव्यवस्था विनिमय प्रबन्धों की स्थापना करना और प्रतिस्पर्धापूर्ण विनिमय मन्दी की स्थिति को दूर करना।

(2) सदस्यों के बीच आलू लेन-देन में मुग्तान की बहुपक्षीय प्रणाली की स्थापना में सहायता करना तथा साथ ही विदेशी विनिमय के उन प्रतिबन्धों को समाप्त करना जो विश्व व्यापार की प्रगति को रोकते हैं।

(3) पर्याप्त सुरक्षाओं के अधीन सदस्यों को कोष के साधनों को उपलब्ध कराना और इस प्रकार उनमें विश्वास की भावना जाग्रत करना। इस प्रकार विभिन्न देशों को राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सम्पन्नता के लिए हानि पहुँचाने वाले प्रयासों को अथवा बिना ही उनके मुग्तान सन्तुलनों की अव्यवस्था को सुधारने का अवसर देना।

मुद्रा कोष द्वारा उपर्युक्त लक्ष्यों की पूर्ति के अतिरिक्त मुग्तान सन्तुलन की विषमता को दूर रहने के लिए, असन्तुलन की अवधि व अंश को कम करने के लिए, लाभदायक ऋणों में दीर्घकालीन पूँजी की सहायता प्रदान करने के लिए,

1 'The International Bank was developed along side of the fund and its articles of Agreements were signed at the same time.'

—J. P. Young The International Economy, 1951, p 455

अल्पकालीन मौलिक सहायता प्रदान करने के लिए तथा ऐसे ही अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रयास किए जाते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मूल सिद्धान्त (Basic Principles of I. M. F.)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विभिन्न सिद्धान्तों के आधार पर अपने सदस्यों की प्राप्ति का प्रयास करता है। इन सिद्धान्तों का अध्ययन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं—

(1) कोष के सभी सदस्य-देश अपनी विनिमय दरों को दयात्मक स्थायी रखने का प्रयास किया करते हैं। वे विनिमय दरों के परिवर्तनों को एक संकीर्ण सीमा के अन्तर्गत करते हैं जो उनके द्वारा स्पष्ट कर दी जाती है। वे उस समय तक अपनी दरों में कोई परिवर्तन नहीं करते जब तक कि यह परिवर्तन एक मौलिक असमसुस्यता को सुधारने के लिए आवश्यक न हो।

(2) एक विनिमय दर का किसी भी प्रकार का समायोजन कोष से बिचार विमर्श किए जाने के बाद ही किया जाना चाहिए। छोटे-मोटे परिवर्तनों के अलावा यदि दरों का समायोजन करना है तो वह केवल कोष की सहमति के बाद ही किया जाना चाहिए।

(3) सदस्यों की मुद्राओं के मूल्य सोने के रूप में अभिव्यक्त किए जाते हैं। लेखों को मुलभूत के लिए सदस्यों द्वारा स्वर्ण की स्वीकार किया जाता है।

(4) कोष के पास वित्तीय स्रोत होते हैं जो सदस्यों द्वारा दिए गए योगदान पर आधारित रहते हैं। यह योगदान उनके लिए सौंपे गए नियतों पर आधारित होता है। ये स्रोत कुछ सुरक्षा पूर्ण शर्तों के अन्तर्गत किसी भी सदस्य को प्रदान किए जाते हैं ताकि वह विनिमय की अपनी अस्थायी कमी को पूरा कर सकें।

कोष के स्रोतों को लेने के लिए एक सदस्य अपनी मुद्रा को वांछित विदेशी मुद्रा में बदल लेता है। कोष के स्रोतों का लक्ष्य एक देश की सहायता करना है ताकि वह अपने चालू अन्तर्राष्ट्रीय खातों में अस्थायी घाटे की व्यवस्था का सामना कर सकें और इस प्रकार विदेशी विनिमय के स्वामित्व को बनाए रख सकें। उदाहरण के लिए, यह हो सकता है कि एक देश की फसल खराब हो जाने के कारण उसका कृषि सम्बन्धी निर्यात कम हो जाए। ऐसी स्थिति में उस देश के पास पर्याप्त विदेशी विनिमय के स्रोत नहीं रहेंगे जिनसे वह अपने आयातों का भुगतान कर सके। कोष उस सदस्य देश को विदेशी मुद्रा की कुछ मात्रा खरीदने की अनुमति दे देगा। वह सदस्य-देश अपनी मुद्रा के बदले में डालर, पाँड या फ्रांक आदि बदल सकता है।

कोष के साधनों का उद्देश्य यह नहीं है कि वे विनियम के लिए पूँजी प्रदान करें अथवा अन्य दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए पूँजी दें वरन् वे सदस्यों को इसलिए दिए जाते हैं ताकि चालू लेन-देन में भुगतान करने के लिए सदस्यों की सहायता की जा सके। इन स्रोतों द्वारा भुगतानों के सन्तुलन में चालू या गैर-सरकारी पूँजी के मचों में परिवर्तन की व्यवस्था की जाती है। मुद्रा कोष के स्रोतों में से कर्ज लेने का

एक सदस्य वा अधिहार उसके नियतांश के प्रकार से सम्बन्ध रखता है। असाधारण परिस्थितियों को छोड़ एक सदस्य एक वर्ष के अन्तर्गत अपने नियतांश में 25% से अधिक नहीं ले सकता और न ही कोष में एक सदस्य देश की मुद्रा उसके नियतांश के 200% से अधिक रखी जा सकती है।

कोष से उधार लिए गए धन पर व्याज दिया जाता है। यह व्याज ऋण की मात्रा और भुगतान के समय के अनुसार बढ़ता है। इस प्रकार प्राप्त धन से कोष अपने कार्य संचालन के खर्च का निर्वाह करता है।

(5) कोष का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि विनिमय में लेन देनो पर से प्रतिबन्धों को समाप्त कर, भुगतानों की अपेक्षा ऐसी स्वतन्त्र बहुपक्षीय व्यवस्था कायम करें जहाँ किसी भी मुद्रा को आसानी के साथ दूसरी मुद्रा में बदला जा सके। यही कारण है कि सदस्य देश इस सम्बन्ध में सहमत होने हैं कि वे समझौते की शक्ति के बिना या कोष की स्वीकृति के बिना धालू अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देनो के भुगतानों पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध लागू नहीं करेंगे। युद्ध के बाद संक्रमण काल में उन विनिमय प्रतिबन्धों को बने रहने की अनुमति दी गई जो पहले स्थित थे, किन्तु यह कहा गया कि इनको ज्यों ही मौका मिले त्यों ही समाप्त कर देना चाहिए। पूँजीगत हस्तान्तरणों पर प्रतिबन्धों की स्वीकृति दी गई। यदि कभी एक विदेशी मुद्रा की माँग बहुत अधिक बढ़ जाए और कोष उसकी पूर्ति में अपने आपको असमर्थ पाए तो वह औपचारिक रूप से उस मुद्रा की कमी की घोषणा कर सकता है। ऐसा होने पर सदस्य देश प्रस्थायी रूप से उस कम घोषित मुद्रा में लेन देनो पर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं।

(6) सदस्य देश उस बात पर सहमत थे कि वे कोष में अपनी मुद्रा की मन्दी नहीं आने देंगे। इस प्रकार वे कोष के द्वारा अपनाई गई अपनी मुद्रा के स्वर्ण-मूल्य को बनाए रखने के बारे में सहमत होते हैं। वे आवश्यकता पडने पर प्रतिरिक्त मात्रा की पूर्ति भी कर सकते हैं।

(7) कोष केवल सरकारी एवं उनके अभिकरणों से ही सम्बन्ध रखता है उसका विदेशी विनिमय वाजारों के साथ कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होना।

(8) कोष को 14 कार्यपालिका निर्देशकों द्वारा प्रशासित किया जाता है। ये निर्देशक कोष के मुख्य कार्यालयों में निरन्तर अधिवेशन करते रहते हैं। इनमें से पाँच की नियुक्ति उन देशों द्वारा की जाती है जो सबसे अधिक नियतांशों से युक्त हैं अर्थात् सयुक्तराज्य अमेरिका, ब्रिटिश, चीन, फ्रांस और भारत। शेष का चुनाव अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। गवर्नरों के मण्डल में एक गवर्नर तथा एक उसका विकल्प होता है। इनकी नियुक्ति प्रत्येक सदस्य द्वारा की जाती है। ये वार्षिक बैठक करते हैं।

उपर्युक्त विचार विमर्श के बाद संशेष में यह कहा जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना करके, एक ऐसी सस्था की स्थापना और ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करने का प्रयत्न किया गया जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आकार

बढ़ सके और घरेलू सम्पन्नता तथा पूरा रोजगार प्राप्त किया जा सके। द्वितीय विश्व-युद्ध से पूर्व जो नीति सम्बन्धी विवाद एवं राष्ट्रीय प्रयास अपनाए जाते थे उनके स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग एवं विचार-विमर्श की स्थापना की गई। मुद्रा कोष द्वारा विनिमय स्थायित्व का सामान्य नियम बनाने का प्रयास किया गया और जब असन्तुलन को सुधारने के लिए किए गए अन्य प्रयास देश की सम्पन्नता या व्यापार की स्वतन्त्रता के प्रयास को चुनौती प्रदान करने लगे तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा स्वीकृत एवं समन्वित विनिमय दरों के समायोजनों की स्वीकृति दी गई।

कोष की सदस्यता एवं नियतांश प्रणाली

(The Membership and Quota System of I. M. F.)

कोष का सदस्य बनने के लिए प्रत्येक उस देश को उपयुक्त माना गया है जो कि इसके समझौते-पत्र (Articles of Agreement) को स्वीकार करता है। कोष के सदस्यों को सामान्य सदस्य और मौलिक सदस्य दो भागों में विभाजित किया गया है। जो देश ब्रैटनवुड्स सम्मेलन में उपस्थित थे और जिन्होंने 31 दिसम्बर, 1945 से पहले ही संधि का सदस्य बनना स्वीकार कर लिया था, उन्हें कोष का मौलिक सदस्य माना जाता है। इनके प्रतिरिक्त जो सदस्य बने हैं, उनको सामान्य सदस्य की संज्ञा प्रदान की जाती है। अप्रैल 1977 तक कोष के सदस्यों की कुल संख्या 129 हो गयी। जब कोई सदस्य-देश कोष से अलग होना चाहता है तो वह इसके लिए लिखित रूप में सूचना देता है। कोष को यह अधिकार नहीं है कि वह त्यागपत्र को अस्वीकार कर दे। इसके प्रतिरिक्त जब कभी एक देश कोष के नियमों का उल्लंघन करता है तो स्वयं कोष भी उसको सदस्यता से बर्चिन कर सकता है।

सोवियत रूस इस कोष का सदस्य नहीं है। कोष की समस्त पूंजी उसके सदस्यों के निपतांशों के कुल योग के बराबर होती है। सदस्यों की संख्या ज्यों-ज्यों बढ़ती है त्यो-र्यो कोष की पूंजी भी बढ़ती है। एक व्यवस्था के अनुसार कोष के द्वारा प्रति पाँचवें वर्ष सदस्य देशों के ग्रन्थों के बारे में विचार किया जाएगा और यदि वह आवश्यक समझे तो उनमें पुनर्विचार का प्रस्ताव कर सकता है। इसी प्रावधान के अनुसार कोष ने 1958 की अपनी दिल्ली बैठक में सदस्यों के ग्रन्थों की 50 प्रतिशत की वृद्धि का निर्णय लिया। इस वर्ष कोष की कुल राशि 15 बिलियन डॉलर थी। 1966 में जब पुनः विचार किया गया तो प्रत्येक सदस्य-देश के नियतांश में 25 प्रतिशत की वृद्धि करके कुल मात्रा को 21 बिलियन डॉलर कर दिया गया। प्रत्येक देश को अधिकार है कि वह अपने ग्रन्थों में आवश्यकता के अनुसार कमी या वृद्धि कर ले। एक देश कमी की अपेक्षा वृद्धि करने में ही अधिक रूचि लेता है।

ग्रन्थों अथवा नियतांश कोष की कार्यवाही तथा संगठन की दृष्टि से पर्याप्त महत्व रखते हैं। नियतांशों के आधार पर ही यह निश्चित किया जाता है कि एक

सदस्य देश कोष के साधनों में कितना योगदान करेगा ? इस प्रकार कोष के साधनों की कुल मात्रा का निर्धारण किया जाएगा। यदि कोष के साधनों की मात्रा को बढ़ाना है तो इसके लिए सदस्य देशों के नियतांश में वृद्धि करनी होती है। नियतांशों का एक अन्य दृष्टि से भी महत्त्व है और वह इसलिए है क्योंकि इन्हीं के आधार पर यह तय किया जाता है कि कोई भी सदस्य-देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कितनी रकम कितने समय में निकाल सकेगा ? साथ ही एक सदस्य के मताधिकार का निर्धारण भी सदस्य के नियतांश की मात्रा द्वारा किया जाता है।

नियतांशों का निर्धारण कई आधारों पर किया जाता है। उदाहरण के लिए एक देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल्य, व्यापार का संगठन एवं विभिन्नता, वर्जदाता एवं कर्ज लेने वाले की स्थिति, अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रतिभूतियों का आकार, राष्ट्रीय शाय, विदेशी व्यापार का सापेक्षिक महत्त्व, राजनैतिक स्थिति एवं अन्य ऐसे ही अनेक तत्त्व। विभिन्न सदस्य देशों के नियतांशों का निर्धारण करने के लिए जिस सुन को काम में लिया जाता है उसकी घोषणा कभी भी कोष द्वारा नहीं की गई।

कोष की कुल अग्र्यश राशि कोष के सदस्यों के कुल अग्र्यशों (Quotas) के योग के बराबर है। आरम्भ में कोष के कुल अग्र्यशों की पूँजी राशि केवल 8800 मिलियन अमेरिकन डॉलर थी जिसे कोष के सदस्यों के अग्र्यशों के रूप में विभाजित कर दिया गया था, किन्तु 1973 के प्रथम चरण के लगभग यह राशि बढ़कर 29169 मिलियन SDR हो गई।¹ कोष के सदस्यों के अग्र्यशों की मात्रा प्रत्येक सदस्य देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा उसके राष्ट्रीय आय और जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। यही कारण है कि जहाँ पनामा के अग्र्यश की मात्रा केवल 1/3 मिलियन SDR है वहीं अमेरिका के अग्र्यश की मात्रा 5107 मिलियन SDR है जिसमें अब और भी वृद्धि हो गई है। प्रत्येक सदस्य देश अपने कुल अग्र्यश का 25 प्रतिशत या अपने कुल स्वर्ण डॉलर कोषों का 10 प्रतिशत (जो भी कम हो) स्वर्ण में कोष को देता है। शेष अग्र्यश राशि सदस्य देश की मुद्रा में जमा की जाती है। आरम्भ में कोष के कुल अग्र्यशों की जो पूँजी राशि 8800 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी उसमें 1800 मिलियन डॉलर स्वर्ण के रूप में और शेष 7000 मिलियन डॉलर सदस्य देशों की मुद्राओं के रूप में थी। जो अग्र्यश राशि सदस्य देश की मुद्रा में जमा की जाती है उसे कोष सदस्य देश के केन्द्रीय बैंक के पास अपने नाम से जमा करा देता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रधान कार्यालय उस देश में होता है जो इसमें सबसे अधिक अग्र्यश प्रदान करे। आजकल यह संयुक्त राज्य अमेरिका (वाशिंगटन) में है। इस कोष की शाखाएँ किसी भी सदस्य देश में खोली जा सकती हैं। कोष को अग्र्यशों से प्राप्त सभी स्वर्ण एक ही स्थान पर नहीं रखा जाता। उसका 50 प्रतिशत

1 उल्लेखनीय है कि 20 मार्च 1972 से कोष का सामान्य लेखा SDR के रूप में लिखा जाता है। एक SDR इकाई का मूल्य 0.888671 ग्राम शुद्ध स्वर्ण के बराबर है।

सबसे अधिक अर्थ्यश वाले राष्ट्र अर्थात् अमेरिका में रखा जाता है और शेष 40 प्रतिशत भाग अगचे चार सबसे अधिक अर्थ्यश वाले राष्ट्रों में रखे जाने का प्रावधान है।

मुद्रा कोष का संगठन एवं प्रबन्ध (The Organisation and Management of I.M.F.)

कोष का प्रबन्ध एक गवर्नर मण्डल (Board of Governors), कार्यकारी सचालकों की समिति (Board of Executive Directors), प्रबन्ध संचालक (Managing Directors) एवं अन्य स्टॉफ की सहायता से किया जाता है। गवर्नरों के मण्डल में प्रत्येक सदस्य-देश को घोर से एक गवर्नर होता है। कार्यकारी सचालकों की समिति के 20 संचालकों में से 6 उन देशों के होते हैं जिनका सबसे अधिक नियतांश होता है (वर्तमान में ये सदस्य हैं—अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, जापान और भारत), शेष 14 देशों के प्रतिनिधि निर्वाचित किए जाते हैं। प्रबन्ध संचालक को कोष के दिन-प्रति-दिन के कार्य के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। वह कार्यकारी सचालकों की समिति का अध्यक्ष होता है। प्रत्येक सदस्य देश 250 मत देने का अधिकार रखता है। संचालक मण्डल द्वारा कार्यकारी सचालकों के लिए महत्वपूर्ण शक्तियाँ हस्तान्तरित नहीं की जा सकती; जैसे नए सदस्यों की भर्ती करना, नियतांश का संशोधन करना, सभी सदस्यों की मुद्राओं के मूल्य में परिवर्तन करना, किसी सदस्य को निकालना, आदि-आदि।

कोष में सभी सदस्यों को समान मत देने का अधिकार नहीं है, जैते कि अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में हुआ करता है। कोष में सदस्यों को साधारण मत प्रदान करने का अधिकार होता है। 250 मत प्रदान करने के लिए एक अतिरिक्त प्रत्येक 1 लाख अमेरिकी डॉलर के लिए एक अतिरिक्त मत प्रदान करने का अधिकार और भी मिल जाता है। इस मत प्रणाली के परिणामस्वरूप मुख्यतः दो देशों के हाथ में शक्ति का केन्द्रीकरण हो गया है जो सबसे अधिक नियतांश वाले हैं। ये हैं—ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये देश जिस किसी प्रस्ताव के बारे में सहमत होते हैं उसे आसानी से पास करा सकते हैं क्योंकि कुल मतदान शक्ति के लगभग 40 प्रतिशत पर इनका अधिकार रहता है।

मुद्रा कोष की कार्य प्रणाली (Mode of Operation of I.M.F.)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को स्वयं और सदस्य देशों की मुद्राओं में जो पूंजी प्राप्त होती है उसके द्वारा वह अस्थायी ऋणों के रूप में सदस्यों को मौद्रिक सहायता देकर विदेशी विनिमय दरों में उच्चावचनों को समाप्त कर बहुपक्षीय मुद्रानान पद्धति को प्रोत्साहित करने, बहुदृष्टीय व्यापार प्रणाली को स्थापित करने एवं विश्व व्यापार का सन्तुलित विकास करने का प्रयत्न करता है। मुद्रा कोष की कार्य प्रणाली निम्नानुसार है—

1. समता दरों का निर्धारण—समझौता-पत्र की धारा 4 के प्रनुसार प्रत्येक राष्ट्र को अपनी मुद्रा की इकाई का मूल्य स्वरूप तथा SDR में व्यक्त करना पड़ना है। इस मूल्य को ही समता दर (Par Value) कहा जाता है। इसके आधार पर ही कोष प्रत्येक सदस्य देश की मुद्रा का एक सामान्य आधार स्थापित कर देना है और इसकी न्यूनतम एवं अधिकतम सीमाओं के बीच ही अवमूल्यन तथा अधिमूल्यन की अनुमति दी जाती है।

2. समता दरों में परिवर्तन—विनिमय दरों में स्थायित्व रखने तथा प्रतिस्पर्धात्मक अवमूल्यन को रोकने की दृष्टि से समता दरों अथवा समता मूल्य (Par Values) में लोच की व्यवस्था की गई है। आवश्यकता पड़ने पर समता दर में परिवर्तन किए जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में निम्न सीमाएँ हैं—(क) सदस्य देश अपनी मुद्रा इकाई समता दर में प्रथम 10 प्रतिशत का परिवर्तन कोष को केवल सूचना देकर कर सकते हैं, इसके बाद अपनी मुद्रा इकाई के समता मूल्य में परिवर्तन करने के लिए सदस्य को कोष की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है, (ख) सदस्य देश अपनी मुद्रा इकाई की समता दर में परिवर्तन केवल अपने भुगतान शेष के मूल असन्तुलन (Fundamental Disequilibrium) को समाप्त करने हेतु कर सकता है, (ग) गम्भीर प्रकृति और व्यापक आकार के भुगतान शेष के घाटे को समाप्त करने के लिए कोष किसी सदस्य देश को अपनी मुद्रा इकाई का दम प्रतिशत में अधिक अवमूल्यन करने की अनुमति दे सकता है। यदि कोष को यह विश्वास हो जाए कि किसी सदस्य देश के भुगतान शेष में मूल असन्तुलन विद्यमान है तो वह उस सदस्य की मुद्रा इकाई की समता दर में परिवर्तन को प्रायः नहीं रोकता।

3. मुद्रा कोष से ऋण व्यवस्था—कोष सदस्य देश को उसके भुगतान शेष के अस्थायी घाटे की पूर्ति के लिए मर्यादाबद्ध सकटकालीन ऋण उस देश के केन्द्रीय बैंक के माध्यम से देता है। अर्थात् कोष सदस्य देशों को उनकी देशी मुद्रा के बदल विदेशी मुद्रा का नय-विक्रय करना है किन्तु शर्त यह है कि किसी भी समय काप क पाम उस देश की मुद्रा उसके निर्धारित अम्यश के 200 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए और कोई भी सदस्य देश 12 माह के भीतर अपने अम्यश के 25 प्रतिशत से अधिक विदेशी मुद्रा ऋण नहीं कर सकता। व्यवहार में इन नियम का प्रायः उल्लंघन होता रहा है।

सदस्य देशों को कोष से 4 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं और ऋणों का उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जा सकता है जिनके लिए ऋण स्वीकृत किए गए हैं। आकस्मिक आर्थिक सकट अथवा राजनीतिक सकट के समय सकटकालीन ऋण दिए जाने की व्यवस्था है। उदाहरणार्थ, 1956 में ब्रिटेन को स्वयं तुरन्त सकट के समय ऐसा ही ऋण दिया गया था। 'स्थायित्व ऋण' आर्थिक कठिनाई के समय विनिमय दरों में स्थायित्व के लिए दिए जाते हैं। इजरायल, ब्राजील आदि को इस प्रकृति के ऋण दिए जाते रहे हैं। आर्थिक सकट के समय विनिमय दरों में स्थायित्व बनाए रखने हेतु ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका को भी अनेक अवसरों पर

पर्याप्त मात्रा में विशेष सहायता दी गई है। उदाहरणार्थ, संयुक्त राज्य अमेरिका को 1971 में 1362 मिलियन डॉलर की और ब्रिटेन को 1972 में 584 मिलियन डॉलर की विशेष व्यवस्था दी गई। “मोसमी अथवा सामयिक ऋण अल्पकाल के लिए ‘प्रायः 6 से 12 महीने तक के लिए’ दिए जाते हैं। ये ऋण उन देशों को दिए जाते हैं जिनके सामने मोसमी या सामयिक निर्यातों के कारण भुगतान शेष की कठिनाई आ जाती है। वयूवा, निकारगुवा, एलसाल्वेडोर को इसी प्रकार के ऋण दिए जाते रहे हैं।” चालू भुगतान शेष की असाम्यता को दूर करने के लिए भी ऋण देने की व्यवस्था है। सदस्य देशों को अपनी विकास योजनाओं को लागू करने में भुगतान शेष की असाम्यता से अल्पकाल में कठिनाई को दूर करने के लिए अनेक बार ऐसे ऋण कोष द्वारा दिए गए हैं। भारत, जापान, कनाडा, फ्रांस आदि देशों को ऐसे ऋण समय-समय पर मिलते रहे हैं।

4. ऋणों पर शुल्क—कोष सदस्य देशों को दिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों पर शुल्क वसूल करता है। यह शुल्क ऋण की मात्रा और अवधि की वृद्धि के साथ-साथ बढ़ता जाता है और 0.5 प्रतिशत से लेकर 6 प्रतिशत तक है। शुल्क की दर 5 प्रतिशत तक पहुँच जाने तक कोष सदस्य देश को अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सुभाव देता है। यह शुल्क मुद्रा कोष को स्वर्ण में चुकाया जाता है।

5. कोष सदस्य देशों को तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। कोष का विशेष विषयक कर्मचारी वर्ग सदस्य देशों की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है। कोष सदस्यों की मुद्रा इकाइयों की समता दरों, विदेशी विनिमय नियन्त्रण, अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों, साल मुद्रा एवं आर्थिक नीति एवं केन्द्रीय बैंकिंग नीति तथा विदेशी विनिमय नियन्त्रण, प्रशासन, आर्थिक विकास योजनाओं आदि का समुचित अध्ययन करके सदस्य देशों को अपनी बहुमूल्य सलाह देता है।

सदस्यों के सामान्य दायित्व

(General Responsibilities of Members)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने सदस्यों पर विभिन्न प्रतिबन्ध लगाता है। इन प्रतिबन्धों का पालन करना सभी सदस्यों का सामान्य दायित्व है। कोष के सदस्यों के प्रमुख दायित्व इस प्रकार हैं—

(1) जो राशि कोष से उधार ली जाएगी, उसका प्रयोग उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाएगा जिनके लिए कोष की स्थापना की गई है।

(2) यदि कोई देश अपने चालू अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देनों पर विनिमय प्रतिबन्ध लगाना चाहता है तो इसके लिए उसे कोष की आज्ञा लेनी होगी।

(3) प्रत्येक देश द्वारा स्वर्ण का क्रय और विक्रय उसी दर पर किया जाएगा जो कोष ने निर्धारित की है।

(4) यदि कोई देश अपनी मुद्रा नीति में परिवर्तन करना चाहता है तो इसके लिए उसे कोष से आज्ञा प्राप्त करनी होगी।

(5) एक देश मुद्रा के सम्बन्ध में विभिन्नतापूर्ण नीति अर्थात् बहुपक्षीय मौद्रिक व्यवहार केवल तभी अपना सकता है जबकि या तो समझौते-पत्र में ऐसी व्यवस्था हो अथवा कोष द्वारा मान्यता प्राप्त कर ली गई हो। यदि वे प्रतिबन्ध कोष के अस्तित्व में आने से पहले ही कायम थे तो सम्बन्धित सदस्यों को इन प्रतिबन्धों को हटाने के बारे में कोष से विचार-विमर्श करना होगा। कोष ने बहुविनिमय दरों को सरल बनाने में कुछ प्रगति की है। बहुविनिमय दरों द्वारा प्रशुल्को एवं अन्य व्यापारिक विषयों पर समझौता-वार्ताओं को जटिल बना दिया जाता है।

(6) प्रत्येक देश के द्वारा विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय उसी दर पर किया जाएगा जो कोष द्वारा निर्धारित की गई है।

(7) कोष के सदस्यों का एक यह भी दायित्व है कि वे कोष के आदेशों का पालन करें और उसके द्वारा माँगी गई समस्त सूचना भेजने का प्रयास करें।

मुद्रा कोष के कार्यों की प्रगति और उपलब्धियाँ (Progress and Achievements of I. M. F.)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य विगत 25 से भी अधिक वर्षों में कुल मिलाकर काफी सन्तोषजनक रहा है। कोष की प्रारम्भिक सम्पदा पूँजी 8800 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी जो बढ़कर 1973 तक ही 29,169 मिलियन SDR हो गई। कोष के सदस्यों की संख्या सन् 1945 में केवल 30 थी वह अप्रैल, 1977 तक बढ़कर 129 हो गई है। यह स्थिति कोष की बढ़ती लोकप्रियता की परिचायक है। 1948 से लेकर अप्रैल, 1973 तक बड़ी संख्या में सदस्य देशों ने कोष से दुर्लभ मुद्राओं का खरीदा है। कोष ने इस अवधि में लगभग 216 मिलियन डॉलर राशि की मुद्राओं की बेचा। कोष के सहायता कार्यों में प्रारम्भ में शिथिलता रही और 1947 से 1957 तक के प्रथम दश वर्षों में इसने केवल 2350.5 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की, लेकिन आगे चलकर कोष के सहायता कार्यों में निरन्तर तेजी आती गई और 30 अप्रैल, 1975 को कोष के 13574.20 मिलियन SDR के ऋण शेष बकाया था। कोष ने सदस्य देशों को 1975 के वित्तीय वर्ष में 5102.45 मिलियन SDR तुल्य ऋण देकर भेजे। वर्ष में रिकार्ड ऋण दिया और सदस्य देशों को भुगतान सन्तुलन के संकट से उबारा। कोष के अफ्रीकी विभाग ने अफ्रीका के कम विकसित देशों की समस्याओं के प्रति भारी जागरूकता प्रदर्शित की है। कोष का तकनीकी विद्यापीठ सदस्य देशों के लिए जिन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है वे बड़े उपयोगी सिद्ध हुए हैं। केन्द्रीय बैंकिंग भुगतान शेष, राजकोषीय मामलों आदि पर कोष ने सदस्य देशों के अधिकारियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत उपयोगी प्रशिक्षण प्रदान किया है।

इन उपलब्धियों के बावजूद कोष के कार्य आलोचना रहित नहीं हैं। सदस्य देशों ने कोष की अनुमति के बिना ही अपनी मुद्राओं की समता दरों में परिवर्तन करके कोष के नियमों का उल्लंघन किया है, लेकिन कोष उनके विशुद्ध कोई कड़ी

कार्यवाही नहीं कर सका है। डॉलर आज भी लगभग उतना ही दुर्लभ है जितना कि यह 1949 में पौण्ड-स्टलिंग के अवमूल्यन के समय था, लेकिन कोप अमेरिका को अभी तक इस बात के लिए नहीं मना सका कि वह डॉलर की दुर्लभता को समाप्त करे। डॉलर की यह दुर्लभता कभी भी अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग के हितों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। कोप सदस्यों के मुद्रा इकाइयों की समता दरों को स्थिर रखने में असफल रहा है। यह इसी बात से प्रकट है कि 1948 से लेकर 1973 तक ही लगभग 120 सदस्यों द्वारा अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन किया गया।

सन्तोष की बात यह है कि कोप की लोकप्रियता, इसकी कमियों के बावजूद बढ़ रही है और आशा की जानी चाहिए कि कोप निरन्तर प्रभावशाली बनता जाएगा।

भारत तथा कोप (India and I. M. F.)

भारत कोप का संस्थापक सदस्य है और कोप के कार्यकारी संचालक मण्डल में भारत का एक स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त है। भारत को कोप के भुगतान-शेष के भारतीय घाटे को पूरा करने के लिए समय-समय पर काफी वित्तीय सहायता मिलती रही है। 1948 और 1949 में भारत ने कोप से 100 मिलियन डॉलर का ऋण प्राप्त किया जिसका भुगतान 1956-57 में कर दिया गया। 1957 में भारत ने कोप से पुनः 200 मिलियन डॉलर का ऋण लिया ताकि अपने भुगतान शेष के अस्थायी असन्तुलन को वह ठीक कर सके। जुलाई, 1961 में भारत ने कोप से 250 मिलियन डॉलर का ऋण छः देशों की मुद्राओं में प्राप्त किया। जुलाई, 1962 में भारत ने कोप के साथ 100 मिलियन डॉलर का ऋण प्राप्त करने का समझौता किया। मार्च, 1964 में कोप ने भारत को 200 मिलियन डॉलर की सहायता दी ताकि वह अपने भुगतान शेष के संकट को समाप्त कर सके। 1967 में कोप ने भारत को भुगतान शेष के अस्थायी घाटे की पूर्ति के लिए 90 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया। विशेष ऋण अधिकार योजना के अन्तर्गत विकास कार्यों के लिए जो SDR राशि आवंटित की जाती है उसमें से भारत समय-समय पर काफी राशि का उपयोग करता रहा है। 30 अप्रैल, 1973 को भारत के कुल SDR कोप की राशि 245.26 मिलियन SDR थी और भारत को कोप से कुल 326.22 SDR राशि के शुद्ध संचयी आवंटन प्राप्त हुए थे। 30 अप्रैल, 1973 को भारत की कुल SDR कोप राशि भारत के शुद्ध संचयी आवंटनों की 75.2 प्रतिशत थी। भारत समय-समय पर कोप के विशेषज्ञों द्वारा अपनी आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था का अध्ययन कराकर उपयोगी परामर्श प्राप्त करता रहा है। 1974 और 1975 में मुद्रा कोप से भारत को 7.57 करोड़ रुपये का ऋण मिला था। भारत ने जिन शर्तों पर ऋण समय-समय पर प्राप्त किए उनका वह समुचित अनुपालन करता रहा है और ऋण भुगतान की दृष्टि से भारत की साख काफी बढ़ी हुई है। मुद्रा कोप से भारत ने जो भी ऋण लिए हैं उनका वह भुगतान कर चुका है और इन ऋणों से लगभग मुक्त है।

आजकल अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की चर्चा एक महत्वपूर्ण विषय बन गई है। अन्तर्राष्ट्रीय तरलता के अन्तर्गत प्रायः उन सभी वित्तीय साधनों एवं सुविधाओं को शामिल किया जाता है जो व्यक्तिगत देशों के मुद्रा सम्बन्धी अधिकारियों के लिए मुग्तान रोप की पूर्ति करने के हेतु उपलब्ध रहते हैं। दूसरे प्रकार से इसे यों कहा जा सकता है कि जब खात की अन्य निधियों से सन्तुलित न किया जा सके तो बची हुई रकम का मुग्तान विदेशी मुद्रा में किया जाय। अन्तर्राष्ट्रीय तरलता में जिन मुद्राओं को शामिल किया जाता है, उनका कोष अन्य देशों में भी होना चाहिए। भारतीय रुपया अन्तर्राष्ट्रीय तरलता का आधार केवल तभी बन सकता है जब यह न केवल भारत के पास बरन् विश्व के अन्य देशों के पास भी हो।

तरलता का अर्थ (The Meaning of Liquidity)

तरलता के अर्थ के सम्बन्ध में एच० डब्ल्यू० आर्न्ड (H W Arndt)¹ तथा फ्रिज मैकलप (Fritz Machlup) आदि ने अपने महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए। मैकलप के कथनानुसार “यदि हम तरलता का अर्थ एक व्यक्ति या समूह की स्थिति से लगाएँ (चाहे उसका आकार सम्पूर्ण राष्ट्र से लेकर सम्पूर्ण सगर तक, कितना ही क्यों न हो) तो हमें इसकी व्याख्या तुरन्त मुग्तान करने की क्षमता (Capacity to pay promptly) के रूप में करनी होगी।” इसके अतिरिक्त एक निश्चिन्त समय के लिए आवश्यक कोषों के लिए जमा किए जाने योग्य कोषों के अनुपातों के रूप में इसकी अभिव्यक्ति की जाती है। यहाँ समस्या यह पैदा होती है कि हमारा अर्थ किस कोष से किस चीज के मुग्तान करने की किस क्षमता से है? इनमें से प्रत्येक प्रश्न अनेक उत्तर प्रस्तुत करता है। इस प्रकार यह शब्द अनेकार्थक है। इससे सही अर्थ को जानने में हमारे सामने अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। विचार लो

का मत है कि तरलता के मत की अनिश्चितता ही इस शब्द की लोकप्रियता का कारण है।

तरलता का सही अर्थ जानने के लिए तीन मुख्य प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी है—(1) कोप के सम्भावित स्रोत क्या-क्या हो सकते हैं ? (2) कोप के उपयुक्त प्रयोग क्या-क्या होंगे ? और (3) भुगतान करने का किसी क्षमता से हमारा क्या अर्थ है ? किज मैकलप ने कोप के सम्भावित दस स्रोतों का उल्लेख किया है। इनमें कुछ स्रोत तो व्यापक और अनिश्चित हैं, विशेष रूप से वे जहाँ बिपयगत निर्णय का महत्त्व है; अर्थात् जहाँ गम्भीर हानियों और बुद्धिपूर्ण शर्तों या वस्तुओं की आवश्यक खरीददारी आदि का उल्लेख किया गया है।

किज मैकलप ने 19 ऐसे बिपयों का उल्लेख किया है जिनमें सम्भावित रूप से कोप का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 11 ऐसे सम्भावित बिपयों का उल्लेख किया है जो भुगतान करने की क्षमता रखते हैं।

जब हम यह जानना चाहते हैं कि एक फर्म की तरलता क्या है अर्थात् तुरन्त भुगतान करने की उसकी क्षमता क्या है ? तो इसके लिए पहले यह देखना होता है कि कोप के किन स्रोतों एवं प्रयोगों को ध्यान में रखा जाना चाहिए ? जब हम दो या दो से अधिक फर्मों की कुल तरलता की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे सामने धारणा सम्बन्धी कठिनाइयाँ आती हैं। यह समस्या पैदा होगी कि क्या हमको उस समूह में एक फर्म द्वारा दूसरे फर्मों से खरीदी गई चीजों को सम्मिलित करना चाहिए ? क्या हमको एक फर्म द्वारा भुगतान किए जाने वाले और दूसरी फर्म द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लेखों को सम्मिलित करना चाहिए ? इन प्रश्नों का उत्तर सरल रूप में नहीं दिया जा सकता। समूह के अन्तर्गत एक-दूसरे को भुगतान करने की फर्मों की क्षमता एक दूसरी चीज है और समूह के बाहर फर्मों को भुगतान करना दूसरी चीज है। उनकी सम्मिलित तरलता के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना प्रश्न का पूरा अर्थ समझे बिना अर्थहीन रहेगा।

कई स्थितियों में ऐसा लगता है कि तरलता शब्द का प्रयोग न किया जाए किन्तु ऐसी स्थिति में भ्रम पैदा होने की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं। यदि इसके लिए हम अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह शब्द प्रायः ऐसा नहीं होता जो अपने अर्थ को निश्चित रूप से अभिव्यक्त कर सके। विचारकों का मत है कि पहले शब्द बना लेना और फिर अर्थ ढूँढ़ना एक अर्थहीन चीज है जबकि होना यह चाहिए कि किसी एक निश्चित अर्थ के लिए उपयुक्त शब्द ढूँढ़ा जाए। जब हम उपयुक्त शब्द ढूँढ़ लेते हैं तो इससे मौखिक या लिखित विचार-विमर्श में समय की पर्याप्त बचत हो जाती है, किन्तु इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए हमें शब्द अन्य अर्थों से ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे भ्रम पैदा होने का अदेशा बढ़ जाता है।

तरलता का एक घरेलू क्षेत्र होता है। इसके अतिरिक्त उसका अन्तर्राष्ट्रीय रूप भी होता है। जब निजी केन्द्रीय बैंक अपने कोप में से विदेशी दायित्वों का निर्वाह करने के लिए उत्तरदायी होता है और इस उत्तरदायित्व को वह तुरन्त पूरा

तरलता प्रथम में उधार लेने की सीमा स्वर्ण निधि की मात्रा तक रख दी गयी है जबकि दूसरे की सीमा सास्र निधि तक रखी गई है। सघर्ष तरलता को उसकी शर्तों के कारण अनुपयोगी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इससे भी एक देश अपनी मुग्तान सन्तुलन की विषमताओं को दूर करने का प्रयास करता है।

तरलता का निर्माण मुद्रा कोष के प्रतिरिक्त साधनों से भी किया जाता है। युद्ध के बाद विश्व की तरलता में जो वृद्धि हुई है, उसका बहुत कुछ श्रेय स्वर्ण उत्पादन एवं अमेरिकी मुग्तान सन्तुलन के घाटे को दिया जा सकता है। जब अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय मुग्तान सन्तुलन में घाटा रहता है तो अन्य देशों की केन्द्रीय बैंकों के पास डॉलर निधि बढ़ जाती है। संयुक्तराज्य अमेरिका से अन्य देशों के मुद्रा अधिकारी प्रार्थना करें तो वह स्वर्ण के बदले में डॉलर देने को तुरन्त तैयार हो जाता है। जब एक देश अमेरिकी डॉलरों को स्वर्ण के रूप में परिवर्तित कर लेता है तो इससे अन्तर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि नहीं होती है क्योंकि दूसरे देशों को जो स्वर्ण मिला वह अमेरिका द्वारा ही प्रदान किया गया था। ऐसी स्थिति में अमेरिका के स्वर्ण कोष कम हो जाएंगे।

निधि-निर्माण के तरीकों की सीमाएँ—एक देश अपनी निधि के निर्माण में जिन तरीकों को काम में लाता है, उन पर अनेक सीमाएँ लगी रहती हैं। प्रथम सीमा, स्वर्ण-परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। जब एक देश डॉलर को सोने के रूप में बदलने का प्रयास करता है तो इसके कारण अमेरिका के स्वर्ण कोष बहुत कुछ कम हो जाते हैं। इसके प्रतिरिक्त एक अन्य सीमा यह भी है कि जब दूसरे देशों की डॉलर निधि बढ़ जाती है तो अनिश्चितता का वातावरण बनता है। ऐसी स्थिति में जो भी डॉलर के स्वामी हैं वे यह सोचने लगेंगे कि अपने डॉलरों को स्वर्ण में परिवर्तित कर दें। ऐसी स्थिति में अमेरिका की डॉलर निधि और भी बढ़ जाएगी। फलतः यदि संयुक्तराज्य अमेरिका में घाटे की स्थिति आती है तो इससे विश्व तरलता में कमी आ जाएगी। यदि संयुक्तराज्य अमेरिका हमेशा ही अपने मुग्तान सन्तुलन में घाटे की स्थिति रखेगा तो यह न तो विश्व के लिए लाभदायक है और न स्वयं उसके लिए ही। ऐसी स्थिति में इसे समाप्त किया जाना उपयुक्त समझा जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या

(The Problem of International Liquidity)

अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की मात्रा को कब पर्याप्त कहा जाए और कब उसे अपर्याप्त माना जाए यह एक मौलिक समस्या है। इसका निर्णय करना अत्यन्त कठिन है। सिद्धान्त रूप में सम्भवतः 'अनेक देश अपनी राष्ट्रीय नीतियों का पालन करते हुए अपने-आपको अन्तर्राष्ट्रीय शक्तों में सन्तुलित पाता है। यदि हम व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो पाएंगे कि विभिन्न देशों का मुग्तान शेष हमेशा सन्तुलित नहीं रहता है और प्रायः वह घाटे की स्थिति में रहता है। इस घाटे की पूर्ति करना परम आवश्यक है। घाटे की स्थिति न रहने पर भी एक देश को यह विश्वास होना

चाहिए कि यदि कभी उसे घाटे की स्थिति का मुकाबला करना भी पड़ा तो घाटे की वित्तीय-व्यवस्था उसे उपलब्ध हो सकेगी जिसके आधार पर वह एक निश्चित समय में पुनः सन्तुलन प्राप्त कर सके। विश्व-व्यापार की मात्रा बढ़ने पर अन्तर्राष्ट्रीय मुग्तान बहुत कुछ असन्तुलित बन जाते हैं। जब तक तरलता का विशेष स्तर नहीं बनाया जाता तब तक विश्व-व्यापार का विस्तार एवं सत्तार की अर्थ-व्यवस्था का विकास दोनों ही रुक जाते हैं।

तरलता के पर्याप्त स्तर को तय करना अत्यन्त कठिन है। परिणाम को देखकर ही इसके सम्बन्ध में कुछ कहा जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय तरलता को पर्याप्तता का बिन्दु वहाँ माना जा सकता है जहाँ से नीचे गिरने पर सत्तार के विभिन्न देश अपने-आपने को सन्तुलित करने के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विकास की लागत पर निर्भर रहते हैं और जिससे ऊँचे उठने पर सत्तार के विभिन्न देश मुग्तान सन्तुलन में लगातार घाटा सहन करते रहते हैं। यह घाटे की स्थिति विदेशों में प्रसार की स्थिति को प्रोत्साहन देती है।

प्रसल में हमारे पास अभी तक आँकड़ों की कोई ऐसी कसौटी नहीं बन पाई है जो निःसन्देह रूप से यह बता सके कि तरलता की एक मात्रा पर्याप्त है अथवा नहीं। एक ही देश की तरलता के बारे में कुछ लोगों का विश्वास होता है कि यह पर्याप्त है जबकि दूसरों का विचार होता है कि यह आवश्यकता से कम है। अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की मात्रा एवं रूप के सम्बन्ध में जटिल समस्या का एक अन्य कारण यह है कि प्रत्येक देश इसे अपने दृष्टिकोण से देखता है। अपनी अधिक स्थिति और राष्ट्रीय तरलता के अनुभवों से प्रभावित होने के बाद वह विश्व तरलता के बारे में दूसरों जैसे विचार नहीं रख पाता वरन् प्रत्येक पक्ष अपने समर्थन के लिए कोई तर्क ढूँढ़ लेता है।

अब तक अमेरिका के घाटे की व्यवस्था विश्व की तरलता का स्रोत मानी जाती थी किन्तु इसके समाप्त होने के बाद अन्तर्राष्ट्रीय तरलता का एक महत्वपूर्ण स्रोत समाप्त हो गया। अब आवश्यकता यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय निधि के निमाण के लिए और कोई तरीका खोजा जाए।

इस समस्या पर वर्तमान काल में पर्याप्त अध्ययन किए गए हैं। इन विभिन्न अध्ययनों में दस देशों का समूह (Group of Ten) और संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास के लिए सम्मेलन (United Nations Conference on Trade & Development) द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के प्रतिवेदन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। दस के समूहों का सम्मेलन जून, 1966 में फ्रैंक फर्ट में किया गया था। इस सम्मेलन में विश्व की मुग्तान प्रणाली को सुधारने के लिए अधिक ठोस सुझाव प्रदान नहीं किए गए थे किन्तु फिर भी सम्मेलन के अध्यक्ष डॉ॰ एमिंगर (Emminger) ने बताया कि समूह के सदस्य निम्न बातों में सहमत थे—

(1) वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्बन्धी तरलता कम नहीं है।

- (2) जब तक संयुक्तराज्य अमेरिका के भुगतान सन्तुलन में घाटे की स्थिति है उस समय तक अतिरिक्त तरलता के निर्माण के लिए विचार नहीं किया जा सकता ।
- (3) वर्तमान परिस्थितियों में निश्चय के साथ यह नहीं कहा जा सकता कि यदि अमेरिका का भुगतान सन्तुलन समतुल्य बन जाए तो अतिरिक्त तरलता अवश्य होगी ।

डॉ० एमिंगर का यह विचार था कि संयुक्तराज्य अमेरिका में स्थित घाटे की अर्थ-व्यवस्था का कारण प्राथमिक नहीं है, बल्कि यह राजनैतिक है । इसमें वियतनाम का युद्ध भी सम्मिलित है । वियतनाम का युद्ध समाप्त होने पर अमेरिका के घाटे की अर्थ-व्यवस्था एकदम बदल सकती है, किन्तु इससे अनेक नवीन प्राथमिक समस्याएँ पैदा हो जाएंगी ।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास के लिए सम्मेलन ने विशेषज्ञों के समूह को अन्तर्राष्ट्रीय तरलता पर विचार करने के लिए नियुक्त किया । इस सम्मेलन ने अपने प्रतिवेदन में यह बताया कि निधियों का विस्तार करना विकासोन्मुख देशों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिए आवश्यक है । समूह का कहना था कि यदि विश्व तरलता का विस्तार कर दिया गया तो विकसित देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं सहायता की नीतियों में अधिक उदार दृष्टिकोण अपना सकेंगे । वर्तमान समय में निधि की मात्रा कम होने के कारण यह सीमित स्तर पर है । समूह ने विभिन्न देशों के विकास की दर एवं व्यापार की समस्याओं के बारे में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की । समूह का कहना था कि निधि का विस्तार और निधि की कमी के प्रभाव न केवल घाटे की व्यवस्था वाले देशों में ही लागू होते हैं बल्कि ये अधिशेष वाले देशों में भी लागू होते हैं । सामान्य रूप से समूह ने यह माना कि निधियों का साधारण स्तर पर्याप्त था और इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय तरलता में विस्तार की आवश्यकता महत्वपूर्ण थी ।

अन्तर्राष्ट्रीय तरलता के सम्बन्ध में जो भी अध्ययन किए गए उनकी अनेक बातें महत्वपूर्ण थीं । उनमें विशेष रूप से उत्प्रेलनीर एक बात यह थी कि नवीन अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की रचना विभिन्न साधनों से करने की बात कही गई । वर्तमान समय में ऐसी तकनीकों पर ध्यान दिया जा रहा है जिन्हें अपनाकर अन्तर्राष्ट्रीय समिति के आधार पर समय के अनुकूल अन्तर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि की जा सके । तरलता में वृद्धि का कार्य कोष के अन्तर्गत और कोष के बाहर दोनों ही जगह किया जा सकता है । इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय यह बताया जाता है कि कोष का विस्तार एवं विस्तार किया जाए क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय तरलता उपलब्ध कराने वाली यह एक आधारभूत संस्था है ।

यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की पर्याप्तता के बिन्दु का पता लगाना अत्यन्त कठिन है किन्तु फिर भी यदि विवाद में न पड़ कर यह मान भी लें कि अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की पूर्ति का स्तर वर्तमान बाल में पर्याप्त है तो भी अधिशेष के बारे में समस्या उठ सकती है । यह कहा जा सकता है कि भावी-वृद्धि की दर सम्भवतः

प्रयोज्य है। भविष्य के प्रबन्ध के लिए ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत् अन्तर्राष्ट्रीय तरलता के सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाही कर सके इस व्यवस्था को करते समय कई बातों का निर्धारण करना होगा, जैसे (1) भविष्य में विश्व की निधियों की कितनी आवश्यकता है और वे सम्भवतः कितनी बढ़ सकती हैं? (2) यदि आवश्यक समझा जाए कि निधि निर्माण यन्त्र होना चाहिए तो प्रश्न यह है कि इस यन्त्र में भाग लेने वालों की संख्या कितनी रखी जाए? (3) विभिन्न देशों के बीच निधियों का वितरण किस आधार पर किया जाए? और (4) इन सब क्रियाओं का नियमन किसके द्वारा किया जाए? निधि निर्माण से सम्बन्धित समस्या का समाधान कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि वह विकसित और विकासोन्मुख दोनों प्रकार के देशों की व्यापक निधि-आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

समस्या का हल

समस्या पर भारत में विचार-विमर्श

(Discussions on the Problem held in India)

दिसम्बर, 1964 में बड़ोदा में भारतीय प्रायिक सस्या के सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय तरलता से सम्बन्धित समस्या पर पर्याप्त विचार विमर्श किया गया। इस विषय पर कुल मित्राक्षर 20 निबंध प्रस्तुत किए गए जो इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते थे। इन सभी के अन्तर्गत सामान्य रूप से यह सहमति प्रकट की गई कि अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की रचना में क्या क्या तत्त्व आते हैं? अन्तर्राष्ट्रीय तरलता को परिभाषित करते हुए यह कहा गया कि इसमें वे सभी साधन खोजे जाँ कि भुगतान सन्तुलन के घाटे की व्यवस्था का मुकाबला करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों की मौद्रिक सत्ताओं के पास उपलब्ध रहते हैं। सम्मेलन के सभी सदस्य इस बात से सहमत थे कि यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की पर्याप्तता का निर्धारण करने का मापदण्ड निश्चित करना बहुत कठिन है किन्तु फिर भी वर्तमान परिस्थितियों में कुल मिला कर अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की कमी नहीं थी, फिर भी भविष्य में यह कभी विकसित हो सकती थी। अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की भविष्य की बढ़ती हुई मांगों के अनुसार किस प्रकार बढ़ाया जाए, इसके सम्बन्ध में विभिन्न विचारकर्त्ताओं के बीच मतभेद था।

बड़ोदा के सम्मेलन में जिन विभिन्न प्रश्नों पर जिन विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया गया उनका यहाँ उल्लेख करना अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की स्थिति को सही जानने के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।

क्रान्तिकारी बनाम विकासवादी दृष्टिकोण

(Revolutionary Vs Evolutionary Approach)

अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की स्थिति को सुधारने के लिए विचारकों ने अनेक सुझाव प्रस्तुत किए किन्तु इनमें से कुछ विचारकों ने दृढ़ अथवा क्रान्तिकारी दृष्टिकोण का समर्थन किया। इन्होंने विश्व केन्द्रीय बैंक जैसी सस्या की रचना के लिए प्रस्ताव

रहे। यद्यपि इन प्रस्तावों के समर्थन में थोड़े ही तर्क दिए गए और इन्हें क्रियान्वित करने में जो विभिन्न समस्याएँ आती हैं उनके बारे में बहुत कम कहा गया। दूसरी ओर मि. नायक और थोनिवास भूति आदि विचारकों ने एक विकासवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया। उन्होंने पिछले दो तीन वर्षों के विभिन्न सुधारों एवं सुविधाओं का केवल उल्लेख किया, मुद्रा कोष की नीतियों में परिवर्तन लाने की बात कही, केन्द्रीय बैंकों में द्विपक्षीय समझौते प्रबन्धों का समर्थन किया और ऐसे ही अन्य उपाय बतलाए। मि. नायक ने प्रपेसाकृत एक व्यापक सध्यगत सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। सम्मेलन में इन विकासवादी और क्रान्तिकारी पक्षों के बीच विचारों का महत्वपूर्ण आदान-प्रदान हुआ। इस सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि विकासवादी दृष्टिकोण को उद्देश्य के रूप में मस्तिष्क में रखते हुए भी निकट भविष्य में विकासवादी दिशा में प्रगति की सम्भावनाएँ अधिक हैं।

वैसे देखा जाए तो इन दोनों विश्वासों के बीच अन्तर की छाई इतनी चौड़ी नहीं जितनी कि समझी जाती है। यदि परिष्कृत यूरोपीय देशों तथा अमेरिका की दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञात होगा कि निकट भविष्य में क्रान्तिकारी प्रस्तावों को स्वीकार करना मुश्किल है किन्तु फिर भी वर्तमान विचार प्रक्रिया में क्रान्तिकारी परिवर्तन आ सकता है। वैसे विकासवादी और क्रान्तिकारी दोनों ही भविष्य की ओर देखने का दृष्टिकोण अपना रहे थे।

पर्याप्तता से सम्बन्धित विचार

(Considerations Regarding Adequacy)

अन्तर्राष्ट्रीय तरलता के प्रमुख तत्त्व, उसका स्तर, उसकी वनावट और उसका वितरण होते हैं। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की वनावट बहुरूपी होती है। ऐसी स्थिति में उसकी पर्याप्तता को निर्धारित करना सरल नहीं है। यह बहुत कुछ एक व्यक्ति के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति सम्बन्धी लक्ष्यों एवं भुगतान सन्तुलन की असमत्तुल्यता के विभिन्न प्रकारों के समाधान की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ बातों के सम्बन्ध में थोड़ी सहमति पाई जाती है जैसे- (1) कीमतों के स्थायित्व की स्थिति में सर्वाधिक रोजगार और विकास हो सकता है, (2) व्यापार एवं विनिमय प्रतिवन्धों से स्वतन्त्रता प्राप्त की जाए, (3) विशेष रूप से अर्द्ध-विकसित देशों की पूँजी के प्रभाव को संवाहित किया जाए, (4) स्थायी विनिमय दरें कायम की जाए, और (5) स्थायित्व के साथ प्रगति को बनाए रखने के लिए उपयुक्त आर्थिक और भौतिक अनुशासन रखा जाए। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के सम्बन्ध में कुछ मतभेदों की सम्भावना भी हो सकती है। भाग लेने वालों में से कुछ विचारकों का मत था कि लोचशील विनिमय दरों की व्यवस्था भुगतानों के सन्तुलन को समतुल्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण रूप से सहायता करती है। वैसे निश्चित विनिमय दरों की व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक सामान्य इच्छा प्रदर्शित की गई। अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की पर्याप्तता को इस पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। सम्भवतः यह कहना सही है कि अन्तर्राष्ट्रीय

तरलता का विनाश विश्व व्यापार घोर पूंजी के आवागमन के विकास की दरों के अनमान के निरुद्ध होना चाहिए। कुन मिलाकर यह सामान्य धारणा थी कि तरलता के प्रसार की दर अतीत की तुलना में अधिक होनी चाहिए।

तरलता की बनावट

(Composition of Liquidity)

बनावट की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय तरलता को प्राथमिक या अधिकृत निधियों एवं सभी प्रकार की उधार लेने की सुविधाओं से भिन्न किया जा सकता है। बनावट की दृष्टि से तरलता के दो रूप हो सकते हैं—स्वजनित तरलता (Automatic Liquidity) और शर्तित तरलता (Conditional Liquidity)। अधिकृत साधन श्रोत कभी-कभी शर्तित तरलता की रचना करते हैं। दूसरी ओर लिए गए ऋण यद्यपि सामान्य रूप से शर्तित होते हैं किन्तु फिर भी वे अशर्त या स्वजनित तरलता की रचना करते हैं। ऋण लेने का प्रबन्ध सामयिक, कुछ समय के लिए अथवा लम्बे समय के लिए हो सकता है। प्रश्न यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय तरलता का प्रसार किस सीमा तक मुद्रा बनाम स्वर्ण का रूप धारण कर सकता है? और दो या तीन अतिगत देशों की मुद्रा के भण्डार बनाम बहुराष्ट्रीय मुद्रा के भण्डार या केन्द्रीय सुरक्षित सहाय की जमा रूप धारण कर सकता है। यह तो स्पष्ट है कि स्वर्ण पैदावार का प्रसार बाँझ अन्तर्राष्ट्रीय तरलता के विकास की दर को बनाए नहीं रख सकता। यह सच है कि आने वाले भविष्य में भी स्वर्ण के बिना काम नहीं चल सकता और यह अन्तिम अन्तर्राष्ट्रीय निधि है जो सामान्य रूप से विभिन्न देशों के बीच समता स्थापित है, फिर भी मुग्तान समुलनों के घाटे की स्थिति को सुलभाने में स्वर्ण का महत्व घट रहा है और इसलिए प्राप्त स्वर्ण भण्डारों का सर्वाधिक प्रयोग करने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

इस दृष्टि से स्वर्ण की कीमतों में वृद्धि का भी पर्याप्त महत्व होता है। स्वर्ण की कीमतों में वृद्धि का अपना राजनैतिक महत्व होता है। सोने के लिए गैर-मौद्रिक माँग की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव तथा पुनर्मूल्यांकन की प्राप्ति के विभिन्न देशों के बीच समानता के आधार पर विवरण एक विचारणीय प्रश्न रहा है।

प्रमुख मुद्राओं की व्यवस्था के लिए परिवर्तन

(Modifications to the System of Key-Currencies)

यदि अन्तर्राष्ट्रीय तरलता को मुद्रा एवं सास के साथ अधिक से अधिक समायोजित होना है तो इसके लिए प्रमुख मुद्राओं की वर्तमान व्यवस्था एवं स्वर्ण विनिमय के मासक में परिवर्तन पर विचार करना होगा। भविष्य में दो प्रमुख सुरक्षित मुद्राओं—पाउण्ड स्टर्लिंग और अमेरिकी डालर में घाटे की व्यवस्था द्वारा तरलता का प्रसार नहीं किया जा सकता क्योंकि भय अधिक समय तक बड़े घाटे की व्यवस्था को बनाए रखने की क्षमता काफी सीमित हो गई है। इस क्षेत्र में समुक्त-राज्य अमेरिका की सामर्थ्य भी बहुत कुछ घट गई है। इसके अतिरिक्त अन्य सुरक्षित

मुद्राएँ भी दीर्घकालीन सन्तुलन नहीं बनाए रखना चाहती। इस दृष्टि से एक रास्ता तो यह है कि विश्व के केन्द्रीय बैंक में निधियों का केन्द्रीयकरण कर लिया जाए किन्तु ऐसा करने पर अनेक व्यावहारिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्रीय बैंक, राष्ट्रीय केन्द्रीय बैंक की अपेक्षा कहीं अधिक जटिल है। इसके द्वारा अनेक तकनीकी समस्याओं को उपस्थित करने के प्रतिरिक्त इसमें अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक सहयोग की एक मात्रा को मानकर चला जाता है जो निकट भविष्य में सम्भवतः दिखाई नहीं देती। इसके साथ ही सुरक्षित मुद्राओं के वर्तमान भण्डार को केन्द्रीय विश्व बैंक को स्थानान्तरित करने में भी अनेक समस्याएँ पैदा होंगी। यह कहा जाता है कि विश्व केन्द्रीय बैंक व्यवस्था द्वारा सदस्य देशों पर जो अनुशासन लाया जाएगा वह स्वाभाविक रूप से आर्थिक समस्याएँ पैदा करेगा और बिना अनुशासन के विश्व केन्द्रीय बैंक मन्दी की स्थिति में आ सकता है, जैसा कि अनेक राष्ट्रीय केन्द्रीय बैंक आ जाते हैं।

नवीन प्रमुख मुद्राओं के भार को हटका करने के लिए एक ग्रन्थ समाधान मि० बर्नस्टीन (Bernstein) द्वारा सुझाया गया। इनके अनुसार एक नई सुरक्षित इकाई रखी जाए जिसमें प्रमुख मुद्राओं में से एक दर्जन के लगभग के निश्चित अनुपात रखे जाएँ और उनका मूल्य वर्तमान अमेरिकी स्वर्ण डॉलर के बराबर रखा जाए। बर्नस्टीन ने बाद में अपनी मौलिक योजना के अन्तर्गत कुछ परिवर्तन किए। विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सुरक्षित इकाई में केवल 20 प्रतिशत का प्रदान दिया गया।

इस सम्बन्ध में आज बहुत कप सन्देह किया जाता है कि साल या ऋण के प्रावधानों द्वारा तरलता का स्वभाव अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए चाहे यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा या द्वितीय रूप से या क्षेत्रीय रूप से किया जाए। प्रश्न यह है कि कर्ज को किस प्रकार कम से कम सशर्त अर्थात् अधिक से अधिक स्वायत्त बनाया जाए? अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यम से लिए जाने वाले ऋण के सम्बन्ध में इसका महत्व विशेष रूप से बढ़ जाता है।

कोष की नीतियों में अर्वाचीन परिवर्तन

(Recent Changes in Policies of I.M.F.)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीति और प्रक्रियाओं में हाल ही में बड़े परिवर्तन हुए हैं। इस दृष्टि से देखने पर हम पाएँगे कि कोष में किए गए अनेक परिवर्तन ऐसे हैं जिनसे भविष्य में अनेक सम्भावनाएँ जन्म लेती हैं। कोष के व्याज की दर में कमी करने का भी प्रस्ताव था। कोष नियन्त्रण में वृद्धि और ऋण सम्बन्धी नीतियों में उदारता अन्तर्राष्ट्रीय तरलता को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। वानूनी रूप से यह एक सशर्त तरलता होगी और तत्पश्चात् रूप से यह अधिक से अधिक स्वजनित होगी। विचारकों का कहना था कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्रीय बैंक भी बना दिया जाए तो उसके कार्यों की प्रकृति बहुत कुछ ऐसी ही होगी,

जो कोप के द्वारा वर्तमान समय में किए जाते हैं। तरलता के कम से कम प्रसार की गारण्टी तो दी ही जानी चाहिए। साख के कुंज प्रसार की भी कुछ सीमाएँ होंगी। अणु सम्बन्धी व्यवहार पर सामूहिक रूप से देखभाल की जानी चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप में अपनी साख स्थिति बनाए रखना, विश्व केन्द्रीय बैंक में जमा रखने अथवा अपनी मुद्रा रखने से भिन्न नहीं है। यह सुझाया जाता है कि कोप में किसी सदस्य की जो स्थिति है, उसके लिए उसे प्रमाण-पत्र दिया जाता चाहिए। इस दृष्टि से राष्ट्रीय सम्प्रभुता को छोड़ना भी मूल रूप से कोई भिन्न चीज नहीं है। कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सस्या राजनीतिक पहलुओं को पूर्ण रूप से नहीं छोड़ सकती। इन सभी दृष्टियों से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप, सुधार के लिए उपयुक्त सस्या बन जाना है।

तरलता का वितरण

(Distribution of Liquidity)

विभिन्न देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय तरलता का वितरण भी एक महत्वपूर्ण विषय है। वर्तमान वितरण अनीन व असन्तुलनों को अभिव्यक्त करता है किन्तु भविष्य में सजगतापूर्वक किए गए प्रयास आवश्यक हैं ताकि तरलता की प्राप्ति में असमानता को कम किया जा सके। जहाँ तक विकसित देशों का सम्बन्ध है उनमें गलत वितरण की समस्याएँ हैं। वहाँ सुरक्षित मुद्राओं के बड़े मौद्रिक बाधितों की समस्याएँ भी हैं। इस समस्या से दबाने वाले देशों को प्रभावित किया जाता है किन्तु इसका समाधान सम्भव है।

विकासशील देशों की तरलता की आवश्यकता के लिए विशेष ध्यान दिया जाना भी आवश्यक है। यह सच है कि इन देशों में विकास के लिए दीर्घकालीन पूँजीगत सहायता की पर्याप्त मात्रा आवश्यक है। इसके अलावा ये तरलता की समस्या से भी प्रभावित हैं। कच्चे माल का उत्पादन करने वाले देश अपने निर्यातों के आकार और मूल्य में पर्याप्त उतार चढ़ाव से प्रभावित होते हैं। उनमें विदेशी सहायता के प्रयोग के बारे में भी पर्याप्त डील रहती है। प्रथम समस्या के निपटारे के लिए मुद्रा कोप ने हान में ही यह सुविधा प्रदान की है कि उसके स्रोतों से अतिरिक्त धन निकाला जा सके किन्तु इससे अधिक फर्क नहीं पड़ता नियतों के बढने से उपलब्ध मात्रा भी बढ सकती है।

इस कोप की सहायता के अतिरिक्त कुछ और भी सुझाव दिए गए, जैसे- निर्यात प्राप्ति को स्थायीकरण कोप (Export Receipt Stabilisation Fund) बनाया जाए। विकासशील देशों की एक जरूरत यह भी है कि वे विकसित देशों के बाजार में स्वतन्त्रतापूर्वक प्रवेश पा सकें। इसके अलावा विकासशील देशों में गरम धन के प्रवाह की भी समस्या है। विकासशील देशों में निधियों का संचय नहीं किया जा सकता, धन अणु लेने की मुविषाएँ उनके लिए विशेष महत्व रखती है। जब मुद्रा कोपों के साधनों का प्रसार होगा तथा कोप की महत्वपूर्ण निधियाँ उदार बन

जाएंगी तो इन देशों को बहुत लाभ रहेगा। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए सुझाई गई विभिन्न योजनाओं का विकासशील देशों के लिए क्या फायदा हुआ ? इस पर विशेष रूप से विचार करना चाहिए। यह उपयुक्त है कि प्रत्येक योजना में विकासशील देशों की आवश्यकताओं के प्रति विशेष ध्यान दिया गया है। यद्यपि वे उन पर भिन्न रूप से विचार करना चाहती हैं।

विकासशील देशों की तरलता पर आवश्यक विचार करते समय यह उल्लेखनीय है कि इन देशों द्वारा उपयुक्त प्रशुल्क एवं मौद्रिक नीतियाँ अपनाई जानी चाहिए ताकि घरेलू कीमतों में उपयुक्त स्थायित्व रह सके। जब तक प्रशुल्क सम्बन्धी एवं मौद्रिक अनुशासन नहीं रखा जाता, तब तक यह भाशंका रहती है कि निधियों का उच्च-स्तर शीघ्र समाप्त हो जाएगा।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और देखभाल (International Collaboration and Surveillance)

यहाँ एक बात महत्वपूर्ण यह है कि स्थिति में सुधार के लिए दिए गए प्रत्येक सुझाव में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और नियरानी रखने की परम आवश्यकता है। इसके प्रतिरिक्त राष्ट्रीय सम्प्रभुता की कुछ मात्राओं को भी छोड़ना पड़ेगा। कुछ विचारकों का सुझाव है कि इस सम्बन्ध में यदि कुछ बिभिनता रखी जाए तो अधिक नुकसान नहीं रहेगा। लोचशीलता एवं कार्य कुशलता के लिए अनेक प्रकार के प्रबन्ध किए जाने चाहिए। ऐसी स्थिति में उपयुक्त अवरोधों तथा सन्तुलनों की स्थापना हो जाएगी। भुगतानों के सन्तुलनों की व्यवस्था अलग-अलग होती हैं। इसके अलावा एक ही समय में यह अलग-अलग देशों में भिन्न होती हैं। सभी स्थितियों में तरलता की गति उल्लेखनीय रहती है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यम से उन उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में पर्याप्त सफलता रही है जो विश्व केन्द्रीय बैंक की स्थापना से प्राप्त किए जाने थे। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए सम्भावित आवश्यकता यह है कि जिस प्रकार राष्ट्रीय केन्द्रीय बैंक से ऋण लेने के लिए व्यापारिक बैंक तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार सदस्य देशों की कोष द्वारा प्रदान की गई मास्य सुविधाओं का प्रयोग संकटकालीन कार्य की अपेक्षा साधारण व्यवहार के रूप में करना चाहिए। कोष के माध्यम से जो लेन-देन का व्यापार किया जाता है उससे मास्य वाले और प्रतिरेक वाले देशों को पर्याप्त सुरक्षाएँ प्रदान की जाती हैं। इसके प्रतिरिक्त कोष की सास्य सुविधाओं को उदार बनाना तथा कोष के साधनों को प्रसारित करना भी बहुत कुछ उपयुक्त रहेगा।

कुल मिलाकर कोष के कार्य पर्याप्त संतोषजनक रहे। एस. एल. सिन्हा के शब्दों में "इसकी नीतियाँ, प्रक्रियाएँ एवं साधन स्रोत, विशेष रूप से वर्तमान वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त की बदलती हुई आवश्यकताओं का मुकाबला करने के लिए निरन्तर

समायोजित होते रहे हैं।¹ आज़ की स्थिति में विकसित अथवा कम विकसित देशों को बाप से जितनी आसानी से मदद मिल जाती है वह आज से एक दशक़ी पूर्व कठिन थी। उदाहरण के लिए, ग्रेट ब्रिटन ने 1957, 1961 और 1964 में जो बड़े कर्ज लिए उनका उल्लेख किया जा सकता है। इसमें सन्देह नहीं कि इससे सदस्य देशों में पर्याप्त विश्वास जाग्रत हुआ है और अन्तर्राष्ट्रीय तरलता में विश्वास एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्व होना है। विकासशील देशों के प्रति कोप का दृष्टिकोण एवं सहयोग पर्याप्त सहायता पूर्ण रहा है और अन्तर्राष्ट्रीय सस्या द्वारा इन देशों के हितों की उत्प्रेक्षणीय रूप से साधना की गई है। कोप अपनी मोनियो एवं प्रक्रियाओं में धीरे धीरे सुधार करता जा रहा है। ग्रेटन बुल्स के सुद्धिमान मृष्टाओं ने बाप के प्रारूप को इतना लोकगील बनाया है कि उसमें बहुत कुछ समायोजन सम्भव है। यदि आवश्यकता यह माँग करे कि कोप के विधान को सशोधित किया जाए तो ऐसा करने में भी कोई हिचक नहीं होनी चाहिए।



1 'Its policies, procedures and resources have been continuously adopted to meet the changing needs of International Finance, particularly in the last few years'
—S. L. Sinker Essays on Finance,

अस्थिरता उत्पन्न करने वाले अल्प-कालीन पूँजीगत आवागमन के प्रभाव, दीर्घकालीन निजी पूँजीगत निवेश की प्रवृत्ति एवं समस्याएँ

(DESTABILIZING EFFECTS OF SHORT-TERM CAPITAL MOVEMENT, LONG TERM PRIVATE INVESTMENT: TRENDS AND PROBLEMS)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विषय माल (Goods), सेवाएँ (Services) और पूँजी (Capital) होते हैं। पूँजी का आवागमन अनेक प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार से भिन्नता रखता है। जब सम्पूर्ण व्यापार में एक देश के वर्तमान उत्पादन और गतिशील माल की खरीद तथा बिक्री की जाती है तो दूसरी ओर प्रतिभूतियों (Securities) का व्यापार स्वामित्व और कर्जदारी के प्रमाणों से सम्बन्ध रखता है। जब माल को जहाज में भर कर एक देश से दूसरे देश में ले जाया जाता है तो उसके प्रभाव तत्कालीन और प्रत्यक्ष होते हैं। निर्यातकर्ता देश की दृष्टि से जहाज में माल लाने का अर्थ है कि उसके देश में माल कम रह जायगा और आयातकर्ता देश की दृष्टि से इसका अर्थ यह है कि उसकी माँगों को पूरा करने के अधिक साधन उपलब्ध हो सकेंगे।

पूँजी के आवागमन का प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन को उस मात्रा पर प्रभाव नहीं पड़ता जो कि एक देश के निवासियों को प्राप्त हो सकती है। जो प्रतिभूतियाँ एक देश द्वारा दूसरे देश को बेची जाती हैं उन्हें दूसरे द्वारा किसी अन्य प्रकार से ख़ाया अथवा प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। इस बिक्री के कारण पूँजी का आयातकर्ता देश ऐसी किसी चीज से वञ्चित नहीं रहता जो उसके प्राप्त उत्पादन को बड़ा सकती है। दूसरी ओर उनकी खरीद पूँजी निर्यातकर्ता देश के निवासियों के माल तथा सेवाओं की पूर्ति के लिए लाभदायक नहीं होती। यद्यपि इस प्रकार के लेन-देन से माल के बाज़ार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते किन्तु विभिन्न देशों के सात बाजारों पर इनका असर पड़ता है। जब कभी पूँजी का आवागमन होता

तो साख की कीमत या दूसरे शब्दों में व्याज की दर प्रभावित होती है। इन प्रभावों के परिणामस्वरूप अन्य महत्वपूर्ण फल भी सामने आते हैं।

पूँजी के आवागमन और व्यापारिक आवागमन के बीच एक अन्य मुख्य अन्तर यह है कि व्यापारिक आवागमन के लेन-देनों में भविष्य के लिए कोई वाञ्छनीयता स्थापित नहीं की जाएगी जबकि प्रथम प्रकार के लेन देनों में की जाती है। जब एक देश दूसरे देश की प्रतिभूतियाँ प्राप्त करता है तो विनीकर्ता देश कर्ज का पुनः भुगतान करने के लिए बाध्य होता है। कुल मिलाकर जब एक देश के निवासियों विदेशी प्रतिभूतियों को प्राप्त करते हैं तो भविष्य में उनका कुछ उत्तरदायित्व बढ़ जाता है जिसे विनीकर्ता देश को पहचानना चाहिए। जब विदेशी बाँण्ड एक देश के निवासियों द्वारा लिए जाते हैं तो व्ययकर्ता देश साधारणतः यह आशा करता है कि उसे कुछ धन प्रतिवष व्याज के रूप में मिले। पूँजीगत आवागमन में कुछ भविष्य के उत्तरदायित्व निहित होते हैं और पूँजी का प्रायातकर्ता देश इन उत्तरदायित्वों का सम्मान करता है। यदि हम माल के व्यापार (Trade of Commodities) और प्रतिभूतियों के व्यापार (Trade of Reserves) के बीच स्थित अन्तरों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहें तो यह बहना होगा कि प्रथम द्वारा माल के वाताहारी को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया जाता है जबकि दूसरे द्वारा साख बाजारों (Credit Markets) को किया जाता है। दूसरे, प्रतिभूतियों का व्यापार कुछ दानों की स्थापना करता है अथवा यूँ कहिए कि इससे एक देश के निवासियों को दूसरे देश के निवासियों के विरुद्ध स्वामित्व के अधिकार प्राप्त होते हैं। माल के व्यापार में ऐसा कुछ भी नहीं होगा।

विदेशी पूँजी द्वारा विश्व के अधिकांश देशों में विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया जाता है। मि० आर्थर लेविस (W Arthur Lewis) के कथनानुसार 'करीब-करीब प्रत्येक विकसित देश को उसने विकास के प्रारम्भिक स्तरों पर स्वयं की अल्प वचनों की सहायता देने के लिए विदेशी सहयोग प्राप्त हुआ। इंग्लैण्ड ने 17वीं और 18वीं शताब्दी में हॉलैण्ड से उधार लिया और 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में इसने विश्व के प्रायः सभी देशों को उधार दिया। संयुक्तराज्य अमेरिका आज दुनियाँ का धनवन्ततम देश है। उसने 19वीं शताब्दी में बहुत उधार दिया। इस शताब्दी में वह प्रमुख ऋणदाता देश बन गया है।' विश्व में केवल जापान और सोवियत रूस एस उदाहरण हैं जिन्होंने बिना किसी महत्वपूर्ण विदेशी पूँजी के अपना विकास किया। जापान में कुछ अनुकूल तत्त्व होने के कारण विदेशी पूँजी व उसका विकास सम्भव हो सका, यह अनुकूलता सभी देशों में नहीं रह पाती।

दुनिया के विभिन्न भागों में श्रम, खनिज, जलवायु और तकनीकी ज्ञान आदि साधनों की भिन्न भिन्न मात्राएँ हैं। यही कारण है कि वहाँ जिस साधन की कमी रहती है उसे उस स्थान से पूर्ण किया जाता है जहाँ इसकी अधिकता रहती है। इसके कारण पूँजीगत आवागमन सम्भव बनता है। विकसित तथा भर्द्ध विकसित देशों के जीवन स्तर के बीच पर्याप्त अन्तर रहते हैं। ये अन्तर विश्व शान्ति के लिए एक

चुनौती कहे जा सकते हैं। स्थायी विश्व शान्ति की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि अर्द्ध-विकसित देशों का तीव्र गति से विकास किया जाए। अर्द्ध-विकसित देशों के घरेलू साधन इतने नहीं होते कि वे अपना तीव्र गति से विकास करें। इन देशों में वृद्धि की दर पर्याप्त अल्प होती है। यदि वृद्धि करनी है तो इसके लिए जीवन को और भी नीचे गिराना होगा जबकि वह पहले से ही नीचा है। इस प्रकार इन देशों के द्रुत गति से विकास के लिए विदेशी पूँजी परम आवश्यक है।

यदि 'घरेलू वृद्धि' विकास की दर को सन्तोषजनक बनाए रखने के लिए पर्याप्त है तो भी भुगतान सन्तुलनों की घाटे की स्थिति को दूर करने के लिए विदेशी पूँजी काम में आ सकती है। विकास की तीव्र गति सामान्यतः भुगतान सन्तुलन में घाटे की स्थिति ला देती है। यह इसलिए होता है कि क्योंकि विकास कार्यों को त्रियान्वित करने के लिए तकनीकी ज्ञान, पूँजीगत माल और आवश्यक कच्चे माल का पर्याप्त आयात करना होता है। इसके अलावा पहले जिन चीजों का निर्यात किया जाता था अब उन्हें नव-निर्मित घरेलू उद्योगों द्वारा उपभोग का विषय बनाया जा सकता है। मूल्य और कीमत के प्रभाव भी भुगतान सन्तुलन को घाटे की स्थिति में लाने का उल्लेखनीय कार्य करते हैं।

शताब्दियों से अन्तर्राष्ट्रीय ऋण-दान प्रगतिशील देशों की विदेशी आर्थिक नीति का मूल तत्त्व रहा है। यही कारण है कि अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी के सिद्धान्त और व्यवहार के बारे में पर्याप्त विचार किया जाता है। अर्द्ध-विकसित देशों के विकास में विदेशी पूँजी के योगदान के सम्बन्ध में अर्थ-शास्त्रियों के बीच विभिन्नता है। इस सम्बन्ध से दोनों प्रकार के मत प्रकट किए जाते हैं। कुछ लोग विदेशी निवेश के नियन्त्रित प्रतिबन्धित प्रसार पर जोर देते हैं जबकि हमारे लोग इसे शुद्ध रूप से राष्ट्रवादी प्रश्न बना लेते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी के योगदान में सम्बन्धित विभिन्न विचार न केवल राजनीतिक विभिन्नताओं का परिणाम हैं वरन् ये अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी के आवागमन के सिद्धान्तों में निहित भ्रम की अभिव्यक्ति करते हैं।

पूँजी के आयात का अर्थ भौतिक मुद्रा का एक देश से दूसरे देश में स्थानान्तरण नहीं होता और न ही इसका अर्थ हमेशा भौतिक पूँजी का मशीन या साधनों के रूप में आयात होता है। पूँजी के आयात के दो रूप हो सकते हैं— (1) भौतिक स्थानान्तरण (Monetary Transfer) और (2) वास्तविक स्थानान्तरण (Real Transfer)। भौतिक स्थानान्तरण के अन्तर्गत ऋण लेने वाले देश को ऋण देने वाले देश में खरीददारी करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ऋण देने वाला देश अपनी वृद्धि की हुई पूँजी को ऋण लेने वाले देश में व्यय करता है। यह निवेश केवल तभी हो सकता है जब ऋण लेने वाला देश उधार में प्राप्त कोष को ऋण देने वाले देश में माल, सेवाओं तथा सोने की खरीद के लिए खर्च करता है। पूँजी के आयात का दूसरा स्तर वास्तविक स्थानान्तरण है जो माल, सेवाओं और स्वर्ण का आयात है। पूँजी के आयात में यह दूसरा स्तर कुछ समय के बाद ही आता है। कभी-कभी यह तुरन्त

या सकता है किन्तु ऐसे भी उदाहरण हैं जबकि माल और सेवाओं का अन्तिम स्थानान्तरण ऋण के सम्बन्ध में समझौता हो जाने के बहुत समय बाद होता है।

पूँजी के आयात और वस्तुओं तथा सेवाओं के आयात के बीच पविष्ट सम्बन्ध रहता है। इन दोनों के बीच स्पष्ट कारण-कार्य का सम्बन्ध स्थापित करना अत्यन्त कठिन है। पूँजीगत आयात वस्तुओं के आयात को प्रोत्साहन देते हैं इसका विपरीत असर भी सही है। अमल में दोनों का सम्बन्ध पारस्परिकता का है।

अन्तर्राष्ट्रीय पूँजीगत आवागमनों के लिए आर्थिक साहित्य में पर्याप्त समूर्त विचारधाराएँ प्रतिपादित की गई हैं। एक महत्वपूर्ण तर्क यह दिया जाता है कि पूँजी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पूँजी की उत्पादित के सीमान्त के निम्न-स्तर वाले देशों से उच्च स्तर वाले देशों की ओर गति करती है। ऐसी स्थिति में सीमान्त उत्पादित को विश्व भर में समान करने की प्रवृत्ति जाग्रत होती है। इसे एक स्वस्थ प्रवृत्ति माना जाता है क्योंकि इससे पूँजीगत साधनों का अधिकतम उपयोग का प्रोत्साहन मिलता है। वैसे सत्य तो यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी के आवागमन की गत्यात्मकता इतनी जटिल है कि वह इस सम्बन्ध में किए गए किसी भी समूर्त और सरल विश्लेषण के अधीन को असत्य बना देती है। अन्तर्राष्ट्रीय पूँजीगत आवागमन को विभिन्न देशों के व्याज या लाभ की दर के अन्तर के रूप में ही परिभाषित नहीं करना चाहिए वरन् इस ऋणदान और ऋण लेने वाले देशों में पारस्परिक लाभों के रूप में भी परिभाषित करना चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी के आवागमन का इतिहास (History of International Capital Movements)

मि स्नाईडर के कथनानुसार "19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्ष गैर-सरकारी अन्तर्राष्ट्रीय धन से सम्बन्धित विषयों के सुनहरी युग माने जा सकते हैं।" यह अनुमान लगाया जाता है कि 1914 तक प्रमुख व्यापारी देशों के दीर्घकालीन विदेशी धन का कुल योग 41 हजार मिलियन डॉलर था। व्यक्तिगत दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी का प्रवाह उस समय के बाद से 1914 के पूर्व की स्थिति तक घात भी नहीं पहुँचा है।

1914 में पूर्व प्रमुख व्ययकर्ता देशों में ग्रेट-ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी प्रमुख थे। ग्रेट-ब्रिटेन के धन की मात्रा कुल योग का 40 प्रतिशत थी। इस काल में सयुक्तराज्य अमेरिका की स्थिति पर्याप्त आलोचनात्मक थी। वह ब्रिटेन में अपने दीर्घकालीन धन की दृष्टि से चौथे नम्बर पर आता है। 1913 में सयुक्तराज्य अमेरिका की विदेशी सम्पत्ति 68 मिलियन डॉलर थी और इसके परिणामस्वरूप वह शुद्ध रूप से एक बर्ज देने वाला नहीं बरन् बर्ज लेने वाला देश था।

बीसवीं शताब्दी के मध्य में अधिकांश पूँजीगत निर्यात जर्मनी और आस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों की ओर प्रेरित थे। इस काल में आकर जर्मनी एक पूँजी निर्यातकर्ता देश बन गया। यह उम्मीद की जा सकती थी कि पश्चिमी यूरोप के विकसित देश उन देशों को बर्ज देंगे जिन्हें मुख्य रूप से इसकी आवश्यकता है किन्तु

उम समय के अनुभव ने इस मान्यता का समर्थन नहीं किया। पूँजी का आवागमन विकसित और अर्द्ध-विकसित देशों के बीच होने की अपेक्षा केवल विकसित देशों के बीच होने लगा। व्यापार करने वाले देश केवल सन्तुलन की स्थिति में ही व्यापार करते थे। यद्यपि उन्होंने दूसरे देशों को सम्पत्ति का निर्यात किया किन्तु साथ ही दूसरे देशों से सम्पत्ति के आयात को भी आकर्षित किया। विदेशी पूँजी प्रायः उन देशों की ओर गई जिनकी आवादी कम थी और प्राकृतिक साधन बहुत थे। ये देश अपने व्यापारिक निर्यात को आसानी से बढ़ा सकते थे। पूँजीगत आयातों से अन्य देश, विशेष रूप से सूदूर पूर्व और अफ्रीका के देश बहुत प्रभावित हुए। संयुक्तराज्य अमेरिका 1914 से पूर्व वर्षों से ऋण देने वाला देश रहा किन्तु 1914 के पाँच वर्ष बाद उसकी स्थिति उल्लेखनीय रूप से परिवर्तित हो गई।

फ्रांस और जर्मनी 19वीं शताब्दी के अन्त तक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय ऋणदाता नहीं बन पाए। इसके अतिरिक्त फ्रांस द्वारा दिए जाने वाले कर्ज राजनीतिक दृष्टि से बहुत प्रभावित होते थे। यही बात जर्मनी के विदेशी व्यय के सम्बन्ध में थी। इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की एक अध्ययनकर्ता संस्था ने यह विचार प्रकट किया कि युद्ध से पूर्व के अन्तर्राष्ट्रीय व्यय की प्रकृति को एक वाक्य में संक्षिप्त किया जा सकता है। फ्रांस और जर्मनी द्वारा राजनीतिक एवं सैनिक उद्देश्यों से दिए जाने वाले ऋणों के अतिरिक्त व्यय का मुख्य भाग अविकसित देशों की ओर संचालित था जो प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करते थे। इनमें प्रमुख कर्ज देने वाले वे थे जो कि सर्वोच्च प्रतिदान दे सकें।¹

प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान पूँजी का आवागमन

(Capital Movements during the First World-War)

प्रथम विश्व-युद्ध ने प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को पूर्ण रूप से बदल दिया। युद्ध ने हुए खर्च को पूरा करने के लिए प्रायः सभी प्रमुख कर्जदाता देश समुद्र पार के अपने व्यय के अधिकांश भाग को बेचने के लिए बाध्य हो गए। इस प्रकार स्नाइडर का यह कहना सही है कि प्रथम विश्व युद्ध अनेक देशों की अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन लाया। इसने पूँजीगत आवागमन के इतिहास में एक नए युग को प्रारम्भ किया। युद्ध का तत्कालीन प्रभाव यह पड़ा कि संयुक्तराज्य अमेरिका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में एक कर्जदार की स्थिति से ऊपर उठकर कर्जदार बन गया। अधिकांश यूरोपीय देशों का विदेशी व्यय पर्याप्त घट गया। यहाँ तक कि जर्मनी आदि देशों में तो यह इतना घटा कि वे कर्ज ग्रहण करने वाले देश बन गए। फ्रांस के अनेक अन्तर्राष्ट्रीय व्यय कम हो गए तथा युद्ध के विध्वंस के कारण उनमें से अनेक मूल्यहीन बन गए; इनमें से अनेक बाद में होने वाली क्रान्ति एवं सामाजिक परिवर्तनों द्वारा जड़त किए गए। अनुमान है कि इस काल में फ्रांस को लगभग चार मिलियन डॉलर की हानि उठानी पड़ी।

1 Royal Institute of International Affairs, the Problems of the International Development, London : Oxford University Press, 1937, p. 120.

इस काल की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह थी कि अल्पकालीन पूँजीगत आवागमनो का सम्पूर्ण लेन-देन में उल्लेखनीय योगदान रहा। सन् 1920 में अन्य देशों को जो फ्रांसिसी सम्पत्ति निर्यात की गई थी वह अल्पकालीन प्रकृति की थी। ये अल्पकालीन आवागमन इतने महत्त्वपूर्ण थे कि अमेरिका और ग्रेट-ब्रिटेन जैसे प्रमुख पूँजी निर्यातकर्ता देशों ने भी अल्पकालीन लेखों पर भारी कर्ज लिया। कहा जाता है कि 1924 से 1927 तक अल्पकालीन पूँजीगत प्रवाह अमेरिका में एक बिलियन से भी थोड़ा ज्यादा था। ग्रेट-ब्रिटेन में इसकी मात्रा और भी अधिक थी। यद्यपि पूँजी को अल्पकालीन आधार पर उधार में लिया गया था किन्तु कुछ देशों ने इसे अपने दीर्घकालीन विकास में प्रयुक्त किया। इसके परिणामस्वरूप पर्याप्त अस्थिरता आ गयी।

जब एक बार महान् आर्थिक मन्दी ने वित्तीय बाजारों को प्रभावित किया तो उधार लेने वाले देशों में व्यक्तिगत व्यय-कर्त्ताओं को सम्बन्धित देशों द्वारा घरेलू कठिनाइयों के कारण इन बात के लिए प्रभावित किया गया कि वे विदेशों से अपनी सम्पत्ति को वापिस ले लें। अल्पकालीन वायदों को समाप्त करने के लिए कहा गया। इन सबके परिणामस्वरूप उधार लेने वाले देशों में अनेक आर्थिक उलझने आ गईं। 1930 के दौरान दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रीय ऋण की मात्रा एवं प्रभाव बढ़ा। प्रायः सप्ताह का प्रत्येक देश इस प्रकार के ऋण से प्रभावित था, किन्तु कुछ देश तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभावित थे। जनाहा, आस्ट्रेलिया, अर्जेन्टाइना आदि देश दीर्घकालीन कर्जदारी में प्रमुख थे किन्तु चीन, भारत, जर्मनी और ब्राजील भी प्रमुख कर्जदार थे।

1930 के पूँजीगत आवागमन

(Capital Movements in the 1930)

1930 के दौरान स्थिति पहले की अपेक्षा असाधारण बन गई। इस काल की आर्थिक मन्दी ने विश्व की अर्थ-व्यवस्था पर भयानक प्रभाव डाला। द्वितीय विश्व-युद्ध से एक दशब्दी पूर्व की इस विश्व व्यापक आर्थिक मन्दी ने आर्थिक सम्बन्धों को पर्याप्त असन्तुलित बना दिया और आने वाले युद्ध के लिए आधार भूमि तैयार की। 1930 में दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी के आवागमन अपनी प्रतिम सीमा तक पहुँच गए। आगे के कुछ वर्षों में बेरोजगारी बढ़ी, घबराहट हुआ और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आकार घटा। इसके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक धन का विखटन हुआ, व्यापार और विनिमय का नियन्त्रण किया जाने लगा, प्रशुनक एवं अन्य विभिन्न बाधाएँ सामने आने लगी और इन सबके परिणामस्वरूप राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। इन सभी विकासों के कारण नवीन दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रीय धन प्रायः रुक गए।

आर्थिक मन्दी के काल में विभिन्न कर्जदार देश भी कर्जदार बन गए। उदाहरण के लिए संयुक्तराज्य अमेरिका ने 1934-1944 के बीच लगभग 6 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया, जबकि इस काल में ग्रेट-ब्रिटेन ने 1½ बिलियन डॉलर का कर्ज लिया। स्विट्जरलैण्ड ने पूँजी का न तो आयात किया और न ही निर्यात।

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी का आवागमन प्रथम विश्व-युद्ध द्वारा स्थापित राजनीतिक अस्थायित्व के पूर्व किस प्रकार होता था। उसके पश्चात् 1920 की असुरक्षाओं में, अन्य महायुद्ध के समय में और 1940 की अस्थायित्वपूर्ण परिस्थितियों से पूँजी का आवागमन किस प्रकार हुआ ? प्रथम विश्व-युद्ध से पूर्व करोड़ों डॉलर के पूँजी के निर्यात उस समय की पर्याप्त सहायता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यद्यपि ये निर्यात प्राथमिक अर्थ-व्यवस्थाओं (Primary Economies) की ओर संचालित नहीं थे, जिन्हें विदेशी पूँजी की सबसे अधिक आवश्यकता थी, बल्कि इन्होंने पर्याप्त स्रोतों वाले और अपेक्षाकृत सुरक्षित एवं स्थायी राजनीतिक दृष्टिकोण वाले देशों को अपना विकास शीघ्र करने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे अन्य देशों को भी विकास का घबराहट मिला।

प्रथम विश्व-युद्ध के बाद जो अस्थायित्व आया और आर्थिक मंदी के साथ कर्ज लेने और देने वाले के बीच जो सम्बन्ध स्थापित हुए उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि इसका कारण पूँजी का आवागमन ही था। जो देश पूँजी की सख्त आवश्यकता महसूस कर रहे थे उनको यह अनुभव हुआ कि इसे प्रदान करने वाला कोई नहीं है। जो देश पहले दूसरे देशों को कर्ज देने की क्षमता रखते थे वे अब विदेशी कर्ज प्राप्त करने में अनिच्छा प्रदर्शित करने लगे। पूँजीगत आवागमनों ने इन वर्षों में प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास के क्षेत्र में बहुत कम योगदान किया।

द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद बाध्यकारी दिवानियतन की स्थिति आई। इस कान में जो कर्ज दिए गए उनका आधार ब्रह्म शताब्दी पूर्व दिए गए कर्जों से भिन्न था। गैर-सरकारी कर्जों का कोई महत्व नहीं रहा। इस प्रकार वर्तमान काल में पूँजी के आवागमन की दिशा को स्थापित करने में राजनीतिक विचार-विमर्श भी पर्याप्त प्रभाव डालने लगे। पिछला इतिहास यह सिद्ध करता है कि विभिन्न क्षेत्रों का आर्थिक विकास, पूँजी के आवागमन की मात्रा, दिशा एवं प्रकृति पर निर्भर करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी की गतिशीलता के कारण

(Reasons of International Capital Movement)

पूँजी की गतिशीलता का क्या कारण है और एक देश से दूसरे देश में पूँजी का आयात और निर्यात क्यों होता है ? यह प्रश्न पर्याप्त महत्व रखता है। इस प्रश्न का जवाब देने के बाद ही हम पूँजी के आवागमनों की वास्तविक प्रवृत्तियों के बारे में कुछ निष्कर्ष ले सकते हैं और तभी हम इस बात का मूल्यांकन कर पाएँगे कि सर्वाधिक वांछनीय किसे माना जाए।

माल और सेवाओं का व्यापार इसलिए होता है क्योंकि इससे खरीददार को आनंद करने में लाभ रहता है। जब एक देश को दूसरे देश में स्थिति पूर्ति के खाते में सस्ता माल प्राप्त हो सकता है तो वह उसी विदेशी माल को अपने अर्थ-व्यवस्था में प्रसारित करके व्यापार का जन्म हो जाएगा। एक समय था जब पूँजी का आवागमन इसलिए होता था क्योंकि खरीददार विदेशी प्रतिभूतियों को प्राप्त करने के सम्बन्ध में स्वयं ही एक विधेयात्मक और सक्रिय निर्यात लेता था। ऐसी स्थिति में वह अपने स्वार्थों को देखने के बाद स्वतन्त्रतापूर्वक कोई निर्यात लेता था।

पूँजी के आवागमन सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार के होते हैं और इनके लिए उत्तरदायी कारण भी राय भिन्न भिन्न होते हैं। यद्यपि इनका प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष अध्ययन किया जाए तो भविष्य उपयुक्त रहेगा।

पूँजी के गैर-सरकारी आवागमन के कारण
(The Reasons of Private International Capital Movement)

पूँजी के आवागमन में जिन प्रतिभूतियों का नाम लिया जाता है, उनका एक व्यापक अर्थ है, इनमें न केवल बॉण्ड्स एवं स्टॉक ही आते हैं बल्कि मल्टीनैशनल नाट, जमा लेव्हे और विदेशों में स्थित वास्तविक सम्पत्ति आदि भी आती है। जिस प्रकार विदेश में स्थित सम्पत्ति की खरीददारी को पूँजी का निर्यात माना जाता है, उसी प्रकार देश में स्थित विदेशी पूँजी की खरीददारी को भी पूँजी का निर्यात माना जाएगा। यदि एक व्यक्ति सम्पत्ति में स्थित अमेरिकी रेलवे कम्पनी के बॉण्ड्स खरीदता है तो यह सम्पत्ति उसके स्वयं के देश में स्थित रहते हुए भी पूँजी का निर्यात कहो जाएगी। आयात के प्रसंग में यहाँ यह बात मुख्य है कि खरीददारी दूसरे देश के निवासियों से की जा रही है। दूसरी ओर विदेशों में स्थित स्वदेशवासियों से यदि किसी सम्पत्ति को खरीदा जाता है तो इसे पूँजी का निर्यात नहीं कहा जाएगा। यहाँ विदेशी प्रतिभूति से हमारा अर्थ ऐसी प्रतिभूति से है जो अपने पूर्व-स्वामि के कारण विदेशी होती है। केवल विदेशों में स्थित होने के कारण ही हम इसको विदेशी नहीं कह सकते।

विदेशी प्रतिभूतियों को कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खरीदा जाता है। जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि एक अमेरिकन व्यक्ति किसी कनाडावासी या अंग्रेज या पश्चिमी निवासी से प्रतिभूतियाँ क्यों खरीदता है तो हम पाएँगे कि यह निर्यात उसने कीमतों के आकर्षण होने के कारण किया है। पूँजी का बहुत कुछ आयात-निर्यात कीमतों के बीच पाए जाने वाले अन्तर के कारण होता है।

पूँजी के आवागमन से सम्बन्धित व्यापक सहमति के लिए हम एक उदाहरण पर विचार कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम एक पूर्णतः सुरक्षित बॉण्ड पर विचार करें। इस प्रकार का बॉण्ड प्रत्येक वर्ष एक निश्चित धन के भुगतान का वायदा करता है। मान लीजिए यह 500 रुपये हैं, इसके परिपक्व होने पर वह मूलधन का भुगतान करेगा। मान लीजिए वह दस हजार रुपये हैं। वर्तमान समय में दी गई व्याज की मात्रा को कितना महत्व दिया जाएगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्याज की दर क्या है? यदि व्याज की दर नीची है तो भविष्य में चुकाए जाने वाले धन की मात्रा पर्याप्त मूल्यवान बन जाएगी और यदि व्याज की दर ऊँची है तो उसको कम महत्व दिया जाएगा। व्याज की दर जिननी ऊँची होगी प्रतिभूति का मूल्य उतना ही नीचा होगा और दर जिननी नीची होगी उसकी कीमत उतनी ही ऊँची होगी।

पूँजी के आवागमन निर्यात का न होना व्याज की एक जैसी दर का आवश्यक

परिणाम नहीं है। एक देश में व्याज की दरें बहुत कुछ उन नीतियों पर आधारित रहती हैं जो उस देश के बैंको तथा भौतिक संस्थाओं द्वारा अपनाई गई हैं। इन नीतियों को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किया जाता है। इनको कोई अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता निर्धारित नहीं करती, यह हो सकता है कि एक समय में एक देश धन से सम्बन्धित सरल नीति अपनाएँ। ऐसी स्थिति में उस देश में व्याज की दर कम होगी। दूसरा देश उसी समय प्रतिरोध की नीति अपना सकता है और इसलिए वहाँ व्याज की दरें अधिक होंगी।

यदि एक स्थिति में दो देशों के समस्त व्ययकर्त्ताओं को एक जैसा जोखिम उठाना पड़ता है तो व्याज की दर में किसी प्रकार का अन्तर भी अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी के आवागमन का कारण बन जाएगा। व्याज की उच्च-दर वाला देश, दूसरे देश से पूँजी का आयात करेगा और उस समय तक करता रहेगा जब तक कि परिस्थितियाँ न बदल जाएँ। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि पूँजी को उस देश में आकर्षित किया जाएगा जहाँ वह उच्च व्याज की दर कमा सके।

कुछ लेखकों का कहना है कि उपर्युक्त स्थिति पर्याप्त धवास्तविक है। यदि पूँजी की प्रवाह को बिना प्रतिबन्ध लगाए रखा गया तो दो देशों में व्याज की दर एक जैसी बन जाएगी क्योंकि पूँजी के निर्यातकर्त्ता देश के बैंको का सुरक्षित भण्डार धीरे-धीरे कम होता चला जाएगा और इसलिए वे भी कुछ समय बाद दर बढ़ाने के लिए बाध्य होंगे। दूसरी ओर पूँजी के आयात करने वाले देश के बैंको का सुरक्षित भण्डार बढ़ जाएगा, इसके फलस्वरूप वह देश व्याज की दर बढ़ाने के लिए चाहे बाध्य न हो किन्तु फिर भी इस दृष्टि से सोच सकता है।

जोखिम—जिन बॉण्ड्स को प्रत्येक देश द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित माना जाता है, उनके सम्बन्ध में भी दृष्टिकोण का अन्तर रह सकता है। व्ययकर्त्ता के जोखिम का सम्बन्ध न केवल प्राप्त किए जाने वाले व्याज से रहता है वरन् इससे भी रहता है कि यदि भविष्य में कभी वह अपने बॉण्ड को देवना चाहे तो उसको क्या कीमत मिल सकेगी? यह हो सकता है कि संयुक्तराज्य अमेरिका की सरकार द्वारा प्रसारित बॉण्ड के प्राप्तकर्त्ता व्याज के भुगतान और मूलधन के पुनर्भुगतान में पूर्ण रूप से सुरक्षा का अनुभव करें किन्तु वे उस बॉण्ड के परिपक्व होने से पहले किस कीमत पर बेच सकते हैं। इस सम्बन्ध में अलग-अलग मत हो सकते हैं। कुछ व्ययकर्त्ता यह सोच सकते हैं कि भविष्य में बाजार अपरिचित रहेगा और कल भी यही भाव रहेगा जो आज है। इस प्रकार भविष्य में कीमतों की वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है यतः व्ययकर्त्ताओं का दृष्टिकोण एक रूप नहीं होता। उनके मध्य स्थित विभिन्नता के कारण पूँजी के आवागमन में अन्तर आ जाता है।

कीमतें—जब पूँजी का आवागमन कीमतों के अन्तर के कारण होता है तो ऊँची कीमतें एक विज्ञेता को प्रतिभूति छोड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। पूँजी के आवागमन को जारी रखने के लिए विज्ञेता देश की दृष्टि से कीमतें निरन्तर बढ़ती चली चाहिए। दूसरी ओर खरीददार देश की दृष्टि से कीमतों को कम से कम होना

चाहिए। इस प्रकार विज्ञेता देश में कीमतों के बढ़ने और खरीददार देश में कीमतों के घटने की प्रवृत्ति रहती है तभी उनके बीच पूँजी का आवागमन हो पाता है। जब कीमतें एक दूसरे के अत्यन्त निकट आ जाती हैं और सस्ता खरीदने और महंगा बेचने से प्राप्त होने वाले लाभ के अवसर कम हो जाते हैं तो पूँजी का आवागमन रुक जाता है।

दृष्टिकोण का परिवर्तन—उक्त विचार-विमर्श के बाद हम इस महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यदि हम ऐसी समतुल्य स्थिति से प्रारम्भ करें जिसमें कि पूँजी का कोई आवागमन नहीं रहा है तो मौद्रिक नीति में थोड़ा व्ययक्तार्थों के दृष्टिकोण में किसी प्रकार का भी परिवर्तन होने से पूँजी का आवागमन प्रारम्भ हो जाएगा। यदि एक देश के व्ययक्तार्थ अधिक आशावादी दृष्टिकोण अपना लें और विदेशों से प्रतिभूतियाँ खरीदने पर उनके ऊपर कोई प्रतिबन्ध न हो तो वे पूँजी के आवागमन को सम्भव बना देंगे। पूँजी का निर्यात केवल उन्हीं देशों को किया जाता है जिनके व्ययक्तार्थ अधिक आशावादी होने हैं। दूसरे देशों से पूँजी का केवल आयात किया जाता है, पूँजी का आवागमन इसलिए भी प्रारम्भ होता है क्योंकि वैक व्यवस्था की नीति के परिणामस्वरूप एक देश में व्याज की दर कम हो जाती है और दूसरे में वे उच्च की लो बनी रहती हैं। इस प्रकार व पूँजीगत आवागमन से उस देश से पूँजी का निर्यात किया जाएगा तथा उस देश में प्रतिभूतियों का आयात किया जाएगा जिसमें व्याज की दरें कम हैं।

भविष्यवाणियाँ—कीमतों के परिवर्तनों के सम्बन्ध में भविष्यवाणियाँ पर्याप्त महत्वपूर्ण होती हैं। सट्टेबाज इस दृष्टि से पर्याप्त महत्त्व रखते हैं। वे आज इस आशा से व्यापार करते या खरीददारी करते हैं कि कल वे ऊँची कीमतों में बिक्री कर सकेंगे। इस प्रकार के व्ययक्तार्थों को उनसे भिन्न माना जाएगा जो प्रतिभूतियों की प्राप्ति केवल आकर्षक व्याज अथवा लाभांश के कारण करना चाहते हैं। वैसे अनेक व्ययक्तार्थ सट्टेबाजों की मनोभावना से प्रभावित रहते हैं।

प्रतिभूतियों के प्रकार—अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जिन प्रतिभूतियों का व्यापार किया जाता है उनका प्रकार भी पर्याप्त महत्त्व रखता है। इस दृष्टि से बाँड्स का नाम उल्लेखनीय है। इनके अतिरिक्त स्टॉक, प्रमाण-पत्र आदि भी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। यदि एक व्यापारी किसी स्टॉक के एक सौ अंश खरीदता है तो वह अपनी खरीददारी व्याज की आशा से नहीं करता क्योंकि वह अपना धन उधार नहीं दे रहा है वरन् वह एक फर्म के स्वामित्व को खरीद रहा है। उसको मिलने वाला प्रतिदान व्याज के रूप में नहीं वरन् लाभांश के रूप में होगा। यहाँ मूलधन के लौटने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार की प्रतिभूतियों से होने वाली आय, बाँड्स से प्राप्त होने वाली आय से सुरक्षित होती है क्योंकि लाभांश की दर के सम्बन्ध में कोई गारण्टी नहीं दी जाती वरन् वह कुछ प्रतिबन्धों के साथ निर्देशकों के निर्णय पर निर्धारित होती है।

प्रतिभूतियों के बीच स्थित पर्याप्त अन्तर भी पूँजी के आवागमन का कारण

वनता है। एक देश में प्रसारित प्रतिभूतियाँ दूसरे देश में प्रसारित प्रतिभूतियों से भिन्न हो सकती हैं। हो सकता है कि संयुक्तराज्य अमेरिका में प्रसारित प्रतिभूतियों तथा किसी भी अर्द्ध-विकसित देश की प्रतिभूतियों के बीच महान् अन्तर हो। यह अन्तर प्रतिभूतियों की स्वीकृति में पर्याप्त महत्त्वपूर्ण बन जाता है। उनकी दर चाहे कुछ भी हो किन्तु इस अन्तर के कारण कई बार प्रतिभूतियाँ स्वीकृत या अस्वीकृत बन जाती हैं। अमेरिका के व्ययकर्त्ता इस प्रकार की विदेशी प्रतिभूतियों को प्राप्त करने में प्रायः रुचि नहीं लेते।

पूँजी के आवागमन की दृष्टि से यह प्रश्न पर्याप्त महत्त्व रखता है कि व्ययकर्त्ता की भावनाओं में परिवर्तन कैसे आ सकता है? विभिन्न विकास व्ययकर्त्ता की आकांक्षाओं को परिवर्तित कर देते हैं। इनको दो शीर्षकों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रथम भाग के अन्तर्गत उन परिवर्तनों को लिया जा सकता है जो विदेशी व्यय से होने वाली कुछ प्राप्ति से होते हैं और दूसरे भाग में वे परिवर्तन आते हैं जो देश में वैकल्पिक व्यय के कलस्वरूप होने वाली प्राप्ति से होते हैं।

पूँजी के आवागमन को प्रभावित करने वाले अनेक कारणों में से कुछ प्रमुख निम्न प्रकार हैं—

1. राजनीतिक विकास (Political Development)—राजनीतिक विकासों का महत्त्वपूर्ण प्रभाव होता है। यदि एक देश में राजनीतिक स्थायित्व को चुनौती प्राप्त होती है तो दूसरे देश के व्ययकर्त्ता को उस देश की प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में निराशापूर्ण दृष्टिकोण अपनाना होगा। उदाहरण के लिए, उसे यह भी डर हो सकता है कि उसकी प्रतिभूतियों को जप्त कर लिया जाएगा। सम्भवतः यह सबसे बड़ी बाधा है जिसके कारण वर्तमान समय में कुछ अर्द्ध-विकसित अर्ध-व्यवस्थाओं में पूँजी का भारी निर्मात नहीं किया जाता। इन देशों में पूँजी के आयात का स्तर बहुत नीचा होता है। इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक अस्थिरता के खतरे और भी अधिक गम्भीर बन जाते हैं। इस प्रकार के आयातों के बिना देश का आर्थिक विकास अत्यन्त घीमा हो जाता है। इससे भारी असन्तोष पैदा होता है और सम्भावित व्ययकर्त्ता के लिए कम आकर्षक वातावरण तैयार होता है। इस प्रकार के विकास के कारणों को रोकने के लिए जब तक कुछ नहीं किया जाता स्थिति निरन्तर बदलती जाती है।

2. मत परिवर्तन (Shifts in Opinion)—इस दृष्टि से एक अन्य महत्त्वपूर्ण बात विदेशी बाजारों से सम्बन्धित मतों के परिवर्तन से सम्बन्ध रखती है। उदाहरण के लिए, जब एक देश के लोगों में यह भावना बढ़ती है कि दूसरे देश की मुद्रा के दाम गिर रहे हैं तो उस देश के व्ययकर्त्ता अपने व्यय में कमी कर देते हैं; दूसरे देश के विनिमय की बदलती स्थिति भी एक देश के मूल्यों को गिरा देती है और इस प्रकार उनके बीच पूँजी का आवागमन रुक जाता है। इस स्थिति में यह भय बढ़ जाता है कि व्ययकर्त्ता को अपने धन का उचित प्रतिदान नहीं मिल पाएगा।

और उसका व्यय निष्फल रहेगा। यदि इस प्रकार का डर व्यापक बन जाए तो इसके परिणामस्वरूप एक देश दूसरे देशों को अपनी सम्पत्ति का निर्यात नहीं करेगा। दूसरे देशों में भी जब इस प्रकार का भय उत्पन्न हो जाएगा तो वे पूंजी का आयात नहीं करेंगे।

3 साधन खोज की खोज (The Discovery of Resources)—जब अन्य देशों में साधनों की खोज की जाती है तो भी एक देश के व्ययकर्त्ताओं को पर्याप्त लाभ प्राप्त होता है। विदेशों में व्यय करने से लाभ की सम्भावनाएँ प्रायः उस समय बढ जाती हैं जब दूसरे देशों के साधनों की खोज से लाभ उठान की नीति को जाना जा सके। उदाहरण के लिए जब पश्चिमी कनाडा में सबसे पहले पेट्रोल के सुरक्षित भण्डारों का पता लगाया गया तो अमेरिकी व्ययकर्त्ताओं को पर्याप्त आशा बनी और उन्होंने कनाडा की प्रतिभूतियाँ खरीदने में रुचि प्रदर्शित की।

4 विश्व माँग में परिवर्तन (Changes in World Demand)—जब विश्व की माँग में परिवर्तन होते हैं और इनके स्थायी रहने की आशा रहती है तो इनसे विभिन्न देशों पर पड़ने वाले प्रभावों का कुछ अनुमान लगाना सम्भव होता है तो उससे पूंजी का आवागमन भी प्रभावित हो सकता है क्योंकि इससे उत्पादन की आकांक्षाओं की प्रवृत्तियाँ प्रभावित हानी हैं। जब एक लम्बे समय तक सैनिक उत्पादन की माँग पर्याप्त उच्च बनी रहनी है तो सौदा, यूरैनियम, टिन आदि साधनों में सम्पन्न देशों की कुछ फर्मों का अधिक लाभ प्राप्त होना है और तब इन उद्यमों में धन लगाना बुद्धिपूर्ण समझा जाएगा।

5. भण्डार के बाजार (The Stock Market)—एक देश के भण्डार में होने वाले विकास भी दूसरे देशों के व्ययकर्त्ताओं के दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। बाजार चाहे गिरे अथवा उठे, प्रवृत्ति हमेशा यह रहती है कि परिवर्तन का सन्तुलन होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि सन्दन में बाजार उठ रहा है तो अमेरिकी व्यापारी यह सोच सकना है कि वहाँ अधिक से अधिक प्रतिभूतियाँ खरीदी जाएँ; जब एक बार शीर्ष के स्तर को प्रभावित कर दिया जाए तो अन्य दिशाओं में भी यह प्रवृत्ति बढ़ती है।

6 कर नीतियों में परिवर्तन (Changes in Tax Policies)—जब कर नीतियों में परिवर्तन किया जाता है और इस परिवर्तन द्वारा भेदभाव की नीति को अपनाया जाता है तो इसमें विदेशी व्ययकर्त्ता का मार्ग या तो मजबूत हो जाता है या सुगम बन जाता है। ऐसी स्थिति में पूंजी का आवागमन पर्याप्त बदल जाता है। यदि एक देश व्यापार के समस्त लाभों पर एक सी दर से कर लगाना है तो वह उन नियमों के लाभों पर भी कर लगाएगा जो कि विदेशियों द्वारा नियमित हैं। वह उन लाभों पर भी कर लगा देगा जो गैर निवासियों को मिलने वाले हैं। ऐसा करने से विदेशी व्ययकर्त्ताओं की आकांक्षा पर पानी फिर जाएगा और वे उस देश में अपने व्यय से होने वाले लाभों के सम्बन्ध में पुन विचार करेंगे।

7 घरेलू स्थिति (Domestic Situation)—जब घरेलू स्थिति कम

अनुकूल रह जाती है तो इसके परिणामस्वरूप देश में प्रतिभूतियों की खरीददारी के सम्बन्ध में निराशावादी दृष्टिकोण का प्रभाव हो जाता है। इस दृष्टिकोण से प्रभावित होकर विदेशी व्ययकर्त्ता भी प्रतिभूतियाँ नहीं खरीदते। जब घरेलू नियमों पर कर की दर की वृद्धि दूसरे देशों की बढ़ी हुई दरों से काफी आगे हो तो इसके परिणामस्वरूप पूँजी का निर्यात होगा क्योंकि अब इस देश में करों की मात्रा अधिक है तो विदेशी नियम के भण्डार अधिक आकर्षक बन जाएँगे।

8. कुछ अन्य कारण (Some Other Reasons)—पूँजी के आवागमन को कुछ अन्य कारणों द्वारा भी प्रोत्साहन दिया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के साथ पूँजीगत आवागमन स्वतः होने लगता है। जब एक देश में कोई आयात करता है तो उसे कुछ न कुछ निर्यात करने का भी प्रवण करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उसे खरीदी गई, चीजों के दाम देने पड़ेंगे। सम्भवतः यह भी हो सकता है कि वह निर्यातकर्त्ता से साख प्राप्त करले अथवा अपने देश से ही आवश्यक विदेशी विनिमय या सोना प्राप्त करले। प्रत्येक स्थिति में पूँजी का आयात करना पड़ेगा। जब एक देश अपने निर्यात को बढ़ाएगा तो उसका आयात भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा। व्यापार से सम्बन्धित आयात बढ़ने पर पूँजी का आवागमन जन्म लेता है और उसे कोई भी प्रतिबन्ध नहीं रोक सकता।

जिस प्रकार माल और सेवाओं के व्यापार में सन्तुलन स्थापित करने के लिए पूँजी के आवागमन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार दूसरे देशों से प्रतिभूतियों की खरीददारी एवं विनी भी आवश्यक बन जाती है। जब एक देश में व्ययकर्त्ता दूसरे देश की प्रतिभूतियाँ खरीदने की ओर प्रेरित होते हैं तो ऐसा करने के लिए या तो उनको अपने देश के विदेशी विनिमय भण्डार कम करने होते हैं अथवा अपने देश की मुद्रा दूसरे देश के निवासियों के हाथ में देनी होती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ये खरीददार या तो इन प्रतिभूतियों के लिए भुगतान करेंगे अथवा नहीं करेंगे। यदि वे भुगतान करते हैं तो किसी न किसी प्रकार पूँजी का आवागमन होकर रहेगा और यदि वे भुगतान को अविव्य के लिए छोड़ देते हैं तो भी पूँजी का आवागमन होता है, यद्यपि यह आवागमन भिन्न प्रकार का होता है। एक देश माल, सेवाओं एवं प्रतिभूतियों का निर्यात करते समय भी पूँजी के आवागमन को प्रोत्साहन देता है।

उक्त प्रकार के पूँजी के आवागमन एक प्रकार से सन्तुलन स्थापित करने के लिए होते हैं। यदि एक देश के आयात उसके कुल निर्यात से आगे बढ़ जाते हैं तो उनके बीच सन्तुलन स्थापित करने के लिए पूँजी का आयात किया जाता है। यदि सम्बन्धित देश पूँजी के आयात की अनुमति न दे तो विदेशों से खरीद करने के इच्छुक आयातकर्त्तों को यह महसूस होगा कि वे भुगतान करने में प्रमथित हैं। ऐसी स्थिति में आयातों के प्रतिरोध को उनकी पूँजी के आयात द्वारा सन्तुलित करना चाहिए।

कभी-कभी सुविधा की दृष्टि से भी सन्तुलन करने वाले पूँजी के आवागमनों का रूप निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए एक देश के निर्यातकर्त्ता यह

मान सकते हैं कि उनको विदेशी उपभोक्ताओं की आजाएँ उस समय तक प्राप्त नहीं होगी जब तक कि वे अपनी साख को यथार्थ में प्रसारित न करें। इस प्रकार आयातकर्त्ता देश के लिए यह आवश्यक बन जाता है कि वह अपने विदेशी विनिमय और सोने के सुरक्षित भण्डारों को काम में लाए। यदि इसे निर्यातकर्त्ताओं की दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञात होगा कि वे इस साख को आयातकर्त्ताओं तक प्रसारित करने का प्रबन्ध करते हैं। उनके द्वारा जब रियायत बाजारों को ढूँढ़ने के लिए भी कठिनाई का अनुभव किया जाएगा तो वे भुगतान की तारीख को बदल देंगे। आयातकर्त्ता को खरीददारी करने के लिए सुविधाजनक साख की शर्तों का प्रबन्ध करना पड़ता है और इस प्रकार निर्यातकर्त्ता अथवा बैंक द्वारा अल्पकालीन पूँजी के आवागमन को प्रारम्भ किया जाता है। दूसरी ओर आयातकर्त्ता भी समय-समय पर निर्यातकर्त्ता को साख की सुविधाएँ प्रदान करता है। निर्यातकर्त्ता भी अपने उत्पादन की लागत को पूरा करने के लिए धन उधार ले सकता है। यदि लागतकर्त्ता वस्तु के प्राप्त होने से पहले ही भुगतान कर देता है तो इसे भी पूँजीगत आवागमन समझा जाएगा।

पूँजीगत आवागमन कभी-कभी स्वेच्छापूर्ण होते हैं जबकि दूसरे समय में वे इतने स्वेच्छापूर्ण नहीं होते। एक देश के व्यापारी समय-समय पर यह अनुभव कर सकते हैं कि जिस देश में उन्होंने व्यय किया है वहाँ से वे उब धन को वापिस न ले पाएँगे और न ही वे अपनी प्रतिभूतियों के व्याज का भुगतान प्राप्त कर पाएँगे। इस प्रकार की स्थिति 1933 के बाद जर्मनी में पैदा हुई थी। उस समय जिन अमेरिकियों के पास जर्मनी की प्रतिभूतियाँ थी, उनको यद्यपि जर्मनी की मुद्रा (Mark) में व्याज लगातार मिल रहा था किन्तु फिर भी वे इस मुद्रा को अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करने के लिए स्वतन्त्र नहीं थे। ऐसी स्थिति में इन अमेरिकी व्यापारियों को जितना व्याज प्रतिवर्ष प्राप्त होना था उतना ही वे जर्मनी को कर्ज में दे देते थे। इस प्रकार वे कर्ज इच्छापूर्ण नहीं बल्कि बाध्यकारी थे। यद्यपि ये व्यापारी चाहते थे कि प्राप्त की गई जर्मन मुद्रा को डॉलर में बदल दें किन्तु वे ऐसा करने में असफल थे।

कभी-कभी व्यापारिक विचार-विमर्श की अपेक्षा दबावों के कारण भी पूँजी का आवागमन सम्भव बनता है। एक कर्ज लेने वाला देश अपने कर्ज का एक भाग किसी निश्चित तारीख को चुकाने के लिए सहमत होता है और जब समय आता है तो वह उनका निर्यात करने के लिए बाध्य होता है किन्तु इस प्रकार का निर्यात आय प्राप्ति की आशाओं से या पूँजी प्राप्त करने अथवा व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं किया जाता बल्कि उसकी मजबूरी होती है।

ऊपर पूँजी के जिन आवागमनों का वर्णन किया गया है उनकी प्रकृति निर-सरकारी है किन्तु प्राधुनिक समय में अनेक पूँजीगत आयात-निर्यात सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं।

पूँजी की सरकारी अन्तर्राष्ट्रीय गति के कारण
(The Reasons of the Official International Capital Movement)

सरकार द्वारा जिस पूँजीगत आवागमन की पहल की जाती है वह 1945 के

बाद के व्यक्तिगत पूंजीगत आवागमन की अपेक्षा बड़े आकार का है। यद्यपि व्यक्तिगत लेन-देन को प्रभावित करने वाली शक्तियों का विस्तार के साथ वर्णन किया जा सकता है किन्तु सरकार द्वारा प्रेरित तथ्यों के बारे में अधिक कुछ कहना अत्यन्त कठिन है।

सरकारी नीति के निर्धारण की कठिनाइयाँ—सरकार की नीतियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना सरल नहीं है। जिस प्रकार हम व्यक्तिगत व्ययकर्ता के बारे में कहते हैं कि वह आर्थिक प्राप्ति चाहता है, सरकार के उद्देश्यों को इतनी निश्चितता के साथ हम नहीं कह सकते, यद्यपि उनका महत्त्व भी कुछ कम नहीं होता, लाभ और हानि की माग्यनाएँ बहुत कुछ निश्चित होनी हैं और इनको भासानी से समझा जाता है किन्तु सामान्य कल्याण जो कि सरकारी व्यय का एक उद्देश्य बताया जाता है, उतना निश्चित नहीं होता। सामान्य कल्याण के अन्तर्गत जो विभिन्न बातें आती हैं उनको पूर्यक् से न तो जाना जा सकता है और न ही उनकी व्याख्या की जा सकती है। इसके अन्तर्गत हम जनसंख्या के आर्थिक कल्याण, आश्रमण से सुरक्षा और राजनीतिक स्वायत्तता आदि बातों को ले सकते हैं किन्तु इनमें से प्रत्येक उद्देश्य अपने आप में जटिल है। जनता के आर्थिक कल्याण में हम सभी के लिए उच्च आयदनी, आय को दर में उपयुक्त वृद्धि, आय का व्यापपूर्ण वितरण और वेचे गए माल का उपयुक्त प्रकार भावि बातों को सम्मिलित कर सकते हैं। ये सभी उद्देश्य अपेक्षाकृत सामान्य हैं और इनकी संक्षिप्त रूप से इंगित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सरकार की क्रियाओं के सम्बन्ध में ये विभिन्न स्पष्टीकरण अधिक सार्थक प्रतीत नहीं होते। सरकार द्वारा जिस पूंजी के आवागमन को प्रोत्साहित किया जाता है, उसके पीछे कई कारण होने हैं और इनकी समझने के बाद सम्भवतः विषय अधिक स्पष्ट हो जाएगा।

सरकारी ऋण के कारण (Causes of Public-debts)—सरकार के द्वारा जब दूसरे देशों को ऋण प्रदान किए जाते हैं तो इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी होते हैं। उदाहरण के लिए, उस सरकार को यह बर रह सकता है कि यदि ऋण न दिया गया तो दूसरा देश उसके उत्पादन को नहीं खरीद पाएगा। एक देश की सरकार अपने देश के उत्पादन का आयात करने के लिए दूसरे देशों को प्रोत्साहित करती है। आर्थिक मन्दी के समय सरकार द्वारा बाजार के आकार को बढ़ाने में विशेष रुचि प्रदर्शित की जाती है क्योंकि इससे देश के उत्पादन, आय, लाभ और रोजगार में वृद्धि होती है। यह तर्क न केवल आर्थिक मन्दी के समय बल्कि साधारण समय में भी महत्त्व रखता है, यद्यपि सम्पन्नता की स्थिति में बाजारों की रचना इतनी अधिक तात्कालिक नहीं होती, किन्तु फिर भी आने वाले भविष्य में इसका पर्याप्त महत्त्व होता है।

सरकार द्वारा निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, 1934 में स्थापित अमेरिकी आयात-निर्यात बैंक का प्रारम्भ में उद्देश्य यह था कि राष्ट्रीय पाय में वृद्धि के लिए निर्यातों को बढ़ावा दें।

कभी कभी एक सरकार अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए केवल इसलिए कर्जा नहीं देती कि उसे बाजार की आवश्यकता है वरन् इसलिए देती है कि ऋण लेने वाले देश को आयात करना चाहिए। उदाहरण के लिए, वह राजनीतिक या सैनिक कारणों से उधार लेने वाले देश की आर्थिक भक्ति का उच्च बनाने का प्रयास कर सकती है। इसके अतिरिक्त जब एक बार कर्ज लेने वाला देश विकास के सन्तोषजनक स्तर पर पहुँच जाएगा तो वह कर्जदाता देश के लिए कच्चे मान तथा अन्य सामग्रियाँ आसानी से भेज सकेगा।

पूँजी के निर्यात करने की स्थिति में रहने वाली सरकार मित्रतापूर्ण विचारों अथवा अतीत के लाभों से प्रेरित होकर भी पूँजी का निर्यात कर सकती है। एक देश की सरकार को कभी-कभी यह भी डर लगना है कि यदि दूसरे देश में स्थित सरकार का पतन हो गया तो उसके स्थान पर आन वाली सरकार कम मैत्रीपूर्ण हो सकती है, अतः वह उसका समर्थन करके उसे पतनोन्मुख होने से बचाती है।

कभी-कभी एक सरकार दूसरे देश को इसलिए भी पूँजी भेजती है कि यदि उसने ऐसा नहीं किया तो दूसरे देश द्वारा ऐसे आर्थिक निर्णय लिए जा सकत हैं जो उसके लिए नुकसानदायक होंगे। वे सम्भवतः सम्भावित कर्जदारों पर बुरा प्रभाव डालेंगे। एक देश के सामने ऐसी स्थिति उपस्थित हो सकती है कि वह आवश्यक आयातों के लिए मुक्तान न कर सके। ऐसा करने के लिए उसे या तो अपनी मुद्रा का मूल्य घटाना होगा अथवा कम महत्वपूर्ण आयातों की मर्यादा को एकदम कम करना होगा। इस प्रकार के प्रयास दूसरे देशों के लिए कष्टदायक होने हैं और इसीलिए वे सफलता प्राप्त कर लेते हैं, किन्तु दूसरे देश भी बदने की ऐसी नीतियाँ अपना सकते हैं और ऐसा होना पर ये नीतियाँ फलहीन बन जाएँगी। जब इस प्रकार की गर्दनतोड़ प्रतिद्वन्द्विता विभिन्न देशों के बीच कायम हो जाएगी तो किसी देश को लाभ नहीं होगा। इस प्रवृत्ति के प्राग्भ होने से पहले ही रोकने के लिए पूँजी के आवागमन का सहारा लिया जाएगा।

विकास और विनिमय श्यायित्व के उद्देश्यों के बीच बहुत कम अन्तर रहता है। 1945 के दौरान संयुक्तराज्य अमेरिका ने ग्रेट-ब्रिटेन को जो कर्ज दिए हैं वे इन दोनों की ही पूर्ति करते थे। अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों को युद्ध के बाद जो सहायताएँ प्रदान की वे भी इस प्रकार के योगदान के उदाहरण हैं। ये विभिन्न कर्ज इन अर्थ-व्यवस्थाओं की पुन रचना में सहायता करने के उद्देश्य से दिए गए। ई आर पी (European Recovery Programme) के अन्तर्गत सम्बन्धित देशों की अर्थ-व्यवस्था को पुन मुधारने के लिए भारी मात्रा में धन की व्यवस्था की गई, क्योंकि युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही के कारण इन देशों की अर्थ-व्यवस्था पर्याप्त त्रिस्तरीय चुकी थी।

सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रेरणाओं के बीच अन्तर

सरकारी व्ययकर्ता की रचि एवं व्यक्तिगत व्ययकर्ता की रचि के बीच उद्देश्यों की विभिन्नता होती है। व्यक्तिगत व्ययकर्ता कभी-कभी तो सरकार द्वारा

प्रेरित होते हैं किन्तु प्रायः उनको सरकार से कोई प्रेरणा नहीं मिलती। कभी-कभी व्यक्तिगत व्ययकर्त्ताओं के हित परिस्थिति की आवश्यकताओं के ठीक विपरीत सिद्ध होते हैं। एक सरकार को जिस बात का भय रहता है उसी बात को प्रेरित करने के लिए कई बार व्यक्तिगत व्ययकर्त्ता अपनी नीतियों को संचालित करते हैं।

एक सरकार के कार्यों की प्रेरणाएँ वे भी हो सकती हैं जो कि व्यक्तिगत व्ययकर्त्ता की नहीं होती। एक देश अपनी सरकार के माध्यम से एक ऐसे देश में पर्याप्त पूँजी भेज सकता है जिसकी मुद्रा अवमूल्यन के नजदीक पहुँच गई थी। यदि अवमूल्यन से एक देश को कोई भय नहीं है तो भी वह सम्बन्धित देश की सहायता कर सकता है।

कई कारणों से एक सरकार व्यक्तिगत व्ययकर्त्ताओं के हाथ में निर्यात की शक्ति छोड़ने की अपेक्षा स्वयं ही पूँजी के आवागमन के सम्बन्ध में निर्यात लेती है। उदाहरण के लिए, यदि एक देश आर्थिक संकट का अनुभव कर रहा है जिसे वह विदेशों में अपने बाजार का प्रसार करके दूर कर सकता है तो इस तथ्य की जानकारी के बाद उसके पड़ोसी देशों के व्ययकर्त्ता उसे श्रृणु प्रदान करके बाजारों की रचना का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जोखिम है।

सरकार जब पूँजी के आवागमन को प्रोत्साहन देती है तो उसका स्पष्ट उद्देश्य यह नहीं होता कि वह केवल लाभ प्राप्ति के लिए ऐसा करे। दूसरी ओर व्यक्तिगत व्ययकर्त्ता हमेशा सम्पन्नता और लाभ को ध्यान में रख कर ही आगे बढ़ता है। सरकार राजनीतिक मित्रता के लिए तथा दूसरे देशों के साथ सैनिक सन्धि का निर्वाह करने के लिए भी पूँजी के आवागमन में रुचि ले सकती है। सरकार के सामने ऐसी घनेक परिस्थितियाँ आ जाती हैं जबकि उसे पूँजी के आवागमन का प्रवन्ध करना होता है। यदि वह इन परिस्थितियों में इस कार्य को व्यक्तिगत व्ययकर्त्ताओं के हाथ में छोड़ दे तो इसके कलस्वरूप कोई कार्य नहीं किया जाएगा क्योंकि उपर्युक्त प्रेरणाओं के अभाव में व्यक्तिगत व्ययकर्त्ता कोई रुचि नहीं लेंगे।

सरकार जिस प्रकार के पूँजीगत आवागमन में भाग लेती है उसके कई रूप हो सकते हैं। कभी-कभी इसका रूप प्रत्यक्ष वर्ज होता है। इस प्रकार के कर्ज प्रायः दीर्घकालीन होते हैं और सरल शर्तों पर प्रदान किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब अमेरिकी आयात-निर्यात बैंक ने पुनः रचना के लिए कर्ज दिए तो कर्ज लेने वालों को पुनः भुगतान के लिए 20 या 30 वर्ष की छूट दी गई तथा उनसे बहुत कम व्याज की दर (3%) प्राप्त की गई।

वर्ज और अनुदान दो अलग-अलग चीजें हैं और इनके बीच पर्याप्त अन्तर होता है। अनुदान प्राप्त करने वाला देश उसके व्याज या मूलधन का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होता। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि एक सरकार इन शर्तों पर पूँजी का निर्यात क्यों करती है? सरकार धन को पूरी तरह से छोड़ने की अपेक्षा उसे वापिस लेने का प्रयास क्यों नहीं करती? इन प्रश्नों का उत्तर उस देश के भावी स्वार्थ में पाया जाता है। अनुभव ने यह प्रदर्शित किया है

कि यदि एक देश की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है और विदेशी कर्ज का मुग्तान करने का भार भी उसके ऊपर डाल दिया जाए तो वह पर्याप्त कमजोर हो जाएगा। जब युद्ध के दौरान दो देश सैनिक दृष्टि से मिन होते हैं तो वे अपनी मित्रता को सैनिक सक्षमों के अतिरिक्त अन्य सक्षमों की प्राप्ति के लिए भी प्रयुक्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए ये परस्पर सहयोग कर सकते हैं।

एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार को पूँजी का निर्यात करने की अपेक्षा अन्य प्रकार के प्रबन्ध को भी अपना सकती है। पूँजी का निर्यात करने वाले देश की सरकार स्वयं कर्जा देने की अपेक्षा अपने देश के व्ययकर्त्ताओं को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। इसके लिए वह कर्जदानाओं को यह गारन्टी प्रदान करेगी कि कर्ज लेने वाले अपने धरेलू वित्तीय बाजार पर दबाव डालकर दूसरी सरकार की आवश्यकताओं को पूरी करने की वांछनीयता पर जोर दे सकती है।

कभी-कभी सरकारों के बीच कर्ज का प्रबन्ध अन्य तरीकों से भी किया जाता है। एक सरकार पुनर् रचना और विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (International Bank for Reconstruction & Development) जैसे अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के माध्यम से प्रणिभूतियाँ खरीद सकती है अथवा अनुदान दे सकती है। यह अभिकरण दूसरे देशों को धन उधार देगा। इसी प्रकार एक अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण व्यक्तिगत व्ययकर्त्ताओं से धन प्राप्त करके उन्हें किसी सरकार को देने की अपेक्षा व्यक्तिगत उद्यमों में ही लगा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकारों के बीच पूँजी का आवागमन कई प्रकार से प्रभावित हो सकता है। पूँजी उधार देने वाली सरकार सकीर्ण आर्थिक, राजनैतिक या युद्ध कौशल सम्बन्धी विभिन्न कारणों से प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्त अनेक मानवीय कारण भी इस पर प्रभाव डालते हैं। आजकल व्यक्तिगत व्ययकर्त्ताओं की अपेक्षा सरकार की पहल द्वारा किए गए पूँजी आवागमन अधिक दिखाई देते हैं। इस प्रकार का विकास कोई आश्चर्य की बात नहीं क्योंकि व्यक्तिगत लोगों की अपेक्षा सरकारी व्ययकर्त्ता की प्रेरणा के स्रोत अनेक होते हैं। व्यक्तिगत व्ययकर्त्ता के सामने रण-कौशल सम्बन्धी राजनैतिक या मानवीय आदि विभिन्न कारण नहीं होते।

पूँजीगत आवागमन का वर्गीकरण (Classification of Capital Movement)

पूँजीगत आवागमन के कई रूप हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, इसमें एक देश दूसरे देश का कर्जदार बन सकता है अथवा एक देश को कुछ वस्तुओं का स्वामित्व प्राप्त हो सकता है। पूँजीगत आवागमन का जन्म साधारण व्यापारिक लेन-देन से भी हो सकता है अथवा इसलिए भी हो सकता है कि कुछ लोग इसमें अपना लाभ देखते हैं। इसके द्वारा विभिन्न सरकारों के बीच अथवा गैर-सरकारी व्यक्तियों के बीच अथवा अर्द्ध-सरकारी व्यक्तियों के बीच के प्रबन्धों को अभिव्यक्त

किया जा सकता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि दो पूँजीगत आवागमनों के बीच विभिन्नता के अनेक कारण हैं और उनके अनुसार वे कई प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं।

पूँजीगत आवागमन के कुछ वर्गीकरण सैद्धान्तिक रूप से अपेक्षाकृत स्पष्ट होते हैं फिर भी कभी-कभी उनको लागू करना कठिन होता है। इस प्रकार के वर्गीकरणों की व्याख्या प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। पूँजीगत आवागमन को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है।

(1) प्रथम आधार समय की सम्झाई है जिसके लिए ऐसे आवागमन किए गए हैं—जब एक कर्जा दिया जाता है तो इसके साथ ही यह भी निर्धारित किया जाता है कि यह कितने समय में वापस लिया जाएगा। हो सकता है कि एक कर्ज का भुगतान करने का प्रबन्ध 60 दिन की अवधि में हो। इस प्रकार का कर्जा अल्पकालीन कर्जा कहलाता है और जब यह राष्ट्रीय सीमाओं को लाँघ जाता है तो इसको अल्पकालीन पूँजीगत आवागमन कह देते हैं। दूसरी ओर जो कर्जा एक वर्ष से पहले चुकाना नहीं होता उसे दीर्घकालीन पूँजीगत आवागमन कहते हैं।

पूँजीगत आवागमन को अल्पकालीन या दीर्घकालीन के रूप में वर्गीकृत करना अधिक उपयोगी सिद्ध इसलिए नहीं होता क्योंकि हम खरीदी गयी वस्तु को देखकर ही निश्चित रूप से यह पता नहीं लगा सकते कि खरीददार का वास्तविक इरादा क्या है? खरीददारी और विक्रेताओं के वास्तविक इरादों को जानने के पश्चात् ही निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि पूँजीगत आवागमन दीर्घ-आवागमन को वर्गीकृत करेगा तो वह केवल यह देखेगा कि अगर प्रतिभूतियाँ एक वर्ष से कम समय में परिपक्व हो जाती हैं तो वे अल्पकालीन हैं वरना वे दीर्घकालीन हैं। इस प्रकार के आँकड़ों की व्याख्या करते समय हमको पर्याप्त सजगता रखने की आवश्यकता है क्योंकि इससे स्पष्टतः पूँजीगत आवागमन का काल ज्ञात नहीं हो पाता।

(2) पूँजी के वर्गीकरण का एक अन्य आधार यह है कि भाग लेने वाले देशों के बीच एकरूपता रहती है। पूँजी की गतिशीलता या आवागमन प्रायः गैर-सरकारी व्यक्तियों या व्यापारिक कर्मों के बीच होता है। कुछ अन्य पूँजीगत आवागमनों में सरकारी निकाय जैसे केन्द्रीय बैंक आदि भी हो सकते हैं। पूँजीगत आवागमनों को हम सम्बन्धित पक्षों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं।

(3) इसका तीसरा आधार पूँजी का आयात करने वाले देश द्वारा भ्रवणाए गए उत्तरदायित्वों की प्रकृति है। यदि वह देश विदेशों को बॉण्ड्स बेचता है तो वह सामयिक रूप से व्याज का भुगतान करेगा और समय पूरा हो जाने पर मूलधन को वापिस करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि सम्बन्धित देश को समय-समय पर भुगतान करने की आवश्यकता न पड़े अथवा मूल-धन को लौटाने की जरूरत न पड़े क्योंकि किए जाने वाले भुगतान की मात्रा उस लाभ के आकार पर निर्भर करेगी जो सम्पत्ति के स्वामियों द्वारा कमाया जाता है। इस प्रकार यह उत्तरदायित्व कम कठिन है। वैसे कभी-कभी भुगतान किए जाने वाले धन का आकार इतना अधिक हो जाता है जो मूलधन से भी आगे निकल जाता है।

पूँजी के आवागमन के विभिन्न रूपों को हम निम्न प्रकार वर्णित कर सकते हैं—

(1) दीर्घकालीन निजी पूँजीगत आवागमन

(Long Term Private Capital Movements)

पूँजी के दीर्घकालीन आवागमन सरकारी, गैर सरकारी या मिलेजुले किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। इसमें स्वामियों की समानता या जमाकर्ताओं के दाव भी निहित रह सकते हैं। इस प्रकार के लेन-देनों की कुछ अन्य विशेषताएँ भी हानी हैं। इनकी एक विशेषता यह है कि इस अर्थ-व्यवस्था के व्यक्तिगत उद्यम में एक देश का निगम दूसरे देश के वित्तीय बाजारों में बाँट्स का व्यवसाय करता है। इस प्रकार का व्यवसाय प्रायः देश के वित्तीय केन्द्र द्वारा संचालित किया जाता है। जहाँ बाँट्स विदेशी विज्ञी के लिए प्रसारित किए जाने हैं वे खरीदने वाले अथवा उधार लेने वाले देश की मुद्रा में भी अभिव्यक्त होते हैं।

यद्यपि अधिकांश महत्वपूर्ण दीर्घकालीन गैर-सरकारी पूँजी के आवागमन राष्ट्रीय सीमाओं के पार प्रतिभूतियों की विज्ञी का रूप धारण करते हैं किन्तु इनके अनिर्दिष्ट एक ऐसा रूप भी है जो अप्रत्यक्ष अधिक महत्वपूर्ण है और जिस पर अधिक विचार करना उचित है। तकनीकी रूप से इस प्रकार की खरीददारी प्रतिभूतियों की खरीददारी से भिन्न होती है किन्तु आर्थिक दृष्टि से दूसरा महत्व समान होता है। इस प्रकार के प्रवन्ध को प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं जिसमें वित्तीय बाजार की प्रवृत्तियों की जाती है। एक देश के निवासी दूसरे देश में स्थित वास्तविक सम्पत्ति या व्यापारिक फर्मों का खरीद लेते हैं और उसका प्रवन्ध या तो वे स्वयं करते हैं या अपने एजेंटों द्वारा करवाते हैं। द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान अमेरिकी फर्मों ने दूसरे देशों में अपनी अनेकों शाखाएँ खोलीं। अनेकों कारणों से इस प्रकार का व्यय दूसरे व्यय की अपेक्षा अधिक आकर्षक लगता है। यद्यपि इस प्रकार का व्यय कुछ उद्योगों अथवा देशों तक ही सीमित रहता है फिर भी संयुक्तराज्य अमेरिका के द्वारा अधिकांश गैर-सरकारी व्यय इसी प्रकार से किया गया। इस प्रकार के पूँजीगत आवागमनों का अभिलेख रखना अत्यन्त कठिन होता है। जब तक ये सम्पत्तियाँ बाजार की प्रतिभूतियों का रूप धारण न कर लें उस समय तक इनका रजिस्टर में लिखना कोई सरल काम नहीं है।

(2) सार्वजनिक पूँजीगत आवागमन

(Public Capital Movements)

पूँजीगत आवागमन केवल गैर-सरकारी व्यक्तियों, निगमों या बैंकों के बीच होने वाले लेन-देन का परिणाम ही नहीं है। कई बार एक सरकार द्वारा अन्य सरकारों को भी ऋण प्रदान किया जाता है। इस प्रकार के प्रवन्ध द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद से बहुत महत्वपूर्ण बन गए हैं। कभी-कभी इस प्रकार के कर्ज थोड़े समय के लिए होते हैं किन्तु प्रायः ये दीर्घकालीन कर्ज होते हैं। यदि हम अल्पकालीन पूँजीगत आवागमनों का उदाहरण लेना चाहें तो हमें ऐसे अनेक उदाहरण

मिल जाएंगे जहाँ कि एक देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा दूसरे देश के केन्द्रीय बैंक को थोड़े समय के लिए कर्जा दिया जाता है। न्यूयार्क का संघीय रिजर्व बैंक, इंग्लैण्ड के बैंक के लिए डॉलर के रूप में ऋण दे सकता है। ऐसा होने पर इंग्लैण्ड का बैंक न्यूयार्क के संघीय रिजर्व बैंक से उतने ही डॉलर निकाल सकता है जितने उसे कर्ज में प्रदान किए गए थे।

सरकारों के बीच जो प्रबन्ध होते हैं वे प्रायः दीर्घकालीन प्रकृति के होते हैं। ये कर्जें 25 वर्षों अथवा उससे भी अधिक समय के हेतु लिए जा सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन में जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है वह प्रायः वही होती है जो व्यक्तिगत वित्तीय लेन-देनों में अपनाई जाती है। एक सरकार दूसरे देश के राजकोष से प्रत्यक्ष कर्जा प्राप्त कर सकती है और तब कर्जदार देश के सामान्य बजट में उस कर्ज में ली गयी राशि को रखा जाता है। कर्ज लेने वाले देश का राजकोष या तो अपने ही खाते के अनुसार चल सकता है और या इस प्रकार लिए गये कर्जों की वित्तीय व्यवस्था का स्वयं प्रबन्ध कर सकता है अथवा अपने देश की जनता को कर्ज में ली गयी प्रतिभूतियों को वह बेच सकता है।

कुछ समय से संयुक्तराज्य अमेरिका विश्व का आर्थिक केन्द्र बन गया है। यह विश्व के अधिकांश देशों को ऋण देता है। इस कर्ज का रूप या तो राजकोष के लिए होता है अर्थात् अमेरिकी राजकोष प्रत्यक्ष रूप से दूसरे देश के राजकोषों को धन कर्ज में देता है अथवा वह कर्जदान ऐसी संस्थाओं के द्वारा भी किया जा सकता है जिन पर सरकार का स्वामित्व है तथा सरकार द्वारा ही जो प्रारम्भ की गयी है। इस प्रकार के कर्ज प्रायः उन सरकारों को दिए जाते हैं जिनके बॉण्ड्स गैर-सरकारी बाजार के लिए अपेक्षाकृत कम आकर्षक होते हैं।

द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद एक नए प्रकार का सरकारी तथा गैर-सरकारी पूँजीगत आवागमन अस्तित्व में आया है। इनका एक श्रेष्ठ उदाहरण पुनर्रचना एवं विकास के लिए विश्व बैंक द्वारा किए जाने वाले प्रयत्नों में प्राप्त होता है। इसका कार्य यह है कि अपने सदस्यों को कर्ज लेने में सुविधा प्रदान करे। इनके लिए यह बैंक सरकारों को पुनः मुग्तान की गारन्टी प्रदान करता है। इस प्रकार के पूँजीगत आवागमनों में कुछ विशेषताएँ सरकारी होती हैं और कुछ गैर-सरकारी होती हैं और इस प्रकार न तो वे पूर्ण रूप से व्यक्तिगत होते हैं और न अव्यक्तिगत।

(3) अल्पकालीन पूँजीगत आवागमन

(Short Term Capital Movement)

अल्पकालीन पूँजीगत आवागमन भी सरकारी, गैर-सरकारी या मिले-जुले तीनों प्रकार के हो सकते हैं। इनका सम्बन्ध सम्पत्ति के स्वामी की अपेक्षा प्रायः विभिन्न दावों अथवा ऋण से रहता है। यह इसलिए होता है क्योंकि वास्तविक सम्पत्ति की सारी बिक्री की दीर्घकालीन पूँजीगत आवागमन के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है। अल्पकालीन पूँजीगत आवागमन द्वारा जो विभिन्न दावे किए जाते हैं उनके अनेक रूप हो सकते हैं। सामान्य रूप से एक देश के निवासियों के अल्प-

कालीन कर्जों में किसी प्रकार की वृद्धि जो अन्य देश के पक्ष में होती है, उसका अर्थ यह होगा कि प्रथम प्रकार के देश ने पूँजी का आयात किया था। इसी प्रकार दूसरी ओर यदि एक देश के निवासियों द्वारा लिया गया अल्पकालीन कर्ज थोड़ा बहुत घटता है तो इसका अर्थ यह होगा कि दूसरे देश ने अल्पकालीन पूँजी का आयात किया है। इसी प्रकार यदि एक देश के आयातकर्त्ता विदेशों से की जाने वाली अपनी खरीददारी को बढ़ा देते हैं और इस कार्य के लिए वे निर्यातकर्त्ता से अधिक साख प्राप्त करके वित्तीय व्यवस्था करने हैं तो आयातकर्त्ता देश भी पूँजी का आयात करता है।

अल्पकालीन पूँजीगत आयात और निर्यात का एक अन्य रूप यह भी है कि एक देश का केन्द्रीय बैंक विदेशी मुद्रा के अपने भण्डार को घटा लेता है। इसी प्रकार जब एक देश के व्यावसायिक बैंक दूसरे देश के बैंकों में अपनी जमा रकम घटा लेते हैं तो प्रथम देश को अल्पकालीन आघार पर पूँजी का आयातकर्त्ता माना जाएगा। इन विभिन्न रूपों में पूँजी का आयात व निर्यात अल्पकालीन आघार पर होता रहता है।

अल्पकालीन पूँजीगत आवागमन कई कारणों से अस्तित्व में आता है। यह कहा जाता है कि वस्तुओं के लेखे में होने वाले सभी सेन-देन अल्पकालीन पूँजीगत आवागमन को प्रोत्साहन देते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक आयातकर्त्ता विदेशों से कोई माल प्राप्त करता है तो निश्चय ही उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। इसके लिए या तो वह प्रत्यक्ष रूप से भुगतान कर सकता है अथवा निर्यातकर्त्ता से साख प्राप्त कर सकता है। यदि वह प्रत्यक्ष रूप से भुगतान करना चाहता है तो इसके लिए उसे विदेशी मुद्रा चाहिए अथवा वह निर्यातकर्त्ता को, या निर्यातकर्त्ता देश के किसी व्यक्ति को उसके लिए राजी करेगा कि वह आयातकर्त्ता देश की मुद्रा ग्रहण करे। इन विभिन्न सम्भावनाओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि या तो आयातकर्त्ता देश को अपने विदेशी विनिमय का भण्डार कम करना होगा अथवा निर्यातकर्त्ता देश को अपना भण्डार बढ़ाना होगा। यह भी हो सकता है कि निर्यातकर्त्ता देश आयातकर्त्ता देश के लिए अतिरिक्त साख प्रदान करे। आयातकर्त्ता देश की दृष्टि से इनसे प्रत्येक सेन देन अल्पकालीन पूँजीगत आयात की रचना करता है। माल अथवा सेवाओं का प्रत्येक आयात अल्पकालीन पूँजी आयात के लिए एक अवसर बन जाता है।

यद्यपि वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार अल्पकालीन पूँजीगत आवागमनों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है किन्तु फिर भी यही एक मात्र कारण नहीं है। आधुनिक समय में अधिकांश महत्वपूर्ण पूँजी आवागमन कुछ भिन्न कारणों से अस्तित्व में आए हैं। उदाहरण के लिए, जब एक फ्रांसीसी अपनी मुद्रा के बदले डॉलर खरीदता है तो यह जरूरी नहीं कि वह अमेरिकी कार खरीदने के लिए ही ऐसा कर रहा है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि वह उसके धन को अमेरिकी बैंक में जमा के रूप में अधिक सुरक्षित समझे। इस प्रकार अल्पकालीन पूँजी आवागमन अस्तित्व में आ गया, किन्तु भिन्न कारणों से।

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बातें भी हो सकती हैं जो व्ययकर्ता को अपने घन को दूसरे घन में बदलने के लिए प्रेरित करती हैं। कुछ प्राप्त करने की आशाएँ कभी-कभी कुछ खोने के डर की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बन जाती हैं। यदि हम अभिवर्णित परिवर्तनों का प्रबन्ध कर दें तो प्राप्ति के अवसर बढ़ जाते हैं। जब हम यह देखते हैं कि हमारे देश की अपेक्षा अन्य देशों में व्याज की दर अधिक है तो हम उस देश को अधिक घन उधार देने में लाभ का अनुभव करेंगे।

अस्थिरता उत्पन्न करने वाले अल्पकालीन पूँजीगत आवागमन के प्रभाव (Destabilizing Effects of Short-Term Capital Movement)

जब कभी सटोरियों द्वारा स्वयं ही विनिमय जोखिम होने के कारण अल्पकालीन पूँजीगत आवागमन होते हैं तो ये स्थिरता लाने वाले भी हो सकते हैं अथवा इनके द्वारा अस्थिरता भी उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में बड़ा दर में वृद्धि करने पर स्वर्ण बाहर जाने लगेगा जबकि बड़ा दर में कमी करने पर स्वर्ण बाहर से आने लगेगा। ऐसी अवस्था में पूँजी का बाहर जाना मौद्रिक अधिकारियों की सामर्थ्य का परिचायक नहीं माना जाएगा क्योंकि उन्हें मुग्तान सन्तुलन की अवस्था को बनाए रखने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए, परन्तु सटोरियों की जिज्ञासिलता के कारण पूँजी का बाहर जाना अधिकारियों की दुर्बलता का द्योतक होता है जिसके परिणामस्वरूप बाह्य में देश की मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ सकता है।

अस्थिरता के कारण सट्टा प्रवृत्ति के अन्तर्गत आयात का अतिरेक होने पर विनिमय दर में कमी आती है तथा मुग्तान सन्तुलन शेष के चालू खाते में वित्त की पूर्ति स्वर्ण के आवागमन की अपेक्षा इसके द्वारा पूँजी बाहर जाने लग जाती है तथा सुरक्षित कोष कम हो जाते हैं। इसके विपरीत निर्यात का अतिरेक होने पर विनिमय दर में वृद्धि होती है, व्याज की दर में कमी होती है तथा स्थिरता लाने वाले सट्टे से सम्बन्ध रखने वाली पूँजी के बाहर जाने की अपेक्षा स्वर्ण का बाहर से आयात होने लगता है।

यदि चालू खाता असमतल रूप से सन्तुलित है तो अस्थिरता उत्पन्न करने वाली पूँजी का बाहर जाना स्वर्ण को बाहर जाने में सहयोग प्रदान करेगा जबकि पूँजी के बाहर से आने की प्रवृत्ति स्वर्ण के आने के रूप में प्रोत्साहित होगी। कभी-कभी पूँजी प्रवाह का मौद्रिक प्रभाव स्वर्ण के आवागमन के फलस्वरूप नष्ट भी हो जाता है।

पूँजी के आवागमन की समस्याएँ (The Problems of Capital Movement)

यह कहा जाता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार की व्याख्या करना पूँजी के आवागमन की व्याख्या करने में अधिक कठिन होता है। यह कहना सत्य है किन्तु साथ ही यह भी सत्य है कि पूँजीगत आवागमन की सही मात्रा का अभिलेख रखना एक अत्यन्त कठिन काम है। जब कोई माल अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार

करके निकलता है तो उसका पता आसानी से लगाया जा सकता है क्योंकि प्रायः अधिकांश देशों में उनकी सीमाओं पर चुंगी कर प्रशासन सक्षम रहता है जो प्रत्येक वस्तु के आने और जाने को पंजीकृत करता रहता है। जब हम सीमाओं के पार सेवाओं की गति का अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं तो मापने का कार्य अधिक कठिन हो जाता है। व्यापार के ये अपरिहार्य भाग इस प्रकार की प्रकृति के होते हैं कि इनको रोकना कठिन होता है। जहाज से सम्बन्धित सेवाएँ कुछ आसानी से मापी जा सकती हैं क्योंकि जहाज की कम्पनियाँ अपेक्षाकृत कम होती हैं और जो जहाज सेवा प्रदान करते हैं उनको देखा जा सकता है तथा आसानी से उन पर नजर रखी जा सकती है किन्तु विदेशों में यात्रियों द्वारा यानों पर कितना खर्च किया जाता है इसका अनुमान लगाना बड़ा कठिन है यद्यपि यात्रियों की संख्या अधिक नहीं होती फिर भी उनके द्वारा किया जाने वाला व्यय कुछ ऐसा अटिखतापूर्ण होता है जिसका अनुमान लगाना सम्भव नहीं होता।

इसी प्रकार व्याज के भुगतान को बिलना और भी कठिन होता है क्योंकि हो सकता है कि वे सीमाओं को पार भी न करें और किसी विदेशी बैंक में प्राप्तकर्ता के खाते में जोड़ दिए जाएँ। जब कभी उनको टार द्वारा एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है तब भी वे अवरोध से बच सकते हैं। इस प्रकार दो देशों के बीच जा सेवाओं का लेन देन होना है उसका अनुमान लगाना कठिन है फिर भी वे कठिनाइयाँ उन कठिनाइयों से अत्यन्त अल्प होती हैं जो पूँजी के आवागमन का सही-सही अनुमान लगाने में उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार क अनुमान बहुत सावधानी के साथ लगाने चाहिए। पर्याप्त सावधानी बरतने के बाद भी अनेक कारणों से ये अनुमान पूर्ण-रूपेण सही नहीं हो सकते।

पूँजीगत आवागमन के अनुमान के तरीके (Methods of Estimating Capital Movement)

पूँजी की गतिशीलता का अनुमान लगाने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों का काम में लाया जा सकता है। जब प्रत्यक्ष तरीके को अपनाया जाता है तो वह वास्तविक पूँजी के लेन-देन का अभिलेख रखता है। इस प्रकार के पूर्ण अभिलेख में विभिन्न बाधाएँ आती हैं। कुछ देशों में इस बात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता कि एक देश के निवासी विदेशों में कितनी प्रतिभूतियाँ प्रसारित करते हैं। अधिकांश देश उस धन का अनुमान लगाने में पर्याप्त कठिनाई का अनुभव करते हैं जो कि उन्होंने विदेशों में स्थित अपनी सम्पत्ति पर लगाया हुआ है। अधिकांश देश इस बात का भी सही-सही अनुमान नहीं लगा पाते कि उनके परे लूँ बैंकों में विदेशियों की जमा के अन्तर्गत क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं, ऐसे अनेक तरीके हैं जिन्हें अपनाकर पूँजी एक देश से दूसरे देश में सार्वजनिक अधिकारी की नज़रों से बचकर जा सकती है। असल में जब सरकार इस प्रकार के आवागमन को रोकना चाहती है तो उसके द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों के स्थान पर पुलिस अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते हैं। इन अधिकारियों की पर्याप्त मजबूती के बाद भी काफी

पूँजी का आवागमन चलता रहता है। इस प्रकार पूँजी के आवागमन का अनुमान लगाने के प्रत्यक्ष तरीके अनेक सीमाओं के विषय होते हैं।

अनुमान के कुछ अन्य तरीके भी हैं जिनका प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है और जिनके आधार पर अधिक सही परिणामों तक पहुँचने की कोशिश की जाती है। इनको हम अप्रत्यक्ष तरीकों का नाम देते हैं। अप्रत्यक्ष अनुमान इस तथ्य पर आधारित होते हैं कि जब एक देश निर्यात की अपेक्षा अधिक माल और सेवाएँ आयातित करता है तो इस अन्तर का स्पष्टीकरण ऋण के आधार पर किया जा सकता है जो कि वह देश अन्य देशों से ग्रहण करता है। दूसरी ओर, जब एक देश आयातों की अपेक्षा अधिक माल और सेवाओं का निर्यात करता है तो वह देश आवश्यक रूप से एक कर्जदाता या अन्य देशों को पूँजी का निर्यातकर्ता बन जाएगा। जब हम एक देश के चालू खाते में यह पाते हैं कि उसने पाँच लाख रुपए का निर्यात और चार लाख रुपए का आयात किया है तो इससे यह सिद्ध होता है कि उस देश ने उस काल में एक लाख रुपए की पूँजी का निर्यात किया होगा। ये अप्रत्यक्ष तरीके प्रत्यक्ष तरीकों की अपेक्षा अधिक उपयोगी एवं प्रभावशील होते हैं।

उपयोगिता होते हुए भी पूँजी के आवागमन लगाने के अप्रत्यक्ष तरीके की सीमाएँ हैं। इनके द्वारा वह सब कुछ नहीं जाना जाता जो हम जानना चाहते हैं। इनके द्वारा पूँजी के आवागमन के रूप का उल्लेख नहीं किया जाता। इनमें यह नहीं बताया जाता कि पूँजी का आवागमन अल्पकालीन है या दीर्घकालीन, वह सरकारी है अथवा गैर-सरकारी।

पूँजी के आवागमन का अनुमान लगाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीकों की सीमाओं के कारण इनके अनुमान में सामान्य रूप से यह सिद्धान्त अपनाया जाता है कि पूँजी के जिस आवागमन के सम्बन्धों में अधिक निश्चित आँकड़े प्राप्त होते हैं, उनके लिए प्रत्यक्ष अनुमान का प्रयोग किया जाए और अन्य पूँजीगत आवागमनों के लिए प्रत्यक्ष तरीके का प्रयोग किया जाए।

1930 की महान् आर्थिक मन्दी से पहले पूँजी के आवागमन का अनुमान लगाने की कठिनाइयाँ विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण थीं। इस सरलता के युग में कोई भी व्यक्ति अपनी मुद्रा को इच्छानुसार किसी भी विदेशी मुद्रा में बदलने के लिए स्वतन्त्र था। उस पर न कोई प्रतिबन्ध था और न ही उसको किसी को सूचना देनी पड़ती थी किन्तु उस समय भी पूँजी के आवागमन के सही आँकड़े प्राप्त करना असम्भव था। आर्थिक मन्दी और उसके बाद के काल में अधिकांश देशों में विनिमय-नियन्त्रण की किसी न किसी प्रणाली को अपना लिया गया। आज अधिकांश देशों में वहाँ के निवासियों को विदेशी प्रतिभूतियाँ अथवा सन्धति खरीदने से या तो रोक दिया जाता है अथवा उनकी खरीददारियों को सरकार द्वारा अभिलेखित किया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि प्रत्येक खरीददारी का अभिलेख रखा जाएगा फिर भी अधिकांश आवागमनों पर नियन्त्रण और प्रतिबन्ध लगाए जाएंगे। परिणामस्वरूप आजकल पूँजीगत आवागमन के अनुमान पहले की अपेक्षा कुछ

अधिक सही बन गए हैं फिर भी सामान्य रूप से यह विश्वास किया जाता है कि आज भी पूँजी के आवागमनों के अनुमान पर्याप्त अनिश्चितता रखते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी के आवागमन का मूल्यांकन

(An Appraisal of International Capital Movements)

अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी के आवागमन से सम्बन्धित उपर्युक्त विचार विमर्श के बाद यह कहा जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है। इसके द्वारा विश्व के उत्पादन की मात्रा को बहुत कुछ बढ़ा दिया जाता है। इसे अनादर ऐसा प्रभाव दिया जाता है कि विभिन्न देशों के बीच पूँजी का अधिक से अधिक वितरण हो सके। विभिन्न देशों के बीच पूँजीगत कोषों की किस प्रकार वितरित किया जाए? यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सम्बन्ध में कई अन्य प्रश्न भी उठते हैं जैसे क्या अर्द्ध-विकसित देशों को सम्पूर्ण पूँजी का केवल एक भाग मात्र ही प्रदान किया जाए? क्या पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका को सबसे बड़ा भाग प्रदान किया जाए? दूसरा प्रश्न यह भी है कि विकासशील अर्थ व्यवस्थाओं में पूँजी के आयातों की कीमतें ऊँची रखी जाए और विकसित देशों में इन्हें नीचा रखा जाए? इन प्रश्नों का उत्तर ढूँढना पूँजीगत आवागमन के वास्तविक मूल्यांकन के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

जो कर्ज दिए जाते हैं वे प्रायः दो उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं—(1) वे उपभोक्ताओं को वह सब खरीदने के योग्य बना सकते हैं जो वे अन्य प्रकार से नहीं खरीद सकते क्योंकि उनकी आय सीमित होती है। (2) इनके द्वारा उत्पादन में सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग कर सकते हैं तथा उत्पादन कम कीमत पर और अच्छा हो सकेगा। यदि हम कर्ज को उपभोक्ताओं की दृष्टि से देखें तो यह कहना होगा कि सबसे अच्छा निर्धारण उस समय प्राप्त किया जा सकता है जब समस्त उपभोक्ता एक जैसी कीमत का भुगतान करें। कर्ज का सर्वश्रेष्ठ वितरण वह होता है जिसमें प्रत्येक कर्ज लेने वाला उपभोक्ता समान शर्तों के ऊपर कर्ज ले सके। यदि सभी उपभोक्ता कर्जदारों के लिए व्याज की दर बराबर न हो तो इसका अर्थ यह होगा कि कुछ उपभोक्ताओं को अन्य की अपेक्षा खरीदे गए माल के लिए अधिक भुगतान करना होगा। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उपभोक्ता वस्तुओं का उपभोक्ताओं के बीच वितरण इतना कुशल नहीं होता जितना कि यह होना चाहिए। यदि माल सभी उपभोक्ताओं को समान मूल्य पर प्राप्त कराया जा सके तो बल्पाण में वृद्धि होती है। यही बात व्यापारिक उद्यमों पर भी लागू होती है। यदि हम यह चाहते हैं कि व्यापारिक उद्यमों के बीच पूँजीगत कोषों को अधिक से अधिक मात्रा में निर्धारित किया जाए तो इसके लिए यह आवश्यक है कि सभी व्यापारिक उद्यमों के लिए पूँजीगत कोषों की कीमत एकसी होनी चाहिए।

विभिन्न अर्थ व्यवस्थाओं में पूँजी का आदर्श-वितरण वह माना जाएगा जिससे अन्तर्गत कुछ मूलभूत मापदण्डों को आधार मान कर चला जाए। विभिन्न देशों में धन की जो आवश्यकता होती है उसी व्यापकता के आधार पर ही धन का वितरण किया जाना चाहिए। इसके अनिश्चित विभिन्न देशों में ऋण लेने से सम्बन्धित

ओलिग की मात्रा को भी ध्यान में रखना होगा। उसके आधार पर ही व्याज की दर को निर्धारित किया जाएगा। व्याज की दरों में समय-समय पर परिवर्तन भी किया जा सकता है। जब आय का छोटा सा भाग कुछ देशों को जाय और दूसरे देश उससे बहुत कुछ कमाने लग जायें तो व्याज की दरों में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी अनेक तत्त्व हो सकते हैं। कुछ देशों में ऐसी चीजें अधिक उत्पादित की जाती हैं जिनका सामाजिक मूल्यांकन बाजार के मूल्यांकन की अपेक्षा अधिक होता है। इस प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा या तो सहायता दी जाती है अथवा अधिक कर लगाए जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रायः ऐसा ही होता है। जिस देश में उपयुक्त उत्पादन किया जा सके उस देश के लिए कर्जा विशेष रूप से आसाम शर्तों पर दिया जा सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय कर्जों द्वारा एक देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। यदि कर्जा शीघ्र किसी रचना करने के उद्देश्य के लिए दिया जाता है तो कर्ज लेने वाले देश की अर्थ-व्यवस्था को इससे अनेक लाभ प्राप्त होंगे। जब ऐसी स्थिति बनती जाती है जिसमें व्याज की दरें समान हो तो इसके परिणामस्वरूप एक अर्थ व्यवस्था का प्रसार पर्याप्त प्रोत्साहित रूप से होता है। व्याज की एक दर विभिन्न देशों के बीच पूँजी के वांछनीय वितरण की दृष्टि से अस्यन्म महत्वपूर्ण होती है। यह दर प्रायः हमेशा एक-रूप नहीं होती बल्कि इसके विपरीत यह देशों के बीच विभिन्नता भी स्थापित करती है।

दीर्घकालीन पूँजीगत निवेश की प्रवृत्ति एवं समस्याएँ

(Long Term Private Investment : Trends & Problems)

अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में दीर्घकालीन पूँजीगत निवेश एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है क्योंकि विकसित देश अपनी कम्पनियों द्वारा विदेशों में किए जाने वाले निवेश पर नियन्त्रण रखकर, भुगतान सन्तुलन को बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं, जबकि विकासशील राष्ट्र बाहर से आने वाली निवेश पूँजी को शंका की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि यह पूँजी शोषणकारी भी हो सकती है तथा इसके निवेश द्वारा विदेशी कम्पनियाँ देश में उपलब्ध साधनों का ज्यादा से ज्यादा आहरण भी कर सकती हैं। इसी कारण ज्यादातर विकासशील देश विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए यह शर्त लगा देते हैं कि ऐसी कम्पनियों के प्रबन्ध, वर्मचारियों की नियुक्ति तथा नियम व्यापार में स्थानीय भागीदारी भी रखी जाएगी। यदि किसी कम्पनी के शेयर पूँजी में 50% से 100% तक प्रत्यक्ष स्वामित्व विदेशी निवेश के रूप में हो, तो इससे निवेश करने वाली कम्पनी का नियन्त्रण भी इसी अनुपात में होता है। यहाँ पर नियन्त्रण से हमारा अभिप्राय उत्पादन की प्रकृति एवं मात्रा, उच्च-स्तरिय अधिकारियों की नियुक्ति, पूँजीगत-अनुदान शोध आदि का निर्धारणकर्ता से होता है।

यदि किसी अन्य देश में निवेश करने वाली कोई दम् या वहाँ के स्थानीय बाजारों से ऋण लेती है तो इस प्रकार के प्रत्यक्ष निवेश से पूँजी का कोई आवागमन नहीं होता है। एक बार निवेश लाभप्रद बन जाने पर वह विदेशी कम्पनी अपने

क़णों का भुगतान कर देगी और यहाँ तक कि अपने लाभों को पुनः निवेश करने लगेगी। परन्तु अधिकांश स्थितियों में प्रत्यक्ष निवेश के अन्तर्गत पूँजी का आवागमन होता है, विदेशों में स्थित कम्पनी के प्रबन्ध पर आंशिक रूप से नियन्त्रण विदेशी फर्म का होता है। इसके अतिरिक्त तकनीकी का आवागमन किया जाता है। कभी-कभी सशुक्त उद्योग भी स्थापित किए जाते हैं, जिनके अन्तर्गत विदेशी कम्पनियाँ विदेशी विनिर्माण के रूप में शेयर पूँजी प्रदान करती हैं, अथवा उनके स्वयं की मशीनों, औद्योगिकी या अन्य प्रकार के योगदान को ही शेयर पूँजी में उनके योगदान के रूप में मान लिया जाता है।

आर्थिक इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनके अन्तर्गत कुछ कम्पनियों ने भूतकाल में लाभ अर्जित करने के उद्देश्य के बजाय निवेश के निवेश-करण अथवा हानि से बचने के लिए अन्य देशों में पूँजी का निवेश किया था। फिर भी यदि लाभ का 50% अथवा इससे अधिक उन्हीं कम्पनियों में पुनः निवेश कर दिया जाए तो विदेशी निवेश तथा जुए में कोई अन्तर नहीं रह जाता है क्योंकि किसी कम्पनी के लिए किसी दूसरे देश में व्यवसाय करना स्थानीय उद्यमियों की अपेक्षा अधिक लाभदायक तथा कम लाभप्रद कार्य होता है, अतः विदेशों में निवेश करने वाली ज्यादातर कम्पनियाँ इस कमी को पूर्ति करने हेतु स्थानीय फर्मों की अपेक्षा अपनी तकनीक या अपने पेटेंट एवं प्रसिद्ध वस्तु की श्रेष्ठता के आधार पर अपना व्यवसाय करती हैं। यदि फर्म को देश के बाहर पूँजी निवेश करके लाभ अर्जित करना है तो उसे विशिष्टता का लाभ अथवा श्रेष्ठता का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक हो जाता है कि यह कम्पनी पूँजी का अन्य देशों में निवेश करके, अपने देश में किए जाने वाले निवेश की अपेक्षा अधिक लाभ अर्जित करे। साथ ही यह लाभ मेजबान देश की फर्मों द्वारा उतनी ही पूँजी निवेश से प्राप्त लाभों की अपेक्षा अधिक होना चाहिए।

उपरोक्त तथ्यों से विदेशी निवेश के बारे में तीन बातें स्पष्ट होती हैं—

(1) जिन उद्योगों में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान है उनमें दीर्घकालीन पूँजीगत विदेशी निवेश नहीं किया जाएगा। इसी कारण से कृषक या खुदरा व्यापारी विदेशों में प्रत्यक्ष रूप से निवेश करना पसन्द नहीं करते हैं।

(2) एक विदेशी कम्पनी यथासम्भव स्थानीय उद्यमियों की तुलना में अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने का हर सम्भव प्रयत्न करती है। जबकि स्थानीय उद्यमी भी विदेशी निवेशकर्ता को सर्ववशता की दृष्टि से देखते हैं।

(3) दीर्घकालीन विदेशी पूँजीगत निवेश एक ही उद्योग में दो दिशाओं में प्रयुक्त किए जाते हैं, क्योंकि कुछ तो विभेदात्मक स्थिति के लाभों में अन्तर के कारण तथा कुछ अत्याधिकारिक स्थिति के कारण एक फर्म यथासम्भव किसी दूसरी फर्म को अप्रत्याशित लाभ प्राप्त नहीं करने देनी है। यह उस नौका-दौड़ की भाँति है जिसमें कोई भी नाविक किसी दूसरे की नौका को अपने से आगे नहीं जाने देना, वरन् अपने नेता के पीछे रहकर अपनी स्थिति को बनाये रखता है।

गणितीय रूप से दीर्घकालीन विदेशी पूँजीगत निवेश के सिद्धान्त को निम्न रूप से प्रकट किया जा सकता है—

$$C = \frac{I}{r}$$

यहाँ पर C = निवेश का मूल्य है,

I = निवेश से होने वाला माय प्रवाह है,

r = बाजार की व्याज दर है ।

कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि विदेशी लोग किसी अन्य देश A में माय प्रदान करने वाले किसी व्यवसाय के लिए उस देश के निवासियों की तुलना में अधिक पूँजी निवेश करने को इसलिए तैयार नहीं होते हैं कि देश A में व्याज की दर (r) कम है, बरन् इसलिए तैयार होते हैं कि इस निवेश (C) से प्राप्त होने वाला माय प्रवाह (I) अधिक होता है । अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता नहीं होती है तथा सामान्यतः व्याज की दरों के अन्तर का पूँजी के आवागमन पर भी प्रभाव पड़ता है । परन्तु विदेशी लोग व्याज की दर वही होने पर तथा I का मान अधिक होने पर किसी दूसरे देश में पूँजी का निवेश कर देते हैं ।

विदेशी निवेश के कारण निवेश करने वाले, तथा निवेश प्राप्त करने वाले दोनों ही देशों के भुगतान सन्तुलन प्रभावित होते हैं क्योंकि पूँजीगत निवेश के कारण सारा सज्जा कलपुजों, भण्डार आदि के निर्यात में वृद्धि होती है तथा इसके प्रतिरक्ति प्रत्यक्ष निवेश के कारण निवेशकर्ता को लाभान्वित तथा व्याज की प्राप्ति होती है । इस प्रकार, यद्यपि प्रत्यक्ष निवेश से निवेश करने वाले देश के भुगतान सन्तुलन पर प्रारम्भ में तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है परन्तु बाद में व्याज एवं लाभान्वित की प्राप्ति तथा बढ़ते हुए निर्यातों के कारण उसका भुगतान सन्तुलन अगले अनेक वर्षों तक अनुकूल बना रहता है । परन्तु दीर्घकाल में मेजवान देश द्वारा निवेश करने वाले देश से अनेक वस्तुओं का आयात बन्द कर दिया जाता है क्योंकि तब तक उसकी स्वयं की उदरगदन क्षमता में विदेशी निवेश के कारण काफी सुधार हो चुका होता है । अतः दीर्घकाल में निवेश करने वाले देश के भुगतान सन्तुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, फिर भी यह प्रभाव अन्य वस्तुओं के निर्यात में हुई वृद्धि, राष्ट्र की भुगतानों, तथा मेजवान देशों से आने वाली व्याज व लाभान्वित की राशि की तुलना में बहुत कम होता है ।

विदेशी निवेश के प्रारम्भ के वर्षों में मेजवान देश का भुगतान सन्तुलन काफी अनुकूल हो जाता है परन्तु धीरे-धीरे आगे के वर्षों में परिशोधन, व्याज तथा लाभान्वित के भुगतानों के कारण इसका भुगतान सन्तुलन प्रतिकूल होने लगता है । ये बाहरी भुगतान किस सीमा तक उसके भुगतान सन्तुलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि मूल निवेश पर कितना लाभ प्राप्त होता है तथा व्याज व लाभान्वित के आवागमन हेतु क्या शर्तें रखी गई हैं ।

की नवीन वस्तुओं के उपभोग पर व्यय किया जाना है, जिनकी पूर्ति भी विदेशों से मंगाकर की जाती है। अनेक अर्द्ध-विकसित देश कृषि-प्रधान होते हुए भी कृषि व्यवसाय और उत्पादन-पद्धतियों के अवनत होने के कारण देश की आवश्यकतानुसार खाद्यान्न और उद्योगों के लिए कृषि-जनित कच्चा माल भी उत्पन्न नहीं करते। अतः उन्हें खाद्यान्न और ऐसे कच्चे माल का भी आयात करना पड़ता है। भारतीय योजनाओं में ऐसा ही हुआ। अधिकांश अर्द्ध-विकसित देश अधिक जनसंख्या से ग्रसित होते हैं और उनकी जनसंख्या-वृद्धि की दर भी अधिक होती है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक मात्रा में उपभोग सामग्री और उत्पादक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति के लिए आयातों का आश्रय लेना पड़ता है। कई अर्द्ध-विकसित देशों में आयातों के बढ़ने का यह भी एक कारण है। इस प्रकार, विकासार्थ नियोजन के प्रारम्भिक वर्षों में आयातों के बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। इन देशों को परिपोषक आयात (Maintenance Imports), विकासार्थक आयात (Developmental Imports) और अस्थैतिकारी आयात (Anti-inflationary Imports) करने पड़ते हैं। इन सब आयातों के भुगतान हेतु विदेशी विनिमय की आवश्यकता होती है।

निर्यात और विदेशी-विनिमय का अर्थ—स्पष्ट है कि विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था में वृद्धिमान दर से आयात करने पड़ते हैं। विदेशों से इन पदार्थों का आयात करने के लिए इनका भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, जिसे ये देश अपनी वस्तुओं का निर्यात करके प्राप्त कर सकते हैं। अधिक मात्रा में वस्तुएँ आयात की जा सकें, इसके लिए यह आवश्यक है कि ये देश अधिकाधिक मात्रा में अपने देश से पदार्थों का निर्यात करके अधिनाधिक विदेशी मुद्रा या विदेशी विनिमय अर्जित करें। इन निर्यातों में दृश्य और अदृश्य (Visible and Invisible Exports) दोनों निर्यात सम्मिलित हैं। इस प्रकार, विकासोन्मुख देशों के लिए निर्यातों में वृद्धि करना आवश्यक होता है। किन्तु दुर्भाग्यवश, इन देशों में नियोजन की प्रारम्भिक अवस्थाओं में निर्यात-क्षमता बहुत अधिक नहीं होती है। एक तो स्वयं देश के विकास कार्यक्रमों के लिए वस्तुओं की आवश्यकता होती है। दूसरे, आर्थिक विकास के कारण बढ़ी हुई आय को भी जनता, उपभोग पर ही व्यय करना चाहती है, क्योंकि इन देशों में उपभोग की प्रवृत्ति अधिक होती है। अतः निर्यात-योग्य आधिशेष (Exportable Surplus) कम बच पाता है। योजनायुक्त आर्थिक विकास में जो कुछ उत्पादन किया जाता है, वह उपभोग की बढ़ती हुई आवश्यकता में प्रयुक्त कर लिया जाता है। परिणामस्वरूप, इतनी अतिरिक्त निम्न-स्तरीय उत्पादकता और मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियों के कारण उत्पादन लागत अधिक होती है और विश्व के बाजारों में वे प्रतिस्पर्धा में प्रारम्भिक वर्षों में नहीं टिक पाते, फलस्वरूप, व्यापार प्रतिफल हो जाता है क्योंकि, एक ओर आयातों में वृद्धि होती है तथा दूसरी ओर उनके भुगतान के लिए निर्यात अधिक नहीं बढ़ पाते। इस प्रकार विदेशी विनिमय का संकट पैदा हो जाता है। जिसकी विदेशी सहायता द्वारा पूरा करने का प्रयत्न किया जाता है।

ग्रहों विकसित ग्रहों विकासशील देश योजनाबद्ध आर्थिक विकास के मार्ग पर हैं और इसमें सहायता देने के लिए उन्हें विकसित राष्ट्रों से ऋण (Loans) के साथ साथ अनुदान (Grants) भी प्राप्त होने हैं। इसलिए प्रायः 'विदेशी पूँजी' (Foreign Capital) के स्थान पर "विदेशी सहायता" (Foreign Aid) शब्द अधिक प्रचलित हो गया है। भारत के आर्थिक विकास में विदेशी सहायता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, तथापि इसमें कुछ समस्याएँ भी उत्पन्न कर दी हैं। स्पष्ट है कि विदेशी सहायता के लाभ और हानि दोनों हैं।

विदेशी सहायता की आवश्यकता

ग्रहों विकसित और विकासशील देशों के लिए विदेशी सहायता मुख्यतः इन दो कारणों से बहुत आवश्यक है—

(1) इन देशों की प्रायः बहुत कम जमीनी है, अतः आन्तरिक बचन भी कम होती है और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक पूर्ण आन्तरिक साधनों से उपलब्ध नहीं हो पाती। इसलिए विदेशी पूँजी का सहारा लिया जाता है। यदि विदेशी पूँजी सुलभ न हो तो इन देशों का आर्थिक विकास या तो रुक जाता है अथवा बहुत मन्द गति से हो पाना है। आर्थिक विकास का इतिहास बतलाता है कि प्रायः विकसित देशों ने भी अपने विकास की प्रारम्भिक अवस्था में विदेशी पूँजी की सहायता ली थी। उदाहरणार्थ, जर्मन न 17वीं और 18वीं सदी में हॉलैंड में समुक्त राज्य अमेरिका ने 17वीं सदी में यूरोप से और कनाडा न 1900 में 1930 के बीच इंग्लैंड तथा अमेरिका से काफी पूँजी प्राप्त की थी। लेकिन कम इसका प्रभाव रहा है, क्योंकि जहाँ उपभोग घटाकर अनिवार्य बचन द्वारा पूँजी-निर्माण करके आर्थिक विकास किया गया पर लोकनानैतिक पद्धति वाले देशों में यह मार्ग अपनाया जाना सम्भव नहीं है।

(2) विकसित और अर्द्ध-विकसित देशों के बीच आर्थिक असमानता की खाई को पाटने के लिए भी यह आवश्यक है कि विकसित देश बड़े पैमाने पर अर्द्ध-विकसित देशों को आर्थिक सहायता दें। यह आर्थिक सहायता और सहायता दोनों पक्षों के लिए हितकारी है, क्योंकि जब विश्व की आर्थिक समृद्धि बढ़ती है तो सभी देशों के नागरिकों का जीवन-स्तर ऊँचा उठता है।

पियरसन समीक्षण द्वारा विश्व बैंक का अक्टूबर, 1969 में पक्ष की गई अपनी रिपोर्ट में विदेशी सहायता का 'नैतिक' और 'व्यावहारिक' कारणों के आधार पर समर्थन दिया गया। नैतिक दृष्टि से यह उचित है कि जो समर्थ और शक्तिशाली हैं वे दुबला की सहायता करें। व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो विदेशी सहायता विश्व की परीची दृष्टि के लिए आवश्यक है। प्रायः विश्व-समाज की धारणा बन पकड़ रही है और 'व्यंग्य' विभाज्य (Divisible) नहीं रह गया है।

भारत को विदेशी सहायता से लाभ

भारत योजनावद्ध रूप में आर्थिक विकास के लिए प्रयत्नशील है। विदेशी सहायता के लिए भारत के सन्दर्भ में मुख्यतः निम्नलिखित आधार हैं—

1. प्राकृतिक साधनों के विदोहन के लिए—भारत प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से धनी है, लेकिन पूँजी के अभाव में अपने प्राकृतिक साधनों का समुचित विदोहन नहीं कर सकता। विदेशी पूँजी के सहयोग से देश प्राकृतिक साधनों का तेजी से विदोहन करके आर्थिक विकास को तीव्र गति दे सकता है और देशवासियों का जीवन-स्तर ऊँचा उठा सकता है।

2. पूँजी-निर्माण बढ़ाने के लिए—विदेशी सहायता के अभाव में भारत के लिए अचना उपभोग घटाकर पूँजी-निर्माण करना होगा, जो निश्चिन्त ही बड़ा कठिन काम है। विदेशी सहायता का उपयोग आयात बढ़ा कर उपभोग वस्तुओं की घरेलू पूर्ति की वृद्धि में किया जा सकता है जिससे अर्थ-व्यवस्था पर भार में कमी आती है।

3. देशी पूँजी के प्रभावपूर्ण उपयोग के लिए—विदेशी पूँजी अथवा विदेशी सहायता के अभाव में देशी पूँजी प्रभावशाली नहीं हो पाती। नए कारखाने खोलने पर मशीनों, औजारों, कच्चे माल तथा अन्य विकास सामग्री की खरीद विदेशों से करनी पड़ती है। पूँजी के अभाव में समुचित खरीद नहीं हो पाती और कार्यक्रम ठप्प हो जाते हैं। पर यदि आवश्यकता के समय विदेशी पूँजी सुलभ हो तो देशी पूँजी का भी प्रभावशाली उपयोग हो सकता है।

4. विदेशी विनिमय का सकट ढालने के लिए—विकास की प्रारम्भिक अवस्था में आयात तो बढ़ते जाते हैं जबकि निर्यात उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाते। अतः विदेशी मुद्रातान की समस्या उत्पन्न हो जाती है। देश का विदेशी विनिमय कोष समाप्त होने लगता है। इस परिस्थिति में “विदेशी सहायता” द्वारा विनिमय सकट को टाँसना सम्भव हो पाता है।

5. स्वदेशी विनियोजकों को प्रोत्साहित करने के लिए—विदेशी पूँजी से स्वदेशी विनियोजकों को भी विनियोग-वृद्धि की प्रेरणा मिलती है। विदेशी सहायता के बल पर देश में ऐसी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने लगता है जो अन्य सधोगों के लिए कच्चा माल बन जाते हैं। इस प्रकार देश के उद्योगों में विनियोजन बढ़ जाता है।

6. स्थायी सम्पत्तियों का निर्माण बढ़ाने के लिए—विदेशी पूँजी की सहायता से देश में सिंचाई साधन, बाँध, बिजली घर आदि के रूप में स्थायी सम्पत्तियों से भविष्य में लाभ अर्जित करके हम विदेशी पूँजी का मुद्रातान कर सकते हैं।

1. भारत एक बड़ा विकसित राष्ट्र है अतः भारत के लिए लागू लगभग सभी आधार अन्य बड़े-विकसित राष्ट्रों के लिए भी लागू होते हैं।

7 विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में विदेशी अनुभव का लाभ उठाने के लिए—परिवहन विकास, खनिज व्यवसाय एवं ग्रन्थून पूँजीगत उद्योगों के विकास आदि में विदेशी अनुभव का लाभ उठाने की दृष्टि से भी विदेशी पूँजी महत्त्वपूर्ण है। भारत औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों की उत्पादन-विधियों को अपना कर तेजी से अपना औद्योगीकरण कर सकता है।

॥ आन्तरिक स्वायत्त के लिए—विदेशी पूँजी की सहायता से आर्थिक विकास को गति देकर देश में आन्तरिक स्वायत्त के तत्वों को बल पहुँचाया जा सकता है।

9 मुद्रा-स्फीति विहीन विकास सम्भव बनाने के लिए—विदेशी पूँजी से देश में मुद्रा-स्फीति विहीन विकास सम्भव होता है। विदेशी पूँजी का आयात न होने से हीनार्थ प्रवर्धन द्वारा वचन से अधिक विनियोजन करने की नीति से देश में मुद्रा-स्फीति का प्रसार होना है। किन्तु विदेशी पूँजी के आयात से मुद्रा स्फीति का यह भय बहुत कम हो जाता है, वगैरह कि विदेशी पूँजी से उत्पादन शीघ्रता शीघ्र क्रिया जाए और यदि उद्धारित सामान का निर्यात हो तो देश के उपयोग के लिए समुचित आयात भी हो।

इन सभी कारणों से भारत के लिए विदेशी सहायता का बड़ा उपयोग है। देश की पञ्चवर्षीय योजनाओं में विदेशी सहायता का भारी उपयोग किया गया है और जब तक देश सभी प्रकार की मशीनरी में आत्म निर्भर नहीं हो जाता तब तक हम विदेशी सहायता लेनी पड़ेगी। पर विदेशी सहायता पर अत्यधिक निर्भरता मुकामान्वेष है। इसके कुछ बड़े खतरे हैं जिनसे सावधानियाँ धरती जाना प्रति आवश्यक है।

विदेशी सहायता के खतरे और हानियाँ

भारत जैसे अर्द्ध-विकसित देश विदेशी पूँजी के माध्यम से अपने आर्थिक विकास को तीव्र करने का प्रयत्न करत हैं, लेकिन इस स्रोत पर अधिक निर्भरता के अनेक खतरे भी हैं, जैसे—

(1) विदेशी पूँजी देश में राजनीतिक हस्तक्षेप को साथ लाती है। भारी मात्रा में आर्थिक सहायता देने वाला देश “आर्थिक प्रभुत्व” के साथ-साथ “राजनीतिक प्रभुत्व” भी बढ़ाने का प्रयत्न करता है। भारत की विदेश-नीति गुट निरपेक्षता पर आधारित है, तथापि विदेशों से लगातार आर्थिक सहायता लेने पर हमारी आर्थिक नीति पर परीक्षा रूप में उनका कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। योजना की प्राथमिकताएँ भी प्रभावित होती हैं। विदेशी विनियोगकर्तों को सन्तुष्ट रखने के लिए देश की कर-नीति में भी कुछ न कुछ परिवर्तन सघोधन करने पड़ते हैं। औद्योगिक नीति, प्रशुल्क नीति आदि को इस रूप में जाना जाता है कि विदेशी पूँजी के प्रवाह में बाधा न पड़े। यद्यपि, भारत ने अभी तक विदेशी ऋणों का सकलता-पूर्वक सामना किया है, तथापि अमेरिका आदि देशों की दबाव-नीति हमें सतर्क कर देने के लिए काफी है। भारत यह नहीं भूल सकता कि पाकिस्तानी आक्रमण से

उत्पन्न संकटकाल में अमेरिका ने अपनी आर्थिक सहायता को भारत पर दबाव डालने के हथियार के रूप में प्रयोग करने का कुत्सित प्रयत्न किया।

(2) विदेशी सहायता देश की सुरक्षा के लिए संकट पैदा कर सकती है। जब संकटकाल में अचानक विदेशी सहायता बन्द कर दी जाती है और विदेश पूँजी वापस लौटने लगती है तो देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाता है।

(3) विदेशी पूँजी के अत्यधिक आयात से देश के आर्थिक दिवालियापन का खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि व्याज और लाभ के भुगतान के रूप में भारी मात्रा में राशि विदेशों को चली जाती है। इससे देश में आवश्यक पूँजी-निर्माण सम्भव नहीं हो पाता और आर्थिक विकास की योजनाएँ ठप्प होने लगती हैं। इसी प्रख्यापन में हम प्रागे चल कर पढ़ेंगे कि पूँजी के कारण भारत पर व्याज और मूल-धन चुकाने का कितना भारी बोझा बढता जा रहा है।

(4) भारी मात्रा में विदेशी मशीनों और उपकरणों को निरन्तर काम में लेने से इनके सम्बन्ध में देश की निर्भरता बढ जाती है। यद्यपि भारत मशीनरी के सम्बन्ध में आत्म-निर्भरता की ओर बढ रहा है, तथापि आयातभूत उद्योगों के लिए आवश्यक जटिल और भारी मशीनों के खातिर विदेशों पर उसकी निर्भरता काफी बढी हुई है। यह स्थिति देश के लिए गम्भीर चुनौती है।

(5) विदेशी पूँजी के साथ-साथ जो विदेशी लोग देश में घुस आते हैं उनके कारण गोपनीयता कायम नहीं रह पाती। कभी-कभी अवांछित विदेशी तत्त्व देश के हितों को बड़ा नुकसान पहुँचा देते हैं।

इन दोषों और हानियों के प्रकाश में अनेक अर्थ-शास्त्रियों का मत है कि भारत को अपने आन्तरिक साधनों पर ही अधिक निर्भर रहना चाहिए। विकास की प्रारम्भिक प्रवृत्ति में हमारे लिए विदेशी सहायता की बहुत अधिक आवश्यकता थी, लेकिन अब समय आ गया है कि हम विदेशी सहायता पर अपनी निर्भरता को तेजी से कम करते जाएँ—इसके लिए चाहे हमें कुछ अधिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ें और विकास की गति को चाहे धीमा करना पड़े। विदेशी पूँजी का जितना अधिक ध्याज भारत को चुकाना पड़ रहा है वह चिन्ताजनक पहलू है।

विदेशी सहायता के प्रति भारत सरकार की नीति

भारत सरकार प्रारम्भ से ही यह मानकर चली कि देश के विकास के लिए घरेलू बचतों के पूरक के रूप में विदेशी पूँजी का भारी महत्व है वस्तुतः नवोदित स्वतन्त्र भारत के सामने विकास का दबाव इतना प्रबल था और देश के आन्तरिक साधन इतने अल्प थे कि सरकार के पास विदेशी पूँजी लेने के अलावा कोई विकल्प न था। सरकार ने अप्रैल, 1948 के औद्योगिक नीति संकल्प में और तत्पश्चात् 1949 में संविधान सभा में प्रधानमन्त्री ने विदेशी पूँजी के बारे में सरकारी नीति के आधारक सिद्धान्त इस प्रकार व्यक्त किए—

(1) विदेशी पूंजी तथा उद्यम की हिस्सेदारी को राष्ट्रीय हित में इस प्रकार विनियमित किया जाएगा कि कुछ अपवादों को छोड़कर स्वामित्व का अधिकांश भाग और नियंत्रण भारतीयों के हाथों में रहे।

(2) भारतीय कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अन्तर्गत विदेशी विशेषज्ञों का स्थान ग्रहण कर सकें।

(3) देशों और विदेशी पूंजी में कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा विदेशी हितों पर कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं लगाए जाएंगे।

(4) विदेशी विनियोगकर्त्ताओं का लाभ और पूंजी देश से बाहर भेजने की अनुमति होगी, किन्तु इस सम्बन्ध में देश की मुद्रा स्थिति का ध्यान अवश्य रखा जाएगा।

(5) राष्ट्रीयकरण कर लेने की सूरत में उचित और न्यायपूर्ण मुआवजा दिया जाएगा।

विदेशी पूंजी अथवा विदेशी सहायता के सम्बन्ध में सरकार की आधारभूत नीति अभी तक यही बली आ रही है और इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुए हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विदेशी पूंजी का स्वागत करते हुए इस बात पर विशेष बल दिया गया था कि विदेशी सहयोग मुख्य रूप से उन्हीं क्षेत्रों में लिया जाए जहाँ एक तो वास्तविक अन्तराल को भरना आवश्यक हो और दूसरे उसके कारण घरेलू सेवाओं और ज्ञान के अधिकतम उपयोग में बाधा न पड़े। जुलाई, 1970 में सरकार ने ऐसी इकाइयों की स्थापना की अनुमति दी जो विदेशी कम्पनियों की अधीनस्थ कम्पनियों के पूर्ण स्वामित्व में कायम की जाए, यद्यपि कि वे अपना शत प्रतिशत उत्पादन निर्यात करें। इस सम्बन्ध में आगे चलकर भारत सरकार ने कुछ निदेशक तत्व भी जारी किए। लाभों को बाहर भेजने की अनुमति देने की नीति जारी रही, लेकिन फिर भी शत-प्रतिशत विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियों द्वारा घोषित लाभों के भेजने पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिए गए। सार रूप में, विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति अभी यही है कि कुछ चुने हुए क्षेत्रों में इसका स्वागत किया जाए तथापि अन्तिम रूप में यह सदैव भारतीयकरण के उद्देश्य के अधीन रहे।

सम्पूर्ण योजना-काल में विदेशी सहायता का आकार व उपयोग

सन् 1950-51 में योजनाबद्ध आयिक विकास का सूत्रपात करने से लेकर 1973-74 तक विदेशी सहायता के आकार और उपयोग की जानकारी महत्वपूर्ण है। विदेशी सहायता को मोटे रूप में तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है— (क) ऋण (Loans), (ख) अनुदान (Grants) एवं (ग) सार्वजनिक अधिनिधन सहायता (Public Law Assistance)। कुल विदेशी सहायता का चित्र अग्रिम सारणी से भली भाँति स्पष्ट होगा—

कुल विदेशी सहायता
(Overall External Assistance)

वर्ष	ऋण (Loans)	अनुदान (Grants)	जोड़	पी.एल. 480/665 आदि सहायता		कुल जोड़
				रूपे मे चुकाई जाने वाली	परिवर्तनीय मुद्रा मे चुकाई जाने वाली	
1	2	3	4	5	6	7
(क) दी गई विदेशी सहायता						
तीसरी आयोजना के						
ग्रन्त तक	3808.8	392.0	4200.6	1510.8	—	5711.6
1966-67	1034.1	79.7	1113.8	392.7	—	1506.5
1967-68	398.5	16.8	415.3	235.6	67.6	718.8
1968-69	753.1	68.4	821.5	71.6	53.7	946.8
1969-70	421.8	26.0	447.8	73.6	112.9	634.8
1970-71	705.4	56.5	761.9	—	—	761.9
1971-72	774.5	36.0	810.5	22.5	96.2	929.2
1972-73	639.6	36.6	676.2	—	—	676.2
1973-74	1129.5	41.1	1170.6	—	—	1170.6
1974-75	1481.4	189.8	1671.2	—	—	1671.2
1975-76	2192.8	440.7	2633.5	—	20.0	2653.5
1976-77	806.7	386.1	1192.8	—	93.6	1286.4
योग	14146.1	1769.7	15915.9	2307.1	440.0	18667.0
(ख) उपयोग की गई						
विदेशी सहायता						
तीसरी आयोजना						
के ग्रन्त तक	2768.7	336.9	3105.6	1403.2	—	4508.8
1966-67	674.7	67.1	741.7	359.2	—	1506.5
1967-68	793.2	60.7	853.9	310.6	30.8	1195.6
1968-69	679.8	65.1	745.0	84.5	73.1	902.6
1969-70	660.7	26.1	686.8	107.5	62.0	856.3
1970-71	658.9	43.5	702.4	37.7	51.3	791.4
1971-72	671.7	50.5	722.2	8.8	103.1	834.1
1972-73	649.9	12.0	661.9	—	4.3	666.2
1973-74	1015.0	20.7	1035.7	—	—	1035.7
1974-75	1220.4	93.0	1314.3	—	—	1314.3
1975-76	1464.6	283.3	1748.2	—	93.2	1840.5
1976-77	1285.3	245.8	1531.1	—	67.8	1598.9
योग	12543.2	1335.7	13878.9	2312.2	484.1	16675.8

Source : Economic Survey, 1977-78.

सारणी से स्पष्ट है कि कुल विदेशी सहायता स्वीकृतियाँ (Authorisations) तीसरी योजना के अन्त तक 57116 करोड़ रुपया थी जो बढ़कर 1976-77 तक कुल मिलाकर 186670 करोड़ रुपया हो गई। इस कुल योग में ऋण की राशि 141461 करोड़ रुपये, अनुदान की राशि 17697 करोड़ रुपये और सार्वजनिक अधिनियम सहायता 27471 करोड़ रुपये की रही। विदेशी सहायता के उपयोग को लें तो तीसरी योजना के अन्त तक उपयोग 45088 करोड़ रुपये का हुआ जो बढ़कर 1976-77 तक 166758 करोड़ रुपये हो गई।

विदेशी सहायता की प्राप्ति : सकल एवं शुद्ध

विदेशी सहायता की शुद्ध प्राप्ति के लिए कुल प्राप्ति (Gross Inflow) में से मूलधन और व्याज का मुफ्तान को घटा दिया जाता है। वस्तुतः योजनाओं में आर्थिक विकास के लिए इसी राशि का उपयोग होता है। सकल और शुद्ध विदेशी सहायता की प्राप्ति की 1967-68 से 1977-78 तक जो स्थिति रही वह निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है—

विदेशी सहायता की प्राप्ति सकल और निवल (Inflow of External Assistance Gross & Net)

(करोड़ रुपये)

वर्ष	1967-68	1970-71	1972-73	1974-75	1975-76	1977-78
1	2	3	4	5	6	7
1 सकल प्राप्ति जिसमें	1196	691	666	1314	1841	1585
(क) पब्लिक लॉ 480 के अन्तर्गत अनाज	385	57	—	—	92	22
(ख) पब्लिक लॉ 480 के अन्तर्गत अनाज से भिन्न पदार्थ	57	32	4	—	—	—
(ग) अन्य खाद्य सहायता	45	36	—	162	97	32
2 कुल ऋण परिशोधन जिसमें	333	450	507	626	687	842
(क) मूलधन की अदायगियाँ	211	290	327	411	463	594
(ख) ब्याज की अदायगियाँ	122	160	189	215	224	248
3 विदेशी सहायता की निवल प्राप्ति (1-2)	863	341	159	712	1156	743

Source Economic Survey 1977-78 p 46

भारत को मिलने वाली विदेशी सहायता की राशि में 1967-68 के बाद में ही कमी आती चली गई किन्तु 1974-75 से पुनः वृद्धि होने लगी। 1972-73 में

विदेशी सहायता का स्तर सबसे नीचा था, अर्थात् केवल 159 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए। 1975-76 में स्तर सबसे ऊँचा रहा, इस वर्ष 1154 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई। 1976-77 में सहायता की राशि गिरकर 844 करोड़ रुपये और 1977-78 में 743 करोड़ रुपये रह गया। 1977-78 में विशुद्ध सहायता के नीचे स्तर को देखते हुए यह अनुमानित किया जाता है कि भविष्य में सहायता राशि का अनुपात और घटेगा। 1975-76 में सहायता राशि में वृद्धि मुख्यतः तेल उत्पादक मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास समूह से मिली सहायता के कारण हुआ। विदेशी सहायता के सन्दर्भ में यह उत्साहवर्धक बात है कि पिछले कुछ वर्षों में सहायता देने वाले कुछ देशों द्वारा दी गई सहायता की क्रिस्म में सुधार हुआ है। यूनाइटेड किंगडम से मिलने वाली सहायता, जो अब पिछले कुछ समय से मुकम्मिल और पर अनुदानों के रूप में रही है 1976-77 में पहले से अधिक थी। जर्मन संघीय गणराज्य ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास सभ की शर्तों पर सहायता दी। नीदरलैंड्स की सहायता भी अन्तर्राष्ट्रीय विकास सभ की शर्तों के अनुरूप थी और 1976-77 के दौरान इस सहायता में काफी वृद्धि कर दी गई। स्वीडन तथा नार्वे पहले से ही भारत को अनुदान के रूप में सहायता प्रदान कर रहे थे। कनाडा तथा डेनमार्क द्वारा अनुदान के रूप में दी गई सहायता में वृद्धि हुई है।

विदेशी सहायता के उपयोग के कुछ मुख्य क्षेत्र

विदेशी सहायता किसी देश की उत्पादन-क्षमता का विकास करने में किस सीमा तक सहायक हो सकती है, यह विदेशी सहायता के विवेकपूर्ण उपयोग पर निर्भर है। उपयोग-वस्तुओं के रूप में प्राप्त सहायता के प्रभाव का ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है, अतः हम भारत की उत्पादन-क्षमता (Productive Potential) की वृद्धि में विदेशी सहायता के योगदान को लेंगे—

(1) प्राप्त सहायता में से आधी से कुछ कम सहायता वस्तु रूप में रही है, जिसके अधिकांश भाग का उपयोग देश में खाद्यान्नों का आयात करने के लिए किया गया है। विदेशी सहायता के एक अंश का उपयोग कच्चे माल एवं प्रतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिए किया गया है।

(2) देश की सिंचाई क्षमता का विस्तार करके कृषि-उत्पादन की वृद्धि में विदेशी सहायता का योगदान विशेष महत्वपूर्ण रहा है। कृषि के कुछ क्षेत्रों में और ग्रन्थपालन के क्षेत्र में उत्पादन-तकनीकों के प्राधुनिकीकरण में भी विदेशी सहायता काफी लाभदायक सिद्ध हुई है।

(3) परिवहन, विशेषकर रेलवे विकास में सहायता का उपयोग हुआ है।

(4) विदेशी सहायता ने भारत में इस्पात जैसे मूलभूत उद्योग की उत्पादन-क्षमता से निर्माण करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है।

(5) दूर सेवाओं की व्यवस्था में भारतीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण में और देश में शिक्षण, गवेषणा तथा प्रशिक्षण संस्थानों के विस्तार और स्थापना में भी विदेशी सहायता का उपयोग मूल्यवान सिद्ध हुआ है।

ब्याज और मूलधन के भुगतान का बढ़ता हुआ भार

भारत पर विदेशी सहायता के सदर्भ में मूलधन और ब्याज के भुगतान का भार चिन्ताजनक रूप में बढ़ता जा रहा है, जैसा कि निम्नांकित आंकड़ों से स्पष्ट होगा—

(करोड़ रुपये में)

प्रवधि	ऋण परिशोधन	ब्याज का भुगतान	कुल ऋण परिशोधन
पहली आयोजना	10.5	13.3	23.8
दूसरी आयोजना	55.2	64.2	119.4
तीसरी आयोजना	305.6	237.0	542.5
1966-67	159.7	114.8	274.8
1970-71	289.5	160.5	450.0
1975-76	462.7	224.2	686.9
1976-77	507.4	247.3	754.7
1977-78 (अनुमानित)	593.7	248.0	841.7

Source: Economic Survey 1977-78, p. 113

वास्तव में उपयोग क्षमता (Utilisation capacity) को सीमित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण किसी देश के वर्तमान में लिए गए ऋणों के भविष्य में भुगतान कर सकने की क्षमता है। भारत विशाल निर्यात-क्षमता का अभी तक निर्माण नहीं कर पाया है। अतः भुगतान दायित्वों (Repayment Obligation) का बोझ और भी बिपन्न बन गया है। जब तक देश का निर्यात-उपार्जन (Export Earnings) काफी अधिक बढ़ नहीं जाता तब तक समस्या का दूसरा प्रभावी विकल्प एक कठिन प्रश्न है। सरकारी क्षेत्रों को विश्वास है कि भारत शीघ्र ही अपनी भुगतान क्षमता में तेजी से सुधार कर लेगा।

बढ़ बनाम अबाध सहायता

भारत को बद्ध और अबाध (Tied and untied) दोनों प्रकार की विदेशी सहायता प्राप्त होती है। समुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य कुछ देशों से प्राप्त होने वाली अधिकांश सहायता बद्ध सहायता के रूप में है। इसके अन्तर्गत उधार लेने वाले देश को ऋणदाता देश से वस्तुएं अथवा उपकरण खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ऋणदाता देश इस स्थिति का प्रायः अनुचित लाभ उठाने हैं और वस्तुओं की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों से काफी अधिक वसूल करते हैं। अबाध सहायता (Untied aid) में इस प्रकार का बन्धन नहीं होता। भारत को लम्बे अंतराल तक लगभग 70 से 90 प्रतिशत के बीच बद्ध सहायता मिलती रही है और इस प्रकार देश के लिए विदेशी सहायता बहुत महंगी सिद्ध हुई है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय भाव में बहुत अधिक मूल्य वस्तुओं पर भारत का चुकाना पड़ा है।

विदेशी सहायता से सम्बन्धित कुछ प्रश्न और समाधान के उपाय

विदेशी सहायता से सम्बन्धित प्रत्येक समस्याएँ देश के सामने उपस्थित हुई है, जिनमें मुख्य इस प्रकार हैं—

(1) मूलधन और व्याज के भुगतान का भाग निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

(2) प्राकृतिक प्रकोपों तथा अन्य संकटों के कारण समय-समय पर देश की अर्थ-व्यवस्था को भारी घबका पहुँचा है और फलस्वरूप ऋणों के मूलधन और व्याज को चुकाने में हमारे समक्ष बड़ी कठिनाई उपस्थित हुई है। भारत सरकार को भुगतान 1 या अधिक वर्ष तक स्थगित करने अथवा नए ऋण लेकर पुराने ऋण चुकाने और शर्तों को पुनः निर्धारित करने के प्रयत्न करने पड़े हैं। ऋण-राहत (Debt relief) की आवश्यकता में वृद्धि की यह स्थिति हमारे लिए दयनीय है।

(3) भारत को जो विदेशी ऋण मिले हैं उनमें से अधिकांश ऋणों के उपयोग पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्ध लगे रहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबन्ध वास्तव में देश के हितों की क्षति पहुँचाने वाले होते हैं, उदाहरणार्थ बड़-सहायता के अन्तर्गत भारत को सहायता देने वाले देश से ही निर्धारित वस्तुएँ खरीदनी पड़ती हैं और इनका मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय भाव से बहुत अधिक चुकाना पड़ता है।

(4) भारत को दी गई विदेशी सहायता में प्रोजेक्ट-सहायता (Project aid) का अनुपात अधिक रहा है। ऐसी सहायता में हमें क्षेत्र परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ही सहायता प्राप्त होती है। विश्व बैंक तथा विकसित देशों ने अधिकांशतः ऐसी ही सहायता स्वीकार की है। भारत को गैर-प्रोजेक्ट सहायता अधिक दी जानी चाहिए और सन्तोष की बात है कि कुछ वर्षों से भारत की इस माँग पर अधिक सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाने लगा है। भारत को गैर-प्रोजेक्ट सहायता में भी स्वतन्त्र सहायता अधिक स्वीकार है।

(5) विदेशी सहायता की स्वीकृति (Authorisation) तथा सहायता के प्रयोग (Utilisation) में काफी अन्तर बने रहना भी देश के हितों के प्रतिकूल है। इस अन्तर का एक बड़ा कारण यह रहा है कि प्रोजेक्ट सहायता अधिक मिली है, अतः सहायता का पूरा उपयोग करने में विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। गैर प्रोजेक्ट सहायता के उपयोग में अधिक कठिनाई नहीं होती।

(6) देश में निजी विदेशी पूँजी (Private Foreign Capital) के आवात को जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए या उतना नहीं मिला है। विदेशों में भारत की आर्थिक नीति के सम्बन्ध में काफी भ्रम पैदा हुआ है और वे भारत में अपनी पूँजी लगाने से कुछ हिचकिचाते हैं। भारत सरकार को अनावश्यक भ्रम का निराकरण करने हुए अपनी कर नीति में ऐसे संशोधन करने होंगे जिनसे विदेशी

पूँजीपति भारत में पूँजी लगाने में अनुरक्षा का अनुभव न करें। विदेशी निजी विनियोग के लिए आवश्यक उत्पन्न करना ही होगा।

(7) जो विदेशी सहायता प्राप्त हुई है, उसका प्रभावपूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है। कुछ क्षेत्रों में तो सहायता का उपयोग अनुचित ढंग से हुआ है। भारी मात्रा में विदेशी सहायता और घरेलू विनियोग के बावजूद देश में आर्थिक विपमना बढ़ती जा रही है उपयोग वस्तुओं का अभाव है और वस्तुओं की कीमतें बेहताशा बढ़ रही हैं।

विदेशी पूँजी के सम्बन्ध में उपस्थित कठिनाइयों का सामना करने के लिए और विदेशी सहायता पर आर्थिक विकास की निभरना कम करने के लिए भारत को निम्नलिखित बातों पर प्रभावी रूप में ध्यान देना होगा—

(1) विदेशी पूँजी का प्रयोग देनदार देश के निर्यात को बढ़ाने या आयात का घटाने के लिए किया जाना चाहिए।

(2) निर्यातों की वृद्धि और आयातों की कमी का समय इस तरह व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि मूलधन और व्याज का निर्धारित समय पर शोधन हो जाए।

(3) पूँजी अथवा ऋण की अदायगी के समय में देनदार देशों को अधिक माल लेने के लिए राजी किया जाना चाहिए।

(4) 1979 में पूँजी अथवा ऋण सम्बन्धी न्यून अधिक नहीं होने चाहिए। बरता उनके शोधन में राष्ट्रीय आय की वृद्धि का एक बहुत बड़ा भाग देश से बाहर चला जाएगा।

(5) पूँजी उत्पादक कार्यों में ही प्रयुक्त की जानी चाहिए और इस सम्बन्ध में प्रशासनिक कुशलता तथा मितव्ययिता पर पूरा बल दिया जाना चाहिए।

(6) परम्परागत कच्ची सामग्री के निर्यात के साथ-साथ निर्मिन और परम्परागत वस्तुओं के निर्यात को भी प्रोत्साहन दिया जाए।

(7) सार्वजनिक क्षेत्र के साथ ही निजी क्षेत्र में भी मितव्ययिता बरती जाए। विकास कार्यों का भी समय-समय पर मूल्यांकन किया जाए।

(8) देश की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप देश में कर लगाने और बसत करने की प्रणालियों में भी आवश्यक परिवर्तन किए जाएँ।

(9) यथासम्भव तकनीकी सहायता के लिए भारत में अधिकाधिक तकनीकी संस्थान कायम किए जाने चाहिए और विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजन के कार्यक्रमों को सीमित करना चाहिए।

(10) सहायता सम्बन्धी समझौते लम्बी अवधि के होने चाहिए क्योंकि कम अवधि के समझौते से अनिश्चितता की मात्रा बढ़ जाती है।

(11) बढ़ सहायता कम से कम ली जानी चाहिए। जो बढ़ सहायता पहले से ही है उसकी शर्तों में आवश्यक सुधार के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए।

1977-78 में विदेशी सहायता

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं. देश/संस्था	अप्रैल-दिसम्बर 1977 तक किए गए सहायता करार		
	परियोजना, निम्न सहायता जिसमें ऋण-राहत शामिल है	परियोजना सहायता	जोड़
1	2	3	4
1. जापान	2.4	—	2.4
2. कनाडा	44.2	0.7	44.9
3. पश्चिमी जर्मनी	40.2	97.7	137.9
4. जापान	68.0	30.6	98.0
5. नीदरलैंड	68.0	—	68.0
6. स्वीडन	46.3	—	46.3
7. ब्रिटेन	4.6	—	4.6
8. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक	—	214.7	214.7
9. आई. डी. ए.	—	547.4	547.4
10. सोवियत रुब	—	250.0 ¹	250.0 ¹
11. मउसी अरबिया फड	—	100.3	100.3
12. ओ. सी. ई. सी. विशेष फंड	—	—	—
13. यूरोपीय आविन समुदाय	10.7	—	10.7
योग	284.4	991.4 ²	1275.8 ²
सहायता का स्वरूप			प्रयुक्तता ³
जोड़ जिसमें			1585
(i) परियोजना निम्न सहायता			710
(ii) परियोजना सहायता			875

टिप्पणी : स्वीकृत सहायता के अंतर्गत भारत के रुपये तथा सहायता देने वाले देशों की अलग-अलग मुद्रा के बीच की नौ महीने की औसत विनिमय दर के आधार पर निकाले गए हैं। ऋण उपयोग के अंतर्गत तत्सम्बन्धी तारीखों को रुपये और सहायता देने वाले देश की मुद्रा के बीच द्रव्यमान वार्षिक वार्षिक विनिमय दरों पर आधारित है।

1 मिलियन इक्विवलेंट में।

2 रुपये 250 मिलियन इक्विवलेंट की सभी परियोजना सहायता शामिल नहीं है।

3 1977-78 के लिए अनुमान।

विदेशी ऋण और व्याज आदि का भुगतान

(करोड़ रुपये)

वर्ष	ऋण परिचोदन	व्याज का भुगतान	कुल ऋण परिचोदन
1	2	3	4
पहली आयाजना	10.5	13.3	23.8
दूसरी आयाजना	55.2	64.2	119.4
तीसरी आयाजना	305.6	237.0	542.5
1966-67	159.7	114.8	274.8
1967-68	210.7	122.3	333.0
1968-69	236.2	138.8	375.0
1969-70	268.5	144.0	412.5
1970-71	289.5	160.5	450.0
1971-72	299.3	180.0	479.3
1972-73	327.0	180.4	507.4
1973-74	399.9	195.9	595.8
1974-75	411.0	215.0	626.0
1975-76	462.7	223.6	686.3
1976-77	502.6	258.1	760.7

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (ROLE OF THE INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION)

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, जिसे कई बार विश्व बैंक भी कहकर पुकारा जाता है, की स्थापना जुलाई, 1944 में ब्रेटनवुड्स सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ही कर दी गई। कोष की स्थापना का लक्ष्य सदस्य-देशों की युगतान सम्बन्धी विषयताओं को दूर करना था किन्तु विश्व बैंक की स्थापना इसलिए की गई ताकि युद्ध के कारण उत्पन्न सदस्य-देशों की आर्थिक अवस्था की स्थिति को दूर किया जा सके और विकसशील एवं प्रविष्टित देशों को दीर्घकालीन ऋणों के रूप में सहायता दी जा सके ताकि वे प्रगति के पथ पर बढ़ सकें। इस सम्बन्ध में स्लाइडर का कहना है कि "बैंक और कोष दोनों अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ थी, जो अनुपूरक कार्यों से युक्त थी तथा जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्बन्धों के क्षेत्र में सहकारी कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया था।"¹

विश्व बैंक के उद्देश्य (The Objectives of World Bank)

विश्व बैंक भी कोष की भाँति प्रतीत के असन्तोषजनक अनुभव की उपज थी। यह उन युद्धोत्तर परिस्थितिमें एवं समस्याओं के कारण सगठित की गई त्रिनकी सफलतापूर्ण व्यवहारों और समस्याओं द्वारा सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता था। इस समय विशेष रूप से एक और तो उन अन्तर्राष्ट्रीय अनुदानों के दुर्भाग्य पूर्ण परिणामों की याद ताजा थी जो प्रथम विश्व-युद्ध के बाद प्रथम शताब्दी में किए गए; दूसरी और द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद पुनर्रचना और विकास में महायत्ना करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी की स्पष्ट आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति में दो आवश्यकताओं के कारण कुछ कदम उठाना जरूरी बन गया—(1) विश्व-युद्ध के बाद की

1 "The Bank and the Fund were to be twin International Institutions, complementary in function and designed to promote cooperative action in the field of International Monetary Relations."

जटिल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पकालीन पूँजी प्रदान की जाए जिसे व्यक्तिगत पूँजी या तो पूरा नहीं कर सकनी अथवा पूरा करना नहीं चाहती, (2) व्यक्तिगत अनुदान कोषों के व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाह को दीर्घकालीन रूप में प्रेरित किया जाए।

यह सोचा गया कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पूर्ण किया के माध्यम से की जा सकेगी। इस प्रकार एक स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की रचना की गई, जिसकी बनावट और संगठन बहुत कुछ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलता हुआ था। ब्रेटनवुड के सम्मेलन में जिन 44 देशों ने प्रतिनिधित्व किया उन सभी ने विश्व बैंक को स्वीकार नहीं किया। सोवियत रूस इसका सदस्य न बना। 1953 के अन्त तक इस बैंक में 54 देश सदस्य बन गए।

विश्व बैंक मुख्य रूप से चार उद्देश्यों का सेन्टर संगठन की गई—

1 सदस्यों को आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास कार्य में सहायता देना—विश्व बैंक का प्रथम मुख्य उद्देश्य यह था कि युद्ध में सदस्य देशों को जो क्षति हुई है उसे सुधारने के लिए पुनर्निर्माण और विकास की दृष्टि से सहायता दी जाए। वर्तमान में यह बैंक विकसित सदस्यों की अर्थ व्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण कार्य में वित्तीय सहायता देता है और अविकसित सदस्यों को पर्याप्त माना में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देकर उनके तीव्र आर्थिक विकास को सम्भव बनाता है।

2 अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी निवेश में वृद्धि करना—विश्व बैंक का दूसरा मुख्य उद्देश्य अल्पविकसित देशों को अविकसित देशों में उद्घाटन कार्य के लिए पूँजी का निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करता है। इसके लिए वह निवेश-वर्तकों को उनकी पूँजी की गारंटी देना है अथवा उनके निवेश या ऋण में हाथ बँटाता है।

3 दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन—विश्व बैंक द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाता है। यह अपने सदस्य देशों के उत्पादन के माध्यमों का विकास करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विनियोगों को प्रोत्साहन देना है ताकि सम्बन्धित देश में रोजगार प्रायः तथा जीवन-स्तर आदि ऊँचा उठाया जा सके।

4 शान्तिकालीन अर्थ व्यवस्था की स्थापना—युद्ध के समय देश की आवश्यकताओं की प्रकृति शान्तिकाल की अपेक्षा भिन्न होती है। युद्ध के बाद यह आवश्यकता हुई कि उस समय की अर्थ-व्यवस्था को शान्तिकालीन अर्थ-व्यवस्था में परिणत किया जाए। यह कार्य विश्व बैंक को सौंपा गया।

विश्व बैंक का संगठन

(The Organisation of World Bank)

जो देश 21 दिसम्बर, 1945 तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य बने केवल उन्हीं को विश्व बैंक के मूल सदस्य माना गया। कोई देश दो शर्तों पर विश्व बैंक का सदस्य बन सकता है। प्रथम उन देश के आर्थिक प्रगति में सदस्यों की मददगार शक्ति के बहुमत द्वारा स्वीकार किया जाए और दूसरे, वह देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

का सदस्य होना चाहिए। यदि कोई सदस्य कोष की सदस्यता से त्याग-पत्र देना है तो विषय बैंक से भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जानी है। कोष की सदस्यता त्यागने पर भी एक देश को ऐसी स्थिति में बैंक का सदस्य बनाए रखा जा सकता है जबकि उसके तत्कालीन सदस्यों में से 75 प्रतिशत उसके पक्ष में मत प्रकट करें। बैंक की सदस्यता केवल तभी तक बनी रहती है जब तक कि सम्बन्धित देश उसके नियमों का पालन करता रहे। बैंक की सदस्यता का परित्याग एक लिखित सूचना के आधार पर भी किया जा सकता है। इस प्रकार त्याग-पत्र देने से पूर्व सदस्य को चाहिए कि वह ऐसा करने से पूर्व बैंक के सारे दायित्वों का मुहताब करें। 30 जून, 1977 तक बैंक की सदस्य संख्या 122 तक पहुँच गई और 1979 के अन्त तक 150 तक पहुँचने की प्रत्याशा है।

बैंक की शक्तियाँ संचालक मण्डल में निहित होनी हैं जिसके अन्तर्गत समस्त सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है। बैंक के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का संचालन कार्यपालिका संचालकों द्वारा किया जाता है जिनकी शक्तियाँ संचालक मण्डल द्वारा हस्तान्तरित की गई होती हैं। अध्यक्ष के अधीन अन्तर्राष्ट्रीय कर्मचारियों का एक स्टॉफ कार्य करता है। यह स्टॉफ अध्यक्ष के निदेशन के अधीन कार्य करता है। अध्यक्ष का चयन कार्यपालिका संचालकों द्वारा किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भाँति बैंक भी विशेष संगठन है। इसने दुनियाँ के अधिकांश राज्यों को पच्चीस बार एक साथ मिलाया है।

परम्परागत रूप से प्रायः सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों को ही बैंक का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। बैंक की सभाओं में भाग लेने के लिए स्थानापन्न गवर्नर भी नियुक्त किए जाते हैं किन्तु वे मतदान का अधिकार नहीं रखते। वैसे सैद्धांतिक दृष्टि से विश्व बैंक की सारी शक्तियाँ गवर्नर मण्डल में निहित हैं किन्तु व्यवहार में इसके अधिकांश अधिकारों का प्रयोग संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है।

प्रशासकीय संचालक मण्डल की सदस्य संख्या कम से कम बारह होती है। इनमें से पाँच की नियुक्ति वे देश करते हैं जिनके चन्दे की मात्रा सबसे अधिक है। प्रत्येक संचालक का कार्यकाल दो वर्ष होता है और प्रतिमास इसकी सभाएँ आयोजित की जाती हैं। संचालकों द्वारा किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त कर लिया जाता है जो उनकी सभाओं का सभापतित्व करता है। वह अध्यक्ष बैंक का प्रमुख अधिकारी होता है। उसे मतदाधिकार प्राप्त नहीं होता, किन्तु वह निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है।

बैंक की एक सलाहकार समिति होनी है जो उसकी सामान्य नीति के सम्बन्ध में परामर्श देती है। इस समिति के सदस्यों की संख्या कम से कम 7 होती है। समिति की सभा का वर्ष में एक बार आयोजन होना जरूरी है।

संचालक मण्डल द्वारा एक अन्य समिति भी नियुक्त की जाती है जिसे ऋण समिति कहा जाता है। जब कोई देश ऋण के लिए कहना है तो उसकी उपयुक्तता की जाँच इस समिति द्वारा की जाती है। इसमें ऋण के लिए प्रार्थना करने वाले

देश का भी एक सदस्य बैठता है। विश्व बैंक का प्रमुख कार्यालय वाशिंगटन में है। इसके अनिरिक्त न्युयॉर्क, लन्दन तथा वेरिस में भी इसके कार्यालय हैं।

पूँजी (Capital)

प्रारम्भ में विश्व बैंक की अधिकृत पूँजी 10 बिलियन (100 000 मिलियन) अमेरिका डॉलर थी जो 100,000 डॉलर राशि मूल्य के प्रत्येक 10,000 अंशों में विभाजित थी। प्रत्येक राष्ट्र की अंश पूँजी निर्धारित कर दी गई थी। बैंक की इस अधिकृत पूँजी में से कुल 9.4 बिलियन डॉलर (9400 मिलियन डॉलर) राशि 44 सदस्य देशों से चन्दो द्वारा प्राप्त हुई थी।

बैंक के प्रत्येक सदस्य का चन्दा निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किया गया है—

(क) प्रत्येक सदस्य को अपने कुल चन्दे का 2 प्रतिशत स्वयं अथवा अमेरिकी डॉलरों में बैंक के पास तुरन्त जमा करना पड़ता है। बैंक को अधिकार है कि वह इस स्वयं राशि को ऋण देकर उपभोग करे।

(ख) प्रत्येक सदस्य को अपने कुल चन्दे का 18 प्रतिशत अपनी राष्ट्रीय मुद्रा में बैंक को देना पड़ता है।

(ग) कुल चन्दे का शेष 80 प्रतिशत भाग आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों से लिया जा सकता है।

अभिप्राय यह हुआ कि विश्व बैंक को अधिकृत पूँजी का 20 प्रतिशत भाग स्वयं अथवा अमेरिकी डॉलरों में तथा सदस्य देशों की राष्ट्रीय मुद्रा में प्राप्त होता है और इस प्रदत्त पूँजी (Paid-up-Capital) का विश्व बैंक अपने ऋण साधनों के रूप में उपयोग कर सकता है।

बैंक के कार्यों के विस्तार और सदस्यों द्वारा बैंक से अधिक मात्रा में ऋण लेने की प्रवृत्ति के कारण विश्व बैंक की पूँजी में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। फलस्वरूप बैंक की अभिदत्त पूँजी (Subscribed Capital) कुछ अंशों पूर्व बढ़कर 25,197.3 मिलियन डॉलर हो गई और बैंक की अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) भी बढ़कर 27,000 मिलियन डॉलर तक जा पहुँची। यह स्थिति 1972-73 तक थी। 1975 के अन्त तक विश्व बैंक की कुल स्वीकृत पूँजी 2700 करोड़ डॉलर थी जो 128 सदस्यों में विभाजित थी। अम्यशों (Quotas) की दृष्टि से अमेरिका का स्थान प्रथम है और फिर क्रमशः इंग्लैंड, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, जापान और भारत का है। 1975 के अन्त में अमेरिका के अम्यश की मात्रा 635 करोड़ डॉलर अर्थात् कुल का 23.8 प्रतिशत थी। इंग्लैंड के अम्यश की मात्रा 260 करोड़ डॉलर अर्थात् कुल का 11.4 प्रतिशत थी। भारत के अम्यश की मात्रा 90 करोड़ डॉलर का अर्थात् कुल का 3.5 प्रतिशत थी।

उल्लेखनीय है कि प्रत्येक सदस्य का मताधिकार उसके अम्यश के आधार पर निर्धारित किया जाता है। मताधिकार के अन्तर्गत प्रत्येक अंश के लिए एक मत के अनिरिक्त प्रत्येक सदस्य को 250 मत का अधिकार है। इस प्रकार भारत का

मताधिकार $250 + 9000 = 9250$ है। भारत का ग्रम्यंश 90 करोड़ डॉलर है और चूँकि एक ग्रंश 1 लाख डॉलर का है अतः प्रति ग्रंश एक मत से 90 करोड़ डॉलर पर 9000 मत हुए और 250 सदस्यता के अतिरिक्त मत हुए, इस प्रकार कुल मताधिकार 9250 हुए। मताधिकार प्रतिशत को लें तो 1975 के अन्त में अमेरिका का यह प्रतिशत 25, इंग्लैंड का 10.3, पश्चिमी जर्मनी का 5.1, फ्रांस का 4.8, जापान का 4.0 और भारत का 3.2 था।

बैंक की पूँजी की सुरक्षाएँ (Safeguards of the Bank-Resources)

बैंक द्वारा सदस्य-देशों के क्षेत्र में किसी भी व्यापारी उद्यम प्रथवा सरकारों को कर्ज की गारन्टी दी जाती है। उनमें प्रशस्तान किए जाते हैं प्रथवा स्वयं कर्ज दिए जा सकते हैं। जब बैंक ने प्रपना कर्ज सरकार प्रथवा उसके किसी राजनीतिक उप-सम्भाग को नहीं दिया है और किसी गैर-सरकारी प्रोजेक्ट को दिया है तो जिस देश की सीमा में वह प्रोजेक्ट स्थित है उस देश की सरकार उस कर्ज के पुनर्मुग्तान प्रथवा व्याज के भुगतान की पूरी पूरी गारन्टी नहीं दे सकती, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं होता कि बैंक की पंजी डब जाएगी।

बैंक के स्रोतों की रक्षा के लिए तथा उनके उपयुक्त प्रयोग की व्यवस्था के लिए भार अतिरिक्त सुरक्षाएँ स्थापित की गई हैं—

1. कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर ऋण केवल पुनर्रचना तथा विकास के विशेष प्रोजेक्टों को ही दिया जाना चाहिए। बैंक द्वारा किसी प्रकार का बर्जा या गारंटी दी जानी चाहिए कि उस विशेष प्रोजेक्ट की आवेदित धन प्राप्त किया जाए अथवा नहीं। बैंक को यह देखना चाहिए कि उसके कोष का प्रयोग उत्पादन के लिए किया जाए, बैंक अथवा कम महत्व के विषयों में उनको न लगाया जाए।

2 वैक यह देखता है कि कर्ज लेने वाला अथवा उसकी गारन्टी देने वाला देश कर्ज के दायित्वों को निभाने की स्थिति में हो। पहले जो गैर-सरकारी ऋणदाता थे वे प्रायः यही देखा करते थे कि कर्ज लेने वाला व्यक्ति व्याज देने और पुनर्मुगतान करने में योग्य है अथवा नहीं है। उस समय हस्तान्तरण की समस्या पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। एक अन्तर्राष्ट्रीय कर्ज के शुद्ध पुनर्मुगतान के लिए यह जरूरी है कि कर्ज लेने वाले देश के मुद्रातान सन्तुलन के खालू लेख में अतिरिक्त हो और कर्ज देने वाले देश के गल तथा सेवाओं के आयात अतिरिक्त की स्थिति में हो। ये शर्तें पूरी होती हैं या नहीं, यह बात सामान्यतः अपनाई गई वार्षिक, मौद्रिक एवं व्यापारिक नीतियों पर निर्भर करती है। इसके अलावा प्रभावशील व्यापार चक्र का स्तर तथा अन्य ऐसे ही चक्र भी प्रभाव डालते हैं जिन पर निम्नी कर्जदाता अथवा कर्जदाता का कोई नियन्त्रण नहीं है।

वैसे कोई भी निश्चय के साथ इस बात की भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि अन्तर्राष्ट्रीय वर्ज या उसके मुग्तान में क्या-क्या कठिनाइयाँ आएँगी। यहाँ तक कि बैंक का विशेषज्ञ भी इससे अनभिज्ञ रहता है। यदि वर्ज लेने वाला देश गम्भीर रूप

से विनिमय के प्रभाव से पीड़ित है तो बैंक उसके कर्ज पर व्याज की शर्तों को हल्का कर सकता है। यह भी हो सकता है कि तीन वर्ष तक व्याज का भुगतान मर्यादित-देश अपनी मुद्रा में करे। इस काल में उस देश के सामने विनिमय की समस्या नहीं रहेगी।

3 बैंक से लिए जाने वाले कर्ज की एक अन्य सुरक्षा का यह प्रावधान है कि इस प्रकार प्राप्त स्रोतों का प्रयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाएगा जिनके लिए कर्ज दिया गया है।

4 बैंक द्वारा दिए गए कर्जों सामान्य रूप से उसी विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध करते हैं जो सम्बन्धित प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक है। किसी भी प्रोजेक्ट का स्थानीय मुद्रा का व्यय उस कोष से हो पूरा किया जाना चाहिए जो उस देश में प्राप्त किया गया है। इसका अर्थ यह स्थिति हो सकती है जब आवश्यक स्थानीय मुद्रा उपयुक्त शर्तों पर कर्जदार द्वारा प्राप्त न की जा सके।

बैंक की कार्य-प्रणाली

(The Functions of the Bank)

विश्व बैंक द्वारा मुख्य रूप से विकास योजनाओं के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। यह एक देश को केवल तभी ऋण देता है जबकि उसे यह विश्वास हो जाए कि सदस्य देश ऋण लेने के योग्य है और अन्य साधनों से उसे उचित शर्तों पर ऋण प्राप्त नहीं हो रहा है।

विश्व बैंक द्वारा अपनी पूँजी में से प्रत्यक्ष रूप से ऋण दिए जाते हैं। कई बार यह उधार सी गई पूँजी में से ऋण प्रदान करता है। यह स्वयं गारण्टी देकर भी ऋण दिला सकता है। इस प्रकार की गारण्टी देने से पूर्व बैंक यह देख लेता है कि ऋण देने की शर्तें उचित तथा न्यायपूर्ण हैं, जिस कार्य के लिए ऋण लिया जा रहा है वह उचित है, ऋण लेने वाला देश उसे वापिस कर सकता है तथा सम्बन्धित देश की सरकार भी उस ऋण की गारण्टी दे रही है।

बैंक द्वारा जो ऋण देते समय एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। विश्व बैंक का सम्बन्ध या तो सदस्य देश की सरकार अथवा उसके केन्द्रीय बैंक से रहता है वह सदस्य देश की गैर सरकारी संस्था को केवल तभी ऋण प्रदान करता है जबकि उस देश की सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक उस ऋण के मूलधन, व्याज एवं अन्य खर्चों के भुगतानों की गारण्टी प्रदान कर सके।

विश्व बैंक द्वारा दिए गए ऋण की राशि को सम्बन्धित देश के केन्द्रीय बैंक में जमा किया जाता है और वहाँ से कर्ज लेने वाली संस्था अपनी आवश्यकता के अनुसार धन ले सकती है।

ऋण की मात्रा और गारण्टी आदि के निर्धारण का कार्य स्वयं बैंक द्वारा किया जा सकता है।

विश्व बैंक ऋण देते समय ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा सकता कि ऋण देने वाले देश में ही खर्च किया जाए।

ऋण लेने वाला देश प्राप्त राशि को केवल उसी विकास योजना के काम में जा सकता है जिसके लिए ऋण लिया गया है। विश्व बैंक निरीक्षण का भी अधिकार रखता है।

विश्व बैंक के पास जितनी प्राप्ति पूँजी और संचित निधि होती है वह उससे अधिक ऋण न तो स्वयं दे सकता है और न गारन्टी देकर किसी से दिला सकता है।

जब विश्व बैंक किसी को गारन्टी दिलाकर कर्ज दिलाता है तो कर्ज लेने वाला भुगतान करते समय स्वयं अथवा उसी मुद्रा को काम में लेगा जिसमें कर्ज दिया गया था।

जब बैंक स्वयं गारन्टी देकर ऋण दिलाता है तो उस पर 1 या 1½ प्रतिशत कमीशन होता है। यह कमीशन एक विशेष कोष में जमा किया जाता है। जब कोई कर्ज वाला कर्ज का भुगतान नहीं कर पाता तो विश्व बैंक इसी कोष में से उसका भुगतान करता है।

सिद्धान्त रूप से बैंक एक अन्तिम ऋणदाता है। सामान्य नियम यह है कि बैंक केवल उसी समय हस्तक्षेप करेगा जबकि उसे यह संतोष हो जाए कि सदस्य देश ऋण लेने योग्य है और उचित शर्तों पर वह अन्य वही से भी ऋण प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार बैंक वर्तमान साख-सुविधाओं को केवल सहायता प्रदान करती है, उनके ऊपर उठकर सहयोग नहीं देती। साख के अन्य स्रोतों के साथ इसकी प्रतियोगिता नहीं है। बैंक के उधार देने की क्षमता, कुल योगदान एवं सुरक्षाओं अथवा प्रतिरेकों को मिलाकर बनती है। बैंक अपने कुल योगदान में से केवल 20 प्रतिशत ही उधार दे सकता है। यह स्वयं के बॉण्ड्स की वित्री करके उधार दे सकती है अथवा ऋणों की गारन्टी देकर निजी ऋण दान को भी प्रोत्साहित कर सकता है। ऋण दान सम्बन्धी निम्न कार्यों का अध्ययन करने के बाद हमें बैंक के कार्यों का स्पष्ट ज्ञान हो सकता है—

(1) बैंक के कोष में से प्रत्यक्ष ऋण (Direct Loan from the Bank's Own Funds)—बैंक के पास उसके सदस्यों द्वारा दिया गया धन रहता है। इसके प्रतिरिक्त कुछ सुरक्षित भण्डार एवं प्रतिरेक भी रहते हैं। इन सब में से बैंक 20 प्रतिशत उधार दे सकता है। इस 20 प्रतिशत में दो प्रतिशत स्वर्ण के रूप में होता है जिसका प्रयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। दोष 18 प्रतिशत भाग जिस देश की मुद्रा में दिया जा रहा है उसकी स्वीकृति आवश्यक है। यह प्रावधान सदस्यों द्वारा दिए गए ऋण पर उनके नियम को लागू करता है। एक बार उधार देने के बाद सदस्य को यह अधिकार नहीं होता कि वह कर्जदार से प्राप्त करने में नियन्त्रण रख सके।

व्याज और मूलधन का जो भुगतान किया जाता है वह मुद्रा के उसी मूल्य में होता है जो उधार देने के समय था। समझौते-पत्र में कहा गया है कि "ये भुगतान" के उन भुगतानों के मूल्य के बराबर होंगे जो कर्ज देने के समय था। यह

भुगतान उस मुद्रा में होगा जो बैंक के कुल मनदानाओं के 3/4 बहुमन से इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा। इन प्रावधान के अनुसार पुनर्भुगतान अवमूल्यन मुद्रा में नहीं किया जा सकता।”

(2) बैंक द्वारा उधार लिए गए कोष में से प्रत्यक्ष ऋण देना (Direct Loan from Funds Borrowed by the Bank)—बैंक को यह शक्ति दी गई है कि वह अपने बॉण्ड प्रसारित कर सके। इसके बॉण्ड नामान्वित विश्व बैंक के बॉण्ड क रूप में जाने जाते हैं। बैंक द्वारा जिस देश के बाजार के लिए बॉण्ड प्रसारित किए जाते हैं वह उस देश से पहले स्वीकृति प्राप्त करता है। इसके अनिवार्य यदि बॉण्ड के अनिवार्य किसी मुद्रा में ऋण दिया जा रहा है तो उस मुद्रा बाजार देश की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। इस स्वीकृति के प्रभाव में हो सकता है कि सदस्य देश मान्य और सेवाओं के उन दावों को स्वीकार न करें जो बैंक के माध्यमों से जन्म लेते हैं। स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही गई मुद्रा का स्वतन्त्रतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है।

बैंक अपने उधार लिए गए कोष में से उतना ही ऋण दे सकता है जितना उसने स्वयं उधार लिया है। उदाहरण के लिए, यदि बैंक अपने बॉण्ड्स बेचकर 10 बिलियन डॉलर प्राप्त करे तो वह इतना कर्ज नहीं दे सकता कि इसकी मात्रा 10 बिलियन डॉलर से अधिक बढ़ जाए। इस प्रावधान द्वारा उन देशों के भुगतान संतुलन की रक्षा करने का प्रयास किया जाता है जिनका बैंक द्वारा ली गई मात्रा से अधिक मात्रा में भुगतान करना पड़े।

अब तक बैंक से अधिकतर डॉलर की मांग की गई है और इस मांग को पूरा करने के लिए उसने अपने बॉण्ड्स (Bonds) अमेरिकी बाजार में बेचे हैं। बॉण्ड्स के खरीददार दुनिया की कई मुश्किल काम नहीं है।

(3) गारन्टीज (Guarantees)—जो कर्ज लेने वाले उपयुक्त शर्तों पर दूसरी जगहों में कर्ज प्राप्त नहीं कर पाते वे बैंक में प्रार्थना करते हैं और यदि बैंक इस प्रार्थना को स्वीकार करले तो वह अपने कोष में से कर्ज दे देती है अथवा कर्ज लेने वाले का ध्यान निजी पूंजीगत बाजार की ओर इंगित कर देती है, किन्तु ऐसा करते समय वह पूर्ण अथवा आंशिक रूप से गारन्टी प्रदान करती है। बैंक द्वारा ऐसे ऋणों के लिए केवल तभी गारन्टी प्रदान की जाती है जब वह पहले उन देशों की स्वीकृति प्राप्त करले जिनके बाजारों से कोष एकत्रित किया जाएगा तथा जिस देश की मुद्रा में वह ऋण दिया जाएगा। एक बार स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद सम्बन्धित देशों का वापसी के सम्बन्ध में कोई नियन्त्रण नहीं रहना। प्रारम्भ में यह विश्वास किया गया था कि निजी ऋणों को गारन्टी देना, बैंक का मुख्य कार्य रहेगा, किन्तु अनुभव से यह सिद्ध नहीं हुआ।

बैंक के कार्यों का लेखा-जोखा

(An Account of the Functions of World Bank)

विश्व बैंक द्वारा अपनी स्थापना से अब तक किए गए कार्यों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व उत्तेजनशील कार्य ऋणों से सम्बन्धित है। बैंक ने अपनी स्थापना से

30 जून, 1975 तक लगभग 113 सदस्य देशों को कुल 24690 मिलियन डॉलर के लगभग 1151 ऋणों की स्वीकृति प्रदान की। चूंकि ऋणों के वितरण में समय लग जाता है, अतः कुछ असें पूर्व तक उपरोक्त स्वीकृत ऋणों में से लगभग 50-55 प्रतिशत ऋणों का ही वितरण किया जा सका था। इस बैंक द्वारा सबसे अधिक ऋण मध्य विकसित राष्ट्रों को उनके विकास कार्यों के लिए स्वीकृत किए जाते हैं। प्रकेले वित्तीय वर्ष 1975 में ही विश्व बैंक ने 51 देशों को 4319.7 मिलियन डॉलर के 112 ऋण स्वीकृत किए थे जो अपने आप में एक रिकार्ड था। विश्व बैंक द्वारा दिए गए ऋणों का बहुत बड़ा भाग विकास कार्यों के लिए स्वीकृत किया गया है जिसमें सबसे अधिक ऋण यातायात एवं परिवहन विकास के लिए, तत्पश्चात् विद्युत विकास के लिए दिए गए हैं। उद्योगों और कृषि क्षेत्र के लिए ऋण तीसरे और चौथे स्थान पर आते हैं। विश्व बैंक ने पिछड़े और विकासशील राष्ट्रों को ऋणों की स्वीकृति में प्राथमिकता दी है।

विश्व बैंक विकास कार्यों के लिए धन की व्यवस्था करने के अलावा मर्द्ध-विकसित तथा अर्द्धविकसित देशों की तकनीकी एवं प्रौद्योगिक सहायता भी प्रदान करता है। पश्चिमी यूरोप, अमेरिका के विभिन्न देशों तथा जापान ने जो अद्वितीय सम्पन्नता प्राप्त की है उसका श्रेय बहुत कुछ विश्व बैंक को दिया जा सकता है। विश्व बैंक अर्द्धविकसित सदस्य राष्ट्रों में आर्थिक सर्वेक्षण की व्यवस्था करता है। यह इन देशों में प्रौद्योगिक, परिवहन, प्राकृतिक सम्पदा आदि के विकास की सम्भावनाओं की जाँच करता है। विभिन्न आयोजना कार्यों में सहायता के लिए बैंक के विशेषज्ञों को भेजा जाता है। यह बैंक विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं की सर्वेक्षण और अनुसंधान बाधों के लिए सहायता प्रदान करता है। बैंक यूनेस्को, साक्षान्त कृषि संगठन और समुक्त राष्ट्र सभ के विशेष विकास कोष से प्रावधान सहायता भी प्रदान करता है। हममें सन्देह नहीं कि पिछड़े देशों की अर्थव्यवस्था को सुधारने और उनके उद्धारन को बढ़ाने में विश्व बैंक का सहायनीय सहयोग रहा है।

विश्व बैंक विकासशील सदस्य राष्ट्रों के अधिकारियों और विशेषज्ञों को प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करता है। इसके अतिरिक्त सदस्य राष्ट्रों के पारस्परिक विवादों का शान्तिपूर्ण निपटारा करने के लिए निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में भी बैंक अपनी सेवाएँ देना रहा है। विश्व बैंक की अध्यक्षता के कारण ही भारत एवं पाक नहर-विवाद का निपटारा हुआ और 1956 में स्वेज नहर विवाद के निपटाने में भी बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

विश्व बैंक ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं की स्थापना में सहयोग दिया। ये संस्थाएँ सीधे अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों से अधिक विकास और पुनर्निर्माण के लिए दीर्घकालीन विदेशी पूँजी विनियोग करती हैं। 1956 में विश्व बैंक की एक पूरक और सम्बद्ध संस्था के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation) की स्थापना की गई और 1960 में अन्तर्राष्ट्रीय विकास (International Development Association) की स्थापना भी बैंक ने ही

प्रयासों का परिणाम है। इनके अतिरिक्त, फोर्ड एवं राकफेलर संस्थानों द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता से विश्व बैंक ने एक आर्थिक विकास संस्थान (Economic Development Institute) की स्थापना की है जहाँ अर्थव्यवस्था के विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है।

बैंक विकासशील राष्ट्रों को ऋण दिलाने के लिए समय-समय पर ऋणदाता देशों की बैठकें आयोजित करना है। भारत को विकास कार्यों में ऋण देने के लिए विश्व बैंक ने भारत सहायता क्लब (Aid India Club) की स्थापना की और इसी प्रकार पाकिस्तान के लिए भी सहायता क्लब बनाया गया।

बैंक के कार्यों की आलोचना

विश्व बैंक ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पुनर्निर्माण विकास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तथापि कई कारणों से बैंक के कार्य क्लब आलोचना के पात्र हैं। बैंक पर प्रायः आरोप लगाए जाते हैं कि— (1) बैंक की व्याज दर अधिक है। अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से 7.25 प्रतिशत व्याज की दर इतनी अधिक है कि ऋण-भुगतान का भार बहुत अधिक हो जाता है। (2) व्याज की ऊँची दर के अतिरिक्त बैंक प्रतिशत का अतिरिक्त कमिशन भी लेता है जो अनुचित है। वाणिज्य मित्राणा की कीमत पर सहायता की भावना को भुलाना उचित नहीं। (3) बैंक यह है कि बैंक प्रत्येक उधारकर्ता देश से उसकी आर्थिक एवं भुगतान मामलों के अनुसार व्याज और कमिशन प्राप्त करे। (4) बैंक उधारकर्ता सदस्य का ऋण देने से पूर्व उसकी ऋण-भुगतान शक्ति का अध्ययन करता है जो उचित नहीं है। ऋण भुगतान की शक्ति का ऋण के उत्पादन उपयोग के उपरान्त उत्पन्न होनी है, पहले नहीं। यदि ऋण प्राप्त करने से पूर्व ही उधारकर्ता देश में ऋण-भुगतान शक्ति मौजूद है तो वह ऋण ही क्यों लेगा? (5) बैंक ने अर्थ-व्यवस्था के विकास को काफी मात्रा में ऋण तो दिए हैं लेकिन फिर भी ये ऋण उनकी वित्तीय आवश्यकताओं के मुकाबल बहुत कम हैं। (6) बैंक का ऋण वितरण का कार्य भी बहुत विलम्बपूर्ण है।

विश्व बैंक और भारत

भारत विश्व बैंक के संस्थापक सदस्यों में से एक है और बैंक के पाँच बड़े अंशधारियों में होने के नाते, उसको बैंक के कार्य संचालक मण्डल में स्थायी स्थान प्राप्त है। बैंक भारत में अपने विशेषज्ञों की टोलियाँ भेजकर भारत की विभिन्न आर्थिक विकास योजनाओं का अध्ययन करता है। भारत की आर्थिक विकास योजनाओं की पूर्ति के लिए विश्व बैंक ने काफी सहायता दी है। 30 जून, 1975 तक विश्व बैंक ने 113 देशों को कुल मिलाकर 24609 मिलियन डॉलर के जो 1151 ऋण स्वीकृत किए उनमें से भारत को कुल 1536 मिलियन डॉलर के 44 ऋण प्राप्त हुए हैं। अनेकों वित्तीय वर्षों 1975 में विश्व बैंक से भारत को 209 मिलियन डॉलर के दो ऋण मिले हैं। भारत को विश्व बैंक से जिन विकास

कार्यों के लिए ऋण मिले हैं उनमें मुख्य हैं—रेलो का विकास और सुधार, कृषि विकास, व्यास बांध योजना, दामोदर घाटी योजना, कोयला उद्योग विकास, टाटा लोहा इस्पात उद्योग तथा इण्डियन प्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी का विकास, कलकत्ता एव मद्रास बन्दरगाहों का विकास, औद्योगिक साख एव विनियोग निगम, रासायनिक खाद उद्योगों का विकास आदि। बैंक द्वारा राजस्थान की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 1975 तक 140 करोड़ रुपए अर्थात् 200 मिलियन डॉलर से भी अधिक के ऋण और सहायता स्वीकृत किए गए हैं। 1957 से ही भारत में विश्व बैंक का एक स्थायी प्रतिनिधि रहता आया है। विश्व बैंक के प्रयासों के कारण ही दस विकसित राष्ट्रों का एक सघ 'भारत सहायता क्लब' (Aid India Club) के नाम से अस्तित्व में आया है। इस क्लब की बैठकें भारत को आर्थिक सहायता देने के लिए बैंक द्वारा आयोजित की जाती हैं। फिर भी बैंक ने भारत की विकास आवश्यकताओं के मुकाबले बहुत कम ऋण दिया है और बैंक का व्यवहार पक्षपातपूर्ण भी रहा है। बैंक ने एशिया और अफ्रीका के देशों के साथ सीतेला सा व्यवहार करते हुए यूरोप और पाँच राष्ट्रों के मुकाबले बहुत कम ऋण दिए हैं। भारत से ऋणों पर 2.5% से लेकर 5-8 प्रतिशत तक व्याज लिया गया है जो बहुत अधिक है। नए ऋणों पर व्याज दर 8 प्रतिशत से 8½ प्रतिशत तक ऊँची कर दी गई है। ऋणों के उपयोग पर प्रतिबन्ध की नीति भी उचित नहीं है। विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण केवल उन्हीं योजनाओं पर व्यय किए जा सकते हैं जिनके लिए वे स्वीकृत किए गए हैं। यह उचित नहीं है कि आवश्यकता पड़ने पर ऐसे ऋणों का दूसरा अधिक वाञ्छित उपयोग न किया जाए।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास-संघ

(International Development Association)

जैसा कि कहा जा चुका है, अन्तर्राष्ट्रीय विकास-संघ विश्व-बैंक से सम्बन्धित है। इसकी स्थापना मिनटवर, 1960 में की गई थी। अल्पविकसित देशों को आसाम शर्तों पर ऋण देने के लिए ही इस नई संस्था की स्थापना की गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास-संघ का उद्देश्य अल्पविकसित देशों को परिवहन, विद्युत-मंचार, मिर्चाई, वाट-निगमन, आदि के लिए ऋण प्रदान करना है। यह सदस्य देशों को आवास-गृहों के निर्माण, पेय जल की आपूर्ति, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि से सम्बन्धित योजनाओं के लिए भी ऋण देता है। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय विकास-संघ विश्व-बैंक के पूरक के रूप में अविकसित सदस्य देशों के आर्थिक विकास के लिए सस्ता दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। इन पर व्याज की कम दर कर ली जाती है। दीर्घकालीन ऋणों का मुग्तान देश की मुद्रा में ही ले लिया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास-संघ की कुल पूँजी 1000 मिलियन डॉलर है। सघ के सदस्य दो श्रेणियों में विभाजित हैं। पहली श्रेणी में आर्थिक दृष्टि से अति विकसित 18 देश हैं जो अपना चन्द्रा स्वर्ण तथा परिवर्तनीय मुद्रा में देते हैं। दूसरी श्रेणी में अल्पविकसित 76 देश हैं जो अपने चन्दे का 10 प्र. श. भाग स्वर्ण में और शेष

90 प्रश्न भाग अपनी मुद्रा में देने हैं। विकास सच का प्रबन्ध उन्हीं अधिकारियों के हाथों में है जो विश्व-बैंक का संचालन करते हैं। आवश्यकानुसार सच के लिए पृथक् कर्मचारी अधिकारी भी नियुक्त किए जाते हैं।

आर्थिक विकास के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ का विशेष कोष

संयुक्तराष्ट्र के इस विशेष कोष की स्थापना 1 जनवरी, 1959 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पिछड़े तथा अल्पविकसित देशों का आर्थिक सामाजिक एवं तकनीकी विकास के लिए धनसम्भव महायत्ना प्रदान करना है। कोष का प्रबन्ध मदक राष्ट्रसंघ के हाथों में है। कोष द्वारा समय-समय पर निश्चित उद्देश्यों के लिए भारत को ऋण प्राप्त होते रहे हैं।

व्यापार विकास सम्मेलन

व्यापार और विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना कुछ ही वर्षों पूर्व सन् 1964 में हुई थी। इस सम्मेलन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विषमताओं को दूर करना और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना है। यह सम्मेलन राष्ट्रों को आपस में प्रतिस्पर्धा से बचाता है तथा उन्हें अधिकाधिक निर्णयों के लिए प्रोत्साहित करता है।

संयुक्तराष्ट्र विकास कार्यक्रम

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सन् 1966 से चालू है। यह विकासशील देशों की आर्थिक सम्भावनाओं और उनके सर्वोत्तम उपयोग की योजना बनाने हेतु आवश्यक सर्वेक्षण और अध्ययन करता है। इस प्रकार विकास-कार्यक्रम की महती उपयोगिता है। वर्तमान में संयुक्तराष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 10 हजार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ लगभग 130 से भी अधिक देशों में विकास-परियोजनाओं में कार्यरत हैं। ये परियोजनाएँ बड़ी व्ययसाध्य हैं। इन पर करोड़ों डॉलर का व्यय होना है। यह व्यवस्था है कि जिन देशों में इन परियोजनाओं पर कार्य हो रहा हो, उन्हें परियोजना का कुल व्यय देना पड़ता है।

मूल्यांकन

(Evaluation)

विशेष एजेंसियों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है एवं सैद्धान्तिक रूप से उनका कार्य सराहनीय है। मार्क्सिस्ती क्षेत्र में इनका कार्य उपयोगी है। एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण होना है। विशेष एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण अधिक सम्पूर्ण एवं व्यापक होते हुए भी इतने स्वतन्त्र नहीं होते जितने निजी अध्ययन द्वारा। विशेष एजेंसियों की बैठकों के बाद विवादों में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डाला जाता है परन्तु कभी-कभी उनसे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में अड़चन भी पड़ने लगती है क्योंकि वाद-विवादों को प्रचार का माध्यम बना लिया जाता है। विशेष एजेंसियों द्वारा ऐसे प्रारूप एवं समझौते

तैयार किए जाते हैं जिन्हें सदस्य-राष्ट्र सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय भ्रम-संगठन में यह पद्धति बहुत उपयोगी प्रतीत होती है।¹

प्रगतिशील राष्ट्रों को दी जाने वाली सहायता का कुछ अंश इन एजेंसियों द्वारा दिया जाता है। उन्नतिशील राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय नीतियों के आधार पर आवकसित राष्ट्रों की सहायता करते हैं। अमेरिका ने मार्शल-योजना द्वारा युद्धपीड़ित राष्ट्रों को आर्थिक सहायता दी थी। राष्ट्रकुल के उन्नतिशील राष्ट्रों ने कोलम्बो योजना द्वारा दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्रगतिशील देशों के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था की। नशीली तथा हानिकारक औषधियों के प्रयोग पर नियन्त्रण, सत्रामक बीमारियों पर नियन्त्रण, अन्तर्राष्ट्रीय डाक तथा तार सेवामो की उचित व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रीय मार्गिक-उद्घरण संचालन की व्यवस्था, विश्व ऋणविज्ञान सर्वेक्षण, इत्यादि महत्त्वपूर्ण कार्य अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर हो किए जा सकते हैं। प्रत्येक राष्ट्रों के साधनों का उपयोग अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान हेतु विशेष एजेंसियों द्वारा ही सम्भव है। महान् राष्ट्रों की अपेक्षा छोटे-छोटे राष्ट्रों का सहयोग अधिक हितकर प्रमाणित हुआ है। विशेष एजेंसियों के अन्तर्गत सहायता देने वालों की अन्तर्राष्ट्रीय साख तथा प्रतिष्ठा बहुत अधिक बढ़ जाती है तथा जो बड़े राष्ट्र विशेष एजेंसियों के माध्यम से सहायता न कर भ्रम से सहायता या सहयोग करते हैं, उनकी इसलिए आलोचना की जाती है कि बड़े राष्ट्र अपनी सहायता के माध्यम से अपना राजनैतिक स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु साम्राज्यवादी राष्ट्रों द्वारा दी जाने वाली अधिक सहायता को स्वाभिमान की राष्ट्र प्रस्वीकार भी कर देते हैं। विशेष एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली सहायता का दुरुपयोग सम्भव नहीं है क्योंकि ऐसी सहायता अविकसित राष्ट्रों के हितों को ध्यान में रखकर दी जाती है एवं इसके साथ किसी तरह की राजनैतिक शर्तें नहीं लगायी जा सकती जिसके कारण शरीर राष्ट्र किसी भी बड़े राष्ट्र से सहायता स्वीकार करते समय अनुचित आधार का अनुभव नहीं करते। प्राज्ञ के वैज्ञानिक युग में विशेष एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली सहायता अनिवार्य होती जा रही है। पिछड़े तथा अविकसित राष्ट्र अपनी भूल, दरिद्रता, परेगानी तथा अनिष्ठा को दूर करने के लिए बिना किसी राजनैतिक शर्त तथा दबाव के विशेष एजेंसियों द्वारा सहायता प्राप्त करना चाहते हैं। साम्राज्यवादी प्रभिशाय से बचने के लिए विशेष एजेंसियों के माध्यम से ही हर तरह की सहायता प्राप्त करना व्यापक है। इस तरह की सेवा द्वारा यदि उन्नतिशील राष्ट्रों की आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था ठीक हो सके तो यह प्रवश्य ही इतिहास की युगपरिवर्तक घटना होगी।²

1 रामसदा गौतम : वही, पृष्ठ 153.

2 वही, पृष्ठ 153-54.

भारत के विदेश व्यापार के मूल्य, रचना और दिशाओं की आधुनिक प्रवृत्तियाँ

(TRENDS IN THE VALUE COMPOSITION AND
DIRECTION OF INDIA'S TRADE IN RECENT YEARS)

1947 तक भारत के विदेशी व्यापार का स्वरूप परम्परागत औपनिवेशिक और वृषि प्रधान देश की तरह था। भारत का विदेशी व्यापार मुख्यतः ब्रिटन और राष्ट्रमण्डल के अन्य देशों तक ही सीमित था। भारत सूती-वस्त्र, जूट के बने सामान चाय, मसाले, खासों आदि जैसी कुछ वृषि पर आधारित वस्तुएँ और अभ्रक तथा मैंगनीज जैसे खनिज पदार्थों का ही निर्यात करता था। आयात भी सीमित ही था और मुख्य रूप से निर्मित सामान का ही आयात किया जाता था। स्वतन्त्रता के बाद उद्योगों ने तेजी से विकास के फलस्वरूप भारत के विदेशी व्यापार की पूरी तरह से ढाया पलट हो गई है। अब भारत का व्यापार कुछ ही देशों तक सीमित नहीं है। अब विश्व के लगभग सभी देशों के साथ भारत के व्यापारिक सम्बन्ध हैं और भारत से निर्यात होने वाले सामान की सूची में, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय की लगभग 50 वस्तुओं के मुकाबले 3000 से भी अधिक वस्तुएँ हैं।

देश की अर्थ-व्यवस्था के विकास की आवश्यकता के कारण आयात में भारी वृद्धि हुई है। स्वभावतः अब देश ने आयात-व्यापार में वस्तुओं की दृष्टि से बहुत परिवर्तन हो गया है। अब मुख्य रूप से उद्योगों के लिए अत्याधुनिक मशीनों एवं दुर्लभ इन्चो माल का और देश के औद्योगिक एवं वृषि सम्बन्धी विकास के लिए चिकनाई वाले पदार्थ, तेल और रासायनिक खाद का आयात किया जाता है। विकास के लिए भारी मात्रा में आवश्यक आयात करने के परिणामस्वरूप ही देश का व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल रहा है। यह व्यापार सन्तुलन यद्यपि अब भी प्रतिकूल है, लेकिन निर्यात और आयात दोनों ही नीतियों में जनता पार्टी की सरकार ने कुछ आधारभूत परिवर्तन किए हैं। इन परिवर्तनों का सार यह है कि निर्यात नीति को अधिकधिक प्रभावी बनाया जाए और साथ ही, देश के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा को देखते हुए, आयात नीति को इस तरह उदार बनाया जाए कि औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा

मिले, छोटे एवं मध्यम स्तर के लोगों को आयात में परेशानी कम हो और देश की कीमतों पर दुगुना असर न पड़े।

विदेशी व्यापार की मात्रा

राष्ट्रीय सरकार की प्रभावी नीति के कारण भारत के विदेशी व्यापार में मूल्य और मात्रा दोनों ही दृष्टियों से वृद्धि हो रही है और 1950 की तुलना में 1978 के प्रारम्भ तक 10 गुने से भी अधिक वृद्धि हुई है। 1950-51 में 650.21 करोड़ रुपये का आयात हुआ जबकि 1972-73 में 1582.83 करोड़ रुपये का, 1976-77 में 4908.20 करोड़ रुपये का और 1977-78 में लगभग 5832.49 करोड़ रुपये का आयात हुआ। इसी प्रकार 1950-51 में पुनर्निर्यात सहित निर्यात (Exports including re-exports) 600.64 करोड़ रुपये से बढ़कर 1972-73 में 1703.29 करोड़ रुपये, 1976-77 में 4980.60 करोड़ रुपये और 1977-78 में लगभग 5252.67 करोड़ रुपये तक जा पहुँचा। 1977-78 के आँकड़ों में वृद्धि होने की सम्भावना प्रकट की गई है और यह आशा की गई है कि इस वर्ष के आयात और निर्यात के अन्तिम आँकड़े क्रमशः 6000 करोड़ रुपये और 5400 करोड़ रुपये होंगे।

भारत के प्रमुख आयात और आयात मूल्य

इस शीर्षक के अन्तर्गत हम देखेंगे कि कितने प्रमुख देशों से कितना आयात करते हैं और आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएँ कौनसी हैं।

भारत जिन प्रमुख देशों से आयात करता है उनमें उल्लेखनीय हैं—अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, ईरान, जापान, इटली, फ्राँस, सोवियत संघ, बेल्जियम, स्विट्जरलैण्ड, आस्ट्रेलिया, मलेेशिया, सऊदी अरब, कनाडा, चैकोस्लोवाकिया, बंगलादेश, घर्मा, नीदरलैण्ड, सिंगापुर, स्वीडन, मिस्र, केनिया और सूडान। अग्रिम पृष्ठों में भारत की विदेश व्यापार की दिशा के अन्तर्गत बताया गया है कि 1975-76 में भारत में पश्चिम यूरोप से 12.6 करोड़ रुपये का, एशिया तथा ओसीनिया से 1777 करोड़ रुपये का, अफ्रीका से 114 करोड़ रुपये का और अमेरिका से 1552 करोड़ रुपये का आयात किया था। 1976-77 में इन्हीं क्षेत्रों से क्रमशः 1123 करोड़ रुपये, 1994 करोड़ रुपये, 215 करोड़ रुपये और 1235 करोड़ का आयात हुआ। भारत 1976 के अनुसार 1973-74 में विश्व के प्रमुख देशों तथा अन्य देशों सहित कुल आयात 2,92,091 लाख रुपये का हुआ।

भारत में जल, धातु तथा धातु मार्ग द्वारा जिन प्रमुख वस्तुओं का आयात किया जाता है, वे ये हैं—लोहा तथा इस्पात, मशीनें (विजली की मशीनों को छोड़कर), पेट्रोलियम पदार्थ, परिवहन का सामान, विजली की मशीनें तथा उपकरण, कपास, गेहूँ, पेट्रोलियम (विना साफ और शीशीक रूप से साफ किया हुआ), रासायनिक तत्त्व तथा यौगिक धातु की बनी वस्तुएँ, सूत और धागा, ताँबा, जस्ता, चाँदी, ग्रीष्मकालीन, ताजे फल तथा मेवे, कच्ची ऊन तथा बाल, कागज तथा रसा,

तिलहन तथा गिरियाँ आदि, कोलतार, रंग, सामग्रो तथा नील, अलुमीनियम, दूध तथा ग्रीम (डिवाबन्द), कच्चा पटसन आदि तथा वनस्पति तेल ।

भारत के प्रमुख आयातों की दृष्टि से कुछ उल्लेखनीय बातें ये हैं—

(i) भारतीय आयातों में पूंजीगत माल का पहला स्थान है । पूंजीगत माल के अन्तर्गत त्रिजली व अनिश्चित अन्य मशीनें, त्रिजली की मशीनें, परिवहन का आवश्यक माज सामान आदि शामिल किया जाता है । देश के औद्योगिक विकास के लिए मशीनों का आयात अनिवार्य है । भारत विशेषकर मशीनें बनाने की मशीनों के आयात पर जोर देने लगा है ताकि मशीनों के मामलों में शीघ्र पूर्ण आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली जाए ।

(ii) आर्थिक विकास के प्रभावपूर्ण आयोजन के फलस्वरूप देश में लोह और इस्पात की माँग पूर्ति से अधिक है अतः इन वस्तुओं का आयात किया जाता है । दश वर्ष इस क्षेत्र में तभी से आत्मनिर्भर होता जा रहा है ।

(iii) भारत के आयातों में खनिज ईंधन चिकनाई तथा अन्य सम्बन्धित पदार्थों का भी विशेष महत्त्व है । देश को पेट्रोल, मिट्टी का तेल तथा पेट्रोल की अन्य वस्तुएँ बड़ी मात्रा में आयात करनी पड़ती हैं । कच्चा तेल मुख्यतः ईरान तथा अन्य अरब देशों से आयात किया जाता है ।

(iv) दश में बढिया निम्न की कपास का आयात मुख्यतः अमेरिका पाकिस्तान सूडान तथा मिस्र से होता है जबकि माट रेश की कपास का हमारे यहाँ से निर्यात किया जाता है । विभाजन के फलस्वरूप कपास के प्रमुख क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने से भारत इस वस्तु के निर्यात पर दश की अग्रगण्य आयातक देश बन गया । विभाजन के बाद दश में जूट का भी अभाव हुआ गया, लेकिन निर्यात बाल में जूट का उत्पादन बढ़ा कर इस अभाव का बहुत कुछ कम कर दिया गया है ।

(v) घनाज का आयात अमेरिका, कनाडा, बर्मा और रूस से किया जाता रहा है । रूस में घनाज का आयात हान ही के वर्षों में बढ़ा है ।

(vi) दश में उबरक और रसायन पदार्थ भी बड़ी मात्रा में आयात किए जाते हैं ।

(vii) आयात की जाने वाली अन्य वस्तुएँ में ताँबा, शीशा, रंग तथा कुछ दूसरे खनिज पदार्थ हैं । कुछ वर्षों से सायाबीन तेल और भेड़ की चर्बी का भी काफी आयात किया जाने लगा है ।

आर्थिक समीक्षा 1977-78 के अनुसार आयात स्थिति

भारत सरकार के प्रकाशन 'आर्थिक समीक्षा' 1977-78 में भारत के आयात की मात्रा मूल्य आदि पर जो प्रकाश डाला गया है वह इस प्रकार है—

वर्ष 1976-77 के दौरान, भारत के आयात का मूल्य कुल मिलाकर 5074 करोड़ रुपए हुआ था और यह 1975-76 के आयात के स्तर से 3.6 प्रतिशत कम था । सायान, उबरक तथा साहा और इस्पात के आयात में 887 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई । कुल आयात में इन वस्तुओं के आयात का अनुपात जो कि 1975-76 में

काफी ज्यादा अर्थात् 42.6 प्रतिशत था, कम होकर 1976-77 में 26.7 प्रतिशत रह गया। किन्तु इन वस्तुओं के आयात के मूल्य में जो भी कमी हुई वह कपास, वनस्पति तेल और बसा, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम के उत्पादों, पूँजीगत वस्तुओं तथा अलौह धातुओं के आयात में काफी ज्यादा वृद्धि होने से, पर्याप्त रूप में प्रति संतुलित हो गई। कपास, वनस्पति तेलों तथा बसा आदि के आयात मूल्य में 188 करोड़ रुपये की, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम के उत्पादों के आयात-मूल्य में 187 करोड़ रुपये की, पूँजीगत वस्तुओं के आयात मूल्य में 40 करोड़ रुपये की तथा अलौह धातुओं के आयात मूल्य में 59 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

वर्ष 1976-77 में पेट्रोलियम तथा उसके उत्पाद (अर्थात् पेट्रोलियम, तेल और चिकनाने के पदार्थ) ही अकेले आयात की सबसे बड़ी मद थे और इनके आयात का मूल्य, आयात की गई वस्तुओं के कुल मूल्य के एक चौथाई भाग में अधिक था। पहले के वर्षों के विपरीत, पेट्रोलियम, तेल तथा चिकनाने के पदार्थों के आयात की मात्रा में 1976-77 में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इकाई कीमत में भी 11.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और उसके परिणामस्वरूप पेट्रोलियम, तेल तथा चिकनाने के पदार्थों के आयात मूल्य में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कपास के आयात मूल्य में चौगुनी से भी ज्यादा वृद्धि हुई अर्थात् 1975-76 में 28.2 करोड़ रुपये के मूल्य की कपास का आयात हुआ था जबकि 1976-77 में 129.5 करोड़ रुपये के मूल्य की कपास का आयात किया गया। आयात की गई कपास की मात्रा दुगुनी हो गई जबकि इकाई कीमत में 130 प्रतिशत की अधिक वृद्धि हुई। कपास का आयात, हमारी आवश्यकता और देश में कपास के उत्पादन के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए आवश्यक था। इसी प्रकार वनस्पति तेलों तथा बसा के आयात में, मूल्य की दृष्टि में इस अवधि में सात गुनी वृद्धि हुई; इसका मुख्य कारण यह था कि घरेलू उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए आयातों में बहुत वृद्धि करनी पड़ी। अलौह धातुओं के आयात में, मूल्य की दृष्टि से 59.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसका आयात मूल्य बढ़कर 160 करोड़ रुपये हो गया। इसका मुख्य कारण यह था कि आयात की गई अलौह धातुओं की मात्रा में वृद्धि हुई अर्थात् 1975-76 में 84.5 हजार मीट्रिक टन अलौह धातुओं का आयात हुआ जबकि इसके मुकाबले 1976-77 में 140.7 हजार मीट्रिक टन अलौह धातुओं का आयात किया गया। इसके अलावा एक कारण यह भी था कि निकल, एल्युमिनियम, टिन तथा जस्तों की इकाई कीमत में और ज्यादा वृद्धि हुई। आयात नीति को उदार बनाए जाने के परिणामस्वरूप पूँजीगत माल के आयात में 4.1 प्रतिशत वृद्धि हुई और इनका आयात मूल्य 1008 करोड़ रुपये हो गया।

दूसरी ओर, साख के आयात में जो 1975-76 में आयात की जाने वाली घरेली सबसे बड़ी मद थी, मूल्य के हिसाब से 34.6 प्रतिशत की कमी हुई और आयात मूल्य कम होकर 878.6 करोड़ रुपये रह गया। इसका मुख्य कारण यह कि आयात की गई गेहूँ की मात्रा में कमी हुई और वह 71 लाख मीट्रिक टन से

घटकर 50 लाख मीट्रिक टन रह गई। इसी के साथ ही इसकी इकाई कीमत में भी 5 प्रतिशत की मामूली सी कमी हुई। उर्वरकों तथा उर्वरक सामग्री के आयात मूल्य में इसी अवधि के दौरान 330.6 करोड़ रुपये की भारी कमी हुई और यह कम होकर 261.2 करोड़ रुपए हो गया। इसका मुख्य कारण यह था कि उर्वरकों की इकाई कीमत में 77 प्रतिशत की तथा विनिर्मित उर्वरकों की इकाई कीमत में 57.5 प्रतिशत की कमी हुई। किन्तु आयात किए गए उर्वरक तथा उर्वरक सामग्री की कुल मात्रा में करीब 15 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई और यह मात्रा बढ़कर 45 लाख मीट्रिक टन हो गई। उर्वरक तथा उर्वरक सामग्री के आयात की मात्रा में वृद्धि की आवश्यकता इसलिए हुई कि उर्वरकों की कीमतों में कमी किए जाने के कारण उनकी घरेलू खपत में वृद्धि हो गई थी। साथ ही और इस बात के आयात मूल्य में 92 करोड़ रुपए की कमी हुई जिसका मुख्य कारण यह था कि आयात की मात्रा में 30 प्रतिशत की कमी हुई थी। घरेलू उत्पादन में जो वृद्धि हुई उससे लोहे तथा इस्पात के आयात की मात्रा में कमी करने में सहायता मिली।

वर्ष 1977-78 के पहले आठ महीनों में कुल आयात का मूल्य 3400 करोड़ रुपए था जो कि 1976-77 के पहले आठ महीनों के आयात मूल्य के स्तर के मुकाबले 3.8 प्रतिशत ज्यादा था। इस अवधि के दौरान आयात का आयात नगण्य ही था जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष के पहले आठ महीनों में 696 करोड़ रुपए के मूल्य के आयात हुआ था। इस कमी का समायोजित करने के लिए बालू बर्ष के पहले आठ महीनों में खाद्य भिन्न आयात में, 1976-77 की इस अवधि के खाद्य भिन्न आयात के स्तर के मुकाबले 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वस्तुवार ब्यापार बालू वर्ष की पहली तिमाही तक की रफ्तार ही उपलब्ध है। इस मोटे से पता चलता है कि एक ओर आयात के आयात मूल्य में लगभग 200 करोड़ रुपये की कमी हुई और दूसरी ओर काजू, प्लास्टिक सामग्री, धातु भिन्न खनिज पदार्थों विनिर्मित वस्तुओं तथा सामान्य औद्योगिक मशीनरी तथा उपकरणों के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

भारत सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय की

1977-78 की रिपोर्ट के अनुसार आयात स्थिति

भारत सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय की 1977-78 की वार्षिक रिपोर्ट में भारत के आयात की स्थिति इस प्रकार दर्शायी गई है—

1974-75 तथा 1975-76 के दौरान आयातों में काफी वृद्धि के बाद 1976-77 में भारत के कुल आयात 5074.36 करोड़ रु० के रूप में लगभग 3.6 प्रतिशत की गिरावट प्रकट होती है। 3 प्रमुख समूहों अर्थात् धातु, पौ० प्रो० एवं तथा विनिर्मित उर्वरकों के समुक्त आयात 1975-76 के दौरान हुए भारत के कुल आयातों के 58 प्रतिशत ठहरने हैं, लेकिन 1976-77 में उनका भाग घटकर 49 प्रतिशत रह गया। घरेलू उत्पादन में सुधार के कारण धातु का भाग, जो 1975-76 में 25.5 प्रतिशत था घटकर 17.3 प्रतिशत हो गया तथा विनिर्मित

उर्वरकों का भाग 8.9 प्रतिशत से घटकर 3.9 प्रतिशत हो गया। तथापि पी० ओ० एल० के मामले में उसके भाग में वृद्धि हुई है जो 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 27.8 प्रतिशत हो गई।

1976-77 के दौरान पूर्ण मूल्य के आधार पर जिन मदों में 1975-76 की अपेक्षा वृद्धि प्रकट होती है, उनमें मुख्यतः ये शामिल हैं : पी० ओ० एल० (+15 प्रतिशत), मशीनरी (+9 प्रतिशत), परिवहन उपकरण (+13 प्रतिशत), अलौह धातु (+59 प्रतिशत), कपास (+356 प्रतिशत), खाद्य तेल (+549 प्रतिशत), रासायनिक तत्त्व तथा यौगिक (17 प्रतिशत), कागज तथा गत्ता (+8 प्रतिशत), सखिल्लट तथा किर से तैयार फैब्रिक्स (+370 प्रतिशत), प्लास्टिक सामग्री (+40 प्रतिशत) तथा कच्ची ऊन (+8 प्रतिशत)। तथापि आयातों में जो वृद्धि हुई है वे अन्य अनेक मदों के आयातों में गिरावट आने से खत्म हो गई। इनमें मुख्यतः ये शामिल हैं—अन्न तथा अन्न से बने पदार्थ (-35 प्रतिशत), विनिर्मित उर्वरक (-58 प्रतिशत), लोहा तथा इस्पात (-29 प्रतिशत), धातु से बना माल (-9 प्रतिशत), मृत्युवान तथा अर्द्ध-मृत्युवान पत्थर (-4 प्रतिशत), कच्चे काजू (-46 प्रतिशत)।

1977-78 की पहली तीन तिमाहियों (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान आयातों के अंतिम आँकड़ों के अनुसार कुल आयात 3917.92 करोड़ रु० के हुए जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए 3767.70 करोड़ रु० के आयात स्तर की तुलना में लगभग 4 प्रतिशत बढ़े हैं। तथापि सरकारी लेखों के सम्बन्ध में पूरी रिटर्न प्राप्त हो जाने पर इन आयात-आँकड़ों में वृद्धि होने की सम्भावना है।

1977-78 की पहली छमाही के आयात आँकड़ों के सव्ययन से प्रकट होता है कि अन्न तथा अन्न से बने पदार्थों का आयात घटकर 42 करोड़ रु० का हुआ जब कि अप्रैल-सितम्बर 1976 में 479 करोड़ का हुआ था। पी० ओ० एल०, लोहा एवं इस्पात तथा कुछ सीमा तक मशीनरी और परिवहन उपकरणों के आयातों में भी गिरावट प्रकट होती है। वर्ष 1977-78 के लिए आयात नीति और अधिक उदार बना दी गई है ताकि आयातित कच्चे माल, उपकरणों, फालतू पुर्जों तथा उपकरणों के लिए अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा किया जा सके तथा कम सप्लाई वाली कुछ ग्राम उपभोग की मदों की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। इसे देखते हुए यह सम्भावना है कि 1977-78 की पहली छमाही के दौरान कच्चे माल, मशीनरी तथा परिवहन उपकरण सम्बन्धी मदों के आयातों में तथा अन्य पोषण सम्बन्धी आयातों में जो वर्तमान गिरावट आई है उसकी स्थिति वर्ष की दूसरी छमाही में बदल सकती है।

खाद्य तेल, रुई, मानव-निर्मित रेशे के मामले में आयात विशेषकर इस उद्देश्य से अधिक किए गए कि इन मदों की घरेलू उपलब्धता बढ़े तथा उनकी कीमतों पर नियन्त्रण हो। रासायनिक तत्वों तथा यौगिकों, भेषजीय तथा औषध, कागज तथा गत्ता, प्लास्टिक सामग्री, विनिर्मित उर्वरक, बिना तराशे हुए मृत्युवान तथा अर्द्ध-पत्थरों में भी वृद्धि भिन्न-भिन्न मात्रा में हुई।

अप्रैल-दिसम्बर 1977 के दौरान 5375 करोड़ रु० मूल्य के आयात लाइसेंस जारी किए गए थे जबकि 1976 की इसी अवधि में 2835 करोड़ रु० के हुए थे। विदेशी मुद्रा की अच्छी स्थिति का लाभ उठाते हुए अप्रैल-दिसम्बर, 1977 में जारी किए गए लाइसेंसों में स 75 प्रतिशत लाइसेंस मुक्त विदेशी मुद्रा के आवाह पर जारी किए गए थे।

पिछले 3 वर्षों के प्रमुख मद्य/समूहों के सम्बन्ध में आयातों का रुख निम्न-लिखित तालिका में दिखाया गया है—

भारत द्वारा प्रमुख वस्तुओं के आयात

(करोड़ रु० में)

क्रमांक	वस्तुएँ	1975-76	1976-77	अप्रैल से सितम्बर	
				1976	1977
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	घस्र तथा घन में बने उत्पाद	1342.08	878.06	478.83	42.32
2	काष्ठ तेल	15.50	100.61	38.18	333.62
3	कपास	28.02	उ० नहीं	14.09	96.91
4	मरियट्ट तथा पुन तैयार किया हुआ रेशा	6.04	30.01	2.51	उ० नहीं
5	खनिज तेल, स्नेहक तथा सम्बद्ध उत्पाद	1226.00	1412.01	651.74	504.32
6	मोती, मूल्यवान तथा घड़े मूल्यवान पत्थर	83.87	80.64	76.46	147.83
7	लोहा तथा इस्पात	311.09	220.05	122.95	91.90
8	विविध उर्वरक	469.04	197.07	55.11	58.38
9	सोनीह धातु	100.04	159.08	72.12	62.17
10	गणायनिक तत्व तथा यौगिक	117.37	137.21	62.70	74.60
11	मशीनरी	777.05	845.08	399.27	384.92
12	परिवहन उपकरण	157.01	176.08	70.11	64.52

भारत के प्रमुख निर्यात एवं निर्यात मूल्य

भारत जिन प्रमुख देशों को निर्यात करता है, उनमें उल्लेखनीय हैं—ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ, जापान, आस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जर्मनी (फंडरल रिपब्लिक), कनाडा, बर्मा, मिस्र, फ्रांस, अर्जेन्टाइना, सूडान, मलेशिया सिंगापुर, नीदरलैंड, चैकोस्लोवाकिया, कीनिया, इटली, नाइजीरिया, क्यूबा, न्यूजीलैंड, बंगलादेश तथा इण्डोनेशिया ।

भारत 1976 के अनुसार विश्व के प्रमुख देशों तथा अन्य देशों को 1950-51 में 60,064 लाख रुपए का निर्यात हुआ था जो बढ़कर 1973-74 में 3,48,322 लाख रुपए का हो गया । 1976-77 में मस्यौदाई आँकड़ों के अनुसार भारत का कुल निर्यात 4,980,60 करोड़ रुपए का था जो बढ़कर 1977-78 में (पुनर्निर्यात सहित) 5,252,67 करोड़ रुपए हो गया । 1977-78 के आँकड़ों में वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है और यह भाशा की जाने लगी है कि इसी वर्ष पुनर्निर्यात सहित निर्यात की राशि 5400 करोड़ रुपए होगी । जैसा कि पहले पृष्ठों में भारत के विदेश व्यापार की दिशा में बताया गया है कि विश्व के सभी क्षेत्रों में भारत के निर्यातों में वृद्धि हुई है, लेकिन यह वृद्धि विशेषकर पश्चिमी यूरोप को (खासकर यूरोपीय साम्राज्य बाजार को) तथा जेप एशिया तथा द्वीप देशों की अधिक हुई है । 1976-77 में पश्चिम यूरोप को 1605 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था, जिसमें यूरोपीय साम्राज्य बाजार को निर्यात की राशि 1394 करोड़ रुपए थी । एशिया तथा ओसीनिया को 1834 करोड़ रुपए का, अफ्रीका 311 करोड़ रुपए का और अमेरिका को 649 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था ।

देश से जल, थल और वायुमार्ग द्वारा जिन प्रमुख वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, वे ये हैं—पटसन की वस्तुएँ (मूत आदि के अतिरिक्त), चाय, सूती वस्त्र (मूत आदि के अतिरिक्त अन्य वस्त्र), सूती वस्त्र (सूती वस्त्र और पटसन को छोड़कर), वस्त्र की बनी चीजें (सूती तथा पटसन के वस्त्र, ऊनी कालीन, चटाई, गलीचे आदि छोड़कर), मूत और धागा, अलौह धातुओं के अवस्क और सांद्र अवस्क, चमड़ा, कपास (रुई कपास आदि छोड़कर) ताने फन तथा गिरियाँ (तेल वाली गिरियों को छोड़कर), कच्ची वनस्पति-जन्म सामग्री (अल्लाह), चीनी (सोरा सहित) लौह अवस्क और सांद्र अवस्क, कच्चा तम्बाकू, वनस्पति, तेल (निर्गन्धीय), कच्चे खनिज पदार्थ (कोयला, पेट्रोल, ज्वरक तथा रत्नों को छोड़कर), ऊनी कालीन, गलीचे और चटाई आदि लोहा तथा इस्पात कड़वा, चमड़ा तथा खालें (कच्ची), पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, कोरक तथा कोयला-चूरे की ईंटें ।

देश के निर्यात-व्यापार का उत्पादनक पहलू यह है कि कुछ गैर-परम्परागत वस्तुओं जैसे इन्जीनियरी का सामान, रसायन, खनिज, ईंधन, लोहा एवं इस्पात हस्त-शिल्प के सामान आदि का निर्यात बढ़ता जा रहा है । भारत अपने योजनावद्ध आर्थिक विकास के फलस्वरूप अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं से निर्यात की स्थिति में आ गया है । कृषि सम्बन्धी मशीनरी और औजार, हाथ-पम्प, स्टील फर्निचर, विजली

का माज सामान, चमड़े की बड़िया वस्तुएँ, प्लास्टिक का सामान, माइक्रो, घनेक ऊँची घोर पेचीदा श्रेणी की वस्तुओं जैसे मशीन टूलम एव वस्त्र मशीनरी, सिनाई की मशीनें, रेलव बंगनो, बिजली की माटर, डीजल इन्जन आदि का निर्यात बढ़ता जा रहा है। इन वस्तुओं का निर्यात दक्षिण पूर्वी एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों तथा यूरोप के विकसित देशों-दोनों को किया जा रहा है। भारत आधुनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ गया है, अतः उसकी प्रतियोगिता-शक्ति काफी उन्नत हुई है। संक्षेप में, देश के निर्यातों का स्वरूप एक औद्योगिक देश के निर्यातों के अनुरूप बनता जा रहा है। निर्यातों का एक उत्सेखनीय पहलू यह है कि न केवल वस्तुओं का बल्कि अपने प्राविधिक ज्ञान और डिजाइन तथा परामर्शदात्री सेवाओं का निर्यात भी भारत करने लगा है। भारतीय उद्यमकर्त्ताओं ने सऊदी अरब, थाई, ईरान श्रीलंका नेपाल नाइजीरिया, मलेशिया आदि देशों में ही नहीं बल्कि ब्रिटेन तथा में समुचित उपक्रम चालू किए हैं।

प्राथमिक समीक्षा 1977-78 के अनुसार निर्यात स्थिति

प्राथमिक समीक्षा 1977-78 में भारत के निर्यात की मात्रा, मूल्य आदि पर जो प्रकाश डाला गया है वह इस प्रकार है—

'वर्ष 1976-77 के दौरान निर्यात में परिमाण तथा मूल्य दोनों ही दृष्टियों से उत्साहवर्धक वृद्धि हुई है। निर्यात में हुई कुल आय में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह आय बढ़कर 5143 करोड़ रुपये हो गई। प्राथमिक गतिविधि में तेजी आ जाने से केवल विकसित देशों में सार्वजनिक सामान की परिपूर्ति किए जाने से और देश में चल रहे निर्माण सम्बर्द्धन के जोरदार अभियान के कारण, निर्यात के परिमाण में 18 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जबकि इसके मुकाबले इससे पहले के दोनो वर्षों में हर साल 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। निर्यात की इकाई कीमत में 6.6 प्रतिशत की साधारण सी वृद्धि हुई जबकि इसके विपरीत 1975-76 में 7.7 प्रतिशत की और 1974-75 में 25.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

वस्तुवार विवरण से पता चलता है कि खली, कपास (रुई) और कृत्रिम रेशम का कपड़ा, कहुवा (बाफी) और चाय जैसी वस्तुओं का निर्यात जो 1975-76 में काफी शिथिल हो गया था 1976-77 में काफी ज्यादा बढ़ा है। अन्य वस्तुओं जैसे समुद्री उत्पादों, चमड़े और चमड़े के सामान, दस्तकारी के सामान, सामायिक पदार्थों, इन्जीनियरी वस्तुओं और सूती कपड़ों के निर्यात में बराबर वृद्धि होती रही और उनके निर्यात से प्राप्त होने वाली आय में भी वृद्धि हुई। लोहा और इस्पात के निर्यात से पहले के वर्षों में कोई महत्वपूर्ण आमदनी नहीं होती थी परन्तु इन अवधि में उसका काफी योगदान रहा। दूसरी ओर जूट से बने वस्तुओं के निर्यात से होने वाली आमदनी में और बमो शार्ड और चीनी के निर्यात से होने वाली आमदनी तो एक दम घट गई।

प्रनिर्मित वस्तुओं के वर्ग में चाय कहुवा, कच्चा लोहा, खली, काजू की गिरी, मछली तथा मछली से बने पदार्थों के निर्यात से प्राप्त होने वाली आय में

सामान्य स्तर से लेकर काफी ज्यादा वृद्धियाँ हुईं। निर्यात की गई चाय के मूल्य में 23.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका कारण यह है निर्यात की जाने वाली चाय की मात्रा में 14.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और उसकी इकाई कीमत में भी 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 1976-77 की दूसरी छमाही के ग्राम-पास चाय की विदेशी मण्डियाँ हमारे लिए और ज्यादा अनुकूल हो गई क्योंकि केनिया तथा श्रीलंका जैसे प्रतियोगी देशों से चाय की सप्लाई कम हो गई थी। मूल्य की दृष्टि से बांकी (बहवा) के निर्यात में 71 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो मुख्य रूप से इकाई कीमत में 114 प्रतिशत की प्रभूतपूर्व वृद्धि हो जाने के कारण हुई। बांकी की विदेशी मण्डियों में बांकील के द्वारा जो दुनिया का सबसे बड़ा काफी उत्पादक देश है, बड़े पैमाने पर की गई खरीद के कारण, बहुत तेजी रही। यदि घरेलू पूँज पर अधिक लगाम लगाया गया होता तो बांकी के निर्यात से अपेक्षाकृत और ज्यादा आमदनी होती। वास्तव में, 1976-77 में बांकी के निर्यात में मात्रा की दृष्टि से 20 प्रतिशत कमी हुई।

खली का निर्यात, जो पहले के दो वर्षों में शिथिल रहा था, 1976-77 में फिर से बड़ा और उसके निर्यात मूल्य में 132 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि हुई। खली की इकाई कीमत में 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि उसके मुकाबले निर्यात मात्रा में 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सूरजमुखी तथा सोयाबीन की फसल कम होने से विश्व बाजार में तनी की जो स्थिति बनी यह उसकी माँग तथा कीमत दोनों में हुई वृद्धि के लिए बहुत हद तक उत्तरदायी है। मछली और मछली से बने पदार्थों के निर्यात में 42 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण यह था कि इकाई कीमत में 26.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इसी तरह खनिज लोहे के निर्यात में मूल्य की दृष्टि से 11.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई; इसका कारण यह था कि निर्यात की मात्रा में 3.5 प्रतिशत की और इकाई कीमत में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। काजू की गिरी के निर्यात में मूल्य की दृष्टि से 10.5 प्रतिशत की मामूली सी वृद्धि हुई जो पूर्ण रूप से इकाई कीमत में 14.5 प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण हुई थी।

विनिर्मित वस्तुओं के वर्ग के अन्तर्गत, लोहे और इस्पात, इजीनिपरी सामान, सूती कपड़े, सजली रेशम के कपड़े, चमड़े और चमड़े का सामान तथा दस्तकारी की वस्तुओं के क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई। वास्तव में, 1976-77 में निर्यात की आय में सबसे ज्यादा वृद्धि लोहे और इस्पात के निर्यात से हुई। इससे 283 करोड़ रुपये की आमदनी हुई जबकि इसके मुकाबले 1975-76 में केवल 68 करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी। यह मुख्य रूप से निर्यात की मात्रा में वृद्धि होने से हुआ। इजीनिपरी के सामान के निर्यात में 34.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कुछ नोखाडी (गल्लू) के देशों में बाजार की स्थिति अनुकूल होने के कारण और कुछ विद्युत में सुधार तथा निर्माण सुविधामें वृद्धि होने के कारण हुई।

सूती कपड़ों की माँग फिर से बढ़ी और 1976-77 में निर्यात की आमदनी में 31.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निर्यात की मात्रा में, लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई, मिल से बने कपड़े की इकाई कीमत में 24.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मकली

रेगम के कपड़ों के निर्यात के मूल्य में 88 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो मुख्य रूप से निर्यात किए गए कपड़ों की मात्रा के दुगुने हो जान के कारण हुई, हालांकि इकाई कीमत में 6 प्रतिशत की साधारण-सी कमी भी हो गई थी। सूती परिधान (सिले-सिलाए कपड़े) के निर्यात में 76 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो प्रभावशाली वृद्धि है और इस प्रकार सूती परिधान निर्यात की एक ऐसी वस्तु बन गया, जिसका निर्यात सबसे अधिक तेजी से बढ़ रहा है। 1976-77 में चमड़े और चमड़े से निर्मित सामान के निर्यात में और वृद्धि हुई और निर्यात के मूल्य में 31 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई जिससे इस बात का पता चलता है कि पूरी तरह से कपाए हुए चमड़े और चमड़े के सामान के निर्यात का प्रोत्साहन देने की नीति पूरी तरह से सफल रही है क्योंकि पूर्वोक्त माल में छद्म-निर्मित चमड़े और खालों के मुकाबल ज्यादा ऊँचे मर्यादित मूल्य का नए समाविष्ट रहना है। दस्तकारी की वस्तुओं के निर्यात के मूल्य में भी 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण यह है कि एक तो इन वस्तुओं की माँग बढ़ी और दूसरे खान तोर सख्ती के देशों से हीर जवाहरात आदि बहुमूल्य पत्थरों और मृद बस्तुमूल्य पत्थरों की खरीद की माँग में और उनकी बिक्री के अवसरों में बहुत वृद्धि हुई।

वर्ष 1976-77 में जूट से बनी वस्तुओं और चीनी के निर्यात में उल्लेखनीय कमी हुई। निर्यात आमदनी की दृष्टि से जूट से बनी वस्तुओं के निर्यात में 20 प्रतिशत की कमी हुई क्योंकि इनकी खपत कम हुई और दूसरे इसकी इकाई कीमत में भी 8.4 प्रतिशत की कमी हुई। सश्लिष्ट पदार्थों से बनी वस्तुओं के उत्तरोत्तर बढ़ने हुए प्रचार और अन्य निर्यातकों की ओर से कड़ी प्रतिस्पर्धा होने के कारण मुख्य रूप से उपर्युक्त वस्तुओं की मात्रा में कमी हुई और निर्यात में इनका मूल्य घट। चीनी का निर्यात जो 1975-76 में 472 करोड़ रुपये का हुआ था, 1976-77 में कम होकर केवल 148 करोड़ रुपये का रह गया क्योंकि इकाई कीमत में 35 प्रतिशत की गिरावट आई और निर्यात की मात्रा में भी 52 प्रतिशत की कमी हुई। यह सब विश्व भर में चीनी की मुलद स्थिति रहने के कारण हुआ।

1977-78 के पहले छठ महीनों में किए गए निर्यात का मूल्य 3472 करोड़ रुपये है जो 9.3 प्रतिशत वृद्धि का घातक है जबकि इसका मुकाबल इससे पहले के वर्ष की इसी अवधि में निर्यात मूल्य में लगभग 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। जो यह विचारणीय निम्नलिखित घाई है वह अतः इस बात की ओरक है कि विरहित देशों में, उनकी अपनी आर्थिक विकास की गति में घीमापन का जान के कारण कम मात्रा में मात्र मँगवाया है और इसके अलावा तानिस्मय सामान की माँग इन देशों में अलग कम होती गई है। वर्ष 1977-78 की पहली निमाही तर के वस्तुवार उपलब्ध पत्र प्रौद्योगिकी से पता चलता है कि लोहा और इस्पात जैसी मशों के निर्यात से हान वाली प्रायः, विश्वभर में माँग में गिरावट आने के कारण, तथा चमड़ा और चमड़े के सामान और सूती परिधान के निर्यात से होने वाली प्रायः में विरहित देशों में प्राधान पर और ज्यादा पात्रन्धियाँ लगा दिए जान के कारण कमी आई है। इन तीनों मशों से 1976-77 में 804 करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी और निर्यात

से होने वाली घाटती में कुल मिलाकर 1100 करोड़ रुपये की वृद्धि का 35 प्रतिशत भाग इन्हीं तीनों मदों के कारण प्राप्त हुआ था। चीनी के निर्यात में बराबर कमी होती गई और पहली तिमाही में उसने केवल 10.5 करोड़ रुपये का योगदान दिया था। पहली तिमाही में जूट से बनी वस्तुओं के निर्यात में और ज्यादा कमी हो गई। दूसरी और मछली और मछली से बने पदार्थों तथा इनीनियरी सामान के निर्यात में चालू वर्ष की पहली तिमाही में क्रमशः 5 प्रतिशत तथा 16.6 प्रतिशत की साधारण वृद्धियाँ हुईं। कुल मिलाकर इस वर्ष में जो निर्यात हुआ है उसे साधारण रूप में ही उत्साहवर्धक कहा जा सकता है। केवल माघ चाय और काफी के निर्यात की दूरी में मराहनीय वृद्धि हुई है।

भारत सरकार की रिपोर्ट 1977-78 के अनुसार निर्यात स्थिति

भारत सरकार के वाणिज्य विभाग की 1977-78 की वार्षिक रिपोर्ट में भारत की निर्यात स्थिति पर जो प्रकाश डाला गया है वह इस प्रकार है—

1976-77—वर्ष 1976-77 से सम्बन्धित निर्यातों की वस्तुवार प्रतुतियों में पता लगता है कि प्राथमिक तथा निमित्त उत्पाद दोनों की प्रत्येक मदों के निर्यातों के मूल्य में सुधार हुआ है। 1975-76 की तुलना में वर्ष 1976-77 के दौरान निर्यातों में प्रभावशाली वृद्धि हुई। खासकर इन मदों के निर्यात में वृद्धि हुई—बघा सूती परिधान सहित सूती वस्त्रों के निर्यात 371.5 करोड़ रुपये से बढ़कर 603.2 करोड़ रुपये हो गए अर्थात् उनमें 62.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, इनीनियरी माल के निर्यात 41.3 करोड़ रुपये से बढ़कर 554.4 करोड़ रुपये हो गए अर्थात् उनमें 34.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रत्न तथा आभूषण सहित हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात 25.2 करोड़ रुपये से बढ़कर 404.8 करोड़ रुपये के हो गए अर्थात् उनमें 60.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, बमड़ा तथा चमड़ा निमित्त माल, जिसमें जूने भी शामिल हैं के निर्यात 220.7 करोड़ रुपये से बढ़कर 290.2 करोड़ रुपये के हो गए अर्थात् उनमें 31.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई, खनी के निर्यात 106.6 करोड़ रुपये से बढ़कर 256.5 करोड़ रुपये के हो गए अर्थात् उनमें 140 प्रतिशत की वृद्धि हुई, मछली के निर्यात 127.2 करोड़ रुपये से बढ़कर 180.6 करोड़ रुपये के हो गए अर्थात् उनमें 42.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, रसायन तथा सह-उत्पाद के निर्यात 85.3 करोड़ रुपये से बढ़कर 109.5 करोड़ रुपये के हो गए अर्थात् उनमें 28.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, काफी के निर्यात 66.7 करोड़ रुपये से बढ़कर 125.8 करोड़ रुपये के हो गए अर्थात् उनमें 88.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1976-77 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में व्यापार की दशा, मुख्यतः पटसन निमित्त माल तथा चीनी जैसे प्रमुख निर्यातों के सम्बन्ध में, प्रतिकूल बनी रही। वर्ष के दौरान चीनी की विश्व कीमतों में विशेष गिरावट आई तथा पटसन निमित्त माल के इकाई मूल्य प्राप्ति में भी और गिरावट आई। चीनी के निर्यात घटकर 1976-77 में 148.1 करोड़ रुपये के रह गए जबकि 1975-76 में 472.3 करोड़ रुपये के थे। उसी अवधि में पटसन निमित्त माल के निर्यात 250.9 करोड़ से घटकर

निर्यात में गिरावट दर्शाने वाली मदें

(करोड़ रुपए)

	1976-77	अप्रैल-सितम्बर	
		1976	1977
श्रेणी ख			
चीनी	148.1	89.6	10.5
मछली	180.6	87.9	88.1
सब्जी तथा फल	158.2	93.8	128.1
तिलहन	71.2	37.5	2.3
कच्ची रुई	27.0	26.6	0.10
अयस्क तथा लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क आदि को छोड़कर)	55.2	24.7	21.5
मैंगनीज अयस्क	19.1	5.1	2.3
अन्नक	17.4	8.4	8.4
वनस्पति तेल तथा चर्बी	50.1	33.67	10.5
चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित माल	264.1	135.1	121.3
सीमेंट	28.8	9.5	6.7
लोहा तथा इस्पात	292.3	188.4	137.6
सिले-सिलाए परिधान	265.0	161.5	145.3
जूते-चप्पल आदि	29.5	12.1	3.83

भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य प्रवृत्तियाँ
अथवा

1947 से भारत के निर्यात-आयात व्यापार की प्रवृत्तियाँ

भारत के विदेशी व्यापार के आकार, आयात-निर्यात की प्रमुख मदों, आयात और निर्यात के प्रमुख देशों आदि का विवरण देने के उपरान्त भारत के विदेशी व्यापार अथवा निर्यात-आयात व्यापार की मुख्य प्रवृत्तियों को समझना आवश्यक है—

(क) निर्यात-व्यापार की प्रवृत्तियाँ और परिवर्तन

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त अब तक के आयोजन काल में देश के निर्यात-व्यापार में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए या मुख्य प्रवृत्तियाँ दिखाई दी वे इस प्रकार हैं—

(1) वस्तु के अनुसार परिवर्तन—देश के निर्यातों में यद्यपि परम्परागत वस्तुओं का महत्व घना हुआ है लेकिन गैर-परम्परागत वस्तुओं का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। पटसन के माल, चाय, कढ़वा आदि परम्परागत निर्यात-वस्तुओं से हम काफी विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं, किन्तु लोहा एवं इस्पात, इजीनियरी के सामान आदि गैर-परम्परागत निर्यात-वस्तुओं की स्थिति में भी बड़ा उत्साहवर्द्धक सुधार हुआ

है। परम्परागत और नैर-परम्परागत दोनों ही वस्तुएँ भारत के निर्यात व्यापार में निम्नी मध्यवर्ती बनती जा रही हैं, इसका आभास हम भारत सरकार की 25.5-78 की प्रेस विज्ञप्ति के निम्नलिखित अनुच्छेद से होना है—

‘चाय, काफी और मसालों के निर्यात से अधिक चाय हुई। इन्जीनियरी माल रसायन और मस्बड़ उत्पादों तथा पटमन से नैयार वस्तुओं का भी अच्छी मात्रा में निर्यात हुआ और हीरे जवाहरान के निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। निर्यात प्रोत्साहन परिषद और जिम्मेबोर्डों से प्राप्त जानकारी के आधार पर चाय का निर्यात मूल्य 295 करोड़ रुपए से बढ़कर 556 करोड़ रुपए हो गया और इस प्रकार चाय का निर्यात में 88 प्रतिशत वृद्धि हुई। काफी का निर्यात मूल्य 114 करोड़ रुपए में बढ़कर 230 करोड़ रुपए हो गया। इस प्रकार काफी के निर्यात में 102 प्रतिशत वृद्धि हुई। मसालों का निर्यात मूल्य 76 करोड़ रुपए से बढ़कर 138 करोड़ रुपए हुआ अर्थात् इसमें 82 प्रतिशत वृद्धि हुई। इन्जीनियरी माल के निर्यात में 12 में 13 प्रतिशत रसायन और मस्बड़ उत्पादों के निर्यात में 17 प्रतिशत और हीरे-जवाहरान के निर्यात में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई।”

(2) विश्व के अनुसार परिवर्तन—विदेशी व्यापार की दिशा (Direction of Foreign Trade) का आशय इस बात में होता है कि भारत का व्यापार किन देशों के साथ है अर्थात् किन देशों से वह आयात करता है और किन देशों को निर्यात करता है। यदि निर्यात व्यापार की दिशा को लें तो 1951-52 से 1971-72 की अवधि में जापान का प्रतिशत अंश लगभग 2.2% से बढ़कर 11.5% हो गया, पूर्वी यूरोपीय देशों का प्रतिशत अंश लगभग 1.2% से बढ़कर 2.2% हो गया, ब्रिटेन का प्रतिशत अंश 27 प्रतिशत से गिरकर 11 प्रतिशत पर और इसी प्रकार अमेरिका तथा कनाडा का प्रतिशत अंश लगभग 21 प्रतिशत से घटकर 19 प्रतिशत पर आ गया। निर्यात माल के मुख्य खरीददारों में 1971-72 में अमेरिका सबसे ऊपर, हम दूसरे नम्बर पर जापान तीसरे नम्बर पर, और ब्रिटेन चौथे नम्बर पर थे। 1972-73 में देश का निर्यात-निर्यातन काफी प्रभावित रहा, क्योंकि बंगला देश के साथ व्यापार आरम्भ हो गया और विश्व की प्रमुख मुद्राओं के बीच द्वितीय की नई दरी की व्यवस्था हो गई।

(3) घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के बाद वस्तुओं का निर्यात—जनता पार्टी की सरकार ने निर्यात नीति को एक नया मोड़ दिया है। वर्ष 1977-78 के दौरान सरकार ने घरेलू जरूरतों को पूरा करने के पश्चात् ही घाम जरूरत की वस्तुओं का निर्यात करने की नीति अपनाई। 1977-78 के दौरान तिलहन, वनस्पति तेल, भूगर्भीय, धोती, ताजी सस्त्रियों जिनमें प्याज और आलू शामिल हैं चावल, दालें और मीमेट जैसी घाम उपयोग की वस्तुओं का कुल निर्यात 160 करोड़ रु का हुआ जबकि इसकी तुलना में 1976-77 में यह निर्यात 500 करोड़ रु का था। घरेलू उपयोगियों को अधिक चाय उपलब्ध कराने के लिए, चाय के निर्यात की मात्रा को कम रखा गया। 1976-77 के दौरान 24.2 करोड़ कि ग्रा चाय का निर्यात किया गया था।

(4) विश्व व्यापार में कमी के कारण निर्यात की अनेक वस्तुओं पर प्रतिकूल प्रभाव—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार विश्व व्यापार की मात्रा की वृद्धि में तेजी से कमी आई है। 1976 में यह लगभग 12 प्रतिशत थी जबकि 1977 में यह 5 प्रतिशत रह गई। या तो संरक्षणवाद या फिर मन्दी के कारण दस्य, इस्पात, अनेक इंजीनियरिंग उत्पाद, खनिज और चमड़ा व चमड़े से धने सामान सहित निर्यात की अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं विशेष तौर से सूती वस्त्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 1977-78 के दौरान घरेलू माँग बढ़ जाने से इस्पात के निर्यात में लगभग 100 करोड़ रु की कमी आई। 1977-78 के दौरान सूती कपड़ा और चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित सामान के निर्यात में कम से कम 45 से 50 करोड़ रु. की कमी होने का अनुमान है।

(5) नई निर्यात नीति के उद्देश्य—जनता सरकार द्वारा व्यापार में विविधिकरण की बढ़ावा देकर व्यापार में परिवर्तन लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नई निर्यात नीति का उद्देश्य कच्चे माल के स्थान पर तैयार माल का निर्यात करना है ताकि इनका अधिक मूल्य हो और देश में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें। नई निर्यात नीति का उद्देश्य अर्तमान क्षमता का बेहतर उपयोग, अधिक निवेश और प्राधुनिकीकरण के माध्यम से अधिक निर्यात करना है। नई निर्यात नीति का उद्देश्य नए बाजारों का पता लगाना है और उन्हें अपने अनुकूल बनाना भी है।

(ख) आयात-व्यापार की मुख्य प्रवृत्तियाँ और परिवर्तन

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त भारत के आयात-व्यापार में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं या मुख्य प्रवृत्तियाँ दिखाई दी हैं वे निम्न प्रकार हैं—

(1) वस्तु के अनुसार परिवर्तन—आयात की जाने वाली वस्तुओं में लोहा एवं इस्पात, मशीनों (विजली की मशीनों को छोड़कर) परिवहन के सामान, विजली के मशीनों एवं उपकरणों, कपास, गेहूँ, पेट्रोल (बिना साफ तथा आंशिक रूप से साफ किया गया), रासायनिक तत्व तथा यौगिक धातु की बनी वस्तुओं, ताँबा आदि का विशेष महत्व है।

भारत सरकार की 1977-78 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार—“1974-75 तथा 1975-76 के दौरान आयातों में काफी वृद्धि के बाद 1976-77 में भारत के कुल आयात 5074.36 करोड़ रु के हुए जिससे लगभग 36 प्रतिशत की गिरावट प्रकट होती है। 3 प्रमुख समूहों अर्थात् अनाज, पी. ओ. एस. तथा विनिर्मित चरकरों के समुक्त आयात 1975-76 के दौरान हुए भारत के कुल आयातों के 58 प्रतिशत ठहरते हैं, लेकिन 1976-77 में उनका भाग घटकर 49 प्रतिशत रह गया। घरेलू उत्पादन में सुधार के कारण अनाज का भाग, जो 1975-76 में 25.5 प्रतिशत था, घट कर 17.5 प्रतिशत हो गया तथा विनिर्मित उर्वरकों का भाग 8.9 प्रतिशत से घटकर 3.9 प्रतिशत हो गया।

खाद्य तेल, रुई, मानव निर्मित रेशे के मामले में आयात विशेषकर इस उद्देश्य से अधिक किए गए कि इन मशे की घरेलू उपलब्धता बढ़े तथा उनकी कीमतों

पर नियन्त्रण हो। रसायनिक तत्वों तथा यौक्तिकों, भेषजीय तथा औषध, वाहन तथा गन्ना, प्लास्टिक सामग्री, विनिर्मित उर्वरक, बिना तराशे हुए मूल्यवान तथा प्रसिद्ध-मूल्यवान पत्थरों में भी वृद्धि भिन्न भिन्न मात्रा में हुई है।

(2) दिशा के अनुसार परिवर्तन—आयातों का दिशा परिवर्तन निम्नलिखित दिशा परिवर्तन के घनत्व है। जिन देशों से आयात किया जाता है उनमें अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, ईरान, जापान, कनाडा और रूस मुख्य हैं। 1971-72 में अमेरिका का स्थान सबसे ऊँचा ब्रिटेन का दूसरे नम्बर पर, जापान का तीसरे नम्बर पर और ईरान का चौथे नम्बर पर था। हम से हमारा आयात व्यापार तुलनात्मक रूप में बहुत अधिक बढ़ा है। जहाँ 1950-51 में हम से केवल 23 लाख रुपये का आयात किया गया वह यहाँ आयात राशि बटवर 1971-72 में 8,156 लाख रुपये हो गई। अमेरिका, ब्रिटेन से हमारा आयात-व्यापार पहले ही काफी बढ़ा हुआ था।

1975-76 में पश्चिम यूरोप से 1256 करोड़ रु का आयात हुआ जिससे यूरोपीय साम्राज्य बाजार से 1096 करोड़ रु का था। इसी अवधि में एशिया तथा ओसीनिया से 1777 करोड़ रु का आयात हुआ जिसमें एस्कंध से आयात की राशि 1064 करोड़ रु और ग्रेप एशिया तथा ओसीनिया से 100 करोड़ रु की थी। इस अवधि में अफ्रीका 5000 करोड़ रु और अमेरिका से 1552 करोड़ रु का आयात हुआ। वर्ष 1977-78 में आयात अस्थायी रूप से 5,832 करोड़ 49 लाख रु मूल्य का होना अनुमानित किया गया है।

(ग) भारत का प्रतिबल व्यापार सन्तुलन और उसके कारण

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से 1971-72 तक प्रति वर्ष भारत के आयातों का मूल्य निर्यातों के मूल्यों से अधिक रहा अतः व्यापार सन्तुलन भारत के विपक्ष में रहा। बाद के वर्षों में भी स्थिति में उतार-चढ़ाव आता रहा। 1977-78 के वर्ष के लिए अनुमान लगाया गया है कि व्यापार सन्तुलन लगभग 600 करोड़ रु विपक्ष में रहेगा। मई, 1978 को भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 1977-78 के माईकडे में प्रतिम रूप से वृद्धि होने की सम्भावना है और आशा है कि निर्यात और आयात के प्रतिम माईकडे प्रमश 5400 करोड़ रु और 6000 करोड़ रु के होंगे।

व्यापार सन्तुलन के विपक्ष में रहने के कारण—प्रश्न उठता है कि देश का व्यापार-सन्तुलन निरन्तर विपक्ष में क्यों रह रहा है? अवश्य ही इसके कुछ विशेष कारण हैं—

1. देश के विभाजन के फलस्वरूप अनाज और कच्चे धातु के उत्पादक प्रादेशिक क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। अतः इन वस्तुओं की जमी पूर्ति के लिए देश को भारी मात्रा में आयात करना पड़ा और व्यापार-सन्तुलन हमारे विपक्ष में हो गया।

2 स्वतन्त्रता के बाद से ही विभिन्न कारणोंवश देश में साधनों का निरन्तर अभाव बना हुआ है और इनके आयात पर विपुल धनराशि विदेशों को चुकानी पड़ती है।

3 योजनावद्ध आर्थिक विकास में औद्योगीकरण पर और कृषि के वैज्ञानिकीकरण पर अधिकारिक बल देने से विदेशों से कच्चे माल, पुर्जे तथा अन्य साज-सामान का भारी मात्रा में आयात करना पड़ा है अतः हमारा आयात-विल निरन्तर बढ़ता गया है।

4. चीन और पाकिस्तान के अनुतापूर्ण व्यवहार और भारत पर आक्रमण के कारण देश को सुरक्षा सामग्री के आयात पर भी भारी व्यय करना पड़ा है, अतः यह भी व्यापार-सन्तुलन के विपक्ष में रहने का एक बड़ा कारण है।

5. देश के विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार की विकास-सामग्री का आयात करना पड़ा है। विकास-मूलक आयातों को तब तक कम नहीं किया जा सकता जब तक हम स्वयं इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर न बढ़ें। विभिन्न किस्म की मशीनरी, परिवहन के साज-सामान, रासायनिक उर्वरक आदि का उत्पादन देश में अपर्याप्त होने से इनके आयात पर भारी व्यय किया गया है और फलस्वरूप व्यापार की बाकी हमारे विपक्ष में रही।

छ देश में आयात-विल तो बढ़ता रहा है जब कि प्रयत्न करने पर भी निर्यातों में हम तेजी से वृद्धि नहीं कर सके हैं। वास्तव में 1971-72 तक तो निर्यात के क्षेत्र में हम बहुत कुछ स्थिरता की दशा में थे। विगत वर्षों में सरकार निर्यात-वृद्धि के सभी सम्भव उपायों पर अग्रसर कर रही है और इसके अच्छे परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं।

भारत जैसे अर्द्ध-विकसित देश में योजनावद्ध आर्थिक विकास की प्राथमिक समस्या में व्यापार-सन्तुलन का प्रतिकूल रहना कोई अस्वाभाविक और चिन्ताजनक बात नहीं है, अतः कि देश की अर्थ-व्यवस्था निरन्तर सबल और समुन्नत होती जाए। उपलब्ध स्रोतों का समुचित विदोहन करके और आर्थिक विकास की हद आधारभूत रखकर निर्यातों में वृद्धि करना तथा विदेशी ऋणों को शुकाना सम्भव है, लेकिन यदि आर्थिक विकास की गति मन्द हो और दीर्घकाल तक व्यापार-सन्तुलन विपक्ष में चला जाए तो यह स्थिति चिन्ताजनक है। इसमें देश के समक्ष विदेशी विनिमय का गम्भीर संकट उपस्थित हो जाता है। दुर्भाग्यवश भारत के सबसँ में यह चिन्ताजनक पहेलू साधू हो रहा है।

भारत के विदेश व्यापार की प्रवृत्तियाँ : सम्पूर्ण स्थिति

भारत सरकार की रिपोर्ट 1977-78

भारत सरकार के वाणिज्य विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 1977-78 के अनुसार 1973-74 से 1977-78 के मध्य भारत के विदेश व्यापार की प्रवृत्तियों की सम्पूर्ण स्थिति का चित्रण इस प्रकार किया गया है—

नवीनतम संशोधन के अनुसार वर्ष 1976-77 के दौरान पुनर्निर्यातों सहित समग्र भारतीय निर्यात कुल 5143.35 करोड़ रु० के रहे। इस प्रकार विगत वर्ष में हुए निर्यातों की तुलना में इसमें लगभग 27.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयातों के मामले में पिछले वर्षों में वृद्धि की जो गति थी वह उलट गई। वर्ष के दौरान कुल

देश के प्रमुख आयाती अर्थात् पी.ओ.एस, खाद्य तथा उर्वरकों जैसी मदों की विश्व कीमतों में तीव्र वृद्धि के कारण 1973-74 तथा 1975-76 के मध्य आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई अर्थात् वे 2,955 करोड़ रु० से बढ़कर 5,265 करोड़ रु० के हो गए। आयातों में 1973-74 में 5 प्रतिशत की तथा 1974-75 में 53 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 1975-76 में 16.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि पेरू उत्पादन, सामान्य साधनों, उर्वरकों तथा लोहा तथा इस्पात में वृद्धि होने के कारण वर्ष 1976-77 के दौरान आयात काफी हद तक कम हुए अर्थात् उसमें 3.6 प्रतिशत की गिरावट आयी। इस प्रकार वर्ष 1976-77 में विदेशों में भारत के व्यापार कारोबार में महत्वपूर्ण मोड़ आया।

निर्यात के सम्बद्ध सूचकांकों से पता चलता है कि 1975-76 तथा 1976-77 दोनों वर्षों में निर्यातों के मूल्य में जो वृद्धि हुई उससे इकाई मूल्य प्राप्ति में वृद्धि की प्रतीक्षा निर्यातों की मात्रा में वृद्धि का अपेक्षाकृत अधिक योगदान था। यह स्थिति 1973-74 तथा 1974-75 से भिन्न थी। निर्यातों के सूचकांक मात्रा में 1973-74 तथा 1974-75 में क्रमशः 4.2 प्रतिशत तथा 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जिसकी तुलना में 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान क्रमशः 10.5 प्रतिशत तथा 18.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, परन्तु इकाई मूल्य प्राप्ति के मामले में यह भ्रम था। विश्व बाजार में मन्दी आने से 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान निर्यातों से इकाई मूल्य प्राप्ति में केवल 7.7 प्रतिशत तथा 6.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1973-74 में 21.7 प्रतिशत तथा 1974-75 में 25.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

आयातों के इकाई मूल्य में वृद्धि की दर सामान्यतः निर्यातों के इकाई मूल्य में वृद्धि से अधिक रही है जिसके परिणामस्वरूप व्यापार की स्थिति में कुल मिलाकर गिरावट रही। तथापि 1976-77 के दौरान आयात के इकाई मूल्य में मामूली गिरावट होने से उसके साथ ही आयात की कम मात्रा के कारण पिछले वर्षों जो व्यापार की स्थिति में जो गिरावट आई थी वह 1976-77 में रुक गई। निर्यात आयात के सम्बद्ध सूचकांक निम्नोक्त तालिका में दिए गए हैं—

सूचकांक

(आधार वर्ष 1968-69=100)

वर्ष	इकाई मूल्य		मात्रा		व्यापार स्थिति (निवल)
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	
1972-73	126	97	120	99	124
1973-74	146	133	125	114	106
1974-75	183	239	133	100	77
1975-76	197	280	147	99	70
1976-77	210	278	174	97	76

क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण बाजार ये हैं—पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य, रूमानिया, बल्गेरिया तथा हंगरी ।

1976-77 के दौरान अफ्रीका क्षेत्र को किए गए निर्यातों में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 1976-77 में इस क्षेत्र में भारतीय माल का सबसे बड़ा खरीददार मिस्र का अरब गणराज्य है जिसके बाद ये आते हैं—सूडान, नाइजीरिया, तंजानिया, कीनिया, लीबिया, मारिशस तथा जाम्बिया ।

1976-77 के दौरान एशिया तथा ओसीनिया द्वारा की गई खरीद लगभग 20 प्रतिशत बढ़ी । एस्कैप के मामले में वृद्धि लगभग 6 प्रतिशत हुई । 1976-77 में उसके द्वारा 1150 करोड़ रु के माल की खरीद की गई जबकि 1975-76 में 1282 करोड़ रु की खरीद की गई थी । शेष एशिया तथा ओसीनिया की निर्यात बढ़कर 582 करोड़ रु के हुए जबकि पहले 341 करोड़ रु. के हुए थे और इस प्रकार 71 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 1976-77 में एस्कैप को किए गए कुल निर्यातों का 44 प्रतिशत भाग अकेले जापान को ही भेजा गया था तथा उसके बाद ईरान तथा मास्डोनिया आते हैं जिनका भाग 12 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत था । 1976-77 में 544 करोड़ रु के कुल निर्यातों में जापान को किए गए हमारे निर्यातों में प्रयस्क तथा मछली प्रमुख मर्चें हैं । अन्य मर्चों में ये शामिल हैं—पटसन खाल, तम्बाकू, लोहा तथा इस्पात, मोती, मूल्यवान तथा अर्द्ध-मूल्यवान पत्थर तथा काजू गिरी । 1976-77 में ईरान को किए गए हमारे निर्यातों को भारी धक्का लगा । 1976-77 में वे घटकर 146 करोड़ रु के हुए जबकि 1975-76 में 273 करोड़ रु. के हुए थे । यह गिरावट मुख्य रूप से चीनी के निर्यातों में तीव्र कमी के कारण आई ।

शेष एशिया को, जिसमें अधिकांशित पश्चिम एशिया के देश हैं, भारत के निर्यात हाल के वर्षों में बढ़ते रहे हैं । 1976-77 के दौरान इस क्षेत्र को किए गए हमारे कुल निर्यातों में से 28 प्रतिशत निर्यात संपुक्त अरब अमोरात, 20 प्रतिशत कुवैत, 13 प्रतिशत सऊदी अरब तथा 8 प्रतिशत ईराक को किए गए । 1976-77 में संयुक्त अरब अमोरात के सम्बन्ध में निर्यात लगभग 152 प्रतिशत बढ़े जो 66 करोड़ रु. से बढ़कर 167 करोड़ रु हुए, कुवैत के सम्बन्ध में 148 प्रतिशत बढ़े जो 47 करोड़ रु. से बढ़कर 117 करोड़ रु. हुए, सऊदी अरब के सम्बन्ध में 27 प्रतिशत बढ़े जो 60 करोड़ रु से बढ़कर 76 करोड़ रु हुए, लेकिन ईराक के मामले में निर्यात 26 प्रतिशत घटे जो 64 करोड़ रु से घटकर 47 करोड़ रु. रह गए । तेल की बीमती में वृद्धि के परिणामस्वरूप तेल राजस्व में काफी वृद्धि होने से मध्यपूर्व के तेल उत्पादक देशों ने विकास की बहुत बड़ी योजनाएं आरम्भ की हैं जिनमें ग्रन्थ स्थापना तथा उद्योगों का विकास शामिल है । इससे माल तथा सेवाओं की सप्लाई के लिए बड़ा बाजार तैयार हो गया है ।

पश्चिम यूरोप, विशेषकर यूरोपीय साभाना बाजार के साथ भारत के विदेशी व्यापार में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि 1975-76 में जो 265 करोड़ रु. का था, उसने स्थान पर 1976-77 में 482 करोड़ रु. का दबिजेप रखा है ।

भारत के विदेश आर्थिक सम्बन्धों से पता चलता है कि बंगलादेश, नेपाल, मर्मा, श्रीलंका, अफगानिस्तान और ईरान जैसे पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय सम्बन्ध और अधिक सुदृढ़ हुए हैं तथा पाकिस्तान और चीन के साथ व्यापार भाग खुले हैं।

1977 में चीन लोक गणराज्य के साथ व्यापार सम्पर्क हुए तथा व्यापार का आदान प्रदान हुआ जिससे उसके साथ व्यापार का सामान्यीकरण हुआ। कैंटन मेले (अप्रैल-मई 1977) और (अक्तूबर-नवम्बर 1977) में भारत के भाग लेने के परिणामस्वरूप चीन के साथ 394 करोड़ रु. मूल्य के व्यापार के लिए सविदा की गयी, जिसके अन्तर्गत जस्ता, एंटीमनी, घातु और गारे का आयात तथा कच्चे लोहे और चमड़े का निर्यात किया जाना है। भारत-पाकिस्तान व्यापार को, जो 1975 में फिर से आरम्भ हुआ तथा पहले जो दोनों देशों के राज्य व्यापार अधिकरणों तक सीमित था, 15-7-76 से प्राइवेट व्यापार के लिए खोल दिया गया। अप्रैल 1977 के दौरान नई दिल्ली में भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो व्यापार समीक्षा सम्बन्धी बात-चीत हुई थी उसके परिणामस्वरूप व्यापार सम्बन्धों में और परिवर्तन हुए हैं। 1976-77 के दौरान पाकिस्तान को किए गए भारत के निर्यात 8.97 करोड़ रु. के हुए। व्यापार बढ़ने लगा और 1977-78 के पहले 6 महीनों के दौरान निर्यात 8.00 करोड़ रु. के स्तर के हुए। भारत से पाकिस्तान को निर्यात की जाने वाली प्रमुख मर्चें ये हैं—घास, इन्जीनियरी माल, लोहे तथा इस्पात से बना माल, कोयला, सीमेंट तथा ताम्रबूल पात्र आदि। पाकिस्तान से हमारे आयातों के विविधीकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं तथा नई मर्चें अभिज्ञात की जा रही हैं। 1977-78 की पहली छमाही के दौरान बंगला देश को किए गए निर्यातों का मूल्य 25.63 करोड़ रु. था।

नेपाल के साथ पृथक् रूप से व्यापार तथा पारगमन सन्धियाँ करने के लिए बातें चल रही हैं। 1976-77 के दौरान नेपाल को किए गए निर्यातों का मूल्य 51.66 करोड़ रु. था तथा 1977-78 की पहली छमाही के दौरान 24.31 करोड़ रु. के निर्यात हुए। श्रीलंका की कुल खरीद बढ़ रही है। श्रीलंका को हमारे निर्यात जो 1975-76 में 23.10 करोड़ रु. के थे, 1976-77 में बढ़कर 39.35 करोड़ रु. के हो गए तथा 1977-78 की पहली छमाही के दौरान उस देश को किए गए निर्यात 24.36 करोड़ रु. हो गए।

निर्यात का महत्त्व और निर्यात-संबन्धन के उपाय

शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना हमारी सरकार की आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों के प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए निर्यात में वृद्धि आवश्यक और वाञ्छनीय है क्योंकि अधिक निर्यात के द्वारा जरूरी विदेशी मुद्रा कमा कर ही हम बहुत-सी महत्वपूर्ण वस्तुएँ और साधन-सामान, जो कि अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक हैं, खरीद सकते हैं। निर्यात मूल्य की अपेक्षा आयात मूल्य अधिक रहने की प्रवृत्ति से व्यापार संतुलन हमारे विपक्ष में रहता है जिसका सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर घातक प्रभाव पड़ता है।

विदेश व्यापार-नीति (Foreign Trade Policy)

व्यापार के सम्बन्ध में सरकारी नीति का बड़ा महत्त्व होता है और विशेषकर एक विकसित देश के सन्दर्भ में तो इसका बहुत ही महत्त्व है। यदि आयातों पर प्रतिबन्ध लगाने की नीति अपनाई जाती है तो घरेलू उद्योगों के विकास के लिए संरक्षित बाजार की व्यवस्था होती है। अमेरिका, जापान, जर्मनी आदि अति उन्नत देशों ने अपने विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में घरेलू अथवा देशी उद्योगों को विकसित करने के लिए आयातों पर सीमा शुल्क लगाने की नीति अपनाई है। निर्यात के क्षेत्र में भी सरकारी नीति-नीति का विशेष महत्त्व है। निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा आर्थिक विद्युद्धेयन से सम्बन्धित कमियों को दूर करने के लिए आज के युग में राज्य का सर्वोपरि महत्त्व है। राज्य द्वारा सूचना-प्रवन्ध, विदेशों में व्यापार अभिकरणों का प्रवन्ध आदि किया जाता है। राज्य निर्यातकों को वित्तीय सहायता एवं प्रोत्साहन प्रदान करता है। आवश्यक होने पर कुछ विशेष वस्तुओं का एवं कुछ विशेष उद्देश्यों के साथ व्यापार राज्य स्वयं भी करता है।

भारत में विदेशी व्यापार नीति के विकास में 1923 का वर्ष एक विभक्तक रहता है। इससे पूर्व भुक्त व्यापार नीति की प्रधानता थी जिसका पूरा उपयोग ब्रिटिश हितों के संरक्षण के लिए किया गया और फलस्वरूप भारत के निर्यात में से विभिन्न मालों का नामनिर्देशन मिटाकर भारत उत्तरोत्तर कृषि-वस्तुओं पर निर्भर बनता गया। भारत से कच्चे माल और खाद्यान्न के निर्यात और इंग्लैण्ड से निर्मित माल के आयात की नीति तत्कालीन भारत सरकार द्वारा अपनाई गई। इस प्रकार देश के व्यापार ने औपनिवेशिक व्यापार का रूप धारण कर लिया। 1923 में भेदभूतक संरक्षण की नीति प्रारम्भ की गई जो प्रायः चल कर यथायथः केवल "विभेद की नीति" ही रह गई, "संरक्षण" प्रदान करने की नीति नहीं बन पाई। 1947 में स्वतन्त्र भारत के उदय के साथ ही राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई और विदेशी व्यापार-नीति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों का सूत्रपात हुआ। अब विदेश व्यापार नीति इस प्रकार ढाली जाने लगी जिससे वह योजनावद्ध आर्थिक विकास एवं औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने में सहायक हो। व्यापार के भारतीयकरण की प्रक्रिया भी प्रारम्भ की गई।

कांग्रेस सरकार की व्यापार नीति

(अ) आयात नीति

भारत सरकार की आयात नीति में समय-समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। कभी यह उदार रही है तो कभी कठोर। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के तुरन्त बाद आयात नीति को उदार रखा गया, फलस्वरूप आयातों में काफी वृद्धि हुई तब मई, 1949 से आयातों पर प्रतिबन्ध की नीति अपनाई गई और फिर 1950-51 में नीति को पुनः उदार बनाते हुए आयात-मुक्ती में कई और वस्तुएँ जोड़ी गईं। फिर भी कुल

(4) आयात-नीति का बुनियादी उद्देश्य अब भी यही रहा कि आयातिन माल की जगह देशी माल का उपयोग किया जाए। अनावश्यक आयातों पर पूर्ण प्रतिबन्ध अथवा रोक की नीति अपनाई गई जबकि कई अन्य मर्चों पर आयातों के आंशिक प्रतिबन्ध की नीति लागू की गई और इस तरह आयात नीति में "इनाम घोर" सजा की नीति का सम्मिश्रण किया गया।

(5) 1969-70 की आयात-नीति में निर्यात के लिए उत्पादन बढ़ाने और आयात में कमी करने पर जोर दिया गया। आयात कम करने के लिए और आयातित वस्तुओं की जगह कई वस्तुएँ बनाने के लिए 316 वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इसके अतिरिक्त 129 नई वस्तुओं का आयात सीमित किया गया।

(6) 1970-71 की आयात-नीति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। सरकारी क्षेत्रों की एजेंसियों द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं में 38 और वस्तुएँ भी शामिल कर दी गईं।

(7) 1971-72 की आयात-नीति में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जैसे—(i) सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों के आयात सम्बन्धी काम बंटा दिए गए, (ii) निर्यात-उत्पादन और निर्यात-श्रमता बढ़ाने के लिए अधिक सुविधाएँ दी गईं, (iii) निर्यात सदनों (Export Houses) सम्बन्धी परिभाषा और ध्यापन बना दी गई, (iv) प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को आवश्यकतानुसार लाइसेन्स देने की नीति जारी रखी गई, लेकिन गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में छोटे-बड़े दोनों उद्योगों को कच्चे माल के आयात के लाइसेन्स वार्षिक आधार पर दिया जाना तय किया गया, (v) लघु-स्तरीय उद्योगों को कच्चे माल के आयात की पहले से अधिक उदार सुविधाएँ दी गईं, एवं (vi) यह निश्चय किया गया कि जो वस्तुएँ देश में ही निर्मित होने लगी हैं उनका आयात घटाया जाएगा। 1971-72 की नीति के अनुसार राज्य द्वारा 51 और वस्तुओं का आयात अपने हाथ में ले लिया गया। इस प्रकार विदेशी व्यापार में सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार की नीति एक कदम और आगे बढ़ी।

(8) 1973-74 की अवधि के लिए, औद्योगिक विकास की दृष्टि से, उदार आयात-नीति अपनाई गई। 11 और उद्योग प्राथमिकता सूची में ले लिए गए, 20 अन्य मर्चों को आयात के लिए सरकारी क्षेत्र में लिया गया। 220 मर्चों का आयात पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया और 81 मर्चों को सीमित कर दिया गया। नई आयात नीति ऐसी रखी गई जो विनामोन्मुख और रोजगार-सम्बर्द्धक हो।

(9) सरकार ने 1974-75 के लिए उदार आयात-नीति घोषित की जिसका उद्देश्य निर्यातों को प्रोत्साहन देना तथा प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल के आयात की व्यवस्था करना था।

(10) 1976-77 की आयात नीति में कुछ और उदारता का समावेश था। आयातित कच्चे माल तथा सघटकों के लिए 1975-76 में लागू की गई

रूपे हो गया। अवमूल्यन का उद्देश्य या निर्यात-संबंधन और आयात-प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन। अवमूल्यन की घोषणा के साथ ही सरकार ने निर्यात-प्रोत्साहन की दूसरी योजनाएँ समाप्त कर दी। कुछ वस्तुओं पर निर्यात-शुल्क लगा दिए गए तो आयात करों में भी कुछ संशोधन किए गए। सरकार का विचार था कि विदेशों में जिन वस्तुओं की मांग बेलेच है, उन पर निर्यात कर लगाना उचित होगा। अवमूल्यन के बाद निर्यात-संवर्धन के और भी विभिन्न उपाय किए गए। 1970 में संसद में एक निर्यात नीति सकल्प प्रस्तुत किया गया और उसी के अनुसार देश की व्यापार नीति चलाई जाने लगी। यह निर्यात नीति सकल्प आज भी प्रभावी है। इसमें निर्यात घाय को अधिकाधिक बढ़ाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं। इस नीति के अनुसार भारत सरकार निर्यात के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु आवश्यक निवेश को प्रोत्साहन देती है। औद्योगिक लाइसेंस नीति के अन्तर्गत विशेष रूप से निर्यात के लिए औद्योगिक उत्पादन का विस्तार करने की व्यवस्था की गई। निर्यात के लिए देश की जरूरत से अधिक उत्पादन और विदेशों में उनके लिए बाजार खूँढने की समस्याएँ हल करने के लिए वाणिज्य मन्त्रालय में निर्यात उत्पादन विभाग खोला गया है। आयात और निर्यात व्यापार को सुचारूँ रूप से चलाने के लिए सरकारी व्यापारिक अभिकरणों को अनुकूल सचि में ढाला जा रहा है। सरकार ने विशेष प्रकार के व्यापार का संचालन करने के लिए अलग-अलग नियम स्थापित किए हैं। इस प्रकार निर्यात व्यापार में विशेषीकरण की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को स्वीकार किया गया है।

निर्यात संवर्धन के लिए सरकार विभिन्न देशों से व्यापारिक समझौते करती है जिनमें मुख्यतः निम्नलिखित उद्देश्य अन्तर्निहित हैं—(1) व्यापारिक लाभ के आधार पर विदेशी व्यापार में वृद्धि करना, (2) दूसरे देशों से, प्रत्यक्ष व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना, (3) देश के परम्परागत और गैर-परम्परागत दोनों ही निर्यात में वृद्धि करना, (4) परम्परागत निर्यातों के मूल्यों में स्थिरता लाना तथा गैर-परम्परागत निर्यातों के लिए आकर्षक भण्डियाँ स्थापित करना, (5) विदेशी विनिमय माघनों पर बिना अतिरिक्त दबाव डाले अथवा कम से कम अतिरिक्त दबाव डाले पूँजीगत माल तथा औद्योगिक कच्चा माल प्राप्त करना, एवं (6) रुपये में मुग्तान वाले देशों से व्यापार में अधिकाधिक प्रगति करना।

जनता सरकार की नई निर्यात-आयात नीति की विशेषताएँ

जनता पार्टी की सरकार ने जो नई आयात-निर्यात नीति अपनाई है उसकी विशेषताएँ निम्न ही उत्साहवर्धक हैं।

नई आयात नीति की विशेषताएँ

जनता सरकार की नई आयात नीति की चार प्रमुख विशेषताएँ हैं। आयात-निर्यात इस दृष्टि का हो कि—

- (1) देश में कीमतों पर बुरा असर न पड़े,

(2) औद्योगिक उत्पादन बढ़े,

(3) आम उपभोग की वस्तुओं का निर्यात न किया जाए, एवं

(4) छोटे व मध्यम स्तर के उद्योगों में परेशानी कम हो।

सब बातें तभी पूरी की जा सकती हैं जब आयात नीति मरन एवं उदार हो। इसलिए नई नीति के तहत विदेशी मुद्रा के उपयोग एवं कच्चे व पूँजीगत माल के आयात का जनता सरकार न काफी उदार बनाया है। वाणिज्य मंत्री श्री मोहन धारिया न तो यह भी संकेत दिया था कि मंत्र भविष्य में पूँजीगत माल एवं औद्योगिक कच्चे माल के आयात को अधिक उदार बनाया जाएगा। इसके सम्बन्ध में केन्द्र में अलवन्डर समिति गठित की है जो जनता सरकार की आयात व निर्यात नीति के परिणामों की समीक्षा करेगी एवं परिवर्तन के सम्बन्ध में सिफारिशें करेगी। अगर परिणामों को देखा जाए तो उदार आयात नीति मरन रही है। इस नीति की पहली सफलता तो यह है कि आलू, प्याज, नमक, शक्कर एवं अन्य ताजी सब्जियों का निर्यात नहीं हो रहा है। अगर इनका निर्यात शुरू कर दिया जाता तो देश में इनके भावों में काफी वृद्धि हो जानी और उपभोक्ता को परेशानी होती। अगर इन वस्तुओं का निर्यात करते तो गत वर्षों की तुलना में यहाँ इनके 1977-78 में निर्यात में 15 प्रतिशत की वृद्धि निश्चय हो जानी, किन्तु दूसरी ओर भाव अधिक बढ़ जाते।

अभी तक देश की आयात नीति काफी नियन्त्रित थी एवं यह सपना देखा जाता था कि निर्यात में अधिक वृद्धि हो। इस सपने का मुख्य कारण यही था कि देश में विदेशी मुद्रा की कमी थी और इसलिए वासमनी चावल, आलू, प्याज, मँगफनी दाल एवं खाद्य तेलों का निर्यात करने का प्रयास किया जाता था। पर अर स्थिति एकदम बदल गई है। अब भारत के पास विदेशी मुद्रा की कोई कमी नहीं है। विदेशी मुद्रा कोष का बढ़ना समस्या बन गई है। इसलिए सरकार ने विदेशी मुद्रा का उपयोग आवश्यक चीजों के आयात करने की बात सोची है और व्यावहारिक आयात निर्यात नीति बनाई है जिससे पूँजीगत व कच्चे माल की कमी न रहे। हमने अपनी औद्योगिक क्षमताएँ बढ़ा ली हैं इसलिए उसके अनुसूच कच्चा माल भी चाहिए। उदार आयात नीति से उत्पादन बढ़ेगा जिससे देश में मूल्यों को स्थिर बनाए रख सकेंगे तथा अनिश्चित उत्पादन का निरात किया जा सकेगा। इस तरह निर्यात बढ़ाने के लिए आयात जरूरी है।

इस उदारता के साथ दूसरी ओर यह सावधानी भी जरूरी है कि कोई ऐसी वस्तुएँ आयात न हों, जिनसे देश में ही पैदा हो रही हैं। कई नीति के तहत कुछ ऐसी कमियाँ हैं जिन्हें ठीक करना है। उदार नीति के अनुसार पूँजीगत माल एवं मशीनरी के साथ-साथ टेक्नोलॉजी के आयात को प्रोत्साहन देते हैं जो उससे देश के विकास को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान विदेशी मुद्रा कोष ऐसे आयात के लिए सहायक होगा।

आयात को उदार बनाने के साथ ही यह देगना भी जरूरी है कि आयात

इतना न बढ़ जाए कि विदेशी-व्यापार में अभी जो सन्तुलन बन रहा है वह बिगड़ जाए। इस सिलसिले में निर्यात के क्षेत्र में आने वाली परेशानियों को भी दूर करना है क्योंकि अब हमारा विदेश व्यापार बहुमुखी बनता जा रहा है। अब कच्चे माल का निर्यात 33 प्रतिशत से भी कम हो गया है अब दूसरी ओर इजीनियरी व हस्त-शिल्प की वस्तुओं के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है।

नई निर्यात नीति की विशेषताएँ

जनता सरकार के वाणिज्य मन्त्री श्री मोहन घारिया ने जनवरी, 1978 के अपने विशेष लेख में इस बात पर अफसोस प्रकट किया कि निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए भी हमने तथाकथित 'निर्यातपरक' विकास की नीति को धीरे-धीरे छोड़ दिया। श्री घारिया ने जनता सरकार की नई निर्यात नीति की आधारभूत विशेषताओं पर प्रकाश डाला। ये विशेषताएँ उन्हीं के शब्दों में निम्न-लिखित हैं—

1. हम निर्यात-मिश्रण को गतिशील क्षेत्रों की ओर मोड़ने पर बल देंगे जिसमें हमे लम्बी अवधि का प्रतियोगिक लाभ होगा और जहाँ कृत्रिम वसावियों के सहारे के बिना ही निर्यात में वृद्धि की जा सकती है। निर्यात विस्तार के अग्रणी क्षेत्रों में इजीनियरिंग वस्तुएँ, रसायन, चमड़ा उत्पाद, सिले-सिलाए कपड़े, हाथ कारवा उत्पाद तथा परामर्श और इजीनियरिंग सेवाएँ और परियोजना निर्यात जैसी तकनीकी सघन उत्पादन शामिल है।

2. परम्परागत निर्यात के क्षेत्रों में हमारा उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना और वस्तु-मिश्रण की निष्पन्नापूर्ण बनाना होगा ताकि हम अपनी भाव्य अधिकतम कर सकें। कुछ क्षेत्रों में यह पहले ही किया जा रहा है। उदाहरण के लिए अब हम कच्ची हड्डियों और मानों के निर्यात के स्थान पर तैयार चमड़े और चमड़ा उत्पादों के निर्यात की ओर उन्मुख रहे हैं। भविष्य में हम भारी मात्रा में खुली भाव्य भेजने के बजाए इसे पैकेटों और थैलों में भेजेंगे। इसी प्रकार, हम समुद्री और वन उत्पादों जैसे समाप्त न होने वाले पदार्थों तथा लोह अपस्क जैसे समाप्त होने वाले पदार्थों के निर्यात में घरेलू उपभोग की वस्तुओं में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। नई निर्यात नीति के इन तरफ के द्वारा अधिक रोजगार के माध्यम से निर्यात के सामाजिक फायदों को अधिकतम किया जा सकेगा।

3. हमारी नई नीति का उद्देश्य आवश्यक आम उपभोग की वस्तुओं के निर्यात को नियमित करके हमारे निर्यात की सामाजिक लागत को न्यूनतम करना है। तिलहन, दालों, चाय, सब्जियों और प्याज जैसे उत्पादों के मामले में इनके निर्यात के बजाए घरेलू सपता की सदा प्राथमिकता दी जाएगी तथा निर्यात का घरेलू उत्पादन और कीमत पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा।

4. हम राज्य व्यापार निगमों की सहायता तथा बेहतर अन्तर्राष्ट्रीय विपणन और सूचना प्रणाली के रूप में अन्य बुनियादी सुविधाओं की मदद से अपने निर्यातकों की सोदा करने की शक्ति बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

हमारी नई निर्यात नीति का मुख्य उद्देश्य हमारे अपार स्रोतों का अधिकतम दक्षता के साथ अधिकतम उपयोग करना होगा। इस नीति से वस्त्र उद्योग हस्तशिल्प, हाथकरघा, चमड़ा उद्योग, धातु पर आधारित उद्योग तथा इंजीनियरिंग और परामर्श सेवाओं जैसे क्षेत्र में कुशल व अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ निर्यात के लिए कोई निर्यात नहीं किया जाएगा तथा निर्यात करने और उसे बढ़ाने की सामाजिक लागत को न्यूनतम रखा जाएगा।

आर्थिक समीक्षा 1977-78 के अनुसार व्यापार नीति की नई बातें

भारत की व्यापार नीति का व्यापक उद्देश्य यही है कि उत्पादन के आधार का विस्तार किया जाए, आर्थिक विकास की गति का और ज्यादा तेज करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाएँ और निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। 1977-78 की आयात नीति की न केवल इस कारण से उद्धार बनाया गया था कि उद्योग ऋणों के लिए आवश्यक वस्तुओं और कच्चे माल की सारी आवश्यकताएँ पूरी हो जाएँ वल्कि इसका उद्देश्य यह भी था कि कीमतों को, खास कर जन उपयोग की वस्तुओं की कीमतों को उचित स्तर पर रखा जाए।

आयात को उद्धार बनाए जाने के उपाय के रूप में बहुत सी वस्तुओं जैसे कि आयातित मशीनरी के फालतू पुर्जों, पातिनासिक तथा विस्कोस रेगो, खाद्य तेल, घड़ियों के पुर्जों और सूखे मेवों आदि को मुक्त लाइसेंस प्रणाली के अन्तर्गत रख दिया गया। इसके साथ-साथ, खुली सामान्य लाइसेंस प्रणाली की व्याप्ति को और ज्यादा व्यापक बना दिया गया और चमड़े की वस्तुएँ बनाने की मशीनरी पोशाक बनाने की मशीनरी तथा बहुत सी औषधी दवाइयों रासायनिक पदार्थों, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, लोहे और इस्पात की वस्तुओं तथा वैज्ञानिक व तकनीकी विषयों की पुस्तकों के आयात को भी खुली सामान्य लाइसेंस प्रणाली के अन्तर्गत रख दिया गया। मुक्त व्यापार क्षेत्रों में मशीनरी के आयात, कच्चे माल तथा उपयोग की अन्य वस्तुओं के आयात को भी खुली सामान्य लाइसेंस प्रणाली के अन्तर्गत रख दिया गया।

स्वतः लाइसेंस प्रणाली की और भी ज्यादा लोचदार बना दिया गया और पहले के वर्ष में जारी किए गए स्वतः लाइसेंसों के मूल्य को ध्यान में न रखते हुए आयातित कच्ची सामग्री के वास्तविक उपयोग के आधार पर लाइसेंस दिए जाने लगे। निर्गम आदेशों के बिना ही वास्तविक उपयोगकर्ताओं को सत्या विशेष के माध्यम से आयात की जाने वाली वस्तुओं के प्रत्यक्ष आवंटन की जो योजना 1976-77 में शुरू की गई थी उसे और ज्यादा व्यापक बना दिया गया और उसके अन्तर्गत इस प्रकार की लगभग सभी वस्तुओं को सम्मिलित कर दिया गया।

लघु क्षेत्र के उद्योगों को उपलब्ध अनुकूल बर्ताव के दायरे को और ज्यादा विस्तृत कर दिया गया। इसके अन्तर्गत आयातित कच्चे माल को सफटकों की प्राप्ति के सम्बन्ध में इन उद्योगों की हकदारी को 20 प्रतिशत और ज्यादा बढ़ा दिया गया। इसके अलावा, क्षमता मूल्यांकन की पेचीदा प्रणाली को समाप्त कर दिया गया तथा

लघु उद्योग-धन्यो को भी अनुपूरक लाइसेंस पद्धति की सुविधा उसी प्रकार से उपलब्ध करा दी गई जैसा कि तकनीकी विकास महानिदेशालय के एकांको को उपलब्ध है।

पजीवद्ध निर्यातकों से सम्बन्धित नीति को नई दिशा प्रदान की गई और उसके अन्तर्गत निर्यात सम्बन्धी प्रयत्नों को और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए आवश्यक प्रेरणा दिए जाने की व्यवस्था कर दी गई। 'शापिंग लिस्ट' को खत्म कर दिया गया और निर्यातकों को जितने माल का पुनर्भरण करने की हकदारी है उतने माल के मूल्य के अन्दर-अन्दर आवश्यक कच्चे माल तथा सघटकों का आयात करने की अनुमति इस शर्त पर दे दी गई कि देशी उद्योग-धन्यो के उचित हिस्से की रक्षा पूरी तरह हो। यह अनुमति इसलिए दी गई कि निर्यातक अपनी वस्तुओं में विविधता ला सकें और अपने उत्पादों की कीटि में सुधार कर सकें। निर्यातकों को आयात पुनर्भरण लाइसेंस प्राप्त कर सकने के लिए किसी भी निर्माता को नामजद करने की भी अनुमति दे दी गई। इसके अलावा, अग्रिम लाइसेन्सों के आधार पर सीमा शुल्क सम्मुक्ति योजना के अन्तर्गत और ज्यादा वस्तुओं को भी शामिल कर दिया गया तथा इस प्रकार की प्रक्रिया को सरल बनाने वाले उपाय भी किए गए, जिनका उद्देश्य निर्यातकों को उत्पादन के क्षेत्र में तारतम्य बनाए रख करने और निर्यात सम्बन्धी आदेशों को पूरा करने के लिए आवश्यक सहायता की व्यवस्था करना था।

आयात पर पूर्ण रोक/निषेध लगाने की नीति में, नई आयात नीति के उद्धार तत्वों के धनुरूप, यथोचित परिवर्तन किया गया। निश्चले वर्ष 59 निषिद्ध वस्तुओं की जो सूची मौजूद थी उसके स्थान पर 17 पूर्णतः निषिद्ध वस्तुओं की सूची निकाली गई। चूंकि ये वस्तुएं देश में ही उपलब्ध हैं, इसलिए इनके आयात की अनुमति नहीं दी जा सकती।

निर्यात व्यापार नियन्त्रण नीति की मोटी रूपरेखा उद्योगों की रखी गई है। पहले जिन 200 वस्तुओं के निर्यात के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत होती थी उनमें से अब लगभग दो-तिहाई वस्तुओं के सम्बन्ध में 5 अगस्त, 1975 से लाइसेंस लेने की औपचारिकताओं को समाप्त कर दिया गया है और अब केवल बहुत ही कम वस्तुएं बची हैं जिन पर इस प्रकार का नियन्त्रण है। इनमें से बहुत सी वस्तुओं को खुली सामान्य लाइसेंस प्रणाली के अन्तर्गत रख दिया गया है। धरेलू, मुलभना तथा कीमती की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1977-78 में कुछ एक वस्तुओं के निर्यात पर या तो रोक लगा दी गई या फिर उनके निर्यात को विनियमित कर दिया गया है। इनमें दाने, बीज के काम आने वाला गेहूं, एच० पी० एस० मूंगफली, बोर्दो, रामनिल (हाटों और नादगर) और तिल तथा उनका तेल, आलू, प्याज, ताजी सब्जियाँ, नमक तथा दूध का पाउडर शामिल है।

निर्यात संवर्धन नीति को भी न्यूनाधिक रूप में अपरिवर्तित रखा गया। निर्यात प्रोत्साहन के क्षेत्र में, नकद मुआवजा सहायता दिए जाने, पुनर्भरण सम्बन्धी हकदारी बनाए रखने, शुल्क वापसी की व्यवस्था तथा रियायती शर्तों पर सदानपूर्व तथा सदान के बाद के ऋण दिए जाने की व्यवस्था को जारी रखा गया। पजीवद्ध

विस्कोस, पिलामेट यानों को भी सीमा-शुल्क से मुक्त कर दिया गया। ये सुविधाएँ इन वस्तुओं को अधिक मात्रा में आयात करने की सुनिश्चित व्यवस्था करने तथा घरेलू पूर्ति की स्थिति को ठीक करने के लिए दी गई थी। बहुत सी अन्य वस्तुओं जैसे कि मिट्टी के तेल, साइ की गिरी के तेल, स्टेनलेस स्टील की प्लेटों आदि के आयात-शुल्कों में भी कमी की गई ताकि घरेलू उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए, जीवन रक्षक औषधियों पर से भी जनवरी 1978 में आयात-शुल्क हटा दिया गया।

प्रालोच्य वर्ष में, भारत ने नवीन अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार पर हस्ताक्षर किए गए। व्यापारिक करारों के क्षेत्र में एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि हंगरी और उत्तरी कोरिया के साथ रपयों में किए जाने वाले व्यापार को हंगरी के साथ जनवरी 1978 से और उत्तरी कोरिया के साथ मार्च 1978 से परिवर्तनीय मुद्रा में करने का निर्णय लिया गया।

भारत में विनिमय नियन्त्रण तथा 1966 में रुपये का अवमूल्यन

(EXCHANGE CONTROL IN INDIA AND
DEVALUATION OF THE RUPEE IN 1966)

भारत के रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम (Foreign Exchange Regulation Act) के तहत विदेशी मुद्रा को नियन्त्रित किया जाता है। विदेशी विनिमय में अधिकृत डीलर ही इसका लेन देन कर सकता है। इसक सभी डीलर प्रायः बैंकिंग कंपनियाँ हैं। इनके पतिरिक्त अनुज्ञप्ति प्राप्त (Licenced) डीलर भी होते हैं जिनको अधिकृत धन परिवर्तनकर्ता (Authorised Money Changers) कहा जाता है। ये विदेशी मुद्रा के नोट तथा सिक्कों को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। उल्लेखनीय है कि अधिकृत डीलरों को हर प्रकार की विदेशी मुद्रा का व्यापार करने की अनुमति प्राप्त होती है जबकि धन परिवर्तनकर्ता केवल सिक्कों तथा नोटों का ही लेन-देन करते हैं।

अधिकृत हुए बिना कोई विदेशी लेखा नहीं रख सकता। विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम के अधीन विदेशी मुद्रा के सभी सपहों की घोषणा करनी होती है। विदेशी विनिमय के रूप में होने वाली प्रत्येक प्रायः अधिकृत डीलरों के माध्यम से भारत के रिजर्व बैंक को सौंप दी जाती है। सौंपने वाले व्यक्ति को बदले में स्थानीय मुद्रा अर्थात् रुपया प्रदान किया जाता है।

विनिमय नियन्त्रण का संगठन (Exchange Control Organisation)

जहाँ तक विदेशी विनिमय के लेन-देन का सम्बन्ध है, रिजर्व बैंक को पर्यक्ष रूप से जनता से सम्बन्ध नहीं रखना होता। इस कार्य के लिए जनता विदेशी विनिमय के अधिकृत डीलरों की सेवाओं से लाभ उठाती है। विनिमय नियन्त्रण के प्रशासन से सम्बन्धित कार्यों की देखभाल रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। विनिमय नियन्त्रण विभाग का अध्यक्ष विदेशी विनिमय का नियन्त्रक (Controller of Foreign Exchange) कहलाता है। उसकी सहायता उपनियन्त्रक (Deputy Controller)

तथा सहायक नियन्त्रक द्वारा की जाती है। विभाग का केन्द्रीय कार्यालय बम्बई में स्थित है। इसकी शाखाएँ कलकत्ता, बम्बई, कानपुर, मद्रास तथा नई दिल्ली में हैं। प्रत्येक शाखा की अध्यक्षता एक उपनियन्त्रक (Deputy Controller) द्वारा की जाती है। विनिमय नियन्त्रण से सम्बन्ध रखने वाले दिन-प्रतिदिन के कार्य इन्हीं कार्यालयों द्वारा सम्पन्न किए जाते हैं। विनिमय नियन्त्रण से सम्बन्धित सभी प्रार्थनापत्र इन कार्यालयों के नाम भेजे जाते हैं। विभिन्न कार्यालयों का अधिनार क्षेत्र निम्न तालिका से स्पष्ट होता है—

विनिमय नियन्त्रण कार्यालय	राज्य
1 बम्बई	गुजरात और महाराष्ट्र
2 कलकत्ता	असम, बिहार, मणिपुर, उड़ीसा, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल (भण्डमान तथा निकोबार द्वीपों सहित)
3 कानपुर	मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश
4 मद्रास	आन्ध्र प्रदेश, केरल (साथ ही लक्षद्वीप, मिनिक्काय और अमिन्डिवी द्वीप), मद्रास, मैसूर और पाण्डिचेरी।
5 नई दिल्ली	देहली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और राजस्थान।

विनिमय नियन्त्रण के लक्ष्य (Objects of Exchange Control)

भारत में विनिमय नियन्त्रण का लक्ष्य है देश की विदेशी विनिमय की समस्त प्राय को राष्ट्र के व्यापक हित की दृष्टि से सरकार को उपलब्ध कराना। व्यापक रूप से देखा जाए तो विनिमय नियन्त्रण निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है—

- (1) मूलभूत आवश्यकता की वस्तुओं का आयात किया जा सके।
- (2) देश के बाहर पूँजी की गति को प्रतिबन्धित किया जा सके।
- (3) देश के हित की दृष्टि से विदेशी विनिमय को वचाश और रक्षित किया जा सके।
- (4) विदेशी विनिमय की दर यथासम्भव एक जैसी बनी रहे।
- (5) राष्ट्र के विदेशी धायित्वों जैसे कर्जा आदि का निर्वाह करने के लिए विदेशी विनिमय उपलब्ध होना रहे।
- (6) विदेशी बाजारों में देश की सोदेबाजी करने की क्षमता बढ जाए।

विदेशी विनिमय की प्राप्ति एवं भुगतान (Receiving and Remitting Foreign Exchange)

विदेशी विनिमय की प्राप्ति तथा भुगतान आयातकता अथवा निर्यातकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं करना भारत के रिजर्व बैंक को सूचना देकर किए जाने हैं।

निर्यातों के लिए प्राप्तिर्था

जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है उनकी सूचना रिजर्व बैंक को दी जाती है। इस बात के लिए बैंक ने विभिन्न प्रकार के फार्म निर्धारित किए हैं। निर्यातकर्ता अपने प्रत्येक लन-देन का प्रतिबदन रिजर्व बैंक को तत्सम्बन्धी फार्म भरकर देना है।¹ जिस समय कौनसा फार्म भरा जाए इसका नियम दो बातों पर निर्भर है—(1) कौन दत्त अन्तिम रूप से भुगतान करेगा, और (2) भारत में यह भुगतान किस प्रणाली द्वारा प्राप्त किया जाएगा। सही काम भरना स्वयं निर्यातकर्ता का दायित्व है।

इन फार्मों के माध्यम से निर्यातकर्ता द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निर्यात की जाने वाली वस्तु में सम्बन्धित विशेष बातें क्या हैं जैसे—माल का विवरण, लक्ष्य, अविहृत विदेशी विनिमय के डीनर का नाम जिसके माध्यम से विदेशी विनिमय प्राप्त किया जाएगा आदि-आदि। निर्यातकर्ता को जो विदेशी विनिमय प्राप्त होता है उसे वह रिजर्व बैंक को समर्पित कर देता है।

रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार इन फार्मों की तीन धार प्रतिलिपियाँ भरी जाती हैं। मूल प्रतिलिपि (Original Copy) को शिपिंग टिन के साथ कस्टम को प्रस्तुत किया जाता है जबकि दूसरी प्रतिलिपि शिपिंग परिपत्रों के साथ निर्यातकर्ता वहाँ को प्रस्तुत की जाती है। कस्टम द्वारा निर्यातित माल के मूल्य को प्रमाणित करने के बाद मूल प्रतिलिपि रिजर्व बैंक को भेज दी जाती है। नियमानुसार भारत से किए गए आयात से सम्बन्धित परिपत्रों को एक अविहृत डीनर के माध्यम से जहाज में लादने के बाद 21 दिन के भीतर प्रदान किए जाने चाहिए। विदेशी विनिमय का अविहृत डीनर, जो कि एक बैंक होता है, फार्म में दी गई बातों को प्रमाणित करने के बाद उसकी दूसरी प्रतिलिपि रिजर्व बैंक में भेज देता है। तीसरी प्रतिलिपि उनी के पास रहती है। विदेशी खरीददार से घन वृत्त करके तथा निर्यातकर्ता के लेख में जमा करके अविहृत डीनर फार्म की तीसरी प्रतिलिपि में इसका उल्लेख कर देता है तथा रिजर्व बैंक को भेज देता है। नियमानुसार कुल निर्यातित माल की कीमत का भुगतान माल को जहाज में लादने के बाद 6 माह के भीतर-भीतर प्राप्त कर लिया जाता है। पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के सम्बन्ध में यह समय केवल तीन माह है। विशेष परिस्थितियों में यह बढ़ाया भी जा सकता है किन्तु इसके लिए निर्यातकर्ता द्वारा रिजर्व बैंक को ऐसे कारण बताने होंगे जो उसके नियन्त्रण से बाहर

हो और यह स्पष्ट किया जाएगा कि बढ़ाए गए समय की सीमा में कुल कीमत वसूल हो सकेगी। ऐसा न करने पर समय नहीं बढ़ाया जाएगा।

आयातों के लिए भुगतान

(Payments for Imports)

भारत में केवल जन्ही वस्तुओं का आयात बिना लाइसेंस के किया जा सकता है जो ओ० जी० एल० (OGL) के अन्तर्गत आती हैं। इनके प्रतिरिक्त प्रत्येक वस्तु के आयात के लिए पहले आयात लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी है। आयात लाइसेंस की हमेशा दो प्रतिलिपियाँ दी जाती हैं। प्रथम प्रतिलिपि Custom Purpose Copy और दूसरी Exchange Control Copy कही जाती है। दूसरी प्रतिलिपि केवल तभी दी जाती है जबकि आयातकर्ता भुगतान करते समय केवल उतना ही विदेशी विनिमय प्राप्त कर सके जितना कि उसके लाइसेंस में दिया हुआ है।

आयातों के भुगतानार्थ विदेशी विनिमय प्राप्त करने के लिए अधिकृत डीलर को प्रार्थना-पत्र दिया जाता है। विदेशी विनिमय के लिए प्रार्थना-पत्र देने के हेतु भार प्रकार के फार्म निर्धारित किए गए हैं।¹ भुगतान जिस मुद्रा में किया जाना है उसी में आधार पर यह निश्चित किया जाएगा कि कौनसा फार्म भरा जाए। आयातकर्ता अधिकृत डीलर से उपयुक्त फार्म प्राप्त करता है। इस फार्म में आयातकर्ता को आयात लाइसेंस सम्बन्धी सूचना, आयातित माल की मात्रा एवं विवरण, उत्पादक देश का नाम तथा भुगतान की जाने वाली मुद्रा का प्रकार आदि लिखना होता है। यह आयात लाइसेंस की विनिमय नियन्त्रण प्रतिलिपि के साथ प्रस्तुत किया जाता है।

विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम के अनुसार आयातित माल का भुगतान उस देश की मुद्रा में ही किया जाएगा जहाँ से माल मंगाया जा रहा है। भुगतान के लिए जो तरीके निर्धारित किए गए हैं केवल उनके अनुसार ही एक व्यापारी अपने आयात का भुगतान करेगा। अनिर्धारित तरीके से भुगतान करने की अनुमति नहीं दी जाती।

आयात नियन्त्रण नियमनों के अधीन जो आयात लाइसेंस जारी किए जाते हैं वे अदेय (Non-Transferable) होते हैं।

भुगतान के तरीके

(How Remittances are made)

भारत में विदेशों को धन जिन विभिन्न तरीकों द्वारा हस्तान्तरित किया जा सकता है, वे ये हैं—

(1) बैंक के द्वारा

(2) बैंक ट्रफ्ट के द्वारा

- (3) डाक स्थानान्तरण द्वारा (Mail Transfer)
- (4) तार स्थानान्तरण द्वारा (Telegraphic Transfer)
- (5) साख्त पत्र द्वारा (Letter of Credit)

रुपए के बदले आयात

(Imports against Rupee Payments)

भारत सरकार ने कुछ देशों के साथ रुपए के बदले आयात करने के सम्झौते किए हैं। इनमें पूर्वी यारोप के देश जैसे—बल्गारिया, जर्मनी गणराज्य, हंगरी, रूमानिया, साबियत तथा पोलैण्ड आदि प्रमुख हैं। इन सम्झौतों के द्वारा यह सुविधा दी गई है कि आयातित माल का जमाना रुपए में ही किया जा सके। इन आयातों में विदेशी विनिमय का कोई खर्च नहीं आया। ऐसा जमाना है किन्तु यह सच नहीं है क्योंकि आयातों के बदले जो रुपए विदेशों में गए उनके द्वारा सम्बन्धित देश भारतीय माल या सेवा खरीदना और इस प्रकार भारत उस विदेशी विनिमय में वचन रह जाएगा जो अन्यथा उस प्राप्त होता। रुपए में जुगनान करने वाले सत-दना में भी रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त करनी होती है।

(घ) अवमूल्यन (The Devaluation)

अवमूल्यन का अर्थ

अवमूल्यन का अर्थ देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम करने से है। जब एक देश की मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया जाता तो उसके बदले में अब विदेशी मुद्राएँ कम प्राप्त हान लगती है। मि० पॉल ऐन्जिग (Paul Enzig) के अनुसार “अवमूल्यन का अर्थ मुद्राओं की अविकृत तुल्यताओं में कमी करना है।”¹ अवमूल्यन में यह जरूरी नहीं होता कि मुद्रा के बाह्य मूल्य कम होने के साथ-साथ वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में उसका आन्तरिक मूल्य भी कम हो जाएगा। जून, 1966 में भारत सरकार ने जब रुपए का अवमूल्यन किया तो अनेक मनोरंजक बातें समाचार पत्रों में पढ़ने को मिली। जब ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुना गया कि रुपए की कीमत 36 5 प्रतिशत कम हो गई है तो अनेक ग्रामीण लोग सौ रुपए के नोट के बदले 64 रुपए लेने को तैयार हो गए। मुद्रा के अवमूल्यन का यह सही अर्थ नहीं था। प्रत्येक देश की मुद्रा का एक आन्तरिक मूल्य होता है और दूसरा बाह्य मूल्य होता है। मुद्रा के आन्तरिक मूल्य से हमारा अर्थ यह है कि एक मुद्रा अपने बदले देश में कितनी सेवाएँ और वस्तुएँ प्रदान कर सकती, मुद्रा के बाह्य मूल्य का अर्थ यह है कि मुद्रा की एक इकाई के बदले कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती। जब एक देश की मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तो उसके आन्तरिक मूल्य में किसी प्रकार की कमी किए बिना ही उसके बाह्य मूल्य को कम कर दिया जाता है। डॉ० शंजुली के कथनानुसार “अवमूल्यन में हमारा अभिप्राय एक देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य कम कर देने से है, आन्तरिक

वही।¹ जब मुद्रा का बाह्य मूल्य कम होता है तो उसका आन्तरिक मूल्य भी प्रायः कम हो जाता है किन्तु यह सम्भावना ही होती है नियम नहीं। असल में अवमूल्यन का अर्थ देश की मुद्रा के आन्तरिक मूल्य का स्थिर रहना है। यदि उसकी कीमत घटें भी तो इतनी नहीं जितनी उसके बाह्य मूल्य की घट रही है।

अवमूल्यन के उद्देश्य

मुद्रा के अवमूल्यन के लिए अनेक कारण उत्तरदायी होते हैं। इनको ही अवमूल्यन का औचित्य माना जा सकता है। जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अवमूल्यन किया जाता है उसमें से कुछ निम्न प्रकार हैं—

1. विदेशी प्रभाव से बचना—जब हमारे देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देते हैं तो उसके परिणामस्वरूप उनका माल एक देश में पहुँचने की प्रेरणा तत्ता माने लगता है इसके परिणामस्वरूप उस देश का निर्यात बाजार दिन जाने का भय रहता है। ऐसी स्थिति में वह देश भी अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करके सुरक्षा प्राप्त करने का प्रयास करता है और तभी वह उन देशों के साथ अपने व्यापार की पूर्ण स्थिति को बनाए रखने में सफल हो सकता है।

2. भुगतान सन्तुलन—बहु वार अवमूल्यन की नीति को भुगतान सन्तुलन की प्रतिकूलता कम करने अथवा दूर करने के लिए भी अपनाया जाता है। जब हमारे देशों की मुद्रा की क्रय शक्ति गिर जाती है अर्थात् वहाँ आन्तरिक मूल्य स्तर गिर जाते हैं तो उन देशों का माल अधिक माना में दूसरे देशों में आने लगता है। इससे दूसरे देशों के उद्योग-धन्ये खतरे में पड़ जाते हैं। कई वार विदेशी में देशी वस्तुओं का राशिपातन करके देशी भुगतान सन्तुलन को अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है अथवा ऐसा करके हमारे देश में किए जाने वाले राशिपातन को रोकने के प्रयास भी किए जा सकते हैं।

जब एक देश यह अनुभव करता है कि उसके विदेशी व्यापार में निरन्तर घाटे की स्थिति रहनी है और स्थित विनिमय दर पर विदेशी श्रम, स्वर्ण आयात एवं अन्य किसी उपाय द्वारा उसे दूर नहीं किया जा सकता तो ऐसी स्थिति में स्वदेशी मुद्रा का अवमूल्यन करके विदेशी विनिमय की दर को कम कर दिया जाता है ताकि घाटे की व्यवस्था को दूर किया जा सके। अवमूल्यन को अपनाने के कारण एक देश की वस्तुएँ हमारे देशों में सस्ती हो जाती हैं और उनके निर्यातों की प्रोत्साहन मिलता है। दूसरी ओर देश में विदेशी वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है इसलिए आयात निम्नताही होते हैं। फलतः भुगतान सन्तुलन में अनुकूलता आने लगती है। अवमूल्यन का मार्ग यद्यपि भुगतान सन्तुलन की स्थापना में महत्त्वपूर्ण योगदान करता है फिर भी इसे बार-बार नहीं अपनाया चाहिए क्योंकि ऐसा करने से विनिमय दर की अस्थिरता के बारे में व्यापारियों एवं सट्टेबाजारों को विश्वास नहीं रहता और वे हमेशा यह आशंका करते रहते हैं कि मूल्य और भी कम हो जाएगा।

अवमूल्यन से लाभ

अवमूल्यन की नीति अर्थ व्यवस्था के दोषों को सुधारने का एक प्रस्थापी साधन है। इस नीति द्वारा जो लाभ प्राप्त होते हैं वे ऐसे ही प्राप्त नहीं होते। ये लाभ केवल उसी समय तक मिलते हैं जब तक धरेलू तथा विदेशी बाजारों में लागत मूल्य संरचनाएँ अवमूल्यन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली नवीन विनिमय क्षमता के अनुसार स्वयं को समायोजित नहीं कर लेती। सामान्यतः यह देखा गया है कि अवमूल्यन के लाभ एक देश को केवल 2-3 वर्ष तक प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार यह एक प्रस्थापी समायोजन है और कुछ समय तक के लिए एक देश को इससे राहत मिलती है। इनके पर अवमूल्यन की नीति को बार-बार नहीं अपनाना चाहिए।

इस नीति की सफलता के लिए कुछ परिस्थितियों का होना आवश्यक है। इनको हम अवमूल्यन की सफलता की शर्तें कह सकते हैं। इनके बिना कोई भी अवमूल्यन से प्राप्त होने वाले लाभों की आशा नहीं कर सकता। इस सम्बन्ध में पहली शर्त यह है कि अवमूल्यन की नीति को अपनाने के बाद सम्बन्धित देश की लागत मूल्य संरचना में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यदि उस देश की कीमतों में वृद्धि हो गई तो जिस सीमा तक वृद्धि हुई है उस सीमा तक अवमूल्यन का प्रभाव लाभदायक नहीं रहेगा। अवमूल्यन की सफलता के लिए दूसरी शर्त यह है कि जिन देशों की मुद्राओं की तुलना में यह अवमूल्यन किया जा रहा है वे इस नीति का समर्थन करें अर्थात् वे प्रशुभक अथवा अन्य किसी उपाय द्वारा इसे प्रभावहीन बनाने की चेष्टा न करें। तीसरे, अवमूल्यन की सफलता बहुत कुछ विदेशी विनिमय से सम्बन्धित माँग और पूर्ति के लोच पर निर्भर करती है। जब लोच कम रहती है तो अवमूल्यन द्वारा भुगतान संतुलन स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने के लिए अवमूल्यन बहुत अधिक मात्रा में करना होगा जो अपने आप में एक धुराई है।

1949 का अवमूल्यन (The Devaluation of 1949)

1949 में पौण्ड का अवमूल्यन किया गया। इसके परिणामस्वरूप भारत ने भी अपने रुपये को उतना ही अवमूल्यित करने का निर्णय लिया ताकि रुपये तथा पौण्ड में समानता बनी रहे। पौण्ड का अवमूल्यन दूसरी अनेक मुद्राओं के अवमूल्यन के बाद प्रचलित किया गया था और इसके परिणामस्वरूप जो परिस्थितियाँ पैदा हुईं उनमें रुपये का अवमूल्यन भी आवश्यक बन गया। उस समय मम्बूँ पौण्ड क्षेत्र में घाटे की स्थिति थी और इसलिए इस स्थिति को विगड़ने में रोकने के लिए ग्रेट-ब्रिटेन के चान्सेलर ऑफ़ एक्सचेजर द्वारा 18 फ़रवरी, 1949 को ब्रिटिश मुद्रा के अवमूल्यन की घोषणा की गई। इस घोषणा का अनुसरण करते हुए भारत ने 20 सितम्बर, 1949 को स्टर्लिंग क्षेत्र के अन्य देशों के साथ अपनी मुद्रा का भी अवमूल्यन कर दिया। भारत द्वारा किए गए अवमूल्यन का अनुपात ब्रिटेन द्वारा किए गए अवमूल्यन के अनुकूल था और इसलिए रुपये का स्टर्लिंग मूल्य पहले जितना ही बना रहा। इस अवमूल्यन का निर्णय स्वयं भारत सरकार द्वारा नहीं लिया गया था। इसे प्रेस अथवा जनता के विचारार्थ

4. भारतीय रुपए का अवमूल्यन इसलिए जरूरी बन गया ताकि पौण्ड पावने का मूल्य बनाए रखा जा सके। अवमूल्यन न किया जाता तो भारतीय वस्तुएं विदेशी प्रतिस्पर्धिता में ठहर नहीं सकती थी।

अवमूल्यन की नीति का समर्थन उक्त कारणों से किया गया, किन्तु फिर भी अनेक लोग अवमूल्यन के विपक्ष में थे और उनके अनुसार अवमूल्यन की नीति आर्थिक कारणों से नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से अपनाई गई थी।

भारत सरकार ने रुपये के अवमूल्यन तथा उसके प्रभावों को व्यापक बनाने के लिए एक आठ सूत्रीय योजना तैयार की। संमद द्वारा यह योजना 5 अक्तूबर, 1949 को घोषित की गई। इसके अन्तर्गत कई बातें बड़ी गई। उदाहरण के लिए भारत द्वारा विदेशी विनिमय का उपयोग कम से कम किया जाएगा, दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र से माल का आयात कम से कम किया जाएगा, दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र को निर्यात किए गए माल पर कर लगाया जाएगा ताकि दोहरी आय प्राप्त की जा सके आदि-आदि। इस योजना को अंगीकार कर यह प्रयास किया गया कि देश की समस्त अर्थ-व्यवस्था को सन्तुलित किया जाए तथा देश को लाभान्वित किया जाए। इसके परिणामों से देश का भुगतान सन्तुलन सुधरे तथा निर्यात बढे। आगे चलकर घाटे की राशि में भी पर्याप्त कमी आई। अवमूल्यन का प्रभाव बहुत कम समय तक रहा, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होते ही भुगतान सन्तुलन में घाटे की व्यवस्था प्रारम्भ हो गई। देश में वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगी। अवमूल्यन के परिणामस्वरूप देश में अनेक बीजे मंहंगी हो गई और इसलिए उनके आयात में होने वाली कमी ने देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाई। शीघ्र ही भारत का भुगतान सन्तुलन पुनः विपरीत दिशा में चला गया। ऐसी स्थिति में अवमूल्यन का विरोध करने वाले अनेक लोगों ने 1951 में यह मांग की कि मुद्रा का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। जब 31 जुलाई, 1955 को पाकिस्तान ने भी अपने रुपये का अवमूल्यन कर दिया तो भारत में रुपये के पुनर्मूल्यन का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण न रहा।

रुपये का अवमूल्यन विचारकों और आलोचकों के भारी विचार-विमर्श का विषय बना रहा। अनेक कारणों से देश का सरकारी धन बढ़ता रहा और उसके बाद बाह्यनीय निर्यात उषी अनुपात में नहीं बढ़ पाए। 1956 में प्रोफेसर बी. आर. सैनाथ ने यह सुझाव प्रस्तुत किया कि रुपये का और भी अवमूल्यन कर दिया जाए। केवल ऐसा करने पर ही भारतीय निर्यात बढ सकता था। द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष मि. सत्यानम ने भी इसी प्रकार का विचार प्रस्तुत किया।

इस अवमूल्यन का अधिक से अधिक लाभ उठाने के कुछ प्रयास किए गए। प्रथम, अवमूल्यन के बाद कीमतों की वृद्धि को रोकने के लिए अवमूल्यित लाभों को विदेशी आयातकर्त्ताओं, घरेलू उत्पादकों और सरकारी कोष के बीच वितरित करने के लिए भारत सरकार ने कुछ निर्यात कर लगाए। कोरिया युद्ध के परिणामस्वरूप तथा शस्त्रीकरण के कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए निर्यात करों को बढ़ाया गया। दूसरे, पाकिस्तान से किए गए आयातों पर जो ओ. जी. एल.

सका। इनके अतिरिक्त ऐसे देशों के माल की जब माँग बढ़ी तो वहाँ के उत्पादकों ने कीमतों में वृद्धि कर दी। इसके साथ ही नरम मुद्रा वाले क्षेत्रों में जब डॉलर क्षेत्र से ऊँची कीमत पर आयात किया जाने लगा तो वहाँ भी उत्पादन लागत में वृद्धि हुई। ऐसी स्थिति में भारत को नरम मुद्रा वाले क्षेत्रों से भी अधिक कीमत पर आयात करना पड़ा।

अबमूल्यन का दूसरा प्रभाव निर्यातों पर पड़ा। मुश्किल सन्तुलन की विपरीत स्थिति को सुधारने के लिए एक तरीका यह अपनाया गया कि निर्यातों को प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए घरेलू उत्पादन के अपने साधन स्रोतों को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की ओर मोड़ना कोई सही करना नहीं था फिर भी अबमूल्यन में उन देशों के लिए निर्यातों को प्रोत्साहित किया, जिनके सम्बन्ध में मुद्रा को अबमूल्यित किया गया था। इस प्रकार अमेरिका और अन्य कठोर मुद्रा वाले क्षेत्रों के लिए भारत के निर्यात प्राथमिक रूप में बढ़े। इसके रूप में निर्यात की आमदनी बढ़ गई। यह वृद्धि कई तथ्यों पर निर्भर थी। इनमें प्रमुख तथ्य यह था कि भारतीय माल की अमेरिकी माँग कितनी लोचनीय है। मैग्नीज और अभ्रक की माँग पहले से ही अधिक थी जिसे सन्तुष्ट करना कठिन जान पड़ रहा था। अतः उसके निर्यात बढ़ाने के लिए उसकी कीमतों को कम करना जरूरी नहीं था। अबमूल्यन द्वारा अमेरिका को भारत की चाय का निर्यात बढ़ाया जा सकता था, फिर भी कुल निर्यात को अन्तर्राष्ट्रीय चाय समझौते के अधीन सीमित कर दिया गया। इस प्रकार सामान्य रूप से अमेरिका के लिए भारत के व्यापार लोच-बिहीन रहे।

अबमूल्यन में जो लाभ प्राप्त हो सकते थे वे भारत में प्रति की लोचहीनता के कारण सीमित हो गए। यहाँ औद्योगिक और कृषि सम्पत्ती उत्पादकों की स्थिति संकटपूर्ण थी। जब देश का उत्पादन बढ़नी हुई माँगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था तो अबमूल्यन में आशान्वित लाभ प्राप्त नहीं किए जा सके। अबमूल्यन की उपयोगिता के हेतु यह जरूरी था कि उत्पादन को घरेलू बाजारों की पूर्ति से निर्यातों की ओर प्रोत्साहित किया जाए। इसके अलावा अबमूल्यन के बाद जूट और सूती कपड़े के उद्योगों के उत्पादन अधिक मूल्यवान बन गए क्योंकि उनमें ऊँची कीमत का आयातित कच्चा माल लगाया जाता था। इस सबके अतिरिक्त अबमूल्यन के लाभ केवल कुछ समय के लिए ही रहे क्योंकि अबमूल्यन न करने वाले देशों ने अपने आयातों पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिए।

इसका अबमूल्यन होने के बाद लगभग 28 देशों ने भी इसी प्रकार का निर्णय लिया और इसलिए उन देशों के लिए भारतीय निर्यात का लाभ शून्य हो गया। उदाहरण के लिए भारतीय चाय का प्रमुख बाजार ग्रेट-ब्रिटेन था और वहाँ उसका मुख्य प्रतिद्वन्द्वी लंका था। जब इन दोनों देशों ने अपनी मुद्रा का अबमूल्यन कर दिया तो भारतीय अबमूल्यन के अच्छे परिणाम प्राप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तम्बाकू और मिमरेटी के क्षेत्रों में आस्ट्रेलिया तथा इंग्लैंड में अच्छी आशाएँ नजर आई क्योंकि वहाँ मुख्य प्रतिद्वन्द्वी केवल संयुक्तराज्य अमेरिका था, किन्तु यहाँ

पोण्ड स्टलिंग की विनिमय दर 13.33 रुपए थी किन्तु अब वह 21 रुपए हो गई। पहले स्वतः की कीमत 5.21 रुपए थी किन्तु अब वह 8.33 हो गई।

भारतीय मुद्रा के इतिहास में अवमूल्यन का यह दूसरा अवसर था। विभिन्न विचारकों, राजनीतिज्ञों एवं अर्थशास्त्रियों ने अवमूल्यन के समर्थन एवं विरोध में अपने विचार प्रकट किए। एक ओर प्रो० वी० एन० शेनैय आदि ने अवमूल्यन का स्वागत करते हुए यह मन प्रकट किया कि अभी भी अवमूल्यन कम है और इसलिए यह अधिक किया जाना चाहिए। दूसरी ओर विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि अवमूल्यन एक गलत कदम था जो हमारी समस्याओं को बढ़ाने का कारण बनेगा।

अवमूल्यन के बारे में यह आरोप लगाया गया कि यह निर्णय विश्व बैंक और अमेरिका के दबाव में आकर लिया गया है। यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने यह सलाह दी कि भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया जाए। इतने पर भी अवमूल्यन का निर्णय भारतीय हितों को ध्यान में रखकर लिया गया। प्रो० सी० एन० वकीन ने अवमूल्यन को एक प्रायश्चित्त कहा। उनके मतानुसार भारत ने घाटे की व्यवस्था और विजूल खर्चों के अपने पुराने पापों का प्रायश्चित्त अवमूल्यन के रूप में किया। उनके मतानुसार सच्चा प्रायश्चित्त यह तभी माना जा सकता था जबकि पुराने पापों को दोहराया न जाए। डॉ० वी० एल० गांगुली के मतानुसार रुपए का अवमूल्यन छिपे रूप में तो पहले ही किया जा चुका था किन्तु अब वह खुले रूप में आ गया। प्रायः सभी अर्थशास्त्रियों का यह मत था कि योजना काल में भारत ने जिन नीतियों का पालन किया है वे यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के स्थान पर निरन्तर कमजोर बनाती गई।

1966 का अवमूल्यन 1949 के अवमूल्यन से कई दृष्टियों से भिन्न था। पहले यह केवल 30.5 प्रतिशत किया गया था किन्तु अब 36.5 प्रतिशत किया गया। दोनों अवसरों पर अवमूल्यन की परिस्थितियाँ भिन्न थी। पहले दूसरे देशों की मुद्राओं के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप यह निर्णय लिया गया किन्तु अब ऐसी बात नहीं थी। प्रथम अवमूल्यन में रुपए की बाजार दर और अधिकृत दर एक कर दी गई थी किन्तु 1966 में अवमूल्यन के बाद भी रुपए की बाजार दर कम रही।

अवमूल्यन के लक्ष्य

(The Objects of Devaluation)

1966 में किया गया अवमूल्यन विभिन्न कारणों का परिणाम था। भारत सरकार ने अवमूल्यन के बाद अपने प्रेम नोट में इसके लिए उत्तरदायी विभिन्न कारणों का उल्लेख किया जो निम्न प्रकार हैं—

(1) विदेशी विनिमय के भार को हल्का करना—पंचवर्षीय योजनाओं में देश के आयातों की वृद्धि की। इस वृद्धि का सामना करने के लिए विदेशी सहायता का सहारा लिया गया किन्तु वह पर्याप्त न रहो और हमारा विदेशी विनिमय कोष खम होता गया। अब और तो औद्योगिक क्षमता बढ़ जाने के कारण अच्छे माल

रोकने तथा रुपए के आन्तरिक मूल्य को कम होने से बचाने के लिए अवमूल्यन जरूरी हो गया।

(5) विदेशी सहायता को आकर्षित करना—अवमूल्यन का एक मुख्य उद्देश्य विदेशी सहायता को अपनी ओर आकर्षित करना था। यह निश्चित नहीं था कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विदेशी सहायता कितनी प्राप्ति हो सकेगी। घतः विनिमय दर को बदल दिया गया। विदेशी मुद्रा की कमी ने उसके दुष्प्रयोग को प्रोत्साहन दिया। निर्यात के विलो का कम मूल्य लगाने और आयात के मूल्यों का अधिक मूल्य दिखाने की व्यवस्था प्रचलित हुई। निर्यातकर्ता एवं आयातकर्ता दोनों ही समान रूप से विदेशी मुद्रा की चोरी में भाग लेने लगे। विदेशी विनिमय की सरकारी दर और काला बाजार की दर में उल्लेखनीय अन्तर आ गया।

(6) विदेशी विनिमय का क्षरण—सरकार यह अनुभव कर रही थी कि विदेशी विनिमय के क्षरण से उसे पर्याप्त हानि हो रही है। विदेशी विनिमय के अप्रत्यक्ष स्रोत पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गए थे। कमीशन, बीमे के प्रीमियम, विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा देशवासियों को रुपए भेजना आदि स्रोत ऐसे थे जिनसे पहले पर्याप्त प्राप्तियाँ होती थीं किन्तु अब ये बहुत थोड़ी रह गईं। विदेशों में स्थित भारतीय जो मुद्रा भेजते थे, उसमें से अधिकांश को विदेशी विनिमय के बैंकों में सम्मिलित नहीं किया जाता था और वे प्रायः बैंकिंग प्रणाली द्वारा नहीं भेजी जाती थी। विनिमय दर को बनाए रखने के लिए कान्तिकारी कदम उठाना परम आवश्यक था और इसीलिए 36.5 प्रतिशत की सीमा तक अवमूल्यन करना जरूरी समझा गया।

तत्कालीन वित्त मंत्री श्री शचीन्द्र बोस ने 5 जून, 1966 को अपने रेडियो भाषण में बताया कि नए उद्योगों की तो बात ही अलग है, हमें स्थित उद्योगों को पूरी शक्ति से काम करने के लिए समर्थ बनाने के हेतु कच्चे माल के आयात का प्रवाह बढ़ाना होगा। इस दिशा में प्रत्येक सम्भव कदम उठाया गया है। इन कार्य के लिए यदि प्रत्यक्ष रूप से करोड़ों पर निर्भर रहा जाए तो इससे हमारे बजट सम्बन्धी माघनों पर असहनीय भार बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि विदेशों से प्रत्यक्ष और छुले रूप में सहायता ली जाए और इसे बहुत समय तक जारी रखा जाए तो यह उस देश पर गलत असर डालेगी जिसे हम निर्यात कर रहे हैं।

अवमूल्यन का प्रमुख उद्देश्य देश की अर्थ-व्यवस्था की हर सम्भव साधन में मुट्ठ बनाना है। भुगतान की समस्या का समाधान करने, देश में रोजगार को बढ़ाने, निर्यात से सम्बन्धित एवं आयात के विकल्प उद्योगों को अधिक प्रोत्साहित करने आदि के उद्देश्य से अवमूल्यन किया गया। अवमूल्यन की सफलता अपने आप में निहित नहीं है। इसकी तुलना एक बड़े आपरेशन से की जानी है जिसका पूरा-पूरा लाभ केवल तभी प्राप्त किया जा सकेगा जबकि मरीज पर्याप्त समय, अनुशासन और त्याग से काम लेगा। अवमूल्यन से मूल्यों के बढ़ने का खतरा रहता है और इसे रोकने का प्रमुख साधन अधिक उत्पादन है। तत्कालीन रक्षा मंत्री, मि० चौहान

के कथनानुसार "प्रचलन स्वयं अधिक उत्पादन की व्यवस्था करेगा, इसके लिए अधिक आयान जोष अन्य कुछ प्रयास भी वांछनीय हैं।" इस सम्बन्ध में श्रीमती गांधी का यह कहना सही था कि प्रचलन एक माधन है यह भाग का उद्देश्य नहीं है। हम कठिन निम्न और अनुशासित प्रयास द्वारा एक नवीन प्रारम्भ करना है जो नए प्रचलन का पूरा लाभ प्रदान करके आत्मनिर्भरता का अर्थ प्रदान करेगा।¹

प्रचलन के अपेक्षित लाभ (The Expected Advantages of Devaluation)

प्रचलन द्वारा यह आशा की गई कि इसमें विभिन्न लाभ प्राप्त होंगे जैसे—

(1) इससे निर्यातों को प्रोत्साहन मिलेगा। पहले सौ डालर का माल निर्यात करने पर केवल 476 रुपये मिलते थे किन्तु अब 750 रुपये प्राप्त हान लगेंगे। इस स्थिति में यह स्वाभाविक था कि निर्यात उद्योगों में अधिक से अधिक निवेश किया जाए। प्रचलन न केवल औद्योगिक माल को प्रोत्साहन देगा बल्कि कृषि निर्यातों को भी प्रभावित करेगा।

(2) प्रचलन के कारण आयात के विकल्पा की भी तीव्र गति से प्रगति होगी। आयातित माल का मूल्य रुपये की दृष्टि से बढ़ जाएगा। इसी स्थिति में व्यापारी उन उद्योगों में निवेश करने की ओर आकर्षित होंगे जो आयातित माल का उत्पादन कर रहे हैं। श्रीमती चौधरी के शब्दों में "निर्यात और आयात बचन-प्रक्रियाओं का लगातार प्रोत्साहन देना हम चौमुखी आत्मनिर्भरता की ओर तीव्र गति से प्रगति बढ़ेगा।"

(3) प्रचलन के बाद की दूरें न केवल आयातों और निर्यातों पर ही लागू होगी बल्कि अदृश्य शक्तियों पर भी लागू होगी। देश में आना वाला धन हर प्रकार से प्रोत्साहित होगा और देश में जाने वाला धन हर प्रकार से निरस्तार्थित होगा। व्यक्तिगत निवेशकर्ता यदि देश में विदेशी विनिमय लाते हैं तो उनका इनके बढ़ते अधिक रुपये प्राप्त होंगे और इस प्रकार उन देशों में तब तक विदेशी निवेश प्रोत्साहित होगा जिनमें हम चाहते हैं। इसी प्रकार भारत विदेशी पदार्थों के लिए आकर्षक बन जाएगा जबकि भारतीयों के लिए विदेश यात्रा महंगी है, इसलिए इस ओर कम आकर्षण हो जाएगा।

(4) रुपये की शक्ति घटने के कारण अनेक गलत व्यवहार और भ्रष्टाचार विरहित हो गए हैं और वे निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। स्वयं वित्तमन्त्री न यह स्वीकार किया कि स्वर्ण तथा अन्य वस्तुओं जैसे घड़ियों, कैमरों तथा ट्रांजिस्टर्स आदि की तस्करी अधिक से अधिक आवृत्ति होती जा रही थी और उसे रोकना कठिन था। यहाँ तक कि बान्सी आयातों में प्राप्त होने वाले लाभ के माध्यम से भी जो धन देश में आया उस पूर्ण तरह गिना नहीं जा सका। यह प्राप्ति की गई कि प्रचलन के बाद की दूरें पर ये समस्त समाज-विरोधी क्रियाएँ पर्याप्त रूप से आकर्षक बन जाएंगी और इसलिए उनका प्रसार रुक जाएगा।

(5) विदेशी विनिमय के कारण मे कमी करके देश के सरकारी विदेशी-विनिमय के भण्डारों को सशक्त बनाया जा सकता था।

(6) अवमूल्यन द्वारा भुगतान सन्तुलन में वांछनीय परिवर्तन किए गए। सरकार द्वारा आशा की गई कि अवमूल्यन द्वारा वह रकम हतोत्साहित होगी जो भारत से विदेशों को जाती है। दूसरी ओर देश में आने वाली विदेशी रकम प्रोत्साहित होगी, इससे भुगतान सन्तुलन पर्याप्त अनुकूल बन जाएगा क्योंकि—(i) विदेशी कंपनियाँ अपने लाभों को स्वदेश भेजने की अपेक्षा भारत में ही लगाना उचित समझेंगी। (ii) भारत में पर्याप्त विदेशी पूँजी आने लगेगी। (iii) भारत में विदेशी यात्रा सस्ती होने के कारण आकर्षक बन जाएगी और भारतीयों के लिए विदेशी यात्रा महंगी होने के कारण अनाकर्षक होगी। विदेशों में स्थित भारतीय घन भी स्वदेश को वापस आने लगेगा।

(7) अवमूल्यन की नीति अपनाकर सरकार की आय बढ़ाने का प्रयास किया गया।

अवमूल्यन की हानियाँ

(The Disadvantages of Devaluation)

अवमूल्यन से विभिन्न हानियाँ होने की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं—

(1) इससे वस्तुओं के मूल्य बढ़ने की आशंका रहती है। इसके विरुद्ध जन-साधारण की रक्षा करना परम आवश्यक बन जाता है। यह जरूरी है कि मूलभूत आवश्यकता की वस्तुओं की कीमत स्थिर रखी जाए। यह सच है कि अवमूल्यन के कारण आयातों की लागत सामान्य रूप से बढ़ जाती है। इनके विरुद्ध तत्कालीन वित्त मंत्री ने यह आश्वासन दिया कि अवमूल्यन द्वारा कुछ मूलभूत वस्तुओं की कीमत को बढ़ने से रोकेंगे। मूल्यों में स्थिरता अन्तिम रूप से केवल अधिक उत्पादन और अधिकतम उत्पादकता द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अवमूल्यन के बाद देश के कृषि-उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए गए।

(2) अवमूल्यन द्वारा यह सनरा भी बढ़ जाता है कि देश पर विदेशी ऋण और उसके व्याज का भार बढ़ जाएगा। नियोजित आर्थिक विकास के लिए भारत ने पर्याप्त ऋण लिया। तीसरी योजना के अन्त तक विदेशी ऋण की मात्रा 2629 करोड़ रुपए हो चुकी थी। यह स्पष्ट था कि अवमूल्यन के बाद ऋणों के भुगतानों का भार रुपए की मात्रा में बढ़ जाएगा। अवमूल्यन ने भारतीय रुपए की विनिमय दरे को विदेशी विनिमय मुद्रा की तुलना में गिरा दिया। ऐसी स्थिति में देश को व्याज का भुगतान करने और ऋण चुकाने के लिए अधिक रुपया देना आवश्यक हो गया। इस स्थिति के उपचार के रूप में यह कहा जाता है कि अवमूल्यन के बाद प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता का मूल्य रुपयों में अधिक होगा।

(3) अवमूल्यन के बाद सरकारी व्यय में पर्याप्त वृद्धि हुई। विदेशी ऋणाबास 1. सरकारी मिशनो पर पहले जो खर्च किया जा रहा था वह अब रुपए के रूप

मन्त्री निरन्तर इस बात से मना कर रहे थे कि वे किसी प्रकार के अवमूल्यन पर विचार कर रहे हैं, फिर भी अवमूल्यन कर दिया गया। इस आरोप के विरुद्ध यह कहा जाता है कि यदि सरकार रुपये से प्रस्तावित बाहरी मूल्य के परिवर्तन से पूर्व ही उसकी घोषणा कर देती है तो इससे अधिक खतरनाक और कुछ भी नहीं रहता। यदि कोई भी मन्त्री अपरिपक्व रूप से इस बात की घोषणा कर देता तो मि. चट्टाण के शब्दों में "हम नष्ट हो सकते थे।"

जहाँ तक अवमूल्यन द्वारा देश के सम्मान को गिराने की बात है उसे भी मि. चट्टाण ने एक गत्तन तक बताया है। उनके कथनानुसार "यह इसी प्रकार है कि कोई एक बीमार व्यक्ति से कहे कि यदि उसने ऑपरेशन कराया तो इससे उसकी बेहज्जती होगी। भारतीय अर्थ-व्यवस्था घड़ी बीमार थी। अब तक जो इलाज किए गए वे प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो रहे थे और इसके लिए शल्य चिकित्सा का सुझाव दिया गया। कोई भी ऑपरेशन बिना तक्रलीक के नहीं हो सकता और ऑपरेशन के बाद पुनः उत्साह प्राप्त करके अपने कार्य में संलग्न होने के लिए मरीज को पर्याप्त समय तक अनुशासन और सावधानी बरतनी होती है।"

अवमूल्यन तत्कालीन परिस्थितियों में आवश्यक था। लन्दन की 'एकनामिस्ट' नामक पत्रिका ने अवमूल्यन को इन्दिरा गांधी का एक साहसपूर्ण कार्य बताया। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने रुपये के अवमूल्यन को अत्यन्त दूरदर्शी नीति सम्बन्धी परिवर्तन बताया। टी. टी. कृष्णामाचारी के मतानुसार अवमूल्यन के अतिरिक्त दूसरा कोई चारा नहीं था। डॉ. डी. आर. गाडगिल के मतानुसार अवमूल्यन विद्यली नीतियों की असफलता का परिणाम था। डॉ. ए. एन. अग्रवाल के मतानुसार रुपये का अवमूल्यन द्रुतगति से विकास के लिए एक गरीब देश द्वारा किए गए नए प्रयोग का प्रारम्भ था। डॉ. पी. एस. लोकरनाथन के मतानुसार सरकार ने अवमूल्यन के पक्ष में जो भी तर्क दिए वे गही नहीं थे। उनका कहना था कि अवमूल्यन के बाद निर्यात नहीं बढ़ेंगे, किन्तु आयातों की कीमत अवश्य बढ़ जाएगी। कीमतें असहनीय स्तर तक पहुँच जाएँगी और भारतीय अर्थ-व्यवस्था उन सब लाभों को प्राप्त नहीं कर सकेगी जिनका उत्तेजित बित्त मन्त्री द्वारा किया गया था।

रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर मि. एच. बी. माधवर का मत था कि यदि योजनाओं की किञ्चलसर्वा को रोकना नहीं गया तो शीघ्र ही पुनः रुपये का अवमूल्यन करना पड़ेगा। मद्रास के उद्योग मन्त्री श्री आर. वेंकटरमन ने बताया कि "अवमूल्यन का निर्यात आर्थिक दृष्टि से विवृत और राजनीतिक दृष्टि से प्रबुद्धिमतापूर्ण था।" रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के तत्कालीन गवर्नर श्री पी. सी. भट्टाचार्य ने भी यह स्वीकार किया कि अवमूल्यन को सभी आर्थिक बुराइयों के लिए रामबाण औपधि नहीं माना जा सकता। निर्दलीय संसद सदस्य डॉ. लक्ष्मीमल सिंघवी ने बताया कि यह इलाज बीमारी से भी बदतर है। कांग्रेसी संसद सदस्य अन्वार हक्कानी का कहना था कि यह मेरे देश के लिए एक काला दिन है। अमेरिका से प्रभावित विश्व बैंक की इच्छाओं के सम्मुख देश ने आत्मसमर्पण कर दिया है। श्री एल. एन. विड़ला ने

- (7) साख नीति का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि निर्यात करने वाले आयात के विकल्प उद्योगों को वित्त की कमी महसूस न हो।
- (8) उद्योगों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राजकोष की ओर से उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए।
- (9) निर्यात योग्य सभी वस्तुओं पर भारी उत्पादन कर लगाए जाएँ।
- (10) विदेशों से पूंजीगत वस्तुओं और धतिगुक्त पुर्जों का आयात कम से कम किया जाए और उन्हें देश में ही बनाया जाए।
- (11) उपयोग के लिए विदेशी साधनों का प्रयोग न किया जाए क्योंकि अवमूल्यन ने विदेशी सहायता और सहयोग को पर्याप्त महंगा बना दिया है।
- (12) आने वाले 12 महीनों में मजदूरी तथा वेतन में किसी प्रकार की वृद्धि न की जाए।
- (13) कार्यालयों और कारखानों में काम के घण्टे अधिक कर दिए जाएँ।

अवमूल्यन के सम्बन्ध में इस मिली-जुली प्रतिक्रिया को देखने के बाद कुछ बातें स्पष्ट हो जाती हैं—(1) अवमूल्यन तत्कालीन परिस्थितियों का परिणाम था, इसे रोकना नहीं जा सकता था, (2) अवमूल्यन से जिन लाभों की आशा की गई वे केवल सभी प्राप्त किए जा सकते थे जब कि पर्याप्त सजगतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाए जाए, (3) अवमूल्यन, समस्याओं का एक समाधान मात्र है। यह अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है, (4) अवमूल्यन के बाद यदि पर्याप्त सावधानी, संयम और मजगता न बरती जाए तो इसका दुष्परिणाम देश को मुग़तना होगा।

अवमूल्यन का आयात-निर्यात पर प्रभाव (Impact of Devaluation on Import-Export)

अवमूल्यन का प्रभाव देश के आयातों और निर्यातों पर उल्लेखनीय रूप में पड़ा। विभिन्न वस्तुओं पर से निर्यात नियन्त्रण हटा दिया गया जबकि दूसरी कुछ वस्तुओं पर निर्यात कर लगा दिए गए। अवमूल्यन से निर्यातों का बढ़ना दो बातों पर निर्भर करता था—(1) विदेशी खरीददारों की हमारी वस्तुओं के प्रति माँग की लोच कितनी है, और (2) हमारे देश में पूर्ति की परिस्थितियाँ कैसी हैं। अवमूल्यन के तुरन्त बाद भारत के निर्यात तेजी से घटे। जून, 1966 में अवमूल्यन के कारण जो अस्त-व्यस्त स्थिति पैदा हुई उसने हमारे निर्यातों को वृत्त कम कर दिया; क्योंकि निर्यात व्यापार से सम्बन्धित विभिन्न फसलों पर अधिकारियों का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं था। बाद में निर्यात व्यापार कुछ बढ़ा। फिर भी वह पिछले वर्ष की तुलना में कम रहा। कुल मिलाकर 1966-67 की अवधि में भारत का निर्यात 1132.4 मिलियन डॉलर था। यह 1965-66 की तुलना में 160 मिलियन डॉलर कम था। इन दोनों वर्षों के निर्यातों को अग्रान्वित तालिका द्वारा वर्णित किया जा सकता है।

बहुधा सावधानी बरती गई। इस उदार नीति के अन्तर्गत सरकार ने 59 ऐसे उद्योगों की सूची प्रकाशित की जिन्हें प्राथमिकता दी गई थी। यह कहा गया कि ये उद्योग अपनी पूरी शक्ति से उत्पादन को बढ़ाने के लिए कच्चा माल, उपकरण और आवश्यक पुर्जें आदि 5 माह तक आयात कर सकते थे। इसके अतिरिक्त अगस्त, 1966 में आयात व निर्यात के मुख्य नियन्त्रक ने 15 नियत उद्योगों के सम्बन्ध में गई आयात नीति की घोषणा की। इन उद्योगों की रक्षा, पुनर्स्थापन, पुनर्वासन, आधुनिकीकरण, विस्तार तथा सुधार के लिए पूंजीगत आयात करने के हेतु विदेशी विनिमय की विशेष व्यवस्था करने का प्रावधान रखा गया। अवमूल्यन के परिणामस्वरूप आयातों की कीमत 57 प्रतिशत बढ़ गई और इसलिए यह डर था कि सम्भवतः आयात हतोत्साहित होंगे। आवश्यक वस्तुओं के आयात पर से सरकार ने आयात कर घटा दिया। आयात के सम्बन्ध में सरकार की उदार नीति होने के कारण आयातों के अधिकारिक बढ़ने की आशाएँ की जाने लगी। व्यापार सन्तुलन की स्थापना के लिए निर्यातों को बढ़ाना पर्याप्त आवश्यक था। यदि निर्यात नहीं बढ़ते तो व्यापार सन्तुलन में घाटे की स्थिति आ जाएगी। जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है उन वस्तुओं का उत्पादन देश में करने के लिए तत्सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन देना भी इसलिए आवश्यक माना गया।



भारतीय विदेश व्यापार में व्यापार निगम की भूमिका (ROLE OF THE STC IN INDIA'S FOREIGN TRADE)

राज्य व्यापार निगम की स्थापना भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत 18 मई सन् 1956 को की गई थी। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक पूर्ण सरकारी संस्थान है। इसकी वर्तमान में अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपये तथा प्रदत्त पूंजी 2 करोड़ रुपये है।

उद्देश्य (Objectives)

व्यापार निगम की स्थापना निम्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई है—

- (1) भारतीय विदेशी व्यापार में पाई जाने वाली त्रुटियों को दूर करके विदेशी व्यापार को बढ़ाना।
- (2) देश के निर्यातों का क्षेत्र विस्तृत करना तथा आवश्यक वस्तुओं का आयात की व्यवस्था करना।
- (3) निर्यातित वस्तुओं के न्यूनतम मूल्य की प्रतिपूर्ति देना तथा उचित मूल्य पर जरूरी वस्तुओं का आयात करना।
- (4) केन्द्रीय सरकार के निर्देशों पर मुख्य स्थिर रखने तथा कुछ वस्तुओं का बकुर-स्टॉक बनाने का कार्य करना।
- (5) चालू बाजारों के विस्तार के साथ-साथ नए बाजारों की खोज करना।

इस प्रकार निगम का मुख्य उद्देश्य निर्यात व्यापार को प्रोत्साहित करके देश के विदेशी व्यापार को अधिक मनुजित बनाना है। निगम निजी व्यापारियों के घनिष्ठ सहयोग से काम करता है और उन्हें वित्तीय तथा समन्वयन सहಾಯता देता है।

भारतीय विदेशी व्यापार में निगम की भूमिका (Role of the STC in India's Foreign Trade)

भारतीय विदेशी व्यापार को बढ़ाने में इन निगम की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं वे अग्रानुसार हैं—

1. पूर्वो यूरोपीय देशों के साथ व्यापार—राज्य व्यापार निगम की महत्वपूर्ण उपलब्धि पूर्वो यूरोप के देशों के साथ विशेष कर समाजवादी देशों के साथ व्यापार में वृद्धि करना रहा है। निगम ने इन बाजारों में न केवल परम्परागत वस्तुओं का ही निर्यात बढ़ाया है वरन् नई मर्दे भी प्रचलित की हैं। वर्ष 1955-56 तक इन देशों के साथ हमारा व्यापार अत्यन्त ही सीमित था, परन्तु 1973-74 तक निर्यात का लगभग $\frac{1}{2}$ भाग इन्हीं देशों को निर्यात किया जाने लगा था। इसी प्रकार आयात का लगभग 20% इन देशों से ही प्राप्त किया जाने लगा है। वर्तमान में इन देशों से जो कुछ भी व्यापार हो रहा है उसका सारा का सारा श्रेय राज्य व्यापार निगम को ही जाता है। वैसे यह असंगत बात है कि इन देशों से किए जाने वाले व्यापार में निगम को एकाधिकार प्राप्त है।

2. निगम के कुल व्यापार में वृद्धि—सन् 1955-57 में राज्य व्यापार निगम ने 58 करोड़ रुपये के निर्यात तथा 3.4 करोड़ रुपये के आयात किए थे जो सन् 1977-78 में बढ़कर 785 करोड़ रुपये के निर्यात तथा 375 करोड़ रुपये के आयात हो गए।

3. निर्यात व्यापार—निगम के निर्यात कार्यक्रमों को पाँच भागों में बाँटा जा सकता है—

(अ) रेल के उपकरण

(ब) इजीनिरी का सामान

(स) रसायन व औषधियाँ

(द) परम्परागत उपभोग की वस्तुएँ जैसे खमड़े के जूते, बिग, तैयार पोशाकें आदि,

(य) मछलियाँ, ताजे फल, फलों का रस आदि।

आज यह निगम के कार्यों का ही परिणाम है कि भारत विकासशील देशों में विशेषकर अरब देशों तथा दक्षिणी एशिया के देशों में विभिन्न वस्तुओं के निर्यात आह्वार प्रग्य देशों से प्रतियोगिता करते हुए ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने में सफल होता जा रहा है।

4. निगम द्वारा आयात—निगम विदेशों से कुछ प्रकार के पूंजीगत सामान, औद्योगिक कच्चा माल और कुछ दुर्लभ वस्तुएँ भी मँगाता है, जो देश की प्रयोज्यवस्था और औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। निगम द्वारा आयात किए जाने वाले पदार्थों में उर्वरक, रुई, इस्पात व औद्योगिक कच्चा माल, कच्चा रेशम, क्लिमें, सोयाबीन का तेल, गन्धक आदि प्रमुख हैं। सीमेन्ट के वितरण का कार्य भी निगम कर चुका है। निगम अल्पकालीन सूचना पर भी कठिन विश्व बाजार परिस्थितियों के बावजूद पूंजीगत सामान, कच्चे मालों एवं दुर्लभ सामग्रियों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर व्यवस्था करने में समर्थ रहा है।

5. सम्पत्ति व्यवस्था—निगम विदेशों में अच्छी ख्याति वाली फर्मों के साथ सम्पत्ति, अदल-बदल तथा समानान्तर व्यवहार भी करता है जिससे निर्यात में वृद्धि

1. निगम की स्थापना निर्यात बढ़ाने एवं नवीन बाजारों की खोज करने के लिए की गई थी, परन्तु निगम इस कार्य को सम्पन्न करते समय व्यापारिक दृष्टिकोण का पालन नहीं कर सका ।

2 निगम उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार तुरन्त ही न्यायोचित मूल्यों पर वांछित किस्म का माल आयात करने में असफल रहा है ।

3 निगम ने कई वस्तुओं का निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय विप्रेषण मूल्यों से कम दरों पर करके विदेशी मुद्रा अर्जन में राष्ट्रीय हितों को उपेक्षा की है ।

4 इस निगम के समानान्तर कोई प्रतियोगी संस्था नहीं होने से इसमें एकाधिकारी व्यवस्था के दोष व्याप्त हैं ।

5 निगम द्वारा निजी निर्यातकों के कोटे में सदा कटौती करने की ही प्रणाली अपनाई गई है जिससे देश के कुल निर्यात व्यापार में अपेक्षाकृत उतनी वृद्धि नहीं हुई जिसनी की होनी चाहिए थी ।

6. निगम के क्षेत्र की स्पष्ट व्याख्या न होने के कारण यह लाभ कर व्यापार को अपने हाथों में लेता रहा है जिससे निजी व्यापार क्षेत्र में इसका हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है और निजी व्यापारियों में यह भय बना हुआ कि किसी दिन निगम निजी व्यापार पर भी अपना आधिपत्य न जमा ले ।

7 निगम ने विश्व बाजार की पूर्ण जानकारी के अभाव में ज्यादातर ऊँचे मूल्यों पर वस्तुओं का आयात किया है जिससे देश की उत्पादन लागतें बढ़ गई हैं ।

8 निगम बाजार की दशाओं से भिन्न मूल्य नीति का पालन करता है तथा उपभोक्ताओं की सुरक्षा तथा उत्पादकों की तकनीकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।

9 सरकार का निगम के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार के कारण यह सही ढंग से प्रगति नहीं कर पाया है ।

भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 1977-78 के अनुसार राज्य-व्यापार निगम के कार्यकलाप

भारत सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय की 1977-78 की रिपोर्ट में समीक्षाधीन वर्ष में राज्य व्यापार निगम के कार्यों का जो लेखा-जोखा दिया गया है, वह इस प्रकार है—

‘भारतीय राज्य व्यापार निगम लि (एस टी. सी.) ने देश के विदेश व्यापार में अपना महत्वपूर्ण योगदान जारी रखा । इसके कार्यकलापों में धुनी हुई मुरघ मत्तों का निर्यात, आयात तथा आन्तरिक व्यापार शामिल है । चालू वर्ष में इसका व्यापार कारोबार अशक्ति सारणी में दिखाया गया है ।’

निगम ने विपणन तकनीकी तथा वित्तीय सहायता उलब्ध करके विशेषतः लघु उद्योग क्षेत्र में, अनेक गैर-परम्परागत उत्पादों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए सप्लाईकर्ताओं के साथ सघों के निर्माण को मजबूत बनाया है। इस स्कीम के अन्तर्गत जो मदे शामिल हैं वे इस प्रकार हैं—सैंघार चमड़ा, चमड़े के उत्पाद, सिले-सिलाए परिधान, पदों के रस, जूते तथा आर्मीसाफ्ट वियर। ये मदे रोजगार बढ़ाने के पहलू से महत्वपूर्ण होने के अलावा उच्च मूल्य वर्धित सासियत भी रखती हैं।

निगम ने कुछ नई मदों का संवर्धन किया है जिनमें पश्चिमी जर्मनी को टोपियों का, चिप्स तथा सूखी खुम्बियों का निर्यात महत्वपूर्ण है। चमड़े के लिए चीन तथा ग्रामोफोन रेकार्डों के लिए सोवियत संघ के नए बाजार ढूँढ़े गए हैं।

कीमत समर्थन कार्य

लाभदान के मामले में अफर स्टॉक नीति तथा प्राकृतिक खंड के मामले में कीमत समर्थन करने से आन्तरिक कीमतों में स्थिरता बनी रही और निगम का कारोबार भी बढ़ा।

आयात

अप्रैल 1977-14 जनवरी, 1978 के दौरान 384.1 करोड़ रुपये मूल्य के आयात हुए जबकि गत वर्ष की इस अवधि में 192 करोड़ रुपये मूल्य के आयात हुए थे। खाद्य तेलों तथा प्रसवारी कागज की बिक्री में वृद्धि होने से कारोबार में यह वृद्धि हुई है। सीधे आयात स्कीम के अन्तर्गत कैरोलैबटम एम. ई. जी को शामिल कर लेने के फलस्वरूप चालू वर्ष में इन मदों की बिक्रियाँ पहले से अधिक हुईं।

खाद्य तेल

चालू वर्ष में निगम का भारी मात्रा में खाद्य तेल आयात करने का कार्यक्रम है ताकि आन्तरिक उत्पादन की अनुपूर्ति की जाए और आन्तरिक कीमत स्तर को भी बनाए रखा जा सके। अब तक निगम ने 6.9 लाख मी. टन आयात करने की सविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें से 4.5 लाख मी. टन का लदान भी हो चुका है। अब तक कुल 4.3 लाख मी. टन की कुल बिक्रियाँ की गई हैं। गत वर्ष की अवधि में 1.8 लाख मी. टन की बिक्रियाँ हुई थी और इस प्रकार आयातित खाद्य तेलों की सप्लाई में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

आयातित वनस्पति तेलों को देश भर के समस्त वनस्पति एकड़ों को किरायाती तथा पूर्व-निर्धारित कीमतों पर वितरित किया जाता है ताकि अन्तिम उत्पाद की कीमतों को बनाए रखा जा सके। निगम सीबी खपत के लिए, राज्य सरकारों के माध्यम से भी खाद्य तेलों की सप्लाई कर रहा है। वनस्पति उद्योग की प्रावश्यकताओं को यथासमय पूरा करने के विचार से निगम ने, भण्डारण की मरम्मत क्षमता को बढ़ाने के अतिरिक्त कई नए वितरण-स्थल भी बनाए हैं। कुल भण्डारण क्षमता वर्ष के आरम्भ में 87,000 मी. टन थी जिसे (14-1-1978 तक) बढ़ाकर 2.21 लाख मी. टन कर दिया गया है और उत्तरी जोन में भण्डारण क्षमता को, जो कि वर्ष के आरम्भ में 5,000 मी. टन थी, बढ़ाकर (14-1-1978 तक) 32,000 मी. टन दिया गया है। इन सभी निगम देश में वनस्पति उद्योग की 75 प्रतिशत

निर्यात और आयात के अन्तर को व्यापार सन्तुलन कहा जाता है। यदि कोई देश आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक करता है तो सन्तुलन उनके अनुकूल माना जाएगा और यदि वह निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक करता है तो सन्तुलन उसके प्रतिकूल कहा जाएगा। आयात और निर्यात केवल दृश्य वस्तुओं के ही नहीं होते किन्तु उन अदृश्य वस्तुओं के भी होते हैं जिन्हें देखा तो नहीं जा सकता लेकिन अनुभव किया जा सकता है तथा जो व्यापार सन्तुलन को प्रभावित करते हैं। आजकल भुगतानों के सन्तुलन का अध्ययन आर्थिक विचारों का मूलभूत विषय बन गया है। एक देश का 'भुगतान सन्तुलन' उस सन्तुलन का परिणाम है जो व्यापार के कारण, बीमाओं से पार बेची गई सेवाओं के कारण तथा लिए गए ऋण के कारण स्थापित किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भुगतान सन्तुलन को प्रभावित करते हुए इसे एक देश के निवासियों और दूसरे देश के निवासियों के बीच स्थित समस्त आर्थिक क्षेत्र-वेतों का एक व्यवस्थित अभिवेल कहा है। एक देश के भुगतान सन्तुलन का मही अनुमान लगाने पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि वर्तमान और भविष्य में उसकी आर्थिक क्रियाएँ क्या रहेंगी, उसकी साल कितनी होगी, वह भुगतान करने की कितनी क्षमता रख सकता है, तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में कितना योगदान कर सकता है।

युद्ध से पूर्व स्वर्ण मापक के अधीन भुगतान सन्तुलन की स्वर्ण की गति और पूंजी या केन्द्रीय बैंक के कार्यों द्वारा मूल्य स्तर में लाए गए परिवर्तनों के माध्यम से समायोजित किया जाता था। आजकल भुगतानों की अन्तर्राष्ट्रीय संरचना उल्लेखनीय रूप से बदल गई है। वर्तमान परिस्थितियों में भुगतान सन्तुलन के समायोजन की सम्पत्ति कम हो गई है और निर्यात और निर्यात को नियंत्रित तथा नियंत्रित करने की आवश्यकता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना भुगतान सन्तुलन के गलत समायोजनों को नहीं रोका जा सकता है।

PRE-WAR BALANCE OF PAYMENTS
(In Crores of Rupees)

Year	Current Account				Capital Account				
	Goods, Mercha- ndise	Services and Interest & Dividends	Gold Other Services	Gold Total	Capital Long term	Capital Short term	Items total	Errors & Ommiss- ions	
1924-25	+ 117.66	- 31.78	- 33.37	- 73.88	- 21.37	- 12.25	- 0.03	- 12.28	+ 33.65
1932-33	- 5.45	- 34.41	- 16.16	+ 65.52	+ 9.48	+ 6.50	- 8.15	- 14.65	+ 5.17
1936-37	+ 56.73	- 32.38	- 18.31	+ 27.84	+ 33.88	-	-	- 33.36	- 0.52
1937-38	- 0.02	- 30.17	- 18.13	+ 16.33	- 31.99	-	-	+ 5.30	+ 26.69
1938-39	+ 7.2	-	- 46.4	+ 23.3	- 15.7	-	-	+ 3.6	- 12.1

में घनिष्ठ रूप से एकरूपता बनाए रखी गई। 1946 में भारत को अपने निर्यातों के बदले 337.5 करोड़ रुपए प्राप्त हुए जबकि खाद्यान्न सहित सौदागिरी की वस्तुओं का आयात कुल 388.7 करोड़ रुपए का हुआ था। 1947 में आयातों पर नियन्त्रण को अग्र रूप में देला कर दिया गया और अग्र भुगतान 534.7 करोड़ रुपए तक बढ़ गए। दूसरी ओर प्राप्तिर्था भी बढ़ कर 453.7 करोड़ रुपए तक पहुँच गई। इसलिए व्यापार सन्तुलन में कोई गम्भीर हानि नहीं हुई। देश के विभाजन के कारण और आयात नियन्त्रणों को पुनः लागू करने के कारण 1946 के उत्तरार्द्ध में व्यापारिक वस्तुओं के आयात का मूल्य 493.5 करोड़ रुपए हो गया। इस समय की प्राप्तिर्था और भुगतानों के बीच एकरूपता इसलिए प्राप्त हो सकी क्योंकि आयात नियन्त्रण नीति में परिवर्तन ला दिए गए थे और 1946 से 1948 के मध्य तक व्यापार शर्तों में सुधार हो गया था। व्यापार शर्तों में सुधार से यह स्पष्ट होता है कि इस काल में व्यापार की मात्रा में कोई उत्प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं हुआ। 1948 तक भारत व्यक्तिगत लेख में अनुकूल सन्तुलन रखता था।

इस काल में गैर-औद्योगिक स्वर्ण के आवागमन ने अत्यन्त महत्वहीन भाग लिया। चालू खाते में शुद्ध स्थिति का निर्धारण सेवा की मदों द्वारा किया गया। 1946 में भारत ने ग्रेट ब्रिटेन से भुगतान प्राप्त किए और इसलिए उसका सन्तुलन अनुकूल बना रहा। 1947 में स्थिति में परिवर्तन आया।

चालू खाते में घाटा कोई बहुत अधिक नहीं था। 1946 में यह केवल 29 करोड़ था। 1947 में पूँजीगत खाते में लगभग 5 करोड़ रुपए का घाटा था, किन्तु इन आँकड़ों की पूरी सावधानी के साथ देखा जाना चाहिए क्योंकि अविशेष पूर्णियाँ गलतियों में पूर्ण हैं। पूँजीगत खाते यह प्रदर्शित करते हैं कि चालू खाते की घाटे की अर्थ-व्यवस्था किस प्रकार की है। बैंक व्यवस्था की विदेशी सम्पत्ति 1946 में 56.9 करोड़ रुपए थी। 1947 में 107.5 करोड़ रुपए और 1948 में 327.0 करोड़ रुपए हो गई। 1948 में 1947 की अपेक्षा व्यक्तिगत सम्पत्ति का प्रवाह अधिक था किन्तु इस खाने में 1948 में शुद्ध भुगतान पर्याप्त कम था।

1948 के उत्तरार्द्ध के दौरान उदार आयात नीति और निर्यातों के मूल्य घटने से स्थिति बिगड़ने लगी। यह प्रक्रिया जून, 1949 तक चलती रही। सरकार द्वारा लिए गए आयातों के उच्च स्तर ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। 1948 के तृतीय चतुर्थांश में व्यापार शर्तें कुछ और खराब हुईं।

मई, 1949 में नई आयात नीति को अपनाने पर आयातों की दर कम होने के कारण भुगतानों का अन्तर कम होने लगा। 1949 में रुपए का अवमूल्यन होने के बाद भुगतानों में सुधार की स्थिति आई। जुलाई, 1948 से जून 1949 तक 236.7 करोड़ रुपया ऐसा रहा जिसे विनियोजित नहीं किया गया। जुलाई 1949 से जून 1950 तक ऐसे रुपए की मात्रा केवल 3.2 करोड़ थी। पीण्ड सैन के साथ भारत के भुगतान सन्तुलन की स्थिति पुनः सन्तुलन की ओर जा रही थी। चालू खाते में अक्टूबर, 1948 से सितम्बर 1949 तक 248.8 करोड़ रुपए का घाटा था।

पौण्ड क्षेत्र में भारत का भुगतान सन्तुलन (India's Balance of Payments with Sterling Area)

युद्ध के बाद भारत के व्यापारिक घाटे ने उसके पौण्ड कोष को कम कर दिया। भारत के पौण्ड सन्तुलन के भारी मात्रा में कमी होने के लिए उत्तरदायी दो अन्य कारण भी थे—

(1) जुलाई, 1948 में एक समझौता हुआ जिसके अनुसार भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार के लिए 2480 करोड़ रुपए का भुगतान करना था ताकि पौण्ड पेशनों के भुगतान की वित्तीय व्यवस्था की जा सके और उन सुरक्षात्मक स्टोरो तथा शस्त्र सामग्री को प्राप्त किया जा सके जिसे युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में छोड़ा था।

(2) पाकिस्तान ने इन सन्तुलनों के लिए अपने भाग का जो भुगतान किया वह भारत की मुद्रा से भिन्न था। यह भुगतान 31 मार्च, 1950 तक चलता रहा, पाकिस्तान ने भारतीय नोटों को प्रसारित होने से रोक दिया और उन्हें भारत के रिजर्व बैंक को सौंप दिया गया। ऐसी स्थिति में भारत को पाकिस्तान को पौण्ड स्टर्लिंग सौंपना पड़ा। 1 मार्च, 1949 तक पाकिस्तान स्टेट बैंक को 1770 मिलियन रुपए की कीमत की स्टर्लिंग मुद्रा दी जा चुकी थी।

जैसे जान मथाई के शब्दों में भारत सरकार की आयात नीति का उद्देश्य व्यापार को इस प्रकार विनियमित करना था कि देश की आवश्यकताओं और मांगों के अनुरूप बना रहे और वह अपने चालू खाते में किसी भी विशेष समय में अपने भुगतान सन्तुलन में घाटे की स्थिति न रहे।

कठोर मुद्रा क्षेत्रों में भुगतान सन्तुलन (Balance of Payment in Hard Currency Areas)

उद्योत्तर व्यापार सांख्यिकी की देखने से यह मालूम होता है कि कठोर मुद्रा वाले क्षेत्रों में भारत का व्यापार सन्तुलन उसके विरुद्ध था। इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका, मजेंटाइना, कनाडा, दलिनियम, पुर्तगाल आदि आते हैं। 1948 में भारत में डॉलर का घाटा 200 मिलियन डॉलर से भी आगे बढ़ गया। इसके लिए भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 100 मिलियन डॉलर का कर्ज लेना पड़ा। 60 मिलियन डॉलर के भूत के परिवर्तन योग्य स्टर्लिंग को काम में लिया गया और 20 मिलियन डॉलर दूसरे तरीके से बचाए गए। इसके बाद भी लगभग 46 मिलियन डॉलर की शुद्ध घाटे की स्थिति रही। 1950 में खासानों की कीमत गिर जाने पर भी डॉलर के घाटे को कम से कम 150 मिलियन डॉलर तक घाँका गया।

युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत का प्रायः प्रतिरेक रहता था क्योंकि युद्ध प्रयास के लिए डॉलर को बचाए रखने हेतु अमेरिका से किए जाने वाले आयात में भारी कटौती की गयी। भारत प्रतिरेक को निरन्तर बढ़ाता रहा और उसने साम्राज्य के डॉलर पूल को महत्वपूर्ण योगदान किया। युद्ध के बाद व्यापार की प्रवृत्तियाँ उसके विरुद्ध बन गयीं। कठोर मुद्रा वाले देशों के साथ भारत

विभाजन के बाद के व्यापार से तुलनात्मक अध्ययन करें तो पाएँगे कि दोनों के बीच काफी अन्तर आ गया था। विभाजन के बाद भारत से जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाने लगा उनमें निर्मित माल का भाग अधिक रहा। भारत के आयातों में कच्चे माल का अनुपात बढ़ गया। इस दृष्टि से देखने पर यह कहा जा सकता है कि अब भारत कच्चा माल उत्पादित करने वाले देशों की श्रेणी में नहीं रहा, जैसा कि वह विभाजन से पहले था। यह कहना अधिक सही रहेगा कि विभाजन के बाद भारत फ्रांस की भाँति अर्द्ध-निर्माणा देश बन गया। ग्रहण्य वस्तुओं की दृष्टि से भारत-पाक विभाजन ने भारत को अधिक ग्रामदानी कमाने वाला देश बना दिया। पहले सेवाओं की दृष्टि से भारत के जो बाहरी दायित्व थे वे अब उतने नहीं रहे। भारत की परिवर्तित भौगोलिक स्थिति ने उसकी मौद्रिक स्थिति को प्रभावित किया, यहाँ तक कि उसकी सम्पूर्ण आर्थिक नीतियाँ प्रभावित हुईं। नयी राजनैतिक सीमाओं ने नवीन हितों को जन्म दिया।

भुगतान सन्तुलन के प्रभावक तत्त्व

(Influencing Factors of Balance of Payments)

भारत के भुगतान सन्तुलन पर जिन विभिन्न तत्त्वों ने प्रभाव डाला है उनमें व्यापार शर्तें (Terms of Trade), डॉलर समस्या (Dollar Problem), विदेशी पूँजी (Foreign Capital), सहायक सेवाओं का विकास (Development of Auxiliary Services) तथा पर्यटक यातायात का विकास (Development of Tourist Traffic) आदि महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय हैं—

1. व्यापार शर्तें (Terms of Trade)—युद्ध के बाद भारत के आयात और निर्यात की कीमतों में युद्ध से पूर्व की तुलना में बढ़ रही थी। 1945-46 का निर्यात का मूल्य सूचकांक 1938-39 की तुलना में दो गुने से भी अधिक था। यह प्रक्रिया 1948-49 तक चलती रही जबकि निर्यात मूल्य लगभग चौगुने हो गए। 1949-50 में वस्तु स्थिति में परिवर्तन आया। 1945-46 में व्यापार शर्तें भारत के अनुकूल नहीं थी, किन्तु वे अगले वर्षों में कुछ सुधरीं। इनके फलस्वरूप हमारे व्यापार की स्थिति विकृत होने से रकी। मई, 1948 में व्यापार शर्तें भारत के पक्ष में उच्च स्तर पर पहुँच गयीं। किन्तु उसके बाद के 1949 के प्रारम्भिक महीनों तक विपरीत बनी रही। व्यापार शर्तों के इस विपरीत मोड़ ने तथा आयातों के प्रकार में वृद्धि ने भुगतान सन्तुलन की हमारी कठिनाइयों को बढ़ा दिया। खाद्यान्न, दाल, आटा और कच्चे जूट आदि के क्षेत्र में देश का आयात निरन्तर बढ़ता जा रहा था। मशीनों का आयात भी बढ़ रहा था। देश के निर्यात कम हो रहे थे। उनके आयात तथा आयातों की कीमतें बढ़ रही थी और इस प्रकार कुल मिलाकर भुगतान सन्तुलन देश के विपरीत होता जा रहा था। मूल्य की ओर ध्यान न देते हुए सरकार ने जो आयात किए उनमें स्थिति और भी बिगड़ गयी। अवमूल्यन के बाद कुछ व्यापार शर्तें (Gross Terms of Trade) निरन्तर भारत के प्रतिकूल रही।

का कही और से संयुक्त राज्य अमेरिका के खरीदने का प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरी ओर डॉलर-विहीन अनेक देश अमेरिका से वह माल खरीदना चाहते हैं जिनकी उन्हें बहुत आवश्यकता है।

(iv) अर्द्ध-विकसित उद्योगों का विकास हो रहा है और वे इस विकास को और भी आगे बढ़ाने की धुन में हैं। उन्होंने यूरोप के औद्योगिक देशों को एक चुनौती दी है जो बहुत कुछ इनके निर्यातों पर निर्भर करती है।

डॉलर की समस्या उपर्युक्त कारणों से एक विश्व-व्यापी समस्या थी और इसलिए भारत भी इससे अछूता न रहा। भारत को डॉलर समस्या विश्व के अन्य देशों की डॉलर की समस्या से भिन्न नहीं थी। वस्तु स्थिति के परिणामस्वरूप भारत को डॉलर क्षेत्र के देशों से आयात करना पड़ा। जब तक कठोर मुद्रा के घाटे डॉलर पूल द्वारा पूरे किए जाते रहे तब तक डॉलर की समस्या अधिक गम्भीर नहीं रही, किन्तु जब ग्रेट-ब्रिटेन ने पौण्ड को डॉलर में परिवर्तित करने की सुविधा को सीमित कर दिया तो भारत को कठोर मुद्रा वाले क्षेत्रों से आयातों पर प्रतिबन्ध लगाने पड़े। इस प्रकार कुछ समय के लिए उसे सन्तुलन प्राप्त हो गया किन्तु अन्न के आयात ने उसकी समस्या को बढ़ा दिया क्योंकि इसके लिए डॉलर की आवश्यकता थी। कठोर मुद्रा वाले देशों के साथ घाटे की स्थिति बढ़ी और इसलिए इन देशों के लिए किया जाने वाला निर्यात बढ़ाना परमावश्यक बन गया।

निर्यात को बढ़ाना जितना आवश्यक था उतना सरल नहीं था। विभाजन के बाद कच्चे जूट की पूर्ति अनिश्चित और भूल्यवान बन गई। इसलिए उत्पादन घटा और निर्यातों को हानि हुई। विभाजन के बाद कच्ची रुई आदि में जो निर्यात घटिरके उलब्ध था वह भी समाप्त हो गया। भारतीय माल की जैची कोमत के कारण उसका निर्यात बहुत घट गया।

भारत की डॉलर समस्या ने यहाँ के व्यापार की दिशाओं को मोड़ दिया। 1938-39 में नर्म मुद्रा वाले क्षेत्रों द्वारा हमारे माल का लगभग 71 प्रतिशत निर्यात समाहित कर लिया जाता था किन्तु 1947-48 में यह घटकर 67.5 प्रतिशत रह गया। इसका कारण पौण्ड क्षेत्र में योगदान की गिरावट थी। इसके लिए हमारे निर्यातों को डॉलर बाजार खोजने पड़े। 1938-39 में डॉलर क्षेत्र के इन देशों को हमारा लगभग 12 प्रतिशत निर्यात होता था किन्तु 1947-48 में इसकी मात्रा 27 प्रतिशत हो गई। 1949-50 में इन क्षेत्रों को हमारे निर्यात अक्षमूल्यन के कारण घट गए थे किन्तु फिर भी इनकी कुल मात्रा 20 प्रतिशत बनी रही। इस प्रकार भारत एक दुविधापूर्ण स्थिति में था। एक ओर डॉलर की कमी के कारण वह डॉलर बाजारों की खोज की ओर प्रयत्नशील था और दूसरी ओर मूल्य की प्रेरणाओं ने उससे निर्यातों को नर्म मुद्रा वाले क्षेत्रों में बढ़ाने को प्रेरित किया।

भारत ने पौण्ड क्षेत्र का एक सदस्य होने के नाते डॉलर के आयातों और निर्यातों में उस सामान्य नीति को स्वीकार कर लिया जिस पर सम्पूर्ण पौण्ड क्षेत्र के देश एकमत हैं। सितम्बर, 1950 में राष्ट्र मण्डल के वित्त मन्त्रियों का एक सम्मेलन

की परिस्थितियों ने माल की अधिक पूर्ति को आवश्यक बना दिया ताकि देश में अभाव की समस्या को सुलझाया जा सके। पहले जो पौण्ड की छूट दी गई थी उसे व्यावहारिक रूप से पूरा काम में से लिया गया। आयात के सम्बन्ध में बरती जाने वाली नीति ने स्थिति को गम्भीर बना दिया। इसके कारण इतना अधिक आयात हुआ कि इससे हमारे सारे अन्य खर्चे सन्तुलन समाप्त हो गए और अप्रैल, 1949 तक 42 मिलियन पौण्ड का अधिक खर्च कर लिया गया। यह कहा जाता है कि इस काल में भारत के सामने जो कठिनाइयाँ आईं उनमें से कुछ को सुलझाया जा सकता था, बशर्ते कि हमारी आयात नीति नियन्त्रित और व्यापारपूर्ण ढंग से प्रशासित की जाती।

इतनी मात्रा में आयातों को अधिक समय तक जारी नहीं रखा जा सकता था और इसलिए मई, 1949 तथा अगस्त, 1949 में आयात नीति को कठोर बनाया गया। इसके परिणामस्वरूप आयातों में धीरे-धीरे कमी हुई और पौण्ड सन्तुलनों की दर का गिरना भीमा पड़ गया। रुपये के अवमूल्यन ने निर्यातों को बढ़ा दिया और आयातों को कम किया और इस प्रकार 31 मार्च, 1950 तक पौण्ड सन्तुलन 859 करोड़ रुपये तक घट गए। देश औद्योगिक कच्चे माल और आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं से वंचित रह गया। इसके परिणामस्वरूप प्रमुख उद्योगों में उत्पादन घटा तथा मुद्रा स्फीति की प्रवृत्तियाँ बढ़ने लगी। यह स्थिति भी बहुत समय तक नहीं रहती जा सकती थी और इसलिए आयातों को उदार बनाया गया। अवमूल्यन के कुछ समय बाद निर्यात भी गिर गए। ऐसी स्थिति में पौण्ड सन्तुलन दुबारा घट गया। यह घटाव कोरिया युद्ध के कारण पुनः रोक दिया गया। ऊँचे मूल्यों और अनुपलब्धता के कारण निर्यात बढ़े और आयात घटे। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पौण्ड के क्षेत्र में जो भारी भुगतान सन्तुलन के उतार-चढ़ाव आए उनका मूल कारण आयात और निर्यात के सम्बन्ध में हमारी अनियोजित नीतियाँ थीं।

1948 में पौण्ड सन्तुलन समझौते के स्थान पर एक दीर्घकालीन समझौता किया गया जिसमें 6 वर्ष तक हमारे पौण्ड सन्तुलनों में प्रतिवर्ष 35 मिलियन पौण्ड की राहत प्रदान की गई। यह समय एक जुलाई, 1951 से प्रारम्भ होना था। इस समझौते के प्रावधान पर्याप्त लोचनील थे, इनके अनुसार यदि किसी विशेष वर्ष में कुल मात्रा के किसी भाग को काम में न लाया जा सके तो उसे आगे के काल में मिला दिया जाएगा।

4. विदेशी पूँजी (Foreign Capital)—1947 के मूल्य स्तर को आधार बनाकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत की पूँजीगत व्यय की कम से कम आवश्यकताएँ 250 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष हैं। मूल्यों में वृद्धि होने के कारण यह आवश्यकता निरन्तर बढ़ती रहती है। यदि खाद्य और औद्योगिक कच्चे माल की कमी की ध्यान में रखा जाए तो कृषि का अर्थ पर्याप्त बढ़ जाता है। भारत की कम से कम पूँजीगत आवश्यकताओं और उसकी घरेलू वचतो के बीच एक बड़ा रिक्त स्थान है। ऐसी स्थिति में विदेशी पूँजी की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है। भारत की

विकास योजनाओं को संचालित करने के लिए पूँजीगत माल और प्रसाधनों पर भारी व्यय करना जरूरी था। ये केवल विदेशों से ही खरीदे जा सकते थे और इनका भुगतान विदेशी मुद्रा, विशेषकर डॉलर में किया जाना था। पौण्ड सन्तुलनों को डॉलर में स्वतन्त्रतापूर्वक नहीं बदला जा सकता था और इसलिए विदेशी ऋण एक मात्र उपाय था। तकनीकी ज्ञान, औद्योगिक अनुसंधान तकनीकी विशेषज्ञों का प्रशिक्षण, प्रबंधकों और प्रशासकों के प्रशिक्षण आदि के लिए निश्चय ही विदेशी मुद्रा परमावश्यक थी। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक विकास के लिए 6 वर्षीय ऋणों योजना ने हमारी अनेक औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं को वास्तविकता में परिणत कर दिया। इस योजना के अधीन यह सम्भव था कि देश बिना किसी राजनीतिक सोच विचार के विदेशी सहायता स्वीकार कर सके।

विदेशी पूँजी के विभिन्न स्रोत थे। इन स्रोतों में व्यक्तिगत निवेशकर्ता (Private Investor), अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (The International Bank of Reconstruction and Development) विदेशी सरकारों द्वारा भेंट और ऋण (Gifts and loans from Foreign Governments) आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन सभी स्रोतों ने भारत को विदेशी पूँजी प्रदान करके यहाँ के भुगतान सन्तुलनों को प्रगुलता की ओर प्रेरित किया।

5 सहायक सेवाओं का विकास (Development of Auxiliary Services) — भारत को सहायक सेवाओं (Auxiliary Services) की खातिर भारी भुगतान करना होता था। 1948 के दौरान विदेशी यातायात और बीमा कंपनियों की निर्यात से होने वाली कुल घासदानी (Gross Income) लगभग 19 करोड़ रुपये थी। इसका एक अल्प भाग मात्र की कंपनियों का माना जा सकता है। यह स्थिति भारत के भुगतान सन्तुलन के विपरीत उत्तरदायी विभिन्न कारणों में से एक है। यदि हम क्षत्र में भारतीय उद्यम विकास करें तो भुगतान यदि पूरी तरह समाप्त नहीं हुए तो कम प्रवण हो जाएँगे। इससे भारत का भुगतान सन्तुलन मजबूत बनेगा।

6 पर्यटक यातायात का विकास (Development of Tourist Traffic) — भारतवर्ष प्रतिवर्ष अपने देशवासियों द्वारा की जाने वाली विदेश-यात्राओं पर भारी व्यय करता है, किन्तु यह सब बहुत कुछ एक पक्षीय रूप से किया जाता है। यह प्रयास किया जाना चाहिए कि भारत विदेशी पर्यटकों से कम से कम इतनी विदेशी मुद्रा प्राप्त करे जितनी कि वह विदेशों में अपने देशवासियों पर खर्च करता है।

के लिए जिन लोगों के पास फालतू समय है, उनकी सहाय बहुत अधिक बड़ गई है। हम सब स्थिति का फायदा उठाते हुए ऐसे प्रयाग किए जा सकते हैं जिनसे भारत को विदेशी मुद्रा की अधिक से अधिक प्राप्ति हो सके और उनका भुगतान संतुलन प्रतिकूलता की ओर जा सके। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए वायु यातायात ने शान्तिकारी कार्य किया है।

यह पाया गया है कि जो देश पर्यटन को प्रोत्साहन देते हैं उनकी प्रायः का एक अन्य स्रोत खुल जाता है। इस दृष्टि से हम स्विट्जरलैंड का नाम ले सकते हैं जिसने पर्यटन को राष्ट्रीय उद्योग के रूप में विकसित किया है। पर्यटन यातायात को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त सरकारी, अर्द्ध-सरकारी और निजी संगठन विदेशों में संगठित किए जाते हैं। पर्यटन उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो पर्याप्त विदेशी मुद्रा की आय का कारण बन सकता है किन्तु इसमें अधिक व्यय नहीं करना पड़ता। इस उद्योग के प्रोत्साहन से हम दूसरे उद्योग के लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। व्यापारिक प्रागन्तुकों को प्रोत्साहित करके यह हमारे निर्यात व्यापार को बढ़ाने में सहायता करेगा। पर्यटक जब पर्यटन करने आते हैं तो व्यक्तिगत रूप से खरीदारी करते हैं और उसके बाद भी वे उन्हीं चीजों को खरीदते रहते हैं। यातायात सेवाओं के बढ़ने से देश में रोजगार की स्थिति अच्छी होगी। इसके द्वारा विदेशी पूँजी के निवेश को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस सब के अलावा हम अपने रहन-सहन के तरीकों की जानकारी प्रदान करके अच्छे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विकास में सहायता कर सकते हैं।

भारत पर्यटकों के आकर्षणों की दृष्टि से पर्याप्त धनवान है। यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों का मुकाबला दुनिया में कोई देश नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त प्राचीन स्मृति की चीजें यहाँ महत्व और प्राचीनता की दृष्टि से किसी भी देश से कम नहीं हैं। इतने पर भी यह दुर्भाग्य की बात है कि इस देश की सम्भव क्षमताओं को पूरी तरह से पहचाना नहीं गया। यद्यपि इन दिनों अनेक प्रयास किए गए हैं फिर भी अभी बहुत कुछ करना शेष है।

पंचवर्षीय योजनाएँ और भुगतान संतुलन

(Five Year Plans and Balance of Payments)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत का प्रमुख दायित्व पिछली शताब्दियों के शासन द्वारा निमित्त व्यापक गरीबी और बहुत जनसंख्या की समस्या को मुलभूताना था। एक कृषि प्रधान देश होने हुए भी भारत का कृषि व्यवसाय अभी तक उम पुराने तरीके से सम्पन्न किया जाता था जिसमें बेलगाड़ी और देशी हल अभी तक मुख्य औजार बने हुए थे। विज्ञान के आधुनिक प्रसाधनों ने कृषि को अभी तक छुपा नहीं था किन्तु उसकी माँग देश में निरन्तर बढ़ती जा रही थी। सतार के दूसरे देशों में सम्पन्नता बढ़ रही थी किन्तु भारत में गरीबी अधिक से अधिक होती जा रही थी। पश्चात्त्य देशों तथा भारत के बीच जीवन स्तर की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण दूरी पैदा हुई, उसे दूर करना और देश को न्यूनतम मानवीय जीवन-स्तर प्रदान

करना एक प्रमुख समस्या थी जिसे सुलभाने तथा प्रति प्रति आय बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण काम किया जाना पड़ेगा। जीवन स्तर के उच्च मापदण्डों की प्राप्ति के लिए और भारत में प्रजनन-आधारित मूल्य की रक्षा के लिए नियोजन आवश्यक बन गया।

प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की दृष्टि से किया गया प्रजनन-आधारित नियोजन देश के भुगतान मनुष्यों के घाट की स्थिति में घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित था। इस नियोजन में निराश्रितों अपनी क्षमता के अनुसार उद्योगों की रचना नहीं करना किन्तु पहले उद्योग निर्धारित किए जाने हैं और फिर उनके माधम होने जते हैं। देश के उच्चतर जीवन की प्राप्ति के लिए पराप्त मूल्य की प्राप्ति और उत्पादन साधनों की वृद्धि एकाग्र नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में देश को उरभोक्ता वस्तुओं और पूँजीगत माल दोनों का अपनी मात्रा में आयात करना पड़ेगा है जिसका वह अधिक नियंत्रण द्वारा नष्टान भुगतान नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में देश का भुगतान मनुष्य घाट की स्थिति में चलना है।

निर्यात देश की प्रत्येक वस्तु तथा बाहरी भुगतान की स्थिति को घाटे की स्थिति में ला देता है क्योंकि—

(1) नियोजन को साकार बनाने के लिए जो खर्च किए जाने हैं उनकी आय उसी समय नहीं होनी, और आ आय होनी है उनका अधिकतर भाग आयातों पर खर्च किया जाता है। नए तरीके के विदेशी माल की दर्जनीय भूत आयात की मात्रा को पर्याप्त ऊँचा रखती है।

(2) नियोजनकर्ता देश में उन मशीनों और पूँजीगत माल की खरीददारी के लिए भाग खर्च किया जाना है जिसे देश घरेलू रूप से बनाने की स्थिति में नहीं है।

(3) परम्परागत रूप से जिन वृष्टि वस्तुओं का निर्यात किया जाता था उनका निर्यात अर्थ-व्यवस्था में अधिक से अधिक प्रयोग होने लगता है। यदि नियोजन निवेश स्पष्ट रूप से निर्यात में सम्बन्ध नहीं रखता तो निश्चय ही निर्यात का आकार और मूल्य घट जाएगा अथवा वह बड़े हुए आयातों की मात्रा के साथ मेल नहीं रख पाएगा।

(4) योजना की आयात आवश्यकताओं की ओर प्रकाशन और प्रचार प्रदान किया जाता है तथा योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो सम्माननीय स्थान प्रदान किया जाना है, उसके कारण पर्याप्त आयात आवश्यक बन जाते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि नियोजित अर्थ-व्यवस्था देश के भुगतान सन्तुलन में विभिन्न प्रकार में घाटे की स्थिति उत्पन्न करती है।

प्रथम योजना काल (1951-56)

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में विदेशी विनिमय की स्थिति काफी सुदृढ़ थी और विदेशी विनिमय कोष की मात्रा 127 करोड़ रुपये थी जो तत्कालीन स्थिति में सन्तोषजनक थी। योजना के पहले वर्ष में काफी घाटा हुआ। बाद के चार वर्षों में

भुगतान-अधिशेष की स्थिति रही। इस योजना काल में व्यापार-कोष में यद्यपि 541 करोड़ रुपए का घाटा रहा लेकिन चालू खाते के भुगतान शेष में यह घाटा केवल 42.3 करोड़ रुपए ही था। प्रथम योजना काल में भुगतान-शेष की इस स्थिति के दो मुख्य कारण :—प्रथम उदार नीति के कारण आयातों में भारी वृद्धि और द्वितीय, कोरिया युद्ध के कारण निर्यातों में काफी वृद्धि।

द्वितीय योजना काल (1956-61)

द्वितीय योजना काल में भुगतान-शेष निरन्तर घाटे में रहा अतः देश में विदेशी मुद्रा का सकट उत्पन्न हो गया। इस योजना काल में व्यापार शेष में कुल घाटे की रकम 2,339 करोड़ रुपए तक पहुँच गई और चालू खाते में भुगतान शेष में 1,721.6 करोड़ रुपए का घाटा रहा। इस भारी घाटे के तीन मुख्य कारण थे—प्रथम, विकास कार्यों के लिए आयातों में भारी वृद्धि, द्वितीय, खाद्यान्नों का भारी मात्रा में आयात, एवं तृतीय, निर्यातों में कमी। सुधार के विभिन्न प्रयासों के बाद भी 1960-61 में देश का विदेशी विनिमय-कोष घटकर 303.8 करोड़ रुपए पर आ गया।

तृतीय योजना काल (1961-66)

इस योजना काल में भी भुगतान शेष की स्थिति द्वितीय योजना काल जैसी ही रही। चालू खाते में घाटा 2,567.5 करोड़ रुपए का हुआ। योजना में कुल घाटा 3,075.5 करोड़ रुपए का था जिसका अधिकांश भाग (2,312 करोड़ रुपए) हमारे व्यापार सन्तुलन का घाटा था। घाटे की पूर्ति मुख्यतः बाह्य सहायता से की गई। वार्षिक योजनाएँ (1966-67 से 1968-69)

इन तीन वार्षिक योजनाओं के दौरान भी चालू खाते में भुगतान शेष की प्रतिबल स्थिति बनी रही। 1966-67 में व्यापार घाटा 904.6 करोड़ रुपए हुआ जबकि कुल घाटा 1157.8 करोड़ रुपए का था। इस घाटे की पूर्ति बाह्य सहायता, अन्तर्राष्ट्रीय कोष में प्राप्ति और विदेशी विनिमय कोष से की गई। बाह्य सहायता (1,032 करोड़ रुपए) का ही प्राधान्य रहा। 1966-67 में विदेशी विनिमय कोषों में 36.5 करोड़ रुपए की कमी हुई किन्तु बाद में निर्वाण में सुधार के फल-स्वरूप 1967-68 और 1968-69 में इन कोषों में प्रोमनन 115 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल (1969-74)

यह योजना काल भारी उथल-पुथल का रहा और 1973-74 में विदेशी विनिमय का सकट गम्भीर हो गया। 1974-75 में लगभग 1,000 करोड़ रुपए का व्यापार शेष में घाटा रहा। जनवरी 1974 में विदेशी विनिमय का कुल कोष 776.5 करोड़ रुपए था जो बहुत ही कम था क्योंकि इस राशि से कुछ ही महीनों के आयात की व्यवस्था की जा सकती थी। योजना के पाँच वर्षों के अन्त में चालू खाते का घाटा 2,140 करोड़ रुपये का रहा। वास्तव में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भुगतान सन्तुलन की हमारी स्थिति बहुत ही बिगड़ गई।

कभी नहीं थी। किन्तु यहाँ पर इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाना जरूरी है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति अशतः वृद्धि (विकास) के लिए किए जाने वाले पूंजीनिवेश की कीमत पर हो सकी है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि होने के कारण देश का आयात बिल भी काफी बढ़ गया है जो कि भविष्य में, जब कभी भी समायोजन नीति का अपना ज़रूरी होगा, हमेशा दुःसाध्य सिद्ध होगा।

चूँकि मार्च 1975 की अवधि के बाद के भारत के मुग़तान शेप के ब्योरेवार ग्राफ़ों के इस समय उपलब्ध नहीं हैं इसलिए देश के समग्र मुग़तान शेप की स्थिति के मुख्य पहलुओं की जानकारी, देश की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में हुई घट-बढ़ से, वार्षिक वार्षिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित विदेशी व्यापार के ग्राफ़ों से और प्राप्त हुई विदेशी सहायता की रकमों तथा उन अन्य अन्तिम ग्राफ़ों से मिल सकती है जो सकल आन्तरिक प्रेषणों (विदेशों से भेजी गई रकमों) के सम्बन्ध में उपलब्ध हुए हैं।

भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में सोना, जिसका मूल्य निर्धारित कीमत पर ग्राह्य जाता है, एस. डी. आर. (विशेष निकासी अधिकार) और विदेशी मुद्रा परिमपत्ति शामिल है। चूँकि सोने का प्रयोग चालू लेन-देन के लिए नहीं किया जाता है और एस. डी. आर. में केवल मामूली घट-बढ़ होती है, इसलिए विदेशी मुद्रा के रूप में भारत विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में होने वाली घट-बढ़ से देश के विदेशी कारोबार के निवल परिणाम का पता चलता है।

1974-75 में भारत के मुग़तान शेप पर भारी दबाव पड़ा था और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 484.7 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त कर लेने के बावजूद, इसकी प्रारक्षित निधि में केवल 29.7 करोड़ रुपये की मामूली वृद्धि हो सकी थी। मुग़तान शेप पर यह दबाव 1975-76 के शुरू में भी बना रहा और अगस्त 1975 में 1975 की 'तेल सुविधा' के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 207.1 करोड़ रुपये (2013 लाख एस. डी. आर.) की रकम ले ली। वर्ष की दूसरी छमाही में ये दबाव घटने लगे और 1975-76 के पूरे वर्ष के बाद भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में सोना और एस. डी. आर. को छोड़कर 881.2 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। 1975 की तेल सुविधा के अन्तर्गत ली गई 207.1 करोड़ रुपये की रकम को छोड़कर इन प्रारक्षित निधियों में 674.1 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

1975-76 में मुग़तान शेप की स्थिति में जो विशेष सुधार हुआ, वह विदेशों से भेजी जाने वाली रकमों के आधार पर होने वाली अदृश्य प्राप्तियों में और विदेशी सहायता से हुई निवल प्राप्तियों में पर्याप्त वृद्धि होने के कारण हुआ। इसके अलावा आयात में वृद्धि की दर में भारी कमी हो जाने तथा निर्यात के लगातार बढ़ते रहने के कारण, चाहे वृद्धि की यह दर 1974-75 के दौरान हुई वृद्धि की दर से कम थी। व्यापार घाटा पहले के वर्ष की तुलना में केवल थोड़ा सा अधिक रहा।

मुग्तान रीप के खानों के 'बी'वार ग्रॉन्ड उपलब्ध न होने की स्थिति में विशिष्ट मदे के सम्बन्ध में जिनमें हाल के असें से निवन अन्ध्र प्राप्ति में सुधार हुआ है कोई पक्का अनुमान लगाना वाच्य नहीं है। जो नानागी 1974-75 1975-76 और 1976-77 के दौरान विदेशों में भारत आने वाली सन्तान रकमों के सम्बन्ध में उल्लेख है उमय यह पता चलता है कि प्राप्ति में की इस राशि में लगातार वृद्धि होती रही है। विदेशों में भेजी जाने वाली सभी रकमों, वास्तव में निष्ठा से होने वाली प्राप्ति से भिन्न हैं और इनमें परिवार के गुजारे के लिए भेजी जाने वाली प्रतिवर्षियों की वचनों के रूप में भेजी जाने वाली, प्रवासियों द्वारा अन्तर्गत की जाने वाली तथा मनीषाडर की 'आवक' प्राप्ति में जैसी मदी के अन्तर्गत जो आवक प्रवासियों (इनवाड रेसिडेंट) शब्द की धारणा के अधिक अनुरूप हैं हवाई कम्पनियों तथा नौ परिवहन की प्राप्ति में वीमा प्राप्ति, लाभांश प्राप्ति और पर्यटन प्राप्ति में भी म. का शामिल किया गया है। चूंकि यह मान लेने का कोई आधार नहीं है कि नौ परिवहन तथा हवाई कम्पनियों और पर्यटन से होने वाली प्राप्ति में जैसी अन्ध्र प्राप्ति में एकत्र से कोई वृद्धि हो गई है इसलिए इस नीति पर पहुँचना ही उचित होगा कि यह वृद्धि आवक प्रवासियों में हुए सुधार के कारण हुई है। विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की सहाय में भारी वृद्धि, तस्करी की रोकथाम, देश और विदेश में मोने की कामों के अन्तर्गत में कभी तथा रुपये की क्षमता में सुधार जैसे कई बातें हैं जिनसे प्राप्ति के माध्यम से आने वाली रकमों में वृद्धि हुई है। प्रतिवर्षी भारतीयों की वचनों को भारत में पार्किंग करने के लिए सरकार की ओर से जो विशेष योजनाएँ शुरू की गई थी उनका बाहर से भेजी जाने वाली रकमों में हुई वृद्धि में कोई बड़ा योगदान प्रतीत नहीं होता।

1976-77 में भारत की विदेशी ऋण शोधन की स्थिति में अनुवृत्त प्रवृत्तियों बराबर बनी रही और व्यापार क्षेत्र में बड़ा अधिपेय होने तथा निवल अन्ध्र प्राप्ति में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा प्रारम्भित निधियों में वृद्धि का स्तर 1975-76 की अपेक्षा कहीं अधिक ऊँचा था। यदि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की की गई वापसी अदायगियों की हिसाब में न लिया जाए तो भारत की विदेशी मुद्रा प्रारम्भित निधियों (सोना, तथा एम डी आर को छोड़कर) मार्च 1977 तक अन्त में 28630 करोड़ रुपये की थी अर्थात् मार्च 1976 के अन्त में मौजूद राशि की तुलना में 16741 करोड़ रुपये अधिक थी। भारत ने फरवरी 1974 में प्रतिपूरक वित्त व्यवस्था सुविधा के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ली गई रकम के सम्बन्ध में अग्रस्त, 1976 में 647 करोड़ रुपये की पूरी वापसी अदायगी समय से पहले कर दी और 1974 की तब सुविधा के अन्तर्गत ली गई रकम के सम्बन्ध में पूरी वापसी अदायगी और 1974 में लिए गए ऋण के प्रथम अंश की आंशिक रूप में वापसी अदायगी के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पुन 2381 करोड़ रुपये की मुद्राएँ खरीदी ली। इन वापसी अदायगियों के फलस्वरूप

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रति भारत की पुनः खरीद सम्बन्धी वकालात देनदारियों में काफी कमी हुई है।

ऐसी हालत में जबकि विश्व की प्रमुख मुद्राओं के विनिमय मूल्य में उतार-चढ़ाव बराबर हो रहे थे रुपये की प्रभावी विनिमय दर को अधिक स्थिरता प्रदान करने के उद्देश्य से 25 सितम्बर, 1975 को पीण्ड स्टैबिलि से रुपये का सम्बन्ध विच्छेद कर दिया गया था। तब से रुपये का मूल्य उन देशों की मुद्राओं की दोरूरी के अनुरूप निर्धारित किया जाता है जो व्यापार के क्षेत्र में भारत के मुख्य साझेदार हैं। जबसे यह व्यवस्था लागू की गई है रुपये की विनिमय दर में मध्यवर्ती मुद्रा (इन्टरवेंशन करेंसी) के अनुरूप कई बार परिवर्तन किया गया है, और अब तक के अनुभव से यह पता चलता है कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत काम सुचारु रूप से चला है और इससे विदेशों के साथ हमारे व्यापार में किसी प्रकार की कोई असुविधा पैदा नहीं हुई है।

प्राथमिक समीक्षा 1977-78 के अनुसार विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में घट-बढ़ और समग्र भुगतान शेष की प्रवृत्तियाँ

पिछले दो तीन वर्षों में भारतीय अर्थ-व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही है कि इसके विदेशी भुगतानों की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इस सुधार में जितना योगदान व्यापारिक भास के निर्यात में लगातार होने वाली वृद्धि का रहा है उतना ही महत्व प्राप्तियों में हुई वृद्धि का भी है। इसी के साथ ही, पहले के वर्षों में आयात में जो वृद्धि हुई थी वह भी लाञ्छना तथा उर्वरकों के आयात में जो 1975-76 में देश के कुछ आयात के 37 प्रतिशत भाग के बराबर था, तेजी से कमी हो जाने के कारण बराबर हो गई। निर्यात, आयात तथा महत्व मद्यो के मामले में जो परिवर्तन हुए हैं उनसे देश की विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि में अत्यन्त आकस्मिक सुधार हुए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ हुए लेन-देनों की हिसाब में न लेते हुए भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि (सोना तथा एस. डी. आर. को छोड़ कर जिनमें घट-बढ़ बहुत ही साधारण हुई है) जिसमें 1975-76 में 674.1 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई थी, 1976-77 में 1674.1 करोड़ रुपये और बढ़ गई। जनवरी, 1978 के साथ समाप्त हुए चालू वर्ष के दस महीनों में प्रारक्षित निधि में 1344.9 करोड़ रुपये की और अधिक वृद्धि हुई है। इस वर्ष, 1976-77 की इस अवधि की तुलना में प्रारक्षित निधि में वही ज्यादा वृद्धि हुई।

भारत के भुगतान शेष पर जो दबाव था, वह 1975-76 में काफी कम हो गया। इस दबाव को कम करने का श्रेय विदेशों से प्राप्त होने वाली प्रेषणों के रूप में मिलने वाली महत्व प्राप्तियों की वृद्धि को तथा विदेशी सहायता की प्राप्तियों में होने वाली काफी ज्यादा वृद्धि हुई किन्तु आयात में कुछ और ज्यादा वृद्धि हो जाने से 1222 करोड़ रुपये का व्यापारिक घाटा रहा जो अधिकतम था जबकि इसकी तुलना में 1974-75 में 1190 करोड़ रुपये का व्यापारिक घाटा रहा था।

इस पर भी प्रारक्षित निधि में—वृद्धि हुई क्योंकि निवल चालू अदृश्य प्राप्तियों तथा सहायता के रूप में मिलने वाली राशि में वृद्धि हुई थी और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तेज सुविधा के अन्तर्गत रकम की निकासी की गई थी ।

वर्ष 1976-77 में, भारत की विदेशी मुग्तान की स्थिति में और ज्यादा सुधार हुआ । 69 करोड़ रुपये का सामान्य व्यापारिक अविशेष भी रहा क्योंकि निर्माण बढ कर 5143 करोड रुपये का हो गया और आयात कम होकर 5074 करोड रुपये का रह गया । विदेशों से भेजी जाने वाली राशि में बराबर वृद्धि होनी गई और इस तरह के उपायों अर्थात् तत्कर व्यापार की रोकथाम के लिए किए गए उपायों से तथा विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की सहाय में अत्यधिक वृद्धि हो जाने से तथा समार की कई एक महत्वपूर्ण मुद्राओं की स्थिति में अनिश्चितता आ जान में इस राशि की वृद्धि को भी बल मिला । यद्यपि निवल सहायता की प्राप्तियों में 306 करोड रुपये की कमी हुई तथापि देश की विदेशी मुद्रा प्राग्क्षित निधि में 1976-77 में 1674 करोड रुपये की वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में 1975-76 में 674 करोड रुपये की वृद्धि हुई थी । भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में इस कदर काफी अधिक वृद्धि हो जाने के कारण भारत ने 1976-77 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को 302.8 करोड रुपये की राशि लौटा दी जबकि इसके विपरीत इससे पहले के वर्ष में उसने 207.1 करोड रुपये की रकम उधार ली थी ।

चालू वर्ष के दौरान व्यापारिक माल के लेन-देन तथा अदृश्य मदों की वे सभी प्रवृत्तियाँ, जो कि 1976-77 में दृष्टिगोचर हुई थी, बराबर जारी रही । वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय के द्वारा सक्तनि प्रारम्भिक आँकड़ों के अनुसार, अप्रैल-नवम्बर 1977 में कुल मिलाकर 3472 करोड रुपये के मूल्य का निर्यात हुआ जबकि इसके मुकाबले आयात 3400 करोड रुपये के मूल्य का हुआ और इस प्रकार 72 करोड रुपये का अधिशेष रहा । इससे तथा अदृश्य मदों के क्षेत्र में बराबर चली आ रही अनुकूल प्रवृत्तियों से विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि के भण्डार में और अधिक वृद्धि हुई है । चालू वित्तीय वर्ष में 31 जनवरी, 1978 तक प्रारक्षित निधि में 1345 करोड रुपये की वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में 1976-77 की इसी अवधि में 1201 करोड रुपये की वृद्धि हुई थी । जुलाई, 1977 में देश ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को 248.6 करोड रुपये की राशि की और वापसी अदायगी की और इस प्रकार से कोष के प्रति हमारी वकाया देनदारी कम होकर 207 करोड रुपये रह गई जो कि तेज सुविधा के अन्तर्गत अप्रैल, 1975 में की गई निकासी के कारण थी ।

हमारी अर्थ-व्यवस्था के वैदेशिक पक्ष में लगातार मजबूती बनी रहने के कारण, पूँजी निवेश में वृद्धि करने तथा विकास के क्रियाकलाप को और ज्यादा तीव्रगति से सम्पन्न करने के लिए नीति सम्बन्धी विम्वय खुल गए हैं । 1977-78 की आयात नीति के द्वारा, उत्पादन के आधार को और सुन्द बनाने के लिए आयात

प्रक्रिया को उदार बनाए जाने का सिलसिला और आगे बढ़ाया गया ताकि अर्थ-व्यवस्था की प्रगति की दर और बढ़ सके। बहुत-सी अनिवार्य वस्तुओं के आयात की प्रक्रिया को और उदार बना दिया गया है। वर्तमान आयात नीति को इस प्रकार नई दिशा प्रदान की गई है कि जिससे घरेलू उपयोग तथा निर्यात के दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयोजन से उद्योग घरों की कच्चे मान तथा सघटकों की सभी उचित आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। चमड़े तथा परिधान बनाने की मशीनरी, बहुत-सी औपधियो तथा दवाइयो, रासायनिक पदार्थों, इलेक्ट्रानिक वस्तुओं तथा लोहे और इस्पात की मदों का आयात, धत लुनी सामान्य साइसेंस प्रणाली के अन्तर्गत किया जा सकता है और इस प्रणाली को और ज्यादा व्यापक बना दिया गया है। इसके अलावा, बहुत-सी वस्तुओं, जैसे आयातित मशीनरी के फालतू पुर्जों, ऐसी मशीनरी की कतिपय मदों को जो देश के अन्दर उपलब्ध नहीं है, पोलिस्टर रेजो, घड़ियों के पुर्जों तथा सूखे मेवों को उम्मुक्त साइसेंस प्रणाली के अन्तर्गत रख दिया गया है। इससे अलावा, घरेलू उपलब्धि में वृद्धि करने और इस तरीके से कीमतों पर नियन्त्रण रखने के लिए खाद्य तेलों, कपास तथा मानव निर्मित रेजो जैसी आवश्यक वस्तुओं का आयात उदारता से किए जाने की अनुमति दे दी गई है। देश में पूँजी के निवेश को बढ़ावा देने के प्रयोजन से, सरकार बिजोपकर विद्युत (पावर), उर्वरक तथा सीमेन्ट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपातित सयंत्रों तथा उपकरणों के उपयोग के सिलसिले में और ज्यादा लचीली नीति को अपनाती रही है।

आवश्यक वस्तुओं की घरेलू उपलब्धि में वृद्धि करने तथा पूँजी के निवेश को बढ़ाने के लिए आयात प्रक्रिया को उदार बनाने के प्रयोजन से ये जो तमाम उपाय किए गए हैं, वे आगामी कुछ महीनों में अपना फल दिखलाएंगे। आयात नीति को उदार बनाने का असर तो अभी से मालूम होने लगा है क्योंकि इससे आयात साइसेंसों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। अप्रैल-अक्तूबर, 1977 में 4147 करोड़ रुपये मूल्य के आयात साइसेंस जारी किए गए जबकि इसी तुलना में 1976 की द्नी अवधि में 2149 करोड़ रुपये मूल्य के साइसेंस जारी किए थे। अर्थ-व्यवस्था के वैदेशिक पक्ष की निरन्तर मुश्किलों को देखते हुए, सरकार ने हाल ही में, भारतीयों द्वारा विदेशों की यात्रा करने पर लगी पाबन्दियों को भी ढीला कर दिया है।

देश की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति, कुछ वर्ष पहले की तुलना में इन समय बहुत ज्यादा सुधरी हुई है। कृषि उत्पादन में जिनकी घटबढ़ होनी है उसको ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य के लिए गुंजाइश छोड़ते हुए कि भारत के पास, बहुत से अन्य विकसित देशों की तरह, जरूरत के समय गुजारा करने के लिए प्रारक्षित निधि का कोई दूसरा साधन नहीं है, यह वांछनीय प्रतीत होता है कि देश को प्रचुर मात्रा में विदेशी मुद्रा का भण्डार सदा अपने पास रखना चाहिए। चूँकि यह निधि हमारा एक बहुमूल्य साधन है, इसलिए इसे विकास सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किए जाने की अविलम्ब आवश्यकता है।

स्मरण रह कि भारतीय रुपय का सम्बन्ध 25 मिनम्बर 1975 में पौण्ड स्टर्लिंग में ताल दिया गया था और स्वयं की प्रभावी विनिमय दर का और ज्यादा स्थिरता प्रदान करने के लिए स्वयं को पौण्ड के बजाय मासिक मात्र मुख्य रूप से व्यापार करने वाले देशों की मुद्राओं की टांगी के साथ जोड़ दिया गया था। तथापि पौण्ड स्टर्लिंग का मध्यवर्ती मुद्रा के रूप में काम में लाया जा रहा है। सितम्बर 1975 में 18 3084 स्वयं प्रति पौण्ड की माध्यमिक दर निर्धारित कर दी गई है। तब से मुद्राओं की टांगी के आधार पर कई बार मासिक दर में समायोजन किया गया है। अन्तिम समायोजन पहला नवम्बर 1977 को किया गया जबकि माध्यमिक दर का 15 75 स्वयं प्रति पौण्ड, हिमाचल में निर्धारित किया गया था।

व्यापार शेष

वर्ष 1976-77 में भारत के वैदेशिक व्यापार सम्बन्धी जनदना में एक महत्वपूर्ण माह आया। पट्टानियम खाद्य उर्वरकों तथा औद्योगिक केबल मान की कामता में वृद्धि हो जाने से जा खराबी पैदा हुई उस 1976-77 में रफ दिया गया और व्यापार खाते में 69 करोड़ रुपये का थोड़ा अधिशेष भी प्राप्त हुआ। 1976-77 में निर्यात मूल्य में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह वस्त्र 5143 करोड़ रुपये तक जा पहुँचा लेकिन परिणाम की दृष्टि से यह वृद्धि 18 प्रतिशत रही। निर्यात के क्षेत्र में 27 प्रतिशत की वृद्धि भी उत्तलनीय है विशेषकर जब हम इसका मुकाबला विदेशी निर्यात क्षेत्र में हुई 13 6 प्रतिशत की वृद्धि और औद्योगिक क्षेत्र में हुई 11 प्रतिशत की वृद्धि से करते हैं। दूसरी ओर आयात में 3 6 प्रतिशत की कमी हो गई और आयात 5074 करोड़ रुपये के मूल्य का रहा गया। आयात में यह जो कमी हुई वह परिमाण तथा इकाई कीमत (यूनिट प्राइस) में लगभग समान अनुपात में कमी होने के कारण हुई। पहले के वर्षों में व्यापारिक मूल्य में जो गिरावट आई थी उसका 1976-77 में रोक दिया गया और पहले के वर्षों की तुलना में निर्यात व्यापारिक मूल्य में 7 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय के द्वारा प्रस्तुत किए गए अन्तिम आँकड़ों के अनुसार 1977-78 के पहले आठ महीने के दौरान हुए भारत के आयात तथा निर्यात का मूल्य क्रमशः 3400 करोड़ रुपये तथा 3472 करोड़ रुपये का इनके परिणामस्वरूप 72 करोड़ रुपये का व्यापारिक अधिशेष रहा जबकि इससे पहले के वर्ष के पहले आठ महीने में 98 करोड़ रुपये का व्यापारिक घाटा हुआ था। इस अवधि के दौरान निर्यात में वृद्धि की दर घीघी होकर 9 प्रतिशत रह गई जबकि 1976-77 के पहले आठ महीने के दौरान इसमें 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी किन्तु आयात के मूल्य में 3 6 प्रतिशत की मापदण्ड की वृद्धि हुई थी जबकि इसका मुकाबला विदेशी वर्ष की इसी अवधि में 11 7 प्रतिशत की कमी हुई थी।

भुगतान असन्तुलन की समस्या के निराकरण के उपाय

यद्यपि भुगतान सन्तुलन प्रतिवर्ष सन्तुलित हो जाता है या उसे सन्तुलित कर लिया जाता है, पर इसका यह आशय नहीं होता कि भुगतान सन्तुलन सदैव सन्तुलित रहता है। वास्तव में चालू खाते में (आयात-निर्यात एवं विभिन्न सेवाओं की मदों को शामिल करते हुए) भुगतान सन्तुलन विपदा में हो सकता है। भारतीय अर्थ-व्यवस्था में भुगतान असन्तुलन की समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक है कि—

1. निर्यातों को प्रोत्साहन दिया जाए और निर्यात-संवर्धन के लिए सभी उपायों को अमल में लाया जाए। देश पर जो ऋण-प्रभार है उन्हें चुकाने का वास्तविक समाधान यही है कि हम अपनी आय बढ़ाकर उन प्रभावों से मुक्त हो। इस दिशा में विदेशी सहायता पर निर्भर करना उचित नीति नहीं है क्योंकि एक तो वह अनिश्चित होती है और दूसरे पिछले कुछ वर्षों से उसमें निरन्तर गिरावट आ रही है। निर्यात-संवर्धन के साथ ही आयातों पर समुचित नियन्त्रण लगाना भी आवश्यक है। देश में 1956-57 के बाद से प्रतिवर्द्धात्मक आयात नीति प्रारम्भ की गई, लेकिन उस पर और प्रभावी अमल की आवश्यकता है। यह पुनः लक्ष्य है कि 1976 के प्रारम्भ से हमारे आयात कम हो रहे हैं जबकि निर्यात बढ़ रहे हैं। 1977-78 से आयात नीति को पुनः उदार बनाया गया है, फलस्वरूप हमारा व्यापार शेष पुनः प्रतिकूल हो चला है।

2. भुगतान-असन्तुलन की समस्या को दूर करने का एक अन्य उपाय विनिमय नियन्त्रण है। सरकार आयात-निर्यात नीतियों को कठोरतापूर्वक लागू करने के लिए विदेशी मुद्रा के लेन-देन पर यथोचित नियन्त्रण लगा देती है जिसके फलस्वरूप निर्यातों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा अनिवार्य कार्यों में ही प्रयुक्त की जाती है। भारत सरकार विनिमय नियन्त्रण के उपाय को अपनाती रही है। यह भी आवश्यक है कि देश में विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहित किया जाए इससे विदेशी विनिमय प्राप्त किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने विदेशी पर्यटकों की सुविधाओं का सराहनीय विकास किया है। उत्पादन में वृद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार ने कपास और कच्चे जूट का उत्पादन बढ़ाकर इनका आयात कम करने का प्रयत्न किया है। निर्यात उद्योगों में भी उत्पादन वृद्धि के प्रयत्न विकासमान हैं। उत्पादन वृद्धि के साथ ही उत्पादकता में वृद्धि भी आवश्यक है और पिछले कुछ वर्षों से उत्पादकता-वृद्धि आन्दोलन को बल मिला है।

यदि सरकार इन सभी प्रयत्नों पर कठोरता से अमल करती है तो अगले दशक तक देश अपने भुगतान खाते को बहुत कुछ सन्तुलित कर सकेगा।

प्रश्नावली

(UNIVERSITY QUESTIONS)

अध्याय 1 से 8

- 1 अन्तराष्ट्रीय व्यापार के मूल कारणों को समझाइए। अन्तराष्ट्रीय व्यापार का एक सिद्धान्त का क्या औचित्य है? पूर्ण विवेचना कीजिए। (1978)

Explain the basic reasons for international trade. What is the justification for a separate theory of International Trade? Discuss fully

- 2 अन्तराष्ट्रीय व्यापार को अन्तर्देशीय अथवा अंतःस्थानीय व्यापार का विभिन्न रूप माना जाता है। (बर्टिल ओहलिन) (1978)

इस कथन को समझाइए तथा अन्तराष्ट्रीय व्यापार के अर्थ सिद्धान्त की आवश्यकता प्रतिपादित कीजिए।

'International trade should be regarded as a special case within the general concept of inter regional or perhaps rather inter local trade'

(Bertil Ohlin)

Discuss this statement and explain the need for a separate theory of International Trade

- 3 अन्तर्देशीय एवं अन्तराष्ट्रीय व्यापार में अंतर बताइए। अन्तराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक सिद्धान्त की क्या आवश्यकता है? इस सम्बन्ध में बर्टिल ओहलिन का विचार को ध्यान में रखिए। (1977)

Distinguish between inter regional and international trade. Why is there need for a separate theory of international trade? Give the reasons and views of Bertil Ohlin

- 4 'अन्तराष्ट्रीय व्यापार अन्तर्देशीय व्यापार का नै एक विभिन्न रूप है।' यदि यह सत्य है तो अन्तराष्ट्रीय व्यापार के एक एक सिद्धान्त की क्या आवश्यकता है? व्यापार का शुद्ध सिद्धान्त का क्या अर्थ है? (1976)

International Trade is only a special case of Inter regional Trade. What then is the justification for a separate theory of trade? What is the meaning of 'Pure' theory of trade?

- 5 अन्तराष्ट्रीय व्यापार अन्तर्देशीय व्यापार को ही एक विभिन्न रूप है।' (ओहलिन) विवेचना कीजिए। (1976)

'International Trade is only a special case of Inter-regional Trade' (Ohlin) Discuss

- 6 अन्तराष्ट्रीय व्यापार के क्लासिक सिद्धान्त का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आज के अन्वेषिक देशों के सन्दर्भ में यह सिद्धान्त कहीं तक व्यावहारिक है?

Examine critically the classical theory of International Trade. How far is it applicable to the underdeveloped countries of today?

7 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रमुख विशेषताएँ कौन-सी हैं ? क्या इसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से निम्न मानना सुचित है ?

What are the salient features of inter-regional trade ? Is it justifiable to distinguish it from international trade from an analytical point of view ?

8 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार किन प्रकार क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से भिन्न है ? क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन पर आधारित विशिष्टीकरण द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को हमेशा अधिकतम किया जा सकता है ? अपने उत्तर में उपयुक्त कारण दीजिए ।

In what way is the international trade different from the regional and inter-regional trade ? Would specialization on the basis of international division of labour always lead to the maximization of world trade ? Give reasons for your answer.

9 क्या आज के संदर्भ में भी आन्तरिक व्यापार की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी वस्तुओं का विनिमय मात्र है ? इन दोनों के बीच क्या मूल अन्तर है ?

Is international trade any more a case of barter of goods than domestic trade ? What are the fundamental points of difference between the two ?

10 "चूँकि विभिन्न देश भी निश्चयतः विभिन्न लेखों की भाँति हैं, इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त का एक प्रमुख प्रयोग है ।" इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए ।

"As nations are certainly the most significant of all regions, so the theory of International Trade represents the chief applications of the general theory of inter-regional trade." (B Ohlin) Discuss this statement critically.

11 दो व्यापारकर्ता देशों के मध्य किन स्थितियों में वस्तुओं का मुक्त व्यापार लाभकारी मानते हैं ? प्रवृत्ति रचना है ? व्याख्या कीजिए । (1978)

Under what conditions will free international trade in commodities tend to equalise factor prices in the two trading countries ? Explain.

12 रिकार्डों के तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए । यदि इन मान्यताओं की कि (अ) श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन है, तथा (ब) उत्पादन स्थिर लागत नियम के अन्तर्गत होता है, त्याग दिया जाए तो इस सिद्धान्त में किस प्रकार का संशोधन हो जाएगा ? (1978)

Explain the Ricardian theory of comparative costs. How will the theory be modified when the assumptions of (a) labour as the only factor of production, and (b) the law of constant cost are dropped ?

13 मात्र-प्रचुरता प्रतिलोमता का अर्थ समझाइए । इससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के हेक्शर-ओहलिन सिद्धान्त के परिणामों पर क्या प्रभाव पड़ता है ? विवेचना कीजिए । (1978)

Explain the meaning of factor intensity reversal. How does this affect the conclusion of the Heckscher Ohlin theory of International Trade ? Discuss

14 "हेक्शर-ओहलिन सिद्धान्त से यह सिद्ध होता है कि वस्तुओं की यन्त्रिनीयता साधनों की यन्त्रिनीयता का पूर्णरूप से प्रतिस्थाप है ।" समझाइए । (1976)

"The Heckscher Ohlin theory proves that mobility of goods is a perfect substitute for mobility of factors." Explain

15 "दो देशों में बाजार की दशाएँ जितनी अधिक समान होंगी (विशेषकर आय स्तरों पर) उतनी ही विभी द्रुप उत्पाद में यन्त्र निर्यात प्रक्रिया होने की अधिक सम्भावनाएँ हैं ।" हेक्शर-ओहलिन प्रमेय के संदर्भ में उपर्युक्त वक्तव्य की विवेचना कीजिए । (1975)

"The more similar the market conditions are in the two countries, especially in regard to income levels, the greater the prospect of successful export performance in any given product" Discuss the above statement in the context of Heckscher Ohlin theorem.

- 16 भारत सरकार दर वका द्वारा दो व्यापार करने वाले देशों के बीच व्यापार समुदाय का स्वरूप बनाइए और समझाइए । (1975)
Show and explain the trade equilibrium of two trading countries with Marshall Edgeworth offer curves
- 17 अवसर का प्रतिकारिता अवधारणा व्यापार के अवसर लागत सिद्धान्त की नींव में समझाइए । (1975)
Briefly explain the opportunity cost doctrine of international trade as propounded by Haberler
- 18 रिकार्डो के मुक्तवापस सिद्धान्त का व्याख्या करें व्यापार का स्वरूप । इस सिद्धान्त में क्या प्राप्तिवादी है ? (1976)
Discuss with the example the Comparative Cost Theory of Ricardo ?
What are the major criticisms advanced against it ?
- 19 रिकार्डो के अवसर लागत सिद्धान्त का आधार क्या है ? (1976)
On what assumptions the Heckscher Ohlin theory is based ?
- 20 अवसर लागत सिद्धान्त का व्याख्या निम्न दो में कीजिए—
(अ) समान लागत और (ब) बढ़ती लागत । (1976)
Discuss the Heckscher's theory of Opportunity Cost in case of
(i) Constant Cost and (ii) Increasing Cost
- 21 व्यापार शर्तों का निर्धारण करने वाले कारकों का व्याख्या कीजिए । (1976)
Discuss the factors determining the terms of trade ?
- 22 रिकार्डो और हेक्शर ओहलिन के व्यापार शर्तों में समुदाय अंतर क्या है ? (1976)
What are the basic differences of the Ricardian and the Heckscher Ohlin trade models ?
- 23 व्यापार के दोष की व्याख्या के बिना सिद्धान्त में मुक्तवापस लागतों के अंतर पर ध्यान दिया जाता है । वास्तविक व्यापार के बीच माध्यम वस्तु समुदाय के बिना अनुचित शर्तों पर व्यापार का अवसर है ? (1976)
Trade theory emphasizes differences in comparative costs to explain trade patterns. What other factors need to be taken into account if actual trade patterns are to be fully explained ?
- 24 निम्नलिखित प्रस्तावों का विवेक कीजिए—
(i) मुक्त व्यापार सर्वश्रेष्ठ नीति है
(ii) सीमित व्यापार बिना व्यापार के स्थिति से श्रेष्ठ है । (1976)
Prove the following propositions
(i) Free trade is the best policy
(ii) Restricted Trade is better than no trade
- 25 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी हेक्शर ओहलिन सिद्धान्त का व्याख्यात्मक परीक्षण कीजिए । (1976)
Examine critically the Heckscher Ohlin Theory of International Trade
- 26 व्यापार का शर्तों का क्या अर्थ है ? वह कब प्रतिवृत्त हो जाता है ? इस विचार का स्वरूप कीजिए कि एक गरीब देश के लिए या प्राथमिक उत्पाद का निर्यात करना है व्यापार की शर्तों की प्रतिकारिता और प्रतिवृत्त होना की होता है । (1976)
What is meant by terms of trade ? When do they become unfavourable ?
Examine the view that the term of trade of a poor country exporting primary products generally tend to be unfavourable

- 27 "तुलनात्मक लागतों के अन्तर के कारण ही विदेशी व्यापार का अस्तित्व है तथा इसी के द्वारा विदेशी व्यापार के परिमाण एवं संरचना का निर्धारण होता है।" स्पष्ट कीजिए।
 "Differences in comparative costs account for the existence of foreign trade, and determine its composition and magnitude." Discuss.
- 28 "प्रतिष्ठित सिद्धान्तों में तुलनात्मक लागतों का सिद्धान्त अपेक्षाकृत बेहतर सिद्ध हुआ है।" स्पष्ट कीजिए।
 "The theory of comparative costs has stood up much better than other parts of the old theory." Discuss.
- 29 "तुलनात्मक लागतों के अन्तर विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक व सामाजिक विकास के अन्तर को प्रतिबिम्बित करते हैं, न कि अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण में निहित लाभों को।" स्पष्ट कीजिए।
 "Differences in comparative costs, in international trade, reflects differences in the social and economic development in different areas rather than the innate advantages of international specialization." Discuss.
- 30 यह बताइए कि किन सीमा तक एक अल्पविकसित देश का विदेशी व्यापार तुलनात्मक लागतों के सिद्धान्त के अनुसंग है।
 Consider how far the theory of comparative costs conforms to the conditions of foreign trade of an under-developed country.
- 31 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दशा को स्पष्ट करने हेतु प्रस्तुत हेक्शर-ओह्लिन सिद्धान्त का परीक्षण कीजिए।
 Examine the Heckscher Ohlin theory as an explanation of the pattern of international trade.
- 32 ल्योन्टिफ विरोधाभास से आप क्या समझते हैं ? इसका महत्त्व तथा सीमाएँ बताइए।
 What do you understand by Leontief Paradox ? Explain its importance and limitations. (1978)
- 33 व्यापार की शर्तों से आप क्या समझते हैं ? इनका निर्धारण किस प्रकार होता है ? व्यापार की शर्तों के सूचकांक को व्यापार से लाभों का सूचक मानने की क्या सीमाएँ हैं ? (1978)
 What do you understand by term of trade ? How are they determined ? What are the limitations of using a terms of trade index as an indicator of the gains from trade ?
- 34 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में मार्शल एजवर्थ के अर्पण वक्रों को बिंदुओं के रूप में व्यक्त कीजिए तथा इसे समझाइए। (1976)
 Give the graphical representation of Marshall Edgeworth offer curve in International trade and explain it
- 35 व्यापार सिद्धान्तों की निम्नलिखित रेखीय विधियों का विवरण दीजिए—
 (i) व्यापार उद्योगिता वक्र; (ii) ऑफर वक्र;
 (iii) दो-देश, दो वस्तु, दो साधन मॉडल में व्यापार साम्य का रेखीय चित्रण। (1976)
 Explain the following graphical tools of trade theory :
 (i) Trade indifference curves, (ii) Offer curves,
 (iii) Graphical analysis of trade equilibrium in a two country, two commodity, two factor model.
- 36 हेक्शर-ओह्लिन द्वारा प्रतिपादित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या आनुमानिक प्रमाण द्वारा इन सिद्धान्तों की पुष्टि होती है ? (1977)
 Examine critically the Heckscher Ohlin theory of international trade. Is the theory supported by empirical evidence ?

- 37 रिचार्डों के तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए। यदि इन मान्यताओं को कि (अ) धम उत्पादन का एकमात्र साधन है तथा (ब) उत्पादन स्थिर लागत नियम के अधीन होता है स्थापित किया जाए तो सिद्धान्त में किस प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा ? (1977)
Explain the Ricardian theory of comparative costs. How will the theory be modified when the assumptions of (a) Labour as the only factor of production, and (b) the law of constant cost are dropped ?
- 38 हेकशेयर ओह्लिन द्वारा प्रतिपादित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या आनुभाषिक प्रमाण द्वारा इस सिद्धान्त की पुष्टि होती है ? (1978)
Examine critically the Heckscher Ohlin theory of International trade. Is the theory supported by empirical evidence ?
- 39 बेच वक्र को समझाइए। मार्शल एजवर्थ बेच-वक्रों के द्वारा दो व्यापारकर्ता देशों के बीच व्यापार सन्तुलन को दर्शाइए तथा समझाइए। (1978)
What is an offer curve ? Show and explain the trade equilibrium of two trading countries with the help of Marshall Edgeworth offer curves
- 40 व्यापार की शर्तों का अर्थ समझाइए तथा जट्टा एवं मकल दम्पु विविध व्यापार की शर्तों के मध्य अन्तर बताइए। किस स्थिति में ये दोनों व्यापार की शर्तें एक समान (बराबर) होंगी। उन घटकों की व्याख्या कीजिए जो व्यापार की शर्तों को निर्धारित करते हैं। (1976b)
Explain the meaning of terms of trade and distinguish between net and gross barter terms of trade. In what situation will these two terms of trade be identical ? Discuss those factors which determine the terms of trade
- 41 उन स्थितियों का वर्णन कीजिए एवं समझाइए जिनमें ओह्लिन का साधन मूल्य समानिकरण सिद्धान्त वैध होता है।
State and explain the conditions under which Ohlin's factors price equalization theory is valid
- 42 इस धारणा को स्पष्ट कीजिए कि किसी देश के निर्यात हेतु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध साधन का महत्व उपयोग किया जाता है। इस धारणा की वैधता हेतु बार कोन सी शर्तें प्रस्तुत करेंगे ?
Elucidate the proposition that a country's exports use intensively its abundant factor and lay down the conditions for its validity
- 43 व्यापार की शर्तों से क्या अर्थ समझते हैं ? उन घटकों का विवरण दीजिए जो इसके निर्धारण को प्रभावित करते हैं।
What is meant by terms of trade ? Explain the factors that influence its determination
- 44 व्यापार की शर्तों से सम्बद्ध विभिन्न धारणाओं को स्पष्ट रूप से समझाइए।
Explain clearly the different concepts or terms of trade
- 45 यह बताइए कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ क्यों प्राप्त होते हैं ? इन लाभों को किस प्रकार मापा जाता है ?
Explain how gains of international trade accrue ? How are they measured ?
- 46 रेखाचित्र की सहायता से अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के सिद्धान्त में पूर्ति व माँग की लोच की धारणाओं का महत्त्व बताइए।
Explain with the help of diagrams the significance of the concept of elasticity of supply and demand in the theory of International values.

47 व्यापार की शर्तों के निर्धारण में पूर्ण एवं मौल्य की लोचों का क्या महत्त्व है, विस्तार से समझाइए।
Analyse the significance of supply and demand elasticities in influencing the terms of trade

48 टॉसिग द्वारा निरूपित विशुद्ध एवं मक्ख व्यापार-जनों का अन्तर बताइए। किसी देश की सकल व्यापार जनों में परिवर्तन का आपकी दृष्टि में क्या प्रभाव होगा ?
Explain Taussig's distinction between net and gross terms of trade. What significance would you attach to changes in a nation's gross terms of trade ?

49 व्यापार की जनों से सम्बद्ध विभिन्न धारणाओं का उल्लेख कीजिए। क्या आपकी दृष्टि में व्यापार की शर्तों में निरावट का परिणाम आवश्यक रूप में आर्थिक कल्याण की दृष्टि के रूप में होता है ?
Discuss various concepts of terms of trade. Do you think that deterioration in terms of trade necessarily means loss of economic welfare ?

50 व्यापार अर्द्ध (पार्लो) के विभिन्न सूचकांकों की व्याख्या कीजिए। व्यापार अर्द्ध को निर्धारित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। (1978)
Explain different indices of terms of trade ? Discuss those factors which determine the terms of trade

51 दो व्यापारकर्ता देशों के मध्य किन परिस्थितियों में मुक्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्तर्गत सामानों की कीमतों में समानता की प्रवृत्ति होगी। समझाइए। (1978)
Under what conditions will free International trade in commodities will tend to equalise factor prices in the two trading countries ? Explain.

52 ह्योन्टिफ के विरोधाभास से आप क्या समझते हैं ? इसके महत्त्व व सीमाओं की व्याख्या कीजिए। (1978)
What do you understand by Leontief Paradox ? Explain its importance and limitations

अध्याय 7 से 10

53 किसी वस्तु के आयातों पर सीमा शुल्क के आंशिक संतुलन के अन्तर्गत सीमा शुल्क लगाने वाले देश में उस वस्तु के उपभोग, उत्पादन एवं आयातों पर पड़ने वाले प्रभावों की समझाइए तथा चित्र द्वारा दर्शाइए कि सीमा शुल्क लगाने वाले देश में सीमा शुल्क आय के वितरण तथा समुदाय के आर्थिक कल्याण की किन प्रकार प्रभावित करना है ? समझाइए। (1975)
Explain and show in a diagram the effects of an import tariff on production, consumption and imports of a commodity in the tariff imposing country under partial equilibrium. How does tariff affect the distribution of income and community welfare in the tariff imposing country ?

54 आंशिक संतुलन चित्रों की सहायता से प्रभुत्व व आयात अभ्यन पद्धति के विभिन्न प्रभावों को दिखाइए। सरक्षण उपायों के रूप में इनके सापेक्षिक गुण व अवनुषों की व्याख्या कीजिए।
Show with the help of the partial equilibrium diagrams the various effects of tariff and impact quota system. Discuss their relative merits and demerits as protectionist devices. (1978)

55 आयातों पर प्रभुत्व लगाने वाले देश की दृष्टि से प्रभुत्व के उत्पादन, उपभोग तथा आय के वितरण पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या कीजिए। इस मन्द्य में व्यापार नीति के यन्त्र के रूप में इष्टतम प्रभुत्व का अर्थ समझाइए। (1978)
Discuss the effects of tariffs on production, consumption, distribution of income and terms of trade from the point of view of tariff imposing country. In this context explain the concept of optimum tariff as an instrument of trade policy

56 निम्नलिखित पर प्रत्येक के प्रभाव को समझाइए—

- (i) व्यापार की शर्तें, (ii) आन्तरिक कीमत अनुपात और (iii) मापन आय । (1976)
Explain the effects of a tariff on—

- (i) The terms of trade, (ii) The domestic price ratio and
(iii) Factor earnings

In which of the above mentioned contexts are the Metzler effect and the Stolper Samuelson theorem relevant ?

57 टैरिफ व निम्नलिखितों में निम्नलिखित तर्कों का परीक्षण करन हुए इनके नीति सम्बन्धी निष्कर्ष समझाइए—

- (i) इष्टतम प्रत्युत्पाद का तर्क, (ii) बाह्य वृद्धि का तर्क और
(iii) बाजार की असुविधा का तर्क । (1976)

Examine the following arguments in the theory of tariffs and explain their policy implications

- (i) Optimum tariff argument (ii) External economies argument and
(iii) Market distortions argument

58 निम्नलिखित पर लिखितियाँ लिखिए— (1977)

(क) वास्तविक अथवा प्रभावकारी प्रत्युत्पाद का दर तथा

(ख) अनुकूलनम प्रत्युत्पाद ।

इन दोनों प्रत्युत्पादों का व्यापार पद्धति नीति व विद्युत में क्या महत्व है ? समझाइए ।

Write short notes on the following

- (i) The effective rate of tariff, and
(ii) The optimum tariff

Show the importance of the two concepts in the theory of trade policy ?

59 वस्तुस्थिति में क्या प्रभाव होता है ? कल्याण की दृष्टि से क्या वस्तुस्थिति में वृद्धि प्रत्युत्पाद प्रणाली से उत्तम है ? (1977)

What are the effects of a customs union ? Is a customs union superior to a system of all round tariffs from a welfare point of view ?

60 आर्थिक एकीकरण के रूप में खुली मर्यादा की आवश्यक विवरणों का बनावट । खुली मर्यादा के व्यापार मूल्य तथा व्यापार दिशा-परिवर्तन प्रभावों का समझाइए एवं चित्र द्वारा दर्शाइए । क्या आप इस मत से सहमत हैं कि यदि खुली मर्यादा बनाने का उद्देश्य है अर्थ-व्यवस्थाई परम्पर पुरक न होकर परम्पर प्रतिलिखित है तो खुली मर्यादा बनाने से इन उद्देश्यों का आर्थिक लाभ प्राप्त होगा ? समझाइए । (1978)

Explain the essential features of a customs union as a form of economic integration. Explain and show diagrammatically the trade creation and trade diversions effects of a customs union. Do you agree that the gains from coming a customs union will be greater if the economies of the countries forming a union are competitive rather than complementary ? Explain

61 व्यापार पर अनुदान लगाने की विभिन्न विधियों का अंतर बताना हुए—

(i) आयात प्रत्युत्पाद और निर्यात प्रत्युत्पाद के प्रभावों में अंतर और

(ii) आयात कौटा और आयात प्रत्युत्पाद के प्रभावों में अंतर का विवरण दीजिए । (1976)

Distinguish between different methods of restricting trade and explain

(i) How the effects of an export tariff differ from the effects of an import tariff and

(ii) How the effects of an import quota differ from the effects of an import tariff

62 निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए—

(i) “कस्टम्स संघ बहुमुखी प्रशुल्क स्थिति से श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें प्रशुल्कों की संख्या कम होती है।”

(ii) “यदि संघ बनाने वाले देशों की अर्थ व्यवस्थाएँ परस्पर पूरक हों न कि प्रतिस्पर्धात्मक, तो कस्टम्स संघ के प्रभाव अधिक अनुकूल होंगे।” (1978)

Examine the following statements

(i) “A customs union is superior to a system of all round tariffs because it has fewer tariffs”

(ii) “A customs union would have more favourable effects if the economies of countries forming a union are complementary rather than competitive.”

63 व्यापार शर्तों के विभिन्न निर्देशकों की व्याख्या कीजिए। व्यापार की शर्तों के सिद्धान्त का क्या महत्त्व है ? (1976)

Explain the different indices of terms of trade. What is the importance of the concept of terms of trade ?

64 संरक्षण की रीतियों के रूप में अव्यस्य तथा आयात करों के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। Discuss the relative merits and demerits of quotas and import duties as methods of protection. (1975)

65 व्यापार एवं प्रशुल्क पर हुए सामान्य समझौते के प्रमुख उद्देश्य कौन-कौन से हैं ? इन उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हो चुकी है ? आप वर्तमान स्थिति को सुधारने हेतु कौन-कौन से सुझाव देंगे ?

What are the main objectives of the GATT ? To what extent they have been accomplished ? What practical suggestions can you make for improving the present situation ?

66 किन परिस्थितियों में आप विदेशी व्यापार एवं विनियम के क्षेत्रों में विभेदात्मक नीति को उपयुक्त मानते हैं ? इस सम्बन्ध में व्यापार एवं प्रशुल्क पर हुए सामान्य समझौते में क्या प्रावधान हैं ?

Under what circumstances is it advisable to resort to trade and exchange discriminations ? Explain the provisions of the GATT in this regard.

67 व्यापार एवं प्रशुल्क पर हुए सामान्य समझौते का विश्व के व्यापार को सुगम बनाने एवं इसके विस्तार में क्या योगदान रहा है, विस्तार से समझाइए।

State briefly the contribution of GATT in facilitating and expanding the world trade.

68 व्यापार एवं प्रशुल्क पर हुए सामान्य समझौते के आधारभूत सिद्धान्त क्या हैं ? इन सिद्धान्तों को अल्पविकसित देशों के नियोजित आर्थिक विनाश में कहाँ तक प्रभावित किया है ? व्यापार एवं प्रशुल्क पर हुए सामान्य समझौते पर सश्रुति टिप्पणी लिखिए।

What are the basic principles of GATT ? How have they been affected by the planned economic development of under developed countries ?

69 विकासशील देशों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आप व्यापार एवं प्रशुल्क पर हुए सामान्य समझौते में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे ?

What changes would you recommend in the GATT bearing in mind the problems of developing countries ?

अध्याय 11 एवं 12

- 70 मुक्त व्यापार पर अपनी समीक्षा प्रस्तुत कीजिए। क्या किन परिस्थितियों में सरक्षण को व्यापारित मानते हैं ?
Examine the case for free trade Under what conditions do you justify protection ?
- 71 'सैद्धांतिक दृष्टि से किसी भी देश के लिए मुक्त व्यापार सबसे उपयुक्त नीति हो सकती है, परन्तु व्यवहार में कोई भी देश इसे नहीं अपना सकता।' इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।
* Theoretically free trade is the most suitable policy for any country to adopt but in practice no country can adopt it " Comment on this statement
- 72 सरक्षण के पक्ष में दिए गए प्रमुख तर्कों की संज्ञा स्पष्ट कीजिए।
Explain the validity of the main arguments which are put forward in favour of protection
- 73 उन मान्यताओं की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए जिन पर मुक्त व्यापार के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क आधारित हैं। क्या अपने आर्थिक विकास के लिए अल्पविकसित देश मुक्त व्यापार नीति अपना सकते हैं ?
Examine critically the assumptions on which the arguments in favour of free trade are based. Can the underdeveloped countries follow a policy of free trade for their economic development ?
- 74 'मुक्त व्यापार विकसित देशों के लिए सर्वोत्तम लाभदायक हो सकता है परन्तु यह अल्पविकसित देशों के लिए सदैव घातक सिद्ध होता है।' आप इस कथन से कहीं तक सहमत हैं ?
* Free trade may be in the best interest of developed economies, it is always harmful to underdeveloped economies " How far do you agree with this review ?
- 75 सरक्षण के लिए दिए गए 'शिशु उद्योग' तर्क के औचित्य का परीक्षण कीजिए। इस तर्क को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार चार्टर में किन सीमा तक सम्मिलित किया गया है ?
Examine the 'infant industry argument' as a justification for granting protection To what extent has it been incorporated in the International Trade Charter ?
- 76 आप किसी अल्पविकसित देश को इस दुसूरी नीति को कहीं तक उचित मानते हैं, जिसके अनुसार वह निर्यात के लिए तो मुक्त व्यापार तथा आयात को सीमित करने के लिए सरक्षण नीतियों अपनाना चाहता है ?
How can you justify the double standard of an under developed country when it wants free trade to increase its exports and protection to decrease its imports ?
- 77 एक विकासशील देश के औद्योगिकीकरण के लिए शिशु उद्योग सरक्षण विधान के पक्ष में क्या तर्क हैं ? मूल्यांकन कीजिए। (1976)
Appreciate the infant industry argument for protection as a measure to promote the industrialisation of developing countries
- 78 सरक्षण के किसी वस्तु के उपयोग, उत्पादन और आयात पर जो प्रभाव होते हैं एक रेखाचित्र द्वारा दिखाइए और समझाइए। सरक्षण आय के वितरण को किन प्रकार प्रभावित करता है ? (1976)

Explain and show in a diagram the effect of protection on the consumption, production and imports of a commodity. How does protection affect the distribution of income?

- 79 सरसंरक्षक तटकर क्या है ? वलविकिणित देशों में सरसंरक्ष के दृष में क्या तर्क दिए जा सके हैं ?

What is protective tariff? What are the arguments in favour of protection in under-developed countries?

- 80 यह बताइए कि कुछ देश सरसंरक्ष हेतु तटकरों की अपेक्षा आयात कोटा की मात्रात्मक की पाबन्दी की क्यों प्राथमिकता देते हैं ? क्या आपके मत में आयात-कोटा सर्वत्र लाभप्रद सिद्ध होने हैं ?

Describe why quantitative restrictions by imposing import quotas is preferred by some countries to that of protective tariffs for giving protection to domestic industries. Do you think that in all cases quantitative restrictions by imposing quotas is advantageous?

- 81 क्षेत्रीय व्यापार एव मोक्षिक सहयोग द्वारा एशिया में आर्थिक विकास को प्रगति देने की वास्तविक सम्भावनाओं का विश्लेषण कीजिए। (1976)

Discuss the practical possibility of stepping up the pace of economic development in Asia through regional trade and monetary cooperation

- 82 दक्षिणपूर्व एशिया में अधिक सहयोग के लिए कनी व्यवस्थाओं का विवरण कीजिए। इस क्षेत्र में सामा बाजार बनाने की समस्याओं की व्याख्या कीजिए। (1978)

Describe the different arrangements for economic cooperation in the South East Asia. Discuss the problems of forming a common market in the region.

अध्याय 13 से 15

- 83 भुगतान सन्तुलन का क्या अर्थ है ? भारत के सन्दर्भ में उदाहरण देते हुए उन विधियों का वर्णन कीजिए जिनका विपरीत भुगतान-सन्तुलन को ठीक करने हेतु प्रयोग किया जाता है।

What is meant by balance of payments? Briefly discuss the measures adopted to correct adverse balance of payments with reference to India.

- 84 "भुगतान-सन्तुलन सदैव सन्तुलित रहता है।" यदि ऐसा है तो फिर हम किसी देश के भुगतान-सन्तुलन में अतिरिक्त या घाटे की चर्चा क्यों करते हैं ?

"The balance of payment is always balanced." How then do we talk about a surplus or a deficit in the balance of payments of a country?

- 85 किसी देश के प्रतिकूल भुगतान-सन्तुलन से आप क्या समझते हैं ?

What do you understand by a country's balance of payment deficit?

- 86 भुगतान-सन्तुलन में समायोजन करने पर आय, मूल्य-स्तर एवं रोजगार पर होने वाले प्रभावों की व्याख्या कीजिए।

Analyse the possible income effects, price effects and employment effects associated with the adjustment in the balance of payments.

- 87 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत इस व्यवस्था का विवरण कीजिए जिसके अनुसार भुगतान-सन्तुलन को साम्य स्थिति में बनाए रखा जा सकता है, अथवा साम्य स्थिति को फिर से प्राप्त किया जा सकता है।

Discuss the classical theory of mechanism whereby international balance of payment is maintained in, or restored to, equilibrium position

- 88 किसी देश के भुगतान सन्तुलन में 'चाहू खाता' और 'पूजो खाता' में भेद काजिए। निम्न लिखित का किसी देश के भुगतान सन्तुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है—

- (अ) उस देश में मुद्रा प्रसार
- (ब) मुद्रा अतिमूल्यन
- (ग) विदेशों में सहायता।

Distinguish between Current Account and Capital Account in the Balance of Payment of a country. Discuss the impact of

- (a) Inflation within the country
- (b) Over valuation of currency and
- (c) Foreign aid on the balance of payment of a country

- 89 किसी देश के भुगतान सन्तुलन में असाम्यन्ता के क्या कारण हो सकते हैं? विकासशील देशों के विश्व सन्तुलन में यह अनसम्यन्ता कि प्रकार असाम्यन्ता को कैसे सुधारा जा सकता है? (1976)
What are the causes of disequilibrium in the balance of payments of a country? Discuss the correctives of such disequilibrium with special reference to developing countries

- 90 अवमूल्यन के देश के भुगतान सन्तुलन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? अवमूल्यन के प्रभावों के लोच विश्लेषण एवं अवमूल्यन विश्लेषण के अन्तर को समझाइए। (1978)

What are the effects of devaluation on a country's balance of payments? Distinguish between the elasticity analysis and absorption analysis of the effects of devaluation?

- 91 भुगतान सन्तुलन के घाट की कुछ वैकल्पिक अवस्थाओं पर विचार कीजिए। आपकी दृष्टि में इनमें से कौनसी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सकारण उनका दर्शाए।

Discuss a few alternative concepts of balance of payments deficit. Which of these do you think is the most significant? Give reasons for your answer

- 92 यह बताइए कि किसी व्यापार गुणक के माध्यम से किस प्रकार भुगतान सन्तुलन सिद्धांत को गणनीयता प्रदान की जा सकती है।

How is it possible to dynamize the theory of payments by means of foreign trade multiplier?

- 93 भुगतान असन्तुलन ठीक करने हेतु अवशोषण विधि पर विस्तृत लिखिए।

Write a lucid note on the Absorption Approach to correct a disequilibrium in the balance of payments

- 94 इन कारणों का उत्तमय काजिए जिनसे भुगतान सन्तुलन की कठिनाइयाँ वर्तमान काल में बढ़ने की अपेक्षा अधिक सामान्य बन गई हैं।

How do you account for the fact that balance of payments difficulties have become much more common and a recurrent in the recent years than in the older days

- 95 विदेशी विनिमय दर का निर्धारण क्या होता है? मुक्त विदेशी व्यापार के सन्दर्भ में विदेशी विनिमय दर के निर्धारण की प्रतिक्रिया समझाइए।

How is the rate of foreign exchange determined under conditions of free international trade?

- 96 विविध दर के निर्धारण हेतु प्रस्तुत विभिन्न सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Critically examine the various theories for the determination of the rate of exchange

97 उन घटकों का विवरण दीजिए जिनके कारण विनिमय दर में परिवर्तन होते हैं।

Discuss the various factors that bring about fluctuation in the rate of foreign exchange.

98 दो अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्राओं के बीच विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, उदाहरण सहित समझाइए।

How is the rate of exchange between two inconvertible paper currencies determined?

99 स्वर्णमान के अन्तर्गत विनिमय दर के टुकड़ समता सिद्धान्त को स्पष्टतः समझाइए। विनिमय दर के निर्धारण में स्वर्ण-बिन्दुओं का क्या महत्त्व है?

Explain clearly the mint par theory of exchange rate under gold standard. What is the importance of specie points in the determination of the rate of exchange?

100 क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त तथा भुगतान-सन्तुलन सिद्धान्त का अन्तर बताइए। इस अन्तर का व्यवहार में क्या महत्त्व है?

Distinguish between the theory of purchasing power parity and the theory of balance of payments. What is the significance of this distinction?

101 क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। यह आधुनिक देशों में कहीं तक लागू होता है? (1976)

Critically examine the Purchasing Power Parity Theory. How far is it applicable under modern conditions?

102 अवमूल्यन के प्रमुख उद्देश्य बताइए। किसी देश के व्यापार-सन्तुलन में सुधार हेतु अवमूल्यन किन बातों के अन्तर्गत सामग्री हो सकता है?

Discuss the principal objectives of devaluation. Under what conditions can devaluation bring about an improvement in the balance of trade of a country?

103 अवमूल्यन से निम्नीकृत बातों पर होने वाले प्रभावों की पूर्ण व्याख्या कीजिए—

(क) व्यापार की बाड़ी, (ख) राष्ट्रीय आय तथा (ग) घरेलू मूल्य स्तर।

Explain fully the effects of devaluation on the following:

(a) Balance of Trade, (b) National Income and (c) Domestic price level

104 उन घटकों का विवरण दीजिए जिनके कारण हाल के वर्षों में विश्व की प्रमुख मुद्राओं का अवमूल्यन किया गया है।

List the factors that have motivated the devaluation of the major world currencies in recent years.

105 अवमूल्यन की व्याख्या के अवशोषण दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं? यह दृष्टिकोण लोच दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न है?

What is the absorption approach to the analysis of devaluation and how is it different from the elasticity approach?

106 अवमूल्यन के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। किन देशों में अवमूल्यन का व्यापार सन्तुलन में सुधार ला सकता है? (1977)

Discuss the objectives of devaluation. Under what conditions can devaluation bring about an improvement in balance of trade?

107 किसी देश के भुगतान क्षेत्र में असन्तुलन उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारणों की व्याख्या कीजिए। स्वर्णमान में यह असन्तुलन किस प्रकार ठीक किया जाता है? समझाइए। (1976)

Discuss the various factors which cause disequilibrium in the balance of payments of a country. How is this disequilibrium corrected under the gold standard?

- 108 मुद्रा अवमूल्यन के देश के भुगतान शेष पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? मुद्रा अवमूल्यन के प्रभावों के बीच विश्लेषण और अवशोषण विश्लेषण में अन्तर की समझाइए। (1976)

What are the effects of devaluation on a country's balance of payments? Distinguish between the elasticity analysis and the absorption analysis of the effects of devaluation.

- 109 मुक्त विनिमय दरों का क्या अर्थ है? अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था के सुधार के सन्दर्भ में मुक्त विनिमय दरों से सम्बन्धित समस्याओं की व्याख्या कीजिए। (1978)

What are floating exchange rates? Examine the problem of currency floats in the context of reform of the international monetary system

- 110 मुद्रा अवमूल्यन के देश के भुगतान शेष पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या कीजिए। इस सन्दर्भ में—

(i) मार्शल-लार्नर नियम, और

(ii) अवशोषण पर अवप्रत्यक्ष प्रभावों का विवरण सेजिए। (1976)

Analyse the effects of devaluation on a country's balance of payments. Explain in this context—

(a) the Marshall Lerner conditions, and

(b) the indirect effects on absorption

- 111 विदेशी व्यापार गुणकों के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। भुक्तान-सन्तुलन की प्रक्रिया के सिद्धान्तों में इस सिद्धांत का क्या महत्व है? (1976)

Explain the concept of foreign trade multipliers. What is the importance of the concept in the theory of balance of payments adjustment?

अध्याय 16 से 18

- 112 विनिमय नियन्त्रण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? विनिमय नियन्त्रण की विधियों का वर्णन कीजिए।

What are the principal objects of exchange control? Describe the methods of exchange control

- 113 विनिमय-प्रबंध एवं विनिमय नियन्त्रण का अन्तर बताइए। विश्व युद्ध के दौरान तथा युद्धोपरान्त काल में विश्व के अधिकांश देशों ने विनिमय नियन्त्रण की विधियों का उपयोग क्यों किया था?

Distinguish between exchange management and exchange control. Why did most countries of the world adopt exchange control methods during and after the world war?

- 114 विनिमय नियन्त्रण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? भारत में पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति हेतु किस प्रकार का विनिमय नियन्त्रण लागू किया गया है, आलोचनात्मक समीक्षा के साथ बताइए।

What are the main objectives of exchange control? Discuss the nature of exchange control instituted in India for the implementation of her five year plans. Examine it critically.

- 115 विनिमय-नियन्त्रण की परोक्ष विधियों का विवरण देते हुए बताइए कि ये किस सीमा तक प्रभावकारी हो सकती हैं ?

Describe the indirect methods of exchange control and show how far are they effective.

- 116 विनिमय नियन्त्रण का अर्थ समझाइए। विनिमय नियन्त्रण के विभिन्न उद्देश्यों तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नीमा के युग में सप्तर के देशों द्वारा विनिमय नियन्त्रण की अपनई गई विभिन्न रीतियों का उल्लेख कीजिए।

Explain the meaning of exchange control. Discuss the various objectives and methods of exchange control that were employed by World countries to achieve these objectives during the thirties

- 117 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख उद्देश्य कौन-कौन से हैं ? मुद्रा कोष करने सहाय देशों को किस प्रकार सहायता देता है ?

What are the main objectives of International Monetary Fund ? How does the Fund assist its member countries ?

- 118 इन विधियों का विवरण दीजिए जिनके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों में साम्य बनाए रखने का प्रयास करता है। इन विधियों की सफलता का भी मूल्यांकन कीजिए।

Describe the methods by which the IMF helps to maintain international payments equilibrium and estimate their success ?

- 119 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अल्पविविधित देशों के लिए क्या उपयोगिता है। मुद्रा कोष के उद्देश्यों की तुलना में इनकी सफलता का मूल्यांकन कीजिए।

Examine the utility of the IMF for under-developed countries. Evaluate its contribution in relation to its objectives.

- 120 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्यों एवं नीतियों पर प्रकाश डालिए।

Explain the purposes and policies of I.M.F.

- 121 संक्षेप में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य एवं कार्य बताइए तथा अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग बढ़ाने में यह कहां तक सफल हो सका है ?

State briefly the purposes and functions of IMF and give an appraisal as to what extent it has successfully brought about international monetary cooperation.

- 122 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस प्रकार विनिमय दरों में स्थिरता लाने हेतु प्रयास किया है ? यह बताइए कि मुद्रा कोष के कार्यक्रमों एवं नीतियों ने भारत को किस प्रकार प्रभावित किया है ?

In what ways has the IMF helped to stabilize foreign exchange rates ? To what extent has India been affected by the policies and operations of the Fund ?

- 123 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा 'दुर्लभ मुद्राओं' की समस्या के समाधान में इसकी असफलता पर प्रकाश डालिए।

Examine critically the working of IMF and account for its failure to solve the problem of "Scarce Currencies"

- 124 दो देशों के बीच आधारभूत भुगतान अमान्य होने पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या-क्या कदम उठा सकता है ?

What steps can the IMF take if there is fundamental disequilibrium in balance of payments between two countries

- 125 भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता से विदेशी व्यापार एवं आर्थिक विकास के क्षेत्रों में क्या लाभ हुआ है ?

Assess the beneficial effects enjoyed by India in her membership of the IMF on her foreign trade and economic development

- 126 'अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य न तो विनिमय स्थायित्व है न विनिमय में परिवर्तनीयता है, बरन व्यवस्थित विनिमय की व्यवस्था है।'

क्या वहाँ तक अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में सफल हुआ है ? (1976)

The object of International Monetary Fund is neither exchange rigidity nor exchange flexibility but orderly exchange arrangement. Comment
How far has the I M F succeeded in this objective ?

- 127 'अंतर्राष्ट्रीय तरलता' से आप क्या समझते हैं ? इसके विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं ? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विविध आहरण अधिकारों के निवहन से यह समस्या क्या तक मुक्त हुई है ? (1977)

What do you understand by 'International Liquidity' ? What are its different sources ? To what extent has the issue of S D R s by the I M F eased this problem ?

- 128 अंतर्राष्ट्रीय तरलता एवं भुगतान की समस्या पर एक आलोचनात्मक विवेचन लिखिए। इस सम्बन्ध में विद्यमान कठिनाइयों को दूर करने हेतु आप क्या सुझाव दें ?

Write a critical note on the problem of International Liquidity and Payment. What suggestions do you offer to get over the present difficulties in relations to the development of world trade ?

- 129 अंतर्राष्ट्रीय तरलता के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं तथा उनकी वर्तमान स्थिति कैसी है ? विस्तार से समझाइए।

What are the chief sources of International Liquidity and what is their present position ?

- 130 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि करने हेतु क्या-क्या उपाय लिए हैं ? ये उपाय किस सीमा तक सफल रहे हैं ?

What measures have been taken by I M F in recent years to increase International Liquidity and how far they have been proved successful ?

- 131 तरलता के अभाव की समस्या के समाधान हेतु परिवर्तनीय विनिमय दरों की प्रस्ताव का वर्णन कीजिए।

Discuss the role of flexible exchange rates in meeting a situation of liquidity shortage

प्रश्नावली 19 से 21

- 132 दीर्घकालीन पूँजी अन्तरण के सन्दर्भ में देशीय तथा विदेशी पूँजी निवेश के मध्य अन्तर बताइए।

Distinguish between domestic and foreign capital investment in the context of long term capital movements

- 133 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के भुगतान की बाकी पर क्या प्रभाव होते हैं ?
What are the effects of direct foreign investment on the balance of payments ?
- 134 सभार के विकासशील देशों के आर्थिक विकास में विदेशी सहायता के तीव्र प्रवाह के महत्त्व की व्याख्या कीजिए। विकासशील देशों को विदेशी सहायता किस रूप में दी जानी चाहिए ? (1978)
Discuss the importance of increased flow of foreign aid in the economic development of world's developing countries. In what form should foreign aid be given to the developing countries ?
- 135 इस दृष्टिकोण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि विदेशी आर्थिक सहायता का विकासशील देशों के आर्थिक विकास में अधिक महत्त्व नहीं है।
Critically examine the view that foreign economic aid is of minor importance in the economic development of under developed countries
- 136 आर्थिक विकास में विदेशी पूँजी का क्या योगदान है ? विदेशी पूँजी का प्रवाह ऋणो व ऋणदाता देशों को किस प्रकार प्रभावित करता है ?
What is the role of foreign economic aid in economic development ? How does a flow of foreign capital affect the lending and borrowing countries ?
- 137 विकासशील देशों की विदेशी व्यापार सम्बन्धी समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डालिए।
Explain the foreign trade problems of developing countries.
- 138 क्या यह ठीक है कि विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों के निर्यातों से प्राप्त आय से अधिक अस्थिरता है ? इस स्थिति में इन देशों की सहायता हेतु अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली में क्या परिवर्तन होने चाहिए ?
Are under-developed countries suffering from greater instability in export earnings than high income countries? Are any changes necessary in the international economic system to help the poor countries in this respect ?
- 139 पूँजी का निर्यात ऋणदाता देश के लिए किस प्रकार सामाजिक दृष्टि से लाभप्रद या नुकसान-दायक सिद्ध हो सकता है ?
In what respect may the export of capital be socially advantageous or disadvantageous from the point of view of the capital exporting country ?
- 140 अर्द्ध-विकसित देशों के आर्थिक विकास में विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास सभा के योगदान का परीक्षण कीजिए। (1978)
Examine the role of IBRD and IDA in promoting the economic growth of underdeveloped countries
- 141 अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की ऋण नीति की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए तथा विकासशील देशों के आर्थिक विकास में इसके योगदान का विवरण दीजिए।
Critically examine the lending policy of International Bank for Reconstruction and development and evaluate its role in the promotion of the economic development of developing countries.

- 142 अन्तर्राष्ट्रीय विकास बैंक के अर्थ में अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की क्या भूमिका रही है ? बिन्दुओं से समझाइए ।
Examine the role played by the IBRD in assisting the economic development of underdeveloped countries

- 143 क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ये दोनों पूरक संस्थाएँ हैं ? यह बताइए कि ये दोनों संस्थाएँ अपने उद्देश्यों में किस सीमा तक सफल रही हैं ?
The IMF and IBRD are complementary institutions and show how far they have been able to achieve the objectives for which they are meant ?

- 144 अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम एवं अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के लक्ष्यों, उद्देश्यों एवं कार्य प्रणाली की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए ।
Critically examine the aims, objectives and working of the International Finance Corporation and International Development Association

- 145 अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के उद्देश्यों एवं संरचना का विवरण दीजिए । यह भी बताइए कि इस बैंक से भारत को क्या लाभ हुआ है ?
Discuss the organization and objectives of the IBRD To what extent has the Bank been able to help India ?

अध्याय 22 से 25

- 146 1956 के पश्चात् भारत की आयात एवं निर्यात व्यापार नीति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए । (1978)
Critically examine the salient features of India's import and export trade policy since 1966

- 147 पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत की आयात आवश्यकताओं निर्यात सम्भावनाओं और व्यापार आधिक्य के सर्वेक्षण का प्रयास कीजिए । (1978)
Attempt a brief survey of India's import needs, her export prospects and balance of trade position in the Fifth Five Year Plan.

- 148 भारत के विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियों का परीक्षण कीजिए । (1977)
Examine the recent trends in India's Foreign Trade.

- 149 आर्थिक नियोजन की अवधि में भारत के विदेशी व्यापार की संरचना एवं दिशा में हुए परिवर्तनों की विस्तृत समीक्षा कीजिए ।
Describe the changes that have taken place in the composition and direction of India's foreign trade during the planned period

- 150 भारत के विदेशी व्यापार की संरचना में हाल ही में हुए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए । आप निर्यात बढ़ाने व आयातों का प्रतिस्थापन बढ़ाने हेतु क्या सुझाव देंगे ?
Examine the recent trends in the composition of India's foreign trade. What steps do you suggest for promoting exports and substituting imports ?

- 151 भारत के आयात व निर्यात व्यापार में सम्मिलित प्रमुख वस्तुओं का विवरण दीजिए ।
Describe main commodities of India's export and imports.

- 152 निम्न दो दशकों में पूर्वी यूरोप के साथ भारत के व्यापार की संरचना तथा प्रवृत्ति का विवरण प्रस्तुत कीजिए ।

Discuss the composition and trend of India's trade with Eastern Europe during the last two decades.

- 153 वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा अपनाए गए विनिमय नियन्त्रण के उद्देश्यों एवं विधियों का वर्णन कीजिए। (1976)

Describe the objects and various methods of exchange control adopted by the Government of India at the present moment.

- 154 विनिमय नियन्त्रण का क्या अर्थ है ? भारत में विनिमय नियन्त्रण के कार्य की व्याख्या कीजिए। (1976)

What is meant by exchange control ? Discuss the working of exchange control in India.

- 155 क्या आप रुपये के अवमूल्यन का समर्थन करेंगे ?
Would you advocate the devaluation of the Rupee ?

- 156 1966 में हुए रुपये के अवमूल्यन की आधारभूत परिस्थितियों पर विचार कीजिए। इससे हमारे देश का व्यापार किस प्रकार प्रभावित हुआ ?

Discuss the circumstances leading to the devaluation of Rupee in 1966. How did it effect the course of foreign trade in our country ?

- 157 भारतीय राजकीय व्यापार निगम की कार्यप्रणाली की व्याख्या कीजिए तथा यह बताइए कि यह देश के निर्यात व्यापार को किस प्रकार सहायता कर रहा है ? (1978)

Explain the working of the State Trading Corporation of India and state how it is helping the export trade of the country ?

- 158 भारतीय राज्य व्यापार निगम के कार्यों, प्रगति व सीमाओं पर एक निवेदन लिखिए। (1978)
Write a note on the functions, progress and limitations of the State Trading Corporation of India.

- 159 भारत के भुगतान सन्तुलन की अग्रिम प्रवृत्तियों व वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कीजिए। हाल ही में हमारे विदेशी मुद्रा कोषों के उपयोग हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ? (1978)

Discuss the recent trends and present position of India's balance of payments. What steps have been taken by the Government to utilise our foreign exchange reserves recently ?

- 160 तेल में कीमतों की वृद्धि से भारत के भुगतान सन्तुलन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ? स्थिति से निपटने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं ? (1976)

Discuss the impact of the rise in oil prices on India's balance of payments. What steps have been taken to deal with the situation ?

- 161 व्यापार सन्तुलन व भुगतान सन्तुलन में अन्तर बताइए। भारत सरकार द्वारा अपने प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन को ठीक करने के लिए हाल ही में अपनाए गए उपायों की विवेचना कीजिए। (1977)

Distinguish between balance of trade and balance of payment. Discuss briefly the measures adopted by the Government of India to correct its adverse balance of payment recently.

य प्रश्न और टिप्पणियाँ

निम्नलिखित में से किसी दो पर टिप्पणियाँ लिखिए—

- (1) अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार एवं अन्तरराष्ट्रीय तरलता,
- (ii) भुगतान संकट
- (iii) अर्थशास्त्र
- (iv) लघु व्यवसाय विकास।

(1978)

Write short notes on any two of the following—

- (i) IMF and International Liquidity
- (ii) Balance of payments,
- (iii) UNCTAD
- (iv) Regional Economic Cooperation.

3 किसी दो पर टिप्पणियाँ लिखिए—

- (1) वैश्व
- (ii) विनिमय नियंत्रण
- (iii) अर्थशास्त्र
- (iv) विदेशी व्यापार नियंत्रण।

Write notes on any two

- (i) GATT
- (ii) Exchange Control
- (iii) UNCTAD
- (iv) Foreign Trade Multiplier

निम्नलिखित में से किसी दो पर टिप्पणियाँ लिखिए—

- (1) रुपये का विनिमय दर
- (ii) राष्ट्रीय व्यापार नियंत्रण
- (iii) भारतीय व्यापार का विकास
- (iv) द्विपक्षीय व्यापार समझौते।

(1976)

Write notes on any two

- (i) Exchange rate of the Indian Rupee
- (ii) State Trading Corporation,
- (iii) Direction of India's trade
- (iv) Bilateral trade agreements

निम्नलिखित में से किसी दो पर टिप्पणियाँ लिखिए—

- (1) वैश्व अर्थशास्त्र
- (ii) भुगतान संकट
- (iii) विदेशी मुद्रा बाजार एवं अन्तरराष्ट्रीय तरलता, या अर्थशास्त्र विकास,
- (iv) लघु व्यवसाय विकास।

(1977)

Write short notes on any two of the following—

- (i) Factor intensity reversal
- (ii) Balance of payment
- (iii) Foreign aid and economic development of less developed countries
- (iv) Factor price equalisation theorem.